

## स्मरण

जिन्हों ने मुझे सरकार के कामों से पहले-पहल  
शौक़ दिलाया था, उन्हीं पूजनीय पिता  
वाचू मेवारामजी वी० ए० की  
पुण्यस्मृति को

## प्रस्तावना

हिंदुस्तान में राजनैतिक चहल-पहल दिन-दिन बढ़ रही है। चारों तरफ राजनैतिक तब्दीलियों की माँग और कोशिशें हो रही हैं। ब्रिटिश सरकार तक ने हिंदुस्तान के लिए स्वराज्य का ध्येय मजूर कर लिया है। मगडा सिफं इस बात का रह जाता है कि उस स्वराज्य का क्या रूप और रंग होगा और वह किस तरह लिया जायगा। सभी के मन में ऐसी तब्दीलियों के जमाने में हिंदुस्तान की नई सरकार के बारे में तगढ़-तरढ़ के खयाल उठते होंगे।

इन खयालों को अमल में लाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों का हाल जान लेना हमारे लिए अच्छा होगा। अस्तु हम पाठकों के सामने यूरोप की सरकारों का हाल रखते हैं।

इस छोटी किताब में जितना हो सकता था उतना यूरोप की लगभग सभी सरकारों का हाल पाठकों के सामने रखने की कोशिश की गई है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और रूस की सरकारों का हाल ज्यादा दिया गया है। इन छः देशों की सरकारों का हाल विस्तार से जान लेने के बाद फिर दूसरे यूरोपीय देशों की सारी सरकारों का हाल उतना ही विस्तार से जानने की ग्रामतीर पर ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी यूरोप के दूसरे देशों की सरकारों का हाल भी जितना इस किताब में आ गया है, उतना हिंदी की दूसरी पुस्तक में, और शायद हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं के ग्रंथों में अभी तक नहीं दिया गया है। अस्तु हिंदी भाषा-भाषियों के आगे यह ग्रंथ रखते हमें खुशी होती है।

इंग्लैंड की सरकार का हाल जान कर हम अपने देश की राजनीति में अमली बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। फ्रांस की राजनैतिक दलबंदी इत्यादि की कठिनाइयों का हाल पढ़ कर हम अपनी राजनैतिक कठिनाइयों पर नाउम्मेद न हो जाने का सबक ले सकते हैं। इटली की राजनीति से हमें पता लगेगा कि दुनिया में कठिन रोगों के लिए राजनीति में कड़वी दवाएं पीनी पड़ती हैं। जर्मनी में हम राजनैतिक मौत के मुँह में पड़ कर निकल आना सीख सकते हैं। स्विट्जरलैंड से हम अपने गरीब देश की सरकार को क़िफायत से चलाने और अपने देश के गाँवों में खालिस प्रजासत्ता कायम करने, तथा अल्प संख्याओं की समस्या मुलमाने की शिक्षा ले सकते हैं। रूस की मज़दूरपेशा-

शाही सरकार तो हमें राजनीति की एक नई दुनिया में ही ले जाकर खड़ा कर देती है, जिस से हम प्रजा के हित में सरकार का समर्थन करने की बहुत-सी नई बातें भीत सकते हैं। यूरोप के दूसरे राष्ट्रों की सरकारों, खास कर लंडाई के बाद बनने वाले नए राष्ट्रों की सरकारों का हाल जान कर भी हमें अपनी विभिन्न राजनैतिक समस्याएँ सुलझाने में बड़ी सहायता मिल जाती है। अस्तु आशा है कि यह ग्रंथ साधारण मतदारों से लेकर राजनीति के विद्वार्थियों और कौंसिलों के सदस्यों इत्यादि उन सभी लोगों के काम आयेगा जिन्हें इस देश की राजनैतिक उलझनों में दिलचस्पी रहती है।

दुर्भाग्य से अभी तक हमारे देश में सामान्य विषयों पर आधुनिक ग्रंथ लिखने के लिए सहूलियतें बहुत कम हैं। बड़े बड़े नगर और विश्वविद्यालयों तक में एक ही स्थान पर सारे जरूरी ग्रंथों का संग्रह नहीं मिलता है जिस से एक जगह सहूलियत से बैठ कर कोई पुस्तक लिखी जा सके। आधुनिक ग्रंथों की भी इन पुस्तकालयों में बड़ी कमी रहती है। अस्तु इस ग्रंथ को लिखने के लिए सहायक ग्रंथों को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। जबई की रायल ऐशियाटिक सोसाइटी और पेट्रिट इन्स्टीट्यूट पुस्तकालयों से काफी ग्रंथ मिले। मगर जबई और मद्रास के सारे पुस्तकालयों की ख़ास छान कर भी जो ग्रंथ न मिल सके वह परम उपयोगी ग्रंथ मित्रों की सहायता और दया से प्राप्त हुए। इन मित्रों और स्नेहियों की सहायता के बिना इस ग्रंथ का इस रूप में निकलना संभव नहीं था। अस्तु इन सारे मित्रों का और खास कर मेजरअली, कृष्ण मेनन, विश्वनाथ, रंगीलदास कापडिया, बी० शिवराव और श्रीराम का मैं आभारी हूँ। कुछ यूरोपीय देशों के नागरिकों और कौमलों से जो सहायता मिली उस के लिए उन को भी धन्यवाद देना जरूरी है। सब से जरूरी धन्यवाद हिंदुस्तानी एकेडेमी को है जिस के द्वारा ग्रंथ पाठकों तक पहुँचेगा।

अड्यार मद्रास }  
१० जुलाई १९२२ }

चंद्रमाल जोहरी

### पुनश्च

यह ग्रंथ लिख कर १० जुलाई सन् १९२२ ई० को मैंने हिंदुस्तानी एकेडेमी के पास छपने के लिए भेज दिया था। एकेडेमी अपनी कठिनाइयों से अब तक इस ग्रंथ को प्रकाशित न कर सकी। अब तक अर्थात् अक्टूबर सन् १९२२ ई० तक, जब यह ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है हमारे देश में और यूरोप में बहुत कुछ तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के लिए फ़ेडरल दम की सरकार की एक राज्यस्था ब्रिटिश पार्लामेंट ने

स्वीकार कर ली है, और सबों में एक प्रकार का स्थानिक स्वराज्य कायम हो गया है, जहां पार्लियामेंटरी ढंग की प्रांतीय सरकारें काम चलाने लगी हैं। परंतु सात राज्यों में कांग्रेस-दल की सरकारें होने पर भी चूंकि कांग्रेस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की बनाई हुई फेडरेल राजव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है, और उस का घोर विरोध कर रही है, अभी तक इस देश की राजव्यवस्था अनिश्चित ही है। हिंदू मुस्लिम और देसी रजवाड़ों की समस्याएं तय करके अभी हमें अपने देश की राजव्यवस्था निश्चय करनी है। अस्तु यूरोप की सरकारों का हाल जानना हमारे लिए इस समय खास तौर से जरूरी है।

छः वर्ष के जमाने में अर्थात् जब यह ग्रंथ लिख कर तैयार हुआ था तब से आज तक जब कि यह प्रकाशित हो रहा है यूरोप में इतनी सीबूता से राजनैतिक फेरफार हुए हैं और हो रहे हैं कि बदलने वाली इन यूरोपीय सरकारों के काम-काज का पूरा हाल लिखना इस ग्रंथ में समझ नहीं है। जहां तक मुमकिन हो नका है वहां तक इन तब्दीलियों का जिक्र करने की कोशिश की गई है, जैसे कि जर्मन सरकार में हिटलर के ताकत में आने से जो तब्दीलियां हुई हैं उन का। परंतु आस्ट्रिया के बारे में हम इतना ही अधिक कह सके हैं कि चूंकि यह राष्ट्र अब जर्मन रीश में मिला लिया गया है, इस की सरकार भी जर्मन सरकार के रूप रंग की होगी। स्पेन में शत्रुयुद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध के बाद न जाने इस देश की कैसी सरकार होगी ? आज कल आधे देश में इटली के अनुयायी जेनरल फ्रैंको का शासन है और आधे देश में रूस के अनुयायियों का। अस्तु, हम ने पुरानी सरकार का जिक्र करके ही छोड़ दिया है। रूसी राज-व्यवस्था में स्टालिन ने बहुत सी नई तब्दीलियां की हैं जिन से कहा जाता है यह सरकार बहुत कुछ व्यवस्थापकी ढंग की हो गई है। परंतु कागज़ पर व्यवस्थापकी ढंग की सरकार चाहे हो गई हो वास्तव में रूस में कम्यूनिस्ट दल की और स्टालिन की अभी तक वैसी ही ताकत कायम है। दूसरे यूरोपीय देशों में भी फेरफार हुए हैं। परंतु इन सब तब्दीलियों का पूरी तरह हाल कुछ समय बाद ही लिखा जा सकता है।

चंद्रमाल जीदरी



# विषय-सूची

	५४
<b>इंग्लैंड की सरकार</b>	<b>१७</b>
१—राज व्यवस्था	१७
२—राजछत्र	२०
३—मन्त्रि मंडल	२४
४—व्यवस्थापक सभा—हाउस ऑफ् कामन्स	३२
५—व्यवस्थापक-सभा—हाउस ऑफ् लार्डस्	४३
६—स्थानिक शासन और न्याय शासन	४६
७—राजनैतिक दल	५३
<b>आयरलैंड और अल्स्टर की सरकारें</b>	<b>६३</b>
१—आयरलैंड की सरकार	६३
१—राज-व्यवस्था	६३
२—व्यवस्थापक-सभा	६७
३—कार्यकारिणी	६७
४—स्थानिक शासन और न्याय शासन	६८
५—राजनैतिक दल	६८
२—अल्स्टर की सरकार	७०
<b>फ्रांस की सरकार</b>	<b>७१</b>
१—राज व्यवस्था	७१
२—प्रजातन्त्र का प्रमुख	८०
३—मन्त्रि मंडल	८४
४—व्यवस्थापक सभा	८०
५—स्थानिक शासन और न्याय शासन	१०६
६—राजनैतिक दल	११४
<b>इटली की सरकार</b>	<b>१२०</b>
१—राज व्यवस्था	१२०
२—राजछत्र	१२४
३—मन्त्रि मंडल	१२६
४—व्यवस्थापक-सभा	१२८

५—राजनैतिक दलबंदी	१३१
६—फेसिस्ट सरकार	१४३
<b>बेलजियम की सरकार</b>	<b>१५२</b>
१—राज-व्यवस्था	१५२
२—व्यवस्थापक-सभा	१५३
३—राजा और मंत्री	१५५
४—न्याय-शासन	१५५
५—राजनैतिक दल	१५६
<b>जर्मनी की सरकार</b>	<b>१५७</b>
१—साम्राज्य की राज व्यवस्था	१५७
२—शहशाह कैसर	१६१
३—चांसलर	१६३
४—व्यवस्थापक-सभा : ( १ ) बंडसराय	१६४
५—व्यवस्थापक-सभा : ( २ ) रीशटाग	१६७
६—राजनैतिक दलबंदी और कायापलट	१७०
७—प्रजातंत्र राजव्यवस्था	१८१
८—व्यवस्थापक-सभा : ( १ ) रीशटाग	१८५
( २ ) रीशराय	१८६
९—प्रमुख और मन्त्रि-मंडल	१८७
१०—नई दलबंदी	१८९
<b>स्विट्ज़रलैंड की सरकार</b>	<b>२०१</b>
१—राज-व्यवस्था	२०१
२—स्थानिक सरकार	२०७
( १ ) शासन क्षेत्र	२०७
( २ ) कानून रचना	२०९
( ३ ) कार्यकारिणी	२१८
( ४ ) न्याय शासन	२१९
३—संघीय सरकार	२२०
( १ ) व्यवस्थापक-सभा	२२१
( २ ) कार्यकारिणी	२२७
( ३ ) न्याय शासन	२३०
( ४ ) सेना संगठन	२३२
<b>सोवियट सरकार</b>	<b>२४३</b>
राज व्यवस्था	२४३
शहरी और देहाती सोवियट	२५४

स्थानिक सोवियट कांमिसे	२५६
केन्द्रीय सरकार	२६४
शासन-विभाग	२६७
राजनैतिक दल	२७२
फिनलैंड की सरकार	२८३
ऐस्थोनिया की सरकार	२८६
लिथूनिया की सरकार	२८६
लटविया की सरकार	२८२
आस्ट्रिया और हंगरी की सरकार	२८५
पुरानी द्वाराजाशाही	२८५
नई आस्ट्रिया	२८८
कार्यकारिणी	३०२
स्थानिक शासन और न्याय	३०५
हंगरी की नई सरकार	३०७
पोलैंड की सरकार	३११
ज़ेकोस्लोवाकिया की सरकार	३१७
यूगोस्लाविया की सरकार	३२४
रूमानिया की सरकार	३२६
टर्की की सरकार	३३३
अल्बानिया की सरकार	३३८
बल्गेरिया की सरकार	३४०
यूनान की सरकार	३४५
डेन्मार्क की सरकार	३४६
हालैंड की सरकार	३५३
नार्वे की सरकार	३५७
स्वीडन की सरकार	३६१
पुर्तगाल की सरकार	३६५
स्पेन की सरकार	३६६
पारिभाषिक शब्दों की सूची	३७३

## सहायक ग्रंथों की सूची

1. Modern Constitutions. 2 vols. By Dodd.
2. The State. By Woodrow Wilson.
3. Modern Democracies. 2 vols. By Bryce.
4. Governments of Europe. By Munro.
5. Mechanism of Modern State. By Marriot.
6. New Constitutions of Europe. By H. Morley.
7. Governments and Parties in Europe. 2 vols. By Lowell.
8. How we are Governed. By A. de Fontblanque.
9. The European Commonwealth. By Marriot.
10. The Governments of Europe. By F. A. Ogg.
11. Political Institutions of the World. By Preussing.
12. Modern Political Constitutions. By C. F. Strong.
13. The New Constitutions of Europe. By Mc Bain.
14. Select Constitutions of the World—prepared for Dail Eireann by order of the Irish Provisional Government.
15. Europa : Encyclopedia of Europe.
16. A Political Handbook of the World. By Malcolm W. Davis and Walter H. Mallory.
17. Representative Government in Europe. By Guizot.
18. The Working Constitution of the United Kingdom. By Courtney.
19. Men and Manners in Parliamentary. By Sir Henry Lucy.
20. Peeps at Parliament. By Sir Henry Lucy.
21. The Book of Parliament. By McDonagh.
22. Parliament, its Romance, its Comedy, its Pathos. By McDonagh.
23. English Political Institutions. By Marriot.
24. The House of Lords. By T. A. Spalding.
25. The House of Commons. By Sir Richard Temple.
26. The English Constitution. By A. I. Stephen.
27. English Government and Constitution. By John Earl Russell.
28. The Evolution of Parliament. By A. F. Pollard.
29. The Rise of Constitutional Government in England. By C. Ransome.

31. Government and Politics of France. By E. M. Sait.
32. The Government of France. By Joseph Barthélemy.
33. Governance of France. By Raymond Poincaré.
34. The Makers of Modern Italy. By Marriot.
35. Autobiography. By Mussolini.
36. The Making of the Facisti State.
37. Four years of Facism. By Cr. Ferrero.
38. The Awakening of Italy. By Lugivillari.
39. Facism. By Odon Por ?
40. The Rise of German Republic. By H. G. Peniels.
41. New Germany. By Young.
42. Many of Today. By Charles Tower.
43. Government in Switzerland. By Vincent.
44. Government and Politics of Switzerland. By Brooks.
45. Russian Political Institutions. By M. Kovalevsky.
46. Soul of Russian Revolution. By Olgin.
47. Years of Russian Revolution. By A. S. Ra.
48. Russian Revolution. By Mavor.
49. The Eclipse of Russia. By E. J. Dillon.
50. Bolshevism at Work. By W. T. Goode.
51. The History of Russian Revolution. ( Official )
52. Prelude to Bolshevism. By Kerensky.
53. Soviets at Work. By Lenin.
54. Russian Revolution. By Lenin.
55. A. B. C. of Communism. By Bukharin.
56. Communism. By H. Laski.
57. How the Soviets Work. By Brailsford.
58. Soviet Year Book, 1926.
59. Ten Days that Shook the World.
60. Our Revolution. By Trotsky.
61. Report of the Sixteenth Party Congress.
62. The State and Revolution. By Lenin.
63. The Austrian Revolution. By Otto Baner.
64. The Statesmen year Book, 1921—1930
65. The Irish Free State. By Denis Gwynn.
66. My Fight for Irish Freedom, By Dan Breen.

# इंग्लैंड की सरकार

## १—राज-व्यवस्था

यूरोप के देशों में इंग्लैंड से हमारा सबसे अधिक संबंध रहा है। आजकल तो हमारी सरकार अँगरेजी है ही, भविष्य में भी हमारे देश की राज-व्यवस्था पर बहुत कुछ अँगरेजी छाप रहेगी। इस राजनैतिक नाते से, और इस कारण कि यूरोप के और देशों की राज-व्यवस्थाओं पर भी इंग्लैंड की राज-व्यवस्था की बहुत कुछ छाप पड़ी है, यूरोप की और सरकारों का हाल जानने के पहले इंग्लैंड की राज-व्यवस्था का अध्ययन करना ही हमारे लिए ठीक होगा।

इंग्लैंड की राज-व्यवस्था बड़ी विचित्र और मनोरंजक है। दूसरे यूरोपीय देशों अथवा अमेरिका की तरह इस देश की राज-व्यवस्था किसी कागज़ पर लिखी हुई नहीं है। ऐतिहासिक और राजनैतिक विकास के साथ-साथ इंग्लैंड की राज-व्यवस्था का भी धीरे-धीरे विकास हुआ है। यहाँ की राज-व्यवस्था केवल किसी लोमहर्षण क्रांति का तीव्र फल, किसी सधि का अचानक परिणाम अथवा केवल किसी वैध-आंदोलन-द्वारा प्राप्त कानून का नतीजा नहीं है। धीरे-धीरे बढ़ के पेड़ की तरह बढ़ कर युगों में इंग्लैंड की राज-व्यवस्था ने आजकल का विशालकाय स्वरूप प्राप्त कर पाया है। इस वृहत् बढ़ की जटाएँ इंग्लैंड के राजनैतिक-जीवन में फैल कर ऐसी घुस गई हैं कि किसी भी राजनैतिक दल-चल में यह वृत्त दृष्टता दिखाई नहीं देता है। बड़े-बड़े बवंडरों में भी हिल-जुल और झुक कर ही काम बना लेता है।

उन देशों की राज-व्यवस्था की व्याख्या और मीमांसा सरल होती है, जिन की राज-व्यवस्था किसी लिखित दस्तावेज के अनुसार चलती है। अमेरिका की सरकार का कोई काम उस देश की राज-व्यवस्था के अनुसृत है या नहीं यह जान लेना बहुत ही सरल है, क्योंकि वहाँ सरकार के हर काम की परीक्षा वहाँ की लिखित राज-व्यवस्था की कसौटी पर अदालत में की जा सकती है। मगर इंग्लैंड की सरकार का कौन सा काम और कानूनी है यह केवल एक राय की बात है, कानून की बात नहीं, और यह राय बदलती रहती है।

ब्रिटिश राज-व्यवस्था की बुनियाद तो कानून ही है, परन्तु अधिभूत उम्र का आधार रिवाजों पर है। यह कोई नयी अनोखी बात नहीं है। मनुष्य समाज ही विनयी कानूनी और ऐतिहासिक चल्पनाओं पर निर्धारित है। मूल मतलब यह जाने पर भी पुरानी मर्यादों और पद कायम रह जाते हैं और उन का वास्तविक काम कोई दूसरा ही करता है। हाथी के दिराने के दाँतों की तरह इन मर्यादों और पदों का स्थान हो जाता है और वास्तविक कार्य करनेवाले अदृश्य रहते हैं। चारों तरफ ससार में ऐसी ही प्रगति दिखाई देती है। आधुनिक राज-व्यवस्थाओं में इस बात का बहुत प्रयत्न किया जाता है कि सारी बातें लिखित कानूनों के ही अंतर्गत कर ली जायें और कोई भी बात केवल रिवाज के नियम पर निर्धारित न रहे। परन्तु इस प्रयत्न में कभी पूरी सफलता प्राप्त नहीं होती। इंग्लैंड की राज-व्यवस्था का भी काफी भाग अब लिखित कानूनों में समाविष्ट हो चुका है। परन्तु इस देश में आज तक कभी इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया है कि सारी की सारी राज-व्यवस्था लिपि बद्ध हो जावे। इस का कारण अलस्य नहीं है। अंगरेजों को अपनी राज-व्यवस्था के अनूठे ढंग पर गर्व है। राजनीति का एक प्रख्यात अंगरेज विद्वान् बड़े गर्व से लिखता है, “दो सौ वर्ष से अधिभूत चुके फिर भी हमारे देश में कोई राजनैतिक क्रांति नहीं हुई है। हमें न तो नए सिरे से अपनी राज-व्यवस्था की रचना करने की आवश्यकता हुई है और न हमें अपने निवासियों की नींव ही टटोलनी पड़ी है। हमें अपनी जाति की अतर्क-बुद्धि पर धमक है। हम ने जान बूझ कर नियमबद्धता स्वीकार नहीं की है। हम आवश्यकतानुसार काम चलाना जानते हैं। हमें अपनी ऐसी ही कामचलाऊ राज-व्यवस्था पसंद है जो हर आवश्यकता और हर अवसर के उपयुक्त होती है, यद्यपि वह कुछ कानून, कुछ इतिहास, कुछ नीति, कुछ रिवाज और कुछ उन विभिन्न प्रभागों का एक समिश्रण है, जो हर वर्ष या यों कहिए कि हर प्रहर सामाजिक जीवन को बढ़ते और बदलते रहते हैं।”

इंग्लैंड की सरकार का वर्णन लिखना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार किसी जीवित मनुष्य की दस वर्ष बाद की तस्वीर में हाथ, पैर, मुख और शरीर वही रहने पर भी यादृच्छिक, भाव और ऊँचाई-भोलाई में परिवर्तन हो जाने के कारण बहुत कुछ फर्क हो जाता है, उसी प्रकार दस वर्ष बाद भी ब्रिटिश राज-व्यवस्था ऊपर से वैसी की वैसी बनी रहने पर भी भीतर से बहुत कुछ बदल जा सकती है। ऊपर से देखने से इंग्लैंड की राज-व्यवस्था में बड़ी आश्चर्यजनक स्थिरता दीखती है। राजा, पार्लियामेंट, मजिस्ट्रेट, निर्वाचक समूह, न्याय विभाग इत्यादि ब्रिटिश राज-व्यवस्था के विभिन्न अंग सदा जैसे के जैसे नये

रहते हैं यथवा यो कहिए कि जैसे वे तेसे बने लगते हैं या दिखाई देते हैं। परन्तु वास्तव में ज़माने के अनुसार उन में इतना परिवर्तन हो जाता है कि नित नई भीमाला की आवश्यकता रहती है।

इंग्लैंड की राजनीति की हमेशा से यह समस्या रही है कि कैसे राज्य-व्यवस्था के पुर्जों को बिना बदले या तोड़े फोड़े ज़माने के अनुसार ध्येय और सिद्धांतों की पूर्ति की जाय। दूसरे देशों में राज-व्यवस्थाएँ ठेठ कर गयी गई हैं। इंग्लैंड में उसे पौदे की तरह उगने दिया गया है। अतएव इंग्लैंड की राज-व्यवस्था के अग स्वभावतः वातावरण के अनुकूल बन गए हैं। इंग्लैंड की राज-व्यवस्था मगीन की तरह नहीं बनी है, शरीर की तरह नट कर तैयार हुई है।

अंगरेज अपनी सरकार के ऊपरी रूप-रंग में परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं। सदियों बीत जाती हैं और इंग्लैंड की सरकार के बाह्यरूप में जरा भी अंतर नहीं होता है। आंतरिक, आवश्यक और वास्तविक रूप रंग में बहुत कुछ फेर पार होते रहते हैं। मगर इस फेर-पार का राज-व्यवस्था के किसी कानून अथवा पार्लामेंट की किसी लिपि में नहीं जिक्र तक नहीं होता है। न जनता ही को इस फेर पार का कुछ पता होता है। अगर किसी भू-रूप से इंग्लैंड की सम्पत्ता यकायक चकनाचूर हो कर मिट्टी में मिल जावे और हजारों वर्ष बाद इंग्लैंड के गेंडहरों से कोई विद्वान् वहाँ की राज-व्यवस्था का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तो उस के लिए असंभव होगा। उसे सोलहवीं और बीसवीं शताब्दी के इंग्लैंड की राज-व्यवस्था में कोई फर्क नहीं मालूम होगा।

अंगरेजों को जितना पुरातन पर प्रेम है, उतना शायद पश्चिम की और किसी भी जाति को नहीं है। प्राधुनिक समस्याओं को हल करते समय भी वे पुरातन प्रथाओं का विचार रखते हैं। एक अंगरेज विद्वान् ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि, “हमारे देश की राज-व्यवस्था हमारे रस्मोरियाज का ही एक अंग है।”

अगर किसी पढ़े लिखे अंगरेज से पूछा जाय कि इंग्लैंड की राज-व्यवस्था का शान नहीं से हो सकता है, तो वह बेचारा अधिक से अधिक यह कह सकेगा कि मैमफार्ड, पिटीशन ऑफ् राइट्स और विल ऑफ् राइट्स इंग्लैंड की राज-व्यवस्था की जड़ हैं। मगर इन तीनों कागजों को पढ़ कर बड़ी निराशा होगी। मेमफार्ड में सरकारी इमदाद, राँध और नदियों तथा माप और तौल का जिक्र मिलेगा। पिटीशन ऑफ् राइट्स में इस बात का जिक्र होगा कि बिना पार्लामेंट की सलाह के राजा को प्रजा से कर वसूल नहीं करना चाहिए। विल ऑफ् राइट्स में जनता को हथियार रखने की इजाजत इत्यादि का जिक्र मिलेगा। उस। उन्नीसवीं शताब्दी के रिफार्म् ऐक्ट्स और पार्लामेंट की आगतक की सारी चर्चा पढ़ने पर भी इंग्लैंड की राजनैतिक सस्याओं का सचा ज्ञान नहीं होता। पार्लामेंट के नियम, कानून अथवा प्रस्ताव में वही इंग्लैंड में प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित होने का वाक्यावदा जिक्र नहीं है। कानून के अनुसार तो इंग्लैंड में प्रजा-सत्तात्मक राज्य ही नहीं है, राजशाही है। मन्नि मडल जैसी प्रधान सस्या के कायम होने तक का कहीं किसी कानून में जिक्र नहीं है। जिस ऐक्ट के अनुसार वर्तमान स्वरूप में विक्टोरिया को इंग्लैंड की



सरकार मिली थी, उस में भी 'जपाउदार मंत्री' इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल एक कोने पर दिए हुए एक छोटे से नोट में इस बात का इशारा है कि इस ऐक्ट से इंग्लैंड की राज-व्यवस्था में कितना भारी परिवर्तन हुआ था। और भी बहुत-सी असह्य बातों का, जैसे कि निर्वाचन-समूह का पार्लामेंट पर प्रभाव, जन मत का सगठन, प्रधान मंत्री की सत्ता, कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सभा का समाज के विभिन्न अंगों से संबंध, सार्वजनिक सभाओं और राजनैतिक संस्थाओं का सरकार के कामों में भाग इत्यादि किसी चीज का पार्लामेंट के कानूनों में समावेश नहीं है। यही नहीं भाषण स्वातंत्र्य और जनता का एकन हो कर सभा इत्यादि करने के जन्मसिद्ध अधिकारों का भी कानूनों में जिक्र नहीं है। प्रोफेसर डाइसी लिखते हैं, "भाषण स्वातंत्र्य का इंग्लैंड में सिर्फ यह मतलब है कि बारह दूकानदार मिल कर यह पच फैसला कर दें कि अमुक बात कहना उचित है, अमुक नहीं।" इसी प्रकार जन साधारण का मिल कर सभा करने का अधिकार केवल अदालतों के मतानुसार जनता के व्यक्तिगत अधिकारों में आ जाता है, वहाँ किसी कानून में उस का जिक्र नहीं है। इंग्लैंड की सरकार का काम अधिकतर आम समझ पर चलता है। जो बातें इंग्लैंड के राजनैतिक जीवन में मिलती हैं वे वहाँ के कानूनों और कितायों में नहीं हैं, और जो बातें वहाँ के कानूनों और सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए वह कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। इंग्लैंड की राज-व्यवस्था के मुख्य अंग राज-छत्र, मंत्रि मंडल और पार्लामेंट हैं।

## २—राजछत्र

इंग्लैंड का राज्य सिद्धांतानुसार निरा निरंकुश, देखने में परिमित निरंकुश और वास्तविक गुण में प्रजासत्तात्मक है। इंग्लैंड की राज-व्यवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए इंग्लैंड के राजा और राजछत्र का भेद समझ लेना बहुत जरूरी है। यद्यपि कानूनों में इस भेद पर जोर नहीं दिया जाता है।

इंग्लैंड का राजछत्र एक बड़ी कामचलाऊ चीज है। उस को लगभग ब्रह्मा के समान सर्वश, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना जाता है, परंतु इंग्लैंड के जिस राजा की सत्ता का इतना वर्णन कानूनों, अदालतों, दस्तावेजों और सरकारी ऐलानों में आता है वास्तव में न उस को इतने अधिकार हैं और न उसकी इतनी सत्ता है। इंग्लैंड में पुराने विचारों के अनुसार किसी परमात्मा के प्रतिनिधि राजा का राज्य नहीं है। वहाँ प्रजासत्तात्मक राज्य है और राज्य का सिरमौर नाममान के लिए राजा माना जाता है। जो अधिकार और सत्ता राजा की वही जाती है वह उस बहावती राजछत्र की है जिस को राजा न पुकार कर राष्ट्र अथवा 'प्रजा की इच्छा' या और किसी इसी प्रकार के उपयुक्त नाम से पुकार सकते हैं। इंग्लैंड का इतिहास पढ़ने से पता लगता है कि पुराने जमाने में राजा के जो व्यक्तिगत अधिकार थे वे धीरे धीरे सदियों में राजा के व्यक्तिगत अधिकार न रह कर राजछत्र अथवा राष्ट्र के अधिकार हो गए हैं। इन अधिकारों का प्रयोग आजकल का राजा नहीं करता बल्कि

राष्ट्र की प्रतिनिधि पार्लियामेंट की एक समिति करती है। कानूनों के अनुसार राष्ट्र की सारी कार्यकारिणी सत्ता राजा में है। जल और थल सेना के सारे अधिकारियों को नियुक्त करने, सेनाया वा संचालन करने, संधि और विग्रह करने, शासन चलाने के लिए पदाधिकारियों को नियुक्त करने, शासन और दंडनीति पर देख-रेख रखने, अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, पार्लियामेंट से स्वीकृत हुए धन को खर्च करने इत्यादि सारे कार्य-संचालन का पूर्ण अधिकार केवल राजछत्र के है। इंग्लैंड के साधारण मनुष्यों को यह सुन कर अचर्य आश्चर्य होगा कि उन का राजा, सेना के पर्याप्त सर सज्जा है, सेनापति से ले कर सिपाही तक सारे अधिकारियों को निकाल सज्जा है, जहाजों को बेंच और राजसंपत्ति का नीलाम कर सकता है, इंग्लैंड के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को लार्ड बना सकता है और अपराधियों को क्षमा कर के सारी जेलें खाली कर सकता है, परंतु सच बात यह है कि इंग्लैंड का राजा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। यह सारे अधिकार केवल उस के दिखाने के दाँत हैं। सत्र कुछ करने धरने और इन अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार मंत्रि मंडल को होता है। एक बार सन् १८७१ ईसवी में प्रधान मंत्री ग्लैडस्टन ने हाउस ऑफ़ कामन्स में इस आशय का एक मसविदा पेश किया था कि सेना के पदों को बेंचा न जाय। इस मसविदे को हाउस ऑफ़ लार्ड्स के मज़ूर न करने पर रानी के हुक्म से मसविदा कानून बनाया गया था और सेना के पदों की बिक्री रद्द हो गई थी। यह सत्र कुछ हुआ तो राजछत्र के नाम पर था, मगर सच यह है कि रानी विक्टोरिया का इस में कुछ भी हाथ नहीं था और मंत्रि मंडल ने राजछत्र के नाम से हुक्म निकाल कर इस मसविदे को कानून बना दिया था। इसी प्रकार १६०३ ई० में मंत्रि मंडल ने अपनी मर्जा से तीन आदमियों की एक कमेटी के द्वारा सेना-संगठन की जाँच करा के युद्ध दफ्तर की ग्लिफ़ुल पुनर्घटना कर डाली थी, कमांडर इन-चीफ़ के पद तक को खत्म कर दिया था और पार्लियामेंट की राय तक नष्ट ली थी। यह भी राजछत्र के ही नाम पर किया गया था जिस से कि पार्लियामेंट मंत्रि-मंडल के इस निश्चय में कुछ दखल न दे सकी, मगर राजा बेचारे का वास्तव में इस रहस्यदल में कुछ भी हाथ नहीं था। प्रधान मंत्री ने राजछत्र के नाम पर सत्र कुछ किया था।

इंग्लैंड का राजा वैध राजा है। दो सौ वर्ष तक इंग्लैंड में इसी बात पर झगड़ा चलता रहा था कि राजा को क्या-क्या करने का अधिकार है और क्या-क्या नहीं। अंत में विवाजी सिद्धांत के अनुसार यह हल निकाला गया कि राजा की 'करने धरने की सारी सत्ता' पार्लियामेंट की एक जवाबदार समिति के हाथ में आ गई है। राजा के पास सिर्फ़ शान शौकत और प्रभाव रह गया है। राष्ट्र के शासन-संचालन अथवा राष्ट्र की नीति निश्चय करने की उस को सत्ता नहीं है। इंग्लैंड में राजनैतिक कहावत हो गई है कि 'राजा से बुरा नहीं हो सकता।' इस का केवल इतना ही अर्थ है कि राष्ट्र का कोई काम बिगड़े तो उस की जवाबदारी किसी न किसी मंत्री पर रहती है और राजा का नाम ले कर कोई मंत्री या अधिकारी अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकता है। हाँ, अगर इंग्लैंड का राजा बाजार में जा कर किसी की जेब काटे अथवा किसी का रून कर डाले तो उस की जिम्मेदारी अवश्य किसी मंत्री पर नष्ट होगी। इंग्लैंड का राज्य एक प्रकार का मंत्रिया का प्रजातन्त्र राज्य है। राजनीति

के फागडे टूटा से दूर रहने के लिए राजा ने राजगत्ता दूसरों के हाथ में दे दी है। राजा की सत्ता बचने जाने पर भी उस का प्रभाव कायम है।<sup>१</sup> एक मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने और दूसरे के आने तक दोनों के आने जाने के बीच के समय में सारे शासन का भार और सत्ता राजा के हाथ में रहती है। पार्लियमेंट में बहुसंख्यक दल के किसी नेता को प्रधान मंत्री पद के लिए चुनना है, यह भी एक हद तक राजा का ही अधिकार होता है—यद्यपि इस समय में अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए राजा के सामने बहुत बड़ा खेद नहीं होता है।<sup>२</sup> राजा को पार्लियमेंट खर्खास्त करने और नया चुनाव कर के किसी विशेष प्रश्न पर प्रजा की राय लेने के लिए प्रधान मंत्री को मजबूर कर देने का अधिकार होता है। प्रधान मंत्री के पार्लियमेंट का नया चुनाव चाहने पर भी खास हालातों में राजा को नया चुनाव कराने से इनकार कर देने का भी अधिकार होता है। प्रत्यु, शासन पर अपना प्रभाव डालने के लिए राजा के हाथ में काफी शक्ति रहती है। परंतु राजा इस शक्ति का प्रयोग कभी-कभी और खास मौकों पर और यह भी थोड़े समय के लिए ही कर सकता है। साधारण तौर पर राजा को सिर्फ तीन अधिकार होते हैं। एक तो मंत्रिमंडल को सलाह देने का, दूसरा प्रोत्साहन देने का और तीसरा हिदायत करने का। मंत्रियों की समझ में जो आये वह वे कर सकते हैं, परंतु हर आवश्यक निश्चय पर अमल करने से पहले उन्हें राजा की सलाह ले लेनी पड़ती है। राजा की राय वे मानें या न मानें, परंतु उस की बातें उन्हें ध्यान से अवश्य सुननी पड़ती हैं। अस्तु, एक बुद्धिमान राजा चाहे तो मंत्रिमंडल के निश्चयों पर काफी प्रभाव डाल सकता है, परंतु निस्संदेह राजकुल मंत्रियों के काम पर राजा का बहुत असर नहीं होता है। रिवाज हो गया है कि राजा की सलाह मंत्रियों को आदर से इन कान से सुन कर उस कान से निकाल देनी चाहिए और राजा को बुरा नहीं मानना चाहिए। मंत्रिमंडल की प्रथा की तरह वैध राजशाही का भी इंग्लैंड में ऐतिहासिक कठिनाइयों के कारण विकास हुआ है। उदार दल ने सदा लड़-लड़ कर राजछत्र की शक्ति कम करने की नीतिश की और अनुदार दल ने अक्सर राजा के अधिकारों को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। और इस संघर्ष के फल-स्वरूप धीरे-धीरे इंग्लैंड में आधुनिक वैध राजशाही की स्थापना हुई।

वैध राजशाही अपने ढंग की एक अजीब चीज़ है। यद्यपि अभी तक इंग्लैंड में इन प्रश्नों से अधिक अडचन नहीं पड़ी हैं और इस ढंग से काम मजे में चलता आया है, परंतु फिर भी यह कहना उचित न होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था सरल अथवा स्वाभाविक है।

१ कहा जाता है कि सन् १६३२ ई० की राष्ट्रीय सरकार बनाने के निरचय में बहुत कुछ राजा पंचम जार्ज का भी हाथ था।

२ सन् १६३२ में जब एक दल के प्रधान मंत्री मेकडानल्ड ने अपने दल की सरकार हारम न रख कर राजा से पार्लियमेंट भंग कर के नए चुनाव का क्रमनाम निकालने की प्रार्थना की थी, तब राजा ने उसी दल के किसी दूसरे नेता को मंत्रिमंडल बनाने का सुझाव न दे कर पार्लियमेंट भंग कर दी थी—यद्यपि राजा चाहता तो ऐसा कर सकता था।

सच तो यह है कि यह प्रबंध उदा जटिल, अस्वाभाविक और ऐसा गोरतपधा है कि साधारण आदमी की समझ में आसानी से नहीं आता। दुनिया में राजाओं का राज इतने दिनों तक रहा है कि राजाओं की निरुपश राजशाही साधारण मनुष्यों के लिए एक प्राकृति-सी बात हो गई है। परंतु वैध राजशाही साधारण प्रजा की समझ में जल्दी से नहीं आती। अगर इंग्लैंड में राजा के नाम से आज यह एलान निबले कि औरतों को गर्दन खुली नहीं रखनी चाहिए तो राजन्यवस्था के विधान या तो इसे गप्प समझेंगे या समझेंगे कि इंग्लैंड की राजन्यवस्था में अशुभ भाति हो गई है। परंतु बहुत से साधारण मनुष्यों को यह एलान बिलकुल जायज़ और साधारण लगेगा, क्योंकि प्रजा के बड़े भाग ने लिए राजा का वचन ही उन तक कानून है। भविष्य में इंग्लैंड में राजा की क्या स्थिति होगी यह भावी राजाओं के चार-चरार और राजनैतिक नेताओं के व्यवहार पर निर्भर है। आजकल राजा के राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होने पर भी वह राष्ट्र के अन्य गुरु से कामों में सहायता पहुँचाता और पहुँचा सकता है। साहित्य, कला, निगम और बहुत से अन्य सार्वजनिक उपयोगी कामों को अपने प्रोत्साहन से राजा गुरु लाभ पहुँचा सकता है। राजनैतिक दलबंदी से दूर रहने से राजा सब को पिता के समान प्रिय रहता है। अस्तु, वह देश के रचनात्मक कार्य में हाथ बढ़ा कर राष्ट्र का गुरु कुछ भला कर सकता है। राजनैतिक दलों के गुरु से कामों से इस प्रकार के सर्व हितकारी रचनात्मक कार्य, जिन में राजा सर्वप्रिय रह कर हाथ डाल सकता है, देश को कहीं अधिक लाभदायक होते हैं। समुद्रों के आर पार फैले हुए ब्रिटिश उपनिवेशों और चम्बवती ब्रिटिश साम्राज्य को भी इंग्लैंड का राजछत्र एक सूत्र में बाँधे रखने में गुरु सहायक हो सकता है। नेनेडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में उसे हुए अभिमानों गौरे लोग ब्रिटिश मंत्रि मंडल के अंगीन रहना पसंद नहीं करते हैं, परंतु इंग्लैंड के राज छत्र को अपना राज छत्र मानते हैं और उस छत्र की छाया में रहना स्वीकार करते हैं। दूसरे देशों से अच्छा संबंध रखने और इंग्लैंड के व्यापार इत्यादि को बढ़ाने में भी राज छत्र काम आता है। इंग्लैंड की महारानी के सन् १८४३ ई० और १८४५ ई० में फ्रांस जाने से इंग्लैंड और फ्रांस का पैर मिट गया था, और दोनों देश मिन रन गए थे। एडवर्ड सप्तम के गद्दी पर बैठने के समय दुनिया भर इंग्लैंड को, दक्षिण अफ्रीका में अत्याचार करने के कारण, घुरी नजर से देखती थी। राजा ने यूरोप के देशों की यात्रा की और उस के वहा जाने से सारी हवा ही बदल गई थी। फ्रांस, इंग्ली, पुर्तगाल और जर्मनी सब फिर से इंग्लैंड के मिन बन गए थे। इसी प्रकार जब सन् १९३१ ई० में इंग्लैंड का व्यापार घटने लगा था तो पचम जार्ज के युवराज ने दक्षिण अमेरिका के देशों की यात्रा कर के उन देशों में ब्रिटिश माल का प्रचार किया था और ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाया था। दूसरे देशों से सधि और व्यापार केवल परराष्ट्र-सचिव अथवा व्यापारसचिव के प्रयत्नों से ही नहीं होते हैं। एक देश की जनता के दूसरे देश पर स्नेह होने से यह कार्य अधिक सरलता से हो जाते हैं और राजा घूम फिर कर अपने व्यवहार से इस स्नेह-वर्धन के कार्य में अच्छी तरह सहायक हो सकता है।

## ३—मन्त्रिमंडल

जो काम राजा को करने का वेबल नाम मान को अधिकार है उसे करने का वास्तविक अधिकार मन्त्रिमंडल को है। इंग्लैंड की सरकार की राजव्यवस्था का केंद्र मन्त्रिमंडल है। कानून के अनुसार तो मन्त्रिमंडल सिर्फ़ प्रिंसीपैलि की एक समिति है और उस के सदस्य केवल बादशाह सलामत के नौकर हैं—निन्हें बादशाह ने विभिन्न सरकारी विभागों की गगडोर सौंप दी है और जिन से जरूरत पड़ने पर बादशाह सलामत राजकार्य में सलाह लेते हैं, परंतु राजव्यवस्था के रिवाज के अनुसार मन्त्रिमंडल ही उत्तरदायी कार्यकारिणी है और उसी पर राष्ट्र के सारे कार्यसंचालन का भार है। मगर इस महान शक्ति का प्रयोग मन्त्रिमंडल को राष्ट्र की प्रतिनिधि व्यवस्थापन सभा की देर रेल में करना होता है और उसी को अपने हर काम का जवाब देना होता है। खास खास आपत्ति के मौकों को छोड़कर—जैसे कि १९१४ ई० का युद्धकाल अथवा १९३१ ई० का आर्थिक संकट—ग्राम तौर पर मन्त्रिमंडल पार्लियामेंट की समिति नहीं होती, रल्लिक पार्लियामेंट में जो सच से जनरलस्त राजनैतिक दल होता है उसी की समिति होती है। आपत्तिमाल में सब राजनैतिक दल ग्रामसर अपना भेद भाव भूलकर, सच रला के प्रतिनिधि ले कर मन्त्रिमंडल बना लेते हैं।

बहुत से अँगरेज अपनी राजव्यवस्था के लिए अपनी जाति की कर्तव्य बुद्धि की प्रायः सराहना करते हैं और अपने गड़ेबूढ़ों की प्रशंसा के गीत गाते हैं, कि उन्होंने ऐसी सुंदर राजव्यवस्था का गीत बोया। परंतु मन्त्रिमंडल सस्था का इतिहास अभ्ययन करने से मालूम होता है कि जो रूप इस सस्था का आजकल है उस की किसी अँगरेज ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही नहीं बल्कि, मन्त्रिमंडल के इस रूप के विकास के मार्ग में अँगरेजों के गड़ेबूढ़ों ने काफी रोड़े अट्टाए थे। क्रमशः घटनाओं के चक्र से इंग्लैंड का मन्त्रिमंडल ऐसी प्रभावशाली, शक्तिमान और केंद्रस्थ संस्था बन गई है। उन के गड़ेबूढ़ों ने इस सस्था के इस स्वरूप का कभी स्वप्न भी नहीं देखा था। बिना प्रचार बिना किसी हरादे के अँगरेजों का क्रमशः समुद्रा के पार एक चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित हो गया, उसी प्रकार उन की विविध राजव्यवस्था भी धीरे धीरे घटनाओं के चक्र से बनी है। कोई जितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, सोच विचार कर इस प्रकार की राजव्यवस्था की रचना करना सर्वथा असंभव है। सच तो यह है कि सोचा कुछ गया था और हो कुछ गया। अठारहवीं सदी की पार्लियामेंट ने तो इस बात की भी बड़ी कोशिश की थी कि मंत्रियों का व्यवस्थापक सभा में कोई स्थान ही न रहे। मन्त्रिमंडल की सरकार का नाश करने के उद्देश्य से ही बहुत दिनों तक इस सिद्धांत की लकीर भी पींगी गई थी कि सरकार की व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी सत्ताएँ अलग होनी चाहिएँ। ऐक्ज्यूटिव् सेंटिलमेन्ट की मूल धाराओं में एक धारा के अनुसार बादशाह का कोई नौकर हाउस ऑफ् कामन्स का सदस्य नहीं हो सकता और एक दूसरी धारा के अनुसार मन्त्रिमंडल की कोई गुप्त बैठक प्रिंसीपैलि से अलग नहीं हो सकती। अठारहवीं शताब्दी में प्रचार मंत्री के पद के

विरोध भी काफी मत था और कहा जाता था कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को प्रधान मंत्री की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस बात पर भी हमेशा बड़ा जोर दिया जाता रहा है कि सिर्फ हाउस ऑफ् कामन्स को सब कुछ स्याहसफेद करने का हक है। मगर वास्तव में दिन-ब-दिन हाउस ऑफ् कामन्स की शक्ति कम होती जाती है और मंत्रि-मंडल की शक्ति बढ़ती जाती है। मंत्रि-मंडल के सदस्य हाउस ऑफ् कामन्स के सदस्य ही नहीं होते हैं बल्कि मंत्रि-मंडल की बैठकें सदा ही गुप्त और प्रिवी कांसिल से अलग होती हैं। इंग्लैंड का प्रख्यात प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन हमेशा इस बात पर जोर दिया करता था कि सिर्फ हाउस ऑफ् कामन्स ही तो सब कुछ अधिकार है, मगर उसी का, मंत्रि-मंडल को इतनी शक्तिशाली सस्था बनाने में भी, सब से अधिक हाथ था। मंत्रि-मंडल इंग्लैंड की व्यवस्थापन सभा की ही समिति नहीं होती, बल्कि वास्तव में पार्लियामेंट में सब से ज़बरदस्त दल के द्वारा चुनी हुई समिति भी नहीं होती है। बहुसंख्यक दल का नेता दल में से अपने साथी मंत्रियों को अपनी इच्छानुसार चुनता है।

इंग्लैंड का मंत्रि-मंडल एक दुधारी तलवार की तरह है, जिस की एक धार सुधरी होती जा रही है और दूसरी तेज़। ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टि से—परन्तु केवल कहने के लिए—मंत्रि-मंडल प्रिवी कांसिल की एक समिति और बादशाह की चाकर है, और रिवाज से—मगर वास्तव में—यह राष्ट्र की प्रजा की प्रतिनिधि होती है। अस्तु, इंग्लैंड का मंत्रि-मंडल राजा का चाकर और प्रजा का प्रतिनिधि दोनों ही है। प्रारम्भ काल में इंग्लैंड के राजा प्रजा का शासन राव, उमरावा, सरदारों और ज़मींदारों की सलाह से किया करते थे। बाद में यह दूसरे विद्वान् अथवा चतुर मनुष्यों से भी सलाह लेने लगे और धीरे-धीरे ऐसे सलाहकारों की संख्या बढ़ती गई। फिर ग़ुलत दिनों तक बादशाह और पार्लियामेंट का झगड़ा चला क्योंकि राजाओं को यह बात असह्य हो उठी कि उनके चाकर हाउस ऑफ् कामन्स के चुनिंदे हों। हाउस ऑफ् कामन्स के ग़ुलत से दक्षिणान्तर सदस्यों तक को यह बात अनुचित लगती थी कि सरकार का काम बादशाह की मर्ज़ी पर निर्भर न रह कर प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत पर निर्भर रहे। इसी लिए शुरु में कभी कभी ऐसा भी होता था कि बादशाह का विश्वासपात्र मंत्री प्रजा के प्रतिनिधियों का विश्वास पात्र न होने पर भी हाउस ऑफ् कामन्स में अल्पमत से ही सरकार का काम चलाता था। अठारहवीं सदी तक इंग्लैंड के लोग मानते थे कि सरकार का शासन चलाना राजा का काम है, प्रजा के प्रतिनिधियों का नहीं। जिस मंत्री पर राजा का विश्वास होता था उस का विरोध करना ग़ुलत से प्रजा के प्रतिनिधि पसंद नहीं करते थे। पार्लियामेंट का काम, राजा के मंत्रियों से मिल कर राजकार्य अच्छी तरह चलाने के लिए केवल चर्चा करना, समझा जाता था। सरकारी शासन चलाना राजा का ही काम माना जाता था। हाँ, तोय इतना अवश्य चाहते थे कि राजा के सलाह देनेवाले मंत्रियों के नाम सब को मालूम होने चाहिए और वे ऐसे जनप्रसिद्ध लोग होने चाहिए जिन पर जनता की श्रद्धा हो, राजा को अनजाने मनुष्यों से राजकार्य में सलाह नहीं लेनी चाहिए। अठारहवीं सदी तक जनमत के अनुसार इंग्लैंड में मंत्रि-मंडल का यही अर्थ

था, परन्तु उन्नीसवीं सदी में स्थिति बदल गई थी क्योंकि सन् १८३४ ई० में राजा चतुर्थ विनियम के सर राउट पील को प्रधान मंत्री नियुक्त करने पर हाउस ऑफ् कामन्स ने उस का विरोध किया था और पील का सरकार का काम चलाना असंभव हो गया था। फिर भी सन् १८०० ई० तक हाउस ऑफ् कामन्स ने कभी मन्त्रिमंडल को अपनाया नहीं था। 'कैबिनेट' अर्थात् मन्त्रिमंडल शब्द का कहीं सरकारी कागज या चर्चा में जिक्र तक आ जाने पर चारों तरफ से हाउस ऑफ् कामन्स में उस का विरोध होता था। सन् १८०० ई० में पहली बार हाउस ऑफ् कामन्स के कागजों में 'कैबिनेट' शब्द का प्रयोग मिलता है और इस के बाद इस संस्था का इंग्लैंड की राज-व्यवस्था में बाकायदा स्थान मान लिया जाता है। किसी दूसरे देश की राज-व्यवस्था के मुख्य अंग का जन्म इस प्रकार नहीं हुआ होगा।

मन्त्रिमंडल के सदस्यों को राजा के प्रति स्वामिभक्त रहने, अपने अंतःकरण के अनुसार उस को सच्चा सलाह देने और राजा से जिन बातों की चर्चा हो उन को सदा पेट में छिपा के रखने की शपथ अवश्य लेनी पड़ती है, परन्तु यह शपथ वे मंत्री की हैसियत से नहीं प्रिवी कैबिल के सदस्य की हैसियत से लेते हैं। मन्त्रिमंडल अभी तन बूटेन में फ्रान्सीसी दृष्टि से प्रिवी कैबिल की एक उमेदी है और चूँकि प्रिवी कैबिल के हर एक सदस्य को इस प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है, इस लिए मन्त्रिमंडल के सदस्य शपथ लेते हैं। प्रिवी कैबिल इंग्लैंड की एक भूतप्रायः सी संस्था है। उस की एक बगैरी ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का काम अवश्य करती है। परन्तु बाक़ी ब्रिटिश साम्राज्य भर के दो ढाई सौ प्रिवी कैबिल के सदस्यों से न तो किसी राज्यकार्य में सलाह ली जाती है और न उन्हें कोई राज्य का गहन भेद ही पेट में छिपाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। प्रिवी कैबिल का, दिवायती कार्य के अतिरिक्त, उस एक नाम रह गया है। जिस को सरकार लार्ड और नाइट के मध्य का खिताब देना चाहती है उस को कैबिल का सदस्य बना दिया जाता है जिस से उसे अपने नाम के आगे 'राइट आनरेबल' शब्द लिखने का अधिकार हो जाता है। हमारे देश के मगर दल के एक प्रसिद्ध नेता श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री भी इस प्रिवी कैबिल के सदस्य हैं और वे राइट आनरेबल श्रीनिवास शास्त्री कहलाते हैं परन्तु उन से न तो ब्रिटिश साम्राज्य के संचालन में इंग्लैंड के राजा कोई सलाह लेते हैं और न उन्हें किसी उम्मेद के छिपाए रखने का ही मौका आता है। फिर भी अन्य प्रिवी कैबिल के सदस्यों की तरह शपथ उन्हां ने भी ली है।

इंग्लैंड की राज-व्यवस्था में कानून के अनुसार मंत्रियों का उच्च स्थान केवल प्रिवी कैबिल के सदस्यों की हैसियत से है। अन्यथा उन का स्थान केवल अन्य सरकारी नौकरों की तरह है। कई सरकार के नौकरों में तो मंत्रियों से भी अधिक अधिकार होते हैं। उदाहरणार्थ कन्ट्रोलर जनरल इंग्लैंड का सिर्फ एक सरकारी नौकर होता है परन्तु उसे अधिकार होता है कि मन्त्रिमंडल अगर किसी गैर कानूनी मामले पर सरकारी खजाने का रुपया खर्च करना चाहे तो वह उन को एक पाई भी न लेने दे। मगर इतना अधिकार रखते हुए भी कन्ट्रोलर जनरल राजा का एक नौकर ही है और मंत्री राजा का सलाहकार है।

मन्त्रि मंडल और मन्त्रि समुदाय या मन्त्रिमंडली में बड़ा भेद है। मन्त्रि समुदाय में वे सारे सरकारी अधिकारी आ जाते हैं जिन को पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार होता है। मन्त्रि-मंडल की संख्या निश्चित नहीं होती मगर उस में आमतौर पर निम्नलिखित मंत्री होते हैं.—

१. प्रधान मंत्री
२. लार्ड चांसलर
३. लार्ड प्रेसीडेंट ऑफ़ दि कौंसिल
४. लार्ड प्रिवीमील
५. चांसलर ऑफ़ दि एक्सचेकर ( अर्थ-सचिव )
६. होम सेक्रेटरी ( गृह-सचिव )
७. सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफैयर्स ( पर राष्ट्र-सचिव )
८. सेक्रेटरी फॉर कॉलोनीज़ ( उपनिवेश सचिव )
९. सेक्रेटरी फॉर इंडिया ( भारत-सचिव )
१०. सेक्रेटरी फॉर वार ( युद्ध-सचिव )
११. पस्ट लार्ड ऑफ़ ऐडमिरैलिटी ( जलसेना-सचिव )
१२. सेक्रेटरी फॉर ऐयर ( वायु-सचिव )

इन में ज़रूरत के अनुसार पाँच छः ज़रूरी विभागों के मंत्री और भी जोड़ लिए जाते हैं जैसे कि प्रेसीडेंट ऑफ़ बोर्ड ऑफ़ ट्रेड ( व्यापार-सचिव ) प्रेसीडेंट ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ( स्थानिक शासन-सचिव ), चांसलर ऑफ़ दि डची आर्क्बिलेकास्टर और चीफ़ सेक्रेटरी फॉर आयरलैंड। मन्त्रि मंडल में प्रायः इस नियम के अनुसार मंत्री मिलाए जाते हैं कि हर एक ऐसे नियम के लिए, जिस पर कॉमन्स में जोर दिया जाता हो, मन्त्रि मंडल का एक सदस्य हाउस ऑफ़ कामन्स के सामने जिम्मेदार और हाउस को रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। मन्त्रि मंडल में प्रायः बीस पच्चीस मंत्री होते हैं और उन के सिवाय उतने ही या कभी-कभी उन से दुगुने तक अधिकारी मन्त्रि-समुदाय या मन्त्रि मंडली में होते हैं।

मन्त्रि मंडल हाउस ऑफ़ कामन्स की सरकार के हर काम के लिए ज़वाबदार होता है। जिस दिन हाउस ऑफ़ कामन्स का मन्त्रि मंडल पर से विश्वास उठ जाता है, उसी दिन मन्त्रि मंडल को इस्तीफा दे देना होता है। मन्त्रि मंडल की सारे कामों में ज़वाबदारी सम्मिलित होती है अर्थात् किसी एक मंत्री के नाम का सारा यश और अपयश सारे मन्त्रि मंडल के सिर होता है। कोई एक मंत्री कितनी ही चतुरता से अपने विभाग का संचालन करे परन्तु यदि उस का साथी कोई दूसरा मंत्री अपने विभाग में गड़बड़ करता है तो चतुर मंत्री को भी कुछ मंत्री के साथ इस्तीफा दे कर चला जाना होता है। इस का कारण शायद यह है कि

१ सन् १९३२ ई० की मेकडोनेल्ड की राष्ट्रीय सरकार के ज़माने में इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार व्यापारी चुंगी करों के प्रश्न पर मन्त्रि-मंडल के सदस्यों ने अपनी अपनी राय अलग अलग पार्लियामेंट में जाहिर की थी और अलग-अलग अपने मत दिए थे। अर्थ सचिव मिस्टर नेविल चेंबरलेन के अनुदार दल की संख्या बहुत होने से उस का मसविदा स्वीकार हुआ था और सरकार की हार हो जाने का मौका नहीं आया था।



सारे शासन कार्य की मुख्य जिम्मेदारी प्रधान मंत्री पर होती है। वही अपने साथ के मंत्रियों को चुनता है और इस लिए उन के सत्र भले-खुरे नामों का जवाबदार भी बही होता है। सारे मंत्री प्रधान मंत्री के मातहत होते हैं और इस लिए किसी मंत्री से कोई काम बिगड़ने पर जिम्मेदारी प्रधान मंत्री की ही समझी जाती है और उसे अपने सारे मंत्रियों के साथ हस्तोका दे देना पड़ता है।

अब मंत्रि मंडल आम तौर पर हाउस ऑफ़ कॉमन्स के एक दल की समिति होती है। इस समिति की कार्रवाई गुप्त होती है। दलपदी और गुप्त कार्य इंग्लैंड की मंत्रि मंडल पद्धति के मूल लक्षण हैं। मंत्रि मंडल पद्धति के इन मूल लक्षणों में परिवर्तन हो जाने पर इंग्लैंड की राज व्यवस्था में बड़ा अंतर हो जायगा। आश्चर्य की बात है कि जिस इंग्लैंड में हर काम की इतनी चर्चा अखबारों में होती है और जो देश राजनैतिक प्रश्नों पर खुली चर्चा करना प्रजासत्तात्मक राज्य का लक्षण मानता है उसी देश की मुख्य कार्य कारिणी सस्था सदा परदे में काम करती है। मंत्रि मंडल गुप्त सस्था होने पर भी व्यक्तिगत सस्था नहीं है। अन्य सस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों से इस में यह बड़े महत्त्व की भिन्नता है। अन्य सस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों की भी कभी-कभी गुप्त बैठकें होती हैं। परंतु सिर्फ कभी-कभी जरूरत पड़ने पर ही गुप्त होती हैं आमतौर पर नहीं। मंत्रि मंडल की बैठकें हमेशा गुप्त होती हैं। दुनिया की अन्य कार्यकारिणी समितियों के कार्य-संचालन के नियम होते हैं, उन की कार्रवाई और प्रस्ताव लिपि लिए जाते हैं, उन के मंत्री और प्रधान होते हैं, ब्रिटिश सरकार की कार्यकारिणी अर्थात् ब्रिटिश मंत्रि मंडल के कार्य-संचालन के न कोई निश्चित नियम होते हैं, न उस की कार्रवाई और प्रस्तावों का कहीं लेखा ही रहता है और न उस का कोई मंत्री होता है। उस की बैठकों का कोई निश्चित स्थान या ठिकाना तक नहीं होता है। ब्रिटिश मंत्रि मंडल का दुनिया की दूसरी सस्थाओं की तरह कोई आफिस, क्लर्क, कागज़, धन या मुहर कुछ भी नहीं होता है। सिवाय 'फर्स्ट लार्ड ऑफ़ दि ट्रेज़री' के द्वारा न तो मंत्रि मंडल के पास कोई खज़ाना या कागज़ भेजा जा सकता है और न मंत्रि मंडल किसी के पास कोई सदेशा भेज सकता है। किसी भी रूपनी या क़ब्र या अन्य किसी सार्वजनिक सस्था की कार्यकारिणी के इस प्रकार काम चलाने पर उस को दुनिया में बिलकुल एक हीर जिम्मेदार सस्था समझा जायगा और कोई उस पर निश्वास नहीं करेगा। मगर ब्रिटिश साम्राज्य जैसी महान सस्था की कार्यकारिणी, मंत्रि मंडल, का काम इस अजीबो गरीब ढंग से चलता है। जब प्रधान मंत्री को मंत्रि मंडल की बैठक बननी होती है तब मंत्रियों के पास इस प्रकार का एक छोटा हुआ कागज़ का टुकड़ा पहुँचता है। "—स्थान पर,—समय पर, बादशाह के चाकर मिलेंगे।" इस कागज़ के पुर्जों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। परंतु वह 'फर्स्ट लार्ड ऑफ़ दि ट्रेज़री' अर्थात् प्रधान मंत्री के पास से आता है और उस पर समय और स्थान की खाना पूरी प्रधान मंत्री की होती है। मंत्रि मंडल की बैठकों में भाग लेनेवाले भी निश्चित नहीं होते हैं। कभी राजनैतिक दल के नेताओं के साथ किसी क़ान में मंत्रि मंडल की बैठक होती है, कभी किसी सरकारी दफ्तर में शासन विभाग-पतियों के साथ होती है। मंत्रि मंडल का अग्र्यत् प्रधान मंत्री होता है, और उस को अन्य सस्थाओं या

समितियों के अध्यक्षों के साधारण अधिकारों से कहीं अधिक अधिकार होते हैं। जिस विषय पर प्रधान मंत्री चाहता है चर्चा चलाता है और जब वह चाहता है तब चर्चा बंद कर देता है। प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन तो मंत्रि मंडल की बैठकों में मंत्रियों के बैठने की जगहें तब मुक़द़र कर देता था। मंत्रि मंडल में चर्चा किसी नियमित ज्ञान्ते के अनुसार नहीं चलती है; साधारण बातचीत की तरह होती है। मंत्रि मंडल कोई लिखित कार्यक्रम या और कोई कार्यवाई का कागज़-पत्र नहीं रखता है। न तो मंत्रि मंडल में होनेवाली चर्चा का कोई लेखा रक्खा जाता है और न किसी मंत्री को मंत्रि-मंडल की किसी बात का भविष्य की याददाश्त के लिए नोट कर लेने का हक़ होता है। परंतु कहा जाता है कि ग्लेडस्टन, पील और कई अन्य प्रधान मंत्री मंत्रि मंडल में चर्चा चलाने के लिए अक्सर याददाश्त लिए लाया करते थे। मंत्रि-मंडल की प्रत्येक बैठक के सत्रों की रिपोर्टें लिए कर राजा के पास भेज देना प्रधान मंत्री का कर्तव्य होता है। इस एक सत्र के सिवाय और कहीं मंत्रि-मंडल के काम की कोई रिपोर्ट नहीं रहती है। कभी-कभी प्रधान मंत्री किसी खास विषय पर मंत्रि-मंडल के सामने अपना लिखित बयान भी पेश करते हैं। दूसरे मंत्री भी कभी-कभी किसी विशेष प्रश्न पर लिखित बयान पेश कर सकते हैं। मंत्रि मंडल की बैठकों में मंत्री कुछ नहीं लिखते हैं; परंतु अपनी याद के लिए याद या फिर अपनी डाइरियों में काफी लिए लिया करते हैं। कभी कभी मंत्रियों के आपस में झगड़े हो जाने पर, राजा की अनुमति से मंत्रि मंडल की गुप्त कार्यवाई की झलक़ याद भी आ जाती है। मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। साधारणतया मंत्रि मंडल की सारी कार्यवाई गुप्त रहती है, और अखबारों के सवाददाता सिर पटन पटक कर धक़ जाने पर भी भेद नहीं पाते हैं।

अंगरेजों के मंत्रि मंडल के कार्य-संचालन का ढंग अचूक है। दुनिया की किसी दूसरी सरकार का मंत्रि मंडल इस विचित्र ढंग से काम नहीं चलाता है। अमेरिका का मंत्रि-मंडल अमेरिका के प्रेसीडेंट की सलाहकार समिति होती है और प्रेसीडेंट की अध्यक्षता में हमेशा उस की कार्यवाई होती है। फ़्रान्स के प्रेसीडेंट और अन्य देशों के राजाओं को मंत्रि मंडल की बैठकों में आकर कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है। इंग्लैंड में राजा मंत्रि मंडल की बैठकों में नहीं जाता है। फ़्रांस में मंत्रि मंडल की कार्यवाई की रिपोर्ट का सार मंत्रि मंडल की तरफ़ से समाचार-पत्रों तक में छपने तक के लिए भेज दिया जाता है। ब्रिटिश मंत्रि मंडल सिर्फ़ एक युद्ध घोषणा पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी ऐसे ही दूसरे अत्यंत गहन विषय पर कोई कागज़ तैयार करने के अतिरिक्त आम तौर पर कोई लिखा पढ़ी नहीं करता है। इंग्लैंड की राज व्यवस्था का कोई ऐसा नियम नहीं है कि इंग्लैंड का राजा जो सारे शासन का कर्ता धर्ता माना जाता है, मंत्रि मंडल की बैठकों में न बैठे। विनियम तीसरा और रानी ऐन हमेशा मंत्रि मंडल में अध्यक्ष बनकर बैठते थे। परंतु जर्मनी के शाहजादा जॉर्ज प्रथम के इंग्लैंड का राजा बनने पर राजा को मंत्रि-मंडल के कार्य में भाग लेने में बड़ी अडचन होने लगी, क्योंकि जॉर्ज अंगरेजी बिलकुल नहीं समझता था। तब से राजा के मंत्रि मंडल में जाने की प्रथा ही उठा दी गई। अगर इंग्लैंड के राजा मंत्रि-मंडल की कार्यवाई में भाग लेते रहते तो मंत्रि मंडल और आधुनिक ब्रिटिश

सरकार का यह स्वरूप न होगा। न तो मन्त्रि मंडल में दलपदी के विचार से कोई कार्यवाई हो पाती, न मन्त्रि मंडल गुप्त सस्था बन पाती और न कार्यकारिणी और व्यवस्थापक-सभा का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो पाता। इंग्लैंड की राज व्यवस्था का आधुनिक रूप-रंग आज कुछ दूसरा ही होता।

इंग्लैंड की यह विचित्र, चलबत्ती मन्त्रि मंडल सस्था दुनिया की अन्य प्रजा सत्तात्मक व्यवस्थापकी दम की सरकारों के लिए कई कारणों से आदर्श स्वरूप बन गई है। एक तो इस दम से सारी सत्ता प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है, जिस से हर बात का आखिरी फैसला प्रजा के हाथ में रहता है, और प्रजा सत्तात्मक सिद्धांत की पूर्ति होती है। दूसरे इस दम की सरकार से राष्ट्र के शासन की गगनदोर ऐसे लोगों के हाथ में रहती है जिन का मत प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत से मिलता है। तीसरे इस दम से कार्यकारिणी की बड़ी सत्ता और स्वतन्त्रता रहती है, जिस से देश का शासन अन्ध्रा चलता है और शासन पर हमेशा प्रजा के उन प्रतिनिधियों की देख रेख रहती है जो स्वयं प्रजा की जवाबदार होते हैं। चौथे इस दम से हर सार्वजनिक कार्य पर खूब विचार और चर्चा होती है। पाँचवें मन्त्रियों को हमेशा अपने हर काम के लिए प्रजा की एक ऐसी बचदारी के सामने जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ता है जो काम गिरावटे ही उन को फौरन बर्खास्त कर सकती है। छठे इस दम से एक सच्ची जन-सत्ता उत्पन्न होती है जिस का प्रत्येक सरकारी महकमे में तूती बोलता है और जिस का कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सत्ताश्रा पर एक-सा अधिकार रहता है। सातवें इस दम से प्रजा के प्रतिनिधियों की इच्छानुसार राज व्यवस्था में सब प्रकार के सुधार अथवा परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं।

मन्त्रि-मंडल प्रणाली अथवा व्यवस्थापकी पद्धति की सरकार का यह विशेष लक्षण है कि मन्त्री व्यवस्थापक सभा के सदस्य होते हैं और मन्त्रि मंडल के प्रत्येक काम की प्रजा के प्रतिनिधि देख-रेख रखते हैं, जिस से सरकार के बिगड़ते हुए कामों को भी प्रजा के प्रतिनिधि अपनी आलोचना से सुधार और रोक सकते हैं। मन्त्रि मंडल पर प्रजा के प्रतिनिधियों का जत्र-तुर विश्वास रहता है तब तक कार्यकारिणी की अरबइ सत्ता रहती है। इंग्लैंड में प्रधान मंत्री पार्लिमेंट के बहुमत के बल पर जो काम कर सकता है वह अमेरिका में प्रेसीडेंट भी नहीं कर सकता है। मन्त्रियों के पार्लिमेंट के सदस्य होने का रिवाज बन गया है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि मन्त्रियों को पार्लिमेंट का सदस्य होना ही चाहिए। परंतु यदि इंग्लैंड के मन्त्री पार्लिमेंट के सदस्य न रहें और उन पर प्रजा के प्रतिनिधियों की देख रेख न रहे, तो अवश्य ही कुछ दिनों में वे 'राष्ट्र के चाकर' न रह कर केवल 'राजा के चाकर' हो जायेंगे। प्रजा के किसी भी योग्य प्रतिनिधि को पार्लिमेंट में अपनी योग्यता का परिचय दे कर राष्ट्र की सर्वोच्च सस्था मन्त्रि मंडल के सदस्य तक बन जाने का मौका रहता है, जिस से इंग्लैंड में हर योग्य और महत्ताकांक्षी नागरिक को देश सेवा का लालच रहता है। इंग्लैंड में अमेरिका की तरह देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों को अपनी योग्यता का परिचय देने के लिये राजनीति से मुख मोड़ कर दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ता है।

आधुनिक ब्रिटिश राज व्यवस्था के अनुसार मन्त्री पार्लिमेंट को जवाबदार माने जाते हैं

। और पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्र को। मन्त्रिमंडल केवल कानून बनाने और नीति निश्चय करने में ही नहीं लगा रहता है, उस को रोज़मर्रा के शासन की देख रेख भी रखनी होती है। मंत्रियों की योग्यता और ईमानदारी पर तथा प्रजा के प्रतिनिधियों की उन से नाम ले लेने की योग्यता पर इंग्लैंड का सुशासन निर्भर रहता है। मन्त्रिमंडल-पद्धति की सरकार में मंत्रियों के काम बिगाड़ते ही प्रजा उन के कान रसींच सकती है। मन्त्रिमंडल में पार्लियामेंट में ख्याति प्राप्त कर लेने वाले राजनेतिक नेता होते हैं, अगुगवी शासक नहीं। कुछ मंत्री अत्यंत तेजस्वी और चतुर होते तो हैं, कुछ केवल अच्छी योग्यता के चरित्रवान् मनुष्य। आम तौर पर वे किसी कार्य में दक्ष अथवा विशेषज्ञ शायद ही कभी होते हैं। सेना विभाग का मंत्री किसी वकील या व्यापारी को बना दिया जाता है, जिस को सेना अथवा युद्ध-कला का कोई खास शान नहीं होता। शिक्षा विभाग पर कभी कभी कोई ऐसे ज़र्मादार या महाजन महाशय आ धिराजते हैं जिन्हें शब्दों का उच्चारण तब ठीक ठीक करना नहीं आता। मन्त्रिमंडल के सदस्यों से सिर्फ कार्य कुशल मनुष्य की बुद्धि से शासन चलाने की आशा रखी जाती है। प्रजा की प्रतिनिधि-सभा पार्लियामेंट के सामने शासन के लिए ज़वाबदार मंत्री होते हैं और पार्लियामेंट देश की प्रजा को देश के शासन के लिए ज़वाबदार होती है। सारे शासन विभागों का काम लगभग सारा ही शासन विभाग के अधिकारी चलाते हैं। मगर किसी विभाग के छोटे से छोटे अधिकारी की गलती के लिए पार्लियामेंट के सामने ज़वाब मंत्रियों को देना होता है। इस ज़वाबदारी के सिद्धांत को आजकल की राजनेतिक भाषा में 'मन्त्रित्व की ज़वाबदारी' कहते हैं। इस पद्धति का लाभ यह है कि कोई काम बिगड़ने पर जिस मंत्री की ज़वाबदारी होती है उस को पकड़ कर सज़ा दी जा सकती है। मगर सज़ा इंग्लैंड में इतनी ही होती है कि पार्लियामेंट काम बिगाड़नेवाले मंत्री को बर्खास्त कर सकती है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह इंग्लैंड में मंत्रियों पर शासन के कामों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मगर अमेरिका की व्यवस्थापक सभा तो किसी मंत्री को उस की अवधि से पहिले निराला तब नहीं सकती है।

अन मंत्रियों की शासन की ज़वाबदारी इंग्लैंड में मन्त्रिमंडल की सम्मिलित ज़वाबदारी होती है। अर्थात् शासन के हर काम के लिए सारा मन्त्रिमंडल ज़वाबदार समझा जाता है। मन्त्रिमंडल का एक दिल और एक दिमाग माना जाता है और वे मिल कर एक आदमी की तरह राजा और पार्लियामेंट दोनों का सामना करते हैं। अठारहवीं सदी तक इस सिद्धांत पर हमेशा अमल नहीं होता था। मंत्री अक्सर शासन कार्य में सहयोग से काम नहीं करते थे। परंतु बाद में इस सिद्धांत पर सख्ती से अमल होने लगा। सन् १८८५ ई० में जॉर्ज चतुर्थ ने अमेरिका के उपनिवेशों के संघ में मंत्रियों की अलग अलग राय लेनी चाही थी, परंतु मन्त्रिमंडल ने अपने सदस्यों की अलग अलग राय भेजने से इनकार कर दिया था। सन् १८५१ ई० में पर-राष्ट्र सचिव लॉर्ड पामस्टोन के मन्त्रिमंडल की राय के विरुद्ध प्राप्त वे नियम में अपनी राय ज़ाहिर करने पर उसे मन्त्रिमंडल से इस्तीफा दे देना पड़ा था। सन् १८२५ के मन्त्रिमंडल के भारत सचिव लॉर्ड बर्नार्डेट के अखबारों में लेख लिख कर अपना मत अलग दर्शाने का भी प्रधान मंत्री बाल्डविन ने विरोध किया

था और लॉर्ड बर्कनहेड को ज़लम रग देनी पड़ी थी। कभी-कभी किसी मंत्री की व्यक्तिगत नीति और कार्य में अविश्वास का प्रस्ताव भी पार्लामेंट में पेश होता है और ऐसे मौकों पर भिन्न उस एक मंत्री से भी इस्तीफा लिया जा सकता है।<sup>१</sup> परन्तु साधारण तौर पर अगर कोई मंत्री अपनी मर्यादा न लाँधे और मंत्रिमंडल की राय से मिल कर काम चलाता रहे तो सारे मंत्रिमंडल की ढाल उस के कामों के बचाव के लिए तैयार रहती है और सारा मंत्रिदल पार्लामेंट में उस की सहायता करता है। प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने विभाग में मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करता है और सारा मंत्रिमंडल उस से उस के काम के रिषय में पूछ-ताछ कर सकता है। अस्तु, जब कभी किसी विभाग में कोई ऐसी विवादमस्त गान उठती है जिस में कठिनाई खड़ी होने की सम्भावना होती है तो उस विभाग का मंत्री उस रिषय में सारे मंत्रिमंडल की सलाह ले लेता है। फिर जो कुछ भी निश्चय होता है वह मंत्रिमंडल का सम्मिलित निश्चय होता है। अगर इंग्लैंड की राज व्यवस्था नड़ी लचीली है। इस 'मंत्रिमंडल की सम्मिलित जवाबदारी' की पुष्टानी प्रथा को भी, जैसा हम उना चुके हैं, सन् १६३२ ई० की राष्ट्रीय सरकार ने उठा कर, ज़रूरत पड़ने पर, ताक पर रग दिया था। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल प्रायम रगने का मर्या पूरा करने के लिए व्यापारी चुगी करो के प्रश्न पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को पार्लामेंट में अपने अलग अलग निचार प्रगट करने और अलग अलग मत देने की दजाज़त दे दी गई थी। यह सम्झोते हुए भी मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को समी बातों का पता नहीं रहता है। आम तौर पर मंत्रिमंडल के अंदर तीन चार मंत्रियों का एक दूसरा भीतरी दायरा रहता है, जिस से प्रधान मंत्री प्रायः हर प्रश्न पर सलाह लेता है। कहा जाता है कि मजदूर दल के प्रधान मंत्री मेन्शननेट ने जब राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया था तब एक-दो खाशियों को छोड़ कर उस ने मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों से कोई सलाह नहीं ली थी। पार्लामेंट भग करने का समाचार आ कर उस ने अचानक मंत्रियों को बुना दिया था। इंग्लैंड में प्रधान मंत्री की सचमुच बड़ी सत्ता होती है। मंत्रिमंडल के दूसरे सारे सदस्य उससे मातहत होते हैं।

### ४—व्यवस्थापक-सभा—हाउस ऑव् कामन्स

इंग्लैंड की व्यवस्थापक-सभा को पार्लामेंट कहते हैं। पार्लामेंट आयरलैंड की दुनिया भर की सारी व्यवस्थापक-सभाओं में सन से पुरानी, सन से पड़ी, और सन से शक्ति शाली धारा-सभा है। जैसा उस के बारे में कहा जाता है सचमुच वह व्यवस्थापक-सभाओं की मा है। तेरहवीं सदी के लगभग पार्लामेंट का जन्म हुआ था, चौदहवीं सदी में वह पूरी तरह पर दो सभाओं में विभाजित हुई, सत्रहवीं सदी में उस ने राष्ट्र की लगाम राजा के हाथों से ली और उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में उस पर प्रजासत्ता का अच्छी तरह से रग चढ़ा। धीरे धीरे पार्लामेंट ने अपनी सत्ता बढ़ा कर सरकार के हर विभाग पर अपनी हुकूमत जमा ली, और अब हर प्रकार से उस की सत्ता अपार और अराड मानी

१ सन् १६३२ ई० में पेवोसीनिया युद्ध के समय में परराष्ट्र-सचिव सर सेमुयल होर की नीति का विरोध होने पर उस से प्रधान मंत्री ने इस्तीफा ले लिया था।

जाती है। राजनीति का प्रसिद्ध विद्वान लार्ड ब्राइस लिखता है कि "ब्रिटिश पार्लियामेंट हर कानून को बना गौर बिगाड़ सकती है, सरकार के रूप और राजद्वय के उत्तराधिकारियों को बदल सकती है, न्याय शासन के अमल में हस्तक्षेप कर सकती है और नागरिकों के पत्र और पुराने अधिकारों को नष्ट कर सकती है। पार्लियामेंट और प्रजा में कानून कोई भेद नहीं मानता है, क्योंकि प्रजा की सारी अपार सत्ता और अधिकार पार्लियामेंट में होता है, मानों प्रजा ही पार्लियामेंट है। कानूनी सिद्धांतों के अनुसार पार्लियामेंट पुरानी जन-सभा की उत्तराधिकारी होने के कारण बृटेन की प्रजा ही है। अमलन और कानूनन, दोनों तरह से, पार्लियामेंट ही जन प्रजा और राष्ट्र की सारी सत्ता की एकमात्र और समुचित भण्डार है, और इस लिए कानून में उस को गौर जगह दार और सर्वशक्तिमान माना जाता है।" व्यवस्थापक, कानूनी, शासन और धार्मिक, सब प्रकार के प्रश्नों और प्रश्नों का विचार और फैसला करने का अखंड अधिकार पार्लियामेंट को होता है। अस्तु, इंग्लैंड की सरकार को अच्छी तरह समझाने के लिए पार्लियामेंट के रूप रंग और काम-काज को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट की दोनों सभाओं—हाउस ऑफ़ कामन्स और हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स—में हाउस ऑफ़ कामन्स प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा होने से प्रजा की सत्ता का केंद्र हो गई है। यहाँ तक कि इसी एक हाउस ऑफ़ कॉमन्स की सभा को आम भाषा में पार्लियामेंट कहा जाता है।

हाउस ऑफ़ कामन्स में आजकल करीब ७०७ सदस्य होते हैं, जिन को पाँच साल के लिए चुना जाता है। पादरियों, सरकारी नौकरों, दिवालियों, पागलों, सरकारी ठेकेदारों, सख्त अपराधों के अपराधियों, और लार्ड्स को छोड़ कर हर एक मताधिकारी नागरिक हाउस ऑफ़ कामन्स का सदस्य चुना जा सकता है। इक्कीस वर्ष के ऊपर के, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में छः महीने तक बस चुकने वाले मर्दों को मत देने का अधिकार होता है। लड़ाई के बाद सेना से निराले हुए सैनिकों के लिए छः महीने से छः घण्टा तक यह समय एक महीना कर दिया गया था। इस प्रकार एक जगह मताधिकार रखने वालों का दस पौंड की हैसियत का व्यापारी दूसरे किसी निर्वाचन क्षेत्र में होने पर उस क्षेत्र में भी उन्हें एक घूसर मत देने का अधिकार होता है। उसी प्रकार विश्वविद्यालयों में पढ कर उपाधि प्राप्त करने वालों को भी विश्वविद्यालयों के खास निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरा मत देने का अधिकार होता है। इक्कीस वर्ष की उमिर के लोगों को भी जिन को पाँच पौंड निराए के मकान या जमीन का मालिक होने से खुद या जिन के स्वाविदा को स्थानिक चुनावों में मत देने का अधिकार होता है, पार्लियामेंट के चुनाव में मत डालने का हक होता है। हाउस ऑफ़ कामन्स के सदस्यों को ४०० पौंड का वेतन या भत्ता दिया जाता है। उन को कामन्स सभा में जो चाहें सो कहने का हक होता है, और सभा के अंदर प्रगट किए गए विचारों के लिए उन पर बाहर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाउस ऑफ़ कामन्स की सभा की बैठक के जमाने में और बैठकों के चालीस दिन आगे और पीछे, तब सदस्यों को आम तौर पर किसी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हाउस ऑफ़ कॉमन्स की बैठकें टेम्स नदी के किनारे, वेस्ट मिनिस्टर के पुराने पार्लियामेंट भवन में ही अभी तक होती हैं। इस सभा

मन में हाउस ऑफ् कामन्स के सारे सदस्यों के बैठने के लिए स्थान तब नहीं है, परन्तु अपनी पुरानी चीजों के पुजारी अँगरेजों ने अभी तक इस स्थान को बढ़ाने या बदलने का प्रयत्न नहीं किया है। सभा स्थल में बैठने के लिए काफी स्थान न होने के कारण भी अक्सर हाउस ऑफ् कामन्स के अध्यक्ष को सभा में मुख्यवस्था कायम रखने के लिए नियम बनाने पड़े हैं। उदाहरणार्थ जिन सदस्यों को किसी दिन की बैठक में खास तौर पर बोलने की इच्छा होती थी वे शुरू में ही सभा में आ जाते थे और अपना टोप अपने बैठने के स्थान पर रख कर बाहर चले जाते थे। टोप रख देने से यह जगह उन की हो जाती थी और बाद में आने वाले सदस्य उस जगह पर नहीं बैठ सकते थे। आयरलैंड के प्रतिनिधि अपनी सारी जगहों पर बैठा रखने के लिए एक सदस्य के साथ अपने सारे टोप भेजने लगे और वह एक सदस्य उन सब के टोपों को बहुत सी जगहों पर रख कर उन के लिए स्थान रख लेता था। अस्तु, सभा के अध्यक्ष को यह नियम बनाना पड़ा था कि कोई सदस्य अपने इस्तेमाली टोप के बिना दूधरा टोप सभास्थल में नहीं रख सकता है। सभा की बैठकें दर्शकों के लिए खुली होती हैं, मगर पहले यह नियम था कि किसी एक सदस्य के उठ कर अध्यक्ष से यह कहते ही कि, 'मुझे अजनबी दीखते हैं,' अध्यक्ष को सभा से दर्शकों को हटा देना पड़ता था। एक बार स्वयं प्रिंस ऑफ् वेल्स हाउस ऑफ् कामन्स में माननीय दर्शक की तरह बैठे हुए थे। आयरलैंड के एक शरीर सदस्य ने उठ कर अध्यक्ष से कह दिया कि, 'मुझे अजनबी दीखते हैं।' अध्यक्ष को मजबूर हो कर प्रिंस ऑफ् वेल्स को सभा से हटा देना पड़ा। परन्तु बाद में फौरन ही इस नियम को बदल दिया गया। हाउस ऑफ् कामन्स ससार की एक बड़ी प्रख्यात और प्रतिभाशाली सभा है। हाउस ऑफ् कामन्स बृटिश जाति के जीवन का प्राण और उस की राजनीति का केंद्र है। राजा और मन्त्रि मंडल की तरफ दुनिया की आँखें इतनी नहीं रहती जितनी कि हाउस ऑफ् कामन्स की तरफ। उस की चर्चाओं की खबरें समुद्रों के पार जाती हैं और अँगरेजी न जानने वाले लोग भी उन्हें अपने वैसी अखबारों में पढ़ते हैं। हाउस ऑफ् कामन्स में जो मनुष्य प्रसिद्ध होता है उसे ससार जान जाता है। बृटिश जाति का इतिहास ही हाउस ऑफ् कामन्स का अमीर उमरावों और राजा से लड़ लड़ कर स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त करने का इतिहास है। महारानी विक्टोरिया के काल के लेखकों का कहना था कि हाउस ऑफ् कामन्स की सभा को सब कुछ करने का अधिकार है, और यही सभा इंग्लैंड पर सब प्रकार से सीधा राज्य करती है। विक्टोरिया के समय में शायद ऐसा था, परन्तु अब ऐसा कहना ठीक न होगा क्योंकि बहुत सी बातें अब हाउस ऑफ् कामन्स के हाथ में न रह कर मन्त्रि-मंडल के हाथ में चली गई हैं।

हाउस ऑफ् कामन्स की सभा का मुख्य काम कानून बनाना है। अन्य कामों की अपेक्षा यह काम ही हाउस ऑफ् कामन्स का लोगों की नज़र के सामने अधिक रहता है। परन्तु जिस प्रकार कानून के अनुसार इंग्लैंड का राजा, पार्लियामेंट की सलाह और मंजूरी से, कानूनों का बनानेवाला समझा जाता है, उसी प्रकार वेगल कानूनी बुनियाद पर ही यह कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट या हाउस ऑफ् कामन्स कानून बनाता है। वास्तव में अब कानून बनाता है मन्त्रि मंडल। हाउस ऑफ् कामन्स की यह सख्या केवल मन्त्रि मंडल के मसविदा

की हाँ में हाँ मिलाती है और अल्प सख्या उन का विरोध करती है। हर कानून और हर मसला हाउस ऑफ् कामन्स में बहु सख्या की सहायता और अल्प सख्या के विरोध से तय होता है। मन्त्रि मंडल बहुसंख्यक दल का होता है इस लिए हाउस ऑफ् कामन्स की बहु-सख्या हमेशा उस का साथ देती है। जिन दिन कामन्स में बहु-सख्या मन्त्रि मंडल का विरोध करती है उसी दिन मन्त्रि मंडल के हाथ से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और दूध की मक्खरी की तरह उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। फिर भी कानून बनाने में न इंग्लैंड के राजा अथवा पार्लिमेंट की दूसरी सभा हाउस ऑफ् लॉर्ड्स का भाग रहता है और न हाउस ऑफ् कॉमन्स के साधारण सदस्यों का ही। जिस प्रकार हाउस ऑफ् कॉमन्स में अल्प सख्या तीन आलोचना अथवा घोर विरोध करने के अतिरिक्त मन्त्रि-मंडल की ओर से पार्लिमेंट में पेश किए मसविदों का और कुछ बना बिगाड़ नहीं सकती उसी प्रकार मन्त्रि मंडल दल के सदस्य भी उन मसविदों में फेरफार नही कर सकते हैं। हाउस ऑफ् कामन्स के अध्यक्ष के दाहिनी ओर बैठनेवाले पंद्रह-बीस मंत्रियों को छोड़ कर अन्य पार्लिमेंट के सदस्यों का कानून बनाने में उतना ही हाथ होता है जितना पार्लिमेंट के बाहर रहनेवालों का। पार्लिमेंट के साधारण सदस्यों को केवल आलोचना करने, उग्र करने और सरकार का किसी खास चीज की तरफ ध्यान-दीक्षित करने का मौका रहता है, परंतु यह बातें कोई भी बाहर का आदमी श्रवणारों में लेना लिए कर अथवा व्याख्यान दे कर भी कर सकता है। पार्लिमेंट में कानून बनाने की ताकत मन्त्रि मंडल के उन सदस्यों के हाथ में रहती है जो मन्त्रि-मंडल के भीतरी दायरे में होते हैं। हाउस ऑफ् कॉमन्स में मन्त्रि-मंडल के विरोधी दल के नेता की बात बहुत ध्यान से सुनी जाती है, क्योंकि उस के पीछे देश के लार्ड मनुष्य होते हैं। मगर वह भी किसी सरकारी मसविदे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। मन्त्रिगण उस की बातें ध्यान से अवश्य सुनते हैं और अगर उस की कोई छोटी-मोटी बात या सुधार उन की पसंद आ जाता है तो उसे मान भी लेते हैं। परंतु जिस मंत्री के विभाग से मसविदे का संबंध होता है यदि वह विरोधी दल के नेता की बात मानने को तैयार न हो और विरोधी दल का नेता अपने सुधार को मजूर कराने के लिए हठ पकड़े तो दलबंदी का सवाल खड़ा हो जाता है। मन्त्रि-दल के सारे सदस्यों को मंत्रियों की तरफ से दल के लिए मत देने का सख्त आदेश हो जाता है। उस मसविदे की हार जीत मन्त्रि-मंडल के जीवन भरण का प्रश्न बन जाती है क्योंकि मन्त्रि-मंडल के किसी जरूरी प्रस्ताव की कामन्स में हार हो जाने पर मन्त्रि मंडल के इस्तीफा दे देने की इंग्लैंड में प्रथा हो गई है। अतः मन्त्रि-दल की बहु सख्या मसविदे के पक्ष में मजबूर हो कर मत देती है और अल्प सख्या उस के विरोध में। मन्त्रि पक्ष की बहु-सख्या होने के कारण स्वभावतः मन्त्रि पक्ष की जीत होती है और विरोधी दल की हार होती है। विरोधी दल का नेता इस प्रकार अपने सुधार पर जोर दे कर सिर्फ जनता का ध्यान आकृष्ट करता है, मसविदे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। कैसी विचित्र बात है कि इंग्लैंड के प्रायः सारे कानून व्यवस्था पर सभा के सदस्यों की एक काफी सख्या की इच्छा के हमेशा विपक्ष बनाए जाते हैं। व्यवस्थापक सभा के कर्तव्य आये सदस्यों का प्रायः कानून बनाने में कुछ हाथ नहीं होता है। हाँ, व्यवस्थापक-सभा के सभी सदस्यों को आलोचना और चर्चा का अधिकार होता



है, परन्तु व्यवस्थापक पद्धति की सरकार में व्यवस्थापक सभा में होने वाले व्याख्यानों का किसी प्रश्न के निश्चय पर असर नहीं पड़ता है क्या कि हर प्रश्न पर मत दलनदी के हिसाब से दिए जाते हैं। अफ़लानून की प्रक्रामदी से भरी वसूताएँ और शम्भराचार्य की चर्चा भी आजकल के दलनदी के अफ़ाडे हाउस ऑफ़ वॉमन्स में सदस्यों के मतों को ठस से मत नहीं कर सकती है। पालमिंट के सदस्यों का चुनाव ही मंत्रियों के पक्ष अथवा निपक्ष में मत देने के लिए किया जाता है। जो सदस्य जिस क्षेत्र से चुन कर आता है वह उस क्षेत्र के निर्वाचक-समूह का प्रतिनिधि माना जाता है और उस क्षेत्र में रहनेवाले उस सदस्य के दल के कार्यकर्ता उस पर हमेशा नजर रखते हैं। अगर वह जरा भी डावाँडोल होता और पालमिंट में दल के साथ मत देने में आना-सानी करता दिखाई देता है, तो फौरन ही यह कार्यकर्ता उस की खबर लेते हैं और अगले चुनाव में उस को न चुनने की धमकी देते हैं। शर्क जरूर अपने मतदारों की राय के विरुद्ध भी पालमिंट में मत दिया करता था। परन्तु ऐसे सदस्य निरले ही होते हैं। आजकल के पालमिंट के सदस्य अच्छी तरह समझते हैं कि दल के नेताओं के विरुद्ध गए तो दूसरे चुनाव के बाद पालमिंट में बैठ भी न सकेंगे। कभी कभी दल में फूट पड़ जाने पर किसी मंत्री मडल की हार भी हो जाती है, अथवा ऐसे अवसर पर मंत्री मडल स्वयं ही इस्तीफा दे देता है। उदाहरणार्थ ग्लैडस्टन सरकार सन् १८८५ ई० में और रोडपरी सरकार सन् १८८५ ई० में अपने दल के सदस्यों में मतभेद हो जाने से खत्म हो गई थी। सन् १८८६ ई० के उदार दल के मंत्री मडल ने आपस में फूट पड़ जाने पर स्वयं इस्तीफा दे दिया था। परन्तु अपवादों को छोड़ कर आम तौर पर हमेशा मंत्री मडल की पालमिंट में बहु-संख्या रहती है, और मंत्री-मडल ही बृटेन में कानून बनाने का काम करता है।

मंत्री मडल का ही कानून बनाने का काम करना इंग्लैंड की राजनैतिक प्रणाली की एक खास चीज़ है। मंत्री मडल कानूनों के मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक सभा के सामने बहस के लिए पेश करता है। व्यवस्थापक सभा में उन पर व्यक्तिगत सदस्यों के विचारों के अनुसार ग़हस नहीं होती है। सारे मसविदे मंत्रियों की तरफ से पेश होते हैं और उन पर दूसरे राजनैतिक दलों के विचारों की दृष्टि से पालमिंट में ग़हस होती है। मंत्रियों का कोई मसविदा पालमिंट में मज़ूर न होने पर मंत्री मडल को इस्तीफा दे देना पड़ता है और निर्वाचक समूह के उस भाग को धक्का पहुँचता है जिस के नेता मंत्री होते हैं। सिर्फ मंत्री मडल के ही कानून बनाने का काम करने की प्रथा से कानून धीरे धीरे और देर में भले ही बने परन्तु एक बड़ा फायदा होता है। मंत्री मडल पर ही कानूनों पर अमल करने की जिम्मेदारी होने के कारण ऐसे कानून नहीं बनते हैं जिन पर अमल में कठिनाइयाँ पड़े या जिन पर अमली दृष्टि से काफी विचार न हुआ हो। दूसरे यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में तो कानून बनाने की संस्था और कानूनों पर अमल करनेवाली संस्थाओं को मिलकुल एक-दूसरे से अलग रक्खा गया है। यूरोप के दूसरे देशों में मंत्रियों और व्यवस्थापक-सभा के साधारण सदस्यों में इतनी शोड रहती है कि बहुत-सी बार मंत्री मडल की ओर से आए हुए मसविदे व्यवस्थापक सभा में स्वीकृत नहीं होते हैं और साधारण

सदस्यों की ओर से था। हुए मसविदे मंजूर हो जाते हैं। इन योरोपीय देशों में न तो मसविदे पेश करने का अधिकार सिर्फ मंत्री मंडल ही का रहता है और न सब मसविदों पर मत ही सिर्फ दलों के निचार से दिए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि कानूनों का प्रमल में लाने की जिम्मेदारी कानून बनानेवालों पर न रहने से बहुत से ऐसे कानून बन जाते हैं जिन पर अमल में काफी रुठिनाइयाँ होती हैं।

बिना उचित नेतृत्व के हर सभा का वही हाल होता है जो बिना सेनापति के किसी सेना का होता है। यही हाल सत्रहवीं सदी के अंत और अठारहवीं सदी के प्रारंभ काल में हाउस ऑफ् कामन्स का था। न सरकारी कर्मचारी ही हाउस ऑफ् कामन्स का रास्ता दिगाते थे और न प्रतिनिधियों के चुने हुए मंत्री ही होने थे। हाउस ऑफ् कामन्स सट्टे का बाजार-सा था। जिग के जो दिल में आता था करता था, और राजनैतिक सत्ता का दुरुपयोग होता था। आखिरकार इस बीमारी का इलाज मंत्री मंडल की सरकार में मिला, जिस पद्धति को उन्नीसवीं सदी में सर्वथा मान लिया गया। अब यह बात प्रायः सर्वमान्य होगई है कि हाउस ऑफ् कामन्स की सभा का काम शासन करना नहीं है। उस का नाम केवल शासन की बागडोर ऐसे कुछ लोगों के हाथ में थमा देना है जो शासन को अच्छी तरह चला सके और फिर उन लोगों के कामों पर देख रखा रखना है। पार्लियामेंट के साधारण सदस्यों का कानूनी मसविदे पेश करने का अधिकार नाममात्र के लिए रह गया है। कोई भी सदस्य कोई मसविदा पार्लियामेंट में पेश कर सकता है। परंतु मंत्री मंडल की सहायता न होने पर उस के मसविदे का पास होना असंभव होता है। कभी भाग्य से किसी साधारण सदस्य की तरफ से पेश होनेवाला मसविदा मंजूर हो कर कानून भी बन जाय तो भी जब तक मंत्री मंडल न चाहे उस पर अमल नहीं हो सकता है। हाउस ऑफ् कामन्स में सदस्यों को धैर्य देने के प्रस्ताव बहुत दिनों तक पास होते रहे परंतु जब तक इन निचारों को मंत्री मंडल ने नहीं अपनाया तब तक उन पर कोई अमल नहीं हो सका। सन् १६०२ ई० में स्त्री के मर जाने पर साली से विवाह करने को जायज ठहराने के लिए एक मसविदा पेश हुआ था, और पार्लियामेंट में लगभग दुगने मत से वह पास भी हो गया था। मगर मंत्रियों ने इस कानून पर अमल करने के लिए सहूलियतें नहीं दीं और बहुत दिनों तक यह मसविदा मृतप्राय ही रहा। हाउस ऑफ् कामन्स के अधिकारों के संबंध में कहा जाता है कि "हाउस ऑफ् कामन्स आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के सिवाय बूटेन में और सत्र उड़ कर सकता है।" यह कहना भी गलत है क्योंकि निस्तन्देह कामन्स को संपूर्ण सत्ता होती है। मगर आमन्त्र अपनी इस सत्ता का प्रयोग सिर्फ मंत्री मंडल की सलाह और उस के नेतृत्व में ही कर सकता है, क्योंकि अब कानून बनाने तक की वास्तविक ताकत हाउस ऑफ् कामन्स के हाथों से निकल कर कार्यकारिणी के हाथों में चली गई है।

हाउस ऑफ् कामन्स की सभा के नियमों के अनुसार मंगलवार और बुधवार की सभा को छोड़ कर हमेशा पार्लियामेंट में सरकारी काम पहले लिया जाता है। मंगलवार और बुधवार के दिन साधारण सदस्यों के प्रस्तावों की सूचनाएँ पहले ली जाती हैं, और शुक्रवार

के दिन उन के मसविदों पर विचार होता है। ईस्टर के बाद से मंगलवार की शामे भी सरकार ले लेती है, और व्हिटसनटाइड के त्योहार के बाद से सिर्फ व्हिटसन के बाद के तीसरे और चौथे शुक्रवार को छोड़ कर और सारे दिन सरकार अपने काम के लिए लेने लगती है। अस्तु पार्लामेंट के साधारण सदस्यों को अपनी रचनात्मक राजनीतिज्ञता दिखाने का काफी समय तक नहीं मिलता है। जो दिन साधारण सदस्यों के लिए निश्चित होते हैं, उन पर भी उन के लिए बड़ी बढ़िसे रहती हैं। रोज रात के बारह बजेते ही पार्लामेंट की बैठक अपने आप खत्म हो जाती है। हर शुक्रवार को सप्ताह शाम के साढ़े पाँच बजे खत्म हो जाती है। साधारण सदस्य की तरफ से आई हुई कितनी ही जरूरी सूचना या मसविदे पर चर्चा चल रही हो, रात के बारह बजेते ही कोई भी मंत्री प्रस्ताव ला कर पार्लामेंट की बैठक एकदम बंद करा सकता है। परंतु सरकार को वक्त की जरूरत होने पर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। बारह बजे का नियम इस लिए बनाया गया था कि थोड़े से जिद्दी सदस्य लगी लगी बकतूताएँ म्हाड म्हाड कर पार्लामेंट को रात भर बिठाकर तंग न कर सकें। परंतु इस से साधारण सदस्यों का अधिकार और भी कम हो गया है। किसी भी साधारण सदस्य के मसविदे के थोड़े से त्रिरोधी रात के बारह बजे तक रोल कर मसविदे का गला घोंट डाल सकते हैं और वह बेचारा सदस्य उन्हें नहीं रोख सकता। अपने प्रस्ताव की तरफ सिर्फ ध्यान रींचने के अतिरिक्त और पार्लामेंट का साधारण सदस्य अब कुछ नहीं कर सकता है। ईस्टर के बाद तो इतना करना भी मुश्किल हो जाता है और व्हिटसनटाइड के बाद तो बिलकुल कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार अपनी गद्द सख्या की सहायता से पार्लामेंट में यहाँ तक तय कर लेती है कि अगुक्त तारीख तक अगुक्त काम खत्म हो जायगा। साधारण सदस्यों को आलोचना करने के अतिरिक्त और किसी काम का मौका नहीं मिल पाता। पार्लामेंट में गद्द सख्या दल के साधारण सदस्य तो मसविदों को देखने और समझने की फोशिश तक नहीं करते हैं। अपने दल के नेताओं को सारे मामलों में पूरी स्वतंत्रता दे कर वे सतोष कर लेते हैं। जिन बातों के लिए मत देने का नेताओं की ओर से उन्हें आदेश मिलता है, उन के लिए पार्लामेंट में वे अपना मत दे देते हैं।

सच तो यह है कि हाउस ऑफ़ कामन्स को अग्न व्यवस्थापक सभा कहना उचित नहीं है, क्योंकि हाउस ऑफ़ कामन्स अब कानून बनाने का काम नहीं करता है। यहाँ मंत्रि मंडल के बनाए हुए कानूनों पर सिर्फ चर्चा होती है। अस्तु, राजनैतिक विषयों पर राय ज़ाहिर करने का अखबारों और व्याख्याना की तरह हाउस ऑफ़ कामन्स को भी एक जरिया बहा जा सकता है। बहुत सी बातें जो कभी-कभी हाउस ऑफ़ कामन्स में बहुत कुछ शोर मचाने से भी नहीं हो पाती हैं, अखबारों में थोड़ा सा आदोलन करने से हो जाती हैं। हाउस ऑफ़ कामन्स के इंग्लैंड की राज व्यवस्था में से किसी प्रकार अकस्मात् निकल जाने पर अग्न यहाँ की सरकार के कामकाज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।

जिस प्रकार कानून बनाने की सत्ता अब हाउस ऑफ़ कामन्स के हाथ में नहीं है, उसी प्रकार उस को कार्यकारिणी सत्ता भी नहीं है। हाउस ऑफ़ कामन्स का मंत्रि मंडल पर दबाव रहने के उजाय अग्न उल्टा मंत्रि मंडल का हाउस पर दबाव रहता है। कहने के

लिए तो मंत्रियों को अपने प्रत्येक काम के बारे में राष्ट्र के प्रतिनिधियों को सतुष्ट करना पड़ता है, और अगर प्रतिनिधि उन के काम से सतुष्ट नहीं होते हैं तो मंत्रियों को इस्तीफा दे देना होता है, परन्तु वास्तव में आजकल का मन्त्रिमण्डल कुछ भी करे पार्लियामेंट उसे निमालती नहीं है। अपने आप ही मन्त्रिमण्डल किसी नीति के कारण भले ही इस्तीफा दे दे। मन्त्रिमण्डल को किसी काम के लिए पार्लियामेंट में दोषी ठहराना असम्भव होता है, क्योंकि मंत्रियों के समर्थनों की ही पार्लियामेंट में बहुसंख्या रहती है। हाँ, एक चीज का डर अवश्य मंत्रियों को रहता है, वह है वृत्ते या जनमत। परन्तु जनमत का भय मंत्रियों को हाउस ऑफ़ कॉमन्स न हो तो भी रहेगा। अस्तु, पार्लियामेंट की दाय की बजाय मन्त्रिमण्डल पर अब निर्वाचक-समूह की दाय रहती है। मगर निर्वाचक समूह को अपना मत प्रगट करने का मौका केवल खुनाब के समय मिलता है। उस समय भी वह सिर्फ़ सरकारी नीति की उन्हीं एक-दो विशेष बातों पर अपना मत प्रगट कर सकता है जिन पर मन्त्रिमण्डल की तरफ़ से जोर डाला जाता है। फिर भी राष्ट्र का निर्वाचक समूह मंत्रियों की नीति के बारे में अपना मत बदल सकता है। परन्तु दलपट्टी की जज़ीरा में जकड़े हुए हाउस ऑफ़ कॉमन्स को मन्त्रिमण्डल की सहाई म हाँ ही मिलानी पड़ती है।

साल भर में छह महीने पार्लियामेंट बंद रहती है। इन छह महीने में मन्त्रिमण्डल के कामों की किसी को कोई खबर नहीं होती है। केवल अखबारों से उन के कामों की थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती है। पार्लियामेंट की बैठक होने पर भी साधारण सदस्यों को मन्त्रिमण्डल के कामों पर देख रेख रखने का अधिक अवसर नहीं रहता है। एक तो वेमे ही साधारण सदस्यों को मंत्रियों की कार्रवाई का हर पहलू समझना मुश्किल होता है। तिम पर लदन में इस समय मौसम अच्छा होने के कारण दावत तबाज़ार की भरमार रहती है और बहुत से सदस्यों को पार्लियामेंट की रूपी चर्चाओं से स्वभावतः उन में अधिक मजा आता है। वे चारों तरफ़ आनन्दोत्सवों में भाग लेते फिरते हैं और उन के लिए पार्लियामेंट की बैठकों में जम कर बैठना अथवा विभिन्न विषयों पर सरकारी रिपोर्टें पढ़ना असम्भव हो जाता है। दल प्रबन्धकों<sup>१</sup> के पास उन के पते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें टेलीफोन से पत्त डालने के लिए बुला लिया जाता है। परन्तु कभी-कभी वेस्ट म्ने भी वे नहीं आते हैं। साधारण तौर पर सदस्यों को पार्लियामेंट में बैठा रखने का एक ही रास्ता मालूम होता है कि उन्हें अंदर बैठा कर बाहर से जरूरत रहने तक ताला बंद कर दिया जाय। सदस्यों के आगम के लिए और उन की हाज़िरी उठाने के लिए ही यह नियम बनाए गए थे कि बजाय लगातार बैठकों के<sup>२</sup> पार्लियामेंट की चार दिन टाई वजे दिन से साढ़े-सात रजे शाम तक

<sup>१</sup> 'पार्टी डिप्टी'।

<sup>२</sup> पहले पार्लियामेंट की लगातार दिनभर और रात में देर तक बैठकें हुआ करती थीं। बहुत से सदस्य जेबों और टोपों में नारंगियाँ और विस्कुट भर लाया करते थे और पार्लियामेंट में बैठे बैठे और कभी कभी खोलते खोलते भी नारंगियाँ खाते जाते थे। बहुत से सदस्य अपनी जगहों पर लेट भी जाते थे। एक बार तो एक सदस्य महाराज पार्लियामेंट के गुसलखाने में टब में पड़े हुए स्नान का मज़ा लूट रहे थे, कि इतने में घोट देने की घटी घन

बैठके हो और फिर खाना और आराम के लिए छुट्टी से बाद, रात के नी बने गे रात के बारह बजे तक । लेकिन इन नियमों के बन जाने पर भी अधिक लाभ नहीं हुआ है । साधारण सदस्य कितने ही मेहनती बन जायें और कितनी ही होशियारी से काम करे तो भी उन के लिए पार्लामेंट का काम सँभाल लेना पठिन है । पार्लामेंट में काम इतना अधिक रहता है और समय इतना कम रहता है कि साधारण सदस्यों पर अगर लगाम न रखी जाय और मंत्रियों के भरोसे पर अधिकतर काम न छोड़ दिया जाय तो पार्लामेंट का काम पूरा करना नामुमकिन हो जाय ।

मन से बड़ी हाउस ऑफ़ कॉमन्स की सत्ता 'थेली' की सत्ता' मानी जाती है । अर्थात् कॉमन्स को सरकारी बजट पढ़ाने, उद्घाने, स्वीकार करने, न करने का पूरा अधिकार होता है । इस सत्ता के बल पर राजा को खर्च के लिए रुपया न देने की धमकियाँ दे कर हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने राजछत्र तक का बल घटा दिया था । परन्तु ब्राजकल जिस प्रकार कानून बनाने और शासन करने में हाउस ऑफ़ कॉमन्स का हाथ नहीं रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय बजट के बनाने में भी उस का हाथ नहीं रहता है । विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ और अधिक रिया की सलाह से मन्त्रिमंडल जो आय-व्यय-प्रकृति तैयार कर के पार्लामेंट के सामने पेश करता है, उस की माँग सब सदस्यों को स्वीकार करनी पड़ती है । अगर कोई खान मॉग सदस्यों को स्वीकार न हो, तो उन्हें सारे मन्त्रिमंडल को निकाल देने के लिए तैयार रहना चाहिए । मन्त्रिमंडल दल के बहुत से सदस्यों को खास माँगें पसंद न होने पर भी वे अपने दल के नेताओं के विरुद्ध मत दे कर अपने दल की पार्लामेंट में हार और विपक्ष की जीत बनाना पसंद नहीं करते हैं । इस लिए वे चारों मतना गुडगुडाएँ और बुडबुडाएँ मत आखिरकार अपने नेताओं के पक्ष में ही देते हैं । आय-व्यय की प्रारम्भिकों को भी अधिकतर सदस्य समझते नहीं हैं, इस लिए भी बजट पर अधिक चर्चा करना उन के लिए असंभव होता है । उदाहरणार्थ सेना विभाग की माँगों को पार्लामेंट के थोड़े से सेना विशेषज्ञों और पेशान वाफता कर्नलों और कैप्टनों के और कोई सदस्य नहीं समझ पाता है । अस्तु, जब इस विभाग की माँगों पर गहस चलती है, तो इन थोड़े से सेना विभाग की बारीकियों को समझने वाले खास आदमियों को छोड़ कर दूसरे सदस्य बाहर जा कर सिगरेट पीने और गुप्पें लगाने लगते हैं और पार्लामेंट में सिर्फ थोड़े से लोग बैठे रह जाते हैं । मत देने के लिए पट्टी बजने पर वे सब बाहर से आ कर अपने दलों के हुक्म के अनुसार मत दे जाते हैं । पार्लामेंट के अंदर चर्चा कर के मन्त्रिमंडल के प्रस्तावों में कैंफार बनाना हर तरह से असंभव होता है । कोई भी प्रख्यात विशेषज्ञ विद्वान् अखबारों में एक छुली चिट्ठी लिख कर अथवा समाचार-पत्रों में आदीनन उठा कर अधिक सरलता से मन्त्रिमंडल के कामों पर असर डाल सकता है ।

प्रस्तावों द्वारा सरकार के शासन की गुरियाँ बताना भी साधारण सदस्यों को नामुमकिन होता है, क्योंकि उन के साधारण प्रस्तावों पर बहुत होना और उन का सरकार गई । सदस्य महाशय टय में से उठल कर केवल एक तौलिया लपेट कर और टोप पहनकर बार जोगों के कहनाई की परवाह न कर के थोटे दे आए ।

वे विरुद्ध पास होता पार्लिमेंट में अख्यमन होता है। परंतु कॉमन्स की प्रति दिन की बैठकों में सरकार से सदस्यों के सरकारी कामों के विषय में प्रश्नोत्तर खत्म हो जाने के बाद और पार्लिमेंट का दूसरा काम शुरू होने से पहले किसी भी सदस्य को, किसी आवश्यक विषय पर चर्चा करने के लिए, सभा या साधारण कार्य स्थगित कर देने का प्रस्ताव रखने का अधिकार होता है। सरकारी कामों की आलोचना करने के लिए सदस्य इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव के पक्ष में चालीस से अधिक सदस्यों के खड़े हो कर अपनी इच्छा प्रगट करने पर ही उस प्रस्ताव पर चर्चा चल सकती है। अगर कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव किसी पुरानी चर्चा को पुनर्जीवित करने के लिए या किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए होता है, जिस विषय पर भविष्य में चर्चा करने के लिए कोई प्रस्ताव या सुझाव होता है, तो वह प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन्स के नियमों के अनुसार नहीं लिया जा सकता है और हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष उस को लेने से इन्कार कर देता है। सरकारी पक्ष के लोग, सोच सोच कर, पहले ही से सारे सभावित विषयों पर, प्रस्ताव भेज रखते हैं जिस से कि सरकार के विरोधियों को सरकार के विरुद्ध कार्य स्थगित करने के प्रस्तावों के लाने का अभी मौका ही न मिल सके। अस्तु, सरकार के विरुद्ध आवाज उठानेवाले सदस्य के सारे मार्ग पटे पड़े रहते हैं। हाँ, एक रास्ता है और उस का सदस्य उपयोग भी खून करते हैं। प्रति दिन पार्लिमेंट की बैठक शुरू होते ही मंत्रियों से सवाल जवाब करने की पुरानी प्रथा चली आती है। सदस्यों को जो कुछ प्रश्न मंत्रियों से किसी विषय पर पूछना होता है, उस विषय पर वे प्रश्न लिख कर मंत्रियों के पास पहले से भेज देते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मंत्रियों से जवानी लेना होता है, उन प्रश्नों पर वे एक खास निशान लगा देते हैं। सभा शुरू होते ही इन प्रश्नों के छपे हुए उत्तर सदस्यों की मेजों पर रख दिए जाते हैं। जवानी उत्तर चाहनेवालों को जवानी उत्तर दे दिए जाते हैं। जरूरी विषयों पर सदस्यों को यथायक प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है। परंतु मंत्रियों को किसी प्रश्न का 'प्रजा के हित में' उत्तर न देने या साफ़ उत्तर न देने या बिल्कुल चुप रहने का भी अधिकार होता है। फिर भी सरकार को इन प्रश्नों का बहुत भय रहता है, क्योंकि कोई भी सदस्य सरकारी भेदों का पता लगाकर मौके से मौके उचित अनुचित प्रश्न पूछ कर सरकार की पोल खोल सकता है। सभा के अध्यक्ष को प्रश्न स्वीकार करने में करने का अधिकार भी होता है। उस की राय में जो प्रश्न बहुत लंबा, व्यगमय, घुरी भाषा में, मंत्रियों अथवा किसी सदस्य के चरित्र पर आक्षेप करनेवाला या केवल मंत्रियों की राय जानने के लिए होता है, उस को पूछने की वह इजाजत नहीं देता है। सदस्य सरकार से प्रश्न पूछने की सत्ता का आम तौर पर खूब प्रयोग करते हैं।

हाउस ऑफ कॉमन्स राष्ट्र के नेतृत्व का अखाड़ा होता है और देश भर की आँखें उस की तरफ़ रहती हैं। पार्लिमेंट में जो लोग नाम पैदा करते हैं, उन्हें देश के लोग अपना नेता मानते हैं। सात सौ देश भर के जुने हुए चतुर और अनुभवी प्रतिनिधियों में नाम पालेना वास्तविक योग्यता का काम होता है। वर्षों में जा कर कहीं पार्लिमेंट में किसी का सिफ़ा जम पाता है। परंतु योग्य नेताओं के हाथ में राष्ट्र की बागदोर रहने से देश का कल्याण

होता है। पहले जिस मंत्रि मंडल पर राजा का विश्वास नहीं रहता था, उस को इस्तीफा दे देना पड़ता था। बाद में मंत्रि मंडल को हाउस ऑफ् कॉमन्स का विश्वास पान रहने की चिंता रहती थी। अब मंत्रि मंडल को निर्वाचकों का ध्यान रखना पड़ता है। अतः हाउस ऑफ् कॉमन्स की तरफ़ों का निर्वाचकों पर क्या असर होगा, इस की मंत्रियों को गंभीरता से सोचना पड़ती है, और इसी लिए बहुत बार जरूरी जाता पर पार्लियामेंट में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जितना उन बातों पर जिन का अन्तर चुनाव में राजनैतिक दलों पर पड़ता है। प्रधान मंत्री को हमेशा ऐसे मोर्के में पिराया रहती है, जिस पर चुनाव करने से उस के दल की जीत और विपक्षियों की हार होने की सम्भावना हो। जब उसे कोई ऐसी बात समय पर मिला जाती है, जिस पर चुनाव में जोर देने पर देश के निर्वाचक समूह की उस के दल के पक्ष में मत देने की सम्भावना होती है, तभी वह अपने मंत्रि मंडल का इस्तीफा राजा के सामने पेश कर के नया चुनाव करवा लेता है। मंत्रि मंडल पद्धति की सरकार में सरकार की प्रजा तक हमेशा सीधी पहुँच रहती है। जब जिस बात पर चाहे, सरकार प्रजा का मत मालूम कर सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ जब तक अवधि पूरी न हो जाय तब तक प्रेसीडेंट, मंत्रि मंडल या व्यवस्थापक सभा का चुनाव नहीं हो सकता है। इंग्लैंड का प्रधान मंत्री जिस समय प्रजा के दिल से उतर जाय, उसी समय निकाला जा सकता है। अमेरिका का प्रधान अपनी अवधि पूरी होने से पहिले हर्गिज़ नहीं निकाला जा सकता। कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के प्रधान मंत्री को अपने दल के हित से जब चाहे तब चुनाव करा के देश भर को तंग करने और इस सत्ता का दुरुपयोग करने का मौका रहता है। परन्तु प्रधान मंत्री के लिए केवल दलबन्दी के विचार से अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना ब्रिटिश प्रजा के सामने कठिन है। दूसरे ऐसी अवस्था में राजा को यह भी अधिकार होता है कि वह नया चुनाव न करा के दूसरे दल के नेताओं को मंत्रि मंडल बनाने के लिए न्योता दे। परन्तु इस अधिकार का राजा प्रयोग करेगा या नहीं, यह कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसे अवसर नदा आते हैं।<sup>१</sup> प्रधान मंत्री के हाथ में यह सत्ता अपने दल में सुव्यवस्था रखने के लिए अकुश के समान होती है। जब मंत्रि मंडल दल के लोग मंत्रियों के कामों में अड़चन डालने लगते हैं अथवा दल की व्यवस्था बिगाड़ने लगते हैं, तब प्रधान मंत्री उन को पार्लियामेंट भग कर देने और नया चुनाव करने की धमकी दे सकता है, जिस से सदस्य दब कर डीर उताव करने लगते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सदस्य बनने में काफी मेहनत और खर्च का खर्च होता है। हाउस ऑफ् कॉमन्स का ब्रिटिश राजनीति में इतने महत्व का स्थान है और उस की इतनी सत्ता मानी गई है कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, पार्लियामेंट की इस एक सभा ही को आम भाषा में पार्लियामेंट कहा जाता है।

१ मन् १९३३ ई० में राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए मेकडोनेल्ड के राजा से नया चुनाव कराने की प्रार्थना करने पर ऐसा अवसर आया था। राजा ने दूसरे दल के नेताओं को मंत्रि-मंडल रखने का न्योता दे कर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया था और प्रधान मंत्री की प्रार्थना सज़ूर कर के पार्लियामेंट भग कर दी थी।

## ५—व्यवस्थापक-सभा—हाउस ऑफ़ लार्ड्स

पार्लियामेंट की दूसरी सभा हाउस ऑफ़ लार्ड्स एक मिश्रित संस्था है। कम से कम छह श्रेणी के मनुष्यों को हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बैठने का अधिकार होता है। एक तो शाही खानदान के शाहजादे लार्ड्स के सदस्य होते हैं और उन का दर्जा पीयर्स के ऊपर होता है। परन्तु ये कभी हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बैठने के लिए जाते नहीं हैं और हाउस ऑफ़ लार्ड्स की कार्रवाई में उन का कोई हिस्सा नहीं होता है। दूसरी श्रेणी उन लोगों की होती है जिन की हाउस ऑफ़ लार्ड्स में मौलसी जगह होती है। यह लोग पीयर्स कहलाते हैं और इन के तीन भाग होते हैं। एक भाग इंग्लैंड के पीयर्स का दूसरा भाग ग्रेट ब्रिटेन के पीयर्स का और तीसरा भाग यूनाइटेड किंगडम के पीयर्स का। पीयर्स बनाने का अधिकार राजा को माना गया है। परन्तु वास्तव में मन्त्रि मंडल और खास कर प्रधान मंत्री के इशारे पर साहित्य, कानून, कला, विज्ञान, राजनीति और व्यापार में ख्याति प्राप्त करने-वाले लोगों को मान देने के लिए अथवा हाउस ऑफ़ लार्ड्स का राजनैतिक रंग बदलने के लिए, पीयर्स बनाए जाते हैं। सन् १८८४ ई० में साहित्य में नाम पैदा करने के लिए रॉबिन्सन का पीयर बनाया गया था। इसी प्रकार लार्ड लिटन कला, लार्ड केल्विन और लिस्टर विज्ञान, लार्ड गोशेन व्यापार, जेनरल रोगर्ट्स, बुल्गले और बिचनर युद्ध-कला में प्रवीणता दिखाने के लिए पीयर्स बनाए गए थे। लार्ड मेकाले और लिटन को कुछ राजनैतिक कारणों से पीयर बनाया गया था। हमारे देश के अत्यंत सफल और प्रसिद्ध वफ़ील लार्ड सरयेंद्रप्रसन्न सिन्हा को, भारतवासियों को खुश करने और शायद यह निवास दिखाने के लिए कि महारानी विक्टोरिया के एलान के अनुसार ब्रिटिश सरकार गोरे काले का भेद नहीं मानती है, रायपुर का पीयर बनाया गया था, जिस से लार्ड सिन्हा को हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बैठने का हक हो गया था। राजा अर्थात् ब्रिटिश मन्त्रि मंडल को अवश्य पीयर्स बनाने का अधिकार है और प्रधान मंत्री इस अधिकार का काफी प्रयोग करता है। थोड़े से अपवादों को छोड़ कर पीयर्स की हाउस ऑफ़ लार्ड्स में मौलसी जगह होती है। थाप के मर जाने पर वारिस बेटा २१ वर्ष की उम्र होते ही हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बैठने का अधिकारी हो जाता है। पीयर्स की पाँच उपश्रेणियाँ होती हैं—ड्यूक, मार्कुइस, अर्ल, वाइकाउंट और बैरन। इन के आपस में छोटे बड़े दर्जें हैं जिन का राजनैतिक बातों से अधिक सम्बन्ध नहीं है। जिस पीयर का दिवाला पिट जाता है या जिस को किसी सख्त अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है, उस को फिर हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बैठने का अधिकार नहीं रहता है। पीयर का स्वतंत्र और हाउस ऑफ़ लार्ड्स में मौलसी जगह हो जाने पर किसी को उस से पीछा छुड़ा लेने का अधिकार नहीं होता। कई बार मौलसी पीयर बनने वालों में से कुछ ने इस बात का प्रयत्न भी किया कि वे हाउस ऑफ़ लार्ड्स में न बैठ कर हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सदस्य बनें, परन्तु उन के सब प्रयत्न असफल रहे क्योंकि कानून के अनुसार उन्हें हाउस ऑफ़ लार्ड्स में ही बैठना चाहिए। कियों को हाउस ऑफ़ लार्ड्स का सदस्य होने का अधिकार देने का कई बार



प्रयत्न किया गया, परन्तु अभी तक उस में सफलता नहीं हुई है।

हाउस ऑफ़ लार्ड्स के तीसरी श्रेणी में पीयर्स के स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर्स होते हैं। प्रत्येक नई पार्लामेंट में बैठने के लिए स्कॉटलैंड के चारों पीयर्स मिल कर अपने सोलह प्रतिनिधि चुन लेते हैं जिन को उस पार्लामेंट की जिदगी तक हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बैठने का अधिकार रहता है। चौथी श्रेणी में इसी तरह आयरलैंड के पीयर्सों के चुने हुए २८ प्रतिनिधि होते थे, जिन को अपने जीवन पर्यंत हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बैठने का अधिकार होता था। आयरलैंड के जो पीयर्स हाउस ऑफ़ लार्ड्स के लिए चुने नहीं जाते थे, उन को आयरलैंड के अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन के और किसी भी भाग से हाउस ऑफ़ कॉमन्स में चुने जाने का अधिकार होता था। परन्तु जबसे आयरलैंड की सरकार अलग हो गई है तब से स्थिति बदल गई है। लॉर्ड्स की पाँचवीं श्रेणी में वे फ़ानूनी पंडित होते हैं जिन का खास तौर पर न्यायाधीश का कार्य करने के लिए हाउस ऑफ़ लार्ड्स का सदस्य बनाया जाता है। हाउस ऑफ़ लार्ड्स या एक काम ब्रिटिश साम्राज्य भर की अदालतों की अपीलें सुनना भी होता है और इस लिए यह आवश्यक होता है कि लार्ड्स के सदस्यों में फ़ानूनी के विशेषज्ञ भी कुछ रहे। इन फ़ानूनी सदस्यों की जगह हाउस ऑफ़ लार्ड्स में मौरूसी नहीं होती। जिदगी भर तक ही लार्ड्स का सदस्य रहने का उन्हें अधिकार होता है। लॉर्ड चारलर की अध्यक्षता में इन सदस्यों की कचहरी ब्रिटिश साम्राज्य की सब से बड़ी अपील की अदालत मानी जाती है। भारतवर्ष से हाई कोर्ट के पैसलों के वाद अपीलें इसी अदालत के सामने जाती हैं। अदालत का कार्य चलाने के लिए सिर्फ़ तीन फ़ानूनी सदस्यों की सख्या काफी होती है। वैसे तो हाउस ऑफ़ लार्ड्स के चारों सदस्यों को, खास कर फ़ानूनी में दखल रखनेवालों को, इस अदालत के काम में भाग लेने का अधिकार होता है, परन्तु आम तौर पर सिर्फ़ फ़ानूनी सदस्य ही न्याय का काम करते हैं, अन्य सदस्य उस में दखल नहीं देते।

छठी श्रेणी हाउस ऑफ़ लार्ड्स में पादरिया की है। किसी जमाने में हाउस ऑफ़ लार्ड्स में इन्हीं लोगों की सख्या सब से अधिक होती थी। परन्तु अब फ़ानूनी के अनुसार धार्मिक सस्थाओं के सिर्फ़ २६ प्रतिनिधि हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बैठ सकते हैं। कॅटररी और यॉर्क के आर्चबिशपों और लंडन, डरहम और विंसेस्टर के बिशपों को फ़ानूनी लार्ड्स में बैठने या अधिकार प्राप्त है। शेष २१ धार्मिक प्रतिनिधि उन के सिवा तमय के अनुसार प्रधान मंत्री की इच्छा से चुने जाते हैं। हाउस ऑफ़ लार्ड्स में आजकल ६७१ के लगभग सदस्यों का औसत रहता है। सातवें हैनरी के समय में लॉर्ड्स में सिर्फ़ ८० सदस्य थे, उन में भी अधिकांश पादरी ही थे। परन्तु पिछले डेढ़ सौ वर्ष में यह सख्या ८० से बढ़ कर ६७५ के करीब हो गई है। केवल सन् १८३० ई० और १८६८ ई० के बीच के समय में ही ३६४ नए लार्ड्स बना डाले गए। चालीस वर्ष के अपने शासन में उदार दल ने २२९ नए लार्ड्स बनाए और अनुदार दल ने २७ वर्ष में १४२। आजकल के लॉर्ड्स में से करीब आधे से अधिक पिछले ६० वर्षों में इस पद को प्राप्त हुए हैं। इतने बड़े हाउस ऑफ़ लार्ड्स का कोरम सिर्फ़ तीन होता है। मगर लार्ड्स में ३० सदस्य मौजूद न होने पर किसी बात का निश्चय नहीं किया जाता है। आम तौर पर लार्ड्स की गताह में

चार बैठकें होती हैं, परन्तु अधिन वाम न रहने से बहुत शीघ्र ही, प्रायः एक घंटे में, खत्म हो जाती हैं। हाउस ऑफ़ लार्ड्स का अध्यक्ष लार्ड चांसलर होता है जिस की प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राजा नियुक्त करता है। परन्तु लार्ड चांसलर हाउस ऑफ़ कामन्स के प्रमुख 'स्पीकर' की तरह हाउस ऑफ़ लार्ड्स की वार्डवाइ की बहुत नियमित नहीं करता। बोलने वाला सदस्य उस को सपोन न कर के 'माई लार्ड्स' बर के सब सदस्यों को संबोधित करता है और अगर दो या अधिक सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो हाउस ऑफ़ लार्ड्स की सभा ही इस बात का फैसला करती है कि कौन पहले बोले।

सौ वर्ष से हाउस ऑफ़ लार्ड्स को सुधारने या सर्वनाश कर डालने के लिए आंदोलन चला रहा है। परन्तु थोड़े से भावुर दल के लोगों को छोड़ कर और कोई हाउस ऑफ़ लार्ड्स का सर्वनाश कर डालने के लिए तैयार नहीं है। लार्ड्स के विरोधियों का कहना है कि लार्ड्स के सदस्य अधिकतर दक्षिणायनी विचारों के मौलसी जमींदार और महाजन होते हैं, जो प्रगतिशील विचारों और परिवर्तनों से डरते हैं, और इस लिए देश की उन्नति के मार्ग में रुकावट आते हैं। लार्ड्स का वेटा, बुद्धि हो या बुद्धिमान, केवल मौलसी एक से हाउस ऑफ़ लार्ड्स का सदस्य बन कर राष्ट्र का भाग्य उतारने बिगाड़ने या अभिभारी हो जाता है। अधिकतर सदस्य हाउस ऑफ़ लार्ड्स के काम में शौर तक नहीं देखाते हैं। सभाओं में बहुत कम आते हैं और आते भी हैं, तो गहन विषयों तक का जल्दी-जल्दी निश्चय कर के चले जाते हैं। लोग लार्ड्स का विरोध इस लिए भी करते हैं कि लार्ड्स की सभा प्रजा के हितों की प्रतिनिधि नहीं है। मगर १९ वीं सदी के सुधारों से पहले हाउस ऑफ़ कामन्स में भी लार्ड्स की तरह जमींदारों और शर्मोरों की ही अधिक संख्या होती थी। सन् १८६७ और १८८४ ई० के सुधारों के बाद सर्व-साधारण को मतधिकार मिल जाने से हाउस ऑफ़ कामन्स प्रजा का प्रतिनिधि बना और मंत्रिमंडल पद्धति की सरकार के विकास के बाद से शासन पर प्रजा का अक्रूर हुआ। मगर हाउस ऑफ़ लार्ड्स लगभग जैसा का वैसा ही रहा है। सन् १८३२ ई० से हाउस ऑफ़ लार्ड्स को सुधारने का प्रश्न जोरों से उठा और सन् १९०६ ई० तक हाउस ऑफ़ कामन्स और लार्ड्स में सुधार के कई प्रयत्न किए गए। मगर लार्ड्स में सुधार के सब प्रयत्न निष्फल रहे। सन् १८८६ ई० तक हाउस ऑफ़ लार्ड्स में उदार और अनुदार, दोनों दलों के सदस्य काफी संख्या में होते थे। अनुदार दल ने सदस्या की संख्या अधिक होती थी, परन्तु उदार दल ने सदस्या की संख्या भी उन से कुछ ही कम रहती थी। जोर मार कर आकर उदार दलवाने बहुत सी अपनी जातें लार्ड्स में पास करा ले जाते थे। परन्तु सन् १८८६ ई० में म्लैडस्टन के पहले आयरिश होमरूल बिल पर उदार दल में फूट पड़ जाने से उदार दल कमजोर हो गया। जोसेफ चेंबरलेन के नेतृत्व में उदार दल के बहुत से लोगों ने 'लिबरल यूनिफिल्ट' नाम का एक नया दल बना लिया, जो बाद में धीरे धीरे अनुदार दल में जा मिला। इस घटना के बाद से हाउस ऑफ़ लार्ड्स में अनुदार दल का जोर हो गया और तब से आज तक लार्ड्स में उसी दल का नती बोलता है। उदार दल के हाउस ऑफ़ लार्ड्स में बहुत थोड़े सदस्य रह गए। सन् १९०५ ई० में हाउस

ऑव् लार्ड्स के ६०० सदस्यों में सिर्फ ४१ सदस्य उदार दल के थे और सन् १९१० में ६१८ सदस्यों में सिर्फ ७१ सदस्य उदार दल के थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि सन् १८३० ई० से १९१० ई० तक उदार दल ने अपने दो सौ नरणीयम उनाए। मगर देखने में आया है कि हाउस ऑव् लार्ड्स की गजल की मोठरी में जो सदस्य जाता है वह कुछ दिनों में, वह नहीं तो उस का चेरा, दक्खिनायूस भिचारो का हो कर अनुसर दल में मिल जाता है। अस्तु, हमेशा ही हाउस ऑव् लार्ड्स अनुसर दल का सहायक और दूसरे प्रगतिशील दलों का विरोधी रहता है।

सन् १९०६ ई० में हाउस ऑव् लार्ड्स और कॉमन्स में जोर का झगडा ठन गया था। सन् १९०७ ई० से यह बात आम तौर पर मान ली गई थी कि स्पष्ट पैसे के सन्ध रानने वाले सारे मसविदे हाउस ऑव् कॉमन्स में पेश होने चाहिए और कॉमन्स में मंजूर हो जाने पर लार्ड्स को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। परन्तु लार्ड्स ने राजापदा इन भिन्नता को कभी स्वीकार नहीं किया था। अतः में कॉमन्स ने हाउस ऑव् लार्ड्स के आर्थिक मसविदों को और अपने आर्थिक मसविदा पर लार्ड्स के सुधारों को नामजूर कर के अपने स्पष्ट पैसे सन्धी अधिकार लार्ड्स से स्वीकार कर लिए। उदाहरणार्थ सन् १८६० ई० में कॉमन्स ने कागज पर से कर उठाने का एक मसविदा पास किया और लार्ड्स ने इन मसविदों को अस्वीकार किया। इस पर कॉमन्स ने देश में इतना शोर मचाया कि दूसरे वर्ष ही कागज वा कर उठा लिया गया। हमेशा से राष्ट्रीय आय-व्यय पर प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा हाउस ऑव् कॉमन्स का अधिकार रखना ब्रिटिश प्रजा की पसन्द रहा है, क्योंकि 'धैर्य की सत्ता' हाथ में रख कर ही प्रतिनिधि सभा सरकार पर अपनी हुकूमत तायम रखती है। सन् १९०८ ई० में उदार दल के अर्थ सचिव लायड जॉर्ज के बजट को हाउस ऑव् लार्ड्स ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर देश भर में बडा तहलका मच गया और हाउस ऑव् लार्ड्स और हाउस ऑव् कॉमन्स वा द्वन्द्व युद्ध छिड़ गया। अतः में हाउस ऑव् कॉमन्स में एक प्रस्ताव पास हुआ कि "हाउस ऑव् कॉमन्स के मंजूर किए हुए सालाना आय व्यय पत्र को हाउस ऑव् लार्ड्स ने स्वीकार न कर के देश की राज व्यवस्था को भंग किया है और हाउस ऑव् कॉमन्स के अधिकारों को कुचला है।" साथ ही उदार दल के मंत्री मडल ने यह भी निश्चय किया कि, "इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रजा की राय देने की जरूरत है।" अस्तु, पार्लियामेंट भंग कर के सन् १९१० ई० में नया चुनाव किया गया जिस में फिर से उदार दल के लोग ही अधिक संख्या में चुन कर आए। नई पार्लियामेंट चुलने पर राज छन की ओर से होनेवाली वक्तृता में कहा गया कि "शीघ्र ही हाउस ऑव् लार्ड्स और हाउस ऑव् कॉमन्स के परस्पर संघर्ष की ऐसी माफ-साफ व्याख्या कर दी जायगी कि जिस से हाउस ऑव् कॉमन्स का राष्ट्रीय आय व्यय पर पूर्ण अधिकार और कानून बनाने में भी हाउस ऑव् लार्ड्स से अधिक अधिकार स्पष्ट हो जायगा।"

नई पार्लियामेंट चुलने पर राजा मन्त्रि मडल की तरफ से तैयार की हुई एक वक्तृता पढ़ता है जिसमें मन्त्रि-मडल की भावी नीति का वर्णन रहता है।

की प्रधानता और प्राबल्य का सिद्धा जमाया, कानून बनाने में तार्न्स का आज भी काफी हाथ रहता है। हाउस ऑफ् कॉमन्स में पास हो जानेवाले मसविदों को हाउस ऑफ् लार्ड्स बिलकुल अस्वीकार करने का अधिकार न रखने पर भी दो वर्ष तक उन को लटकाए रखने का अधिकार तो अभी तक रखता ही है। अस्तु, कोई वास्तविकी मसविदा हाउस ऑफ् कॉमन्स बिना हाउस ऑफ् लार्ड्स की मर्जी के जल्दी से पास नहीं कर सकता है। गौर जरूरी मसविदा को दो वर्ष तक लटका कर हाउस ऑफ् लार्ड्स आसानी से खत्म कर सकता है। परंतु जो मसविदे इतने जरूरी होते हैं कि दो वर्ष तक लटके रहने पर भी प्रजा की आँखों में चढ़े रहते हैं और सब प्रकार की समालोचनाओं की कसौटी पर चढ़ कर भी चमकते हुए निवल आते हैं उन को रोक लेना अब जरूर हाउस ऑफ् लार्ड्स की सामर्थ्य में नहीं रहा है। 'प्लूरल वोटींग बिल' इत्यादि कई आवश्यक मसविदे दो वर्ष तक लटके रहने के बाद भी पार्लीमेंट से पास हुए हैं। कानून बनाने में यह प्रधानता और प्राबल्य हाउस ऑफ् कॉमन्स को प्राप्त हो जाने के बाद से लगभग कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता हाउस ऑफ् कॉमन्स के हाथ में आ गई है। हाउस ऑफ् लार्ड्स अब अधिक से अधिक कानून बनाने में जल्दबाजी रोक सकता है, कानून बनाना नहीं रोक सकता है। अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं है कि साधारण मसविदे हाउस ऑफ् लार्ड्स में पहिले पेश न होकर कॉमन्स में पहिले पेश हो। मगर रियाज के अनुसार सारे मसविदे कॉमन्स में ही शुरू होते हैं। पार्लीमेंट ऐक्ट पास हो जाने के बाद भी हाउस ऑफ् लार्ड्स के सुधार की चर्चा अब तक चलती है। बहुत से लोगों का कहना है कि हाउस ऑफ् लार्ड्स में मौजूदा पीयर्स को बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए—कुछ पीयर्स प्रजा के द्वारा चुन कर आना चाहिए, कुछ कामन्स के सदस्यों द्वारा चुने जाने चाहिए और कुछ देश भर के विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने चाहिए जिन को विज्ञान, कला, साहित्य और व्यापारी सभा समाजों से चुन कर आना चाहिए। इस पर कुछ राजनीतिशों का कहना है कि यदि हाउस ऑफ् लार्ड्स भी हाउस ऑफ् कॉमन्स की तरह देश के हितों का प्रतिनिधि बन गया तो वह हाउस ऑफ् कॉमन्स से कम हैसियत का रहना क्यों पसंद करेगा? हमारी समझ में यह डर किजूल है, क्योंकि प्रथम तो हाउस ऑफ् कॉमन्स कोई ऐसा कानून ही पास होने नहीं देगा जिस से उस की ताकत कम हो जाय। दूसरे जब तक जवाबदार मन्त्रि मंडल पद्धति की सरकार इंग्लैंड में कायम रहेगी, तब तक व्यवस्थापक सभा की प्रतिनिधि सभा ही सर्व शक्तिमान रहेगी। एक प्रख्यात यंगरेज लेखक लिखता है कि “जब तक हाउस ऑफ् कॉमन्स के पीछे देश का निर्वाचन-समूह रहेगा, तब तक लार्ड्स उस की लगाम नहीं धाम सकते। सुधारों को रोकना तो दूर रहा, अगर निर्वाचन समूह क्रांति करने पर तुल जाय और उस का साथ देने के लिए मन्त्रि मंडल तैयार हो जाय, तो हाउस ऑफ् लार्ड्स इंग्लैंड में क्रांति होना तक नहीं रोक सकता है।”

## ६—स्थानिक शासन और न्याय-शासन

बृटेन के स्थानिक शासन में भी अब वह पुरानी अव्यवस्था और पेचीदापन नहीं रहा है। शासन-क्षेत्रों की विभिन्नता कम हो गई है। अधिकारियों की संख्या भी कम कर दी गई है और उन के एक-दूसरे से संबंध साफ और सीधे हो गए हैं। केंद्रीय अधिकारियों का साथ भी स्थानिक शासन की रहनरी के लिए मजबूत कर दिया गया है। सारे देश को शासन प्रबंध के लिए 'काउंटीज़' और 'राउंटी गेरोज' में बांट दिया गया है। काउंटीज़ को देहली जिलों, शहरी जिलों और बौरोज में बांट दिया गया है और इन भागों को और भी छोटे भागों—'पेरिश'—में विभाजित किया गया है। गरीबों की मदद के लिए बनाए गए 'गरीब कानूनों' का शासन चलाने के लिए इन पेरिशों को अलग सचेतना दी जाती है। राजधानी लंदन शहर का शासन एक खास ढंग पर चलता है।

यूरोप के दूसरे देशों की अपेक्षा बृटेन में हमेशा से केंद्रीय सरकार ने स्थानिक शासन में कम हस्तक्षेप किया है। जैसा आगे चल कर हम फ्रांस के स्थानिक शासन में केंद्रीय सरकार के अधिकारी प्रीफेक्ट को स्थानिक शासन का कर्ता धर्ता अधिकारी पाएँगे वैसा इंग्लैंड के स्थानिक शासन में हमें कोई केंद्रीय सरकार का अधिकारी नहीं मिलता है। स्थानिक शासन केंद्रीय सरकार के समूह का निरा एक अंग न बन जाने पर भी पिछले साठ सत्तर वर्षों से गरीबों की मदद, शिक्षा, आर्थिक प्रबंध, स्वास्थ्य इत्यादि स्थानिक शासन के विभिन्न विभागों पर केंद्रीय सरकार का काफी नियंत्रण रहने लगा है। केंद्रीय सरकार के पाँच विभागों का थोड़ा-बहुत इन विषयों में स्थानिक शासन में नियंत्रण रहता है। केंद्रीय सरकार का यह विभाग स्थानिक पुलिस और कारखानों की देख-रेख करता है। 'शिक्षा बोर्ड' विभाग सारे सार्वजनिक धन से चलनेवाले विद्यालयों की देख-रेख और संचालन करता है। केंद्रीय सरकार का तीसरा 'फ़िरोर्ड' विभाग स्थानिक बाजारों और मवेशियों की नीमारी के कानूनों और नियमों का पालन करता है। चौथा 'व्यापार बोर्ड' विभाग पानी, गैस, बिजली और नुगियों के दूसरे व्यापारी कामों की जाँच और संचालन करता है। पाँचवाँ 'स्थायी-सचिव' का विभाग आजकल खास तौर पर स्थानिक स्वास्थ्य और ग्राम तौर पर सारे स्थानिक शासन के मामलों की देख-भाल रखता है। केंद्रीय सरकार के यह विभाग अपने हुकों और नियमों के द्वारा स्थानिक संस्थाओं के कामों को स्वीकार और अस्वीकार कर के तथा उनको अपनी होशियार सलाह दे कर स्थानिक शासन में अपना नियंत्रण रखते हैं। पार्लियामेंट को भी कानून बना कर स्थानिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता ही है।

स्थानिक शासन का काम-काज काउंटी में काउंटी काउंसिल चलाती है। बृटेन में छोटी-बड़ी कुल मिला कर करीब ६२ काउंटियाँ हैं जिन में छोटी से छोटी स्टर्लैंड काउंटी की आबादी करीब १६७०६ होगी और बड़ी से बड़ी लक्साशायर काउंटी की १८२७४३६ आबादी है। काउंटी काउंसिल में प्रजा के तीन साल के लिए चुने हुए सदस्य और इन चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा छ साल के लिए चुने हुए पेल्लरमैन

होते हैं। ऐल्डरमैनों की सदस्यों से एक तिहाई सदस्य होती है और हर तीसरे साल उन के आधे भाग का चुनाव होता है। काउंटी काउंसिल के इन दोनों प्रकार के सदस्यों को एक ही से अधिकार और सत्ता होती है। काउंसिल के चुनावों में दलदली का खयाल न रखता जा कर प्रायः सभी दलों के सदस्य ले लिए जाते हैं। आम तौर पर काउंटी काउंसिल के सदस्यों की संख्या ७५ होती है। काउंसिलों की बैठकें आम तौर पर साल में चार बार से अधिक नहीं होती हैं। अधिकतर शासन का काम-काज काउंसिल की स्थायी समितियाँ और अधिकारी चलाते हैं। काउंटी काउंसिल को स्थानिक शासन के लिए फर उगाने, करों की आमदनी खर्च करने और कर्ज लेने का अधिकार होता है। काउंटी काउंसिल काउंटी की सार्वजनिक मिलकियत, इमारतों, पुलों, पागलखानों, रिफॉर्मेटोरियों और उद्योगी स्कूलों की सँभाल और प्रबंध रखने, छोटे अधिकारियों को नियुक्त करने, कुछ व्यापारी लाइसेंस देने, सड़कों और रास्तों को ठीक रखने, जलाशयों को स्वच्छ रखने, और मवेशियों, मछलियों, चिड़ियों और कीटों से संरक्ष रखनेवाले तमाम नियमों का पालन करने का काम करती है। माध्यमिक स्कूलों को स्थापन करने तथा उच्च शिक्षा की योजना करनेवालों को सहायता देने का काम करने के अतिरिक्त काउंटी काउंसिल की एक समिति 'जस्टिस ऑफ़ दि पीस' के प्रतिनिधियों से मिल कर स्थानिक पुलिस का प्रबंध भी करती है। काउंसिल काउंटी का शासन चलाने के लिए उपनियम बनाती है और देशतः ये छोटे अधिकारियों की देख रेख भी रखती है।

काउंटी के अंदर के दूसरे शासन-क्षेत्रों, देहाती जिलों, देहाती पैरिशों, शहरी जिलों और म्यूनिसिपल बोरोज़ की भी, इसी प्रकार शासन चलाने के लिए, काउंसिलें होती हैं। जिलों की काउंसिल को तीन साल के लिए आबादी के अनुसार प्रजा चुनती है और हर साल काउंसिल के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। तीन सौ से अधिक आबादी के पैरिशों में पाँच से पंद्रह तक सदस्यों की तीन साल के लिए इसी प्रकार काउंसिलें चुनी जाती हैं। ग्रामों को भी इन काउंसिलों में चुने जाने का अधिकार होता है। पैरिश की एक सालाना जन सभा में पैरिश की काउंसिल के सदस्यों का चुनाव होता है। जिन तीन सौ से कम आबादी के पैरिशों में काउंसिल नहीं होती है, वहाँ जन-सभा साल में दो बार मिल कर स्थानिक शासन समस्याओं पर विचार करती है और स्थानिक शासन का काम चलाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करती है।

शहरी जिलों के स्थानिक शासन का संगठन और प्रबंध विस्तृत देहाती जिलों की तरह होता है। उन की भी वैसी ही तीन साल के लिए चुनी हुई काउंसिलें होती हैं, जिन की स्थायी समितियाँ शासन का सारा काम-काज चलाती हैं। शहरी जिले इन क्षेत्रों को इस लिए कहा जाता है कि वे बौरो उनमें के करीब पंद्रह चुके होते हैं। चुगियों की इकाई बौरो होती है और स्थानिक शासन के विस्तृत अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन को राजस्व की तरफ से एक 'अधिकार पत्र' दिया जाता है। म्यूनिसिपल बोरो और काउंटी

बीरो के गगठन और काम काज के दग म बोई अतर नहीं होत है। दोना चुगिया का काम करती हैं। तिक पचास हजार से ऊपर की आनादी की बीरो की, जिस काउटी मे यह बीरो होनी हैं, उग के दखल से निमाल कर काउटी बीरो उना दिया जाता है। साधारण म्युनिसिपल बीरो काउटी के दखल और सानैतिक अधिकार-क्षेत्र ना भाग होती है। बीरोज की भी जिला की तरह, नौ से लेकर सौ सदस्यों तक की, तीन साल के सदस्यों और उन के एक निहाई छ साल के ऐल्डरमैन की, सारे मर्द म्बी नागरिकों के द्वारा चुनी हुई, कौंसिलें होती हैं। ऐल्डरमैनों ना आम तोर पर सदस्यों से स्थानिक शासन-नीति पर अधिक अतर रहता है। कौंसिल के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, जिस को एक साल के लिए चुना जाता है और जिस को सभा का अध्यक्ष बन कर काम चलाने के अतिरिक्त कोई और खास कार्य कारिणी सत्ता नहीं प्राप्त होनी है। इन कौंसिलों को भी जिला की कौंसिलों की तरह ही सत्ता होती है। जिलों की कौंसिला की हिंदुस्तान के जिला बोर्डों और बीरो कौंसिलों की शहर और कस्बा की चुगियों से समता की ना करती है।

लंदन ना शासन 'बोर्ड और क्लर्क' के कोरपोरेशन् की तरह एक खास 'लंदन सरकार कानून'<sup>१</sup> के अनुसार चलता है। गिल्डहल कानूनी दृष्टि से तो लंदन सिर्फ 'येम्स' के गार्ड किनारे पर एक वर्ग मील का लडा शहर है। वही सारे व्यापार का केंद्र है। उस की सारी आनादी सिर्फ पचास हजार है और लार्ड मेयर, ऐल्डरमैन की एक कचहरी और प्रतिनिधियों की सभा मिल कर उस का शासन चलाती है। मगर इस शहर के चारों तरफ फैली हुई २८ बीरोज हैं, जिन सभ को मिला कर लंदन की काउंटी कौंसिल बनती है। इस कौंसिल में आनादी के अनुसार करीब ११८ सदस्य, उन्नीस ऐल्डरमैन और एक चुना हुआ अध्यक्ष होता है। राजधानी की इन शासन-संस्थाओं को उन्ने अधिकार हैं। 'राजधानी जल बोर्ड' का अधिकार-क्षेत्र बहुत दूर तक देश के भीतरी भागों म फैला हुआ है। 'राजधानी पुलिस बोर्ड' का अधिकार-क्षेत्र चैरिंग क्रॉस स्थान से ले कर पद्रह मील के भीतर के आस-पास के सार पैरिशों तक म 'प्रधान' करीब सात सौ वर्ग मील तक होता है।

ब्रिटेन भर में न्याय शासन का एक ही तरीका नहीं है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड के न्याय-शासन के ढंगों म भेद है। फ्रांस, इटली और जर्मनी इत्यादि राष्ट्रों की तरह ब्रिटेन में 'शासकी अदालतें' अलग नहीं होती हैं। शासन-सम्बंधी अधिका रियों के आपस के झगडे और अधिकारियों और नागरिकों के झगडों का फैसला मा साधारण अदालत ही करती हैं। पहले अलग अलग दीवानी की अदालतें, फौजदारी का अदालतें, इन्साफ की अदालतें, आम कानून की अदालतें, वसीयत की अदालतें, तलाक की अदालतें, धार्मिक अदालतें इत्यादि इतनी विभिन्न अदालतें होती थीं कि कौन-सा झगडा किस अदालत के सामने जाय इसका निश्चय करना मुश्किल हो जाता था। उन के नाज काज का दग भी इतना मुश्किल होता था कि वरीलों तक को उन भूल-भुलैयाओं म से निबलना कठिन होता था। अस्तु, सन् १८७३ ई० से १८७६ ई० तक कई कानून

<sup>१</sup> 'लंदन गवर्नमेंट ऐक्ट'।

पास कर के न्यायशासन में सुधार किया गया था। छोटी अदालतों को छोड़ कर और सारी विभिन्न अदालतों को एक 'सर्वोपरि न्यायालय' के अधीन कर दिया गया था और हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में न्यायाधीशों को न्याय का काम करने के लिए रखा गया था। सारे न्यायाधीशों के राजा के नाम पर 'लार्ड हाई चांसलर' या उस की नामजदगी पर राजा नियुक्त करता है। न्यायाधीशों को बिना कसूर निकाला नहीं जा सकता है। लार्ड हाई चांसलर को नाम के लिए राजा के नाम में न्यायाधीशों को हटा देने की सत्ता होती है। मगर अमल में पार्लियामेंट की दोनों सभाओं की सम्मिलित प्रार्थनाओं पर ही किसी न्यायाधीश को निकाला जाता है। केवल धारा-सभा को ही न्यायाधीशों को हटाने की सत्ता होने से न्याय शासन कार्य-कारिणी के दबाव से बचा रहता है, और इस के परिणाम-स्वरूप ब्रिटेन के न्यायालय उड़ी निष्पक्षता और आजादी से काम करते हैं।

फौजदारी के मुकदमों में लगभग उसी प्रकार चलाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में। मगर बहुत सा न्याय शासन का वह काम जो हिंदुस्तान में मजिस्ट्रेट करते हैं, ब्रिटेन में 'जस्टिस ऑफ़ दि पीस' नाम के अधिकारी करते हैं। इन न्यायाधीशों को हमारे देश के ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटों की तरह कोई वेतन नहीं मिलता है और उन के जोड़ का एक तरह उन को अधिकारी कहा जा सकता है। मगर 'जस्टिस ऑफ़ दि पीस' को हमारे ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट से कहीं अधिक अर्थात् हमारे यहाँ के मैजिस्ट्रेटों के से अधिकार होते हैं। सारे फौजदारी के मुकदमों में पहले उन की अदालत में जाते हैं और उन का काम शिफायती गवाही सुन कर सिर्फ़ यह तय करना होता है कि मुलाजिम के खिलाफ़ जाहिर कोई मुकदमा है या नहीं। उन की समझ में मुकदमा जाहिर होने पर वह मुलाजिम को मुकदमों के लिए चालान कर देते हैं और जाहिर मुकदमा न लगने पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार के चालान किए हुए छोटे अपराधों, नाबालिगों और पहले अपराधों के मुकदमों में 'जस्टिस ऑफ़ दि पीस' की 'छोटी सेरास' अदालत में तै किए जाते हैं, जहाँ जुमाने या थोड़ी सी जेल की सज़ा दी जा सकती है। छोटे सेरास के फैसलों के खिलाफ़ अपराधी बाउटी के सारे 'जस्टिस ऑफ़ दि पीस' की तिमाही बैठनेवाली 'तिमाही सेरास' की अदालत में अपील कर सकते हैं। उड़े अपराधों के मुकदमों में तीसरे 'तिमाही सेरास' की अदालत या हाईकोर्ट के एक जज जी 'ऐसादज' अदालत के मामले जाते हैं। दोनों अदालतों में 'शेरिफ़' की चुनी हुई तरह सद्व्यक्तियों की एक 'जूरी' न्यायाधीशों के साथ बैठ कर अभियोग का फैसला करती है। हमारे देश की सेरास अदालतों और इन अदालतों में एक बड़ा महत्व का अंतर है। हमारे यहाँ की सेरास अदालतों में सिर्फ़ 'असेसर' बैठते हैं, जिन की राय मानने, न मानने का जज को अधिकार होता है। परंतु ब्रिटेन की अदालतों में फैसला न्यायाधीश के हाथों में न हो कर जूरी के हाथ में होता है। जूरी के अपराधी को निर्दोष करार दे देने पर अपराधी फौजदारी मुक्त कर दिया जाता है और उस पर फिर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जूरी में मत



मेद हो जाने पर दूसरी जूरी के सामने फिर से मुकदमे पर विचार होता है। जूरी के फैसले के खिलाफ अपराधी तीन जजों की 'अपील की अदालत' के सामने अपील कर सकता है। उस के आगे भी सार्वजनिक हित का कोई कानूनी प्रश्न तय करने के लिए, सरकारी ऐगर्ना जेनरल की राय से, अपराधी 'अपील की अदालत' के फैसले के खिलाफ भी हाउस ऑफ लार्ड्स के आगे अपील कर सकता है। इसी प्रकार दीवानी के मुकदमे झगड़े की रकम के अनुसार मुस्तलिफ्त अदालतों के सामने जाते हैं।

### ७—राजनैतिक दल

रहा जाता है कि इंग्लैंड की राज-व्यवस्था समार भर में सब से अधिक प्रजा सत्तात्मक है। यह ठीक हो सकता है। परन्तु मन्त्रि मंडल के सदस्य अर्थात् वे लोग जिन के हाथ में देश के शासन की गांठें रहती हैं, अभी तक अक्सर अभीर ही घरा के होते आए हैं। आज तक के सारे मन्त्रि मंडलों को देखा जाय, तो पता लगेगा कि उन के मंत्रियों में अधिकतर जमींदार, व्यापारी, महान और धनवान् वकील और प्रेस्टिजिये। मजदूर-दल के आने से कुछ फर्क जरूर पड़ा है, मगर बहुत नहीं। पार्लियामेंट के सदस्यों में भी पैसवाले लोगों की ही अधिक संख्या रहती थी। मजदूर दल के कारण बहुत से साधारण केटि के लोगों को भी मजदूर वर्गों की वोटों और धन के बल पर पार्लियामेंट में घुसने का अब अवसर मिलने लगा है। वर्ना उदार और अनुदार दल के जमाने में तो पैसवाले के लिए ही पार्लियामेंट की कुर्सी होती थी, परन्तु साधारण मनुष्यों को आजकल की राजनीति के सार प्रश्नों का समझना असंभव होता है। दिन २ दिन सरकार के अधिकारों और कामों का दायरा बढ़ता जाता है। डाक, तार, टेलीफोन, शिक्षा, रेल, दवादारू, जहाज, व्यापार कौन-सा ऐसा सार्वजनिक काम है, जिस में आजकल सरकारी हाथ नहीं रहता? सरकार के सारे कामों को अच्छी तरह समझने के लिए साधारण नागरिक के पास समय नहीं होता है। उस बेचारे को सुबह से शाम तक अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए एड़ी से चोटी तक का परीना एक करने में लगा रहना पड़ता है। अस्तु, राजनीति इंग्लैंड में उन साते पीते लोगों का पेशा हो गया है, जिन्हें अपनी रोटी कमाने की चिंता नहीं होती है और जो उस के लिए काफी समय दे सकते हैं।

हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को वेतन मिलना शुरू होने के बाद से जरूर कम हैसियत के लोगों को भी राजनीति की तरफ आने का उत्साह होने लगा है। जब छोटी छोटी स्थानीय पंचायतों द्वारा शासन चलता था, तब साधारण लोगों को शासन की बातें समझने और शासन में भाग लेने का मौका रहता था। अब राजनीति के प्रश्नों को एक विशेष केटि के लोग ही समझते हैं और साधारण मनुष्य तो विभिन्न राजनैतिक दलों की नीति भी अच्छी तरह नहीं समझ पाते। वे चुनावों में या तो इस नेता के लिए मत दे आते हैं, या उस नेता के लिए। प्रायः यह देखने में आया है कि जिस नेता का मन्त्रि-मंडल काफी शासन कर सकता है, दूसरे चुनाव में लोग उस को मत न

दे कर दूसरे दल के नेता के लिए वोट देते हैं। शायद वे यह सोचते हैं कि हर नेता को मौका देना चाहिए, अथवा सत्तार की रीति के अनुसार वर्तमान से असन्तुष्ट हो कर वे परिवर्तन चाहते हैं।

इंग्लैंड में सरकार एक दल की होती है। दूष्ण दल कितना ही बड़ा क्यों न हो आम तौर पर उस का उस में साम्रा नहीं रहता। इंग्लैंड की राजनीति दलबन्दी का नमूना है। बहुत दिनों तक इंग्लैंड में दो ही राजनैतिक दल थे—एक कन्सर्वेटिव दल और दूसरा लिबरल दल। अपनी भाषा में कन्सर्वेटिव दल को अनुदार दल अथवा दक्कानूसी दल, और लिबरल दल को उदार दल कह सकते हैं। इन दोनों दलों की जब मनुष्य स्वभाव की दो प्रकृतियों को नष्ट सकते हैं। अनुदार दल में वे लोग सम्मिलित होते थे, जिन्हें पुरानी बातों पर अधिक विश्वास होता था और जो हर मामले में बहुत ही संभल संभल कर कदम बढ़ाने के पक्षपाती होते थे। उदार दल में वे लोग जाते थे जो मनुष्यित विचारों के विरोधी और थोड़े बहुत आदर्शवादी होते थे। राजनैतिक और प्रार्थिक सिद्धांतों के भेदों से अधिक मनुष्य-स्वभाव का यह प्रकृति भेद ही इन दलों का मूल कारण था। राजनैतिक क्षेत्र में लोगों का इस प्रकार दो दलों में बँट जाना इंग्लैंड के लिए बड़ा हितकर हुआ क्योंकि इन दोनों दलों के संगठित युद्ध और लगातार राजनैतिक संघर्ष से ही इंग्लैंड में राजनैतिक जाग्रति पैदा हुई। जब अनुदार दल की जीत होती थी और शासन की गाँठों उस के हाथ में आती थी, तब उदार दल के रोज़ाना विरोध और आलोचना का उस पर अंगुश रहता था, जिस से शासन कार्य में अनुदार दल सचेत रहता था। उसी प्रकार जब उदार दल ने शासन भार संभाला तो अनुदार दल का उस पर अंगुश रहा। इन प्रकार इन दोनों दलों की आपस में होड़ से सरकार का काम अच्छा चलता था, क्योंकि जिस दल के हाथ में शासन की लगाम होती थी, उसे इस बात का हमेशा भय लगा रहता था कि उस से कोई काम बिगड़ा तो उस की दूसरे चुनाव में हार हो जायगी और विपक्षी दल जीत कर अधिकार में गद्दी पर बैठ जायगा। परन्तु इस दलबन्दी की रस्दों और संघर्ष का तभी तक अच्छा लाभ होता है, जब तक देश में केवल दो ही राजनैतिक दल रहें। इंग्लैंड के सौभाग्य से बहुत दिनों तक वहाँ के राजनैतिक क्षेत्र में दो ही दल रहे जिस से वहाँ की राज व्यवस्था सुसंगठित और सुचारु रूप से चलती रही। तीसरे मजदूर दल के खड़े होने पर इस प्रणम में गड़बड़ देने की संभावना हुई थी। परन्तु जैसा मजदूर दल बड़ा वैसा ही उदार दल घटा।

सन् १९२२ ई० के चुनाव के बाद पार्लियामेंट में तीनों दलों के सदस्य इतनी संख्या में चुन कर आए कि सन् १९२३ ई० में उदार दल के हाथ में मजदूर दल अथवा अनुदार दल को आसन पर बैठाने की कुंजी आ गई। परन्तु इंग्लैंड के जाग्रत जनमत के सामने इस कुंजी का दुर्भ्योग करने की उदार दल की हिम्मत नहीं हुई। जब तक निर्णय दो ही दल थे, तब तक जिस दल की पार्लियामेंट में बहु-संख्या होती थी, उस दल के नेता को राजा मन्त्रि मंडल बनाने के लिए न्योता देता था। परन्तु सन् १९२३ ई० में जब तीन दल के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में इस संख्या में चुन कर आए कि किसी भी दल को सिर्फ अपनी संख्या के बूते पर मन्त्रि

गंडल बना कर शासन चलाना असंभव था तब यह कठिनाई खड़ी हुई कि किस दल को शासन का भार सौंपा जाय। परंतु अंगरेजों की क्रियात्मक बुद्धि सहायनीय है। मजदूर-दल के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में उदार दल से अधिक थे इस लिए अनुदार दल के हस्तीपा रग देने पर मजदूर दल को शासन का भार सौंपा गया और उदार दल ने मजदूर दल के मार्ग में व्यर्थ के रोड़े अटकाने या फांस इत्यादि यूरोप के दूसरे देशों की तरह मंत्रि-मंडल में कुछ अपने भी मंत्री घुसेड़ने का प्रयत्न नहीं किया। मंत्रि-मंडल में सारे सदस्य एक मजदूर दल के ही रहे और शासन भी उसी प्रकार चलाया गया था जिस प्रकार दो दलों के जमाने में चलाया जाता था। दूसरे चुनाव में उदार दल के सिर्फ ४२ सदस्य ही पार्लियामेंट में रह गए और इस के बाद से-उदार दल एक छोटा और कमजोर दल हो गया है। अस्तु, यह भय कि इंग्लैंड की राज-व्यवस्था केवल उसी समय तक अस्थिर रहेगी, जब तक कि इंग्लैंड में केवल दो राजनैतिक दल रहेंगे और दो से अधिक राजनैतिक दल हो जाने पर इंग्लैंड की राजनीति का रंग-रूप बदल जायगा, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तीन दल हो जाने पर भी इंग्लैंड की राज-व्यवस्था का रंग-रूप नहीं बदला है। कुछ तो हम का भ्रम अंगरेजों की क्रियात्मक बुद्धि को है, परंतु मुख्य कारण यह है कि इंग्लैंड में तीन दल बन जाने पर भी दो ही दलों के सदस्यों की पार्लियामेंट में संख्या अधिक रही है। तीसरा उदार दल दिन-दिन क्षीण हो रहा है।

इंग्लैंड के राजनैतिक दलों के रेड कार्टर्स लंदन में रहते हैं और उन की शाखाएँ प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में होती हैं। साल में एक बार उन के वार्षिक सम्मेलन होते हैं जिन में सब शाखाओं से प्रतिनिधि आ कर भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों में दलों की विभिन्न राजनैतिक प्रश्नों पर नीति का और उस को पूरा करने के लिए प्रोग्राम का निश्चय होता है। राजनैतिक दलों के इन निश्चित प्रोग्रामों के लिए ही चुनावों पर प्रजा के मत मांगे जाते हैं। परंतु इंग्लैंड के लोग सिद्धांतों पर रीझनेवाले आदर्शवादी स्वभाव के नहीं होते हैं। सिद्धांती प्रोग्रामों की अधिक परवाह न कर के इंग्लैंड में साधारण लोग नेताओं के पीछे चलते हैं और चुनाव के समय इसी बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि किस नेता को प्रधान मंत्री या किन नेताओं को मंत्री बनाना उचित होगा। अस्तु, जिन नेताओं को उन्हें मंत्रि-मंडल की गद्दी पर बैठाना होता है, उन के दल के पक्ष में वे मत डालते हैं। चुनावों पर सिद्धांतों और राजनैतिक दलों के कार्य-क्रमों से अधिक मतदारों के दिमाग में यही बात अधिक रहती है कि वाल्डविन के लिए वोट देना चाहिए या मेकडानेल्ड के मंत्रि-मंडल के लिए। उदाहरणार्थ सन् १९२६ ई० की पार्लियामेंट में मजदूर दल के सदस्यों की सब से अधिक संख्या होने से मजदूर दल की सरकार थी। परंतु सन् १९३१ ई० में मजदूर दल के प्रधान मंत्री रेम्से मेकडानेल्ड ने देश को आनेवाले आर्थिक संकट से बचाने के विचार से एक दल की सरकार खत्म कर के एक सर्वदल राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया। मजदूर दल के दो और मंत्रियों को छोड़ कर और सभी मंत्री इस निश्चय के विरुद्ध थे। फिर भी प्रधान मंत्री मेकडानेल्ड अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और उस ने राजा से प्रार्थना की

त्रि पार्लीमेंट भग कर के नया चुनाव कराया जाय। राजा ने उस की प्रार्थना मज़दूर कर के पार्लीमेंट भग कर दी और नए चुनाव का हुक्म निज़ाला। इस पर मज़दूर दल ने मेकडानेल्ड को मज़दूर दल के नेतृत्व से हटा दिया और उन के दूसरे दोनों माथियों सहित उस को मज़दूर दल तक से निकाल दिया। परन्तु चुनाव में मज़दूर दल की ऐसी भयंकर हार और मेकडानेल्ड की ऐसी जीत हुई कि जिस मज़दूर दल के पार्लीमेंट में सब से अधिक प्रतिनिधि थे उसी के पचास से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुने गए और मेकडानेल्ड के समर्थक अन्य दलों के सारे प्रतिनिधियों से लगभग तीन सौ में अधिक संख्या में चुन कर आए। मज़दूरदल के एक दो मंत्रियों को छोड़ कर अन्य उन सब मंत्रियों का चुनाव तक न हो सका, जो मेकडानेल्ड के मंत्रि मंडल के सदस्य थे और जिन्होंने उस का विरोध किया था। इस घटना से साफ पता चलता है कि इंग्लैंड की जनता अभी तक इतनी मिठांतों और राजनैतिक दलों के कार्य क्रमा की परवाह नहीं करती है जितनी • व्यभिगत नेताओं और क्रियात्मक गतों की। समाजवादी सिद्धांतों को माननेवाले मज़दूर दल की इतनी उन्नति हो जाने और सर्व-साधारण को मताधिकार मिल जाने पर भी इंग्लैंड में पुस्तकों और व्याख्यान मंचों को छोड़ कर कहीं आर्थिक दिस सघर्ष के सिद्धांतों पर अभी तक चुनाव इत्यादि में अमल होता नहीं दिखाई देता है।

लड़ाई के बाद से खास कर तीन गतों की बुनियाद पर बृटेन में दलबंदी का रूप रग बढ़ता है। एक तो मतदारों का और उस के परियामस्वरूप सारे राजनैतिक दलों का इस बात पर एक मत होने लगा है कि बृटेन को जहाँ तक उने वहाँ तक, शांति क्रायम रगने के प्रयत्नों को छोड़ कर, यूरोप के दूसरे भागों और क़मेलों से दूर रहना चाहिए। दूसरे बैनारी की गठ और समाजशाही की तरफ लोगों का रुझान उने से मज़दूर दल की संख्या और शक्ति बहुत बढ़ गई है। तीसरे किसी भी सरकार का मतदारों की बहुत उड़ी संख्या ने गमर्थन नहीं किया है। लायड जॉर्ज और बोनर ला की उदार दल और अनुदार दल की सम्मिलित सरकार को साठे नब्बे लाख मतों में से पाँच लाख मत सन् १९१८ ई० के चुनाव में मिले थे जिस के तल पर कॉमन्स की ७०७ जगहों में से ४८५ उन को मिली थीं। नवंबर सन् १९२२ ई० के चुनाव में अनुदारदल को १३०३ लाख मतों में से सिर्फ ५०३ लाख मत मिले थे और कॉमन्स में ६१५ जगहों में से ३४४ जगह मिली थीं। सन् १९२४ ई० के चुनाव में बाल्डविन की अनुदार सरकार को १६०१ लाख मतों में से ७०८ लाख मत मिले थे और ६१५ जगहों में से ४१५ जगहें मिली थीं। सन् १९२४ ई० की कुछ महीनों तक क्रायम रहनेवाली मज़दूर दल की सरकार के, कॉमन्स में ६१५ सदस्यों में सिर्फ १६१ सदस्य थे जिन को पिछले चुनाव में करीब ४३५ लाख मत मिले थे।

सन् १९१८ ई० में अस्थायी सचि के चर्चाचौध में 'सचि की सफलता के लिए सब की सहायता की जरूरत है' की आवाज़ उठा कर लायड जॉर्ज ने अपनी सरकार के पक्ष में बहुत से मत कर लिए थे। मगर सरकार के सदस्यों की संख्या पार्लीमेंट में बहुत अधिक होने का बुरा परिणाम यह हुआ कि पार्लीमेंट ने सरकार की टीसा टिप्पणी करनी बिल्कुल ही बंद कर दी थी और पार्लीमेंट लायड जॉर्ज की उँगली पर नाचती थी। यह

सरकार देश को लड़ाई के बाद के व्यापार के उतार से न उचा सकी। मजदूरों की आर्थिक उन्नति हो जाने, सारे मर्दों को मताभिन्न मिल जाने और बेकारी बंद जाने के कारण मजदूर दल की चुनौती से बचने के लिए इस सरकार को स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्षा, मकान बनाने में सहायता, बेकारी से रक्षा, असंगठित उद्योगों में मजदूरी का दर नियमित करने, और रेलवे और ज्वेली गरी पर सरकारी प्रबंध चलाने इत्यादि के बहुत से मजदूर दल के कार्यक्रम से मिलते-जुलते काम करने पड़े। फिर भी इसी सरकार के जमाने में रेलवे के मजदूरों की एक लगी हड़ताल हुई और मजदूरों में बहुत असंतोष बढ़ा। लायड जॉर्ज को सधि और मुआवजे के प्रश्नों को दूसरे राष्टों से तय करने से ही फुरसत नहीं रहती थी कि घर की समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान दे। मुश्किल से हमें में एक बार वह पार्लिमेंट में आता था। इधर अनुदार दल को भी उस की बढ़ती हुई ताकत देख कर डर होने लगा था। इस लिए लायड जॉर्ज के परराष्ट्रनीति में भयकर लक्षण दिखाने ही अनुदार दल उस से अलग हो गया और लायड जॉर्ज को हस्तीका दे देना पड़ा। इस के बाद सन् १९२२ ई० के चुनाव के बाद योनर ला की अभ्यक्षता में अनुदार दल की सरकार बनी जिस के पार्लिमेंट में ३४४ सदस्य थे। इस सरकार के खिलाफ मजदूर दल के १४० सदस्य और उदार दल के ११६ सदस्य थे। सन् १९२३ में योनर ला के हट जाने पर बॉल्डविन प्रधान मंत्री हुआ और इन मौके पर इंग्लैंड की राज व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या हल की गई। योनर ला के बाद अनुदार दल का नेता बनने रा लॉर्ड नॉर्न को एक था, मगर कर्जन हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स का सदस्य था, इस लिए उस को नेता न मान कर बॉल्डविन को, जो हाउस ऑफ़ कामन्स का सदस्य था, प्रधान मंत्री बनाया गया। अस्तु, यह बात निश्चय हुई कि इंग्लैंड का प्रधान मंत्री कामन्स का ही सदस्य होना चाहिए, लार्ड्स का नहीं। बॉल्डविन ने प्रधान मंत्री बन कर मजदूर दल के बढ़ते हुए जोर को कम करने के लिए डिस्कापली की नीति पर अमल करने और बेकारी कम करने के लिए करा के द्वारा राष्ट्रीय व्यापार की रक्षा और उन्नति करने का निश्चय किया। मगर योनर ला पिछले चुनाव में व्यापारी चुनौती न जारी करने से मतदारों से बचने दे चुका था, इस लिए नीति बदलाने के पहले पार्लिमेंट का नया चुनाव करा लेने की जरूरत थी। बॉल्डविन ने पार्लिमेंट से भग कर के नया चुनाव कराया, जिस में अनुदार दल के ८० सदस्य कम हो गए और किसी भी दल के सदस्यों की पार्लिमेंट में साफ बहुसंख्या न हुई। अस्तु, उदार दल की सहायता से धनी-मानी इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार इस चुनाव के बाद मेकडॉनेल्ड की अभ्यक्षता में मजदूर दल की सरकार गयी। अपनी थोड़े से महीनों की जिंदगी में मजदूर सरकार कुछ न कर सकी और दस महीने बाद ही प्रधान मंत्री मेकडॉनेल्ड ने पार्लिमेंट भग करा दी। इस सरकार के जमाने में भी इंग्लैंड की राज व्यवस्था का एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न तय हुआ। राजा ने मजदूर दल की सरकार के कंधे ढाल देने पर, किसी दूसरे दल की सरकार बनाने का प्रयत्न नहीं किया, और अल्प-संख्यक दल के प्रधान मंत्री की पार्लिमेंट भग करने की प्रार्थना

मजदूर की, क्योंकि अपनी सत्ता का प्रयोग कर के राजा का राजनैतिक चर्चा में पड़ना उचित नही समझा गया।

नए चुनाव में मजदूर जिनोवीफ<sup>१</sup> दल का सोवियेत हीआ गढ़ कर के अनुदार दल ने मजदूर दल की पार्लामेंट में शक्ति कम कर दी। इस चुनाव में अनुदार दल के ४१५ सदस्य चुन कर आए, और मजदूर दल के १५२ तथा उदार दल के सिर्फ ४० सदस्य। दो सौ की बहुसंख्या रखनेवाली अनुदार दल की सरकार बनी जो पार्लामेंट में पूरे पाँच साल तक कायम रह सकती थी। मगर इस सरकार ने बेकारी की समस्या सुलझाने का प्रयत्न नहीं किया और परराष्ट्र नीति में भी इतनी विचित्रता दिखाई कि लार्ड सिमिल उक्तता कर जेनेवा में इस्तीफा दे कर चला आया। कोयले की समस्या सुलझाने में तो इतनी बेवकूफी दिखाई कि इंग्लैंड के इतिहास में अद्वितीय मजदूरों की आम हड़ताल हुई, जिस से कहा जाता है पार्लामेंट की सत्ता को बड़ा धक्का पहुँचा। अस्तु, सन् १९२६ के दूसरे चुनाव में अनुदार दल की हार हुई और मजदूर दल के सत्र में अधिक सदस्य चुन कर आए। मगर किसी भी दल की साफ बहुसंख्या फिर भी नहीं थी। मजदूर दल के २८८ सदस्य थे, अनुदार दल के २६० सदस्य, उदार दल के ६६ सदस्य और ८ सदस्य स्वतन्त्र थे। मैकडॉनैल्ड की अध्यक्षता में मजदूर दल की सरकार गनी जिस ने घर पर बेकारी की समस्या और यूरोप में शांति कायम रखने की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न शुरू किया। इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार इस सरकार के मंत्रि मंडल की सदस्य मित्र मार्गरेट बौडपील्ड नाम की एक महिला मजदूर विभाग की मंत्री बनाई गई थी। इसी सरकार के जमाने में भारतवर्ष में दूसरा अखंडयोग आंदोलन चला, जिस को पहले दवाने का प्रयत्न कर के पीछे से सरकार ने गांधीजी ने अस्थायी 'हरबिन-गांधी' समझौता किया था, जिस के परिय्याम-रूप गांधीजी गोजमेन सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बन कर गए थे। मगर गोलमेज सम्मेलन चल ही रहा था कि इस सरकार ने अथवा या कहिए कि प्रधान मंत्री मैकडॉनैल्ड ने अपने दो मित्रों की सलाह से आर्थिक संकट का सामना करने के लिए, पार्लामेंट को भग करा कर, एक सर्वदल 'राष्ट्रीय सरकार' बनाने के लिए नया चुनाव कराया इस चुनाव में इंग्लैंड के दलों की काया-गलट हो गई। जैसा पहले कहा जा चुका है, मजदूर दल के तीन प्रमुख नेताओं मैकडॉनैल्ड, स्लोडन और गौमस को मजदूर दल से निकाल दिया गया, मजदूर दल की भयंकर हार हुई। दो चार को छोड़ कर मजदूर-दल के वे सारे नेता, जो पिछले मंत्रि मंडल के सदस्य थे, इस चुनाव में नही चुने जा सके और पार्लामेंट में मजदूर दल के २८८ सदस्य से घट कर सिर्फ ४६ सदस्य रह गए। उदार दल के भी सिर्फ ७२ सदस्य ही चुन कर आए। बाकी सब अनुदार दल के सदस्य चुने गए। इस चुनाव में अनुदार दल और उदार दल के नेताओं तथा मजदूर दल के निकाले हुए तीनों नेताओं की तरफ

१ अनुदार दल के अग्रधारों ने चुनाव से कुछ पहले बोव्शेविक रुसी नेता जिनो वीक का मंत्रि मंडल के सदस्यों को भेजा हुआ एक पत्र छाप कर मजदूर दल पर बोव्शेविकों से सहपत्र करने का इल्जाम लगाया था।

से प्रजा से दलपदी का खयाल न कर के चुनाव म राष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि से मत देने की प्राथना की गई और कहा गया कि इस चुनाव का परिणाम किसी खास दल की नीति नहीं समझी जायगी। अस्तु, इस चुनाव के परिणाम से बृटेन के राजनैतिक दलों का भविष्य बताना कठिन है। मुमकिन है इस चुनाव म बहुत बड़ी गहु-सख्या प्राप्त कर के पालामंट म निरकुश बन जानेवाले अनुदार दल की सब १६२४ ई० के चुनाव की तरह दूसरे चुनाव म फिर हार हो जाय और मजदूर दल की सग्या उठ जाय। यह भी मुमकिन है कि मजदूर दल के नेताओं के आपस के झगड़ के कारण मजदूर दल बहुत दिनों तक ताजत में न आ सके। मगर दो बात तो निश्चय ही दीखती हैं। एक तो मजदूर दल दूसरे चुनाव के बाद पालामंट म किसी हालत म इतना कमजोर न रहेगा जैसा अब है। दूसरे उदार दल फिर कभी न उभरेगा। अस्तु, इंग्लैंड की राजनीति के मैदान म राजनैतिक द्वन्द्व-युद्ध के लिए दो ही उड़े दल रहेंगे और अनुदार दल और मजदूर दल के सघर्ष और सर्द्धा से बृटेन की राजनीति हमेशा की तरह परिमार्जित और उन्नत होती रहेगी।<sup>१</sup> मेरुडॉनेल्ड की राष्ट्रीय सरकार के बनने के बाद इन सरकार ने एक ऐसा काम किया, जो इंग्लैंड की राज-व्यवस्था के इतिहास और राजनैतिक विकास में बिल्कुल नया था। हमेशा से मंत्रि मंडल की—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं—पार्लिमेंट के प्रति सम्मिलित जवाबदारी मानी जाती थी और वे एकमत से पार्लिमेंट का मुताबला करते थे। पार्लिमेंट के अंदर किसी प्रश्न पर कभी मंत्रि मंडल के सदस्य एक-दूसरे के विरुद्ध विचार प्रगट करते या मत नहीं देते थे। परंतु इस राष्ट्रीय मंत्रि मंडल के सदस्यों ने व्यापारी चुंगी करों के प्रश्न पर पार्लामेंट म एक दूसरे के विरुद्ध व्याख्यान और मत दिए, जिस से मंत्रियों की सम्मिलित जवाबदारी की पुरानी प्रथा म पहली बार रंग म भंग पड़ा। मजदूर दल की तरफ से पार्लामेंट म कहा भी गया कि सरकार का यह काम बृटिश राज-व्यवस्था के विरुद्ध है। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इस घटना से मंत्रियों की सम्मिलित जवाबदारी का सिद्धांत इंग्लैंड म खत्म हो गया क्योंकि यह सरकार राष्ट्रीय सरुत काल म—अस्थायी प्रबंध की तरह सभी मतों के मधिये की—जान बूझ कर बनाई गई थी, और 'आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति' के सिद्धांत पर हमेशा से ही इंग्लैंड की राज व्यवस्था गढ़ती आई है। यहाँ तक तो हुई इंग्लैंड के राजनैतिक दलों के काम और उस काम के सरकार की नीति और बाल पर असर की बात। अब हम उन के कुछ इतिहास और लक्षित कार्यक्रम का परिचय देते हैं।

<sup>१</sup> इस पुस्तक के प्रेस से निकलते समय तक दूसरा चुनाव भी हो चुका है, जिस के बाद फिर दूसरी राष्ट्रीय सरकार बनाई गई है। परंतु इस चुनाव में अनुदार दल की सख्या बढ़ गई है और प्रधान मंत्री मैकडॉनेल्ड के स्थान म अनुदार दल का नेता बॉलडविन है। मजदूर दल के नेताओं के विरवासघात के कारण इस दल की सरकार शीघ्र घटने के कोई लक्षण नहीं दीखते हैं। परंतु उदार दल की शक्ति आखिरी चुनाव में और भी कम हो गई है। अस्तु, इंग्लैंड के राजनैतिक क्षेत्र में अनुदार और मजदूर दो ही दलों का द्वन्द्व-युद्ध होता रहेगा।

अनुदार दल पुराने 'टेरी दल' का उत्तराधिकारी है, जिस को डिसराइली ने अपनी बुद्धि के प्रभाव से बदल कर आधुनिक बनाया था। आज्ञाकल के अनुदार दल का जन्मदाता वास्तव में डिसराइली ही था। उस ने इस दल का ध्येय "इंगलैंड की पुरानी सस्थाओं को सुरक्षित रखना, साम्राज्य को कायम रखना और प्रजा की दशा सँभालना" बताया था, और अभी तक अनुदार दल का मुख्य ध्येय मध्य यही चला आता है। आयरलैंड को होमरूल देने के प्रश्न पर उदार दल में फूट पड़ जाने पर ड्यूक ऑफ़ केवीनशायर और जोज़ेफ़ चेंबरलेन के ग्लैडस्टन के विरुद्ध हो कर अपने साथियों को ले कर अनुदार दल के सामाज्यवादी कार्यक्रम में शरीक हो जाने पर अनुदार दल की नीति में और भी परिवर्तन हुआ था, और डिसराइली की नीति और उदार दल से टूट कर आनेवाले लोगों की नीति के मेल से, जो बाद में नई नीति बनी थी, वही आज कल के अनुदार दल की नीति है। इस नीति के पूरा करने के लिए लीग ऑफ़ नेशन्स का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिमय निपटारा करना, बृटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों की आर्थिक उन्नति करना और उन का एक दूसरे से आर्थिक नाता घनिष्ठ कर के साम्राज्य के आर्थिक जीवन का एकीकरण करना, जिस से बृटिश साम्राज्य का टूटना असंभव हो जाने, बृटेन में व्यापारी चुगी करों को बुद्धिमानी से लगा कर व्यापार की उन्नति करना, कृषि की सहायता कर के बृटेन के लिए खाद्य पदार्थ बृटेन में ही पैदा करना, सरकारी खर्च में कमी कर के सरकारी करों को कम करना, प्रजा के रहने के घरों की दशा सुधारना, बुढ़ापे में ६५ वर्ष के बाद बूढ़ों को बुढ़ापे की पेंशन सरकारी खजाने से देना और अनाथ विधवाओं और अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करना, शिक्षा की उन्नति और कृषि की आम उन्नति करना, इस दल ने अपना लक्षित कार्यक्रम बनाया है। इस दल की खास सस्थाओं में अनुदार और यूनियन सस्थाओं ७ राष्ट्रीय सभ 'ग्रिमरोज़ लीग', 'जूनियर इपीरियल लीग', 'स्कॉटिश यूनियनिस्ट एसोसिएशन', 'कन्जरवेटिव क्लबों का सभ' और 'अनुदार नौजवान सभ' हैं। इस दल के पक्षपाती बहुत से समाचार पत्र हैं जिन में खास 'डेली मेल' और 'मॉर्निंग पोस्ट' हैं।

उदारदल के विचारों की जड़े बहुत पुरानी हैं। सत्रहवीं सदी के आम कानूनो और राजस्व के झगड़ों, प्यूरिटन और पुराने धार्मिक शोरों के झगड़ों, फ्रांस की क्रांति के फैलाए हुए विचारों, माचेस्टर गुट के आर्थिक विचारों इत्यादि सब से मिल कर उदार दल की पुरानी नीति का जन्म हुआ था। मगर ऐतिहासिक दृष्टि से उदार दल की शुरुआत बीसवीं सदी के प्रारंभ काल में हुई थी। सन् १९०५ ई० में पहली उदार सरकार बनी और तब से यूरोपीय युद्ध शुरू होने तक बराबर उदार दल की सरकारें ही बृटेन में रही। उदार दल को प्रख्यात करनेवाले नेताओं में ग्लैडस्टन, ऐस्क्विथ और लायड जॉर्ज के नाम खास तौर पर लिए जा सकते हैं। उदार दल का मुख्य उद्देश "समाज का ऐसा संगठन करना है, जिस में हर एक व्यक्ति को काम की स्वतंत्रता और उन्नति का मौका हो और कोई एक दूसरे के मार्ग में न आ सके।" यह दल अनुदार दल की आज्ञाकल की सस्थाओं के सिर्फ़ सुधारों के कार्यक्रम का और मजदूर दल के समाज शाही स्थापित



करने के उद्देशों का विरोधी है। अपनी नीति को पूरा करने के लिए यह दल लीग ऑफ नेशन का समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय भगड़ों का शांतिमय निपटारा, सोवियट रूस से व्यापारी संबंध, ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों की भीतरी स्वाधीनता दे कर उन की सलाह और महानुभूति से साम्राज्य कायम रखना, साम्राज्य के मार्गों की उन्नति कर के साम्राज्य का संबंध घनिष्ठ करना, स्वतंत्र व्यापार की नीति कायम रखना, प्रत्यक्ष कर लगाना, रानो पर सरकारी अधिकार रखना, कृषि और जंगलात की उन्नति करना, बेकारी के खिलाफ सामाजिक बीमा और सरकार की तरफ से सार्वजनिक निर्माण-कार्य शुरू कर के बेकारी कम करना, व्यापारी इजारों के खिलाफ कानून बनाना, मजदूरों की दशा सुधारना, अनुपात-निर्वाचन और शिक्षा-उन्नति करने का कार्य कम जरूरी समझता है। पिछले चुनाव में इस दल के तीन भाग हो गए थे। लायट जॉर्ज का अनुयायी और राष्ट्रीय-सरकार नीति का विरोधी एक भाग था, जिस के सिर्फ चार सदस्य चुने गए थे। हर्बर्ट सेमुअल लायड जॉर्ज की बीमारी के कारण दल का नेता हो गया था और उस के हाथ में दल की सारी सत्ता आ गई थी। वह स्वतंत्र व्यापार-नीति पर समझौता कर के राष्ट्रीय सरकार का पक्षपाती था और उस के अनुयायियों में से १३ चुन कर पार्लियमेंट में आए थे। तीसरा भाग जॉन साइमन के अनुयायियों का था, जो अपने को 'राष्ट्रीय उदार' कहते थे और राष्ट्रीय सरकार के हर तरह से समर्थक थे। जॉन साइमन के अनुयायियों में से १५ पार्लियमेंट के लिए चुने गए थे। इन तीनों भागों ने चुनाव में अपना अलग-अलग प्रयत्न किया था और अनुदार दल से मिल कर मजदूर दल को हर जगह हराने का प्रयत्न किया था। इस दल की मुख्य संस्थाओं में एक नेशनल लिबरल फेडरेशन है, जिस में देश भर की सारी उदार शालाएँ सम्मिलित हैं। दूसरा एक 'लिबरल ऐग्रीमेंटेशन' है, और एक 'लिबरल पब्लिकेशन डिपार्टमेंट', एक 'विमेन्स लिबरल फेडरेशन', एक 'लिबरल काउंसिल', एक 'लिबरल नौजवान सघ', एक 'लिबरल एंड रेडीकल कैंडीडेट्स एसोसिएशन', एक 'समर स्कूल्स कमेटी' और देश भर में सात मशहूर क्लब हैं। इस दल के विचारों का सब से मशहूर समाचार-पत्र 'माचेस्टर गार्डियन' है।

'मजदूर दल' का जन्म सन् १९०० में हुआ था। सन् १८६६ ई० में ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर के सारी मजदूर संस्थाओं को मिल कर एक राजनैतिक मजदूर दल बनाने का बुलावा दिया था, और इस बुलावे के फल-स्वरूप मजदूर संघों, समाजवादी संस्थाओं, स्थानिक उद्योग-समितियों और सहकारी संस्थाओं के मेल से मजदूर दल कायम हुआ था। इस के बाद 'मजदूर-प्रतिनिधि-समिति' कायम कर के पार्लियमेंट में मजदूर पक्षी सदस्यों का एक ऐसा अलग समूह कायम करने का निश्चय किया गया था, जो 'मजदूर हितैषी कानून बनाने में हर एक दल से मिल कर काम करने और मजदूरों के विरोधियों से दूर रहने' का हमेशा प्रयत्न करे। पहले ही वर्ष में चालीस मजदूर सघों, जिन के करीब साढ़े तीन लाख मजदूर सदस्य थे; करीब छः स्थानिक उद्योग समितियाँ जिन के एक लाख सदस्य थे, और तीन समाजवादी संस्थाएँ

जिन के तेईस हजार सदस्य थे, इस दल में शरीक हो गई। मगर पार्लामेंट के लिए खड़े होनेवाले १५ उम्मीदवारों में से पहले वर्ष में सिर्फ दो ही को सफलता मिली। दूसरे चुनाव में दो से बढ़ कर इस दल के पार्लामेंट में २१६ सदस्य हो गए और फिर हर चुनाव में इस दल की शक्ति बढ़ती गई। सन् १९१८ ई० में मजदूर दल की पुनर्घटना की गई, जिस के अनुसार मजदूर दल में सम्मिलित सम्पाद्या के सदस्यों के अलावा मजदूर दल के द्वार दल के उद्देश्यों का माननेवाले हर एक आदमी के लिए खोल दिए गए। इस निश्चय के बाद मजदूर दल थोड़ी सी सम्पाद्या की एक सघन रह कर पूरे तरीके पर एक राजनैतिक दल बन गया और कुछ ही समय में देश भर में मजदूर दल की शाखाएँ फैल गईं। मजदूर दल अपना मुख्य उद्देश्य मजदूर पेशा लोगों को उन की मजदूरी का पूरा फल प्राप्त कराना और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पैदावार का उचित बाँट करने के लिए पैदावार के ज़रियों पर समाज का रुझान और सार्वजनिक शासन और नियंत्रण कायम करना मानता है। इसी नीति को पूरा करने के लिए यह दल आम प्रजा की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति खास कर मजदूर पेशा लोगों की उन्नति करने, दूसरे देशों की मजदूर संस्थाओं से सहकार करने, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिमय उपायों से सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए सारे राष्ट्रों का एक सघन बनाने के कार्य में काम का भोसमर्थक है। इस दल की मुख्य संस्थाओं में 'राष्ट्रीय मजदूर दल', 'स्वतंत्र मजदूर दल', 'लेबर रिटर्च डिपार्टमेंट', 'फेबियन सोसायटी', 'सोशल डिमोक्रेटिक प्रोडरेशन', 'सोसायटी ऑफ़ लेबर कंट्रोलिन्ग्स' और एक 'नेशनल लेबर क्लब' हैं। इस दल का मुख्य दैनिक पत्र 'डेली हेराल्ड' है।

# आयरलैंड और अल्स्टर की सरकारें—

## १-आयरलैंड की सरकार

### राज-व्यवस्था

बारहवीं सदी में जब से अंग्रेजों ने आयरलैंड पर विजय प्राप्त की तब से आयरलैंड बराबर अंग्रेजों को तंग करता चला आता था। हमेशा अंग्रेज राजनीतिज्ञों के सामने आयरलैंड की समस्या मुँह बाएँ प्यड़ी रहती थी। सन् १८५० ई० तक आयरलैंड की समस्या के धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों पहलू थे। आयरलैंड के उत्तर और उत्तर-पूर्व के पाँच जिलों में अर्थात् अल्स्टर प्रांत में बसने वाले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से आये हुए लोग प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के थे और शेष ६ देश के लोग रोमन कैथोलिक पंथ के थे। फिर भी इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंट चर्च आयरलैंड का संयुक्त-राष्ट्रीय-चर्च माना जाता था। आयरलैंड के लोगों को इंग्लैंड के इस प्रबंध के प्रति धार्मिक विरोध था। दूसरे लूट-खसोट और ज़न्तियाँ कर के आयरलैंड की सारी ज़मीन के मालिक अंग्रेज ज़मींदार बन बैठे थे और आयरलैंड-निवासी फ़ैवल गरीब किसान बन गए थे। तीसरे आयरलैंड को जो कुछ थोड़ी-थोड़ी शासन-सत्ता १८ वीं सदी में थी वह भी उस से छीन ली गई थी और उस पर अन्य उपनिवेशों की भाँति लंदन से निरकुंश शासन होता था। बाद में सन् १८६६ ई० में इंग्लैंड और आयरलैंड का चर्च अलग कर दिया गया, जिस से इंग्लैंड और आयरलैंड का धार्मिक भगड़ा खत्म हो गया। सन् १८७० ई० से ज़मीन के संबंध में भी क़ानून बनना शुरू हुए और १९१४ ई० तक लगभग ज़मींदारी का प्रश्न भी हल हो गया; परंतु राजनैतिक प्रश्न बहुत दिनों तक हल नहीं हुआ।

सन् १८०० ई० तक आयरलैंड की पार्लामेंट इंग्लैंड से अलग थी। सन् १८०० ई० में आयरलैंड की पार्लामेंट और ब्रिटिश पार्लामेंट में एक कानून पास हुआ जिस के अनुसार आयरलैंड की पार्लामेंट को तोड़ कर आयरलैंड को ब्रिटेन से मिला दिया गया। आयरलैंड की पार्लामेंट में अधिकतर अंगरेज सदस्य थे। तब पर भी रिश्तों के बर यह कानून पास कराया गया था। आयरलैंड वासियों की मर्जी से यह कानून पास नहीं हुआ था। अस्तु, आयरलैंड वासियों ने प्रारम्भ ही से इस प्रबंध के विरुद्ध आवाज उठाई। ऐमेट नाम के नौजवान एक उड़े होनहार वैरिक्टर ने तो इंग्लैंड के विरुद्ध सन् १८०३ ई० में डबलिन में खल्लमखुल्ला विद्रोह ही खड़ा कर दिया। परन्तु उस को पकड़ कर फाँसी दे दी गई और विद्रोह बुचल दिया गया। बाद में भी इसी प्रकार की बहुत-सी दुर्घटनाएँ होती रहीं। आखिरकार सन् १८३४ ई० में डेनीयल ओ'कॉनोल् के नेतृत्व में आयरलैंड में एक राजनैतिक दल बना, जिस का उद्देश्य "शांतिमय उपायों से आयरलैंड में स्वराज्य कायम करना था।" इस आंदोलन को १८४३ ई० में सरकार की तरफ से दबा दिया। अस्तु, फिर क्रांतिकारियों की तरफ से सरकारी अफसरों पर हमले शुरू कर दिए गए। सन् १८४८ ई० में 'फ्रीनियन ब्रदरहुड' नाम की एक संस्था कायम हुई, जिस का उद्देश्य, आयरलैंड में हिंसात्मक उपायों से पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित करना था। इस संस्था की स्थापना अमेरिका में बसे हुए आयरलैंड प्रवासियों ने की थी और इस की तरफ से बाद में बहुत से सरकारी अफसरों के खून किए गए। सरकार की ओर से भी खून दमना हुआ। तीन वर्ष तक दोनों तरफ की मार काट जारी रही और इंग्लैंड और आयरलैंड का वैर भाव बढ़ता ही रहा।

डेनीयल ओ'कॉनोल् इत्यादि बहुत से आयरलैंड के नेताओं को 'फ्रीनियन ब्रदरहुड' की हिंसात्मक नीति पसंद नहीं थी। वे शांतिमय उपायों से इंग्लैंड का हृदय पलटने के पक्षपाती थे। अस्तु, सन् १८७० ई० में डबलिन में ग्राइजक बट की अध्यक्षता में एक सम्मेलन कर के फिर से, "शांतिमय उपायों से आयरलैंड के लिए संस्थानिक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए" एक 'होमरूल लीग' बनाई गई। सन् १८७४ ई० में इस लीग की तरफ से ब्रिटिश पार्लामेंट में आयरलैंड के सात प्रतिनिधि चुन कर आए। आयरलैंड का मोतीलाल नेहरू प्रख्यात चार्ल्स स्पीवार्ट पारनेल इस दल का इंग्लैंड की पार्लामेंट में नेता था। उस ने अपने दल को सुसज्जित कर के इस होशियारी से पार्लामेंट की नाक में दम करना शुरू किया कि जिन आयरलैंड की माँगों को सुन कर ब्रिटिश पार्लामेंट के सदस्य अबहेलना से मुँह सिकोड़ा करते थे, वही माँगें उन की पार्लामेंट के लिए बाद में एक समस्या बन गई। उदार दल को आयरलैंड की इस पार्टी की सहायता के बिना पार्लामेंट में अपने प्राण बचाने मुश्किल हो गए। लांगर हो कर ग्लेड्स्टन ने सन् १८८६ ई० में आयरलैंड को संस्थानिक स्वराज्य दिलाने के लिए पार्लामेंट में एक बिल पेश किया जो पास नहीं हुआ। सन् १८८३ ई० में ग्लेड्स्टन ने प्रधानमंत्री बनने पर चैन ही मसविदा पत्र पेश किया और फिर हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के विरोध के कारण वह मसविदा पास न हो सका। बाद में 'पार्लामेंट बिल' पास हो जाने पर हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के पने

घिस जाने पर फिर सन् १९१२ ई० में उदार-दल की तरफ से आयरलैंड को स्वराज्य देने के लिए एक मसविदा पेश किया गया, और हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के विरोध करने पर भी वह पार्लियामेंट में सन् १९१४ ई० में पास हो गया। अल्स्टर प्रांत के छः जिलों ने शेष आयरलैंड से मिलना स्वीकार नहीं किया, इस लिए उस प्रांत की एक अलग पार्लियामेंट बनाने का प्रयत्न किया गया। मगर इसी बीच में यूरोपीय महासमर छिड़ गया और सारे काम छोड़ कर ब्रिटिश सरकार को एकदम युद्ध में जुट जाना पड़ा। आयरलैंड को स्वराज्य देने का कानून पास हो जाने पर भी उस पर अमल न हो सका, मगर ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह वादा कर दिया गया कि युद्ध खत्म होते ही कानून पर अमल किया जायगा।

आयरलैंड के नरम-दल के नेता मिस्टर रेटमंड इत्यादि इस वादे से सन्तुष्ट हो कर ब्रिटिश सरकार को युद्ध में विजय प्राप्त कराने के लिए सहायता करने लगे। उत्तर से ले कर दक्षिण तक सारे देश में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्तियाँ शुरू हो गईं। ऐसा मालूम होता था कि सारा आयरलैंड सन्तुष्ट हो गया है। एक वर्ष तक देश भर में त्रिभुल शांति रही। परन्तु भीतर ही भीतर असंतोष की आग भड़क रही थी। साल का अन्त आते-आते ऐसी घटनाएँ घड़ी होने लगीं जिन का सरकार ने स्वप्न भी नहीं देखा था। चारों तरफ से "फौरन् आयरलैंड में स्वराज्य" स्थापित करने के लिए माँगें उठने लगीं। सैनिकों की भर्तियाँ भी कम हो गईं और आयरलैंड के पश्चिमी किनारे से जर्मनी के जहाजों को ज़रूरत का सामान मिलने लगा। पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपातियों की आयरलैंड में संख्या बढ़ने लगी। 'सीनपीन' संस्था जो आयरलैंड के लिए पूर्ण स्वाधीनता की पक्षपाती और अँगरेजों को आयरलैंड से त्रिभुल निकाल देने की हामी थी, जोर पकड़ने लगी। सन् १९०५ ई० से आर्थर ग्रिफिथ के नेतृत्व में यह संस्था काम कर रही थी। परन्तु आज तक उस को अधिक सफलता नहीं मिली थी। सन् १९१२ तक सीनपीन लोगों की आयरलैंड में गैरजिम्मेदार और बक़्वासी समझा जाता था। मगर अल्स्टर प्रांत के आयरलैंड की स्वाधीनता का विरोध करने और इंग्लैंड के यूनियनिस्ट दल के अल्स्टर प्रांत की इस आंदोलन में सहायता करने के बाद से आयरलैंड में 'सीनपीन' दल का जोर बढ़ने लगा था और १९१४ ई० तक सीनपीन दल का जोर काफी बढ़ गया। लड़ाई शुरू हो जाने के बाद एक वर्ष तक इस दल के नेता अँगरेजों से ऊपर से मिले रहे और भीतर भीतर आयरलैंड में पूर्ण स्वाधीनता स्थापित करने के आंदोलन की तैयारी करते रहे। उन का विचार था कि जर्मनी से मिल कर अँगरेजों को आयरलैंड से निकाला जा सकेगा। आखिरकार सन् १९१६ ई० में ईस्टर के बाद के सोमवार के दिन इस दल की ओर से डबलिन में खुला विद्रोह खड़ा कर दिया गया और सीनपीन दल ने आयरलैंड को प्रजातन्त्र एलान कर के डी वेलेरा को उस का प्रमुख चुन लिया। यह विद्रोह फौरन् ही दबा दिया गया। फिर भी इस घटना से सत्तार की दृष्टि आयरलैंड की तरफ ज़रूर पड़ी। इस के बाद आयरलैंड के लोगों और ब्रिटिश सरकार में एक प्रकार का युद्ध ही छिड़ गया। सरकार की तरफ से 'मारशल ला' जारी कर दिया गया और क्रांतिकारियों की तरफ से हथियार उधर अक्सर बर और गोलिएँ बरस उठतीं।

यूनन से आयरिश नौजवान पॉलिशों पर लटका गए, और बहुत से सरकारी अफसरों की जानें चली गईं, आयरलैंड में 'सीनफीन' शब्द प्रख्यात और प्यारा होने लगा था। सीनफीन दल का नेता डी वेलेरा देश का अधिनायक बन गया और लोग उस की ओर आशा की दृष्टि से देखने लगे। सन् १९१८ ई० के ब्रिटिश पार्लामेंट के चुनाव में आयरलैंड की ओर से १०५ सदस्यों में से ७३ सीनफीन चुने गए। यह सदस्य ब्रिटिश पार्लामेंट में बैठने नहीं गए उन्होंने ने पब्लिक में अपनी एक अलग सभा बना कर प्रजातन्त्र आयरलैंड की एक शासन व्यवस्था पार कर ली, जिस राज व्यवस्था के अनुसार आयरलैंड में सारी सत्ता एक व्यावस्थापक भा, प्रजातन्त्र के प्रमुख, और एक मंत्रि मंडल में रखी गई थी।

मगर इंग्लैंड ने इस राज व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। आयरलैंड के पानन यादियों ने प्रेसीडेंट रिल्मन, फ्रांस, इटली और सवि-सम्मेलन सभी के द्वार सदस्यता र आयरलैंड को एक स्वाधीन और स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राष्ट्र मजूर कराने का बहुत प्रयत्न किया। मगर नहीं से उन को कोई सहायता नहीं मिली। सन् १९१९ ई० में डी वेलेरा गिरंजा की जेल से निकल कर अमेरिका भाग गया। वहाँ जा कर उसने आयरलैंड की स्वाधीनता के लिए आंदोलन शुरू किया। इधर आयरलैंड में मारकाट जारी रही। सीनफीनों की कायम की हुई सरकार को ब्रिटिश सरकार काम नहीं करने देती थी, और सीनफीन मारकाट र के ब्रिटिश सरकार का शासन बद करने का प्रयत्न करते थे। रोज़ मर्ती-सड़नों पर खून खेते थे। आखिरकार लॉर्ड जॉर्ज ने सन् १९२० में समझौते की बात चलाई और सन् १९२१ में ब्रिटिश सरकार और आयरलैंड के नेताओं में एक सधि हुई जिस के अनुसार आयरलैंड को ब्रिटिश साम्राज्य में इंग्लैंड के बराबरी का भागीदार माना गया। ब्रिटिश साम्राज्य में आयरलैंड ही एक ऐसा भाग है जिस ने अपनी राज-व्यवस्था को अपने आप ढा है। इस राज व्यवस्था में बाद में सन् १९२८ में बहुत-से परिवर्तन किए गए। आयरलैंड की इस राज-व्यवस्था के अनुसार सारी राजनैतिक सत्ता आयरलैंड की प्रजा के प्रधीन मानी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत, धार्मिक विचार और मिलने-जुलने की पूरी आजादी मानी गई है। किसी को बिना कारण जेल में उद नहा रक्खा जा सकता है, और हर एक को प्राथमिक शिक्षा मुक्त पाने का अधिकार है। कानून बनाने की सत्ता ब्रिटिश राज दून और व्यवस्थापक सभा की दो सभाओं—सिनेट और प्रतिनिधि सभा—में रखी गई है। आयरलैंड ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर केनेडा की ही हैसियत का एक भाग है। परंतु एक तरह से केनेडा और आयरलैंड की राज व्यवस्था में बड़ा फर्क भी है। एक तो ब्रिटिश सरकार और आयरलैंड के नेताओं में जो समझौता हुआ था, उस को 'सधि' कहा गया है, जो मिक दो बराबर के राष्ट्रों में होती है। दूसरे आयरलैंड में साम्राज्य के दूसरे भागों की तरह गवर्नर जनरल भी है और साथ ही वहाँ की कार्य कारिणी के मुख्य अधिकारी को जिस की साम्राज्य के दूसरे दोमिनियम स्टेट्स प्रांत देशों के प्रधान मंत्री की सत्ता होती है, प्रेसीडेंट अर्थात् प्रधान या प्रमुख कहते हैं, जो आम तौर पर प्रजातन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रपति को कहा जाता है। इन शब्दों के शायद आयरलैंड के प्रजातन्त्रवादी दल को बदलाने के लिए रहने

१ प्रजातन्त्र दल की सरकार बनने ही पर इस पद का अंत कर दिया गया है।

दिया गया होगा<sup>१</sup>। मगर इन से आयरलैंड की बग़िश साम्राज्य में एक खास हैसियत हो गई है, जिस से नई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं।

## २—व्यवस्थापक-सभा

आयरलैंड की प्रतिनिधि सभा को डेल ग्राइरीन कहते हैं। उस में १५० सदस्य होते हैं, जिन को चार साल के लिए २१ वर्ष के ऊपर के सब स्त्री पुरुष नागरिक अनुपाते निर्वाचन की पद्धति के अनुसार चुनते हैं। हर मतदार<sup>२</sup> को उम्मीदवार बनने का भी हक होता है। व्यवस्थापक सभा की दूसरी सभा सिनेट में ६० सदस्य होते हैं, जिन के एक तिहाई भाग को हर तीसरे साल देश की खास सेवा करने या खास योग्यता होने की बुनियाद पर डेल ग्राइरीन के सदस्य मिल कर चुनते हैं, नौ साल के लिए चुनते हैं। उन की उम्र कम से कम तीस साल होने की क़ैद रखनी गई है। व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को वेतन दिया जाता है। एक सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता है। डेल में मज़ूर हुए साधारण कानूनी मसज़िदों को सिनेट को सशोधित करने या २७० दिन तक रोक रखने या प्रजा के हवाले के लिए भिजवाने का अधिकार होता था। बाद में राज व्यवस्था में सशोधन कर के सिनेट से मसज़िदा को हवाले के लिए भिजवाने का अधिकार ले लिया गया। अब डेल से गए हुए मसज़िदों को केवल १८ मास तक सिनेट रोक रख सकती है। यदि समय पूरा हो जाने के बाद डेल में फिर वही मसज़िदा पास होने पर एक निश्चित समय में अगर सिनेट उसे मज़ूर नहीं करती है, तो वह मसज़िदा व्यवस्थापक सभा से मज़ूर माना जाता है और कानून बन जाता है। आय-व्यय सबही मसज़िदे पेश करने का सिर्फ़ कार्य कारिणी का अधिकार होता है और उन को मज़ूर-नामज़ूर करने का अधिकार सिर्फ़ डेल को होता है। मगर उन को सिनेट के पास सिनेट की सिफारिश जानने के लिए भेजा जाता है और वहाँ से हकीस दिन के भीतर ही वे अवश्य लौट कर डेल के पास आ जाते हैं, जिस के बाद डेल को उन पर पूरा अधिकार होता है। व्यवस्थापक-सभा से मज़ूर हुए कानूनों के लिए 'राज छन' की मज़ूरी की आवश्यकता होती है। राज छन को कानूनों को मज़ूर या नामज़ूर करने या एक साल तक रोक रखने का अधिकार होता है।<sup>३</sup>

## ३—कार्यकारिणी

पाँच या छ या सात मंत्रियों के एक मन्त्रिमंडल की मन्त्रिमंडल के प्रधान की सिफारिश पर गवर्नर जनरल कार्यकारिणी का काम चलाने के लिए नियुक्त करता है। मन्त्रिमंडल के चार सदस्यों को डेल का सदस्य होने और उन में प्रधान, उपप्रधान और अर्थ-सचिव अवश्य होने की राज-व्यवस्था में शर्त रखी गई है। मन्त्रिमंडल सिर्फ़ डेल को जवाबदार माना गया है, सिनेट को नह। कार्यकारिणी के प्रधान को डेल चुनती है और प्रधान एक उपप्रधान को नियुक्त करता है। दूसरे मंत्रियों

<sup>१</sup> परंतु गवर्नर जनरल के पद का अंत हो जाने से राष्ट्रपति शब्द अब बहुत कुछ सार्थक हो गया है।

<sup>२</sup> इस अधिकार को भी प्रजातन्त्रवादी सरकार अब स्वीकार नहीं करती।

को प्रधान डेल की सलाह से नियुक्त करता है। मन्त्रि-मंडल की डेल को सम्मिलित जवाब दारी होती है और डेल का विश्वास उस में न रहने पर सारा मन्त्रि-मंडल एक साथ इस्तीफा दे देता है। मगर इस्तीफा दे देने के बाद भी नया मन्त्रि-मंडल न बन जाने तक पुराना ही काम चलाता है। मन्त्रि-मंडल के सदस्यों को व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं में बोलने का अधिकार होता है।

## ४—स्थानिक-शासन और न्याय-शासन

आयरलैंड का स्थानिक शासन और न्यायशासन इंग्लैंड से मिलता जुलता है।

## ५—राजनैतिक दल

आयरलैंड और ब्रिटिश सरकार में सन् १९२१ में जो समझौता हुआ उस के अनुसार आयरलैंड का उत्तरी भाग अल्स्टर आयरलैंड से अलग हो गया। यह बात आयरलैंड को एक 'स्वतंत्र प्रजातन्त्र राष्ट्र' बनाने का स्वप्न देखनेवाले प्रजातन्त्रवादियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने ने हथियार उठा कर सरकार का विरोध शुरू किया, जो एक साल के भीतर ही दबा दिया गया। पुराने सीनफीन दल के एक भाग ने कौंसप्रेव के नेतृत्व में नई राज-व्यवस्था को मंजूर कर के उस पर अमल शुरू किया और दूसरे भाग ने डी वेलोरा के नेतृत्व में आयरलैंड को 'स्वाधीन प्रजातन्त्र राष्ट्र' बनाने का आंदोलन जारी रखा। सन् १९२३ ई० में नई राज-व्यवस्था के अनुसार पहला चुनाव हुआ जिस में डी वेलोरा के दल ने भी भाग लिया और १५३ में से ५१ सदस्य इस दल के चुने गए। मगर डी वेलोरा के प्रजातन्त्रवादी सदस्यों ने इंग्लैंड के राजछत्र के प्रति स्वामिभक्ति की शपथ ले कर डेल में बैठना स्वीकार नहीं किया और इस लिए वे डेल की कार्यवाही से दूर रहे। सन् १९२५ ई० में अल्स्टर और आयरलैंड के एकिकरण के प्रश्न पर एक कमीशन विचार करनेवाला था। परन्तु इस कमीशन ने यह प्रश्न जेसा का तैसा छोड़ दिया, जिस से कौंसप्रेव की सरकार काफी बदनाम हो गई। मगर प्रजातन्त्रवादियों के डेल से बाहर रहने के कारण कौंसप्रेव के दल की सरकार कायम रही। बाद में सन् १९२७ ई० के दूसरे चुनाव के बाद हिंसात्मक प्रजातन्त्रवादियों में से किसी ने कौंसप्रेव दल के उपप्रधान को मार डाला, जिस से कौंसप्रेव ने हिंसावादियों को बिल्कुल दबा दिया। सरकारी सत्ता का मान बढ़ाने के लिए कौंसप्रेव ने चुनाव के लिए खड़े होने के लिए स्वामिभक्ति की शपथ, एक कानून द्वारा अनिवार्य बना कर डी वेलोरा के अहिंसात्मक प्रजातन्त्रवादियों को भी—स्वामिभक्ति की शपथ लेने के लिए मजबूर कर दिया। डी वेलोरा के दल को मजबूर हो कर शपथ लेनी पड़ी। मगर उन्होंने ने साफ़ एलान कर दिया कि सिर्फ़ कानूनी शर्त पूरी करने के लिए वे शपथ लेते हैं और इस लिए शपथ लेने के बाद भी वे राजछत्र के प्रति स्वामिभक्ति के लिए अपने आप को पाबंद नहीं समझेंगे।

आयरलैंड को प्रजातन्त्र बनाने के अतिरिक्त डी वेलोरा का 'फ़ायना फेल' नाम का प्रजातन्त्रवादी दल आयरलैंड को क्रौरन ब्रूटेन की आर्थिक गुलामी से मुक्त करने में विश्वास रखता है। आयरलैंड के किसानों को जमींदारों से—जो अधिकतर अंगरेज थे—जमीन खरीदने



में सहायता करने के लिए आयरलैंड की तरफ से इंग्लैंड से कर्जा लिया गया था, और इस कर्ज को अदा करने के लिए आयरलैंड के खजाने से लगभग तीस लाख पौंड सालाना की किश्त दी जाती। फायना फेल दल इस किश्त को नाजायज़ मानता था और जैसे ही इस दल की सरकार बनी, यह किश्त बंद कर दी गई, जिस पर इंग्लैंड में बड़ा शोर मचा। कौमग्रेव का दल ब्रिटिश बाजार में बेचने के लिए देश में मक्खन और गायें इत्यादि बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता देने के पक्ष में है। फायना फेल दल आयरलैंड में राद्य-पदार्थ और अनाज पैदा कराने की नीति में विश्वास रखता है। सन् १९३२ ई० के चुनाव में फायना फेल दल के ताकत में आ जाने पर डी वेलेरा ने अपनी नीति पर अमल शुरू कर दिया है, और वह धीरे धीरे आयरलैंड को संपूर्ण स्वाधीनता की तरफ ले जा रहा है।

डी वेलेरा के प्रजातन्त्रवादी 'फायना फेल दल' और कौमग्रेव के 'आयरिश लीग दल' के अतिरिक्त आयरलैंड के छोटे छोटे दलों में एक 'मज़दूर दल', एक 'किसान दल', एक 'स्वतंत्र दल', एक हिंसावादी प्रजातन्त्रवादियों का 'सीनफीन दल' और एक 'राष्ट्रीय संघ दल' भी हैं।

---

## १—अल्स्टर की सरकार

### १—राज-व्यवस्था

उत्तरी आयरलैंड के छः जिले, जो 'अल्स्टर' के नाम से प्रख्यात हैं, 'ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संयुक्तराज्य' का भाग हैं। ब्रिटिश राजछत्र का प्रतिनिधि एक लार्ड लेफ्टीनेन्ट नाम का अधिकारी राजा की ओर से अल्स्टर की व्यवस्थापक सभा के मज़ूर किए हुए कानूनों को मज़ूर या नामज़ूर करता है। एक माल तक किसी भी मन्त्रिदे को यह शक्ति नहीं मिल सकती है, जो यह समय पूरा होने के बाद कानून हो जाता है। यही अधिकारी व्यवस्थापक सभा की बैठकें बुलाता और बंद करता है। तरह तरह के अल्स्टर की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुन कर जाते हैं।

### २—व्यवस्थापक-सभा

अल्स्टर की व्यवस्थापक सभा की दो सभाएँ होती हैं—एक गिनेट और दूसरी हाउस ऑफ़ कामन्स। कामन्स राजा के ५२ प्रतिनिधियों की सभा होती है। उस के सदस्यों का उर्नी चुनाव क्षेत्रों से अनुपात निर्वाचन के अनुसार चुना होता है, जिन से ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए सदस्यों का होता है। गिनेट में २६ सदस्य होते हैं। चीफ़ के अल्स्टर की कामन्स सभा चुनती है; वेल्फ़ास्ट और लंडनडेर्री के दो मेयर अपने पद की बुनियाद पर गिनेट में बैठते हैं। आय वषय के मन्त्रिदे कामन्स में शुरू होते हैं और सिनेट उन में परिवर्तन नहीं कर सकती है। कामन्स के किसी मन्त्रिदे को सिनेट के दो बार नामज़ूर कर देने पर दोनों सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में उस मन्त्रिदे पर निर्धार कर के फैसला कर लिया जाता है। कामन्स के सदस्यों को खर्च के लिए २०० पौंड सालाना दिया जाता है।

### ३—कार्यकारिणी

कार्यकारिणी सत्ता लार्ड लेफ्टीनेन्ट और व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार एक मन्त्रि मंडल में होती है। सेना, परराष्ट्र विषय, मिलक्रियत जन्म करने के, धार्मिक समता क़ायम रखने के, और कुछ आर्थिक अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकार में रखे गए हैं। अल्स्टर की आर्थिक स्वतन्त्रता भी सीमित है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अल्स्टर के ६० फी सदी कर एकन करती है।

## फ्रांस की सरकार

### १—राज-व्यवस्था

इंग्लैंड के बाद यूरोप के देशों में फ्रांस से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है। जिस प्रकार क्राइय की इंग्लैंड की सरकार ने पीठ टोकी, अगर उसी प्रकार डुपले की फ्रांस की सरकार ने सहायता की होती, तो शायद आज भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थान में फ्रेंच साम्राज्य होता और थोड़े से इधर-उधर छोटे-मोटे शहर ही फ्रांस के अधिकार में न रह गए होते। परंतु फ्रांसीसी साम्राज्य फैलाने की कला में इतने निपुण नहीं हैं जितने अंगरेज। भारतवर्ष में फ्रेंच साम्राज्य होने पर भी हमारे देश की राजनैतिक संस्थाओं के विकास में अधिक भेद नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रांस की सरकार का संगठन भी लगभग उन्हीं सिद्धांतों पर किया गया है। दोनों के रूप-रंग और चलन में बहुत समानता है। फ्रांस की भयंकर राज्यक्रांति ने भी सिर्फ यूरोप ही नहीं, संसार भर का हृदय हिला दिया था। उस ने काली की तरह मुर्दे के ढेर पर खड़े हो कर मानव-जाति को एक ऐसे नए संसार की तरफ आने को हुंकारा था, जिस में 'स्वाधीनता, समानता और भ्रातृ-भाव' हो। इंग्लैंड के प्रख्यात राजनीतिज्ञ डिसरादली का तो यहाँ तक कहना था कि 'इतिहास में केवल दो ही घटनाएँ हुई हैं; एक दाय का घेरा और एक दूसरी फ्रांस की राज्यक्रांति।' डिसरादली का वाक्य अतिशयोक्ति मान लेने पर भी यह तो निश्चय ही है कि फ्रांस की राज्य क्रान्ति ने विचारों का एक नया प्रवाह बहा कर यूरोप की आधुनिक सरकारों का रूप-रंग बदल डाला। अतः, हर प्रकार से इंग्लैंड के बाद फ्रांस की राज-व्यवस्था का ही अध्ययन करना हमारे लिए उचित होगा।

फ्रांस की राज्य क्रांति ने आठ सौ वर्ष से चलती आनेवाली राज व्यवस्था फ्रांस में उलट डाली। यह राज-व्यवस्था निरंकुश राजाशाही थी। राजाशाही के सिद्धांत के अनुसार राजा के सिर पर स्वयं ईश्वर मुकुट रखता था और कोई नहीं। अस्तु, प्रजा के लिए कानून बनाना और प्रजा पर शासन करना राजा ही का अधिकार होता था और किसी का नहीं। देश भर पर एक केंद्रित नौकरशाही का चक्र चलता था और पेरिस के दरबार में बैठनेवाले राजा के छ मंत्रियों और लगभग चालीस सलाहकारों के सिवाय जनता की आवाज़ का राज व्यवस्था में कहीं कोई स्थान नहीं था। स्थानिक-स्वशासन का भी प्रजा को अधिकार सिर्फ नाम के लिए था।

जिस काल में इंग्लैंड में पार्लामेंट का विकास हुआ, उसी समय में फ्रांस में 'एस्टेट्स जेनरल' नाम की सभा का विकास हुआ था। इस सभा के तीन भाग थे—एक सरदार और अमीरों की सभा, दूसरी पादरियों की सभा और तीसरी मध्यम श्रेणी के लोगों की सभा। पहली दोनों सभाओं के विचार प्रायः हर विषय पर मिलते थे और वे दोनों मिल कर हमेशा मध्यम श्रेणी की सभा की आवाज़ दबा देती थी। इंग्लैंड की पार्लामेंट की तरह एस्टेट्स जेनरल का फ्रांस की राजनीति में स्थान नहीं था। कुछ समय के बाद तो राजा ने एस्टेट्स जेनरल को बुलाना भी बंद कर दिया था, और सिर्फ जब प्रजा से धन वसूल करने की आवश्यकता होती थी, तब एस्टेट्स जेनरल को बुला कर उस की सहायता से कर वसूल किया जाता था। एस्टेट्स जेनरल के सदस्यों को राजा के सामने प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई शासन अथवा आय व्यय इत्यादि में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। जिस प्रकार हमारे देश के कुछ रजवाड़ों में आजकल नाम की व्यवस्थापर सभाएँ हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए बुलाई जाती हैं, उसी तरह फ्रांस में सन् १७८९ ई० में एस्टेट्स जेनरल नाम की सभा थी। फ्रांस के कुछ प्रांतों में भी 'स्थानिक एस्टेट्स' सभाएँ थीं। परंतु वे भी राष्ट्रीय एस्टेट्स की बाँदी के अतिरिक्त और कुछ नहीं थीं। अमीर, उमरावों, सरकार के पुछलागुओं और पिददुओं की पाना भी में रहती थीं। साधारण आदमी की बात पूछनेवाला कोई नहीं था। किसी भी आदमी को बिना कसूर बताए पकड़ कर जेल में बंद किया जा सकता था। पादरियों और सरदारों से नाम मात्र का कर लिया जाता था और बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होने तथा किसानों से काम लेने की उन्हें ठेकेदारी-सी दे दी गई थी।

दस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठी, और जिस तूफान की धूल फ्रांस के आकाश में बहुत दिनों से उठती हुई दिखाई दे रही थी, उस ने सन् १७८९ ई० में जोर से आ कर फ्रांस के अमागे राजा लुई और उस की राज व्यवस्था को उलट पुलट कर पक दिया और सारे पुराने निचारों और निशानों की जड़ हिला डाली। २६ अगस्त सन् १७८९ ई० को फ्रांस के प्रतिनिधियों ने एक हो कर 'मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का एक एलान किया' जिस के पहले भाग में निम्न लिखित सिद्धांतों का समावेश था—

१—मनुष्य स्वतंत्र पैदा होने हैं, और वे अधिकारों में स्वतंत्र और समान हैं।

२—सारी राजनीति मन्थानों का केवल एक ही उद्देश होता है कि वे मनुष्य के

प्राकृतिक और अद्विज अधिकारों की, जैसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जान माल की रक्षा, अन्याय का विरोध करने के अधिकारों की रक्षा करें।

३—प्रभुता प्रजा अथवा राष्ट्र की है और राष्ट्र की अनुमति के बिना किसी सत्ता या किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

४—स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि जिस काम से किसी दूसरे को नुकसान न पहुँचे उस के करने का सब को अधिकार है।

५—कानून प्रजा की इच्छा व्यक्त करता है और हर एक आदमी को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा कानून बनाने में भाग लेने का अधिकार है।

६—कानून सब के लिए एक है।

अधिकारों के इस एतान में विरोधकर इन बातों पर भी जोर दिया गया था कि गैर कानूनी तरीके से किसी को गिरफ्तार या कैद नहीं किया जायगा, सब को धार्मिक विश्वास, भाषण, लिखने और बोलने की स्वतन्त्रता रहेगी, स्वयं अथवा प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कर के सन्ध में मत देने का अधिकार होगा, गैर-कानूनी तरीके से किसी का माल या जायदाद जप्त नहीं की जायगी और अगर सरकार को किसी चीज़ की जरूरत होगी, तो उस का मुआवजा दिया जायगा।

अभी तक यूरोपीय देशों में राज-व्यवस्था लिखित नहीं होती थी, सिर्फ़ रिवाजों पर ही निर्भर रहती थी। परन्तु फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की जो राज-व्यवस्था बनी उस को लिखनी पड़ किया गया। फ्रांस के नेताओं को अलिखित रिवाजी राज-व्यवस्था से लिखित राज-व्यवस्था पसंद आने के कई कारणों में से एक खास कारण यह था कि लिखित राज-व्यवस्था का सर्वसाधारण को आसानी से ज्ञान कराया जा सकता है। फ्रांस इस और कदम बढ़ा कर इस विषय में यूरोप का अग्रगण्य बना और बाद में जर्मनी, इटली, स्पेन आदि अन्य यूरोपीय देशों में भी यही विश्वास बढ़ता गया कि स्वाधीनता की रक्षा के लिए लिखित राज-व्यवस्था अनिवार्य है। प्रजातन्त्र सरकार स्थापित कर के फ्रांस की राज-क्रांति ने यूरोपीय देशों को दूसरा यह सबक भी पढ़ाया कि प्रजातन्त्र ढंग की सरकार न सिर्फ़ फ्रांस के ही लिए उपयुक्त है बल्कि फ्रांस की तरह यूरोप के अन्य पुरातन और माननीय राष्ट्रों में भी स्थापित हो सकती है। वरना अभी तक यूरोप के बहुत से निचारका का यही विचार चला आता था कि प्रजातन्त्र-राज्य केवल छोटे क्षेत्र के राज्यों में स्थापित हो सकता है। क्रांति के बाद नई राज-व्यवस्था का निर्माण करने के लिए फ्रांस की प्रजा के जो प्रतिनिधि एकत्र हुए उन में अधिक सख्या राजाशाही के क्लायम रखने के पक्षपातियों ही की थी, और सन् १७६१ तक इस प्रतिनिधि सम्मेलन ने जो राज-व्यवस्था रच कर तैयार की थी, उस में राजाशाही क्लायम रखी गई थी। परन्तु घटनाओं के चक्र से, राजा की कमजोरी और उस के सकल विमत्त्या और आखिरकार उस के देश छोड़ कर भाग जाने से, राजा के प्रजा मत का विरोध करने और राजा के पिटुष्टों के लगातार पड़थवा से, उक्त कर फ्रांस में सब का मन राजाशाही की तरफ से हट गया, अस्तु २१ सितम्बर सन् १७९२ ई० को प्रजा के प्रतिनिधियों ने मिल कर सन्तत के दफन किया और अगले प्रजातन्त्र

राज्य की फ्रांस में स्थापना की। फ्रांस के बाद फिर इधर-उधर के दूसरे यूरोपीय देशों में भी प्रजातन्त्र की हवा फैली और चारों ओर कई छोटे बड़े प्रजातन्त्र राज्य सज्जे हो गए। इन प्रजातन्त्र राज्यों और फ्रांस के प्रजातन्त्र राज्य को पीछे नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं के सामने अवश्य झुक जाना पड़ा, फिर भी इस समय से यूरोप के लोगो का प्रजातन्त्र में विश्वास हो चला और प्रजातन्त्र सरकार यूरोप के राजनैतिक जीवन का एक अंग बन गई।

पुरानी राजनैतिक संस्थाओं को तोड़ फोड़ कर क्रांति के बाद लगभग सौ वर्ष तक, फ्रांस में तरह-तरह की तन्त्रालियाँ और तन्त्रावे होते रहे। ८४ वर्ष के अरसे में सात विभिन्न राज व्यवस्थाओं पर अमल करने की कोशिश की गई। परन्तु कुछ वर्ष से अधिक उन में से कोई भी राज व्यवस्था न टिक सकी। फिर भी इन तन्त्राओं से राष्ट्र को बहुत कुछ राजनैतिक अनुभव अवश्य हुआ। क्रांति के जमाने में ही तीन राज व्यवस्थाएँ बनाई गई थीं। एक ३ सितंबर सन् १७९१ ई० को नेशनल एसेम्बली ने बना कर तैयार की थी। जिस को अगस्त १० के उपद्रव में भस्मीभूत कर दिया गया। दूसरी १५ फरवरी सन् १७९३ ई० की राज व्यवस्था को कन्वेंशन ने तैयार किया था। परन्तु उस पर भी कभी अमल नहीं हुआ। तीसरी २२ अगस्त सन् १७९५ ई० की दूसरी, कन्वेंशन द्वारा तैयार की हुई राज व्यवस्था पर २३ सितंबर सन् १७९५ ई० से ६ नवंबर सन् १७९६ ई० के अचानक परिवर्तन तक ही सिर्फ अमल हुआ। पहली राज व्यवस्था में सीमित राजाशाही, मंत्री जिन पर कुशासन के लिए मुकदमा चलाया जा सके और एक सभा की और तीन दिन की मजदूरी का कर देनेवाले २५ वर्ष की आयु के ऊपर के मनुष्यों द्वारा चुने हुए ७४५ सदस्यों की एक व्यवस्थापक सभा की योजना की गई थी। सन् १७९३ ई० की दूसरी राज-व्यवस्था में एक ऐसे प्रजातन्त्र की व्यवस्था की गई थी जिस में एक सभा की एक धारासभा होती, इस धारासभा का सारे नागरिक हर वर्ष चुनाव करते, २४ सदस्यों की इस धारासभा द्वारा चुनी हुई एक कार्यकारिणी होती, और जो कानून बनाए जाते उन का अंतिम फैसला सारे देश के नागरिक अपनी अपनी जगह पर सभाओं में एकत्र हो कर करते। इस राज-व्यवस्था को फ्रांस के लोगों ने स्वीकार भी कर लिया था, परन्तु इस पर भी कभी अमल नहीं हुआ। सन् १७९५ ई० की राज-व्यवस्था में भी जिस को भी फ्रांस के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, प्रजातन्त्र की ही व्यवस्था की गई थी। इस के अनुसार धारासभा की दो सभाएँ की गई थीं एक 'पाँच सौ की सभा'¹ और दूसरी 'बड़ों की सभा'²। निचली सभा को कानूनों के मसविदे पेश करने का अधिकार था, ऊपरी सभा सिर्फ उन्हें मंजूर या नामंजूर कर सकती थी, उन में सुधार नहीं कर सकती थी। दोनों के सदस्यों को जनता तीन वर्ष के लिए चुनती और एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर वर्ष होता। कार्यकारिणी पाँच सदस्यों की एक डाइरेक्टरी में रखी गई थी, जिन का पाँच वर्ष के लिए चुनाव होता और जिन का एक सदस्य हर वर्ष बदल जाता था। 'पाँच सौ की सभा' दस नाम चुन कर भेजती। जिन में से पाँच को डाइरेक्टरी के लिए 'बड़ों की सभा' चुन लेती। हमेशा से फ्रांस के सुधारक दो सभा की धारासभा का विरोध करते आते थे। परन्तु इस व्यवस्था में पहली बार दो सभा की

¹ 'काउंसिल ऑफ़ फाइव हंट्रेड' ² 'काउंसिल ऑफ़ एल्डर्स'।

धारासभा की व्यवस्था की गई थी। बाद की सन् १७९६ ई० की राज व्यवस्था, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद, सियेज़ नाम के एक विद्वान् और दो कमीशनो की सहायता से बनाई। इस के अनुसार वह स्वयं फ्रांस का भाग्य विधाता बन बैठा और १८१४ ई० तक लगभग इसी के अनुसार उस ने फ्रांस का शासन चलाया। इस राज व्यवस्था ने एक नए स्वरूप में निरंकुश शासन को फिर से फ्रांस में स्थापित कर दिया था। दो सभाओं की धारासभा के सीवे सादे प्रश्न को तोड़ कर इस राज-व्यवस्था के अनुसार धारासभा का कार्य चार सस्थाओं के सुपुर्द किया गया था। सौ सदस्यों की एक 'ट्रिब्युनेट' नाम की सभा बनाई गई थी जिस का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता था और जिस का काम सिर्फ़ कानूनी मसविदों पर प्रारम्भिक विचार करना था। दूसरी एक 'फोर लेजिस्लाटिव' नाम की सभा थी जिस में पाँच वर्ष के लिए चुने हुए तीन सौ सदस्य होते थे, और जिस का काम ट्रिब्युनेट के भेजे हुए मसविदों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना था। तीसरी सभा एक अस्सी आज़न्म सदस्यों की 'सिनेट' थी जो सिर्फ़ इस बात का फैसला करती थी कि मज़ूर होनेवाले कानून राज-व्यवस्था के अनुसार हैं या नहीं। चुनाव के झगड़ों का भी फैसला यहीं सिनेट करती थी। चौथी सभा कौंसिल ऑफ़ स्टेट थी जिस का काम प्रथम कौंसिल<sup>१</sup> की निगरानी में कानून बनाना और कानूनों की सिफारिश करना था। कौंसिल ऑफ़ स्टेट को प्रथम-कौंसिल नियुक्त करता था। सिनेट का चुनाव सिनेट खुद करती थी। ट्रिब्युनेट और फोर लेजिस्लाटिव का चुनाव उम्मीदवारों की एक सूची में से बड़े धुमाव पिराव से होता था। राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता तीन कौंसलों की एक समिति में रखी गई थी जिन का दस वर्ष के लिए चुनाव होता था और जो अरबों समय तक बार-बार चुने जा सकते थे। कार्यकारिणी सत्ता एक से अधिक के हाथ में रखती तो गई थी, परन्तु यह नाममात्र ही के लिए था। राज-व्यवस्था ने प्रथम-कौंसल को ही सर्वशक्तिमान बनाया था और उस के दूसरे दोनों साथियों को उसे केवल सलाह देने का हक दिया था। सब तो यह है कि इस राज-व्यवस्था ने नागरिक बोनापार्ट के हाथ में जिस को इस राज व्यवस्था में प्रथम-कौंसल माना गया था, फ्रांस के शासन की सारी बागडोर दे दी थी। सन् १८०२ ई० में बोनापार्ट को जिंदगी भर के लिए कौंसल बना दिया गया और १८०४ ई० में कंग्रेट-सरकार साम्राज्य में परिणत हो गई। फिर नेपोलियन बोनापार्ट के राज्यच्युत होने के तीन सप्ताह बाद ३ मई सन् १८१४ ई० को फ्रांस की गद्दी से उतारा हुआ बूर्बन खानदान का राजा लुई १८ वॉ पेरिस में प्रवेश कर के फ्रांस के सिंहासन पर जब आ बैठा तब एक नई राज-व्यवस्था का एलान किया गया, जिस को तीन राजा के प्रतिनिधियों, नौ सिनेट के सदस्यों और नौ फोर लेजिस्लाटिव के सदस्यों के एक कमीशन ने तैयार किया था। सन् १८३० ई० के थोड़े से सुधारों के सिवाय यह राज व्यवस्था जैसी की तैसी फ्रांस में सन् १८४८ ई० की क्रांति तक कायम रही। इस राज-व्यवस्था को इंग्लैंड की राज व्यवस्था के ढंग पर बनाने का प्रयत्न किया

<sup>१</sup> 'क्रस्ट कौंसल' अर्थात् नेपोलियन बोनापार्ट।

गया था। एक मन्त्रि मंडल स्थापित किया गया था, परंतु फिर भी धूरी जवाबदार सरकार कायम नहीं की गई थी। राजा को आर्डिनेंस निकालने, पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने और सारे कानूनों का अंगीकार करने का अधिकार रक्खा गया था। हाँ, मिना धारासभा की मर्जा के कोई कर अवश्य ही नहीं लगाया जा सकता था, न कोई कानून बनाया जा सकता था। मंत्रियों पर कुशासन के लिए मुकदमा भी चलाया जा सकता था जिस से उन को शासन के लिए जवाबदार माना गया था। दो सभा की धारासभा बनाई गई थी। 'चेंबर ऑफ् पीयर्स' की ऊपरी सभा के सदस्य राजा की तरफ से जीवन भर के लिए नियुक्त किए हुए अथवा मौलसी होते थे। धारासभा की दूसरी निचली सभा 'चेंबर ऑफ् डेपुटीज' के सदस्य डिपार्टमेंटों में से पाँच वर्ष के लिए चुन कर आते थे, और उन का पाँचवा भाग हर साल चुना जाता था। धारासभा की साल में एक बार बैठकें जरूरी रक्खी गई थीं, और दोनों में से किसी भी सभा को किसी नए विषय पर कानून बनाने के लिए राजा से प्रार्थना करने का अधिकार था। तीस वर्ष के उपर के वे सब नागरिक जो साल भर में कम से कम तीन सौ फ्राक<sup>१</sup> का सरकार को कर देते थे, डिपार्टमेंट के मुख्य नगरों में एकत्र हो कर डिपार्टमेंटों की ओर से निश्चित सख्या में डेपुटीज को चुन सकते थे। इस प्रबंध से उदार विचार के लोगों का फायदा हुआ, क्योंकि उन की सख्या अधिकतर नगरों में थी। परंतु सन् १८२० ई० में अनुदार लोगों ने जोर मार कर चेंबर के सदस्यों की सख्या २५८ से बढ़ा कर ४१० कर दी और डिपार्टमेंट<sup>२</sup> के रजाय ऐरोंडाइजमेंट<sup>३</sup> से एक एक डिपुटी चुने जाने का फायदा कर दिया। अस्तु, बाद में ऐरोंडाइजमेंटों की तरफ से २५८ सदस्य चुने जाने लगे और शेष १७२ सदस्य डिपार्टमेंटों के मुख्य नगरों में से सब से अधिक कर देनेवालों द्वारा चुने जाते थे। इस प्रबंध से करीब बारह हजार धनिक लोगों का दो दो मत देने का अधिकार मिल गया था। सन् १८२४ ई० में एक दूसरा कानून बनाया गया जिस के अनुसार सारे चेंबर का परिवर्तन हर सातवें वर्ष होने लगा। सन् १८३० के राजविद्रोह के बाद जब चार्ल्स दसवाँ गद्दी से उतार दिया गया और लुई फिलिप गद्दी पर बैठा तब फिर धारासभा के एक कमीशन ने राज-व्यवस्था पर विचार किया और उस में बहुत कुछ परिवर्तन किए गए। पुरानी राज-व्यवस्था की भूमिका में लिया था कि राज-व्यवस्था राजा की ओर से प्रदान की गई। भूमिका का यह भाग निराल दिया गया। राजा से कानूनों को रोक रखने का अधिकार ले लिया गया और धारासभा की दोनों सभाओं को कानूनों का प्रस्ताव करने का अधिकार दे दिया गया। मौलसी पीयर्स का बनाना बंद कर दिया गया और 'चेंबर ऑफ् पीयर्स' की बैठकें खुली होने लगीं। 'चेंबर ऑफ् डेपुटीज' का जीवन सात वर्ष के रजाय फिर पाँच वर्ष कर दिया

<sup>१</sup> फ्रांस का सिक्का। <sup>२</sup> डिपार्टमेंट फ्रांस का लगभग उसी प्रकार का भाग है, जैसे हमारी कमिश्नरी या प्रांत। <sup>३</sup> ऐरोंडाइजमेंट डिपार्टमेंट से छोटा देश का भाग कहलाता है, जैसे हमारा जिला या कमिश्नरी।



गया और मतदारों की उम्र ३० वर्ष से घटा कर २५ वर्ष कर दी गई। बाद में १८३१ ई० के एक कानून के अनुसार मतदारों की नर सन्धी शर्त भी तीन सौ फ्रांस से घटा कर दो सौ फ्रांस और खारा धक्के के लिए सौ फ्रांस कर दी गई। इस योजना से देश भर में मतदारों की संख्या दुगुनी हो गई—फिर भी देश की सारी आजादी का डेढ़ सौवां भाग मत देने के अधिकार से वंचित रहा। इस राज व्यवस्था से भी फ्रांस में जन साधारण की सरकार नहीं बनी, हाँ, राते पीते लोगों की सरकार स्थापित हो गई थी। अन्तु सन् १८४८ ई० की दूसरी क्रांति में इस राज-व्यवस्था का भी अंत किया गया, और फिर कुछ दिन तक फ्रांस को वही सन् १७८९ ई० की-सी मारनाट और व्यवस्था देखनी पड़ी। फिर कई वर्ष तक प्रजातन्त्र का तबुरा किया गया और फिर उस का अंत राजाशाही साम्राज्य और द्वितीय बोनापार्ट के शासन में हुआ। क्रांति के समय की अस्थाई सरकार ने प्रजातन्त्र की घोषणा कर पे जनता से देश की राज-व्यवस्था बनाने के लिए एक 'प्रतिनिधि-सम्मेलन' चुनने की प्रार्थना की थी।

देश भर के बालिश मर्दों को इन प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार मान लिया गया था। यह चुनाव फ्रांस के इतिहास में अद्वितीय था। 'व्यवस्थापक-सम्मेलन' में नौ सौ प्रतिनिधि देश भर से चुन कर आए थे, जिन में से प्राठ सौ नरम निचारों के प्रजातन्त्रवादी थे। ४ नवंबर सन् १८४८ ई० तक इस सम्मेलन में नई राज-व्यवस्था बन कर स्वीकृत हो गई थी। इस राज व्यवस्था ने फ्रांस में अखंड प्रजातन्त्र स्थापित होने और जनता को पूर्ण प्रभुता होने की घोषणा की और सरकारी समाजों के पृथक्करण को स्वाधीनता की कुंजी करार दिया। इस राज व्यवस्था के अनुसार सात सौ पचास सदस्यों की एक सभा की एक व्यवस्थापक-सभा बनाई गई, जिस के सदस्यों को चुनने का अधिकार राष्ट्र के प्रत्येक २१ वर्ष से ऊपर के मनुष्य को दिया गया। कार्यकारिणी सत्ता प्रजातन्त्र के एक प्रमुख में रखी गई, जिस का चुनाव चार साल के लिए फ्रांस और ऐलजीरिया के मतदारों की नुदु संख्या कर सकती थी। प्रमुख पद के उम्मीदवारों में से किसी को भी मता की गुरुसंख्या और कम से कम देश के बीच लाख मत न मिलने पर सत्र से अधिक मत पानेवाले पाँच उम्मीदवारों में से किसी एक को व्यवस्थापक सभा चुन सकती थी। एक बार प्रमुख रह चुकने के बाद फौरन दूसरे काल के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उड़ा हो सकता था। प्रमुख को कानूनों का प्रस्ताव करने, सधि की बात चलाने और व्यवस्थापक सभा की राय से सधि मंजूर करने, मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों को रखने और निकालने और सेना को भग कर देने तक के अधिकार दिए गए थे। मगर मंत्रियों के अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह खुलासा नहीं किया गया था। दिसंबर सन् १८४८ ई० में नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा लुई नेपोलियन इस राज-व्यवस्था के अनुसार फ्रांस के प्रजातन्त्र का प्रमुख चुना गया और मई सन् १८४९ ई० में नई व्यवस्थापक-सभा का चुनाव हुआ, जिस में दो तिहाई राजाशाही के पक्षपाती सदस्य चुन कर आए। दुर्भाग्य से प्रजातन्त्र का प्रमुख और नई व्यवस्थापक-सभा दोनों ही प्रजातन्त्र के पक्षपाती नहीं थे। अखु, मई सन् १८५० ई० में एक कानून पास किया गया, जिस के अनुसार मतदारों को छ. मास के स्थान में तीन वर्ष तक एक स्थान पर रहने

पर ही मत देने का अधिकार मिल सकता था। इस कानून के कारण मतदारों की सख्या घट कर लगभग एक तिहाई रह गई। दूसरी दिसम्बर सन् १८५१ ई० को उड़ी चालाकी के साथ व्यवस्थापक सभा बर्खास्त कर के जनता से कहा गया कि सन् १८४६ ई० के कानून के अनुसार प्रजा के सार्वजनिक समारोहों में एकत्र हो कर प्रमुख को राज व्यवस्था की पुनर्घटना करने का अधिकार दे देना चाहिए। प्रमुख को यह अधिकार दे दिया गया और प्रजातन्त्र शासन को फिर एक बार फ्रांस में दफन कर दिया गया। लुई नेपोलियन ने एक वर्ष तक चुप रह कर दूसरे वर्ष ७ नवम्बर सन् १८५२ ई० को प्रजातन्त्र के स्थान में फ्रांस में साम्राज्य स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी। दूसरी दिसम्बर को लुई नेपोलियन फ्रांस का महाराजा धिराज घोषित कर दिया गया और सन् १८७० ई० तक फ्रांस में लुई नेपोलियन का शासन रहा।

सिडेन में फ्रांस की सेनाओं की हार हो जाने और लुई नेपोलियन के प्रशान लोगों के हाथों में गिरफ्तार हो जाने पर यह साम्राज्य भी बालू की भीत की तरह गिर पड़ा। फ्रांस में फिर किसी के हाथों में सत्ता नहीं रही। अस्तु, एंसेली के कुछ गरम प्रतिनिधियों ने एक होटल में बैठ कर ४ सितम्बर सन् १८७० ई० को फ्रांस में प्रजातन्त्र स्थापित हो जाने की घोषणा निकाल दी और पाँच महीने तक, जब तक प्रशिया से युद्ध चलता रहा तब तक, जेनरल ट्रौचू की अध्यक्षता में एक अस्थाई सरकार काम चलाती रही। बाद में युद्ध को जारी रखने अथवा सुलह करने का विचार करने के लिए ८ फरवरी सन् १८७१ ई० के दिन राष्ट्र के ७३८ प्रतिनिधियों की, १८४६ ई० के प्रजातन्त्र के कार्यदों के अनुसार चुन कर, एक सभा बुलाई गई। प्रतिनिधियों की इस सभा के बैठने तक राजा, सिनेट, वीर लेजिस्लाटिव, मन्त्रि मंडल इत्यादि राज व्यवस्था की किसी पुरानी सस्था का कोई अधिकार नहीं रहा था। प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाने के बाद अस्थायी सरकार भी खत्म हो चुकी थी। इस एक प्रतिनिधियों की सभा के सिवाय राष्ट्र की प्रभुता की प्रतिनिधि और कोई सस्था फ्रांस में नहीं थी। अस्तु यह सभा ही फ्रांस की व्यवस्थापक बन गई और करीब पाँच वर्ष तक इसी सभा ने सारा शासन का काम चलाया। सर्व सम्मति से महाशय थीयर्स को १७ फरवरी को राष्ट्र का काम चलाने के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया और उस को अपने मन्त्री चुनने और उन की सहायता से शासन कार्य चलाने का अधिकार भी दिया गया। राष्ट्रपति के हथ में स्वतंत्र हो लेने का अधिकार प्रतिनिधि सभा के हथ में रक्खा गया। प्रशिया से सुलह हो जाने के बाद थीयर्स को फ्रांसीसी प्रजातन्त्र के प्रमुख का खिताब दे दिया गया। मन्त्रि मंडल को भी जवाबदार बनाने का प्रयत्न किया गया। परन्तु नई राज व्यवस्था में प्रजातन्त्र का प्रमुख ही प्रजा के प्रतिनिधियों के प्रति शासन के लिए जवाबदार माना जाने से मन्त्रि मंडल पूरी तरह से जवाबदार न हो सका। इस प्रतिनिधियों की सभा में भी राजाशाही के पक्षपातियों की ही अधिक संख्या थी। थीयर्स रम्य शुरु में राजाशाही के पक्ष में था। परन्तु बाद में उस ने देखा कि राजाशाही जनता को प्रिय नहीं है इस लिए वह भी प्रजातन्त्र के पक्ष में हो गया। इस पर राजाशाही के पक्षपाती उस के विरुद्ध हो गए और उन्होंने उसे इस्तीफा देने पर बाध्य कर दिया। थीयर्स से इस्तीफा रखा कर राजाशाही के पक्षपातियों ने मार्शल मैकमोहन को सात वर्ष के लिए प्रजातन्त्र का प्रमुख चुना। राजतन्त्रवादी सम्मते

ये कि सात वर्ष के भीतर वे अपने आपसे के भगड़ों को मिटा कर राजाशाही की फ्रांस में पुनः स्थापना कर सकेंगे। परन्तु उन की आशा पूरी न हुई और सात वर्ष की मार्शल मेनमोहन की मियाद सदा के लिए फ्रांसीसी के प्रजातन्त्र के प्रमुख की मियाद बन गई। ३० जनवरी सन् १८७५ ई० के वालन नाम के एक प्रतिनिधि ने प्रतिनिधियों की सभा में प्रमुख पद के सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे, जिन के पास हो जाने से प्रमुख का पद सदा के लिए प्रजातन्त्र के प्रमुख का पद बन गया था, और इस विचित्र ढंग से आखिरकार फ्रांस में प्रजातन्त्र की सदा के लिए स्थापना हो गई। सन् १८७६ ई० में नई सिनेट और नए 'चेंबर ऑफ़ डिपुटीज' का चुनाव किया गया, और राष्ट्र की नई व्यवस्थापन-सभा चुन कर आ जाने के बाद अस्थायी 'प्रतिनिधियों की सभा' भंग हो गई। इस नई राज व्यवस्था पर प्रजा की राय नहीं ली गई, परन्तु वर्षों की खीचातानी से थकी हुई फ्रांस की प्रजा ने बड़े उत्साह से इस नई व्यवस्था का स्वागत किया।

इतनी कठिनाइयों, झगड़ों, भगड़ों, इतजारों, तजुरबों और आनाकानी के बाद जाकर वही फ्रांस में प्रजातन्त्र राज-व्यवस्था की स्थापना हुई। जिन लोगों के हाथों प्रजातन्त्र की स्थापना हुई, वह स्वयं प्रजातन्त्रवादी नहीं थे। अस्तु, फ्रांस की राज-व्यवस्था दूसरी राज व्यवस्थाओं से भिन्न है। फ्रांस की राज-व्यवस्था लिखित जरूर है, परन्तु उस के तीन अलग अलग भाग हैं। इन तीनों भागों में वे सारी बातें जो एक लिखित राज-व्यवस्था में आ जानी चाहिए, नहीं आ गई हैं। न तो वही प्रजा के अधिकारों का जिक्र है, न चेंबर ऑफ़ डिपुटीज और मंत्रियों का चुनाव किस ढंग से किया जायगा इस का ही जिक्र है। सिनेट का चुनाव, न्याय, बजट किसी का विस्तार से जिक्र नहीं किया गया है। फ्रांस की पिछली राज व्यवस्था काफी तूल तवील थी। परन्तु सन् १८७५ ई० की यह राज-व्यवस्था बहुत छोटी और सिर्फ शासन संगठन की मुख्य बातों का जिक्र करती है। अधिकतर बातों को रिवाज और साधारण कानूनों के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरह से बड़े अमली ढंग की व्यवस्था है। सन् १७९२—९५ ई० के 'कन्वेंशन' और सन् १८४८ ई० के 'व्यवस्थापक सम्मेलन' की तरह ग्राखिरी 'प्रतिनिधियों की सभा' में अधिक सिद्धांतों पर चर्चा नहीं की गई थी। संगठित शासन और राज-व्यवस्था के लिए भूखे फ्रांस के लिए अनुभव और जरूरत के अनुसार यह राज व्यवस्था तैयार कर ली गई थी। राजाशाही-सभ के पक्षपातियों ने अपना मनोरथ सफल न होते देख, देश में अव्यवस्था रहने से फिर से नेपोलियन वंश का राज्य स्थापित हो जाने के डर से, निराश हो कर, अनमने, प्रजातन्त्र के लिए लाचार हो कर अपना मत दे दिया था। प्रजा-तन्त्रवादियों ने भी अपना मुख्य ध्येय प्रजातन्त्र पाने के लिए, रखे सिद्धांतों पर जोर न दे कर, तरह तरह के समझौते स्वीकार कर लिए थे। अस्तु, इन समझौतों के कारण फ्रांस की सन् १८७५ ई० की राज-व्यवस्था किसी एक सिद्धांत पर बनी हुई नहीं है। परन्तु आज कल जो राज व्यवस्था फ्रांस में प्रचलित है वह सिर्फ सन् १८७५ ई० की यह तीन भाग की राज-व्यवस्था ही नहीं है, उस में बहुत से और कानूनों और रिवाजों का समावेश भी हो गया है।

इन दूसरे कानूनों का साधारण ढंग पर फ्रांस की धारासभा में नामज़ूर किया

जा सकता है। परन्तु इन कानूनों ने सन् १८७५ ई० की राज व्यवस्था की बहुत सी कमियों को पूरा कर दिया है और वे भी उतने ही आवश्यक हैं, जितनी लिखित राज व्यवस्था की धाराएँ। फ्रांस की राज व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन करने का तरीका बहुत सरल रखा गया है। प्रजातंत्र का प्रमुख, उस के नाम पर दूसरे मंत्री, अथवा व्यवस्थापक सभा की दोनों शाखाओं में से कोई राज-व्यवस्था में परिवर्तन या सुधार करने की चर्चा उठा सकते हैं। चर्चा उठने के बाद प्रगर व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाएँ अलग-अलग इस नतीजे पर पहुँचें कि राज व्यवस्था में सुधार अथवा परिवर्तन की जरूरत है, तो फिर दोनों सभाओं के सभासद एक सम्मिलित राष्ट्रीय सम्मेलन<sup>१</sup> में निचार करने के लिए वारसेलज के महल में मिलते हैं। इस सम्मेलन के फ्रांस की राज व्यवस्था में सब कुछ फेर-भार करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं के सदस्य 'सिनेट' और 'चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़' के सदस्यों की हैसियत से नहीं आते हैं। वे निम्नलिखित एक नई हैसियत से—राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों की हैसियत से—मिलते हैं। राज व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए ऐसी आसानी रखने के कारण भी इस राज व्यवस्था के स्वीकृत होने में प्रतिनिधि सभा में आसानी हुई थी, क्योंकि राज तन्त्रवादी दलों के यह आशा रही कि वे जब चाहेंगे तब राज व्यवस्था को बदल सकेंगे। अमेरिका में राज व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन के प्रस्ताव कांग्रेस अथवा एक विशेष कन्वेंशन में पास हो जाने के बाद फिर सारी स्टेट्स की तीन चौथाई धारासभाओं अथवा विशेष कन्वेंशनों में मंजूर होने पर कानून बनते हैं। बेल्जियम में हर परिवर्तन और सुधार का प्रस्ताव धारासभा की दोनों सभाओं में हर सत्र में अलग अलग स्वीकृत होने की कैद है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट के अन्य कानूनों की तरह राज व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार होने पर भी हर ऐसे मौकों पर प्रायः नया चुनाव करा के प्रजा की राय ले ली जाती है। अस्तु, फ्रांस की राज-व्यवस्था में फेर-भार करने का तरीका इन सब देशों से सरल है, क्योंकि फ्रांस में धारासभा के सदस्य ही राज-व्यवस्था को भी बदल सकते हैं।

## २—प्रजातंत्र का प्रमुख

फ्रांस की सरकार की कार्यकारिणी सत्ता का सर्वोच्च प्रतिनिधि फ्रांस के प्रजा तंत्र का प्रमुख है। उस को चुनने के लिए सिनेट और चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़<sup>२</sup> के सदस्य नेशनल एसेंबली की बैठक में वारसेलज के प्रख्यात राज भवन में, जिस को जुई १४ वे ने बनवाया था, मिलते हैं। इस राज भवन में सन् १८७३ ई० से सन् १८७६ ई० तक सिनेट और चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़ की सभाओं की बैठकें हुआ करती थीं। परन्तु बाद में व्यवस्थापक सभा की बैठकें पेरिस में होने लगीं। तब से यह राज भवन सिर्फ 'नेशनल एसेंबली' की बैठकों के काम आता है। जब सिनेट और चेंबर के सदस्य राज-व्यवस्था में परिवर्तन

<sup>१</sup> 'नेशनल एसेंबली'

<sup>२</sup> सिनेट और चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़ फ्रांस की धारासभा के दो भाग हैं।

करने अपना प्रजातन्त्र के प्रमुख का चुनाव करने के लिए एक सम्मिलित सभा में बैठते हैं। एक महान् अर्ध-गोलाकार दीवान में, जिस के चारों ओर स्थलों की पंक्तियाँ हैं, सदस्यों के बैठने के लिए कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। अर्ध-गोलाकार दीवान के व्यास के बीचो-बीच घोलने वाले के लिए एक चबूतरा बना होता है और ऊपर चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए गैलेरियाँ होती हैं। प्रमुख का चुनाव करने के लिए जब नेशनल ऐसेंबली की बैठक होती है तब सदस्य कोई और चर्चा न कर के सिर्फ प्रमुख के लिए मत देते हैं। एक बर्तन बीच के चबूतरे पर रखा दिया जाता है। एक चोबदार जो चाँदी की जर्जिरे डाले होता है, सदस्यों का नाम ले-ले कर पुकारता है और वे एक पंक्ति में जा कर पारी-पारी से निर्वाचन पत्र पर अपना मत लिख कर उस बर्तन में डाल आते हैं। नेशनल ऐसेंबली के अध्यक्ष के आसन पर सिनेट का अध्यक्ष बैठता है, जिस के दाएँ बाएँ शांति और सुव्यवस्था की दो सुंदर मूर्तियाँ रनी हैं। मत लेने में काफी समय लग जाता है क्योंकि करीब नौ सौ मत पड़ते हैं। जब मत पड़ चुकते हैं तब पत्ती खींच कर सदस्यों में से कुछ आदमी मतों को गिनने और जाँचने के लिए चुन लिए जाते हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार को आगे से एक अधिक मत नहीं मिलते हैं, तो फिर से चुनाव के लिए मत पड़ते हैं, और जब तक किसी एक उम्मीदवार को आगे से एक अधिक मतों की बहुत संख्या नहीं मिलती है, तब तक बार-बार बार-बार चुनाव किया जाता है। चुनाव हो जाने पर ऐसेंबली का अध्यक्ष प्रजातन्त्र के प्रमुख का नाम एलान कर देता है और प्रजातन्त्र की जय बोल कर सभा प्रसन्न हो जाती है। नया प्रमुख अपने मंत्रियों के साथ पैरिस में आकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है।

प्रमुख का चुनाव सात वर्ष के लिए होता है। परंतु सात वर्ष खत्म होने पर वह फिर प्रमुख पद के लिए उड़ा हो सकता है, और फिर से उस का चुनाव हो सकता है। कानून के अनुसार तो वह जिंदगी भर तक बार-बार चुना जा सकता है, परंतु ऐसा किया नहीं जाता क्योंकि एक ही आदमी के हाथ में सारी ताकत सौंप देना प्रजासत्तात्मक राज्य के लिए अच्छा नहीं होता। सात वर्ष खत्म होने से एक महीना पहले प्रजातन्त्र के प्रमुख को नया प्रमुख चुनने के लिए ऐसेंबली को बुलावा देना चाहिए। अगर प्रमुख किसी कारण से इस काम के लिए ऐसेंबली को समय पर बुलावा न भेज सके तो सिनेट के अध्यक्ष को पंद्रह दिन पहले बुलावा भेजना चाहिए। अगर कोई प्रमुख यकायक मर जाय या इस्तीफा दे दे तो व्यवस्थापक सभा का दोनों शाखाओं के सदस्यों को फौरन् स्वयं मिलने का अधिकार होता है। प्रमुख के मर जाने पर दो-तीन दिन तक राष्ट्र बिना प्रमुख के भी रह सकता है। परंतु ऐसे समय में सारी सत्ता मंत्रि-मंडल के हाथ में आ जाती है।

सन् १८७१ से १८७५ ई० तक प्रजातन्त्र के प्रमुख को शासन के लिए व्यवस्थापक सभा के प्रति जबाबदार माना गया था। परंतु यह प्रणय ठीक तरह चला नहीं, इस लिए सन् १८७५ ई० से सिर्फ विद्रोह के काल में तो प्रमुख को शासन के लिए जबाबदार रखा गया है बाकी शासन की सारी जिम्मेदारी मंत्रि-मंडल के सुपुर्द कर दी गई है। अब इंग्लैंड की तरह फ्रांस का मंत्रि-मंडल भी सारे शासन कार्य के लिए फ्रांस की व्यवस्थापक-

सभा को सम्मिलित रूप से बराबर माना जाता है। परंतु व्यक्तिगत कामों के लिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार समझे जाते हैं। प्रमुख का कोई एलान अथवा हुक्म, जिस मंत्री के विभाग से उस का संबंध हो, बिना उस मंत्री के हस्ताक्षर के जायज़ नहीं होता है। शानन के किसी कार्य के लिए अवेले प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार रागा के नाम पर इंग्लैंड में मजिस्ट्रल हुक्म निवालाता है, उसी प्रकार फ्रांस में प्रमुख के नाम पर मंत्री हुक्म निकालते हैं। प्रमुख का कर्तव्य कानून पर अमल करवाना रक्खा गया है। बड़े कानून सिर्फ़ धारामभा में पास हो कर ही अमल में नहीं आता है, सरकार की कार्यशालिका की तरफ से उस का अमल के लिए एलान किया जाता है, जिस का अर्थ यह है कि, आवश्यकता पड़ने पर, मंत्रियों से ज़रदस्ती भी कानून पर अमल करवाया जा सकता है। वारासभा में पास हो जाने के बाद किसी कानून को रोक लेना प्रमुख के अधिकार की शान नहीं है, चाहे वह कानून उस में इनिज़र हो अथवा न हो। व्यवस्थापन सभा में कानून पास हो जाने के बाद व्यवस्थापन सभा की दोना सभाओं के अध्यक्ष उन्हें प्रमुख के पास भज देने हैं और पहुंचने के साधारण तौर पर एक महीने के भीतर और आवश्यकता होने पर तीन दिन के भीतर ही प्रमुख उन का एलान कर देने के लिए बाध्य होता है। हाँ, प्रमुख को इतना अधिकार जरूर है कि अगर वह समझे कि किसी कानून के बनाने में त्रुटियाँ की गई हैं तो वह उस पर फिर से विचार करने के लिए सभाओं के पास भेज दे। परंतु यदि सभाएँ हठ कर और फिर उसी कानून को जैसा का तैसा पास करें तो प्रमुख को सिवाय उस कानून का एलान करने और उस पर अमल करवाने के और कोई चारा नहीं होता। परंतु इस अधिकार का आज तक कभी किसी प्रमुख ने उपयोग नहीं किया है। प्रमुख का व्यवस्थापन-सभा से मज़ूर किसी प्रस्ताव में भी नामज़ूर करने का अधिकार नहीं होता। न अपने निम्नी हुक्म या एलान में वह किसी कानून की किसी तरफ़ शक़ ही बदल सकता है। हाँ, जो बात कानून में साफ़ न हो उन्हें वह स्पष्ट ज़रूर कर सकता है।

महान ने मार राष्ट्रीय तलमा पर अध्यक्षता का स्थान सदा प्रजातंत्र का प्रमुख लेता है, और सभी सरकारी समारंभों पर फ़ॉर्म और प्रजातंत्र का मूर्तिमत् प्रमुख ही होता है। प्रमुख को २४००० फ़्रां मालाना वेतन और २६००० फ़्रां मालाना सफर हत्याके लिए भत्ता मिलता है। रहने के लिए उस को दो आलीशान मकान दिए जाते हैं। अगर इन आलीशान मकानों में तकिया के अलावे बैठ कर वह मज़े से समय नहीं गँवाता। सुबह में शाम तक उस का गारा समय सरकारी काम में ही जाता है। राज व्यवस्था के अनुसार प्रमुख को ही सारे पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। परंतु वह यह काम मंत्रियों की सहायता और राय में करता है और किसी को निम्नी पद के लिए केवल अपनी दृष्टानुसार नहीं चुन सकता। उम्र और योग्यता के नियमों के अंदर ही उसे रहना पड़ता है। बहुत से छोटे छोटे पदाधिकारियों को मंत्री, प्रीफ़ेक्ट्स् और अन्य विभाग-पति उस के नाम में नियुक्त करते हैं। सिर्फ़ खास-खास अधिकारियों को प्रमुख खुद नियुक्त करता है। प्रमुख को अपराधियों पर दया कर के उन की सज़ा कम करने अथवा उन्हें मिलकुल छोड़ देने का भी अधिकार होता है। अगर इस अधिकार का प्रयोग भी वह एक कमीशन की

लिकारिश और 'कीपर ऑफ़ दि मीस' नाम के अधिकारी को जिम्मेदारी पर सिर्फ़ उसी हालत में करता है जब कि किसी खास कारण में अथवा अपराधी के पश्चात्ताप करने में इस दया से कुछ लाभ होने की सम्भावना होती है। सेना पर भी प्रमुख का अधिकार माना जाता है और मनिया की जमानदारी पर वह क्रास के जमाने ग्रामान का जिम्मेदार समझा जाता है।

जिस तरह व्यवस्थापन-सभा की दोनों सभायाँ नो कानूनी मसविदे पेश करने का अधिकार होता है उसी तरह प्रमुख को भी मसविदे पेश करने का अधिकार होता है। मगर धारासभा के सामने विचार के लिए कोई मसविदा तभी आ सकता है, जब कि उस पर प्रमुख के साथ किसी मंत्री के भी हस्ताक्षर हों। जब धारासभा के सामने कोई मसविदा आता है, तब उसी मंत्री को उस मसविदे का पक्ष लेना पड़ता है, जिस के उस पर हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि प्रमुख धारासभा में बैठ कर किसी चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। मन्त्रिमण्डल की राय में धारासभा की बैठक बुलाने और उदर करने का कर्तव्य भी प्रमुख का ही होता है। परन्तु इस समय में भी उसे अधिक अधिकार नहीं हैं। अगर वह धारासभा की बैठक न बुलाय तो कानून के अनुसार धारासभा जनवरी के दूसरे मंगलवार को अपने आप ही मिल सकती है। धारासभा की दोना शाखाओं की बैठकें एक साथ ही खुलनी और बंद हानी चाहिए और माल में कम से कम पाँच महीने तक अवश्य होनी चाहिए। प्रजापक्ष के प्रमुख को धारासभा की सभायाँ को स्थगित कर देने का अधिकार है। परन्तु एक महीने में अधिक अथवा एक बैठक में दो बार से अधिक वह स्थगित न कर सकता है। पाँच महीने की साधारण बैठक हो चुकने पर धारासभा की फिर से बैठक बुलाने का भी अधिकार प्रमुख को है, और अगर व्यवस्थापन सभा की सभायाँ की अनुसूच्या दूसरी बैठक चाहती हो तो दूसरी बैठक बुलाना उस का पत्र हो जाता है। धारासभा की विशेष बैठकें जिन्हें प्रमुख जब उचित समझे उदर कर सकता है, क्रास में उतनी ही आम हो गई हैं जितनी साधारण बैठकें। वे हर साल हुआ करती हैं और प्रायः उन में प्रायः त्रय पर चर्चा होती है। प्रमुख को एक अधिकार बड़े महत्व का है। सिनेट की सम्मति से वह 'चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़' का उस की नीयाद पूरी होने से पहिले ही भग्न कर के नया चुनाव करा सकता है। यह अधिकार इंग्लैंड के राजा के पार्लामेंट भंग करने के अधिकार की तरह का नहीं है, इस को सरकारी गत्ताओं के पृथकरण की स्वाभाविक शर्त समझ कर रक्खा गया है। प्रजा के प्रतिनिधि चुनाव पर जो वायदे प्रजा से कर के आते हैं उन को भूल कर यदि वे अड़-बड़ बातें करने लग जायें तो क्रास में कार्यकारिणी को अधिकार दिया गया है कि वह चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़ को भंग कर के प्रतिनिधियों को, फिर चुनाव में जा कर, प्रजा की राय लेने के लिए मजबूर कर दे। कार्यकारिणी के हाथ में यह सत्ता रखने से प्रतिनिधि-सभा के सदस्या पर प्रजा का एक प्रकार से अक्रुश बना रहता है, जिस से प्रजा के प्रतिनिधि अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। मन् १८७७ ई० में एक बार प्रमुख के इस अधिकार का दुर्भाग्य में दुरुपयोग अवश्य हुआ था, परन्तु इसी लिए इस उपयोगी अधिकार को बुरा नहीं कहा जा सकता।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध में फ्रांस के प्रजातंत्र का प्रमुख बड़ा काम आता है। दूसरे राष्ट्र अपने एलची और राजदूतों को उस के पास भेजते हैं, और उन के लिए यहीं फ्रांस का स्थायी प्रतिनिधि है। प्रमुख ही परराष्ट्र-सचिव द्वारा और परराष्ट्र सचिव की जवाबदारी पर दूसरे राष्ट्रों से संधि की बात-चीत चलाता और पूरी करता है। देश के हित में वह समझे तो संधियों को गुप्त भी रख सकता है और उचित समय पर व्यवस्थापक-सभा को उन का हाल बता सकता है। बिना किसी रोक-टोक के यह अधिकार प्रजातंत्र के प्रमुख को दे दिया जाता तो यह बड़ा खतरनाक था। अस्तु, राज-व्यवस्था के अनुसार ऐसी संधियों को, जिन के कारण राष्ट्रीय संपत्ति पर असर पड़े अथवा विदेशों में बसनेवाले फ्रांसीसियों के व्यक्तिगत और मिलकियत संबंधी अधिकारों पर असर पड़े और शान्ति और व्यापार से संबंध रखनेवाली संधियों को तब तक मंजूर नहीं समझा जाता है, जब तक उन पर व्यवस्थापक-सभा का मत न ले लिया जाय। अधिकतर संधियाँ इस कक्षा में आ जाती हैं; अस्तु थोड़े ही से अंतर्राष्ट्रीय मामले ऐसे रह जाते हैं, जिन्हें व्यवस्थापक-सभा की राय लेने के पहले प्रमुख स्वीकार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक और मैत्री संबंधी संधियों को प्रमुख स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि उन से फ्रांस के आय-व्यय पर असर न पड़े। परंतु किसी संधि के अनुसार देश का कोई भाग दिया, बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता; ऐसा करने के लिए एक नया कानून बनाने की जरूरत होती है। बिना व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं की राय लिए प्रजातंत्र का प्रमुख युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। हाँ, आवश्यकतानुसार वह युद्ध की तैयारी और बचाव का प्रबंध पहले से कर सकता है। अगर लुई नेपोलियन की तरह अब कोई प्रमुख राष्ट्र की राज-व्यवस्था और कानूनों के विरुद्ध पड़्यंत्र रचने का यत्न करे तो 'चेंबर ऑफ् डेपुटीज़' उस पर सिनेट के सामने मुकदमा चला सकता है और अपराधी ठहरने पर सिनेट को प्रमुख को बर्खास्त करने और साधारण कानूनों के अनुसार दंड तक देने का अधिकार रखता गया है।

### ३—मंत्रि-मंडल

पुराने ज़माने में फ्रांस के राजाओं के महल का प्रबंध ठीक रखने के लिए कुछ पदाधिकारी रहते थे जिन से राजा राज-कार्य में भी सहायता ले लिया करता था। भंडार का प्रबंध रखने के लिए भंडारी होता था, घुड़छाल का दरोगा 'मारशल' कहलाता था, खजानची धन-संपत्ति की सँभाल रखता था, साक्री या बोतलबंदार शराब की बोतलें ठीक रखता था। राज-महल का संरक्षक<sup>१</sup> न्याय का काम भी करता था। महल का दरोगा<sup>२</sup> यह-प्रबंध ठीक रखता था। बाद में धीरे-धीरे इन अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य बदल गए। भंडारी सिर्फ रोटी-दाल की चिंता ही न रख कर युद्ध और न्याय की बातों में भी दखल देने लगा और वह इतनी कठिनाइयाँ खड़ी करने लगा कि राजा को इस पद ही को खत्म कर देना पड़ा। मारशल के स्थान में कांस्टेबल<sup>३</sup> नाम का अधिकारी आया और अंत में

<sup>१</sup> 'कार्ट ड्रॉप् दि पैलेस ।' <sup>२</sup> 'मेयर ऑफ् दि पैलेस ।' <sup>३</sup> 'कार्ट ड्रॉप् दि स्ट्युरस ।'



यह भी केवल घोड़ों की देख-भाल न रख कर युद्ध में मेनाओं का संचालन तक करने लगा। चांसलर, जिस का काम सिर्फ फ्रांस की शाही मुहरें रखना होता था धीरे-धीरे न्याय और कार्यकारी विभागों के सिर पर जा चढ़ा और इतना बलवान पदाधिकारी बन गया कि राजा के सारे क्रमानों तक को बाद में वही लिखने लगा। अस्तु, निरंकुश राजाओं को इन शक्तिशाली पदाधिकारियों का बाद में भय रहने लगा, और उन्होंने उन के पर कतरने शुरू किए। कांस्टेबल का पद खत्म कर दिया गया। चांसलर की शक्ति कम करने के लिए उन की दुम में थोड़े से और अधिकारी बाँध दिए गए, जिन को पहले "राजा के हुक्मों के मंत्री", के नाम से पुकारा जाता था। बाद में वे "राष्ट्र के मंत्री" कहलाने लगे। यह "राष्ट्र के मंत्री" राजकार्य के लिए राजा को जवाबदार होते थे, और लुई १३ वें और लुई १४ वें के समय तक उन की इतनी ताकत बढ़ गई थी कि अमीर-उमरा उन से जलने लगे थे। लुई १४ वें की मृत्यु के बाद मंत्रियों की शक्ति कम करने की अमीरों की ओर से बहुत कोशिश की गई; मगर मंत्री राज-कार्य में इतने चतुर बन गए थे कि उन की शक्ति कम नहीं की जा सकी। अस्तु, वह पदाधिकारी जैसे के जैसे फायम रहे।

सन् १७६१ ई० की फ्रांति के बाद प्रजा के हाथ में सत्ता आ जाने पर, २५ मई के कानून के अनुसार इन्हीं मंत्रियों को राजा के स्थान में राष्ट्र के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदार बना दिया गया। आधुनिक ढंग के मंत्रियों की यह पहली कलक थी। मंत्रियों को धारासभा के बाहर से चुनने और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार राजा को दिया गया था। परंतु फ्रांति और फनक्शन के जमाने में मंत्रियों की कोई हस्ती नहीं थी। 'प्रजारता-समिति' के नियुक्त किए हुए कमीशन सरकार का सारा काम चलाते थे। डाइरेक्टरी के जमाने में मंत्रियों के विभागों की पुनर्घटना की गई, परंतु उन की नियुक्ति डाइरेक्टरी करती थी और उन की न कोई कौंसिल थी और न वह एम्बली के प्रति जवाबदार थे। आजकल के प्रमुख की तरह 'कौंसिल' व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार नहीं माने जाते थे। मगर कौंसिल की तरफ से निकलनेवाले हुक्मों और कानूनों पर किसी न किसी मंत्री को हस्ताक्षर करने पड़ते थे और मंत्रियों को कुछ खाम बातों में व्यवस्थापक-सभा के प्रति जवाबदार माना गया था। इस समय की व्यवस्थापक-सभा में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते थे, इस लिए प्रजा का कोई अंकुश सरकार पर कहीं नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जान धूसर कर राज-व्यवस्था को सूक्ष्म और अस्पष्ट रक्खा था, जिस से सारी ताकत उस के हाथ में आ गई थी, और मंत्रियों की हस्ती हेड-क्लर्कों से अधिक कुछ नहीं थी। बाद में साम्राज्य की स्थापना हो जाने पर तो मंत्री पद ही नहीं रहे। उन की जगहों पर बड़े-बड़े नामधारी साम्राज्य का 'महामहोमंत्री' 'महामहोकेपाध्यक्ष' 'महाजलनायक' इत्यादि पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इन बड़े-बड़े नामधारियों में कुछ बड़े योग्य पुरुष भी थे।

<sup>१</sup> राजा के क्रमान या आर्डिनेंस ही उस समय फ्रांस में कानून समझे जाते थे।

<sup>२</sup> 'सेक्रेटरीज ऑव् दि कमांडमेंट्स ऑव् दि किंग'। <sup>३</sup> 'सेक्रेटरीज ऑव् स्टेट'। <sup>४</sup> 'कमिटी ऑव् पब्लिक सेक्रेटरी'।

परन्तु उन को अपने आका के हुक्म उठा लाने के मियाय और कांड अधिकार नहीं था। बाद में राजाशाही की पुनः स्थापना होने पर मंत्रियों की जमावदारी फिर से कायम की गई। मगर इस योजना के मंत्रियों को भी प्रजा के प्रति पूरी तरह में जवाबदार नहीं रह सकते, क्योंकि जिन व्यवस्थापक मन्त्रियों के प्रति उन्हें जवाबदार माना गया था, उस का चुनाव करने का अधिकार मंत्रिमाधारण्य को नहीं था। दूसरे साम्राज्य के समय में तो व्यवस्थापकी-पद्धति का ही मूला धौंट दिया गया था, और जब दूसरा साम्राज्य निष्कुल आखिरी सौम्य ले रहा था, तब उस को फिर से नीवित करने की व्यर्थ चेष्टा की गई थी। आन्ध्रनगर सन् १८७५ ई० की प्रजातन्त्र राज-व्यवस्था में मंत्रियों की प्रजा की जवाबदारी के सिद्धांत को पूरी तरह से मान कर कायम किया गया और तब से फ्रांस का प्रत्येक मंत्री अपने शासन विभाग के कामों के लिए व्यवस्थापक सभा को व्यक्तिगत रूप से जवाबदार और शासन की ग्राम नीति के लिए सार मंत्री मन्मिन्त्रित रूप में उत्तरदायी होते हैं।

प्रजातन्त्र का प्रमुख का काम मंत्रियों का चुनाव करना भी होता है। मगर वास्तव में यह मन्त्रि-मंडल के सिर्फ प्रधान का चुनाव करता है और शेष मंत्रियों को प्रधान मंत्री स्वयं चुनता है। जब कोई मन्त्रि मंडल इस्तीफा देता है, तब प्रजातन्त्र का प्रमुख, जिन राजनैतिक नेताओं से उचित समझता है, बुला कर नए मन्त्रि मंडल के बनाने का सव्य म सलाह देता है। ज्ञात सौर पर यह धारासभा की दोनों सभाओं के अध्यक्षों की सलाह से किसी ऐसे नेता को जिस को यह समझता है कि वह ऐसा एक नया मन्त्रि मंडल बना सकेगा जो धारासभा को कृष्ण होगा, मन्त्रि मंडल बनाने के लिए बुलाना मेचता है। सिनेट या चेंबर के किसी सदस्य अथवा बाहर के किसी मनुष्य को भी वह इस प्रकार का बुलाया दे सकता है। प्रमुख से बातचीत करने के बाद यदि वह नेता मन्त्रि-मंडल का प्रधान बनना स्वीकार कर होता है, तो फिर अन्य मंत्रियों का चुनाव उसी की मर्मा पर छोड़ दिया जाता है। फिर प्रधान मंत्री के अपने मन्त्रि मंडल का चुनाव कर लेने के बाद प्रजातन्त्र का प्रमुख अपने शोर इस्तीफा दे कर जानेवाले प्रधान मंत्री के हस्ताक्षरों से नए प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है, और अपने सया नए प्रधान मंत्री के हस्ताक्षरों से नए मन्त्रि मंडल के मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रारंभ में मन्त्रि मंडल में छः से कम और आठ से अधिक सदस्य नहा होते थे। परन्तु सन् १८४८ ई० की राज-व्यवस्था में मंत्रियों की सख्या निश्चित करने का अधिकार व्यवस्थापक मन्त्रियों को दे दिया गया और सन् १८७५ ई० की राज व्यवस्था में मंत्रियों की सख्या का फोड जिन तब नहीं किया गया। अस्तु, आवश्यकतानुसार मंत्री घटा-बढ़ा लिए जाते हैं।

प्रधान मंत्री जिस विभागको उपयुक्त समझता है स्वयं अपने हाथ में रखता है। अगर प्रधान मंत्री न्याय मंत्री का स्थान नहीं लेता है तो मन्त्रि मंडल का उपप्रधान न्याय मंत्री के आसन पर बैठता है। प्रधान मंत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष, मन्त्रि मंडल का प्रधान, और फ्रांस की 'मुद्रों का भंडारी' होता है। परराष्ट्र-सचिव फ्रांस के

दूसरे राष्ट्रों से मन्ध की देख रेख रखता है, और फ्रांस के दूसरी देशों में रहनेवाले राजदूतों और एलचियों से काम लेता है। यह मन्त्री के मातहत सारे प्रीफेक्ट्स डिपार्टमेंटों का 'सामन', 'दंडशासन', अस्पताल, जेल, पागलखाने, पुलिस, खुफिया इत्यादि देश में अमनो आमान और सुव्यवस्था रखनेवाले सारे देश के भीतरी शासन-विभाग रहते हैं। अर्थ-सचिव राष्ट्रीय आव-व्यय-पत्रक तैयार करता है और रजिस्ट्री, साधारण करों, व्यापारी चुगी करों, और सरकारी उद्योग धंधों की देख रेख और प्रबंध का ज़िम्मेदार होता है। पेंशनयाक्ता अधिकारियों को भी वही पेशने बाँटता है। राष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था का सारा उत्तरदायित्व अर्थ-मन्त्रि पर होता है, अस्तु, व्यक्तिगत हितों के आक्रमणों से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना उस का मुख्य काम होता है। युद्ध-सचिव का काम देश की रक्षा और यन्त्रों का प्रबंध ठीक रखना होता है। अस्तु, वह सारी सेनाओं को रोज़ कवायद करा कर मुस्तैद रखता है, काफी हथियार, धन, रमद, भूमा-वास, तोपें, गोला-बारूद तैयार रखता है और देश की शान्ति से रक्षा करने के लिए ज़रूरी क़िलों और स्थानों को सब तरह से ठीक ठाक रखता है। जलसेना-सचिव उनी प्रकार जलसेना को तैयार रखता है। शिक्षा-सचिव के हाथ में शिक्षा-विभाग की सारी शाखाएँ रहती हैं। वह इनाम इत्यादि बाँट कर सब प्रकार से देश में ज्ञानवृद्धि के प्रयत्न करता है। सार्वजनिक-कार्य-मन्त्री राष्ट्रीय जल-थल मार्गों की देख-रेख करता है और उन को बनसता और मरम्मत कराता है। रेल, सड़कें, नहरें, डाक और तार भी उसी के विभाग में रहते हैं। पहले व्यापार और खेती भी इसी विभाग में शामिल थे। मगर अब व्यापार और खेती दोनों के दो दूसरे सचिव होते हैं। व्यापार मन्त्रि व्यापारिक शिक्षा और देश के व्यापार की वृद्धि के प्रयत्न करता है। उनी प्रकार का इण्डि सचिव भी खेती-बारी की शिक्षा, फसलों की वृद्धि, उत्तम पशुओं की उत्पत्ति, जंगलों की देख-रेख करता है और देश के जिस जिस भाग में लकड़ी की कमी होती है वहाँ जंगल लगवाता है। उपनिवेश मन्त्री का अधिकार दुनिया भर में फैले हुए फ्रांसीसी उपनिवेशों पर रहता है। अम-सचिव के अधिकार में कुछ एहमन्त्री और कुछ व्यापार मन्त्री के विभागों का हिस्सा आ जाता है। यह समाज को दरिद्रता और दुखों से दूर रखने तथा अमजीवियों की उन्नति के प्रयत्न में रहता है। हर सप्ताह कई बार मन्त्री आपस में राजकार्य-सबधी परामर्श करने के लिए मिलते हैं। एक सप्ताह में कम से कम मन्त्रियों की दो बैठकें प्रजातन्त्र के प्रमुख की अध्यक्षता में, और एक बैठक प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में ज़रूर होती हैं। जब मन्त्री प्रमुख की अध्यक्षता में बैठते हैं तब उन की बैठक को 'मन्त्रियों की काँसिल' कहते हैं और जब वे प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में बैठते हैं तब उन की बैठक 'केबिनेट' अर्थात् मन्त्रिमंडल कहलाती है। मन्त्रियों की काँसिल में सारे अधिक ज़रूरी राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों पर निचार होता है। 'मन्त्रिमंडल' की बैठकों में थोड़े राजनीति की प्रति दिन की समस्याओं पर निचार किया जाता है। एक सप्ताह में कुल मिला कर नौ घंटे से अधिक मन्त्रिमंडल की बैठकें आम तौर पर नहीं होती हैं। इतना समय

<sup>१</sup> 'मिनिस्टर ऑफ़ दि इंडीरियर'। इन का विवेचन आगे आवेगा। <sup>२</sup> 'कस्टम'।

फ्रांस जैसे बड़े देश की सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए काफी नहीं है। मंत्रियों का बहुत-सा समय व्यवस्थापक सभा की चर्चाओं के विचार में ही चला जाता है। हर मंत्री को अपने विभाग से संबंध रखनेवाले जन हितकारी गिथियों पर व्यवस्थापक-सभा में मसविदे पेश करने की फिज रहती है और इन मसविदों को पहले मंत्रियों को अपने साधियों के सामने विचार के लिए रखना पड़ता है जिस से सारे मंत्रिमंडल की उन्म सहायता रहे। बहुत-सा ज्ञान्ते या काम भी मंत्रियों की कौंसिल को करना होता है, उदाहरणार्थ म्युनिसिपल कौंसिल को चुनाव के लिए भग करना अथवा 'स्टेट कौंसिल' के सदस्यों की नियुक्त करना इत्यादि। मंत्रिमंडल के सामने किसी प्रश्न को विचार के लिए रखने या न रखने की सारी जिम्मेदारी उस मंत्री की होती है जिस के विभाग से उस प्रश्न का संबंध होता है मगर मंत्रियों की व्यवस्थापक सभा को सम्मिलित जवाबदारी होने के कारण सारे विभागों की ज़रूरी बातें आमतौर पर कौंसिल के सामने विचार के लिए रखी जाती हैं। कौंसिल और कैबिनेट दोनों में से किसी की कार्यवाई का चिन्ता नहीं रहता जाता है। प्रमुख या गृह-मंत्री कौंसिल की कार्यवाई का सार अखबारों के प्रतिनिधियों को बतला देने हैं। मगर आवश्यक बातें नहीं बताई जाती हैं।

दिल से काम करनेवाले मंत्री के लिए हर रोज बड़ा काम रहता है। सबेरे उठते ही उसे एक खतो का पुलिदा पढ़ने और जवाब देने के लिए मिलता है। जो खत उस के निजी पते पर नहीं होते हैं, वह तो विभाग के कर्मचारी खोल ही लेते हैं। मगर फ्रांस में व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की मंत्रियों पर लिफारिशी चिट्ठियों बरसाने की इतनी ज़ुरी प्रथा पड़ गई है कि उस के बारे में वेचारे मंत्रियों का नातका बढ़ रहता है। प्रातः काल ही जो चिट्ठियाँ या डेर प्रत्येक मंत्री को मिलता है उस में अधिकतर ऐसी लिफारिशी चिट्ठियाँ ही होती हैं। लगभग नौ बजे अपनी गाड़ी या मोटर में बैठ कर जिस का कोचवान या ड्राइवर तिरगा झुन्वा लगाए होता है—मंत्री कौंसिल या कैबिनेट की बैठक में जाता है और दोपहर तक वहाँ रहता है। जिस दिन बैठक नहीं होती है उस दिन वह अधिकारियों और व्यवस्थापक सभा के सदस्यों से मिलता है जिन की उस से मिलने के लिए कतार लगी रहती है। दोपहर का भोजन कर के मंत्री को चेंबर अथवा सिनेट की सभा में जाना होता है। वहाँ से लौट कर जब वह अपने दफ्तर में आता है तो उसे अपनी मेज पर तरह-तरह के कागज़ातों और फाइलों के ढेर देखने के लिए रखे मिलते हैं जिन में उस के विभाग की तरफ से लिखे हुए पत्र और तैयार किए हुए ज़रूरी मसविदे होते हैं जो मंत्री शीघ्र भूँद कर इन कागज़ों पर दस्तखत नहीं करना चाहता है, उस के घटो इन कागज़ों के देखने हो ग चले जाते हैं। फिर जो अपने विभाग के मुख्य अधिकारियों से विभाग के रोज़ाना काम के विषय में भी बातचीत करनी होती है। ऐसी अवस्था में जो मंत्री मेहनती होने के साथ ही साथ कार्य-कुशल और शीघ्र निश्चयी नहीं होता है, वह या तो व्यवस्थापक सभा में अपनी हँसी कराता है या अपने विभाग का बिलौना हो जाता है। जब कभी किसी सरकारी समारोह में कोई

मनी पेरिस अथवा किसी प्रांतीय नगर में जाता है, तो बड़े ठाठ-बाट से सेना उस का स्वागत करती है। गाजे गाजे के साथ फौज एक कतार में खड़ी हो कर और सेना के अफसर तलवारें गींच कर उस को सलामी देते हैं। राष्ट्र का झंडा उसे सलामी देता है और एक केप्टन के नेतृत्व में साठ सैनिकों का 'गार्ड ऑफ़ ऑनर' उस की अगुवानी के लिए जाता है और दो सतरी मी उम्र के घर पर पहरा लगाने के लिए दिए जाते हैं।

फ्रांस में मंत्रियों को व्यवस्थापक सभा की दोनों सभायाँ, सिनेट और चेंबर, की चार्जवादी में भाग लेने का अधिकार होता है। जो मंत्री चेंबर का सदस्य होता है वह सिनेट में जा कर बोल सकता है और जो सिनेट का सदस्य होता है, वह चेंबर में जा कर बोल सकता है। जो दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, वह भी दोनों में जा कर बोल सकता है। चर्चा की सारी बातों में हमेशा मंत्रियों को काम-काज के कारण भाग लेना असंभव होता है। अस्तु, प्रजातन्त्र के प्रमुख के आदेश से चर्चा में भाग लेने के लिए सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिन को सरकारी 'कमीसेरीज' कहते हैं। मंत्री व्यवस्थापक सभा को शासन के लिए ज़ाबदार होते हैं, इस लिए धारासभा में सदस्य उन से उन के शासन के समय में प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री को किसी प्रश्न का उत्तर न देने या चुप रहने का अधिकार होता है। परन्तु सभा या अध्यक्ष जो प्रश्न लिख कर पूछता है उस का उत्तर न देने का मंत्रियों को अधिकार नहीं होता है, अधिक से अधिक मंत्री उस प्रश्न पर कुछ समय के लिए चर्चा स्थगित करा सकता है। परन्तु घरेलू शासन के विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन को एक महीने से अधिक स्थगित नहीं कराया जा सकता है। जो सदस्य प्रश्न पूछता है, वह चर्चा शुरू करता है और दूसरे सदस्य अगर जरूरत होती है, तो उस में भाग ले कर चर्चा को उठाते हैं। अतः म हर चर्चा के बाद जिस मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, उस की इच्छा के अनुसार व्यवस्थापक सभा उस प्रश्न पर प्रस्ताव स्वीकार करती है। मंत्री की इच्छा के अनुसार धारासभा में प्रस्ताव स्वीकार न होने पर उस मंत्री को प्रजातन्त्र के प्रमुख के सामने अपना इस्तीफा रख देना पड़ता है। अगर प्रश्न मंत्रि-मंडल की सारी नीति के विषय में होता है, तो सारा मंत्रि-मंडल इस्तीफा दे देता है। प्रजातन्त्र के प्रमुख की तरह मंत्रियाँ पर भी, चेंबर की तरफ से सिनेट की अदालत के सामने मुकदमा चलाया जा सकता है और उन को हर प्रकार की सजा दी जा सकती है। उन पर सिर्फ़ राष्ट्र के प्रति शान्तेतिक अपराधों के लिए ही नहीं, बल्कि पौजदारी के साधारण कानूनों के अनुसार भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अपने कामों से राष्ट्र को माली नुकसान पहुँचाने के लिए उन पर दीयानी का मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त करने तक के लिए कई बार व्यवस्थापक-सभा में चर्चा उठ चुकी है। परन्तु अभी तक राष्ट्र को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए मंत्रियों पर दीयानी का मुकदमा चलाने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा को नहीं है।

## ४—व्यवस्थापक-सभा

### १—नेशनल एसेंबली

फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा को 'नेशनल एसेंबली' अर्थात् राष्ट्रीय सभा कहते हैं। उस की दो सभाएँ होती हैं। एक को 'मिनेट' कहते हैं और दूसरी को 'चेंबर ऑफ़ डिपुटीज' अर्थात् प्रतिनिधि-सभा। सन् १७८९ ई० से पहले फ्रांस में कानून बनाने और कानूनो का शासन करने, दोनों ही की सत्ता राजा के हाथ में थी। सन् १७८९ ई० के व्यवस्थापक-सम्मेलन के निश्चय के अनुसार कानून बनाने का अधिकार फ्रांस की धारा सभा नेशनल एसेंबली को दे दिया गया था। मगर कानूनो का धारासभा से स्वीकृत होने के बाद अमल के लिए एलान करने का अधिकार राजा के ही हाथ में रहता गया था। सन् १७९२ ई० में राजा से यह अधिकार भी ले लिया गया था, और एसेंबली से स्वीकृत हो जाने के बाद ही कानून अमल में आने लगे थे। पाठकों को याद होगा कि क्रांति के समय कानून बनाने के सारे अधिकार थे। फ्रांस के जमाने में कानून पेश करने का अधिकार सिर्फ़ सरकार का था। उन पर केवल उद्देश्य करने का अधिकार ट्रिब्युनेट का था और उन पर मत केवल लेनिस्लातिफ़ में लिए जाते थे। प्रथम साम्राज्य के जमाने में कानूनों पर वृत्त केवल लेनिस्लातिफ़ में होने लगी थी और ट्रिब्युनेट बंद कर दी गई थी। कानूनों को 'कौंसिल ऑफ़ स्टेट' की सहायता से महाराजा बनाता था। बाद में पुराने राज घराने को फिर फ्रांस का राज मिलने पर राजा को कानून पेश करने, स्वीकार करने और अमल के लिए एलान करने के अधिकार दे दिए गए थे। 'चेंबर ऑफ़ डिपुटीज' और 'चेंबर ऑफ़ पीयर्स'—उस समय की व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाओं—को कानूनों पर सिर्फ़ महसूस करने और मत देने का अधिकार था।

सन् १८३० ई० की क्रांति के बाद व्यवस्थापक-सभा के अधिकार बढ़ गए थे, और सन् १८४८ ई० की राज-व्यवस्था ने तो कानूनसभों के सारे अधिकार सिर्फ़ प्रतिनिधियों की सभा को ही दिए थे। प्रजातन्त्र के प्रमुख को किसी कानून पर धारासभा को पुन विचार करने के लिए मजबूर करने का अधिकार अवश्य दिया गया था। दूसरे साम्राज्य के जमाने में फिर 'कौंसिल ऑफ़ स्टेट' कानूनों के मसविदे बनाने लगी थी और 'प्रतिनिधि सभा' को सिर्फ़ फिर उन पर महसूस करने और उन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार रह गया था। प्रजा के प्रतिनिधि कानूनी मसविदा में कोई संशोधन नहीं कर सकते थे। मिनेट को कानून नामजूर करने का और महाराजा को मजूर करने का अधिकार दिया गया था। साम्राज्य के आखिरी दिनों में 'केवल लेनिस्लातिफ़' को कानूनों के प्रस्ताव और कानूनों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था। बाद में 'नेशनल एसेंबली' ही कानूनों को बनाने का सारा काम करने लगी और प्रजातन्त्र के प्रमुख को केवल एसेंबली में फिर से किसी मसविदे पर विचार करवाने का केवल अधिकार रह गया। अतः सन् १८७५ ई० की राज-व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा

की दोनों सभाओं, 'सिनेट' और 'चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़' में बाँट दिया गया। प्रजातन्त्र के प्रमुख को इस राज-व्यवस्था के अनुसार भी सिर्फ़ यही अधिकार रहा कि जो कानून उस की समझ में उचित न हो, उस पर वह, कुछ शर्तों परी हो जाने पर, दोनों सभाओं से फिर से विचार करना सकता है। व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं के सदस्यों की सम्मिलित बैठक में प्रजातन्त्र के प्रमुख को चुनने और राज-व्यवस्था में फेर पार करने का काम किया जाता है।

## २—चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़ या प्रतिनिधि-सभा

हर एक २१ वर्ष से ऊपर का आदमी 'चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़' के सदस्य के चुनाव में अपना मत डाल सकता है, और हर एक २५ वर्ष से ऊपर का मतदार सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार हो सकता है। कुछ अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र से उम्मीदवार नही हो सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों के अपने अधिकार क्षेत्र से चुनाव के लिए लड़ने से मतदारों पर दबाव पड़ने और चुनाव में अन्याय होने का खतरा रहता है। जल और थल सेना के सिपाही और अधिकारी भी उम्मीदवार नही हो सकते हैं, क्योंकि सेना का राजनीति के झगड़ों से अलग रखा जाता है। उन राजकुलों के लोग भी, जो प्रास पर राज कर चुके हैं, उम्मीदवार नही हो सकते हैं, क्योंकि सभ्य है कि वे धारासभा में कुछ कर प्रजातन्त्र के निरुद्ध पड़्यन रचने का और देश की राज-व्यवस्था को उलट पलट करने का प्रयत्न करें। जिस स्थान में मतदार अपना मत देना चाहता है, वहाँ या तो उसे रहते होना चाहिए या वहाँ छ मास रह चुका हो। मिया को प्रास में इंग्लैंड और अमेरिका की तरह मताधिकार नही है, और न वहाँ इस अधिकार की अधिक माँग ही है। अगर कोई मतदार कोई निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का अधिकार रखता हो, तो उस को उन में से एक क्षेत्र अपना मत देने के लिए चुन लेना होता है, क्योंकि प्रास में एक आदमी एक से अधिक मत किसी हालत में नहीं दे सकता है। जिस क्षेत्र में जिस का चेंबर के चुनाव के लिए मत रहता है, उसी में और सब चुनावों के लिए भी रहता है। एक क्षेत्र से चंबर के लिए और दूसरे से चुगी के लिए कोई नागरिक मत नहीं दे सकता। डेपुटीज़ डिपार्टमेंट<sup>१</sup> से चार वर्ष के लिए चुन कर आते हैं, और हर चार साल के बाद 'चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़' का नया चुनाव होता है। हर डिपार्टमेंट से पच्चहत्तर हजार आदमी और उसके उड़े भाग के लिए चेंबर में से एक प्रतिनिधि चुन कर आता है। मगर हर एक डिपार्टमेंट से कम से कम तीन डेपुटीज़ जरूर चुने जाते हैं। शुरू-शुरू में चेंबर में ५३३ डेपुटीज़ थे। सन् १६१६ ई० में प्रास की मर्दुमशुमारी के अनुसार चेंबर में ६२६ डेपुटीज़ थे और इसी के लगभग आमतौर पर रहती है। इन में प्रास के साम्राज्य के अन्य भागों के भी प्रतिनिधि शामिल रहते हैं—ऑल्डोमर्स के पाँच प्रतिनिधि, कैचिन चाइना, गुइडेलूप, गायगा, मार्टिनिक्कू, रियूनियन, सेनेगल और भारतवर्ष के एक-एक प्रतिनिधि। हमारे देश में

<sup>१</sup> प्रास की तरह एक भाग का नाम।

चन्ननगर, पाडेचेरी इत्यादि जो छोटे छोटे थोड़े से भाग अभी तक फ्रांस के आधीन हैं, उन सब की तरफ से एक प्रतिनिधि फ्रांस के चेंबर ऑफ् डेपुटीज़ में बैठता है। चेंबर का चुनाव किसी कानून के अनुसार निश्चित तारीख या समय पर नहीं होता है। राज व्यवस्था के अनुसार चेंबर की मियाद खत्म होने के साठ दिन धानी चेंबर भंग होने के दो मास के भीतर कोई तारीख प्रमुख को, चेंबर का नया चुनाव करने के लिए, अपना हुक्म निवाल कर निश्चित करनी चाहिए। इस हुक्म निम्नलने की तारीख और चुनाव की तारीख में कम से कम तीन दिन का अंतर होना चाहिए। चुनाव हो जाने के बाद दस दिन के भीतर चेंबर की पहली बैठक होनी चाहिए। चुनाव के कानून के अनुसार सन् १९१६ ई० तक मत से अधिक मत पाने से ही कोई उम्मीदवार डेपुटी नहीं चुना जा सकता था। उस को सफल होने के लिए जितनी सख्या मतदारों की उस के निर्वाचन क्षेत्र में हो, उस का कम से कम एक चौथाई भाग और जितने मत चुनाव में उस के निर्वाचन-क्षेत्र में पड़े, उन की बहु-सख्या पहले पचें<sup>१</sup> पर मिलनी आवश्यक होती थी। अगर पहली दफा पचें पड़ने पर किसी उम्मीदवार को इतने मत नहीं मिलते थे, तो फिर दो हफ्ते बाद दूसरी बार पचें पड़ते थे। इस दूसरे पचें पर फिर जिस को सिर्फ़ सब से अधिक मत मिलते थे, वही डेपुटी चुन लिया जाता था। इस क़ायदे से एक तुल्यमान यह होता है कि बहुत से बार लोग या तो अपना जोर दिखाने और उम्मीदवारों को तग कर के अपना कुछ फायदा उठाने के लिए चुनाव में खड़े हो जाते थे, और पहले पचें पर किसी उम्मीदवार को आवश्यक सख्या मतों की नहीं मिलने देते थे। पहले पचें पर नाकामयाब होने से उन का ख़य तो कुछ गिगड़ता नहीं था, परन्तु दूसरे चुनाव पर उन की पूँछ उठ जाती थी और हम प्रकार वे कुछ रियायतें पा जाते थे।

यूरोपीय युद्ध समाप्त होने के बाद सन् १९१६ ई० में चुनाव के कानून में परिवर्तन हो गया। जिन डिपार्टमेंट से छ से अधिक डेपुटी चुन कर आते थे उन को इस प्रकार विभाजित किया गया कि वहां से छ से अधिक प्रतिनिधि चुन कर न आ सकें। अनुपात निर्वाचन<sup>२</sup> और चुनाव में एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनने के स्थान में 'सूची-पद्धति'<sup>३</sup> का प्रयोग प्रारंभ किया गया। सूची-पद्धति का मतलब यह है कि किसी क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार अलग अलग चुनाव के लिए नहीं खड़ा होता है। एक क्षेत्र में जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उतने उम्मीदवारों की एक सूची दाखिल कर दी जाती है और मतदार एक एक आदमी के लिए मत न दे कर सूची के लिए मत देते हैं। जितने विचार और दलों के उम्मीदवार खड़े होते हैं, उतनी ही प्रायः सूचियाँ होती हैं। मतदारों को यह हक भी होता है कि वे किसी भी प्रस्तावित सूची के लिए मत न दे कर कई सूचियों में से नाम चुन कर अपने चुनाव के पचें पर एक नई सूची बना कर उस के लिए मत दे आवे। मगर इतने स्वतंत्र विचार के गिरले ही मतदार होते हैं। जिस प्रकार अन्य सारे प्रजा-सत्तात्मक राज्यों में दलों के हियान से मत पड़ते हैं, वैसे ही मांस में भी मत पड़ते हैं। अगर कोई आदमी अकेला ही खड़ा होता है तो उस के नामज़दगी के कागज़ को भी एक

<sup>१</sup> फ़रेंट बैलट। <sup>२</sup> प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। <sup>३</sup> लिस्ट सिस्टम।



नामवाली सूची मान लिया जाता है। क्षेत्र से जितने प्रतिनिधि चुने जाने वाले होते हैं उन से अधिक नाम किसी सूची में नहीं हो सकते, कम नामों की सूचियाँ हो सकती हैं। यह सूचियाँ चुनाव में पाँच दिन पहले डिपार्टमेंट के सौ मतदारों के हस्ताक्षरों के साथ डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी प्रीफेक्ट के पास कानून के अनुसार दारिद्र्य हो जानी चाहिए। इन सूचियों की नक़्क़े चुनाव से दो दिन पहले चुनाव के स्थानों पर चिपका दी जाती हैं। मतदार चुनाव के दिन, निर्वाचन पर<sup>१</sup> पर छपी हुई इन सूचियों के लिए गंथवा उन में से कुछ नाम काट कर और दूसरी सूचियों के कुछ नाम किसी सूची में जोड़ कर या अपनी तरफ से कुछ नए नाम किसी सूची में जोड़ कर अपनी इच्छानुसार जैसा चाहते हैं मत देते हैं।

गलत और खाली पत्रों को खारिज कर के, जिन उम्मीदवारों को चुनाव में पड़नेवाले मतों की ग़ुनग़ुना मिलती है, उन को मतों की सख्या के हिसाब से आवश्यक सख्या तक चुन लिया जाता है। अगर आवश्यक सख्या में उम्मीदवारों को इतने मत नहीं मिलते हैं और कुछ जगह खाली रह जाती हैं, तो चुनाव में जितने मत पड़ते हैं उन की सख्या को, जितने प्रतिनिधि चुने जानेवाले होते हैं उन की सख्या से बाँट कर जो सख्या प्राप्त होती है, उस से हर एक सूची को मिलानेवाले मतों के श्रौसत को बाँट कर विभिन्न सूचियों के लिए जो सख्या प्राप्त होती है, उतने उतने प्रतिनिधि मतों की सख्या के हिसाब से उन सूचियों में से चुन लिए जाते हैं। विभिन्न सूचियों को जो मतों की सख्या मिलती है, उस को उस सूची में जितने नाम होते हैं उससे बाँट कर जो सख्या प्राप्त होती है उस को उस सूची में ग़ौमत माना जाता है। हर एक सूची में से मतों की सख्या के हिसाब से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और अगर दो उम्मीदवारों को बराबर मत मिलते हैं तो उन में से जो अधिक उम्र का होता है वह चुन लिया जाता है। जिस उम्मीदवार को अपनी सूची के ग़ौमत के आधे से अधिक मत नहीं मिलते हैं उस का चुनाव नहीं लिया जा सकता है। अगर चुनाव में उस क्षेत्र में जितने मतदार होते हैं, उन की आधी से अधिक सख्या मत नहीं देती है, या किसी सूची को इतनी सख्या में मत नहीं मिलते हैं, जो उस सख्या के बराबर हो, जो चुनाव में जितने मत पड़े हों उन को जितने प्रतिनिधि चुने जानेवाले हों उन की सख्या से बाँट कर प्राप्त होती है, तो दो हफ़्ते के बाद फिर नया चुनाव लिया जाता है। अगर इस दूसरे चुनाव में भी किसी सूची को इतनी सख्या मतों की नहीं मिलती है तो फिर सब उम्मीदवारों में से जिन को सब से अधिक मत मिलते हैं उन को चुन लिया जाता है। सन् १६१६ के चुनाव के इस कानून के पहले के कानून के अनुसार दूसरे पत्रों पर जो दिक्क़तें होती थीं उन दिक्क़तों से बचने के लिए यह तरीका अख़्तियार किया गया था। इसी दंग के चुनाव को हमने अनुपात निर्वाचन नाम दिया है।

अनुपात निर्वाचन को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट से छः डेपुटी चुने जाते हैं और वहाँ चुनाव पर ६०,२४०

<sup>१</sup> बैलट पेपर्स।

पचें पड़ते हैं। अगर यह सब पचें एक ही सूची के उम्मीदवारों को मिलते तो उस सूची को इस से छ. गुने अर्थात् ३६१४४० मत मिलते। मगर ऐसा होता नहीं है। बहुत से पचें-खराब हो जाते हैं और बाकी गई सूचियों में बँट जाते हैं। मान लीजिए कि यह मत चार सूचियों में इस प्रकार बँट जाते हैं:—

## सूची (अ)

जयनदन	३२,६५४
हरिदास	२६,८२७
ईश्वरसहाय	२६,६४०
थम्मन सिंह	२५,२७४
व्यास	१८४०१
जयदेव	१२५२४
कुल	१४८३११
औसत	२४०१८

## सूची (इ)

विश्वनाथ	१८१२५
नारायण स्वामी	१६२४७
जमनादास	१५८२२
दृष्ट मेहन	१२६५६
मूलराज	८४०४
लालभाई	४०३१
कुल	७५२८६
औसत	१२५४७

## सूची (उ)

उमाशंकर	१५२४७
सरजी भाई	१४६२६
बन्धैयालाल	१२१७२
लीलावती	८६२४
पन्नालाल	६०१८
गुलजारी	५१०१
कुल	६१७६१
औसत	१०२६८

## सूची (ए)

गुलाम राय	५१६४
ऐमीनी	४०२०
आविद अली	३२६२
प्यारेलाल	११२३
दोस्त मुहम्मद	१११६
प्रलाउदीन	१०८२
कुल	१५८१२
औसत	२६३५

$$\text{भाज्यफल } ६०२४० \div ६ = १००४०$$

ऊपर की इन चारों सूचियों में सिर्फ जयनदन को, चुनाव में जितने मत पड़े, उन की बहु मख्या मिली। 'प्रत. छ.' प्रतिनिधियों में से सिर्फ जयनदन चुना गया। बाकी पाँच जगहों के लिए चुनाव के भाज्यफल को सूचियों के औसत से बाँटने पर सूची 'अ' के भाग में दो और प्रतिनिधि और सूची 'इ' और सूची 'उ' के भाग में एक एक प्रतिनिधि आते हैं। सूची 'ए' का औसत भाज्यफल से कम होने से उस के हिस्से में एक भी प्रतिनिधि नहीं आता है। सूची 'अ' में से मतों की मख्या के अनुसार दो प्रतिनिधि और चुनने से हरिदास और ईश्वरसहाय तथा सूची 'इ' और सूची 'उ' में से उसी प्रकार एक एक प्रतिनिधि चुनने से विश्वनाथ और उमाशंकर चुन लिए जाते हैं। फिर भी एक जगह रह जाती है। कानून के अनुसार ऐसी हालत में यह जगह उस सूची को मिलती है, जिस का औसत सब से अधिक होता है। मगर उस सूची में यह जगह उसी उम्मीदवार को मिल सकती है जिस को कम से

रुम उस सूची के अंतर्गत के आवे से अधिक मत मिले हों। अगर उस सूची से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं होता है तो उस से रुम अंतर्गत वाली दूसरी सूची से इसी प्रकार के उम्मीदवार को चुन लिया जाता है। अतः, ऊपर की सूचियाँ में से छठा प्रतिनिधि धम्मन सिंह को चुना जाता है।

चेंबर ऑफ़ डेपुटीज का चार साल के लिए चुनाव होता है, मगर जैसा कहा जा चुका है प्रजातन्त्र के प्रमुख को सिनेट की सम्मति से चेंबर ऑफ़ डेपुटीज को चार साल की मीयाद से पहले भी भंग कर देने का अधिकार होता है। परंतु आज तक एक बार सन् १८७७ ई० के बाद, अभी चेंबर अपनी मीयाद से पहले भंग नहीं हुआ है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ़ कामन्स की तरह फ्रांस के चेंबर ऑफ़ डेपुटीज का जन चुनाव न हो कर, अमेरिका की कांग्रेस की तरह, हमेशा समय पूरा होने पर ही प्रायः चुनाव होता है। चेंबर की चार साल की मीयाद अनुभव से सुभीते की समझ कर निश्चित की गई है। सन् १७९१ ई० की राज व्यवस्था में धारासभा की मीयाद दो वर्ष रक्ती गई थी। सन् १७९५ और सन् १८४८ ई० की प्रजातन्त्र राज-व्यवस्थाओं में तीन वर्ष और सन् १७९९ और १८१४ ई० में पाँच वर्ष की रक्ती गई थी। सन् १८५२ ई० में यह मीयाद छ वर्ष कर दी गई और सन् १८७५ ई० की राज व्यवस्था में आखिरकार चार वर्ष रक्ती गई जो अनुभव से काफी सुभीते की मीयाद साबित हुई। इंग्लैंड की तरह किसी डेपुटी को मंत्री बन जाने पर चेंबर से इस्तीफा दे कर, फिर से चुनाव के लिए नहीं खड़ा होना पड़ता। सन् १९१६ ई० तक चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को चुनाव की तारीख से पाँच दिन पहिले, अपने क्षेत्र के प्रीफेक्ट के सामने किसी एक चुगी के अध्वक्ष की गवारी से अपनी उम्मीदवारी के एलान का फागन दाखिल कर देने की जरूरत होती थी। मगर सन् १९१६ के बाद में चुगी के अध्वक्ष के स्थान में सौ मतदारों के हस्ताक्षर होने की शर्त कर दी गई है।

### ३—सिनेट

सन् १८७१ ई० के व्यवस्थापक सम्मेलन ने जब व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओं रखने का निश्चय कर लिया, तब यह समस्या सुलझाने की जरूरत हुई कि न तो दोनों सभाएँ एक रूप की हों और न फ्रांस की प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था में इंग्लैंड के हाउस ऑफ़ लार्ड्स की तरह कुबेरशाही का देखल रहे। 'चेंबर ऑफ़ डेपुटीज' की तरह व्यवस्थापक सभा की ऊपरी सभा का चुनाव भी सर्वसाधारण के मतों से करने से सिनेट केवल चेंबर ऑफ़ डेपुटीज का दूसरा रूप बन जाती। जिस व्यवस्थापक सभा का विकास इंग्लैंड की तरह धीरे धीरे न हुआ हो और जो प्रजासत्तात्मक सिद्धांत पर नए सिरे से बनाई जा रही हो, उस में इंग्लैंड की भाँति मौलसी सदस्यों के रखने का विचार भी नहीं किया जा सकता था। प्रजातन्त्र के प्रमुख को सिनेट के सदस्य बनाने का अधिकार देने में यह कठिनाई आती थी कि सिनेट के सदस्य चेंबर ऑफ़ डेपुटीज के सदस्यों के साथ नेशनल एसेंबली में बैठ कर प्रजातन्त्र के प्रमुख को चुनते हैं। अगर प्रमुख के चुने हुए

सदस्यों को प्रमुख चुनने का अधिकार दे दिया जाय तो प्रजासत्तात्मक राज्य की शीर्ष ही इतिथी हो जाय। अस्तु, सब राजा का विचार रग कर एक ममकीति का समाना निकाला गया। सिनेट के सदस्यों की संख्या कुल ३०० रखनी गई, जिन में से ७५ सदस्यों को ज़िदगी भर के लिए व्यवस्थापन-सम्मेलन ने स्वयं चुन लिया, और उन की जगह खाली होने पर उन को बाद में भरने का अधिकार सिनेट को दे दिया। शेष २२५ सदस्यों को फ्रांस के डिपार्टमेंट और उपनिवेशों से<sup>१</sup> चुनने का निश्चय किया गया। डिपार्टमेंट ग आगदी के हिसाब से सदस्य की संख्या गढ़ दी गई। तीन और नौट के डिपार्टमेंटों को पाँच-पाँच, छह डिपार्टमेंटों को चार-चार, सत्ताइस को तीन-तीन, और गहरी को दो-दो सदस्य दे दिए गए। हर एक डिपार्टमेंट अथवा उपनिवेश के मुख्य नगर में उस डिपार्टमेंट अथवा उपनिवेश के चेंबर और डेपुटीज के सदस्यों, डिपार्टमेंट की कौंसिल के सदस्यों, डिपार्टमेंट के अदर की सारी पेटाडाइज़मेंट<sup>२</sup> की कौंसिल के सदस्यों और डिपार्टमेंट के अदर की सब म्यूनिसिपैलिटियों के एक एक प्रतिनिधिया की एक सभा मिल कर डिपार्टमेंट से चुने जानेवाले सिनेट के सदस्य का चुनाव करती है। सिनेट के सदस्य नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मगर सिनेट के एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल चुने जाते हैं। बाद में सन् १८८४ ई० के एक संशोधन के अनुसार यह निश्चय हुआ कि नेशनल एसम्बली ने १८७५ सदस्यों को ज़िदगी भर के लिए चुना था, वे जब तक ज़िदा हैं, सिनेट के सदस्य रहने। मगर उन की जगह खाली होने पर वे जगह भी और गी तरह आगदी के अनुसार डिपार्टमेंटों ग बाँट दी जायेंगी और म्यूनिसिपैलिटिया की ओर से सिनेट के चुनाव के लिए एक एक प्रतिनिधि ही नहा, बल्कि म्यूनिसिपैलिटियों के सदस्यों की संख्या के अनुसार एक से चौबीस तक प्रतिनिधि आ सकते हैं। अस्तु, पेरिस की म्यूनिसिपैलिटी की ओर से सिनेट में ग्यारह तीस प्रतिनिधि आते हैं। फ्रांस की 'सिनेट' का चुनाव सीधा निर्वाचन नहीं करते हैं, परोक्ष निर्वाचन से प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधिया द्वारा किया जाता है। चालीस वर्ष से कम उम्र का कोई मनुष्य सिनेट का सदस्य नहीं हो सकता। चेंबर ऑफ़ डेपुटीज के पचीस वर्षवाले सदस्यों की जवानी और जोश में सजीदगी और विचारशीलता का समावेश करने के विचार से व्यवस्थापन सभा की दूसरी सभा सिनेट के सदस्यों की ४० वर्ष उम्र रखनी गई है। जो लोग चेंबर के सदस्य नहीं हो सकते हैं, वह सिनेट के भी सदस्य नहा हो सकते हैं। अपने अपने सदस्यों के चुनाव के भगडों का फैसला सिनेट और चेंबर दोनों सभाएँ खुद करती हैं। यह काम वास्तव में अदालती होने से इन सभाओं में उतनी निष्पक्षता से नहीं किया जाता है, जितना अदालतों में हो सकता है। चेंबर ऑफ़ डेपुटीज ग बैठ चुकनेवाले गहुत से लोग सिनेट में चुन कर आते हैं। फ्रांस की सिनेट की गिनती दुनिया की बड़ी से बड़ी धारासभाओं में होती है।

<sup>१</sup> २१८ सदस्य डिपार्टमेंटों से और सात उपनिवेशों से।

<sup>२</sup> डिपार्टमेंट से छोटा देश का भाग।

## ४—काम-काज

सिनेट और चार ग्रॉव् डेपुटीज दोनों अपनी पहली बैठक में अपना काम काज चलाने के लिए मर्मचारी, जिन को 'ब्युरो' कहते हैं, चुनते हैं। ब्युरो में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, क्लर्क इत्यादि सारे मर्मचारी आ जाते हैं।

दोनों सभाओं में लगभग चार-चार उपाध्यक्ष, छ से आठ तक मंत्री और तीन क्लर्क होते हैं। इन का चुनाव सूची पद्धति से सभा के सदस्यों में से किया जाता है, और वे बार-बार चुनाव के लिए रखे हो सकते हैं। ब्युरो सभा का काम चलाने का ढंग निश्चय करता है और स्टैनोंग्रफर्स, क्लर्क, पुस्तकाध्यक्ष और दरगान वगैरह सभा के नौकरों को नियुक्त करता है।

अध्यक्ष सभाओं के प्रतिनिधि और सभाओं के अधिकारों और इज्जत के रखावले समझे जाते हैं। उन का फर्ज होता है कि सभाओं में बोलने की पूरी स्वतन्त्रता कायम रखें और जो नियम काम-काज चलाने के लिए सभा बनावे उन का सदस्यों से पालन करावे। प्रजातन्त्र के प्रमुख के बाद राष्ट्र में सिनेट के अध्यक्ष का दूसरा दर्जा, चेंबर ऑफ् डेपुटीज के अध्यक्ष का तीसरा दर्जा और प्रधान मंत्री का चौथा दर्जा समझा जाता है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ् कॉमन्स के स्पीयर की तरह म्रास की व्यवस्थापक-सभा के अध्यक्ष का काम सिर्फ सभा का काम चलाना ही नहीं होना है। वह चाहे तो कुर्सी छोड़ कर चर्चा में भाग ले सकता है। उपाध्यक्षों में से कोई भी एक, अध्यक्ष की गैरहाजिरी में, अध्यक्ष का काम करता है। मंत्रियों में से चार मंत्री सभा की बैठक में हमेशा उपस्थित रहते हैं। उन का काम सभा के राजज्ञाप तैयार करना और मत गिनना होता है। क्लर्क के हाथों में लेन देन सारी सभा के स्पष्ट पैसे का सारा काम रहता है। उपाध्यक्ष और मंत्रियों को कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। क्लर्क के सदस्य से दुगुना भत्ता मिलता है। इस प्रबंध के अतिरिक्त ब्युरो का एक दूसरा उपयोग भी होता है। व्यवस्थापक-सभा के नियमों के अनुसार सभाओं की पहली बैठक में चेंबर को पत्ती डाल कर सत्ताधन-सत्ताधन सदस्यों के ग्यारह ब्युरो में और सिनेट को तैंतीस या चौतीस चौतीस के नौ ब्युरो में बाँट दिया जाता है। बाद में हर महीने यह भाग होते रहते हैं। हर एक ब्युरो अपना एक प्रधान और एक मंत्री चुन लेता है और जरूरत पड़ती है, तो प्रधान ब्युरो की बैठक करता है। नई व्यवस्थापक सभा के उदने पर ब्युरो सदस्य के चुनाव की जाँच करता है और फिर उस के चुनाव को स्वीकार करती है। सभा के सामने आनेवाले मसविदों और रे मसला पर भी पहले ब्युरो विचार करता है। पहले तो मारे मसविदे सीधे ही ब्युरो के विचार के लिए आते थे। मगर ब्युरो के काफी उधे और सदा उदलते रहने के कारण म में बड़ी दिक्कत होती थी। इस लिए अब मसविदों पर अच्छी तरह विचार करने लिए सारे ब्युरो से एक एक आदमी चुन कर कमेटियाँ बना ली जाती हैं। यह कमेटियाँ अस्थाया होती हैं। जिस मसविदे पर विचार करने के लिए वे बनाई जाती हैं उन पर

विचार कर चुनने के बाद वे खत्म हो जाती हैं। बहुत से सरकारी मगनिदे व्युरो में आ कर इतने बदल जाते थे कि मनी उन्हें स्वीकार नहीं करते थे, और उन्हें इस्तीफा दे देना होता था। इस दिक्कत को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के मसविदों पर विचार करने के लिए व्युरो के स्थान में अब चेंबर ऑफ़ डेपुटीज स्वयं स्थायी कमेटियाँ बना देता है। जरूरत पड़ने पर पहले की तरह अस्थायी कमेटियाँ भी बनाई जाती हैं। चुगी, व्यापार, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, सेना, जल सेना, परराष्ट्र नियंत्रण, शिक्षा, खेती, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मसविदों पर विचार के लिए चेंबर ऑफ़ डेपुटीज की स्थायी समितियाँ रहती हैं।

सन् १८७५ ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा की बैठकें जनता के लिए खुली होती चाहिए। व्यवस्थापक सभा की कार्यवाही की खबर जनता को रहने से जनता व्यवस्थापक सभा पर अपना मत प्रकट कर के देना दे सकती है। फ्रांस के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता रोसपीयर ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि व्यवस्थापक-सभा का कार्य अधिक से अधिक जन समुदाय की आँखों के सामने होना चाहिए। सन् १७८६ ई० में जब एस्टेट्स जनरल की सभा बैठी थी, तो उस के चारों ओर फौज ने घेरा डाल रखा था और जनता को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सभा ने राजनैतिक स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रबंध का विरोध किया था, और राजा के पास इस बात की शिकायत भेजी थी। सन् १७६१ ई० की राज-व्यवस्था में फ्रान्स सभा की बैठकें और चर्चा सार्वजनिक कर दी गई हैं। क्रांति के जमाने में तो दर्शक भी आवाजें लगा कर सभा की बैठकों में भाग लेते थे। इस में बड़े बड़े होने लगे और सभाओं के काम में अड़चनें पड़ने लगीं। अतः, दर्शकों की संख्या निश्चित कर दी गई। पहले और दूसरे साम्राज्य के जमाने में दोनों सभाओं की बैठक दर्शकों के लिए बंद रहती थी। सन् १८५२ ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार चेंबर ऑफ़ डेपुटीज के अध्यक्ष की लिपी हुई रिपोर्ट के सिवाय चेंबर की चर्चा नहीं प्रकाशित नहीं हो सकती थी। परंतु अब सर्व-साधारण को दोनों सभाओं में दर्शक की तरह जाने का अधिकार है। जब दर्शकों की गीलों में बैठने की जगह भर जाती है, तब और आदमियों को अंदर अवश्य नहीं घुसने दिया जाता है। अब अखबारों में भी व्यवस्थापक-सभा की चर्चाएँ बेरोक-टोक छपती हैं। मगर राज-व्यवस्था के अनुसार आजकल भी जरूरत पड़ने पर व्यवस्थापक सभा की बैठकें बंद हो सकती हैं। परंतु इस अधिकार के उपयोग की इतनी कम जरूरत पड़ती है कि उस का लगभग उपयोग ही नहीं किया जाता है।

चेंबर ऑफ़ डेपुटीज की बैठकें बूर्गेज राज-भवन में होती हैं, जो सीन नदी के बाएँ किनारे पर बना हुआ है। १८ वीं सदी में इस जगह पर बूर्गेज की नवाज्जादी ने एक होटल बनवाया था। परंतु सन् १७६० ई० में यह जगह फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार के कब्जे में आई और फिर यहाँ पर पाँच सौ की कंसिल के लिए एक बड़ा हॉल बनवा दिया गया जिस में पूरी सुंदर कारीगरी की सज्जण है और जिस सभामंडप के स्तंभ और 'स्वतंत्रता', 'शांति', 'बुद्धिमत्ता', 'न्याय' और 'वक्त्रता' की मूर्तियाँ रखी हैं। इसी हॉल में आज कल चेंबर ऑफ़ डेपुटीज की सभा बैठती है। कभी सभा में सभा के काम-काज के नियम पर विचारपूर्वक चर्चा चलती है और विचारशीलता और शांति का राज्य रहता है।

कभी सभा वाक्युद्ध का असाइन बन जाती है और सभा स्थल की गौरों तमाशगीना—खास कर औरतों से ठसाठस भर जाती हैं। उद्गुत से दर्शक यहां सिर्फ सरकार या नाटक की तरह तमाशा देखने की गरज से आते हैं। सभा के सदस्यों में बहुत से सुदर व्याख्यान-दाता होते हैं और जन के बोलने के लिए राडे होते हैं, तब सब राडे ध्यान से उन्हें सुनते हैं परंतु जन उद्गुत देर तक चर्चा चलती है और लोग ऊपने लगते हैं, तो लोग शोरगुल भी मचाने लगते हैं।

सिनेट की सभा में ऐसा शोरगुल सुनने में नहा आता है। वह लकड़मनूर के राजभवन में होती है। यह हमारा १७ वीं सदी में मेरी दे मेडीसिस के लिए बनाई गई थी। क्रांति के जमाने में इस को जेलखाना बना दिया गया था, जिस में हिस्ट्री, दाता इत्यादि क्रांतिकारी नेता क्लैद रखे गए थे। डाइरेक्टरी और फासलेट के जमाने में यहाँ पर सरकार का दफ्तर था। पहले साम्राज्य में यहां सिनेट की सभा बैठती थी और फिर राजाशाही के जमाने में हाउस ऑफ पीयरस के उपयोग में यह स्थान आया। सन् १८५२ ई० में फिर यहाँ सिनेट बैठी और सन् १८७६ ई० से परावर यहां सिनेट बैठती है। इस सभा स्थल में भास के प्रख्यात राजनीतिज्ञों की मूर्तियाँ लगी हैं, और सुनहरी पत्थीकारी और लकड़ी का मजा सुदर काम है। सदस्या के बैठने के लिए सभास्थल में लाल मखमल की आराम कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। सिनेट की सभाएँ बनी आत और गभीर होती हैं।

दोना सभाआ के हॉल अर्थ चब्राकार हैं, और उन में जितने सदस्य सभाआ में आते हैं, उतनी ही बैठने की जगह पनी हैं। हाल के बीच में एक ऊँची कुर्सी अध्यक्ष के बैठने के लिए होती है और उस के सामने एक मंच होता है, जिस को ट्रिब्यून कहते हैं। बोलनेवालों को इस मंच पर आ कर बोलना होता है। इस मंच के दोना ओर व्याख्यान और धारवाह की रिपोर्ट लिखनेवाले सरकारी स्टैनेआपर बैठते हैं, जिन की लिखी हुई रिपोर्टें अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने के बाद रोजाना सरकारी 'जरनल' में छपती हैं। मंच के सामने की जगहों पर सरकार की मंत्रि मंडली बैठती है और उन के पीछे सभा के दूर सदस्य इस प्रकार बैठे जाते हैं कि सरकार पक्ष के सदस्य अध्यक्ष के दाहिने और प्रजा पक्ष के राएँ तरफ रहते हैं। जिस सदस्य को 'बोलने की इच्छा होती है, वह मंत्रियों के पास खसी हुई सूत्रियाँ पर अपना नाम लिख देते हैं। किसी भी सदस्य के चर्चा स्थगित करने के प्रस्ताव पर तुरत मत लिए जाते हैं। मत हाथ उठा कर, राडे हो कर अथवा 'हां' के लिए सपेद और 'ना' के लिए नीले पर्चा पर नाम लिख कर दिए जाते हैं।

जनता के हस्ताक्षर, उत्पात और कोनाहल से दूर शांतिपूर्वक काम चलाने के लिए रोयलपीयर के प्रचंड विरोध करने पर भी सन् १८७५ ई० में व्यवस्थापन-सभा और कार्य-कारिणी का स्थान पेरिस में न रख कर वारमेल्ज़ में रखा गया था। मगर कुछ वर्ष बाद पेरिस में शांति स्थापित हो जाने पर और दूरवर्ता वारमेल्ज़ में सरकार की रातधानी रखने की दिक्कतों का विचार कर के पेरिस को ही रातधानी बना लिया गया। व्यवस्थापन सभा की बैठनों का समय राज व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, व्यवस्थापन-सभा की स्वयं इच्छा अथवा प्रजापक्ष के प्रमुख के नाम पर फाम करनेवाले मंत्रि मंडल की इच्छाअनुसार या

प्रजातन्त्र के प्रमुख की इच्छानुसार तय कर लिया जाता है। सन् १८७१ ई० की राज व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा की बैठक हर साल जनवरी के दूसरे मंगलवार को होनी चाहिए और पाँच महीने तक कम से कम चलनी चाहिए और दोनों शाखाओं—सिनेट और चेंबर—को साथ-साथ चलना और उद होना चाहिए। पाँच महीने तक बैठने का यह ग्रंथ नहीं है कि काम न भी हो, तो भी सभा पाँच महीने तक बैठे ही। इस धारा का अर्थ इतना ही है कि इन पाँच महीने बैठने का व्यवस्थापक-सभा को कानूनी हक है और प्रजातन्त्र का प्रमुख अपने सभा स्थगित करने के अधिकार का इस समय में उपयोग नहीं कर सकता है। ग्राम तौर पर प्राग की व्यवस्थापक सभा, गर्मिया की छुट्टी और दो एक दूसरी छुट्टियाँ छोड़ कर साल भर तक परामर्श बैठती है। व्यवस्थापक सभा को अपनी बैठकें बिल्कुल बंद कर देने का अधिकार नहीं है, कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए वह अपना मत प्रकट कर सकती है। दोनों सभाओं के सदस्यों की यह सख्या चाहे तो प्रजातन्त्र के प्रमुख के पास ग्रंथों भेज कर व्यवस्थापक सभा की खास बैठकें भी बुलवा सकती है। साधारण बैठक की राय पनों द्वारा सभाओं के अध्यक्ष सदस्यों के पास भेज देते हैं। खास बैठकें प्रजातन्त्र का प्रमुख बुलाता है, और वही सभाओं की बैठक का उद और स्थगित करता है। प्रमुख को एक बैठक को दो बार से अधिक और एक मास से अधिक स्थगित करने का अधिकार नहीं है। सभा स्थगित किसी निश्चित तारीख के लिए ही की जा सकती है। अनिश्चित समय और तारीख के लिए व्यवस्थापक सभा को विसर्जित करने का अधिकार पास में किसी को नहीं है। सिनेट की सलाह से चेंबर ऑफ् टेपुटीज को भग करने का अधिकार भी प्रमुख को है। मगर आज तक एक बार के अतिरिक्त अभी इस अधिकार का उपयोग नहीं किया गया है।

फ्रांसीसी मत के अनुसार व्यवस्थापक सभा में जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, वे भिन्न क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, सिर्फ उन क्षेत्रों के हितों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, देश भर के सम्मिलित हित के प्रतिनिधि होते हैं। इस सिद्धांत पर जोर देने के लिए ऐरांडाईज़मेंट के छोटे छोटे क्षेत्रों से सदस्य चुनने की प्रथा को सन् १६१६ ई० में हटा कर डिपार्टमेंट के बड़े क्षेत्रों से बहुत से सदस्यों को इकट्ठा चुनने की प्रथा ज़ायम की गई थी, जिस से कि सदस्यों को तम स्थानित हितों का बहुत खयाल न रह कर सारे देश के हित का ही अधिक खयाल रहे। अमेरिका की तरह अपने सदस्यों की योग्यता अयोग्यता का फैसला करने का पूरा अधिकार दोनों सभाओं को दिया गया है। सभाएँ किसी माफ़ायदा चुने हुए सदस्य को सभा का सदस्य रखना उचित न समझे, तो वे उसे निकाल सकती हैं। जब कोई सदस्य दिवाला पिट जाने या और किसी वजह से सभा का सदस्य होने अथवा नागरिकता के अधिकार को खो देता है, तब उस को निकालने या न निकालने या क्या निकालने का सारा अधिकार उस सभा को होता है, जिस का वह सदस्य होता है। चेंबर ऑफ् टेपुटीज के सदस्यों को पेंशनवाले सरकारी पदों को स्वीकार कर लेने पर फौर्न् चेंबर से इस्तीफा दे देना होता है। अगर उस पद पर रह कर भी वह कानून के अनुसार चेंबर का सदस्य रह सकता है, तो उसे फिर से चुनाव में खड़ा हो कर चेंबर में आना होता है। मंत्रियों और उप मंत्रियों का इस प्रकार इस्तीफा देने और इजर्नट की तरह फिर से चुनाव में खड़ा होने की फास में जरूरत



नहीं होती है, क्योंकि उन के लिए यह नियम लागू नही रखा गया है। सिनेट के सदस्यों के लिए भी यह नियम लागू नहीं है और वे सरकारी नौकर होते हुए भी सिनेट के सदस्य हो सकते हैं। फ्रांस जैसे प्रजातन्त्र राज्य में सरकारी नौकरों को व्यवस्थापक-सभा की किसी सभा के सदस्य रहने का अधिकार होना आश्चर्य की बात है।

अगर किसी सदस्य को सभा से इस्तीफा देना होता है, तो उस इस्तीफे पर वह सभा विचार करती है, जिन का वह सदस्य होता है। इंग्लैंड की तरह व्यवस्थापक-सभा के सदस्य को सभा में अपनी इच्छानुसार बोलने और मत देने की पूरी स्वतन्त्रता होती है। सभा में बोलने और मत देने के लिए किसी सदस्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सरकारी नीति और कर्तव्यों का विरोध करनेवालों को सरकार के अत्याचार से बचाने के लिए फ्रांस की राज व्यवस्था में यह शर्त भी रखी गई है कि व्यवस्थापक सभा की बैठकों के जमाने में बिना सभा की राय के किसी सदस्य को किसी अपराध के लिए बारट पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सभा चाहे तो अपनी पूरी अवधि तक भी सदस्य को गिरफ्तार होने से रोक सकती है। अगर कोई सदस्य किसी अपराध के लिए बारदात के मौके पर ही पकड़ जावे अथवा उन ने पुलिस के किसी नियमों का भंग किया हो, तो सभा उस में हस्तक्षेप नहीं करती है। जिस जमाने में सभा की बैठकें नहीं होती हैं, उस जमाने में सदस्यों को अपराध के लिए मामूली नागरिका की तरह बिना किसी रोक-टोक के पकड़ा जा सकता है। सिनेट और चेंबर दोनों के सदस्यों को ६०० पाँड सालाना का वेतन इंग्लैंड की तरह राष्ट्रीय-बोप से दिया जाता है, जिस से गरीब आदमी भी जिन्दे रोटी कमाने की किक रहती है, व्यवस्थापक सभा के सदस्य बन सके और देश पर शासन करने की शक्ति अमीरी का चोचला ही न बन जाय। इस वेतन को न लेने या लौटाने का अधिकार किसी को नहीं है, जिस से सदस्यों में गरीब प्रमीर का भेद नहीं रहता है। सदस्यों को नाम मात्र का किया जा दे कर देश भग की रीति से मर राफर करने का अधिकार भी होता है।

फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा के भीदुनिया की अन्य व्यवस्थापक-सभाओं की तरह तीन काम मुख्य हैं—कानून बनाना, राष्ट्रीय आय व्यय का निश्चय करना, और देश के शासन की देख रेल करना। फ्रांस में कानूनी मसविदे व्यवस्थापक सभा में पेश करने का अधिकार प्रजातन्त्र के प्रमुख और सिनेट और चेंबर के सभी सदस्यों को होता है। प्रमुख की ओर से जो मसविदे पेश किए जाते हैं, वह वास्तव में मंत्रि मंडल के मसविदे होते हैं और उन को प्रधान-मंत्री अथवा और कोई मंत्री सरकारी मसविदों के नाम से व्यवस्थापक-सभा में पेश करता है। बिना प्रमुख के हस्ताक्षर के कोई सरकारी मसविदा धारासभा में पेश नहीं हो सकता। मंत्रियों को अन्य सदस्यों की तरह अपनी ओर से निजी मसविदे पेश करने का अधिकार भी होता है, जिन को सरकारी मसविदे न मान कर साधारण सदस्य के मसविदों की तरह निजी मसविदे माना जाता है। अगर मंत्री अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। निजी मसविदे धारासभा में पेश होने से पहले सभा की एक समिति के पास विचार के लिए भेजे जाते हैं। अगर वह समिति उन मसविदों को पसंद नहीं करती है, तो छ. महीने तक वह मसविदे व्यवस्थापक-सभा में पेश नहीं हो सकते हैं। फ्रांस में साधारण

सदस्या को सरकारी और निजी दोनों मसविदा में सशोधन पेश करने और प्रस्ताव और नए मसविदे पेश करने का इतना अधिकार दिया गया है कि मंत्रिमंडल का व्यवस्थापन सभा पर, इंग्लैंड की तरह अकुश नहीं रहता है। कानून बनने के लिए हर एक मसविदे पर साधारण तौर से दोनों सभाओं में दो-दो बार पांच दिन के अंतर से विचार होना चाहिए। जब तक दोनों सभाओं में, सदस्यों की बहु-संख्या किसी मसले पर मत देने में भाग नहीं लेती है, तब तक कोई मसला तय नहीं समझा जाता है। कुछ खास बातों को छोड़ कर व्यवस्थापन सभा की दोनों शाखाएँ सम्मान और शक्ति में बराबर की मानी जाती हैं, और दोनों का काम भी एक ही सा चलता है। दोनों सभाओं से जब तक कोई मसविदा एक ही सूत्र में मजूर होकर नहीं निकलता है, तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। अक्सर दोनों सभाओं की राय मिलाने के लिए मसविदे इस सभा से उस सभा और उस सभा से इस सभा की यात्रा करते हैं। सरकारी मसविदा पर तो दोनों सभाओं की राय एक करना प्रायः सम्मान होता है, क्योंकि मंत्री दोनों सभाओं में आ जा सकते हैं। मगर जब किसी निजी मसविदे पर राय का फर्क हो जाता है, तो दोनों सभाओं की एक सम्मिलित कमेटी के पास फैसले के लिए मसविदा भेज दिया जाता है। कभी-कभी सरकारी मसविदा का भी इसी प्रकार की कमेटी के पास भेजने की भी नीयत आ जाती है।

क्रांति के बाद में राष्ट्रीय आय व्यय के सन्ध में प्राप्त में कुछ सिद्धांतों का, राज व्यवस्था में खास तौर पर न लिए गए भी अटल माना जाता है। वे सिद्धांत यह हैं—‘प्रजा की राय अथवा उस के प्रतिनिधियों की राय बिना कोई कर नहीं लगाया जायगा, एक साल से अधिक एक बार कोई कर स्वीकार नहीं किया जायगा, देश का धन केवल देश की राय से खर्च किया जायगा, प्रजा के प्रतिनिधि हर साल राष्ट्र की अथात् निर्वात का सरकार की सहायता से एक पत्र तैयार करेंगे।’ रुपए पैसे के सन्ध के सार मसविदे जिस प्रकार इंग्लैंड में निचली सभा हाउस ऑफ़ कॉमन्स में पहले पेश होते हैं, उसी प्रकार प्राप्त में वे पहले चार ऑफ़ डेपुटीज में आते हैं। इंग्लैंड में कुछ नए स्थायी कानूनों के आधार पर लिए जाते हैं और बहुत सा खर्च अनिश्चित समय के लिए मान लिया जाता है। मगर प्राप्त में सारे नए साल भर के लिए ही लगाए जाते हैं और खर्च भी सिर्फ एक वर्ष के लिए ही मजूर किया जाता है। चैंबर ऑफ़ डेपुटीज विभिन्न विभागों की तफ़्तील देख कर उन के लिए खर्च तय कर देता है और नार्थ हारिसी के अधिनियमों के इस सन्ध में इंग्लैंड की तरह अधिक स्वतन्त्रता नहीं छोड़ता है। वित्त का साल पहली जनवरी से शुरू होता है। अक्टूबर या नवंबर से दूसरे साल पेश होनेवाले बजट के बनने की तैयारी शुरू हो जाती है अर्थात् जो बजट सन् १९३७ ई० में पेश होगा, उस का बनना सन् १९३५ ई० में शुरू हो जाता है। सारी मंत्रिमंडली अपने विभागों की मदद से जो आमदनी और खर्च के अंक तैयार करती है, उन सब को मिला कर अर्थ-सचिव लगभग तीन हजार पृष्ठ का एक राष्ट्रीय आय व्यय का प्रयान तैयार कर के चैंबर ऑफ़ डेपुटीज के सामने पेश करता है। चैंबर उस को ग्यारह ब्यूरो के चार-चार प्रतिनिधियों की ४४ सदस्य की ‘बजट-कमेटी’ के पास विचार के लिए भेज देता है। यह कमेटी तीन-चार महीने की काफी मेहनत के बाद चैंबर के

सामने आया व्यय के इस बयान को सशोधित कर के पेश करती है, और फिर उस पर चेंबर में बहस होती है। पहले सारे बयान पर ग्राम चर्चा चलती है, फिर एक एक तफसील पर बहस होती है। सदस्या को सब तरह के सशोधन करने की पूरी स्वतन्त्रता होती है। बजट कमेटी से निकल कर और सदस्यों के सशोधनों के बाद अर्थ-सचिव के पास से आया हुआ राष्ट्रीय आय व्यय पत्रक की शक्ल अक्सर इतनी बदल जाती है, इतनी कि इंग्लैंड में कभी नहीं बदल सकती। इंग्लैंड में जिन खर्चों की माँग सरकार की ओर से नहीं की जाती है, उन को स्वीकार नहीं किया जाता है। फ्रांस में ऐसा कोई नियम नहीं है। साधारण सदस्यों के सशोधनों से अक्सर बहुत-सा खर्च बढ़ तक जाता है। पहले हर एक तफसील पर बहस हो कर हर एक तफसील पर अलग अलग मत लिए जाते हैं, फिर सारे मतविदे पर इकट्ठे मत ले लिए जाते हैं। कमेटी से निकल कर तीन चार महीने तक आय व्यय के मतविदे पर चेंबर में बहस चलती है। चेंबर में मजबूर हो जाने पर मतविदा अर्थ-सचिव के पास फिर जाता है, और उन को वह सिनेट में पेश करता है। वहाँ फिर उस पर चेंबर की तरह चर्चा चलती है। मगर सिनेट में इतना समय नहीं लगता है। फिर भी सिनेट बहुत सी जरूरी तगदीलियाँ करती है और चेंबर और सिनेट की राय मिलाने के लिए मतविदा इधर से उधर, उधर से इधर आता जाता है और कमेटियाँ और कॉन्फ्रेंसें होती हैं। जिन बातों पर दोनों सभायाँ की राय नहीं मिलती है, उन पर सभायाँ में फिर से विचार किया जाता है। अंत में दोनों सभायाँ की राय मिल जाने पर मतविदा पास हो कर कानून बनता है और प्रमुख के हस्ताक्षर हो कर उस पर साक्ष की पहली तापीख से अमल शुरू हो जाता है। चेंबर के सारे बजट को अस्वीकार कर देने का हक होता है। मगर आज तक अभी चेंबर ने ऐसा किया नहीं है।

व्यवस्थापनी दण की सरकार फायम करने में फ्रांस ने इंग्लैंड की नकल ली है। इंग्लैंड के राजा की तरह फ्रांस की सरकार की कार्यकारिणी का प्रमुख अर्थात् फ्रांस प्रजातन्त्र का प्रमुख किसी शासन-कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं समझा जाता है। कार्यकारिणी का सारा काम मंत्री करते हैं। मंत्रियों के शासन की ग्राम नीति के लिए सम्मिलित रूप से और स्वास नामों के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थापन सभा के प्रति जवाबदार माना जाता है। सरकारी मसलों की हार हो जाने पर उन मंत्री एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। यह सब होते हुए भी फ्रांस की व्यवस्थापनी सरकार इंग्लैंड की व्यवस्थापनी सरकार से भिन्न है। इंग्लैंड में मंत्रियों की जवाबदारी का विषय यह अर्थ होता है कि व्यवस्थापन सभा उन के कामों पर बड़ी नजर और देख बाल रखती है। फ्रांस की व्यवस्थापन सभा मंत्रियों की लगाम खींच-खाँच कर उन का नाक में दम किए रहती है। इंग्लैंड की तरह फ्रांस में केवल दो उड़े राजनैतिक दल भी नहीं हैं। वहाँ आठ-नौ राजनैतिक दल होने से किसी एक दल का मंत्रिमंडल नहीं बन पाता है। हर मंत्रिमंडल में कई दलों के मंत्रियों की सिन्धरी रहती है। दलों की आपस की कतह के कारण फ्रांस में बड़ी जल्दी जल्दी मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं। इंग्लैंड में उन्नीसवीं सदी के बीच से पिछले यूरोपीय युद्ध प्रारंभ तक सिर्फ बारह प्रधान मंत्री हुए थे। फ्रांस में सिर्फ १६०० ई० से १९४४ ई०

गारह प्रधान मंत्री हो गए थे। इंग्लंड में सन् १८७३ से १९१४ ई० तक ग्यारह मंत्रि मंडल हुए थे। फ्रांस में इसी समय में पचास हो गए थे। सन् १८७५ ई० से १९०० ई० तक फ्रांस में सिर्फ चार साल ऐसे बीते थे, जिन में कम से कम एक से अधिक मंत्रि मंडल न बदला हो, और पचास में से सिर्फ चार मंत्रि मंडल ऐसे हुए थे जो दो वर्ष से अधिक तक रहे।<sup>१</sup> फ्रांसीसी मंत्रि मंडल कुछ महीना तक रह कर पानी के नुल्ला की तरफ उड़ गए। फ्रांस में मंत्रि मंडलों की जिंदगी का औसत ग्राठ मास से अधिक नहीं होता। इतना कम समय तक अधिकार में रहनेवाले मंत्रि मंडल को शासन की कोई नीति निश्चय करना कठिन हो जाता है। बहुत सी जरूरी बातों का वर्णन तक निश्चय नहीं हो पाता है और जिन आदमियों को इंग्लैंड में मंत्री बनाने का कोई स्वप्न भी नहीं देख सकता वे फ्रांस में मंत्रिया की गद्दी पर बैठ बैठ कर चले जाते हैं। इंग्लैंड में व्यवस्थापकी सरकार का धीरे धीरे विकास हुआ है इस लिए वहाँ जलवायु के माफिक आने का कष्ट उसे नहीं उठाना पड़ा है। फ्रांस में यह पौदा एक दम समूचा लगा दिया गया है, इस लिए वहाँ उस से मीठे फल प्राप्त करने के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंग्लैंड का मंत्रि मंडल कानून बनाने और शासन-कार्य दोनों में व्यवस्थापक-सभा का नाक पकड़ कर चलाता है। पार्लामेंट मंत्रि मंडल को शासन-कार्य के संचालन में पूरी आजादी देती है। परंतु फ्रांस की व्यवस्थापक सभा शासन की नीति ही निश्चय करने के लिए उत्सुक नहीं रहती, बल्कि तपसीलों में भी बहुत देखल देती है—यहाँ तब नि अधिकारियों को नियुक्त करने, उन की तरफकी के हुक्म निभालने और दूसरी बहुत सी बातों में टाँग अड जाती है।

फ्रांस में व्यवस्थापक-सभा छोटी छोटी बातों पर भी मंत्रियों को निभाल देती है। इंग्लैंड में पार्लामेंट में मंत्रियों से शासन सम्बन्धी हाल जानने के लिए सदस्य सिर्फ प्रश्न पूछते हैं। मंत्री चाहते हैं तो प्रश्न का उत्तर देते हैं और उत्तर पा कर सदस्य चुप हो जाते हैं। फ्रांस में प्रश्न पूछने का दम कुछ और ही है। यहाँ मंत्री चाहें अथवा न चाहें, जब किसी सदस्य को कोई प्रश्न पूछना होता है तब उस के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है और निश्चित समय पर प्रश्न पर चर्चा होती है। उत्तर के बाद सभा से इस बात पर मत लिए जाते हैं कि अगर सभा मंत्रियों के उत्तर से सतुष्ट हो गई हो तो दूसरा उस दिन का काम चलाया जाय। अगर सभा दूसरा काम चलाने की इच्छा प्रकट नहीं करती है तो मंत्रियों को इस्तीफा दे देना पड़ता है। फ्रांस में मंत्रियों से इस प्रकार के प्रश्न सिर्फ शासन का हाल-बाल जानने के लिए ही नहीं पूछे जाते हैं, इस महाने से वहाँ मंत्रि मंडलों को गिराने का प्रयत्न किया जाता है। इंग्लैंड में मंत्री के किसी उत्तर पर तब तक चर्चा नहीं हो सकती जब तक चालीस सदस्य मिल कर उस के लिए प्रार्थना न कर और ऐसी प्रार्थना कभी-कभी ही की जाती है। इंग्लैंड में मंत्रि मंडल और व्यवस्थापक-सभा की राय में भेद हो जाने पर मंत्रि-मंडल को हाउस ऑफ़ सामन्स को भग कर के नया

चुनाव कराने का अधिकार होता है, जिस से मंत्रि-मंडल की कॉमन्स पर चाकू रहती है। फ्रांस में मंत्रि-मंडल प्रमुख द्वारा चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़ को बिना सिनेट की राय के, भंग नहीं कर सकता। फ्रांस में एक बार मंत्रि-मंडल ने चेंबर को इस प्रकार भंग कराया था उस समय इस सत्ता का इतना खुला दुरुपयोग हुआ था कि उस के बाद से, इस सत्ता का उपयोग ही अभिय हो गया। अस्तु, मंत्रि-मंडल की यह सत्ता फ्रांस में भूतप्राय हो गई और फ्रांस का मंत्रि-मंडल अक्षरशः व्यवस्थापक-सभा के जवाबदार होता है। अगर मंत्रि-मंडल की बात व्यवस्थापक-सभा न माने तो व्यवस्थापक-सभा के भंग कर के राष्ट्र से अपने मत की सभा चुनने की विनती फ्रांस का मंत्रि-मंडल नहीं कर सकता है। इंग्लैंड का मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा के सिर पर पैर रख कर राष्ट्र से अपने मत की व्यवस्थापक-सभा चुनने की विनती कर सकता है, क्योंकि वह अपने को राष्ट्र के मतदारों के प्रति ज़िम्मेदार मानता है। व्यवस्थापक-सभा के मतों पर नियत रहने से फ्रांस का मंत्रि-मंडल इंग्लैंड की तरह टिकाऊ और जोरदार नहीं होता। एक अंगरेज़ लेखक ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि फ्रांस मुल्क व्यवस्थापकी सरकार के क्रायल ही नहीं है। मगर ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि फ्रांस में बिल्कुल इंग्लैंड के ढंग की व्यवस्थापकी सरकार न होने पर भी व्यवस्थापकी सरकार अवश्य है। मंत्रि-मंडल फ्रांस में अधिक टिकाऊ न होने पर भी वहाँ की सरकार बड़ी प्रजा-सत्तात्मक, सस्ती और वायसर है। इस के दो कारण हो सकते हैं—एक तो वहाँ इंग्लैंड की तरह हर विभाग में होशियार और दक्ष अधिकारी रहते हैं, जिस से काम पर मंत्रि-मंडलों के बदलते रहने पर भी अधिक असर नहीं पड़ता। दूसरे मंत्रि-मंडलों के बदलने पर भी बहुत से पुराने मंत्री लौट-फेर कर किसी न किसी विभाग के अधिनायक बन कर नए मंत्रि-मंडलों में आ जाते हैं। उदाहरणार्थ सन् १८३२ ई० में ब्रिगों के राजनीति से अलग होने पर फ्रांस में बड़ा दुख प्रकट किया गया था, क्योंकि जब तक ब्रिगों राजनीति में भाग लेता रहा, तब तक फ्रांस में कोई मंत्रि-मंडल उस के बिना पूर्ण नहीं समझा जाता था।

चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़ को देश के रुपए-पैसे की थैली पर क़ब्ज़ा रखने का जिस प्रकार विशेष अधिकार है उसी प्रकार सिनेट के भी दो खास अधिकार रखे गए हैं। एक तो सिनेट को प्रजातंत्र के प्रमुख की राय से चेंबर को भंग कर के नया चुनाव कराने का अधिकार है। दूसरा अधिकार अदालती है। जब चेंबर ऑफ़ डेपुटीज़ प्रजातंत्र के प्रमुख पर देशद्रोह अथवा मंत्रियों पर कुशासन का अपराध लगाता है, तो उन का मुक़दमा सिनेट की अदालत के सामने पेश होता है। प्रमुख और मंत्रियों के मुक़दमे सुनने के अतिरिक्त जब कोई नागरिक या नागरिकों का समूह राष्ट्र के प्रति द्रोह करने अथवा उस के अमन-चैन को भंग करने का प्रयत्न करता है तो भी प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रियों के हस्ताक्षर से अपना हुक्म निकाल कर उन लोगों के मुक़दमों का विचार करने के लिए सिनेट की अदालत बिठा सकता है। सन् १८८६ ई० और १८८६ ई० में दो बार इस प्रकार सिनेट की अदालत बैठ चुकी है। हर साल सिनेट अपने सदस्यों में से एक कमीशन चुन लेती है, जो ज़रूरत होने पर इस प्रकार के मुक़दमों की जाँच करता है।

## ५—स्थानिक शासन और न्याय-शासन

### १—स्थानिक शासन

राजाओं के राज अथवा राजाशाही के जमाने में फ्रांस सुखों में बैठा हुआ था। कोई सूबे छोटे थे, तो कोई इतने बड़े, जिन में आज कल के कई डिपार्टमेंट समा जायें। यह सूबे पुरानी नवारी के समय से नवारों के कब्जे में थे। नवाब मनमाने कर लगाते थे और अपनी इच्छानुसार उन का शासन करते और पौज रखते थे अर्थात् यह सूबे एक प्रकार की छोटी छोटी रियासतों की तरह थे। नवारों की इच्छा होती थी तो राजा का साथ देते थे और इच्छा नहीं होती थी तो राजा से बिगड़ भी जाते थे। राजा को अपने से उन्हें मिलाए रखने में बड़ी दिक्कत होती थी। बड़े धीरे धीरे अपनी नवारी कायम रखते हुए भी आपस में मिल कर फ्रांस को एक राष्ट्र बनाने की बात इन लोगों की ममक में आई। जब राजा की ताकत उठ जाती थी तब वह कमजोर नवारों को कुचल कर उन के सुखों पर अपने सूबेदार और अपनी सत्ता कायम कर देता था। राजा के सूबेदारों को जमींदारों, तालुकदारों, अमीर-उमरावों, महाजनों और पादरियों के जरिये से कर लगाने और बसूल करने के अधिकार होते थे। अक्सर यह सूबेदार भी इतने बलवान हो जाते थे कि राजा को उन पर दबाव रखना कठिन हो जाता था। पीछे बड़ी कठिनाइयों के बाद राजा के चुने हुए लोगों की सभाएँ इन सूबेदारों को शासन में सलाह और मदद करने के लिए कायम की जाने लगीं।

परंतु फ्रांस की मानि ने नवारी को छिन्न भिन्न कर दिया। सन् १८८६ ई० के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने, जो फ्रांस की राज्य व्यवस्था की पुनर्घटना करने के लिए बैठा था, इन बात का एलान किया, कि “अधिकार और सत्ता का जन्मदाता राष्ट्र है और कोई नहीं। फ्रांस में कानून का राज्य है और कोई कानून के ऊपर नहीं है।” व्यवस्थापक सम्मेलन का यह भी भय था—और सच्चा भय था—कि बड़े बड़े सूबे और उन पर शासन करनेवाले अधिकारी या सूबेदार कायम रहे तो फ्रांस को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के कार्यक्रम में बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। अस्तु, सभा ने पुराने सुखों को मिटा कर फ्रांस को लगभग बराबर के ऐसे ८३ भागों में बाँटा जिन में स्थानिक जीवन अर्थात् भाषा और रीति-रिवाज एक से थे। यहाँ तक कि पुराने सुखों की याद तब मिटा देने के लिए देश के इन नए विभागों के नाम स्थानिक नदियों, पहाड़ों और समुद्र के नामों पर रखे गए। इन्हीं विभागों को डिपार्टमेंट कहते हैं।

व्यवस्थापक-सभा ने डिपार्टमेंट के शासन का भार स्थानिक चुने हुए प्रतिनिधियों पर रक्खा था। उस ने ३६ स्थानिक प्रतिनिधियों की एक कौंसिल, आठ सदस्यों की एक डाइरेक्टरी और एक अभिपरी की शासन का काम सौंपा था। परंतु कुछ ही दिनों में मालूम हो गया कि इस प्रकार अधिकार बाँट देने से फ्रांस के स्थायी एकीकरण में कठिनाई होगी, इस लिए फ्रांस की उस समय की राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सरकार का एक अधिकारी भी डिपार्टमेंट में रखा गया। बाद में नेपोलियन ने डिपार्टमेंट के बुनाई को बद

कर दिया और उन का शासन चलाने के लिए अपना एक अधिकारी प्रीफेक्ट रक्खा। इस प्रीफेक्ट को मदद और सलाह देने के लिए उस ने एक कौंसिल भी रखी। मगर यह कौंसिल विलुल दिवावटी और खिलौना थी क्योंकि उस के सदस्यों को वह खुद उन जमींदारों में से चुनता था, जो उस की नीति में हाँ में हाँ मिलाते होते थे। सन् १८३० ई० की क्रांति के बाद कौंसिल चुनने का अधिकार फिर डिपार्टमेंट के मतदारों को दे दिया गया। मगर फिर भी मत देने का अधिकार सिर्फ़ पैसेवालों को रहने से सत्ता पूरी तरह में जनता के हाथ में आई। बाद में सन् १८४८ ई० की क्रांति सब के मतधिकार मिल जाने से डिपार्टमेंटों की कौंसिलें पूरी तरह से प्रजा की प्रतिनिधि बनीं और सन् १८७१ ई० में एक कानून बना कर फ्रांस की व्यवस्थापक सभा ने डिपार्टमेंट को शासन के बहुत-से अधिकार दिए जो अभी तक कायम हैं।

अब हर डिपार्टमेंट की राजधानी में एक आलीशान इमारत पर फ्रांस का तिरगा फंडा लहराता हुआ नजर आता है और इस इमारत पर 'प्रीफेक्चर' शब्द लिखे होते हैं। यह इमारत फ्रांस राष्ट्र या किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती बल्कि डिपार्टमेंट की मालिकियत होती है। इस में डिपार्टमेंट का सब से बड़ा अधिकारी प्रीफेक्ट और उस के दफ्तर रहते हैं। इसी में डिपार्टमेंट की कौंसिल का हॉल भी होता है।

प्रीफेक्ट नाम का अधिकारी फ्रांसीसी सरकार का डिपार्टमेंट में प्रतिनिधि होता है। पेरिस से आनेवाले सारे सरकारी हुक्मों की तामील उसी के जरिए होती है। वह डिपार्टमेंट से सेना की भर्ती का जिम्मेदार, डिपार्टमेंट का खज़ांची और पुलिस का मुख्य अधिकारी माना जाता है। कम्पूनों में रक्खी जानेवाली तमाम पुलिस की नियुक्ति वही मजूर करता है। डिपार्टमेंट भर के स्कूलों और पाठशालाओं की देख-भाल और शिक्षकों की नियुक्ति भी वही करता है। दूसरे छोटे-छोटे सरकारी अधिकारियों को भी वही नियुक्त करता है। सरकार का डिपार्टमेंट में प्रतिनिधि होने के साथ साथ प्रीफेक्ट डिपार्टमेंट की कौंसिल का सरकार के प्रति एलची समझा जाता है। वह स्थानिक कौंसिल का सदस्य और उस का मुख्य अधिकारी होता है क्योंकि शासन के जरिये उस के हाथ में होने से कौंसिल के सारे काम उसी के द्वारा होते हैं। एहमची प्रीफेक्ट को नियुक्त करता है और स्थानिक शासन एहमंत्री का विभाग होने से वह एहमंत्री के मातहत होता है। मगर दूसरे मंत्रियों को भी डिपार्टमेंट के सारे काम उसी के द्वारा कराने होते हैं। अस्तु कोई भी मंत्री उस के किसी काम की रोक-थाम कर सकता है। मगर जब तक उस को निकाल न दिया जाय तब तक उस के सिवाय और किसी के जरिये कोई मंत्री डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करा सकता। जो सरकारी हुक्म पेरिस से प्रीफेक्ट के पास आते हैं, उन में अपनी बुद्धि न घुसेड़ कर उसे जैसे के तैसे पालन करने होते हैं। मगर स्थानिक शासन में अपनी बुद्धि चलाने का उसे बहुत कुछ मौका रहता है। अदालत में मुकादमा चलाने या सरकार में अर्जी मेजने के अतिरिक्त उस का हाथ स्थानिक शासन में कोई नहीं रोक सकता। वही डिपार्टमेंट का बजट तैयार करता है और दूसरा काम-काज कौंसिल के सामने पेश करता है। अस्तु, कौंसिल जो कुछ भला बुरा करती है वह बहुत कुछ उसी पर निर्भर रहता है। डिपार्टमेंट की किसी कम्पून की

बैठक को एक मास तक बढ़ करने और किसी मेयर को एक मास के लिए बर्खास्त करने का अधिकार उसे होता है। मेयर जिन पुलिसवालों को रखता है उन की नियुक्ति भी वही स्वीकार करता है। वाज़-वाज़ डिपार्टमेंट में बड़ी-बड़ी कम्प्यूनें और उन के चुने हुए अधिकारी भी होते हैं। मगर उन की पुलिस पर भी प्रीफेक्ट का अधिकार होता है। कम्प्यून के अधिकारियों के पास प्रीफेक्ट अपने खुद हुक्म निकाल कर भी तामील के लिए भेज सकता है और कम्प्यून की जिन कार्रवाइयों को वह गैर-कानूनी समझे उन को रोक सकता है। जब उस के कामों पर कौंसिल में विचार होता हो तब न जा कर दूसरे सब मौकों पर यह कौंसिल की बैठकों में भाग ले सकता है। डिपार्टमेंट से चुने जानेवाले चैंबर और सिनेट के सदस्यों से अच्छा सबध बनाए रखना पड़ता है क्योंकि उन की और गृहमन्त्री की राय पर उस की नौकरी निर्भर होती है। फ्रांस की सरकार का वस्तुतः स्थानिक शासन का दायरा दिन दिन बढ़ा करने की तरफ है। इस लिए हर तरह से प्रीफेक्ट को स्थानिक नेताओं की सलाह से काम करना होता है और वह वहाँ नौकरशाही नहीं जमा पाता।

• **कौंसिल-जनरल**—डिपार्टमेंट में प्रीफेक्ट सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है और उस के मुकाबिले में प्रजा के प्रतिनिधि डिपार्टमेंट की 'कौंसिल जनरल' के सदस्य होते हैं। एक-एक कैंटन, से सार्वजनिक मत से एक एक सदस्य कौंसिल जनरल में चुन कर आता है। किसी डिपार्टमेंट में कम किसी में अधिक, जितनी जिस डिपार्टमेंट में कैंटनों की संख्या होती है उतने सदस्य उस डिपार्टमेंट की कौंसिल-जनरल में होते हैं। सदस्य होनेवाला २५ वर्ष के ऊपर, डिपार्टमेंट में रहनेवाला और सीधा सरकार को कर देनेवाला होना चाहिए। कुछ सरकारी नौकर सदस्य नहीं हो सकते। सदस्यों का चुनाव छ वर्ष के लिए होता है, और हर तीसरे साल आधे सदस्यों का चुनाव होता है। उन को कोई भत्ता नहीं दिया जाता। सदस्य बनने की इच्छा ही उन के लिए काफी सम्झी जाती है। मरी सदस्य डिपार्टमेंट से जानेवाले सिनेट के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इस के सिवाय राष्ट्रीय राजनीति से इन सदस्यों का दूसरा कोई सबध नहीं होता। डिपार्टमेंट के चुनाव के फगड़े 'स्टेट कौंसिल' के सामने फैसले के लिए जाते हैं।

हर साल कौंसिल जनरल की दो बैठके होती हैं। दोनों बैठकों का समय कानून से तय कर दिया गया है—एक का पंद्रह दिन के लिए, दूसरी बैठक का महीने भर के लिए। दो तिहाई सदस्यों की लिखित प्रार्थना आने पर प्रजातंत्र का प्रमुख अथवा प्रीफेक्ट आठ दिन की खास बैठक भी बुला सकते हैं। अगर कौंसिल अपने कानूनी समय से अधिक बैठे तो प्रीफेक्ट उस को भग कर सकता है। अगर कौंसिल अपने कानूनी कामों से आगे बढ़ कर कोई काम करती है तो प्रमुख उस काम को अपने हुक्म से रद्द कर सकता है। सदस्यों को काम में लापरवाही करने या सभा में शौर-हाज़िर रहने पर दंड भी दिया जा सकता है। पहली बैठक में आम शासन के काम-काज का विचार होता है। महीने



भर की दूसरी बैठक में प्रीफेक्ट के पेश किए हुए डिपार्टमेंट के बजट और हिसाब किताब पर विचार होता है। इन बैठकों में सदस्यों को प्रीफेक्ट और दूसरे विभागों के मुख्य अधिकारियों से हाल जानने के लिए जवानी और लिखित सवाल पूछने और उत्तर पाने का हक होता है। देख माल और पूछ-ताछ करने की ताकत कौंसिल को अधिक होती है, प्रस्ताव करने की ताकत कम होती है। जो कर चेंबर ऑफ् डेपुटीज़ तय करता है उसी के एक भाग का उपयोग करने का अधिकार कौंसिल को होता है। किसी तरह के नए कर लगाने का अधिकार कौंसिल जनरल को नहीं होता है। खर्च करने के बारे में भी कौंसिल जो निश्चय करती है उस की मजूरी प्रजातन्त्र के प्रमुख के हुक्म से होती है। कौंसिल का काम खास कर शासन का निरीक्षण और देख-रेख करना माना जाता है, शासन का कार्यक्रम रचना नहीं। कौंसिल अपने अपने अधिकारियों, स्कूलों और अदालतों के काम में आनेवाली इमारतों को किराए पर लेने, उन को अच्छी तरह रखने, पुलिस की तनख्वाह देने, मतदारों की सूचियाँ बनवाने और छपाने का खर्च करने, सड़कों, रेल, पुल और दूसरे डिपार्टमेंट के सार्वजनिक उपयोगी चीज़ों का बनवाने और ठीक रखने और पागलखानों, दवाखानों और गरीबों के मदद करने का काम करती है। डिपार्टमेंट के खर्च के लिए चेंबर ऑफ् डेपुटीज़ जो कर तय करता है उस को कौंसिल जनरल ऐरो डाइज़मेंटों में बाँटती है। हमारे देश में जो काम जिला बोर्ड करते हैं उन सारे कामों को और कुछ जिला मजिस्ट्रेट के कामों तथा कुछ और थोड़े-से कामों को फ्रांस में डिपार्टमेंट की कौंसिल जनरल करती है। कौंसिल की बैठकों के समय को छोड़ कर, और सब समय प्रजातन्त्र के प्रमुख को, कारण बतला कर, कौंसिल को भग कर देने का अधिकार होता है। कौंसिल राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए नहीं होती। अस्तु, जब कभी कौंसिल के सदस्य किसी राजनैतिक प्रश्न पर गरम होने लगते हैं तो प्रीफेक्ट उन्हें धीरे से फ़ादून की याद दिला देता है। फिर भी उस की बात न सुन कर, अगर कौंसिल किसी राजनैतिक प्रश्न पर अपना मत प्रगट करती है तो उस से प्रीफेक्ट के काम पर कुछ असर नहीं पड़ता। कौंसिल साल भर में बहुत थोड़े से समय के लिए बैठती है। अस्तु, वह अपनी गैर-हाज़िरी में प्रीफेक्ट को सलाह और मदद देने के लिए, अपने सदस्यों का एक कमिशन चुन लेती है, जिस की बैठकें हर महीने होती हैं। कहा जाता है कि, “कौंसिलों पर सरकारी अकुश नहुत रहता है, और उन से अधिक काम नहीं लिया जाता है। कोशिश करने से यह कौंसिलें अधिक काम की बन सकती हैं।”

**ऐरोडाइज़मेंट**—डिपार्टमेंटों को ऐरोडाइज़मेंटों में बाँटा गया है। यही ऐरोडाइज़मेंट ही पुराने जिले थे। इन में एक नायब प्रीफेक्ट शासन का काम चलाने के लिए रहता है। डिपार्टमेंट की तरह, एक एक कैंटन से एक-एक चुने हुए प्रतिनिधियों की, एक कौंसिल यहाँ भी होती है। इस कौंसिल को बजट बगैरह बनाने का कोई काम नहीं करना होता। न मालूम हमारे देश के कमिश्नरों की तरह फ्रांस के स्पानिक शासन में यह पाँचवाँ पहिया गाड़ी में क्यों लगाया गया है? बहुत ज़माने से ऐरोडाइज़मेंटों को तोड़ने की बातें होती हैं। मगर शायद स्पानिक जनमत अभी तक इस बात की तरफ इतना नहीं हो पाया है

कि इस काम में हाथ लगाया जा सके।

**केंटन**—केंटन सिर्फ चुनाव के लिए एक सहूलियत का क्षेत्र है जहाँ से 'मंसिल-जनरल' और 'ऐरोंडाईजमेंट' की 'कौंसिलों' के लिए सदस्य चुने जाते हैं। केंटन में एक छोटा न्यायालय भी रहता है।

**कम्प्यून**—डिपार्टमेंट नाम के विभागों की जन्मदानी फ्रांस की 'नेशनल ऐसेंबली' थी। यह क्षेत्र देश की सरकार का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए बनाए गए थे। परन्तु कम्प्यून नाम के क्षेत्र भारतीय गाँवों की तरह थे इँटे और पत्थर हैं जिन से फ्रांसीसी राष्ट्र का निर्माण हुआ है। फ्रांस के गाँव और नगर हमारे देश के गाँव और बहुत से नगरों की तरह बड़े पुराने काल से चले आते हैं। जो मकान और झोपटे आँगन दिखाई पड़ते हैं वे अधिक से अधिक डेढ़ या दो सौ वर्ष पहले के नहीं होंगे। मगर इन मकानों और झोपड़ों के स्थान पर दूसरे रहने के स्थान थे, और उन से पहिले और दूसरे। इसी प्रकार और आगे खोज करें तो और और बहुत काल तक पीछे चले जाने पर भी किसी न किसी तरह के रहने के घरों का पता चलता है। फ्रांस के लोग बहुत काल से खेती-बारी और पशु-पालन का काम करते आए हैं। हमारे देश की तरह उन लोगों के पूर्वजों ने भी नदी, नालों, चश्मों, पहाड़ियों के पास अच्छी सुमते की जगहें देख देख कर, रहने के स्थान बनाए थे। अपनी रक्षा के लिए अक्सर इन रहने के स्थानों के चारों ओर वे पत्थर और चूने की चहारदीवारियाँ भी बना लेते थे। सब मिल कर अपने गाँव की समस्याओं पर निवार करते थे और मिलकर गाँव की व्यवस्था चलाते थे। हर गाँव में सजबूत पचायतें थीं, और पचायती व्यवस्था चलती थी। उसी प्रकार नगरों में भी कारीगरों और दूसरे काम करनेवालों ने व्यवस्था चलाने के लिए पचायतें बना ली थी। इन्हीं का नाम फ्रांस में पीछे से कम्प्यून पड़ा। देश भर में इस प्रकार के हजारों कम्प्यून थे। बारहवीं सदी में किसानों और मजदूरों ने जमींदारों और सरदारों की गुलामी से अपने को मुक्त करने के लिए सर उठाया तो देश भर में मारकाट छिड़ गई जो बहुत दिनों तक फायम रही। कभी कोई कम्प्यून जीत कर राजा से अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने का अधिकार ले लेती थी, तो कभी कोई कम्प्यून हार कर और भी गुलामी में जकड़ जाती थी। कम्प्यूनें अपना शासन चलाने के लिए एक अधिकारी भी चुन लेती थी जिसे को यह मेयर कहती थी। धीरे धीरे कम्प्यूनों की ताकत बहुत बढ़ गई। अस्तु, चौदहवीं सदी से निरंकुश राजाओं ने उन की ताकत घटाने के लिए उन पर हमले शुरू किए जो अठारवीं सदी तक जारी रहे।

राज्य-व्यवस्था के बाद व्यवस्थापन सम्मेलन के बैठने के समय इन कम्प्यूनों की ताकत खत्म हो रही थी। परन्तु व्यवस्थापन-सम्मेलन ने फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन गठने के लिये कम्प्यूनों को उतना ही जरूरी समझा जितना किसी इमारत को बनाने के लिए ईंटे जरूरी होती हैं। अस्तु, व्यवस्थापक सम्मेलन ने फ्रांस को ४४००० कम्प्यूनों में बाँट देने का निश्चय किया। फ्रांस की आबादी को देखते हुए यह संख्या अधिक थी। इस लिए पीछे से सग्या घटा दी गई और अब फ्रांस में करीब ३६२२५ कम्प्यूनें हैं। सन् १९१८ ई०

में करीब ३६२२६ कम्प्यूनें थीं जिन में से अधिकतर की आवादी १५०० से कम थी—यह तो वी तो ५०० से भी कम थी। ११७ कम्प्यूने ऐसी भी थी जिन की आवादी बीस हजार से अधिक थी। पेरिस और लियोन नगरों को छोड़ कर दूसरे सारे शहरों की भी कम्प्यूने हैं। कम्प्यूनों की संख्या आवादी के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जिन कम्प्यूनों की आवादी बढ़ जाती है वह दो में बँट जाती है, जिन की कम हो जाती है वह दूसरे में मिल जाती है। कम्प्यूनों की हैसियत में भी बहुत काल से फर्क चला आता था। पहले 'अच्छा कसबा' आता था, फिर कस्बा, फिर हाट, और हाट के बाद गाँव। व्यवस्थापन-सम्मेलन ने इस भेद को भी मिटा दिया और सब कम्प्यूनों की कति के समय की 'समता' की दुहाई पर, एक हैसियत मान ली गई और सभी कम्प्यूनों को एक एक कौंसिल और एक एक मेयर चुनने का और बहुत सा शासन का काम चलाने का एक सा अधिकार दे दिया गया। सर्व साधारण को स्वतंत्रता और सत्ता देने के जोश में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने कम्प्यूनों को कुछ ऐसे अधिकार भी दे दिए, जो वास्तव में राष्ट्रीय सरकार को होने चाहिए थे। उस का नतीजा यह हुआ कि उन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ जिन को बाद में कन्वेंशन ने रोकने के प्रयत्न किए। परंतु वे प्रयत्न अधिक सफल नहीं हुए। न्यर्थ की गड़बड़ मच गई और कम्प्यूनों का भाग्य फिर अधर में लटकने लगा। अंत में नेपोलियन के हाथ में सत्ता आते ही कम्प्यूनों का भी वही हाल हुआ, जो डिपार्टमेंटों का हुआ। उस ने कम्प्यूनों की सारी स्वतंत्रता छीन ली और मेयर और कौंसिल के सदस्यों को वह स्वयं या उस के अधिकारी नियुक्त करने लगे। स्वतंत्रता के साथ साथ उस ने कम्प्यूनों की समता को भी नष्ट कर दिया। 'अच्छे कस्बों' को फिर से जिलाया गया और बहुत से कम्प्यूनों के मेयरों का खिताब 'बिरन' कर दिया गया। सन् १८३० ई० की क्रांति के बाद फिर से कम्प्यूनों को जिलाने का प्रयत्न शुरू हुआ और सन् १८४८ की क्रांति के बाद ६००० की आवादी से छोटी कम्प्यूनों के मतदारों को अपनी कौंसिल और मेयर चुनने के अधिकार मिले। बाद में दूसरे साम्राज्य ने कम्प्यूनों को फिर दबा दिया और तीसरे प्रजातंत्र ने उन को फिर जीवित किया। पीछे से राष्ट्रीय सरकार और स्थानिक सस्थाओं के अधिकारों को अलग कर दिया गया और तब से पेरिस और लियोन के नगरों को छोड़ कर फ्रांस भर में कम्प्यूनों का शासन चलता है।

फ्रांस के हर गाँव, हाट, कस्बे और शहर में एक इमारत मिलेगी, जो सब नागरिकों की इमारत है। इस पंचायती इमारत में गरीब अमीर सभी जा आ सकते हैं। इसी में मेयर की अध्यक्षता में कम्प्यून की पंचायत बैठती है। कम्प्यून का चुनाव २१ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक दूसरे चुनावों की तरह लगभग उन्हीं शर्तों पर करते हैं। जो आदमी दूसरे चुनावों के लिए खड़े हो सकते हैं, वह कम्प्यून के लिए भी खड़े हो सकते हैं। मगर ५०० की आवादी की एक ही कम्प्यून में बाप, बेटे, दादे, नाती, भाई, बहनोई कानून के अनुसार एक साथ सदस्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि किसी कम्प्यून को किसी एक कुनबे की चीज घना देना उचित नहीं समझा गया है। मगर न जाने क्यों कानून ने धरो के चारों को कम्प्यून के लिए खड़े होने का अधिकार नहीं दिया है। कम्प्यून की बैठकें साल भर में चार बार साधारण तौर पर होती हैं। मेयर और प्रीफेक्ट ग्यास बैठकें भी बुला सकते हैं। कम्प्यूनों में

जो चर्चा चलती है, वह एक रजिस्टर पर लिख ली जाती है और उस पर सारे सदस्यों के दस्तखत रहते हैं। इस कार्रवाई के रजिस्टर और बजट को देखने या नक़ल करने का हक़ सर्वसाधारण को होता है। सर्वसाधारण से कम्प्यून की कार्रवाई गुप्त नहीं रखी जाती। हर नागरिक को कम्प्यून की कार्रवाई के जानने का अधिकार होता है। कम्प्यून के उन सब प्रस्तावों पर जो क़ानून के खिलाफ़ नहीं होते हैं, अधिकारियों को अमल करना होता है। मगर बहुत से प्रस्तावों पर अमल करने के लिए प्रीफ़ेक्ट या उन से अधिक ज़रूरी पर सरकार की, और उन से भी अधिक ज़रूरी पर व्यवस्थापक सभा की राय ले लेने की सैद्द रखी गई है। कौंसिल को अस्पताल वगैरह का हिसाब भी देना होता है और सिनेट के सदस्यों को चुनने के लिए प्रतिनिधि चुनने होते हैं।

दूसरे साम्राज्य के ज़माने में निरंकुशता के प्रतिनिधि मेयरों का रोन बढ़ाने के लिए उन को चमकौली-दमकौली पोशाकें दी गई थीं। सफ़ेद ज़री के काम का एक नीला कोट जिस के कालर पर एक वृक्ष की शाखा का चित्र होता था, एक सफ़ेद जाकेट, एक टोप जिस में फाले पर लगे होते ही थे और सीप की मूठ की एक तलवार हर कम्प्यून के मेयर को दी जाती थी। आज कल वह सिर्फ़ ज़रूरत के वक्त अपनी शक्ति का चिह्न स्वरूप एक तिरगा पेंटा बाँध लेते हैं। मेयर और उस के नीचे काम करने वालों को कौंसिल के सदस्यों में से कौंसिल चुनती है। मेयर जनता के लिए कौंसिल की प्रतिमा और कम्प्यून के लिए सरकार की प्रतिमा होता है। वह कम्प्यून के प्रस्तावों को कार्य में परिणत करता है, कम्प्यून के नौकरों को नियुक्त करता है, कम्प्यून की तरफ़ से सब ज़रूरी कागज़ों पर सही करता है और अगर कम्प्यून पर कोई मुकदमा चलता है, तो उस की तरफ़ से अदालत में हाज़िर होता है। वही गाँव में शांति और स्वास्थ्य कायम रखने और जान माल को सुरक्षित रखने का ज़िम्मेदार होता है। इस सब में वह नियम निकालता है और जो उन नियमों को भंग करता है, उस पर अदालत जुर्माना करती है। सड़कों पर पानी छिड़कने, कीचड़ हटाने, रास्ते साफ़ करने, कुत्तों को न छोड़ने, खिड़की से कूड़ा न फेंकने, गाड़ियाँ न भगाने वगैरह के बहुत से नियम वह बनाता है। लोगों की स़िदगी, स्वास्थ्य, शांति और नींद तक पर वह नज़र रखता है। अगर कहीं आग लग जाती है या कभी अहला आ जाता है, तो वह गाँव के सब लोगों से मदद लेने का अधिकारी होता है। लोगों के छोटे, गाड़ियाँ, हथियार सब कुछ वह ज़रूरत पड़ने पर भाँग सकता है। ऐसे मौकों पर वह 'जनहित के अवतार' का स्वरूप धारण कर लेता है और व्यक्तिगत हिता को उस के सामने सिर मुका देना पड़ता है। सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से वह क़ानूनों का एलान और पालन कराता है। अपराधियों को रोज़ने और पकड़ने में वह न्यायालयों की मदद करता है। कोई फ़िसाद हो जाय, तो पुलिस, गाँव और जगला के चौकीदारों और फौज तक को ज़रूरत होने पर मदद के लिए बुलावा सकता है। विवाह, ज़म, मृत्यु के कागज़ों पर उस की गवाही के दस्तखत होते हैं। प्रीफ़ेक्ट की मज़ी से कम्प्यून अपना बजट भी बनाती है।

## (२) न्याय-शासन

**शासकी अदालतें : कौंसिल ऑव् स्टेट**—फ्रांस में जो मुक्तदमे सरकारी शासन के संबंध में होते हैं उन की सुनवाई न्याय-मंत्री के विभाग के साधारण न्यायालयों में नहीं होती है बल्कि यह मंत्री के विभाग की शासकी अदालतों में होती है। फ्रांस में सार्वजनिक कानून, जिस से सरकारी शासन की कार्रवाई का संबंध होता है और वैयक्तिक-कानून, जिस से साधारण व्यक्तियों के एक-दूसरे से संबंध का तात्त्विक होता है, दोनों में बहुत भेद माना गया है। नागरिकों के एक-दूसरे से झगड़ों को साधारण न्याय की अदालतें तय कर सकती हैं। मगर जो झगड़े नागरिकों और सरकार के शासन में होते हैं, जिन में सरकारी अधिकारों पर हमला होता है, उन का फैसला खास शासकी अदालतों में होता है। सब से बड़ी शासकी अदालत को 'कौंसिल ऑव् स्टेट' कहते हैं। इस में मंत्री और कुछ दूसरे शासन के बड़े अधिकारी न्यायाधीश का काम करते हैं। शासन-संबंधी बातों की यह आखिरी अदालत होती है, अर्थात् दूसरी अदालतों में मुक्तदमा हो चुकने के बाद यहाँ थरीलें आती हैं। शासन-संबंधी जो मामले इस के पास सलाह के लिए भेजे जाते हैं उन पर अपनी राय व्यवस्थापक-सभा की मेजना भी इस का काम होता है।

**प्रीफेक्ट की कौंसिल**—कौंसिल ऑव् स्टेट के नीचे चार अदालतें होती हैं। एक 'प्रीफेक्ट की कौंसिल', दूसरी 'अपीलों की अदालत', तीसरी 'सार्वजनिक शिक्षा की बड़ी अदालत', और चौथी 'हिसाब-जॉच अदालत'। यह चारों अदालतें आपस में एक-दूसरे से नीचे दर्जे की नहीं होती हैं। सब कौंसिल ऑव् स्टेट के नीचे होती हैं। प्रीफेक्ट की कौंसिल इन सब में ज़रूरी होती है। उस का प्रीफेक्ट से बहुत संबंध रहता है। पेरोंडाइज़मेंट और कम्यून की कौंसिलों के चुनाव के झगड़ों का फैसला यह अदालत करती है। सरकार और नागरिकों के बीच के सारे झगड़े भी पहले इसी अदालत के सामने लाए जाते हैं। इस अदालत के फैसले दूसरी अदालतों से जल्दी हो जाते हैं और उन में साधारण न्याय की अदालतों से पैसा भी कम खर्च होता है। इस अदालत के लगभग हर एक फैसले की अपील स्टेट कौंसिल में की जा सकती है। प्रीफेक्ट का इस अदालत से संबंध रहता है, मगर उस पर उस का कुछ ज़ोर या दबाव नहीं रहता है। इस अदालत के जज स्थायी होते हैं और उन में से कम से कम एक को शासन का अच्छा अनुभव होता है। जजों को राष्ट्रीय सरकार नियुक्त करती है और उन को किसी अपराध पर ही निकाल सकती है।

**साधारण न्यायालय**—फ्रांस की सब से बड़ी न्याय की अदालत 'सेसेशन कोर्ट' है। यह पेरिस में बैठती है और उस में दूसरे साधारण न्यायालयों से आनेवाली अपीलें सुनी जाती हैं। इस अदालत के नीचे २३ अदालतें अपील सुनने के लिए और होती हैं, जिन के हर एक के अधिकार की सीमा में कई डिपार्टमेंट आ जाते हैं। उन डिपार्टमेंटों के

<sup>१</sup> 'सुपीरियर कौंसिल ऑव् पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' । <sup>२</sup> 'कोर्ट ऑव् कास्टि' ।

एरोडाइजमेंटों के मुख्य नगरों में बैठनेवाली अदालतों की सारी अपीलें पहले यहाँ आती हैं। एरोडाइजमेंट में बैठनेवाली अदालतें कैंटन के 'जस्टिस ऑफ़ दि पीस' की अदालत से आप हुए मुकदमों पर विचार करती हैं। राष्ट्र की रक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमों का विचार सिनेट के सामने होता है। सारे जजों में न्यायमन्त्री प्रजातन्त्र के प्रमुख के हस्ताक्षरों से नियुक्त करता है। और सिवाय 'जस्टिस ऑफ़ दि पीस' के—जिन को प्रमुख अपनी इच्छा से निमाल सफ़ता है—इन जजों को बिना कथुर के निकाला नहीं जा सकता है।

**जूरी की अदालतें**—साधारण अदालतों में फ़ॉर्म में इंग्लैंड की तरह जूरी नहीं बैठती। जज ही सारी बातों का फैसला करता है। मगर खाल में चार बार हर डिपार्टमेंट में जूरी की खास अदालतें बैठती हैं और उन के सामने फौजदारी के मुकदमों और सार्वजनिक और अख़्तियारी अपराधों की सुनवाई होती है। मुलाजिमों को अपराधी ठहराने या न ठहराने का पूरा अधिकार जूरी को होता है। जज सिर्फ़ सजा तय करता है।

**भगदों की अदालत**—यह अदालत इस बात का फैसला करती है कि तीन या मुकदमा साधारण न्यायालय में और कौन-सा शासकीय अदालत में जाना चाहिए। इस अदालत के न्यायाधीश तीन स्टेट कौंसिल के चुने हुए प्रतिनिधि और तीन नेशनल कोर्ट ने चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उन का अध्यक्ष उन पर न्यायमन्त्री बैठता है।

## ६.—राजनैतिक-दल

फ्रांस की राजनीति के विस्तृत प्रारम्भ में ही फ्रांस के राजनैतिक क्षेत्र में एक ऐसा दल खड़ा हो गया था जिसका उद्देश्य राजाशाही को नाश कर के फ्रांस में प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना करना था। तब से फ्रांस में तीसरे प्रजातन्त्र की स्थापना होने तक राजनैतिक दलों का आपस में झगड़ा बराबर इसी एक प्रश्न पर होता था। प्रजातन्त्रवादी और राजतन्त्रवादी दोनों में से कोई भी दल कभी इंग्लैंड की तरह एक सुसंगठित और ठिकाऊ दल नहीं बना सका। मगर जब कभी व्यवस्थापक सभा के अन्दर अथवा बाहर झगड़ा उठता था तब उस की जड़ में खास तौर पर यही एक विचार होता था। प्रजातन्त्रवादियों की सन् १७९२ ई० और सन् १८४८ ई० में जीत होने पर उन्होंने दोनो बार राजाशाही को हटा कर प्रजातन्त्र की स्थापना की। उन के स्थापित किए हुए प्रजातन्त्र अधिक दिन तक फ़ायदा न रह सके परन्तु प्रजातन्त्रवादी अग्रसर बड़े। सन् १८७१ ई० की 'नेशनल ऐसेंबली' में प्रजातन्त्रवादियों की संख्या से राजतन्त्रवादियों की संख्या ढाई गुनी के करीब अधिक थी। मगर जिस प्रकार राजतन्त्रवादी असंगठित थे उसी तरह प्रजातन्त्रवादी। प्रजातन्त्रवादी जरा राजतन्त्रवादियों से कम असंगठित थे, फिर भी उन में तीन दल थे। एक प्रख्यात गेंबेटा के गरम प्रजातन्त्रवादियों की टोली थी, दूसरी लूवेट के अनुयायियों की एक टुकड़ी थी, तीसरे थियर्स के मध्यस्थ प्रजातन्त्रवादी थे। राजतन्त्रवादियों के घोर विरोध के खतरे के सामने भी यह लोग आपस में मिल नहीं

पाते थे। इसी वजह से सन् १८७३ ई० में थीयर्स को प्रमुख पद पर से हटा कर राजतन्त्रवादी मार्शल मेकमोहन को प्रजातन्त्र का प्रमुख बनाने में राजतन्त्रवादी सफल हुए।

मगर राजतन्त्रवादी भी आपस में मेल न कर सके जिस के फलस्वरूप आखिरकार प्रजातन्त्र की राज-व्यवस्था जैसा प्रारम्भ में बताया ही जा चुका है पास हो गई। सन् १८७६ ई० के चुनाव में सिनेट में राजतन्त्रवादियों की बहुसंख्या आई और वहाँ सन् १८८२ तक कायम रही। मगर 'चेंबर ऑफ् डेपुटीज' में शुरु ही से प्रजातन्त्रवादी राजतन्त्रवादियों से दुगुने थे। पहले तो राजतन्त्रवादी यही ख्वाब देखते रहे कि प्रजातन्त्र को उखाड़ कर वे फिर से राजाशाही कायम कर सकेंगे। उन में से कितने ही लोगों ने इस के लिए बहुत सा प्रयत्न भी किया। मगर नाद में धीरे धीरे वे ठंडे पड़ गए। कुछ तो उन में से प्रजातन्त्र के पक्षपाती बन गए और शेष राजतन्त्रवादी न बन कर 'अनुदार' कहलाने लगे। चेंबर के प्रजातन्त्रवादी दलों में से गेंवेडा का साथ से बड़ा दल उस के मरने के बाद प्रजातन्त्रवादियों से अलग हो कर गरम दल कहलाने लगा। सन् १८८५ ई० के चुनाव में इस दल के १५० सदस्य चेंबर में चुन कर आए थे जिन की बिना सहायता के प्रजातन्त्रवादियों को सरकार पर कब्जा रखना असंभव हो गया। अस्तु, इस के बाद से प्रास में अनुदार दल, गरम दल, और प्रजातन्त्रवादी दल—तीन दल हो गए। किसी भी एक दल को चेंबर में बहु-संख्या नहीं मिलती थी। कभी दोनों प्रजातन्त्रवादी दल मिल कर अनुदार दल के विरुद्ध मन्त्रि-मंडल बना लेते थे, तो कभी एक प्रजातन्त्रवादी दल अनुदार दल से मिल कर दूसरे प्रजातन्त्रवादी दल के विरोध में मन्त्रि-मंडल बना लेता था। इसी प्रकार बहुत दिनों तक काम चलता रहा। जयन्तर एक ही दल का मन्त्रि-मंडल बनाने के भी प्रयत्न किए गए, मगर ऐसे मन्त्रि-मंडल अधिक दिन तक न चल सके।

पिछली सदी की फ्रांसीसी दलबन्दी की टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी की अभिषेख खाक न छान कर हम इस सदी के प्रारम्भ में प्रास के चेंबर ऑफ् डेपुटीज के राजनैतिक दलों पर नजर डाले तो हमें पिछले समय के अनुदार और प्रजातन्त्रवादियों के झगड़ों के मुख्य कारण मिट जाने से इन नामों के इस सदी में कोई दल नहीं मिलते। जो थोड़े-बहुत सदस्य अब तक अपने को यह पुराने नाम देते थे उन के लिए भी उन नामों का अर्थ अब नहीं था जो पिछली सदी में किया जाता था। उदाहरणार्थ इस सदी के अनुदार दल में राजाशाही के पक्षपाती प्रिन्स ही थे, या कोई थे तो उन की बातों की उतनी ही क्रूर की जाती थी जितनी अफ्रीमचियों की। उसी तरह अपने को 'प्रजातन्त्रवादी' के नाम से पुकारनेवालों में 'अनुदार' और दूसरे हर किस्म के प्रिन्सों के आदमी भी थे। यूरोप का पिछला महासमर शुरू होने पर 'चेंबर ऑफ् डेपुटीज' में राजाशाही कायम करने का अब तक स्वप्न देखनेवाले 'राजाशाही दल' के सदस्यों की संख्या कुल छन्वीस थी।

दूसरा दल अपने को 'उदार दल' के नाम से पुकारता था। इस दल का जन्म

सन् १९०१ ई० में धार्मिक सस्थाओं और प्रजातन्त्र विचारों के संघर्ष के कारण हुआ था। इस का उद्देश्य धार्मिक सस्थाओं और प्रजातन्त्र में मेल कराना था। अस्तु, यह दल उन कानूनों का विरोध करता था जो धार्मिक सस्थाओं पर हमला करने के लिए बनाए जाते थे। इस दल के सदस्य अधिकतर पैसेवाले ही होते थे इस लिए यह दल मालदारों की मिलनियत के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कानून बनाने का पक्षपाती भी था। मगर समाजवादियों की होड़ में चुनाव में मजदूरों के मत लेने के लिए यह दल मजदूरों की कम से कम मजदूरी कानून तय करने, उद्योग-सघों<sup>१</sup> और श्रमजीवियों के सामाजिक बीमे<sup>२</sup> का हामी भी था। सन् १९१४ ई० के चुनाव में इस दल को समाजवादी दल से एक लाख मत अधिक मिले। मगर इस दल के मत देश भर में बिखरे होने के कारण ३४ से अधिक इस के प्रतिनिधि चेंबर में नहीं जा सके। 'समाजवादी दल' के मत उद्योग धंधों स्थानों पर इकट्ठे होने से उन के १०२ सदस्य चुने गए। स्वभावतः 'उदार दल' अनुपात निर्वाचन का पक्षपाती था और 'समाजवादी' उस का विरोधी।

'राजाशाही दल', 'उदार दल' और 'समाजवादी दल' के सिवाय सन् १९०० ई० के चेंबर में एक और भी दल बैठता था जिस को 'सब दल' कहते थे। अपनी भाषा में उसे सब न कह कर हम 'पिटारा दल' कह लें तो भी अनुचित न होगा यह दल पूरा भानमती का पिटारा ही था। इस दल में ऐसे सब तरह के लोगों के लिए जगह थी जिन का उद्देश्य फ्रांसीसी प्रजातन्त्र की, भूत और भविष्य के स्वप्न देखनेवाले दलों के ऊटपटांग हमलों से रक्षा करना था। इस दल का संगठन बहुत मजबूत था। लगभग पंद्रह वर्ष तक फ्रांस के सारे मन्त्रि मंडल इसी दल में से बने और फ्रांस सरकार की नीति बिल्कुल इसी दल के हाथ में रही। इस सब में एक 'प्रगतिशील प्रजातन्त्रवादी दल' था जिस का नेता पॉल डेशानेल था। उस में अधिकतर मध्य श्रेणी और खाते-पीते घरों के लोग थे, जो फ्रांस की क्रांति की घोषणा में जिन व्यक्तिगत अधिकारों की घोषणा की गई थी—खास कर मिलकियत के अधिकारों की—उन पर जोर देते थे। दूसरे कई तरह के विचारवालों का एक 'गरम दल' था जिस के सदस्य आम तौर पर अपने को गेंबेटा के सच्चे अनुयायी कहते थे। इन की संख्या सब में सब से अधिक थी, इस लिए वही अधिकतर सब की नीति निश्चय करते थे। प्रख्यात फ्रांसीसी नेता क्लेमांसो, कॉर्नर और कैली इसी गरम दल के थे। सब में तीसरा एक 'गरम समाजवादी दल' था, जो पैदावार के सारे जरियों और राष्ट्र की सारी संपत्ति पर सरकार का कब्जा अर्थात् लालिस समाजवादी कार्यक्रम का पक्षपाती था। इस में त्रियाँ, मिलाराड, और विव्यानी जैसे प्रभावशाली नेता शामिल थे। धार्मिक सस्थाओं के विरोध और उन की ताकत घटाने का प्रश्न जब तक फ्रांस में जोर पर रहा सब तक यह सब दल मिले रहे, और 'भानमती का पिटारा' काम चलाता रहा। सब ने मिल कर धार्मिक सस्थाओं के पजों से फ्रांस की सरकार को मुक्त किया, पाखंडी पयों को देश से निकाला और धार्मिक शिक्षा के साधारण शिक्षा से अलग किया। मगर जब आमदनी पर कर, चुनाव का ढग इत्यादि रचनात्मक कार्यक्रम के सामाजिक प्रश्न



खड़े होने लगे तब मानमती के इन पिछरे में से निकल निकल कर यह विभिन्न मंडलियाँ अपने अपने आर्थिक हितों और सामाजिक विश्वासों के अनुसार भगड़ने लगीं। फ्रांस का 'चमर ऑव् डेपुटीज' दलबंदी का अखाड़ा बन गया। मंत्रिमंडल जल्दी जल्दी बनने और भिटने लगे। इतने में इत्तफाक से यूरोपीय महासमर छिड़ गया और सारे विभिन्न दल आपस में नॉच-खसोट भूल मर देश की रक्षा के गंभीर विचार में पड़ गए।

युद्ध शुरू होने पर विवयानी प्रधान मंत्री था। समाजवादी लड़ाई में देश का साथ देने या नहीं इस में शुरू में कुछ शक था, क्योंकि एक ठड़े समाजवादी नेता जैसे ने युद्ध छेड़ने का विरोध करने के लिए आत्म हथताल करने की घोषणा की थी। मगर जब यह पता लगा कि फ्रांसीसी सरकार के युद्ध रोकने के सारे प्रयत्न निष्फल हो चुके हैं और जर्मनी बेल्जियम और फ्रांस पर हमला करनेवाला है तो फ्रांस के सब दल मिल कर एक हो गए और सब राष्ट्रीय के बचाव की फिक में लग गए। फ्रांसीसी सेना की थोड़ी-सी हारें होते ही विवयानी ने एक नए मंत्रिमंडल की रचना की जिस में डेलकासे, ब्रियाँ, मिलाराड जैसे प्रभावशाली लोगों को उस में शामिल कर लिया। 'सम्मिलित समाजवादी दल' के दो प्रतिनिधि गेरुडे और सेंवा भी उस में शामिल हुए। फ्रांस के लिए ऐसा मिश्रित मंत्रिमंडल कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वहाँ ऐसे मंत्रिमंडल हमेशा ही बनते रहते थे। मगर इंग्लैंड के मिश्रित युद्ध मंत्रिमंडल से नौ महीने पहले ही फ्रांस ने युद्ध-मंत्रिमंडल बना लिया था। एक साल से कुछ अधिक समय गीत जाने पर समाजवादियों ने इस मंत्रिमंडल का विरोध शुरू किया जिस से इस मंत्रिमंडल को हट जाना पड़ा। फिर ब्रियाँ ने प्रधान मंत्री बन कर देश भर के अच्छे-अच्छे आदमियों को ले कर तेईस आदमियों का एक बड़ा मंत्रिमंडल बनाया जिस में सब दलों के बुद्धिमान लोग और छ भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे। समाजवादी सदस्यों ने इस मंत्रिमंडल पर भी शुरू से ही हमले शुरू किए क्योंकि उन को यह बात पसंद नहीं थी कि युद्ध-संबंधी बातें उन्हें न उताई जायें और वे अखंड मीच कर मंत्रिमंडल के लिए मत देते जायें। अस्तु, कुछ ही महीने में इस मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ा। ब्रियाँ ने फिर प्रधान-मंत्री बन कर उन की गार दस आदमियों का एक मंत्रिमंडल तैयार किया और उस ने युद्ध संचालन का भार एक 'युद्ध मंडल' पर रख दिया जिस में प्रधान मंत्री, परराष्ट्र-मंत्री, अर्थ-सचिव, युद्ध सचिव, जलसेना सचिव, अस्त्रशास्त्र-सचिव, और युद्ध सचिव तथा उद्योग सचिव रखे गए थे। मार्च सन् १९१७ तक इस मंत्रिमंडल ने काम चलाया और फिर इस को भी इस्तीफा दे देना पड़ा। बाद में कई मंत्रिमंडल आए और गए और काफी गड़बड़ी रही। अंत में फ्रांस के प्रचंड राजनीतिज्ञ क्लेमांसो ने प्रधान मंत्री बन कर एक मंत्रिमंडल की रचना की जो सब तरफ के हमले भेल कर भी युद्ध के बाद शांति दिले तक कायम रहा।

युद्ध-काल में सब का ध्यान युद्ध में लीन रहने के कारण फ्रांस में नए दल खड़े नहीं हुए। लोगों का ख्याल था कि लड़ाई के बाद पुराने दल फिर अपने अपने रास्ते पकड़ेंगे अगर लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई होती तो शायद ऐसा होता भी। मगर वर्षों तक गून की नदियाँ बहने का नज़ारा देख चुकने के बाद फ्रांसीसियों को पुरानी दलबंदी की बातें

सुच्छ लगने लगी और लड़ाई के बाद उन्हीं पुराने विचारों और कार्य क्रमों पर पुराने दलों का फिर खड़ा होना नामुमकिन हो गया। जिन दलों ने पुराने विचारों पर फिर से खड़े होने की कोशिश की उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 'गरम समाजवादी दल' तो मिलजुल गायन ही हो गया क्योंकि इस दल के लोग सिवाय धार्मिक संस्थाओं के विरोध के और किसी मामले में कभी एक मत के नहीं रहते थे। अस्तु, धार्मिक प्रश्न सामने न रहने पर ये लोग लड़ाई के बाद फिर कर दूसरे दलों में जा मिले। अपने पुराने कार्य क्रम पर खड़े होने में सत्र से अधिक सफलता एक 'सम्मिलित समाजवादी दल' को जरूर मिली। अगर उस के कुछ जेथीले सदस्यों ने उद्योग धर्मों में हड़ताल करा-करा कर एकदम 'मजदूर पेशा शाही का निरंकुश राज्य' स्थापित करने का व्यर्थ प्रयत्न कर के जनता को माराज न कर दिया होता तो इस दल को और भी अधिक सफलता मिली होती। शांति स्थापित हो जाने के बाद कई नए दल खड़े हुए। एक का नाम 'नई प्रजासत्ता' था। यह दल प्रजातन्त्र के प्रमुख और मंत्रियों के अधिकारों को कम करने और व्यवस्थापक सभा के अधिकारों को बढ़ाने का विरोधी, धारासभा और कार्य-कारिणी की सत्ताओं को मिलजुल अलग अलग कर देने और सरकार के काम को अधिक सीधा और सरल कर देने का पक्षपाती था, और सोलेशे विज्ज का घोर विरोधी था। दूसरा एक दल अपने को 'चौथा प्रजातन्त्र' के नाम से पुकारता था। यह देश के सारे राजनैतिक और आर्थिक जीवन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने का कार्य क्रम गढ़ कर लाया था। तीसरा एक 'राष्ट्रीय प्रजातन्त्र सच दल' था जिस में पिछले पिछले की तरह सत्र युगों के लोग थे यह दल सोलेशेविज्ज का विरोधी और समाज में शांति और स्थिरता, धर्म से शिक्षा को अलग करने, देश में मेल रखने, और लीग ऑफ नेशंस का साथ देने का पक्षपाती था। सब तरह के गरम विचारवालों के मेल से एक चौथा 'प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र सच दल' भी बना था, जो सोलेशेविज्ज और अनुदार विचार दोनों का विरोधी एक बड़ा प्रजासत्तात्मक दल बनना चाहता था। मगर उस के कार्य क्रम का अधिकतर भाग 'राष्ट्रीय सच' और 'सम्मिलित समाजवादियों' में बंट जाने के कारण वह उतना जोरदार नहीं बन सका और इस लिए वह रीच का रास्ता छोड़ कर अधिक गर्मा की तरफ चल पड़ा है। सन् १९१६ के चुनाव में सोलेशेविज्ज के विरुद्ध हवा रहने से समाजवादिया भी बहुत हार हुई और 'राष्ट्रीय सच दल' का हर जगह तूती गोल उठा। अस्तु, लड़ाई के बाद फ्रांस में नए दलों ने उठ कर लड़ाई के पहले के दलों को या तो मिटा दिया या मिलजुल बेकार कर दिया। 'गरम समाजवादी दल' लुप्त हो गया और समाजवादी विचारों के लोग संगठित होने और क्रान्तिकारी समाजवाद और सोलेशेविज्ज की तरफ झुकने लगे तथा शांति और कायम सामाजिक जीवन की स्थिरता चाहनेवालों ने अच्युती तरह संगठित हो कर सामाजिक शांति की ओर देश को ले जाने वालों का सामना किया।

फ्रांस में इंग्लैंड और अमेरिका की तरह ऐसे बड़े बड़े राजनैतिक दल नहीं हैं, जिन की देश भर में संगठित शाखाएँ पैली हों और जिन के बड़े-छूटे कार्यक्रम हों। यहाँ के लोग

अपनी तरीयत और रुझान के अनुसार प्रभावशाली नेताओं के साथ हो जाते हैं और जन तबीयत और रुझान बदल जाती है तब अलग हो जाते हैं। वहा के राजनैतिक दल देश भर में न फैल कर व्यवस्थापन-सभा में ही रहते हैं और अधिभूत चुनाव के बाद बनते हैं। 'सम्मिलित समाजवादी दल' और 'उदार दल' के सिवाय दूसरे राजनैतिक दला का न तो कोई संगठन है और न उन में कोई व्यवस्था ही है। व्यवस्थापन सभा के लिए उम्मीदवार अपने आधार और बल पर रखे हो जाते हैं और अपने चुनाव का प्रबंध खुद ही कर लेते हैं। कभी-कभी ही चुनावों में राष्ट्रीय प्रश्नों का विचार रख कर मत दिए जाते हैं, आम तौर पर निजी और स्थानिक विचारों ही का मत देने में रूपांतर रहता है। इंग्लैंड और अमेरिका की तरह फ्रांस में दल बनने की अभी कोई आशा भी नहीं की जा सकती। फ्रांसीसी की अमेरिका की तरह क्रियात्मक बुद्धि और अमली स्वभाव नहीं है। वे आदर्शवादी, फाल्गुनिक और दिलचले स्वभाव के होते हैं। इन सिद्धांतों को वह आदर्श बना लेते हैं उन में उस चिपक जाते हैं और उन को ज़रा भर भी छोड़ना या उन पर समझौता करना पसंद नहीं करते हैं। अस्तु फ्रांस में बहुत से छोटे छोटे दल बनते रहते हैं। फ्रांसीसियों में भावुकता प्रधान है। राजनैतिक मामला में भी वह विचारशीलता से भावुकता ही को अधिक काम में लाते हैं। चुनाव में रखे होनेवाले उम्मीदवारों के एलान भी सिद्धांतों की व्याख्या और भावुक बातों से भरे होते हैं। देश की हाल की राजनैतिक समस्याओं का उन में बहुत कम जिक्र होता है। एक तो फ्रांस का चुनाव का ढंग भी छोटे छोटे दलों को बनने में सहूलियत देता है, दूसरे फ्रांस में व्यवस्थापन-सभा की समितियों को इतनी ताकत रहती है कि मंत्रि मंडल व्यवस्थापन सभा पर इंग्लैंड की तरह अपनी धाक नहीं जमा पाता है। तीसरे फ्रांस में सबाल पूछ कर मंत्रियों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देने का सदस्यों को अधिकार होता है। इन सब कारणों से फ्रांस में मंत्रि-मंडल और उन के परियाम स्वरूप सुसंगठित राजनैतिक दल नही बन पाते। इंग्लैंड की तरह दो दल फ्रांस में इतिहास के कारण नही बन सके। प्रजातन्त्र स्थापित हो जाने के बाद फिर सत्ता एक बार भी राजतन्त्रवादियों के हाथ में आ जाती तो वह अवश्य ही प्रजातन्त्र को खत्म कर के फिर राजाशाही कायम कर देते। अस्तु, फ्रांस में लोगों ने राजाशाही को एक बार दफन कर के फिर राजतन्त्रवादियों को कभी सत्ता नहीं देने दी। किसी न किसी प्रजातन्त्रवादी दल को ही लोग मत देते रहे। प्रजातन्त्रवादी दलों की ही संख्या फ्रांस में बढ़ती रही है, इंग्लैंड की तरह एक के बाद दूसरे दल के हाथ में सरकार नहीं आई। इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ हमेशा से कहते हैं कि बिना दो सुसंगठित दलों के किसी देश में व्यवस्थापकी प्रजासत्तात्मक सरकार का कायम होना असंभव है, परंतु फ्रांस में दो सुसंगठित दल न होने पर भी व्यवस्थापकी प्रजासत्तात्मक सरकार काम करती है।

# इटली की सरकार

## १-राज-व्यवस्था

मेडीटेरेनियन सागर में एक लंबे बूट जैते की तरह घुसे हुए, फ्रांस के दक्षिणी, यूरोपीय देश, इटली की पुरानी राज-व्यवस्था वेलजियम और फ्रांस से मिलती जुलती थी। सच तो यह है कि यह बिल्कुल फ्रांस की नकल थी। इस देश की राज-व्यवस्था के विचारों का अध्ययन और लड़ाई के बाद उस के राजनैतिक रुझान का अध्ययन बड़ा रोचक है। बहुत दिनों तक इटली निर्जीव, निरुत्साह, आपस की फूट और कुशासन से जर्जरित था। मिलान, टस्कनी और मोडेना के धनधान्य पूर्ण भाग पर आस्ट्रिया का राज्य था, पर्मा, नेपल्स और सिसली पर स्पेन साम्राज्य का अधिकार था। बाकी भाग छत्र-शतन रियासतों में बंटा हुआ था। एक, सारडीनिया की रियासत थी जिस में सारडीनिया का जज़ीरा, पीयडमोंट और नाम के लिए सेवॉय और नीस भी शामिल थे। दूसरी भी पर्मा विराज पोप की रियासत थी और लूका और सेनमेरिनो की दो छोटी छोटी रियासतें भी थीं। वेनिस जेनेव्रा की दो पुरानी रियासतें अलग थीं। इन सब में एक सारडीनिया की रियासत में तो कुछ जीवन की झलक दिखाई देती थी, बाकी सब जगह निर्जीविता, अत्याचार, अधाधुंध और अन्याय का राज्जार गम था। विश्वविजयी नेपोलियन ने जब इटली में प्रवेश किया तो उस की तेज तलवार के सामने एक-एक कर के लगभग इन सभी कमजोर रियासतों के द्वार माननी पड़ी। बहुत काल के बाद इटली का लगभग पूरा भाग एक शर के नीचे आया। एक विदेशी की तलवार के नीचे ही सही मगर इटली एक तो बना। गुलामी में इटली एक बन सकता है तो स्वतंत्रता में भी बन सकेगा इस बात पर विचार करने के लिए साधारण लोगों को एक जीती जागती मिसाल तो मिली। मगर नेपोलियन ने इटली को जीत कर एक ही नहीं किया उस ने वहाँ फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न हुई राज-व्यवस्था भी कायम की। कई जगह पर उस ने फ्रांस के नमूने पर प्रजातन्त्र रियासतें भी खड़ी कीं, जिन का काम चलाने के लिए दो सभा की व्यवस्थापक सभाएँ और डाइरेक्टरी बना दी गई थीं। फ्रांसीसी स्थानिक शासन और न्याय शासन का तरीका इटली में भी जारी किया गया जो अब तक इटली में चला जाता है। मगर नेपोलियन की लीजिंग में द्वार होते ही उस का इटली का साम्राज्य भी बालू के महल की तरह गिर पड़ा

और फिर इटली में वही पुरानी रियासते—मुर्दों की भाँति क़त्ल म से निकल कर—  
खड़ी हो गई। इटली देश के फिर छोटे छोटे टुकड़े हो गए। रियाना की कांग्रेस में  
इटली को दस रियासतों में बाँट दिया गया और उस के बाद लगभग पूरा देश सीधे या  
टेंटे तौर पर आस्ट्रिया के अग़र में आ गया। सारदीनिया में विक्टर ऐमोन्युयल की एक  
इटैलियन रियासत रह गई थी, उस ने भी आस्ट्रिया से सदा के लिए दोस्ती की सधि कर  
ली। मगर नेपोलियन के ज़माने में इटली का एकिकरण और उस में प्रजासत्तात्मक  
स्थापना की बात देख चुकनेवाले इटली देश को भविष्य में 'एक और स्वाधीन' इटली  
राष्ट्र का स्वप्न दीखने लगा था।

सन् १८१५ से १८४८ तक इटली आस्ट्रिया के चाणक्य मेटर्निख की निरकुश  
नीति का शिकार रहा। देश भर की किसी रियासत में कोई निश्चित राज व्यवस्था,  
व्यवस्थापक सभा या और किसी किसम के प्रजासत्तात्मक शासन के विद्व नहीं थे।  
सन् १८२० ई० में नेपल्स में क्रांति हो जाने से वहाँ के राजा फर्डीनैंड ने और उसी  
प्रकार सन् १८२१ में, पीयडमांट में क्रांति हो जाने से, वहाँ के राजा ने इन रियासतों में  
प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था मज़ूर कर ली थी। मगर प्रजा के नेता आपस में मेल न कर  
सके जिस से यह आंदोलन त्रिपल हो रहा। आस्ट्रिया के इशारे पर उठती हुई प्रजा का  
विर कुचल दिया गया। इसी प्रकार सन् १८३१-३२ में मोडेना, पर्मा और पोप की  
रियासतों में भी उत्थात खड़े हुए थे, जिन में काफी उमंगती हुई राष्ट्रीयता की कलक थी।

र उन को भी आस्ट्रिया की मदद से दबा दिया गया था। इटली का क्रांतिकारी दल  
को आस्ट्रिया के पजे से क्रांति द्वारा मुक्त कर के एक राष्ट्र बनाने की बहुत दिनों से  
री कर रहा था। प्रख्यात मेज़िनी के 'यंग इटली' अखबार ने बहुत-से नौजवानों के  
और दिमाग क्रांति के लिए तैयार कर दिए थे। देश भर आनेवाली क्रांति की और  
शा की आँखों से देख रहे थे। सन् १८४६ ई० में पोप ने अपनी रियासतों में प्रजा को  
त से अधिकार दिए और पीयडमांट और टस्कनी की रियासतों ने भी उस का प्रौरण  
किया। सन् १८४८ ई० में नेपल्स में फिर क्रांति हो गई और वहाँ के राजा  
फर्डीनैंड को अपने बाप की तरह मजबूर हो कर प्रजा को अधिकार देने पड़े। प्रजा की जुनी  
एक प्रतिनिधि-सभा और राजा की नियुक्त एक पीयर्स की सभा को व्यवस्थापक सभा  
ना गया। टस्कनी के राजा ने भी पाँच दिन बाद इसी तरह की राज-व्यवस्था  
नी प्रजा को दे दी। स्थूनि की म्यूनिविपेलिटि ने पीयडमांट के राजा चार्ल्स एलबर्ट  
पास एक प्रार्थना-पत्र, जिस पर बहुत से अमीरों, सरदारों और सरकारी अफ़सरों के  
हस्ताक्षर थे और जिस में एक प्रजासत्तात्मक राज व्यवस्था की माँग की गई थी, भेजा था।  
एबर्ट ने उस पर खूब विचार कर के मंत्रियों और अधिकारियों की सभा में कहा कि, 'राज्य,  
तक़्क और धर्म की खेर! मेरा विश्वास हो गया है, और इसी में है कि प्रजासत्तात्मक  
व्यवस्था जल्दी से जल्दी क़ायम कर दी जाय।' दूसरे ही दिन इस घोषणा का  
एलान कर दिया गया और राज-व्यवस्था तैयार करने के लिए एक कमीशन पैठा दिया  
गया। इस कमीशन ने फ्रांस की सन् १८३० ई० की राज-व्यवस्था को नमूना मान कर

उसी दग की एक राज व्यवस्था गढ़ कर शीघ्र ही तैयार कर दी। देश की मूल राज-व्यवस्था<sup>१</sup> के नाम से ४ मार्च सन् १८४८ ई० को इस राज-व्यवस्था की घोषणा हुई जो इटली के संयुक्त राज्य की राज्य व्यवस्था का ग्राह्य तत्त्व आधार है। इसी बीच में लुई फिलिप के राज्य-व्युत्पन्न हो जाने, जर्मनी में क्रांति होने और मेटरनिख के पद-व्युत्पन्न होने की खबरें आईं जिससे इटली में उत्साह की लहर उठ खड़ी हुई। पोप और नेपल्स के राजा ने प्रजा के दगम से उत्तरी इटली की रियासतों को आस्ट्रिया के बधनों से मुक्त करने के लिए मेनाए भेरी। ऐसा मानलूम होने लगा मानो पीयडमोंट के राजा चार्ल्स एलर्ट के नेतृत्व में स्वीकार कर के इटली ने एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करके एक राष्ट्र हो जाने का निश्चय कर लिया हो। जुलाई मास में नेपल्स में प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था कायम हो गई और सन् १८४९ ई० की फरवरी में पोप और उस की प्रजा में झगडा हो जाने पर रोम में भी एक पार्लीमेंट बन गई और रोम को प्रजातन्त्र करार दे दिया गया। मगर अचानक ही नेपल्स के राजा ने लड़ाई से हाथ धांच लिया और नेपल्स की प्रजासत्तात्मक राज व्यवस्था को खत्म कर दिया जिस से सुधारका की शक्ति क्षीण हो गई। निरंकुश राजा किस समय क्या करेगा कोई कह नहीं सकता। तुलसीदास की 'जानि न जाय निशाचर माया' निरंकुश शासन के लिए बिलकुल ठीक उतरती है। नेपल्स, आस्ट्रिया और फ्रांस की सहायता ले कर पोप ने भी रोम के प्रजातन्त्र को खत्म करके फिर से अपना निरंकुश शासन कायम कर लिया। उत्तर और मध्य देश की उठती हुई रियासतों को एक एक कर के आस्ट्रिया ने दना दिया और फिर से वहाँ आस्ट्रिया का असर आतंक कायम हो गया। निरंकुशता के राज्स ने प्रजा की स्वाधीनता को कुचल कर फिर अपना माया जाल बिछा दिया और प्रजा के अधिकारों के पक्षगती निराश और दुखी हो कर इधर-उधर तितर-बितर हो गए। एक पीयडमोंट की रियासत में अवश्य स्वाधीनता की कुछ झलक अब तक दिखाई देती थी। वहाँ के राजा चार्ल्स ने एक लड़ाई में बुरी तरह हार हो जाने पर सिंहासन छोड़ दिया था और उस का लडका विकटर इमेनुयल द्वितीय गद्दी पर आ बैठा था।

विकटर इमेनुयल को अपनी प्रजा के अधिकार छीन लेने के लिए सब तरफ से सलाहें दी गईं, बहुत से प्रलोभन दिए गए और तरह-तरह के सब्ज बाग दिखाए गए। मगर उस ने किसी की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया और प्रजा की स्वाधीनता और अधिकारों को जेसा का तेसा कायम रखा। अस्तु, इटली के देश भर्त्ता की निगाहें पीयडमोंट की तरफ लग गई और सब को स्वाधीनता की आशा पीयडमोंट से होने लगी। यह आशाएँ व्यर्थ न गईं। सन् १८४८ ई० के बाद में इटली की स्वाधीनता और राष्ट्रीयता के विकास का इतिहास पीयडमोंट रियासत के संगठन, नेतृत्व, उत्थान और विस्तार का ही इतिहास है। विकटर इमेनुयल खुद कोई बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं था। मगर उस में काफी बुद्धि और ईमानदारी थी। उस ने एक ऐसे मनुष्य को अपना मंत्री बनाया था जो यूरोप के आधुनिक इतिहास के गिने-चुने राज-नीतिज्ञों में हो गया है। उस का नाम काउंट केयूर था। मेज़िनी की क्रांति

<sup>१</sup> स्टेटो फ़ॉन्डामेंटल डेल रेग्ने।

कारी भद्रा और फलम, गेरीगाल्डी की तलवार और केवूर की राजनीति ने इटली को स्वतंत्र और एक राष्ट्र बनाने में अद्वितीय काम किया। केवूर सन् १८५० ई० में मंत्री बनने से पहले ही प्रजा के अधिकारों और इटली की राष्ट्रीय एकता का कट्टर पक्षपाती मशहूर था। पहले तो इमेनुयल और केवूर की इच्छा इटली से आस्ट्रियनों का प्रभाव हटा कर पोप की अध्यक्षता में इटली को कई रियासतों की संघ का एक राष्ट्र बनाने की थी। मगर पीछे से उन का उद्देश्य सारे इटली का एक केंद्रित, राष्ट्रीय सरकार के नीचे एकीकरण करना हो गया। सन् १८५५ ई० में केवूर ने फ्रांस में 'हमले और बचाव में दोस्ती' की एक संधि कर के फ्रांस के इशारे पर सन् १८५६ में आस्ट्रिया से लड़ाई छेड़ दी। आस्ट्रिया की हार हो गई और पीयडमोंट ने लॉगार्डों की रियासत त्रिव के नागरिक बहुत दिनों से पीयडमोंट से मिलना चाहते थे, आस्ट्रिया से छीन ली। मगर संधि की शर्तों के अनुसार केवूर को सेनाय और नीस फ्रांस को दे देना पड़ा। फिर भी पीयडमोंट को उड़ा फायदा हुआ क्योंकि उस की आस्ट्रिया पर जीत हो जाने से देश में उत्साह का नूफान-सा उठ गया हुआ और मध्य इटली की बहुत-सी रियासतों ने गिगडवर पीयडमोंट से मिल जाने का एलान कर दिया। टस्कनी, मोडेना, पार्मा, रोमना की चार रियासतों के प्रतिनिधियों की समाधियों ने मिल कर जब एकमत से पीयडमोंट के राज्य में मिल जाने की राय प्रगट की तब उन के नागरिकों के पीयडमोंट रियासत की तरफ से, इस बात पर मत लिए गए कि वे स्वतंत्र रियासतें रहना पसंद करेंगी अथवा पीयडमोंट में मिल जाना। इन रियासतों की जनता के बहुत बड़ी मख्या में पीयडमोंट से मिल जाने के लिए मत मिलाने पर पीयडमोंट की व्यवस्थापक-सभा की राय से वहाँ के राजा ने पीयडमोंट से इन रियासतों के मिल जाने की घोषणा की और इन सब रियासतों से फौरन प्रतिनिधि चुन कर स्टूरिन की पार्लामेंट में बैठने के लिए आ गए। एक साल के भीतर भीतर ही लगभग इटली के आधे लोग पीयडमोंट के झंडे के नीचे मिल कर एक हो गए। फिर गेरीगाल्डी ने अपने 'हजार वीरों' की सहायता से नेपल्स और सिसली को मुक्त कर के सन् १८६० ई० में पीयडमोंट से मिला दिया। इसी समय में पीयडमोंट की सेनाओं ने पोप की अग्रिया और मार्चेंज नाम की रिपब्लिकों को जीत कर उनके नागरिकों के मत से स्टूरिन की पार्लामेंट में मिला लिया। आखिरकार देशभक्तों का स्वप्न पूरा हुआ, और उन की मेहनत सफल हुई। बहुत घायों से बिसरा हुआ इटली आखिरकार एक बना और "ईश्वर की कृपा और राष्ट्र की इच्छा से विक्टर इमेनुयल द्वितीय को इटली का राजा" फार दिया गया। सिर्फ वेनेशिया और रोम के दो प्रांत मिलने के लिए रह गए। सन् १८६६ ई० में इटली की आस्ट्रिया के विरुद्ध संधि होने पर वेनेशिया भी इटली में मिल गया। फ्रांस और जर्मनी का सन् १८७० ई० में युद्ध छिड़ने पर पोप की सहायता के लिए रक्खी हुई फ्रांस की सेना रोम से हट जाने पर देशभक्तों की सेनाएँ रोम में घुस गईं और रोम को भी इटली के संयुक्त राष्ट्र में मिला लिया गया। प्राचीन रोम फिर इटली राष्ट्र की राजधानी बनाया गया और नवंबर सन् १८७१ ई० में इटली के स्वाधीन राष्ट्र की व्यवस्थापक-सभा की पहली बैठक रोम में हुई।

पीयडमोंट के राजा चार्ल्स एलबर्ट ने जो राज व्यवस्था पीयडमोंट में क्रियम की

भी उसी के अनुसार पीयडमोंट की रियासत का काम चलता था। फिर दूसरी रियासतों ने भी जब पीयडमोंट से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन के नागरिकों के मत ले कर इस राज-व्यवस्था में मिला लिया गया। वेनिशिया और रोम के नागरिकों ने भी इसी व्यवस्था के लिए मत दिए। अस्तु, इटली राष्ट्र की राज व्यवस्था यही रही। यह राज व्यवस्था राजा की ओर से प्रजा को दी गई थी इस लिए यह कहा जा सकता है कि राजा को उस में तबदीली करने या उस को वापिस ले लेने का अधिकार था। मगर बात ऐसी नहीं थी। राज व्यवस्था में इस बात का कोई जिक्र न होने पर भी कि उस में परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, सब की राय यही थी कि उस में परिवर्तन सिर्फ प्रजा की इच्छा से हो सकता है, क्योंकि उस का जन्म प्रजा की इच्छा पर हुआ था। यह राय इटली में सर्वमान्य हो गई है और इस लिखित राज व्यवस्था में अब तक इस सच की कोई शर्त न जोड़ कर भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा का सब प्रकार के कानून बनाने का अधिकार माना जाता है। तब से अब तक इटली की व्यवस्थापक सभा में कई बड़े बड़े उद्योग-पुथल मचा देनेवाले कानून पास हो चुके हैं, जिन का इटली की राज व्यवस्था से साफ सम्बन्ध था। मगर व्यवस्थापक सभा को सर्व शक्तिमान मान कर भी ऐसे कानून सभा में तभी स्वीकार किए जाते हैं जब देश की साफ तौर पर राय उन की तरफ होती है। तरह तरह के कानूनों, रियाजों, और नई नई संस्थाओं के, इस राज-व्यवस्था में बाद में धीरे धीरे मिल जाने से इटली की आजकल की राज व्यवस्था का कामकाज सिर्फ इस चार्ल्स एलबर्ट की लिखित राज व्यवस्था को देख कर ही नहीं जाना जा सकता है। इंग्लैंड की तरह इटली की आजकल की राज व्यवस्था बहुत-से रियाजों पर चलती है जिन को जानने के लिए इटली की राजनैतिक संस्थाओं का अध्ययन जरूरी है। लिखित राज व्यवस्था इटली की बहुत छोटी है, अमेरिका की लिखित राज व्यवस्था की आधी भी नहीं है।

## २—राजछत्र

इटली के १८४८ ई० के क्रांतिकारी अठल में सभी प्रजातन्त्रवादी थे। और उन्होंने ने इटली में प्रजातन्त्र-राज्य की स्थापना का स्वप्न देख कर ही क्रांति की आग भड़काई थी। परन्तु घटना चक्र से इटली का प्रजातन्त्र राज्य बनना असम्भव हो गया और जैसा हम ने देखा, यह पीयडमोंट राजघराने के नेतृत्व में एक 'प्रतिनिधि राजा शाही राज्य' बन गया। अगर मेज़िनी की भ्रष्टा और उस के क्रांतिकारी प्रयत्न, गेरीबान्डी की तलवार और केचर की राज नीति को इटली राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधनेवाला कहा जा सकता है, तो उस के साथ साथ यह बात भी माननी ही पड़ेगी कि पीयडमोंट के राजा निकट इमेनुअल की उदारता, दूरदर्शिता और उस की सर्व प्रियता भी इटली को एक स्वाधीन और सगठित राष्ट्र बना देने में एक मूल कारण थी। इस राजा के ऊँचे के नीचे इटली को मिल कर एक हो जाने का बड़ा अच्छा अवसर मिला। अगर दुनिया के किसी राज घराने को अभिमान के साथ किसी प्रजा सत्तात्मक-राज्य के ऊपर अपना राजछत्र कायम रखने का उचित अधिकार हो सकता है,



तो वह पीयडमोंट के प्राचीन सेवोय राजकुल की है, जिस का अभी तक इटली पर राजछत्र कायम है। यूरोप के राजघरानों में आजकल राज करनेवाला यह सब से पुराना राज-घराना है। इस कुल का सब से बड़ा बेटा इटली के राजछत्र का अधिकारी होता है।

उस का व्यक्तित्व राज-व्यवस्था के अनुसार पवित्र और अखंड माना जाता है। उस को १,६०,५०,००० लाइर<sup>१</sup> सालाना राष्ट्र के खजाने से खर्च के लिए दिया जाता है, जिस में से दस लाख वह खजाने को लौटा देता है। वह एक सुंदर ऊँचाई पर बने हुए राज-महल में रहता है, जिस में प्राचीन काल में स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए पोप अक्सर जा कर रहते थे। कहने के लिए उस को बहुत अधिकार हैं। मगर इंग्लैंड के राजा की तरह वह अपनी इच्छा से राजकाज में कुछ कर नहीं सकता है; क्योंकि इंग्लैंड की तरह इटली में भी बिल्कुल व्यवस्थापकी राज है। मंत्री सारा राजकाज चलाते हैं और वे व्यवस्थापक-सभा के प्रति सारे राजकाज के लिए ज़ायबदार होते हैं। कहने के लिए इटली के राजा को कानूनों को मंजूर और एलान करने, अपराधियों को क्षमा प्रदान करने और उन की सज़ा कम करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, अॉर्टॉनैंस निकालने, मिनेट के सदस्य और अधिकारियों को नियुक्त करने इत्यादि के बहुत-से अधिकार हैं। मगर इन अधिकारों का उपयोग वास्तव में मंत्री-मंडल करता है। नाम के लिए राजा को व्यवस्थापक-सभा के किसी प्रस्ताव को नामंजूर करने का अधिकार है। मगर उस का उपयोग करने का कभी मौका नहीं आता है; क्योंकि जब किसी मंत्री-मंडल का व्यवस्थापक-सभा पर जोर नहीं रहता है, तो वह इस्तीफा दे देता है और नया मंत्री-मंडल जो व्यवस्थापक-सभा के मेल से काम चला सकता है, नियुक्त हो जाता है। अतः राजा को व्यवस्थापक-सभा के किसी प्रस्ताव को नामंजूर करने का मौका ही नहीं आता। राज-व्यवस्था के अनुसार जिन संधियों से राष्ट्र की संपत्ति और सीमा पर कोई असर पड़ता है, उन संधियों को करने से पहले राजा को उन पर व्यवस्थापक-सभा की राय ले लेनी चाहिए। मगर सैनिक और दोस्ती की संधियों के बिना लगभग और सब प्रकार की संधियाँ दूसरे राष्ट्रों से होने से पहले उन पर व्यवस्थापक सभा की राय ले ली जाती है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजा की बात काफी सुनी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों में उस का अच्छा हाथ रहता है।

इंग्लैंड के राजछत्र की तरह इटली का राजछत्र व्यवस्थापक राजछत्र होने पर भी इटली का राजा इंग्लैंड के राजा से अधिक राज-काज में भाग लेता है। इटली का राजा इटली राष्ट्र की सेनाओं का सेनाधिपति होता है और कई बार युद्ध छेड़ने पर वह अपनी सेनाओं के साथ युद्ध-क्षेत्र में भी गया है। उस को प्रधान मंत्री के चुनने में<sup>२</sup> भी बहुत

<sup>१</sup> इटली का सिक्का।

<sup>२</sup> जब से इटली में फ़ेसिस्टदल के नेता मुसोलिनी का अधिकार स्थापित हुआ है तब से राजा की इन सत्ताओं पर बहुत कुछ असर पड़ा है। अब यह कहा जा सकता होगा कि, उस को प्रधान मंत्री के चुनने में बहुत कुछ स्वतंत्रता रहती है क्योंकि वह मंत्रियों को निकाल या भिक्ष कर सकता है।

कुछ स्वतंत्रता रहती है। वह फ्रांस के प्रमुख की तरह मन्त्रि-मंडल की बैठकों का अध्यक्ष हो कर बैठता है और मन्त्रि-मंडल के काम में हिस्सा लेता है। व्यवस्थापक-सभा से मन्त्रियों का समझ ठीक रहने पर भी वह चाहे तो उन को निमाल समझता है और मन्त्रियों को सलाह देने, हिदायत करने और फिटफाने का अधिकार तो उसे हमेशा ही रहता है। हर बात में वह मन्त्रियों की सलाह पर ही अमल करने के लिए, भी बाध्य नहीं होता है। राज-व्यवस्था कायम होने के बाद से आज तक इटली के किसी राजा ने कभी अपना व्यक्तिगत निरंकुश शासन फिर से स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है। इटली के एक राष्ट्र बनने में अतः तक जितने राजा हुए हैं, वे सब अच्छे स्वभाव और प्रवृत्ति के हुए हैं और उन्होंने अपने राजकुल की सर्व प्रियता उड़ाई है। पिछली लड़ाई में यूरोप के बहुत-से राजछत्र ढावांड़ोल हो गए, मगर इटली का राजछत्र लड़ाई के बाद भी सर्व मिय रहा है।

### ३—मन्त्रि-मंडल

राजा प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है, और प्रधान मंत्री अपने मन्त्रियों को चुन कर उसके सामने पेश करता है, जिन को राजा मजूर कर के नियुक्त कर देता है। मगर इंग्लैंड की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा में सरकारी दल के विरोधी दल का अभी हाल तक कोई एक ही नेता नहीं होता था, जिस से राजा बुला कर प्रधान मंत्री नियुक्त कर दे, और जो आसानी से अपना मन्त्रि-मंडल बना ले। फ्रांस की तरह इटली की व्यवस्थापक सभा में मुसोलिनी के आने तक बहुत से दल होते थे। राजा को फ्रांस के प्रमुख की तरह बहुत से लोगों से बात-चीत कर के, निम्नी ऐसे मनुष्य को प्रधान मंत्री चुनना होता था, जो उस की राय में ऐसा मन्त्रि-मंडल बनाने के योग्य होता था, जिस का विरोध व्यवस्थापक-सभा में न हो। इटली के प्रायः सभी मन्त्रि-मंडलों में सभी दलों के लोग होते थे क्योंकि कई दलों की सहायता में ही मन्त्रि-मंडलों को व्यवस्थापक-सभा में बहु-संख्या मिलती थी। मन्त्रि-मंडल के सदस्य, चेंबर ऑफ़ डेपुटीज या सिनेट के सदस्यों में से या बाहर से भी बनाए जा सकते हैं। मगर मन्त्री अक्सर चेंबर ऑफ़ डेपुटीज के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जो बाहर से लिए जाते हैं, वह रिवाज के मुताबिक चेंबर में कोई जगह खाली होने ही चुन कर आ जाते हैं। प्रधान मंत्री भी विरला ही कोई कभी सिनेट का सदस्य होता है। प्रायः वह चेंबर में से ही लिया जाता है। मगर युद्ध और जल सेना के मन्त्री अक्सर सिनेट के सदस्य होते हैं। यह मन्त्री अक्सर विशेषज्ञों में से बनाए जाते हैं, जो प्रायः या तो सिनेट के सदस्य होते हैं या जिन को बाद में सिनेट का सदस्य बना दिया जाता है। आम तौर पर हर शासन विभाग का एक मन्त्री होता है। पिछली लड़ाई खत्म होने पर परराष्ट्र, युद्ध, जल सेना, अर्थ, खजाना<sup>१</sup>, उपनिवेश, शिक्षा, निर्माण कार्य, डाक और तार, न्याय और धर्म, व्यापार और श्रम, खेती, सार्वजनिक सहायता और पेंशन, मार्ग और प्रबन्ध शस्त्र इन चौदह विभागों के चौदह मन्त्री थे। कभी-कभी निम्न विभाग के मन्त्री भी मन्त्रि-मंडल में ले लिए जाते हैं। हर मन्त्री के नीचे

<sup>१</sup> इटली में अर्थ-सचिव और कोष सचिव दो मंत्री होते हैं। मगर कभी-कभी दोनों विभागों को एक ही मंत्री के अधीन भी कर दिया जाता है।

एक उपमंत्री होता है। उस का चुनाव भी मंत्री की तरह ही किया जाता है।

हर एक मंत्री अपने अपने विभाग का शासन चलाता है, और सब मंत्री मिल कर शासन की आम नीति निश्चित करते हैं और कानूनी मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक सभा में रखते हैं। इटली के मंत्रियों को भी वही सारे काम करने होते हैं जो और दूसरे व्यवस्थापकी सरकार के मंत्रियों को करने होते हैं। जो मसविदे सरकार की तरफ से व्यवस्थापक-सभा में पेश किए जाते हैं उन पर और संधिया, शासन मन्धी झगड़ों, धर्म-क्षेत्र और राज क्षेत्र की गुंथियों, व्यवस्थापक-सभाओं की अर्शियां, सिनेट के सदस्यों और एलचियों की नियुक्ति और अन्य दूसरी बहुत-सी शासन और न्याय-सम्बन्धी बातों पर मन्त्रि मंडल में विचार होता है। प्रधान मंत्री मन्त्रि-मंडल की बैठकें बुलाता है, बैठकों में अध्यक्ष का शासन होता है, विभागों के शासन की खबर पृष्ठता है और सब मंत्रियों की नीति और चाल को एक ढंग में रखता है।

मंत्रियों और उपमंत्रियों को व्यवस्थापक सभा को दोनों सभाओं में बैठने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। मगर अपना मत वे उसी सभा में डालते हैं जिस के वे सदस्य होते हैं। सभाओं को किसी मंत्री को सभा की बैठकों में ज़रूरतली हाज़िर रखने का अधिकार नहीं होता। मगर किसी खास मंत्री के खास तारीखों या मौकों पर सभा में हाज़िर रहने के लिए सदस्यों की ओर से अक्सर प्रार्थनाएँ की जाती हैं और अगर आवश्यक मंत्रियों को उस समय पर कोई दूसरा बड़ा ज़रूरी काम नहीं होता है तो वे सदस्यों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। फ़्रांस की व्यवस्थापक-सभा की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा मंत्रियों की कार्रवाइ पर कड़ी नज़र रखती है, और उन के काम-काम में बहुत कुछ हस्तक्षेप करती है। फ़्रांस की तरह इटली में भी मंत्रियों से प्रश्न पूछ कर उन पर चर्चा चलाई जा सकती थी और उस के परिणाम-स्वरूप मंत्रियों को मिनाला जा सकता था। फ़्रांस की तरह अक्सर इस अधिकार का व्यवस्थापक-सभा के सदस्य दुरुपयोग करते थे। व्यवस्थापक-सभा को मंत्रियों से वागजात तलाश करने और उन के काम की जांच करने के लिए कमीशन नियुक्त करने का भी अधिकार होता था। फ़्रांस की तरह इटली में भी मुसोलिनी के आने तक जल्दी जल्दी मन्त्रि मंडल बदलते रहते थे। मगर सरकार की नीति इतनी जल्दी जल्दी नहीं बदलती थी क्योंकि अक्सर वही लोग लौट फिर कर मन्त्रि मंडलों में आ जाते थे। फिर भी इटली के मन्त्रि मंडल, दलबंदी की बीमारी और व्यवस्थापक-सभा की छेड़खानी की वजह से, बहुत अक्सर और जोरदार नहीं होते थे। राजा के नाम पर कार्यकारिणी का काम मन्त्रि मंडल चलाता था। मगर मन्त्रि मंडल के पास व्यवस्थापक-सभा को हमेशा काबू में रखने की शक्ति नहीं होती थी और व्यवस्थापक-सभा के सदस्य शासन के मामलों में व्यर्थ का बहुत-सा हस्तक्षेप करते थे। मसविदे पेश कर के अपने अरसर से कानून बनाने का अधिकार मन्त्रि मंडल को होता था। मगर व्यवस्थापक-सभा पर जोर डालने की शक्ति उस के पास न होने से सभा के सामने पेश किए हुए मसविदे उसी रूप में या कभी कभी बिल्कुल तब स्वीकार नहीं होते थे, और मन्त्रि मंडल जिन सुधारों को करना चाहता था वह प्रायः बहुत दिनों तक रुके पड़े रहते थे। व्यवस्थापकी सरकार की पद्धति में मन्त्रि मंडल

अपनी ताकत के बल पर कार्यकारिणी और धारसभा की शक्तियाँ को एक सूत्र में बाँध कर रखता है। मगर इटली के मन्त्रि-मण्डल दल-पदी के मन्त्रियों की वजह से जल्द-जल्द बदल जाने के कारण बहुत कमजोर रहते थे और वे इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन आर्टोर्नोन्स निकाल कर अर्थात् व्यवस्थापक-सभा की राय न ले कर अपने हुकम से बहुत से काम करने का अधिकार इटली के मन्त्रि मण्डल को था। जिस प्रकार अपने देश में सन् १९३१-३२ ई० के असहयोग आंदोलन के जमाने में वायसराय ने कार्यकारिणी कौंसिल<sup>१</sup> की सलाह से बहुत से आडानस निकाले थे और उन पर उमी तरह अमल किया गया था जिस तरह कानूनों पर किया जाता है, उसी प्रकार इटली के मन्त्रि मण्डल को भी आर्टोर्नोन्स निकाल कर अस्थायी कानून जारी करने या व्यवस्थापक सभा के पास किए हुए कानूनों को उलट देने का जबरदस्त अधिकार होता है। आश्चर्य यह है कि मन्त्रि मण्डल के इस अधिकार की इटली की व्यवस्थापक सभा शिकायत तक नहीं करती थी बल्कि कभी कभी खुद मन्त्रि मण्डल से इस अधिकार का उपयोग करने के लिए कहती थी। सन् १८८९ ई० के बड़े ज़रूरी चुनाव के मसविदे पर व्यवस्थापक सभा ने बहस कर के उस का आखिरी फ़ैसला और उस के जारी करने का काम इस अधिकार के अनुसार मन्त्रि मण्डल पर छोड़ दिया था। मन्त्रियों के अतिरिक्त स्थानिक अधिकारियों को भी इसी प्रकार का अधिकार रहता है। मालूम होता है इटली के लोग अधिकार के जोर के सामने सिर झुकाना पसंद करते हैं, और शायद इसी लिए मुसोलिनी का लोहा इटली ने बड़े उत्साह से मान लिया है।

## ४—व्यवस्थापक-सभा

### १—सिनेट

इटली में कानून बनाने का अधिकार राजद्वय और व्यवस्थापक सभा को है। व्यवस्थापक सभा के दो भाग हैं—एक सिनेट और दूसरा 'केमेरा दे दिपुताती' अर्थात् प्रतिनिधि सभा। इटली की सिनेट दुनियाँ भर में इस बात में अनोखी है कि इस के सदस्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। कुछ वर्ग निश्चित कर दिए गए हैं जिन वर्गों के लोगों में से राजा—अमल में राजा के नाम पर मन्त्रि मण्डल—जितने सदस्य चाहे उतने सिनेट के लिए जिंदगी भर के लिए चुन सकता है। सन् १८४८ ई० में जब राज-व्यवस्था कायम हुई थी तब सिनेट के ७८ सदस्य थे और १९१६ ई० में ३६५ सदस्य थे। अक्सर बड़े अधिकारियों, प्रख्यात लेखकों, वैज्ञानिकों और दूसरे देश का नाम उँचा करनेवाले लोगों और ३००० लाइर का कम से कम तीन वर्ष तक सरकार को सीधा कर देनेवाले लोगों में से सिनेट के सदस्य चुने जाते हैं। सिनेट के सदस्यों की कानून के अनुसार कम से कम चालीस वर्ष की उम्र होना ज़रूरी है। मगर राजा के ख़ादान के राजदुलारा को २१ वर्ष की उम्र से सिनेट में बैठने और २५ वर्ष की उम्र से मत देने का जन्मनिद अधिकार होता है।

<sup>१</sup> इंग्लीशपूब्लिक कौंसिल।

इटली की सिनेट शानदार सस्था होती है क्योंकि उस में देश भर के लगभग सभी मशहूर और बड़े आदमी होते हैं। मगर उस के हाथ में बहुत ताकत नहीं होती है। अगर सिनेट व्यवस्थापक-सभा की दूसरी शाखा 'केमेरा दे दिपुताती' के किसी जरूरी प्रस्ताव का विरोध करने की धमकी देती है तो राजा के नाम से मंत्रि मंडल सिनेट में नए सदस्य भर कर सिनेट का स्वर अपनी इच्छा के अनुसार मिला लेने का अधिकार रखता है। सन् १८६० ई० में ऐसा मौका पड़ जाने पर एक दम सिनेट में ७५ नए सदस्य ठेस दिए गए थे। अस्तु, सिनेट केमेरा दे दिपुताती की बराबरी की समा नहीं है, उस से कहीं कमजोर है। सिनेट में इस बात का फैसला करने का अधिकार होता है कि जो सदस्य सिनेट के लिए चुन कर आते हैं उन को सिनेट में बैठने का अधिकार है या नहीं। मगर इस का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि जो उर्ग निश्चित कर दिए गए हैं उन्हें वहां में से राजा को सिनेट के सदस्य चुनना चाहिए और जब तक राजा इस सीमा का उल्लंघन नहीं करता है तब तक सिनेट किसी सदस्य के बारे में कोई उम्र नहीं करती है।

## २—केमेरा दे दिपुताती

केमेरा दे दिपुताती अर्थात् इटली की व्यवस्थापक सभा की—जिस को हम प्रतिनिधि सभा कह सकते हैं—निचली सभा में, करीब ५०० सदस्य होते हैं। उन का चुनाव एक एक क्षेत्र से एक एक सदस्य और सीधा और गुप्त मत देने के, सिद्धांत पर होता था। प्रतिनिधि सभा पाँच वर्ष के लिए चुनी जाती थी मगर पाँच वर्ष पूर्य होने से पहिले ही अक्सर यह सभा भंग हो जाती थी। ग्राम स्तर पर औसतन प्रतिनिधि-सभा करीब तीन वर्ष तक काम करती थी। तीस वर्ष की उम्र से ऊपर के इटली राष्ट्र के उन सब मर्द नागरिकों को जिन से किसी कारण से मतधिकार छीन नहीं लिया गया है—प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के चुनाव में मत डालने का अधिकार होता है। मगर राष्ट्र की सेना में सेवा कर चुकनेवालों और पढ़ना लिखना जाननेवाले नागरिकों को मत देने का अधिकार २१ वर्ष की उम्र में हो प्राप्त हो जाता है। किसी क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को उसी क्षेत्र में बसने वाला होना जरूरी नहीं है। मगर चुनाव में सफल होने के लिए उस को उस क्षेत्र के सारे मतदारों के दसवें भाग से अधिक और चुनाव में पड़नेवाले मत के आधे से अधिक मत मिलाने चाहिए। अगर किसी भी उम्मीदवार को किसी क्षेत्र से इतने मत नहीं मिल पाते हैं तो एक हफ्ते के बाद फिर से चुनाव होता है। और उस में जिस को सब से अधिक मत मिलते हैं उसी को चुन लिया जाता है। पादरी और मंत्री, उपमंत्री और सेना के अफसरों को छोड़ कर सरकार के तनख्वाहदार नौकरों और सरकार से पैसा पानेवाले और सब मनुष्यों को प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मीदवार होने का हक नहीं है। मंत्रिया और उपमंत्रियों को छोड़ कर दूसरे सरकार के तनख्वाह पानेवाले लोगों की चालीस से अधिक सख्या किसी समय प्रतिनिधि-सभा में कानून के अनुसार नही हो सकती है। सदस्यों को पत्र-व्यवहार के खर्च के लिए २००० लाइर सालाना और कोई दूसरी आमदनी न होने पर निजी खर्च के लिए ४००० लाइर सालाना सरकारी खजाने से दिए जाते हैं। जिन सदस्यों को ४००० लाइर से कम की आमदनी होती है उन को सिर्फ उतने लाइर सालाना और दिए जाते हैं जिन

को मिला कर उन की आमदनी ४००० लाइर साल की हो जाती है। सरकारी रेलों पर मुक्त सफर करने का अधिकार भी सदस्यों को होता है।

### ३—कामकाज

कानून के अनुसार दोनों सभाओं की बैठकें एक साथ ही बुलाई जानी चाहिएँ और दोनों सभाओं की बैठकें एक साथ ही शुरू और खत्म होनी चाहिएँ। कानून में सालाना बैठक के लिए कोई फेद नहीं है। मगर बजट पर विचार करने के लिए हर साल व्यवस्थापक सभा की बैठक होती है और छोटी मोटी छुट्टियाँ ले कर बराबर एक साल तक और कभी कभी दो साल तक बैठक होती रहती है। सिनेट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राजा करता है और मंत्रियों का चुनाव सदस्य अपने साथियों में से स्वयं करते हैं। प्रतिनिधि-सभा के सारे अधिकारियों का चुनाव सभा अपनी बैठक के समय के लिए खुद करती है। मगर इंग्लैंड के हाउस ऑफ़ कामन्स की तरह प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बार बार एक ही आदमी बन तब यह राज़ी होता है चुना जाता है और उस के बारे में दलबन्दी का विचार नहीं किया जाता है। प्रतिनिधि-सभा के सदस्य नौ भागों में और सिनेट के पांच भागों में—जिन्हें युफिसी कहते हैं—बाँट दिया जाता है और दो सहीने के बाद पच्ची डाल कर इन भागों के सदस्य बदलते रहते हैं। यह युफिसी ही विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए कमेटियाँ चुनते हैं। दोनों सभाएँ सब से जरूरी 'अर्थ कमेटी' को स्वयं चुनती हैं। खास प्रश्नों पर विचार करने के लिए खास कमेटियाँ भी प्रतिनिधि सभा बनाती हैं। चुनाव और नियमों के लिए कमेटियाँ सभा के अध्यक्ष नियत करते हैं।

दोनों सभाएँ अपनी कार्यवाही के नियम खुद बनाती हैं। सभाओं की बैठकें सार्वजनिक होती हैं। परन्तु दस सदस्यों की प्रार्थना पर बैठकें गुप्त की जा सकती हैं। दोनों सभाओं की बैठकों में जब तक आधे से अधिक सदस्य मौजूद न हों तब तक कोई बैठक बाधायदा नहीं मानी जा सकती और न किसी विषय पर विचार हो सकता है। प्रतिनिधियों को, जिन लोगों से वे चुन कर आते हैं उन का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। सभाओं में मत खंडे होकर दिए जाते हैं मगर, बाँट होने पर<sup>१</sup> और रुपए-पैसे के मामलों पर या जिन प्रश्नों में किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप होता है उन पर गुप्त दिए जाते हैं। मंत्र मसविदे दोनों सभाओं में स्वीकार हो जाने पर ही कानून का रूप धारण कर सकते हैं। राष्ट्र के प्रति राजद्रोह के मुकदमों और मंत्रियों पर प्रतिनिधि-सभा द्वारा चलाए गए कुशासन के मुकदमों का विचार करने के लिए राजा सिनेट को अदालत का काम भी सौंप सकता है। इंग्लैंड की तरह न्याय-शासन से संबंध रखनेवाले मसविदे पहले सिनेट में पेश किए जाते हैं। घन से संबंध रखनेवाले मसविदे और आम तौर पर दूसरे मतले प्रतिनिधि सभा में पेश होते हैं। जरूरी मतलों को व्यवस्थापक-सभा के सामने अधिकतर प्रधान मंत्री या और दूसरे मंत्री या उपमंत्री पेश करते हैं। मगर साधारण सदस्य

भी बड़ी आजादी से बहुत-से मसले व्यवस्थापक-सभा में पेश करते हैं। इंग्लैंड की तरह साधारण सदस्यों पर दलबंदी का अंकुश इतना नहीं रहता है कि वे अपने नेताओं की इच्छा के बिना कोई प्रश्न न उठावें<sup>१</sup> साधारण सदस्यों को अपने मसविदे पेश करने के लिए सिनेट में सदस्यों के दू मत और प्रतिनिधि सभा में नौ युफिसी में से तीन युफिसी की राय मिल जाने की जरूरत होती है।

## ५—राजनैतिक दलबंदी

यूरोप के लगभग सभी देशों में राजसत्ता और धर्म सत्ता में जनता पर अधिकार के लिए झगड़े हुए हैं। मगर इस सचच में इटली की-सी समस्या का किसी दूसरे देश को सामना नहीं करना पड़ा है। इटली देश में ईसाइयों के कैथोलिक-धर्म के धर्म-गुरु पोप की सत्ता बहुत दिनों से चली आती थी। पोप धार्मिक मामलों में ही अपना अधिकार नहीं दिखाता था, बल्कि राजनैतिक मामलों में भी दखल देता था; क्योंकि अन्य राजाओं की तरह वह रोम के आस-पास की रियासतों पर राज्य भी करता था। एक प्रकार से पोप का इटली में वही स्थान था, जो टर्की में सुल्तान का। टर्की का सुल्तान टर्की का राजा होने के साथ-साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा भी होता था। कमालपाशा ने खलीफा को टर्की से निकाल कर टर्की की राजनैतिक और खिलाफत की उलफन हमेशा के लिए सुलमा दी उसी प्रकार जैसा हम देख चुके हैं, विक्टर इमेनुअल दूसरे ने सन् १८७० ई० में अपनी मेनाएँ भेज कर पोप की रियासतों पर कब्जा जमा कर इटली को एक राष्ट्र और रोम को उस राष्ट्र की राजधानी बना दिया। उस ने पोप को इटली से न निकाल कर उस को अपनी धर्म-नादी पर बैठा रहने दिया क्योंकि देश-भक्तों की इच्छा पोप को मिलाए रखने की थी। सन् १८७१ ई० में इटली राष्ट्र की व्यवस्थापक-सभा ने एक कानून पास कर के पोप को इटली के राजा के समान, महान और पवित्र स्वीकार किया तथा उस को वेदीकन और लेटरन महलों और उस के आस पास की इमारतों, अजायबघरों, पुस्तकालयों, बाग-बगीचों, जमीन और केस्टल गेंडोल्फो गाँव का सदा के लिए राजा माना। पोप की इस जागीर को हर प्रकार के करों और सार्वजनिक उपयोग से बरी माना गया और राष्ट्र के किसी अधिकारी को अधिकारों की हैमियत से पोप की इस जागीर में बिना पोप की इजाजत पौंच रखने का अधिकार नहीं था। पोप की रियासतों के राष्ट्र में मिल जाने से पोप को जो माली नुकसान हुआ उस के मुआवजे में पोप के लिए राष्ट्रीय खजाने से ३२,२५,००० लाइर सालाना की किश्त तय कर दी गई। पोप के धार्मिक कामों में सरकार या सरकार के किसी अधिकारी को दस्तदाजी करने का हक नहीं माना गया। पोप को अपना अलग डाक और तारघर कायम करने और अपनी मोहर लगा कर इटली के राष्ट्रीय डाकखानों के द्वारा खत भेजने या दूसरे राष्ट्रों के राजदूतों की तरह अपने दूतों को इधर-उधर खबर ले कर भेजने का भी अधिकार

<sup>१</sup> यह सब बातें मुसोलिनी के समय के पहले के लिए ही ठीक थी। धप तो पूरा फ़ेसिस्ट दल का राज्य है और जो मसले मुसोलिनी और उस का दल पसंद करता है वही पेश होते हैं।

माना गया। पोप और उस के पादरियों को धार्मिक मामलों में पूरी स्वतंत्रता दी गई और उस में राजसत्ता ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार अपने पास नहीं रखा। मगर साथ ही साथ राजसत्ता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार पोप से भी हमेशा के लिए छीन लिया गया।

यह कानून अभी तक कायम है। आजकल के किसी भी राजनैतिक नेता की नज़र से यह काफी उदार फ़ैसला था। मगर पोप ने इस प्रबंध को हृदय से स्वीकार नहीं किया। उस को यह बात बहुत खली कि उस की रियासतें और उस के राजनैतिक अधिकार उस से छीन लिये गए। वह इटली राष्ट्र को अपना शत्रु समझने लगा और उस ने शत्रु के हाथ से दान लेना पसंद नही किया। उस के आशा थी कि पोपलीला में विश्वास रखने वाले राष्ट्रों की सहायता से वह अपनी रियासतें फिर प्राप्त कर लेगा। अस्तु उन ने बेदीकन के महल में अपने आप को कैदी मान लिया और अपनी जमीन के बाहर इटली के राजा की जमीन पर क़दम न रखने की क़सम-खी खा ली। फ़्रांस इत्यादि बहुत-से राष्ट्रों से सहायता माँगने पर भी जब बहुत दिनांतर उसे कोई सहायता न मिली तो उस ने कुंभला कर इटली की राजनीति में अपने धार्मिक प्रभाव के बल पर रोड़े अटकाने का निश्चय लिया और सन् १८८३ ई० में पोप ने एक फतवा निकाला कि, कैथोलिक पथ में विश्वास रखनेवालों को इटली के चुनावों में मत डालना और इटली सरकार के अधिकारी बनना अनुचित है। फिर बारह बरस के बाद एक दूसरा इसी प्रकार का फतवा निकाल कर इटली की राजनीति में भाग लेना 'अनुचित' के स्थान में 'हराम' कर दिया गया। मगर इस फतवे का असर उल्टा हुआ। इटली में कैथोलिक पथ के लोगों की संख्या अधिक थी। मगर उन में काफी देशभक्ति और राष्ट्रीयता आ गई थी लोगों ने पोप के इन फतवों की कुछ परवाह नहीं की। हाँ, थोड़े-से भले आदमी राजनीति से ज़रूर अलग हो गए और उन की भलाई की सहायता इटली की राजनीति को न मिलने से सरकार कुछ कमजोर ज़रूर हुई। मगर धार्मिक सत्ता ने देशभक्ति का विरोध कर के अपना बल बहुत घटा लिया। इटली की व्यवस्थापक सभा ने पोप के विषय में जो कानून पास किया था उस पर, पोप के स्वीकार न करने पर भी, इटली की सरकार अपनी तरफ से धमक करती रही। अब धर्मसत्ता राजसत्ता की इतनी बहर निरोधी इटली में नहीं रही है। मगर आज तक इटली के खज़ाने से पोप एक पैसा नहीं लेता है और न वह इटली राज्य की ज़मीन पर क़दम रखता है। सन् १९२० ई० में पोप ने एक फतवा निकाल कर 'कैथोलिक राजाओं को इटली के राजा से रोम में बैठ करने की मनाई का फतवा' रद्द कर दिया था। मगर उसी फतवे में उस ने इस बात की ओर भी ध्यान खींचा था कि युद्ध खतम हो जाने के बाद पुराने अधिकार फिर उस को वापस मिल जाने चाहिए।

राजसत्ता और धर्मसत्ता के इस झगड़े, इटली के लोगों की राजनैतिक नातुरुरेकारी और क़प मड़कता तथा हमारे देशवासियों की भी उन की 'तेरह वनौजिया और चौदह चूल्हे' वाली अमागी आदत के मारे इटली में बहुत से छोटे-छोटे राजनैतिक दल बन गए। उन के कार्यक्रम बड़ी जल्दी जल्दी बदलते रहते थे। इटली के एक राष्ट्र बन जाने



के बाद सन् १८७० ई० से १८७६ ई० तक 'अनुदार' कहलानेवाले एक राजनैतिक गुट के हाथ में इटली सरकार की शगडोर रही। यह लोग प्रजा-सत्ता में बहुत विश्वास रखनेवाले नहीं थे। इस का कारण शायद यह था कि इटली के अधिकतर लोग उस समय तक अपढ़ और अज्ञान थे। इस के बाद बीस बरस तक प्रजासत्ता में विश्वास रखनेवालों के हाथ में सरकार की लगाम आई। सन् १८८२ ई० में एक 'सुनाव कानून' पास कर के मतदारों की संख्या बढ़ा दी गई। मंत्रि-मंडल बहुत-से गुटों की सहायता से काम चलाते थे। कोई दल संगठित सर्वदेशीय राजनैतिक दल नहीं था। मगर इस समय के सारे मंत्रि-मंडलों का 'प्रजासत्ता का जोर बढ़ाने' और 'अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिम्मत से काम करने' की तरफ रुकान था। सन् १८८६ ई० से पिछली यूरोप की लड़ाई शुरू होने तक इटली के राजनैतिक अखाड़े में इतने दल आए और गए कि बस एक दंगल की-सी धूम मची रहती थी।

इटली में प्रारंभ ही से पों में अंध-विश्वास रखनेवालों के राजनीति से अलग हो जाने के कारण कोई एक बड़ा और संगठित दक्षिणायनी राजनैतिक दल नहीं बना और इसी लिए उन का विरोध करने के लिए कोई एक बड़ा और संगठित उदार दल नहीं बना। राजनैतिक मामलों में हिस्सा लेनेवाले सभी राजनैतिक मामलों में कम या ज्यादा उदार तथियत के लोग होते थे। कम या ज्यादा उदार तथियत की बुनियाद पर ही दल बनते और बिगड़ते रहते थे। मगर इस प्रकार के दलों को राजनैतिक भाषा में दल न कह कर भुंड, टोलियाँ या गुट ही करना उचित होगा, क्योंकि वे अधिकतर व्यक्तिगत हितों या विचारों पर ही निर्धारित रहते थे। एक टोली को छोड़ कर लोग दूसरे गुट में ज़रा-जरा सी बात पर जा मिलते थे। व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों का अधिकतर स्थानिक बातों पर ध्यान रहता था। पिछली लड़ाई शुरू होने तक या यों कहिए कि बालकन युद्ध तक इटली राष्ट्र को किसी ऐसे जीवन-मरुत के प्रश्न का सामना नहीं करना पड़ा जिस के लिए लोग स्थानिक बातों को भूल कर राष्ट्र-हित की बड़ी बातों पर विचार करने लगते हैं, और जिन विचारों की बुनियाद पर ही राष्ट्रीय राजनैतिक दल बनते हैं। दूसरे इटली में लोगों की आदत विचारों के बजाय किसी तेजस्वी नेता का पल्ला पकड़ कर चलने की भी बहुत है। सन् १८७०-१८९४ ई० के आधे काल तक तो हमेशा इटली के प्रख्यात नेता, वेमेसिस, क्रिसी और जियोलिटी इन तीन में से ही कोई न कोई एक प्रधानमंत्री बनता था। जियोलिटी में बहुत गुण नहीं थे, वह गरम विचारों का प्रजा सत्तावादी नेता माना जाता था; मगर बक्त पड़ने पर उस ने अनुदार से अनुदार काम तक किए। फिर भी उस की इटली में सन् १८९४ ई० में पूजा-सी होती थी।

**समाजवादी दल और कैथोलिक दल**—लड़ाई से पूर्व, कुछ काल से, इटली में राष्ट्रीय दल भी बनने लगे थे। पुराने प्रजातंत्रवादी, गरम दल और समाजवादी विचार वालों के मेल से एक काफी बड़ा 'समाजवादी दल' बन गया था। प्रजातंत्रवादियों ने पिछले समय में इटली की बड़ी सेवा की थी। मगर बाद में न तो उन का संगठन ही रहा और न अधिक संख्या ही। प्रजातंत्र में विश्वास रखनेवाले लोग अधिकतर समाजवादियों

में मिलते जाते थे। राज घटना देश भर में सर्वप्रिय था क्योंकि वह प्रजासत्ता के रास्ते में कमी कोई श्रद्धा देने नहीं डालता था, और राजकार्य प्रजासत्ता के सिद्धांतों पर चलता था। अस्तु, लोग प्रजातन्त्र की कोई खास जरूरत नहीं समझते थे। 'गरम दल' प्रजातन्त्रवादियों से अधिक जोरदार था। यह लोग राजतन्त्रवादी थे मगर पुराने दलों की सरकार पर से उन का निर्यास उठ गया था। इस दल में अधिकतर कारीगर और मध्यम श्रेणी के निचले दर्जे के लोग थे जो समाजवाद से घबराने थे। समाजवाद का गीज इटली में फ्रांस की सन् १८७१ ई० की पद्धतिलिखित 'कम्यून' के लोगों ने आ कर बोया था। पहले तो समाजवादी अधिकतर 'अराजकतावादी' थे। मगर पीछे से सन् १८८२ के चुनाव का कानून बन जाने के बाद वे वैध उपायों से समाजवाद कायम करने के पक्षपाती हो गए। सन् १८८५ में मिलन नगर में धर्मजीवियों की एक कांग्रेस की स्थापना की गई जिस के बहुत जल्द चालीस हजार सदस्य हो गए। मगर इस कांग्रेस पर अराजकतावादियों ने कब्जा कर लिया था और एक ही वर्ष में वह टूटा दी गई। सन् १८८१ ई० में एक समाजवादी पत्र मिलन से निकाला गया और इसी साल मिलन में पहली समाजवादी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिस में डेढ़ सौ धर्मजीवियों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन् १८८७ ई० में तिनोआ की कांग्रेस में अराजकतावादियों को इस कांग्रेस से निकाल दिया गया और तब से इटली के समाजवादी भी फ्रांस इत्यादि देशों के समाजवादियों की तरह हो गए। बाद में क्रिस्ती और उस के बाद की सरकारों के अत्याचार का सामना करने के लिए 'प्रजातन्त्रवादी', और 'गरम दल' एक 'समाजवादी' दल में मिल गए और "वालिंग स्त्री पुरुषों को मताधिकार, प्रतिनिधि सभा और म्यूनिसिपैलिटियों के सदस्यों को वेतन, उदार दबनीति, स्थायी सेना के स्थान में जल सेना, कारखानों के लिए अच्छे कानून, रीमारी के लिए अनिवार्य रीमा,<sup>१</sup> किसान और जमींदार-सम्पत्ती कानूनों का संशोधन, रेलों और रानों पर राष्ट्रीय कब्जा, अनिवार्य शिक्षा, राने की चीजों पर से कर हटाना, आमदनी पर बढ़ता हुआ कर, और वारिसी जागीरे मिलने पर कर", इत्यादि मांगों को इस नए दल ने अपना लक्षित कार्यक्रम बनाया।

पुराने दलों से लोग डकता गए थे। समाजवादी दल की मांगें और कार्यक्रम अमली था और दल के नेता भी काबिल थे अस्तु उड़ी जल्दी ही दल की ताकत बहुत बढ़ गई। सन् १८८५ ई० में जिस दल को सिर्फ ३५,००० मत मिले थे उसी को १८८५ ई० में १,०८,००० मत और सन् १९०४ ई० में ३,०१,००० मत मिले और इस दल के ४४ सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए। इस समय तक इस दल में इटली के उड़े बड़े मशहूर लोग आ मिले थे। मगर और देशों की तरफ समाजवादियों के गरम और नरम पक्षों में यहाँ भी भगडा चलता रहता था। लड़ाई शुरू होने के समय गरम प्रांतिकारी समाजवादियों का समाजवादी दल में जोर था। अस्तु, सुधारी समाजवादी<sup>२</sup> इस दल से अलग होकर एक नए दल में जा मिले थे।

<sup>१</sup> कपड़मारी इरपोरेस अगेंस्ट सिकनेस।

<sup>२</sup> रिफार्मिस्ट सोशलिस्ट्स।

समाजवादियों की ताकत बढ़ती देख कर पुरातन प्रेमी धार्मिक लोग भी घबराने लगे थे। सन् १९०४ ई० के चुनाव में बहुत से उन कैथोलिक लोगों तक ने सरकार का साथ दिया जो अभी तक पोप की इच्छानुसार राजनीति से अलग रहते थे, क्योंकि उन की राय में सरकार का साथ दे कर, पुरातन समाज-व्यवस्था की रक्षा करना धार्मिक कर्तव्य था। पोप ने भी उन लोगों की यह बात मान ली थी और पोप की तरफ से आगे के लिए एक फतवा भी निकाल दिया गया था कि कैथोलिक लोगों को पुरानी समाज-व्यवस्था की रक्षा करने के लिए सगठित रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए।<sup>१</sup> इस के बाद से कैथोलिक राजनीति में खुल कर भाग लेने लगे और सन् १९१३ ई० के चुनाव में उन के दल के 'प्रतिनिधि-सभा' में ३५ सदस्य चुन कर आए। पुरानी समाज-व्यवस्था कायम रखने के साथ ही इस दल के कार्य क्रम में कारखानों की दशा सुधारने के लिए कानून, मजदूरों का बीमा, सहकारी स्थापण और जमीन के अधिक बाँट की मांगें भी शामिल थी। धार्मिक लोगों के सगठित रूप से राजनीति में घुसने से धर्मसत्ता के विरोधियों के दल ने भी जोर पकड़ा और प्रजातन्त्रवादी, गरम दल और समाजवादियों का आपस का मेल और भी दृढ़ हो गया। धार्मिक लोग जिस चीज़ को कमज़ोर करने आए थे उन के आगे से उल्टी यह जोरदार बनी।

लड़ाई के ज़माने में समाजवादी लड़ाई के विरोधी रहे, और कैथोलिक दल के लोग इटली के युद्ध में शरीक होने के पक्षपाती थे। सन् १९१९ में सधि हो जाने के बाद कैथोलिक दल ने अपना नाम बदल कर 'लोक-दल'<sup>२</sup> रख लिया और एक नए कार्य-क्रम का एलान किया, जिस में 'न्याय और स्वतन्त्रता के सिद्धांतों के लिए लड़ने' और 'युद्ध की बीमारी से लोगों को रक्षाने और सामाजिक न्याय को ज़िंदा चीज बनाने' के लिए लोगों को मिल कर एक हो जाने के लिए बुलावा दिया गया। इटली की राजनीति में यह दल शासन का अधिकार विभाजन,<sup>३</sup> कुटुंब, वर्षा, बम्बून, व्यक्तिगत मर्यादा और स्वतन्त्रता की रक्षा और इज्जत, अनुपात निर्वाचन, बिरादों के लिए मताधिकार, निर्वाचित सिनेट, कानून और न्याय शासन का सुधार इत्यादि बहुत सी बातें चाहता था। खास ध्यान देने की बात यह है कि धर्मसत्ता का राज फिर से स्थापित करने की मांग इस दल की माँगों में कहीं नहीं थी। धार्मिक स्वतन्त्रता की सिर्फ माँग की गई थी और राष्ट्र को धर्म का विरोधी न मान कर सिर्फ उन नास्तिक लोगों को नास्तिक धर्म का विरोधी बताया गया था, जो हमेशा धार्मिक लोगों पर अत्याचार करने के पक्षपाती रहते थे। सन् १९१९ के चुनाव में इस दल के १०१ सदस्य प्रतिनिधि-सभा में चुन कर आए और पोप की सहायता और इस दल के योग्य नेताओं की योग्यता के कारण, जिन्होंने समकालीन सभी ज़रूरी बातों के अपने प्रोग्राम में मिला लिया था इस दल की ताकत शीघ्र ही बहुत बढ़ गई। यह दल सरकार का साथी और समाजवादी दल के मुकामिले में एक प्रकार का सुसगठित अनुदार दल था। मगर युद्ध की थकावट का लड़ाई के विरोधी समाजवादियों ने भी इस चुनाव में खूब फायदा उठाया। प्रतिनिधि-सभा में ४० सदस्यों की जगह पर अब उन के भी

<sup>१</sup> पापुलर पार्टी। <sup>२</sup> डिमेंटलाज़ेइशन।

में मिलते जाते थे। राज घराना देश भर में सर्वप्रिय था क्योंकि वह प्रजासत्ता के रास्ते में कभी कोई अड़चने नहीं डालता था, और राजकार्य प्रजासत्ता के सिद्धांतों पर चलता था। अस्तु, लोग प्रजातंत्र की कोई खास जरूरत नहीं समझते थे। 'गरम दल' प्रजातंत्रवादियों से अधिक जोरदार था। यह लोग राजतंत्रवादी थे मगर पुराने दलों की सरकार पर से उन का विश्वास उठ गया था। इस दल में अधिकतर कारीगर और मध्यम श्रेणी के निचले दर्जे के लोग थे जो समाजवाद से घबराने थे। समाजवाद का बीज इटली में फ्रांस की सन् १८७१ ई० की पद्धतिलि 'कम्यून' के लोगों ने ग्राह्य कर लिया था। पहले तो समाजवादी अधिभूत 'अराजकतावादी' थे। मगर पीछे से सन् १८८२ के चुनाव का कानून उन जाने के बाद वे वैध उपायों से समाजवाद कायम करने के पक्षपाती हो गए। सन् १८८५ में मिलन नगर में भ्रमजीवियों की एक कांग्रेस की स्थापना की गई जिस के बहुत जल्द चालीस हजार सदस्य हो गए। मगर इस कांग्रेस पर अराजकतावादियों ने कब्जा कर लिया था और एक ही वर्ष में यह दबा दी गई। सन् १८९१ ई० में एक समाजवादी पत्र मिलन से निकाला गया और इसी साल मिलन में पहली समाजवादी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिस में डेढ़ सौ भ्रमजीवियों की सत्याग्रहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन् १८९२ ई० में जिनेवा की कांग्रेस में अराजकतावादियों को इस कांग्रेस से निकाल दिया गया और तब से इटली के समाजवादी भी फ्रांस इत्यादि देशों के समाजवादियों की तरह हो गए। बाद में किसी और उस के बाद की सरकारों के अत्याचार का सामना करने के लिए 'प्रजातंत्रवादी', और 'गरम दल' एक 'समाजवादी' दल में मिल गए और "गलिसा स्त्री पुरुषों को मताधिकार, प्रतिनिधि सभा और म्युनिसिपैलिटियों के सदस्यों को वेतन, उदार दंडनीति, स्थायी सेना के स्थान में जल सेना, कारखानों के लिए अच्छे कानून, बीमारी के लिए अनिवार्य बीमा," किसान और जमींदार-सबधी कानूनों का संशोधन, रेलों और खानों पर राष्ट्रीय कब्जा, अनिवार्य शिक्षा, राने की चीजों पर से कर हटाना, आमदनी पर बढ़ता हुआ कर, और धारिणी जागीरे मिलने पर कर", इत्यादि मांगों को इस नए दल ने अपना लक्षित कार्यक्रम बनाया।

पुराने दलों से लोग उकता गए थे। समाजवादी दल की मांगें और कार्यक्रम अम्लीय था और दल के नेता भी कागिल थे अस्तु उड़ी जल्दी ही दल की ताकत बहुत बढ़ गई। सन् १८९५ ई० में जिस दल को सिर्फ ३५,००० मत मिले थे उसी को १८९५ ई० में १,०८,००० मत और सन् १९०४ ई० में ३,०१,००० मत मिले और इस दल के ४४ सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए। इस समय तक इस दल में इटली के उड़े-बड़े मशहूर लोग आ मिले थे। मगर और देशों की तरह समाजवादियों के गरम और नरम पक्षों में यहाँ भी भगड़ा चलता रहता था। लडाई शुरू होने के समय गरम नातिकारी समाजवादियों का समाजवादी दल में जोर था। अस्तु, सुधारी समाजवादी<sup>२</sup> इस दल से अलग होकर एक नए दल में जा मिले थे।

<sup>१</sup> कपलमरी इंडोरेस अगोस्ट सिकनेस।

<sup>२</sup> रिफार्मिस्ट सोशलिस्ट्स।

समाजवादियों की ताकत बढ़ती देख कर पुरातन प्रेमी धार्मिक लोग भी घबराने लगे थे। सन् १९०४ ई० के चुनाव में बहुत से उन कैथोलिक लोगों तक ने सरकार का साथ दिया जो अभी तक पोप की इच्छानुसार राजनीति से अलग रहते थे, क्योंकि उन की राय में सरकार का साथ दे कर, पुरातन समाज-व्यवस्था की रक्षा करना धार्मिक कर्तव्य था। पोप ने भी उन लोगों की यह बात मान ली थी और पोप की तरफ से आगे के लिए एक फतवा भी निकाल दिया गया था कि कैथोलिक लोगों को पुरानी समाज-व्यवस्था की रक्षा करने के लिए संगठित रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए।<sup>१</sup> इस के बाद से कैथोलिक राजनीति में खुल कर भाग लेने लगे और सन् १९१३ ई० के चुनाव में उन के दल के 'प्रतिनिधि-सभा' में ३५ सदस्य चुन कर आए। पुरानी समाज-व्यवस्था कायम रखने के साथ ही इस दल के कार्य क्रम में कारखानों की दशा सुधारने के लिए कानून, मजदूरों का बीमा, सहकारी संस्थाएँ और ज़मीन के अधिक बाँट की मांगें भी शामिल थीं। धार्मिक लोगों के संगठित रूप से राजनीति में घुसने से धर्मसत्ता के विरोधियों के दल ने भी जोर पकड़ा और प्रजातन्त्रवादी, गरम दल और समाजवादियों का आपस का मेल और भी दृढ़ हो गया। धार्मिक लोग जिस नीज को कमज़ोर करने आए थे उन के आने से उल्टी यह जोरदार बनी।

लड़ाई के ज़माने में समाजवादी लड़ाई के विरोधी रहे, और कैथोलिक दल के लोग इटली के युद्ध में शरीक होने के पक्षपाती थे। सन् १९१९ में सधि हो जाने के बाद कैथोलिक दल ने अपना नाम बदल कर 'लोक-दल'<sup>२</sup> रख लिया और एक नए कार्यक्रम का एलान किया, जिस में 'न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के लिए लड़ने' और 'युद्ध की बीमारी से लोगों को बचाने और सामाजिक न्याय के ज़िंदा चीज बनाने' के लिए लोगों को मिल कर एक हो जाने के लिए बुलावा दिया गया। इटली की राजनीति में यह दल शासन का अधिकार विभाजन,<sup>३</sup> कुटुंब, धर्म, कम्पून, व्यक्तिगत मर्यादा और स्वतंत्रता की रक्षा और इज्जत, अनुपात निर्वाचन, स्त्रियों के लिए मताधिकार, निर्वाचित सिनेट, कानून और न्याय शासन का सुधार इत्यादि बहुत सी बातें चाहता था। खास ध्यान देने की बात यह है कि धर्मसत्ता का राज फिर से स्थापित करने की माँग इस दल की माँगों में कहीं नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता की सिर्फ माँग की गई थी और राष्ट्र को धर्म का विरोधी न मान कर सिर्फ उन नास्तिक लोगों को नास्तिक धर्म का विरोधी बताया गया था, जो हमेशा धार्मिक लोगों पर अत्याचार करने के पक्षपाती रहते थे। सन् १९१९ के चुनाव में इस दल के १०१ सदस्य प्रतिनिधि-सभा में चुन कर आए और पोप की सहायता और इस दल के योग्य नेताओं की योग्यता के कारण, जिन्हा ने समकालीन सभी ज़रूरी बातों को अपने प्रोग्राम में मिला लिया था इस दल की ताकत शीघ्र ही बहुत बढ़ गई। यह दल सरकार का साथी और समाजवादी दल के मुकामिले में एक प्रकार का सुसंगठित अनुदार दल था। मगर युद्ध की थकावट का लड़ाई के विरोधी समाजवादियों ने भी इस चुनाव में खूब फायदा उठाया। प्रतिनिधि-सभा में ४० सदस्यों की जगह पर अब उन के भी

<sup>१</sup> पापुलर पार्टी। <sup>२</sup> डिसेंटलाज़ेशन।

१९६ सदस्य चुन गए। अस्तु सत्र में उद्घाटन प्रतिनिधि-सभा में 'समाजवादी दल' था।

**फेसिस्ट दल**—इटली सदिया से घरेलू समस्याओं के सुलझाने में लगा था। युनिया में आगे बढ़ कर कोई साम्य या काम करने का उसे मौका नहीं मिला था। सन् १९११ ई० में टर्का में युद्ध छिड़ने पर इटली के नौजवानों की आँखें उसी तरह खुलीं, जिस प्रकार रूस और जापान के युद्ध ने जापान के लोगों की आँखें खोल दी थीं। समाजवादियों ने अपने मित्रों के अनुसार टर्की से युद्ध का विरोध किया। इन समाजवादियों में मुसोलिनी नाम का एक इटेलियन नौजवान भी था, जिसने सरकार की लड़ाई की नीति का विरोध करने के लिए एक ग्राम हड़ताल करा दी जिस के कारण उसे कई महीने जेल की हवा खानी पड़ी। बाद में साम्राज्यशाही का विरोधी रहते हुए भी यही मुसोलिनी देश भक्ति का उपासक बना। जब सन् १९१४ ई० की यूरोप की लड़ाई छिड़ी, तब मुसोलिनी ने इटली के हित में इटली को आस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हो जाने की सलाह दी। उस का कहना था कि हाथ पर हाथ रख कर बैठने और क्रांति की रातें करनेवाले कभी भयभीतियों की क्रांति न कर सकेंगे। ग्राम लोगों को युद्ध में जा कर धियारों का इस्तेमाल और मरना मारना सीखना चाहिए। जो आज युद्ध में लड़ेंगे, वही कल क्रांति कर सकेंगे। समाजवादिया ने उस को अपने दल से निकाल दिया। मगर मुसोलिनी ने अपनी कोशिश जारी रखी। बहुत से उत्साही नौजवान उस से आ मिले। जगह जगह पर देश भर में देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार देश भक्तों के दल खड़े हो गए और उन्हें ने लड़ाई के मैदान में जा कर गोलियाँ खाईं और गोलियाँ चलाईं। देश भक्तों ने अपने इन दलों और टोलियाँ को 'फेरी' का नाम दिया था, जिस का अर्थ 'क्रांतिकारी टोली' है। सन् १९१५ से १९१७ ई० तक मुसोलिनी ने युद्ध क्षेत्र की राईयों में युद्ध किया। बाद में घायल हो कर जब वह लड़ाई के नाफाबिल ठहरा दिया गया, तब वह लौट कर मिलन नगर में आया और एक अखबार का संपादक बन कर युद्ध के पक्ष में उठे जोरा से ध्वजार लेख लिखता रहा। इटली की फौज ने जब आस्ट्रिया की फौजों को हराया तो मुसोलिनी ने ही पहले-पहल विजेता इटेलियन सेनापति की तारीफ के नारे बुलंद कर के इटली की युद्ध में जीत की दुहाई दी। लड़ाई के जमाने में 'फेरी' के सदस्यों ने सैनिक संगठन और कड़ी सैनिक व्यवस्था और साम्राज्यशाही के पाठ सीखे। इटली की व्यवस्थापक सभा एक-मत से लड़ाई के पक्ष में नहीं थी। अस्तु उधर तो इटली के सिपाही गा-बजा कर युद्ध-क्षेत्र में गोलियाँ खाने का भेज दिए जाते थे और इधर व्यवस्थापक सभा में 'ग्राम लोगों की स्वतंत्रता,' 'बोलने की आजादी,' 'मजदूरों के हक' इत्यादि विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएँ चलती थीं और राजनीतिज्ञों के मंत्रि मंडला की गद्दियों पर बैठने के दाँव-पेंच होते थे। इस आचरण रीतिता को देख कर मुसोलिनी का दिल जलता था और उस का और उस के दलवालों का व्यवस्थापक सभा, व्यवस्थापकी राज और प्रजासत्तात्मक कहलानेवाली सभी समस्याओं की तरफ से दिल हटता जाता था। युद्ध छिड़ने से पहले व्यवस्थापक-सभा की युद्ध में शामिल होने या न होने की लंबी चर्चाओं पर लिपटे हुए मुसोलिनी ने ऊपर कर अपने पत्र 'पोपोलो दे इतालिया' के अग्रलेख में लिखा था, 'भाइ मे जाय यह व्यवस्थापक सभा।

जिन प्रजा के प्रतिनिधियों के आगे बढ़ कर प्रजा का उत्साह और बल बढ़ाना था, वह दीली-दीली बातें कर के प्रजा के उत्साह पर पानी डाल रहे हैं, प्रजा को निर्जीव बना रहे हैं। इन प्रतिनिधियों को गोली से मार देना चाहिए और निर्जीव मंत्रियों को जेल में डाल देना चाहिए। व्यवस्था ठीक करने के लिए ऊपर से शुष्कता करने की जरूरत है। इटली की पार्लियमेंट वह जहरीली कुड़िया है, जो राष्ट्र के सारे खून को खराब कर रही है। इस को काट कर फेंक देना चाहिए।' फिर सन् १९१८ ई० में रण-क्षेत्र से लौट कर मुसोलिनी ने व्यवस्थापक-सभा की चर्चाओं के विषय में लिखा—'हम लड़ाई में विश्वास रखनेवालों ने बड़ी शलवी की, जो दिलमिल यक्रीनवालों के हाथ में सरकार की लगान रहने दी। यह लोग सैकड़ों आदिमियों को युद्ध में मरने के लिए भेज कर वहाँ बैठे-बैठे राजनैतिक स्वतंत्रता पर व्याख्यान भ्लाते हैं और तह-तह की माँगें पेश करते तथा ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन से लड़ाई में हार तक हो सकती है। शायद वे हमारे देश को और अच्छी तरह हलाक करने और दिल खोल कर हमारा खून बहाने की स्वतंत्रता चाहते हैं।' उधर सैनिक जिन को मरने के लिए भेज दिया जाता है—जिन्हें जरा भी चूँचों करने की स्वतंत्रता नहीं है और अगर करें तो उन्हें गोली से मार दिया जाता है—खाइयों में पूछते हैं कि हम क्यों मरें? और इधर उन को वहाँ भेजनेवाले अभी तक रोम में बैठे वही चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध में भाग लिया जाय या नहीं? इस अभागी, अपराधी, दिल की बुद्धी शाखियों की भीड़ को दबो देने की जरूरत है।' साम्राज्यशाही की कलक मुसोलिनी में पहले-पहल देखने को तब मिली जब यूनान ने युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ मिलने के लिए कदम बढ़ाया। मुसोलिनी यूनान की इस हरकत पर बड़ा नाराज़ हुआ क्योंकि युद्ध के बाद सुलह होने पर वह यूनान में इटली का दखल चाहता था। मुसोलिनी ने खुल्लम-खुल्ला एलान किया कि इटली की वाढ़ के लिए इटेलियन साम्राज्य की जरूरत है, और इटली को एशिया माइनर में साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। मगर जब सुलह में इटली की इन माँगों पर ध्यान नहीं दिया गया तब इटली के सन्नयान देखनेवाले लोगों को बड़ी निराशा हुई।

लड़ाई के सौतेले-देह-भक्तों की टोलियों की इटली भर में जगह-जगह पर 'फ़ेसियो' फ़ायम हो गई थीं। लड़ाई से लौटे हुए अधिकतर लोग बेकार फिरते थे, और उन को किसी प्रकार का काम मिलना असंभव था। चीज़ें महंगी थीं। चारों तरफ आर्थिक कष्ट के मारे दंगे-फिसाद होते थे। कई प्रांतों की सरकार समाजवादियों के हाथ में थी। क्रांतिकारी—समाजवादी असंतोष की ज़मीन तैयार देख कर लोगों को भड़काते फिरते थे। अस्तु हड़तालें भी चारों तरफ भरमार थीं। लड़ाई से लौटी हुई टोलियाँ अक्सर मार-काट कर डालती थीं। सरकार सब चुप चाप देखती थी। उस में इन सब उत्पातों को रोकने की शक्ति नहीं थी। 'फ़ेसियो' नाम की टोलियों के लोग जिस जगह जैसी जरूरत होती थी उस जगह वैसे ही काम अपने-अपने दकान के माफिक कर बैठते थे। कहीं जबरदस्ती हड़तालों तोड़ डालते थे तो कहीं मजदूरों की तरफ से लड़ बैठते थे। मिलन, ट्यूरिन और फ़ोर्सेस में इन टोलियों का खास तौर पर जोर था। बहुत-से नौजवान अपनी पढ़ाई-लिखाई और काम-

काज छोड़ कर अपने देश का मान बढ़ाने के उत्साह में लड़ाई में भाग लेने गए थे। उन में से बहुत-से सेना में अफसर रह चुके थे, और उन्हें आशा थी कि घर लौटने पर उन का वीरों की तरह स्वागत होगा और वे इज्जत के साथ देश के राष्ट्रीय जीवन में नेता बनेंगे। मगर मान और इज्जत के स्थान में जब उन्हें युद्ध-निरोधियों और निराश जनता के ताने और गालियाँ सुनने को मिलीं और उन को रोष्टियों के लाले भी पड़ने लगे तब उन्होंने अपना संगठन कर के अपनी इज्जत के लिए अपने हाथ कँचे करने का निश्चय किया। मुसोलिनी ने २१ मार्च सन् १९१९ के दिन मिलन में ४५ खास-खास लोगों की एक सभा बुला कर 'फेसियो' का एक संगठन और कार्य-क्रम बनाया, जिस से देश भर में बिखरे हुए फ़ैसियों की टोलियों का एक निश्चित मार्ग और राष्ट्रीय हेतुव्य प्राप्त हो गई। इस ४५ आदमियों के संगठन का नाम मुसोलिनी ने 'लड़ाऊ टोली' रक्खा जिस का उद्देश बोलशे-विजय के मुकाबले में सिकुँ पुरानी समाज-व्यवस्था को कायम रखना ही नहीं था क्योंकि मुसोलिनी के शब्दों में 'लड़ाऊ टोली' ने सिकुँ 'कायम रहने' के लिए जन्म नहीं लिया था बल्कि 'लड़ कर और आगे बढ़ कर', इटली देश में एक सच्चा जीवन पैदा करने के लिए जन्म लिया था। इस टोली का हाल के लिए युद्ध-मन 'क्रांतिकारी युद्ध के क्रांतिकारी फलों के लिए लड़ो' रक्खा गया क्योंकि मुसोलिनी यूरोपीय युद्ध को इटली के लिए क्रांतिकारी मानता था और उस से इटली के लिए जितना फायदा हो सके उठाना चाहता था। इस टोली का कार्य-क्रम भी किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर नहीं रचा गया। 'हाल के—काम का' कार्य-क्रम बना लिया गया क्योंकि मुसोलिनी की राय में यह टोली किन्हीं खास सिद्धांतों के प्रचार के लिए नहीं जन्मी थी। 'लड़ाऊ टोली' देश में केवल सुव्यवस्था और जीवन कायम करना चाहती थी और वह जिन उपायों से और जैने हो सके वैसे करना चाहती थी। अतः, उस के कार्य-क्रम में खास बातें यह रक्खी गईं :—

१. फियूम और सारे डेलमेथिया को इटली के लिए प्राप्त करना।
२. सब बालिग मर्द और औरतों के लिए मतधिकार।
३. सूची पद्धति से अनुपात निर्वाचन।
४. सेनाएँ भग कर देने के बाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय चुनाव।
५. प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवारों की उम्र ३२ वर्ष से बढ़ा कर २५ वर्ष।
६. प्रतिनिधियों का एक नेशनल ऐसेंबली बनाने के लिए चुनाव।
७. नेशनल ऐसेंबली की तीन वर्ष तक बैठक।
८. नेशनल ऐसेंबली का एक नई राज-व्यवस्था गढ़ना।
९. सिनेट को उड़ा देना।

१०. धंधेवालों का कानून बनाने के लिए 'आर्थिक समितियों' का चुनाव।

११. मजदूरों के लिए आठ घंटे की मजदूरी का कानून।

१२. जो मजदूरों की संस्थाएँ अपने उद्योगों का प्रबंध चलाने के योग्य हों उन के द्वारा उन का प्रबंध—खास तौर पर रेलों का—रेल के कर्मचारियों द्वारा प्रबंध।

१ फ़ैसियो दे कॉन्वैटिमेंटो।



१३. एक जल-सेना का संगठन ।

१४. गोला-बारूद के कारखानों पर सरकार का कब्ज़ा ।

१५. मिलकियत पर कड़ा कर ।

१६. कुछ गिरजों के माल पर सरकार का कब्ज़ा और पादरियों की कुछ रियायतों को मिटाना ।

१७. मौलसी जागीर मिलने पर कड़ा कर ।

१८. मुनाफ़ों में से ८१ सैकड़ा ले लेना ।

जिस दिन यह कार्य-क्रम बनाया गया था उसी दिन शाम को फ़ेसिज़्म के व्यवस्थानक-सम्मेलन में "पैदावार में सहकार; बैटाय में वर्ग-संग्राम" का सिद्धांत स्वीकार किया गया और तीन खास निम्न एलान किए गए ।

१. युद्ध के योदों और शहीदों को मान ।

२. लीग ऑफ़ नेशंस स्वीकार, साम्राज्यशाही का विरोध; क्रिपूम और डेल-मेरिया पर कब्ज़ा ।

३. इटली को युद्ध से दूर रखने की सलाह देने वाले सारे उम्मीदवारों का चुनाव में विरोध ।

मुसोलिनी का विचार इस समय शायद जर्मनी की तरह पैदावारी धंधों का एक राज्य कायम करना था । मगर मुसोलिनी के इस प्रोग्राम के लिए किसी ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया । जिन लड़ाई से लौटे हुए सैनिकों पर मुसोलिनी अपनी सफलता के लिए आशा रखता था उन्हें ने उस का साथ न दे कर उभाड़नेवाले समाजवादियों की 'लाल पल्टन' को पसंद किया । फ़ेसिस्ट लोगों को भी उस की बातें नहीं जचीं । इयियारबंद लोगों को ले कर सरकारी अफ़सरों का सामना करने के अपराध में मुसोलिनी और उस के कुछ खास साथियों को चुनाव के ज़माने में पकड़ कर २१ दिन के लिए जेल में भी डाल दिया गया । उस के उम्मीदवारों की बुरी तरह हार हुई और कुछ ही मास में उस के कार्यक्रम की किसी को याद तक नहीं रही । समाजवादी और बुद्धिमान राजनैतिक दलों के लोग मुसोलिनी के कार्यक्रम की सार पर मुँह चिड़ने और कूदकर लगाने लगे । मुसोलिनी के दिल को बड़ी चोट लगी । त्रियोलिटी फिर प्रधान मंत्री हुआ ।

मुसोलिनी का राजनैतिक कार्यक्रम नाकामयाब हुआ । मगर फ़ेसिस्ट टोलियों की प्रतिदिन मार-काट जारी रही । आए दिन ज़िगर मुनो उधर से फ़ेसिस्टों की बोलशेविकों से मुठभेड़ और मार-काट हो जाने के समाचार आते थे । फिर फ़ेसिस्टों की दूसरी नेशनल कांग्रेस मई सन् १९२० में मिली तो उस में एक बहुत छोटा-सा कार्यक्रम बनाया गया जिस में सिर्फ़ तीन बातें रक्खी गईं ।

१. लड़ाई का समर्थन ।

२. विजय का मान ।

३. ज़बानी और अमली राजनीतियों के समाजवाद का विरोध ।

इन तीनों बातों का एक ही अर्थ था, अर्थात् जिन मुनो राजनीतियों के हाथों में

इटली की लगाम थी उन के प्रति 'पृष्ठा और उन का विरोध'। मुसोलिनी और उस के साथियों को अपनी टोलियों की चारों तरफ मार-काट पसंद नहीं थी क्योंकि वे अच्छी तरह समझते थे कि उन का काम पूरा हो जाने पर फिर उन को कायू में रखना असंभव हो जायगा। अस्तु फेसिज्म को सिर्फ एक 'जीवन दायक राड़ाक आंदोलन' ही न रख कर वे उस को जल्दी से जल्दी एक मज़बूत राजनैतिक दल बनाने के प्रयत्न में लगे। मंत्री, उपमंत्री, प्रांतिक मंत्री चुने गए और संगठन करने के लिए चारों ओर देश में आदमी फैला दिए गए। इसी बीच में अप्रैल सन् १९२१ में त्रियोनिटी ने प्रतिनिधि-सभा को अपनी इच्छा के अनुसार न पा कर भंग कर दिया और फेसिस्ट और राष्ट्रीयता के पक्षपातियों से 'समाजवादी-दल' और 'जन-दल' के लोगों के विरुद्ध सरकार की सहायता करने की प्रार्थना की। राष्ट्रीय पक्षपातों ने इस मौके का फायदा उठाया। नव चुनाव में ३५ फेसिस्ट और करीब दस राष्ट्रीय पक्ष के स्वतंत्र सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुन कर आए गए। मगर सभा में दाखिल होने के कुछ ही दिन बाद मुसोलिनी ने उदारदल के नेता त्रियोनिटी से साफ कह दिया कि राष्ट्रीय पक्ष के भरोसे पर यह न रहे क्योंकि उदार दल की पूछ देश में कहीं नहीं है। उदार दल वालों को देश सहायता नहीं देगा और वे कुछ न कर पायेंगे। जब राजा व्यवस्थापक-सभा के खुलने पर व्याख्यान देने आया तो मुसोलिनी अपनी टोली के साथ सभा से उठ कर चला गया। बाद में अखबारों में एक लेख भेज कर उस ने अपने इस काम को समझाने के लिए एलान किया कि फेसिस्ट राजाशाही तंत्र को माननेवाले नहीं हैं। वे प्रजातंत्रवादी हैं। इस पर राष्ट्रीय पक्ष के सदस्य इस टोली से अलग हो गए क्योंकि वे राजतंत्रवादी थे। अस्तु मुसोलिनी अपनी एक मत की टोली का निर्द्वंद्व नेता बन कर प्रतिनिधि-सभा में बैठा। मगर मिलन के गुह्र को छोड़ कर आम फेसिस्ट राजाशाही के विरोधी नहीं थे और राजा पर हमले उन्हें बुरे लगते थे। मुसोलिनी के एलान का उस के दल में भी विरोध हुआ और मुसोलिनी ने ज़मीन अपने पावों के नीचे से रिसकती देख कर प्रजा-तंत्र का झिंक ही छोड़ दिया और कहने लगा कि फेसिस्ट न प्रजा तंत्रवादी हैं और न राज-तंत्र-वादी, वे तो देश का भला करना चाहते हैं। मुसोलिनी ने अपनी मार काट करने वाली टोलियों के समाजवादी दलों पर हमले रोकने और समाजवादियों से मेल करने का प्रयत्न भी करना चाहा। क्योंकि देश में बोलशेविक क्रांति होने का अब खतरा नहीं रहा था। समाजवादी लोग देश में काफी बदनाम और फेसिस्ट लोग प्रजा की नज़रों में काफी उठ चुके थे। जरूरत से अधिक मार-काट जारी रखने से फेसिस्ट दल के बदनाम हो जाने का भी डर था। मगर अधिकतर लड़ने वाली टोलियाँ देशभक्ति के विरोधी समाजवादियों से फौसला करने के बिल्कुल विरुद्ध थीं और वे 'समाजवाद की लाश तक जला देना चाहती थीं। अस्तु मुसोलिनी का समाजवादियों से समझौता फेसिस्टों ने स्वीकार नहीं किया। इस पर रौसी और मुसोलिनी ने फेसिस्ट दल के सामने अपने इस्तीफे रख दिए। मज़बूर हो कर दल ने समझौता मान लिया और नेताओं ने इस्तीफे लौटा लिए। फिर भी समाजवादियों पर टोलियों की मारकाट जारी रही। मुसोलिनी ने दल सुव्यवस्थित और संगठित करने पर बहुत जोर दिया। मुसोलिनी के ही आदमी दल के कर्ता-धर्ता चुने

गए। दल का सैनिक भाग अर्थात् फेसिस्ट 'जनदल' का संगठन ठीक किया गया। जनदल के रीनरिज और गीत निरुचय किए गए। पुरानी रोमन सैनिकों की चाल, रोमन सलाम और 'इया इया आ ला-ला' का नाद अव्यथार किया गया। बिल्कुल रोमन सेना के ढंग पर 'जनदल' का संगठन किया गया और उस का मुसोलिनी स्वयं नायक बना। बर्दा, रोमन सलाम, रोमन चाल, नाद और 'जनदल' के संगठन की नवीनता नौजवानों को बहुत भाई और कालिनों के बहुत से विद्यार्थी और दूसरे नौजवान जनदल में आ आ कर मिलने लगे। फौजी चाल चलने के सिवाय प्रारम्भ में जनदल का काम आमतौर पर समाजवादियों की हड्दतारों तोड़ना ही था। मगर सीमाव्य से उन्हें शीघ्र ही बड़ा काम मिल गया।

नए चुनाव में अनुगत निर्वाचन की पद्धति के कारण मध्यमों के गुट ही फिर चुन कर आ गए थे और प्रतिनिध-सभा के करीब आधे सदस्य इन गुटों के थे। मगर इटली के उत्तर भाग में 'समाजवादी' दल और दक्षिण भाग में अपना नाम 'लोक-दल' रख लेनेवाला पुराना 'कैथोलिक दल' भी काफी जबरदस्त थे। इन दोनों का आपस में मेल दुर्लभ था। सरकार को चलने के लिए इन दोनों में से एक दल की सहायता अनिवार्य थी। अस्तु सरकार ने इन दोनों को लड़ने का खेल खेलना शुरू किया। एक के बाद दूसरे लगातार बहुत से मन्त्रिमंडल बने और टूटे। 'लोकदल' के हाथों में कुर्जी होने से वह अपनी सरकार चाहता था। मध्यम-वर्ग के सदस्य समाजवादी प्रधान मंत्री का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थे। समाजवादी सिवाय समाजवादी के और किसी प्रधान-मंत्री के लिए तैयार नहीं थे। राजा मध्य वर्ग के प्रधान मंत्री चुन चुन कर हार गया। ऐसा मालूम होने लगा कि राजा को समाजवादी प्रधान मंत्री चुनना पड़ेगा और शायद मुसोलिनी भी समाजवादी मन्त्रिमंडल में एक मंत्री का पद लेगा। मगर मुसोलिनी ने खुद प्रधान-मंत्री बन कर 'लोकदल' और 'समाजवादी' दलों का एक मन्त्रिमंडल बनाने की तैयारी तो जाहिर की मगर किसी दूसरे प्रधान मंत्री के मन्त्रिमंडल में स्वयं शामिल होने से साफ इन्कार कर दिया। लोग व्यवस्थापक-सभा की इस हालत से थक गए। राष्ट्रीय पक्ष वालों ने—जो सदा से व्यवस्थापकी सरकार के विरोधी थे—फेसिस्टों से मिल कर किसी एक दल पर हमला न कर के 'व्यवस्थापकी सरकार-पद्धति' पर ही जोरों से अखबारों में हमला शुरू किया। ऊबे हुए अखबारों ने भी इस हमले में उन का साथ दिया।

इधर मुसोलिनी 'उदार सरकार' बनाम 'फेसिस्ट सरकार' पर लेख पर लेख लिख रहा था। २० अक्टूबर के दिन विक्टर इमेन्यूअल की सेनाओं का रोम पर कब्जा करने का वर्ष दिन मनाया गया और इस दिन मुसोलिनी ने ऐलान किया कि फेसिस्ट इटली पर शासन करने के लिए तैयार हैं। उस ने आनेवाली फेसिस्ट क्रांति का भी जिक्र किया और 'रोम पर कब्ज करो!' की पुकार शुरू की। राजा से मेज रखने के विचार से उस ने इस बात का भी ऐलान किया कि फेसिस्ट राजा शाही के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उन को उफ्टी शिकायत है कि आजकल का राजा अपनी राजसत्ता का पूरा उपयोग नहीं करता है।

फिर फेसिस्ट की टोलियों के बोलझानों से जर्मनों को निकाल देने पर भी जब सरकार ने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया, तब मुसोलनी ने प्रतिनिधि-सभा के पास अपनी माँगें पेश कर दीं। उस की माँगें यह थी, 'प्रतिनिधि-सभा को मंग कर दिया जाय, चुनाव के कानून का सुधार और नया चुनाव शीघ्र से शीघ्र किया जाय। सरकार को राष्ट्र की विरोधी शक्तियों का कड़ाई से सामना करना चाहिए, आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए, डेलमेरिया छोड़ देने पर फिर से विचार होना चाहिए और फेसिस्टों को, वायुयान के कमीशन पर कब्जा और परराष्ट्र, युद्ध, जलसेना, भ्रम और सार्वजनिक निर्माण-कार्य के पाँच मंत्रीपद मिलने चाहिए।' उस ने इन माँगों के साथ यह खबर भी भेज दी थी कि 'अगर यह माँगें खुशी से स्वीकार नहीं होंगी, तो वह 'उन्हें ज़बरदस्ती से मंजूर कराएगा क्योंकि व्यवस्थापक-उमा के निकम्भेन से देश को बचाने का अब कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा है।' प्रतिनिधि-सभा के राजनीतिज्ञ उस की इन माँगों पर मुस्कराने लगे। वे अधिक से अधिक फेसिस्टों को बिना विभाग के एक-दो मंत्री और दो-चार उपमंत्री पद दे कर संतुष्ट करने को तैयार थे। वे फेसिज्म को केवल एक मजराऊ और अधिक से अधिक एक नई हवा समझते थे। उस से डरते नहीं थे; क्योंकि फेसिस्ट लोगों की राजनैतिक चेतना में अभी तक अधिक ताकत नहीं थी। उन के काफी सदस्य तक प्रतिनिधि सभा में नहीं थे।

मगर फेसिस्टों का उत्तर इटली के लगभग सारे नगरों पर पूरा जोर था। अक्टूबर के महीने में उन्होंने ने प्रीक्टोसों और पुलिस के दफ्तरों पर कब्जा जमाना और दक्षिण के नगरों में अपनी ताकत फैलाना शुरू कर दिया। जिन रेल और तार के दफ्तरों की उन्होंने ने इज़्तालाओं में रक्षा की थी, उन पर उन्होंने ने अब अरना पहरा रख दिया। २४ अक्टूबर को दक्षिण प्रदेश के नेपल्स नगर में दक्षिण में फेसिज्म का जोर बढ़ाने के लिए फेसिस्टों की कांग्रेस बैठी और उस में खुल्लम-खुल्ला आति का जिक्र करते हुए मुसोलनी ने कहा कि, 'अगर कानूनी तरीके से काम नहीं होगा तो फिर गैर-कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया जायगा और रोम पर कूच करना पड़ेगा।' फेक्टा नाम का एक ईसमुल आदमी इस समय प्रधान मंत्री था। मगर वह बेचारा कुछ कर-धर नहीं सकता था; क्योंकि प्रतिनिधि-सभा में उस का बहुमत नहीं था। अतः जैसे ही उस की सरकार ने इस्तीफा दिया वैसे ही फेसिस्ट टोलियों को रोम से तीस मील दूर के एक मुकाम पर इकट्ठा होने का 'फेसिस्ट सैनिक समिति' की तरफ से हुक्म मिला। और २८ अक्टूबर को रोम में काली क्रमोज़ पढ़ने हुए करीब पचास हजार फेसिस्टों की टोलियाँ घुसीं। 'सैनिक समिति' ने कूच का हुक्म देते बख्त एलान किया था कि यह कूच सेना, पुलिस, राजा अथवा काम करनेवालों के खिलाफ नहीं है; बल्कि उन 'निकम्भे राजनैतिक गुटों के खिलाफ है, जो चार वर्ष से इटली में मजबूत सरकार कायम नहीं कर सके हैं।' सरकारी क्राँचें भी आईं; मगर कोई लड़ाई या खून-खराबा नहीं हुआ। २८ अक्टूबर को तीसरे पहर सातदरा ने मुसोलनी से अपने मन्त्रि-मंडल में मंत्री बनने के लिए पूछा। मुसोलनी ने इन्कार कर दिया। अतः २९ अक्टूबर को टेलीफोन पर मुसोलनी को राजा ने बुला कर अपना मन्त्रि-मंडल बनाने के लिए आग्रह दी और मुसोलनी दूसरी ही

गाड़ी से यह कहता हुआ मिलन छोड़ कर रोम के लिए चल पड़ा कि, 'कल इटली के मंत्रि मंडल ही नहीं; बल्कि सरकार मिल जायगी।' रास्ते में उस ने उतर कर एक लाल पचास हजार एकत्र फेसिस्टों की सलामी ले ३० अक्टूबर को मंत्रि-मंडल तैयार कर के रोम में घुस आनेवाले पचास हजार सैनिकों को चौबीस घंटे के भीतर वापस चले जाने का हुक्म दे दिया। दुनिया के इतिहास में यह एक अनोखी क्रांति हुई। इस को विचारों की क्रांति कहना ही अधिक उचित होगा। क्योंकि इटली के नौजवानों ने एक सड़के के नीचे हफ्ठे ही कर बिना खून-खराबा किए इटली को यूरोप की निर्जीव राजनीति से बचा लिया।

## ६-फेसिस्ट सरकार

मुसोलिनी ने अपने नए मंत्रि-मंडल में अपने सिवाय सिर्फ तीन और फेसिस्ट रखे। बाकी सब मंत्रियों को उस ने एक समाजवादी दल को छोड़ कर और सब दलों से लिया। अपने हाथ में उस ने पर-राष्ट्र-विभाग और प्लांकी को उपमंत्री बना कर, यह विभाग रखे। फेसिस्ट अपनी जीत को किसी से बाँटना पसंद नहीं करते थे। उन्हें इस प्रबंध से काफी निराशा हुई जिस से दल में मुसोलिनी का बहुत विरोध भी हुआ। मगर मुसोलिनी व्यवस्थापक-सभा से मिल कर काम करना चाहता था। मुसोलिनी ने व्यवस्थापक-सभा में जा कर सिनेट से तो अपनी गुस्ताखियों के लिए क्षमा माँगी और इस 'इटली के प्रख्यात पूर्वजों की प्रख्यात जगह के लिए' बहुत इज्जत दिलवाई और उस ने वादा किया कि कानून के अनुसार ही भविष्य में मैं चलूँगा और दूसरे राष्ट्यों से मिल और इटली में पूर्ण स्वतंत्रता की नीति पर कायम रहूँगा। मगर प्रतिनिधि सभा से उस ने बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। वहाँ जाकर वह बोला—'मैं आप के सामने आया हूँ। इस में आप ने मुझे इज्जत नहीं दी है और न मैं आप से अपनी गुस्ताखी के लिए माफी माँगता हूँ। जिन्हें जल के वाक्त्यों पर दुःख हो, वह अपने कमरों में बैठ कर अवलाथों की तरह आँसू के दरिये बहा सकते हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि क्रांति को अपने अधिकार होते हैं। तीन लाख नौजवान जब मेरे इशारे पर सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, तो मैं चाहूँ तो आप की इस निकम्मी सभा में खून की कीबड़ कर दूँ। मैं चाहता तो आप की इस सभा को ठोकर मार कर निकाल देता और निरी फेसिस्टी सरकार कायम कर लेता। मगर मैं ने ऐसा नहीं किया; क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ—कम से कम अभी इन की ज़रूरत नहीं। फिर उस ने अपना कार्यक्रम बढ़ा कर एक साल के लिए सब कुछ सियाह-सफेद करने की पूरी ताकत की माँग पेश की, जिस से सरकार को सुसंगठित बनाया जा सके और खर्च कम की जा सके। उस ने वायदा किया कि अपने सारे कामों का हिसाब वह प्रतिनिधि-सभा को देगा। मगर साथ ही उस ने यह भी जता दिया कि प्रतिनिधि-सभा दो दिन दो वर्ष में जब ज़रूरत होगी मंग की जा सकती है। 'आप को या तो जनता के भावों के सामने सिर झुकाना होगा या नेस्तनाबूद हो जाना पड़ेगा' इन शब्दों में उस ने अपना वाख्यान समाप्त किया, 'भद्र पुरुषों, देश को अब बहुत-सी अपनी बकवास सुनाना बंद कर। वायन सदस्य मेरे व्याख्यान पर बोलना चाहते हैं, यह संख्या बहुत बड़ी है।

इस बरक़ात की वज़ाय अब हम लोगों को शुद्ध हृदय और सचेत मन से देश का मान और धन बढ़ाने के प्रयत्न में लग जाना चाहिए। ईश्वर मेरे इस काम में मेरी सहायता करे।'

सदस्य नीसिलिए मुसोलनी की फटकार सुन कर दंग रह गए। समाजवादियों का नेता बुराती कहने लगा, 'मुसोलनी फिर यह व्यवस्थापक सभा का भूत क्यों कायम रखता है। इस से तो सीधा स्वेच्छाचारी राज्य बढ चलाए तो मैं पसंद करूँगा।' त्रियोलिटी ने कहा—'यह प्रतिनिधि सभा इसी काविल है।' सिनेट के लोग प्रतिनिधि-सभा पर मुसोलनी लगे। मार बाहर देश में और अखबारों में मुसोलनी के इस व्याख्यान की बड़ी तारीफ हुई। प्रतिनिधि-सभा में मुसोलनी की माँग मंजूर हुई और सरकार को एक साल के लिए सारी ताकत दे दी गई। प्रतिनिधि-सभा ने 'नेस्तनाबूद' होने से 'देश के भावों के सामने खिर फुकाना' ही बेहतर समझा। समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने प्रतिनिधि-सभा में मुसोलनी का विरोध किया। मगर मुसोलनी को 'लोकदल' की तरफ से बहुत चिन्ता थी क्योंकि इस दल की सहायता पर ही मुसोलनी की सरकार निर्भर थी। लोकदल का नेता डीनस्तरजो, अपने हाथ में कुंजी देख कर कान रड़के करने लगा। वह शिकायत करने लगा कि उस के दल के काफी आदमी मंत्रि-मंडल में नहीं रखे गए और फेसिस्ट लोग इटली के दक्षिण भाग में उस के दल की हर तरह से ताकत तोड़ने की कोशिश करते हैं। अप्रैल सन् १९२३ ई० में लोकदल की सालाना सभा में मुसोलनी की बड़ी बुराईयाँ भी की गईं। अस्तु मुसोलनी ने अधिक इतज़ार करना उचित नहीं समझा। लोकदल के मंत्रि-मंडल में दो मंत्री थे जिन में से एक तो मर गया और दूसरे का मुसोलनी ने इस सभा के बाद इस्तीफा ले लिया। मुसोलनी को अपनी स्थिति का डर हुआ और इस लिए उस ने चुनाव का क़ानून बदलने की माँग शुरू की। उस ने व्यवस्थापक-सभा के सामने एक मसविदा पेश किया जिस के अनुसार 'जिस दल को देश भर में सब से अधिक मत मिलें उस को हर चुनाव-क्षेत्र से दो तिहाई जगहें मिल जानी चाहिए।' मुसोलनी ने एक व्याख्यान में कहा कि, 'मैं अपने चारों ओर सारे राजनैतिक दलों के खंडर बिलरे हुए देखना चाहता हूँ जिस से फेसिज़्म की एक इमारत ही पर सब की नज़रें पड़े।' अगर यह मसविदा प्रतिनिधि-सभा स्वीकार नहीं करेगी तो एक दूसरी क्रांति करनी पड़ेगी।' लोकदल का नेता इस धमकी को सुन कर चुपचाप इस्तीफ़ा दे कर चला गया और यह चुनाव का क़ानून इस संशोधन के साथ पास हो गया कि सब से अधिक मत मिलने के साथ-साथ कम से कम मतों के २५ फी सदी मत भी मिलने चाहिए।

प्रतिनिधि-सभा का नया चुनाव हुआ और फेसिस्टों के जनदल ने देश भर में चुनाव के दिन एकत्र हो कर फेसिस्टों की मदद की। देश भर में जितने मत पड़े थे उस के दो तिहाई फेसिस्टों को मिले। मुसोलनी ने सोचा कि अब प्रतिनिधि-सभा ठीक तरह से काम करेगी। उस की व्यवस्थापक-सभा के काम के बारे में यह राय थी कि जो मसविदे मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा के सामने रखे उन पर निष्पक्ष रूप से विचार करना और उन पर अपनी निष्पक्ष सलाह देना व्यवस्थापक-सभा का काम है न कि हमेशा सरकार का विरोध करना। उस को यह देख कर बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ कि नई प्रतिनिधि-

सभा के शुरू होते ही अल्प संख्या के दलों ने चुनावों और सरकार के विरोध का और अपने-अपने दलों के कार्यक्रमों का रोना फिर उसी पुरानी चाल से शुरू कर दिया। समाजवादियों के दो नेता ऐसेनडोला और मेडियोटी को खास कर सरकार को तंग करने में मजा-सा आता था। मुसोलनी ने इन दलों से भेल करने और उन्हें समझाने की बड़ी कोशिशें कीं। उस ने समझाया कि 'तुम लोग जो यह अपने-अपने कार्यक्रमों से चिपक गए हो इस का अर्थ क्या है ? तुम्हें आगे या पीछे किधर भी तो जाना होगा। या तो ताकत और हिम्मत हों, तो क्रांति कर के सत्ता हाथ में कर लो अथवा जिन के हाथ में सत्ता है उन का साथ दो।' मगर उस की यह बातें किसी की समझ में न आईं। इसी बीच में दुर्भाग्य से किसी फेसिस्ट ने मेडियोटी की हत्या कर डाली। अब तो विरोधियों ने ची-पुकार मचा दी। मुसोलनी से इस्तीफा माँगा जाने लगा। 'जनदल' को भंग कर डालने के लिए पुकार मंच उठी। मुसोलनी ने राष्ट्रीय पक्ष के लोगों को अच्छी तरह हाथ में रखने के विचार से दो राष्ट्रीय पक्ष के मंत्री अपने मंत्रि मंडल में और फीन बढ़ा लिए और कई राष्ट्रीय पक्ष-वालों को 'फेसिस्ट दल' की बड़ी कौंसिल में भी रख लिया। उस ने अपने दल को फिर से संगठित करने और हिंसा को दबाने का वादा किया मगर अपना इस्तीफा देने या 'जनदल' को भंग करने से साफ इन्कार कर दिया। इस पर लगभग सारे विरोधी प्रतिनिधि सभा छोड़ कर ऐवेंताइन पहाड़ी पर एक आफिस में जा बैठे और वहाँ से कलम और स्पाही की गोला-बारूद और कानाजी वायुयानों से फेसिस्टों पर हमले करने लगे। दस राजनैतिक दलों और छः सात गुटों ने मिल कर फेसिस्टों की सरकार पर हमला शुरू किया। मुसोलनी ने उन्हें मनाने की बड़ी कोशिशें कीं क्योंकि वह विरोधी दलों को व्यवस्थापक-सभा में स्थान देना चाहता था जिस से कि उन की समालोचना और विचारों का सरकार को लाभ मिल सके। मगर जब विरोधियों को वह किसी प्रकार सतुष्ट न कर सका और उन्होंने उस की सरकार के खून की माँग जारी ही रखी, तो उस ने आखिरकार मजबूर हो कर विरोधियों को ४८ घंटे के अंदर कुचल डालने का एलान किया। विरोधी अखबारों को बंद कर दिया गया या उन की आवाज़ कमज़ोर कर दी गई। फेसिस्टों का विरोध करनेवाले वकीलों की सनदे छीन ली गईं और प्रोसेस के निफाल दिए गए और सारी विरोधी संस्थाओं के भस्म कर दिए गए। अपने पक्षपाती सदस्यों की प्रतिनिधि-सभा के आगे मुसोलनी ने बहुत ही कानून और ज्ञान के पाबंदी दिखाई, यहाँ तक कि छोटी-छोटी बंजट इत्यादि की तफसीलों पर भी, जिन पर व्यवस्थापक-सभा में आम तौर पर चर्चा नहीं होती थी, सदस्यों को चर्चा करने का मौका दिया। फेसिस्ट दल की कौंसिल की तरफ से नई फेसिस्ट सरकार फ़ायम करने के विचार से निम्न-लिखित बातों पर विचार करने के लिए एक कमीशन भी बैठाया गया :—

१. कार्यकारिणी और धारा का संबंध।

२. सरकार और अखबार।

३. सरकार और रुपए-पैसे का व्यवहार करनेवाली संस्थाएं।

४. सरकार और गुप्त संस्थाएं।

५. सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दल।

## ६. सरकार और उद्योग संघें ।

मगर इस कमीशन की रिपोर्ट के इंतजार में न बैठे रह कर मुसोलनी ने स्वयं फौरन ही सरकार को सुधारना शुरू कर दिया । अनुपात निर्वाचन उस ने एक कानून पार कर के बदल दिया और ज़िम्मे को उस ने भी मताधिकार दे दिए । कानून बनाने के बजाय अपने हुक्म निकाल कर काम करने की ताकत हाथ में ले लेने से उस का काम आसान हो गया था । परंतु पुराने कानूनों की आदी अदालतों ने उस के इन हुक्मों पर अमल करने से आना-कानी दिखाई इन लिए उसे न्याय शासन को बदलने की भी जरूरत हुई । 'कॉन्सिल ऑफ स्टेट' की सरकारी कामों को गैर-कानूनी ठहराने की ताकत छीन ली गई और सार्वप्रतीय अदालतों को तोड़ कर एक अदालत बना दी गई । नए कानून बनाए गए जिन में फेसिस्टों के सिद्धांतों का समावेश किया गया और नौकरशाही में भी बहुत कुछ 'कॉट-छाँट' कर दी गई । सन् १९२६ ई० के एक अगस्त मास में ही ६५ नायब प्रीफेक्टों को कम कर दिया गया और सत्रह नए प्रांत कायम कर दिए गए । सुधार-कमीशन को फेसिस्ट दल के हुक्म के बजाय राजा के हुक्म से काम करने का हुक्म दिया गया । थोड़े से शब्दों में कहा जाय तो सार्व सरकार का इन फेसिस्ट सिद्धांतों पर संगठन किया जाने लगा कि, "व्यवस्थापकी सरकार कमज़ोर और केवल दलबन्दी का दफोसला होती है । प्रजा के प्रतिनिधियों की सरकार का अर्थ सिर्फ़ यही होता है कि कुछ पेशावर राजनीतिज्ञों के हाथ में सरकार की लगाम रहती है । दलों के एक-दूसरे से झगड़ों के मारे कभी कोई सरकार ताकतवर नहीं हो पाती और जो सरकार ताकतवर नहीं उस को सरकार नहीं कहा जा सकता । सरकार को दलों या व्यक्तियों का प्रतिनिधि नहीं बल्कि राष्ट्र का प्रतिनिधि होना चाहिए । सरकार के मुकाबले में व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती । व्यक्ति कुछ नहीं है; सब कुछ इटली है । स्वतंत्रता अधिकार नहीं, दत्तव्य है । जितनी अधिक मजबूत सरकार होती है उतनी ही अधिक लोगों को स्वतंत्रता मिलती है । स्वतंत्रता उन राष्ट्रों में होती है जो प्रगतिशील, उद्योगी और सृजक होते हैं और जो अपने सदस्यों की सृजकशक्ति को विनाश का मौका देते हैं । जो शक्तिमान होता है उसी को राष्ट्र पर शासन करने का अधिकार होता है । सरकार की सत्ता पर किसी संस्था को हाथ रखने का अधिकार नहीं है । जब तक सरकार मजबूत रहती है तभी तक वह अरक्षण क़रतूतों और शासन करने की शक्ति रखती है ।" "संस्थापक" के शब्दों के अनुसार इटली के मन्त्रिमंडल की कार्यकारिणी सत्ता का जन्मदाता व्यवस्थापक-सभा के स्थान में राजा को समझा जाने लगा और व्यवस्थापक-सभा का काम सिर्फ़ सरकार के प्रस्तावों पर समालोचना और राय जाहिर करना माना गया । फेसिस्ट सरकार, फेसिस्ट दल और फेसिस्टों का 'जनदल' फेसिज़्म के तीन स्तम्भ बन गए । फेसिस्ट दल को मुसोलनी ने फिर से अच्छी तरह संगठित किया और राजा का एक हुक्म निकाल कर 'जनदल' को इटली राष्ट्र की 'राजनैतिक पुलिस' बना दिया ।

रोसीनी नाम का एक मजदूरों का समाजवादी नेता उत्तर अमेरिका में इटली के मजदूरों का संगठन करता था । वहाँ उस ने इटली के मजदूरों के प्रति दूसरे देशों के मजदूरों का बर्ताव देख कर यह निश्चय किया था कि अभी अंतर-राष्ट्रीय भाईचारे के



समाजवादी विचार पर इटली के मजदूरों का संगठन करना ठीक न होगा। इटली के मजदूरों का राष्ट्रीयता के विचारों पर संगठित करना होगा। अस्तु अमेरिका से लौट कर उस ने इटली में मजदूरों का संगठन इसी सिद्धांत पर करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उस ने इटली में बहुत सी मजदूरों की संघे भी बना ली थीं। मुसोलनी और रोसोनी के राष्ट्रीय विचार मिलते-जुलते थे। अस्तु मुसोलनी के हाथ में ताकत आने के बहुत दिन पहिले ही मुसोलनी ने उस से फेसिस्टों के मेल की बात चलाई थी। नई फेसिस्ट सरकार के संगठन पर विचार करने के लिए अगस्त सन् १९२४ ई० में मुसोलनी ने जो कमीशन बेटाया था उस के बैठने के बाद ही देश भर में चारों तरफ मजदूर और मालिकों के झगड़े छिड़े और एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया। अस्तु इस कमीशन ने, जिस का एक सदस्य रोसोनी भी था—अन्य व्यवस्थापक सुधारों पर समय न खराब कर के इटली की आर्थिक व्यवस्था पर ही अधिक विचार किया और इटली के लिए एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था तैयार की जिस के निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा गया था।

१ राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था।

२ उद्योग-संघों की कानूनी हैसियत।

३ मजदूरों के ठेके के उद्योगों के लिए तय करने और उन ठेके पर अमल करने के लिए मजदूरों के कानून और सिद्धांतों के नियम और अदालतें।

इस नई आर्थिक व्यवस्था के अनुसार जो सरकार का नया रूप बना उस का नाम कमीशन ने 'सामाजिक सरकार' रखता था। कमीशन के सदस्य अच्छी तरह जानते थे कि वे इन नए सुधारों से एक विशुद्ध नई प्रकार की सरकार की रचना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में व्यवस्थापकी सरकार को साफ शब्दों में निरुद्धा और इटली के अयोग्य बतलाया। उन के इस 'सामाजिक सरकार' के मसविदे में २३ धाराएँ थीं जिन के अनुसार उद्योगी संघों की कानूनी हैसियत मानी गई थी और व्यापार, उद्योग और खेती के लिए प्रांतों में 'मंडलों' की स्थापना की गई थी। सारे राष्ट्र को ही तीन श्रेणियों में बाँट दिया गया था। एक श्रेणी में साधारण घरेवाले, कारीगर और सार्वजनिक सेवक, दूसरी श्रेणी में ग्वेती और ग्वेती का उद्योग और तीसरी श्रेणी में उद्योग, व्यापार और मकानों के मालिक वगैरह आते थे। इन श्रेणियों की विभिन्न संघों के सदस्यों को एक प्रांतिक मंडल के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। तीनों श्रेणियों के तीन प्रांतिक मंडलों की एक एक सभा और एक एक कांसिल रखी गई थी। तीनों मंडलों का मिल कर एक 'कॉरपोरेट कालेज' बनाया गया था और हर प्रांतिक कालेज की एक सभा और एक कांसिल रखी गई थी। इन प्रांतिक कालेजों का 'राष्ट्रीय सामाजिक सभा' के सदस्य चुनने का अधिकार था और 'राष्ट्रीय सामाजिक सभा' का अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार था। 'राष्ट्रीय सामाजिक सभा' को तीन श्रेणियों के अनुसार तीन समितियों में बाँट दिया गया था। इन प्रांतिक और राष्ट्रीय संस्थाओं का राष्ट्र का सारा आर्थिक शासन—मजदूर और मालिकों के झगड़ों का सुलाना और

<sup>१</sup> कॉरपोरेट स्टेट <sup>२</sup> कॉरपोरेट कालेज <sup>३</sup> दि नेशनल कॉरपोरेट कांसिल।

सरकार को उचित कानून बनाने में सहायता करना इत्यादि सौंपा गया था। सरकार को इन संस्थाओं के संगठन में किसी भी समय हस्तक्षेप करने का अधिकार रखा गया था। परंतु सरकार किसी संस्था को भंग कर दे, तो छ मास के अंदर ही दूसरी नई संस्था का चुनाव जाना जरूरी रखा गया था। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि 'राष्ट्रीय सामाजिक सभा' को इटली की व्यवस्थापक सभा की तीसरी शाखा बना देना चाहिए। मगर कमिशन ने यह निश्चय किया कि व्यवस्थापक सभा की प्रतिनिधि-सभा के आधे सदस्यों को चुनने का अधिकार प्रांतिक 'कॉर्पोरेट कालेजों' को होगा और प्रतिनिधि-सभा के बाकी आधे सदस्यों का चुनाव जैसा अभी तक होता है उसी प्रकार होगा और सिनेट जैसी की तैसी कायम रहेगी।

कमिशन के कुछ उदार तन्त्रियत के सदस्यों को यह व्यवस्था पसंद नहीं थी। उन का मत था कि इस व्यवस्था से राष्ट्र के नागरिक तब आर्थिक हितों की कोटियों में बँट जाते हैं, जिस से राष्ट्र के सम्मिलित हित की तरफ से लोगों का ध्यान हटा रहा करेगा और इटली में एक मजबूत राष्ट्र कायम होने के बजाय वही पुरानी कमजोरियाँ कायम रहेंगी। कहर राष्ट्रीयता के पक्षपाती 'सधवादियों' का कहना था कि हर एक उद्योग के लिए सिर्फ एक ही सघ होनी चाहिए और उस उद्योग में सारे काम करनेवालों को उस एक सघ का ही सदस्य होने के लिए कानून द्वारा लोगों को बाध्य करना चाहिए और मजदूरों के ठेकों को तय करने के लिए हडतालें करना सरकार के हुक्म से गैर कानूनी ठहरा देना चाहिए। कुछ मजदूर नेताओं का कहना था कि मजदूर-सघों पर सरकार का बहुत अधिकार नहीं रहना चाहिए और उन को अपने काम में पूरी तरह से स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उद्योग धर्मों के मालिक भी इस व्यवस्था से घबराए और उन्होंने ने शोर मचाया कि इस कानून से तो इटली के सारे आर्थिक जीवन पर रोसोनी के मजदूर-सघों के महा मंडल का राजनैतिक कब्जा ही जम जावेगा। आखिरकार २ अक्टूबर सन् १६२५ ई० को विदोनी के राजमहल में सरकार की तरफ से मालिक और मजदूर दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बुलाए गए और उन का यह समझौता हुआ कि मजदूरों के नाम के सत्रध में जो ठेके होंगे वे मालिकों की संस्था 'उद्योग महा मंडल' और मजदूरों की संस्था 'सघ महामंडल'<sup>२</sup> की अंतर्गत संस्थाओं में ही होंगे। इस विदोनी राजमहल के समझौते को राजा के फरमान से कानूनी करार दे दिया गया और मालिकों का 'उद्योग महामंडल' और मजदूरों का 'सघ महामंडल' कानूनी संस्थाएँ बन गईं। जिस 'सघ' में कम से कम एक उद्योग या धंधे में काम करनेवालों में से कम से कम दस फीसदी सदस्य न हों उस की कानूनी हैसियत नहीं रखी गई थी। रोसोनी ने उद्योगों में काम करनेवालों की सघों के महामंडल में धंधों में काम करनेवालों की सघों को भी बाद में मिला लिया, जिस से इटली के नागरिकों के तीन वर्ग न रह कर दो ही वर्ग रह गए। ऐसी सघों को जिन में मालिक और मजदूर दोनों शरीक हो जाते थे, बदल कर दिया गया। हर उद्योग या धंधे में एक दिन की मजदूरी का औसत मजदूर सघों के हर एक सदस्य से और उतना ही हर एक मजदूर

<sup>१</sup> कॉन्फेडेरेशन ऑफ़ इटली

<sup>२</sup> कॉन्फेडेरेशन ऑफ़ कॉर्पोरेशंस

के लिए मालिकों से चंदा कानून के अनुसार इटली में कर की तरह ले लिया जाता है। इस चंदा का उपयोग महामंडलों की संस्थाओं के लिए ही किया जाता है। परंतु इन महामंडलों के अंतर्गत संस्थाओं के सिवाय दूसरी स्वतंत्र संस्थाएँ बनने की कानून मुमानियत नहीं करता है। यद्यपि चंदा नव से कानून के अनुसार महामंडलों की संस्थाओं के लिए ही लिया जाता है। स्वभावतः लोग महामंडल की संस्थाओं में शामिल होना पसंद करते हैं। इन संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री संस्थाओं की व्यवस्था के अनुसार चुने जा सकते हैं। मगर गृहमंत्री को यह अधिकारी स्वीकार होने की कद रक्खी गई है। मजदूर और मालिकों के आपस के ठेके विदोनी राजमहल के समझौते के अनुसार कानूनी समझे जाते हैं और उन पर दोनों पक्षों को कानून के अनुसार अमल करना पड़ता है। रोसीनी इन ठेकों से सरमाये में मजदूरों का हिस्सा कायम करना चाहता है क्योंकि यह उस के जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। सैनिकों, पुलिस, सरकारी अफसरों और प्रोफेसर्स को किसी संघ में शामिल होने की इजाजत नहीं है क्योंकि वे सरकार के अंग माने जाते हैं। सब के हितों की रक्षा करना सरकार का धर्म माना जाता है और फेसिद्धम सिद्धांत के अनुसार किसी का हित सरकार से अलग नहीं हो सकता। अस्तु, यह सरकारी नौकर अपने हितों की सरकार से रक्षा करने के लिए संघ नहीं बना सकते हैं और न वे सरकार से मजदूरों के बारे में ठेका कर सकते हैं। परंतु दूसरे सरकारी नौकरों को संघों में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। रेल, तार, डाक, टेलीफोन, प्राइमरी स्कूलों में काम करनेवाले और कर एकत्र करनेवाले, इत्यादि कुछ सरकारी नौकरों की अब कई संघें बन गई हैं। 'उद्योगी अदालतें' भी कायम कर दी गई हैं और जो इन अदालतों का हुक्म नहीं मानते हैं उन को कड़ी सजा दी जाती है। किसी प्रकार की राजनीतिक बातों के लिए मजदूरों की हड़तालें या मालिकों की तरफ से कारखाने बंद तो कानून के अनुसार हो ही नहीं सकते हैं। दूसरे प्रकार की हड़तालों और कारखानों को बंद करने के संबंध में भी इतने कड़े नियम रखे गए हैं कि लगभग उन की मुमानियत ही सी है। मालिकों के इटली में अब छः महामंडल हैं जिन में 'राष्ट्रीय फेसिस्ट उद्योग महामंडल' सब से प्रमुख है। एक मजदूरों का 'राष्ट्रीय फेसिस्ट संघ महामंडल' है जिस में विभिन्न धंधों के मजदूरों के साथ 'संघ-मंडल' शामिल हैं। इन सब के ऊपर महामंडलों का सरकारी विभाग है और उस का एक महामंडल-मंत्री होता है। यह मंत्री सरकार की आर्थिक प्रश्नों पर नीति निश्चय करने के लिए 'उद्योग-महामंडल' और 'संघ महामंडल' के अधिकारियों से अक्सर सलाह लेता है। मुसोलिनी ने स्वयं पहले महामंडल मंत्री का पद ग्रहण किया था क्योंकि वह पुरानी मुदा व्यवस्थापक-सभा के स्थान में एक आर्थिक व्यवस्थापक-सभा कायम करना चाहता था। उस ने एलान किया था कि सन् १९२६ ई० में इस प्रतिनिधि-सभा की मियाद खत्म हो जाने पर नई 'सामाजिक प्रतिनिधि-सभा' काम करना शुरू करेगी। इस 'संघीय प्रतिनिधि-सभा' के चुनाव के बारे में सन् १९२८ ई० में जो नया चुनाव का कानून पास किया गया था उस के अनुसार मालिकों और मजदूरों की तरह संस्थाओं को अपने-अपने उम्मीदवारों के आठ सौ नाम की एक सूची महामंडल-मंत्री को देने का

अधिकार या जिम में से फेसिस्ट दल की कार्यकारिणी की मलाह से महामंडल मंत्री ४०० नाम चुन लेगा। इन ४०० चुने हुए नामों की एक सूची पर इक्के सय सघों के सदस्यों के मत लिए जायेंगे और मतदारों को इस सूची के, बिना कुछ घटाए-बढ़ाए जैसा का तैसा, स्वीकार करने या न करने का ही केवल अधिकार था। अगर मंत्री की चुनी हुई यह सूची मतदारों को स्वीकार न हुई तो इन का अर्थ सरकार में अविश्वास समझा जायगा और उस हालत में रोम की बड़ी अपील की अदालत हुकम निकाल कर चुनाव की एक नई तारीख मقرر करेगी और सब को अपनी अपनी सूचियाँ चुनाव के लिए पेश करने का अधिकार होगा। अगर जिन मन्थानों में पचास हजार या उस में अधिक याक़ायदा चढ़ा देनेवाले सदस्य मतदार होंगे, उन्हीं मन्थानों को उम्मीदवारों की सूचियाँ पेश करने का अधिकार होगा। जिस सूची को सब से अधिक मत मिलेंगे, उस के सारे उम्मीदवार चुन लिए जायेंगे। परंतु किसी भी सूची में जितने सदस्य चुने जानेवाले होंगे, उन से तीन चौथाई से अधिक के नाम न होंगे क्योंकि एक चौथाई सदस्य दूसरी सूचियों में से जितने मत उन को मिलेंगे, उस के हिसाब से ले लिए जायेंगे। इस कानून के अनुसार होनेवाले सन् १९२६ के चुनाव में इटली के ६० फी मदी मतदारों ने 'सामाजिक प्रतिनिधि-सभा' के चुनाव में भाग लिया था और उन में से ६८ फी सदी ने फेसिस्ट दल की सूची के लिए मत डाले थे।

फेसिस्ट सरकार के भविष्य के संबंध में अभी कोई बात निश्चय रूप से कहना कठिन है। यूरोपीय युद्ध के बाद उलट-पलट मच जाने से जगह-जगह पर जो सामाजिक प्रयोग किए जा रहे हैं, फेसिज्म भी उन्हीं में से एक है। इटली की आज कल जिस संस्था में देखो उस में फेसिज्म का रंग मरा जा रहा है। पुराने बेरंगे उदार कहलाने वाले स्कूलों की जगह पर अब स्कूलों में राष्ट्रीयता, स्वाभिमान और चरित्र-बल की शिक्षा दी जाती है। इटली जाति के संगठित और मजबूत बनाने के लिए सात में अठारह वर्ष तक के सभी नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जाती है। पुरानी मतलबी लोगों की आर्थिक नीति के स्थान में अब राष्ट्र के हित के ध्यान से राष्ट्र का आर्थिक पत्रक तैयार होता है। सब अदालतों का एक बड़ी अदालत में मिलान कर के न्याय शासन भी है। फेसिज्म के इस सिद्धांत पर जोर दिया गया है कि राष्ट्र एक बदन की तरह है जिस के हिस्से नहीं किए जा सकते हैं। फेसिज्म सिर्फ एक कैथोलिक सम्प्रदाय का मानता है। आर्थिक जीवन में भी राष्ट्रीय हित के विचार से सरकार हस्तक्षेप करती है। सरकार का राष्ट्रीय जीवन के सब पहलुओं पर अधिकार रखने के लिए कानूनों को इस तरह बदल दिया गया है कि व्यक्तियों के सरकार के मुकाबले में कोई अधिकार नहीं माने गए हैं, और सरकार का हर जगह दबाव रखने की सहूलियतें रखी गई हैं। समाज के धंधे और उद्योग के बल पर एक राष्ट्र में संगठित कर के वर्ग-युद्ध से इटली को दूर रखने की योजना की गई है। प्रांतों के स्थानिक शासन में सब से जरूरी आर्थिक बातों का कुछ भी विचार नहीं रक्खा जाता था क्योंकि हर प्रांत में सरकारी आर्थिक समितियाँ रहती हैं। सरकार की सत्ता की कार्यकारिणी सत्ता ही सब से बड़ा पैमाना होने से प्रधान मंत्री, दूसरे मंत्रियों और प्रीफेक्टों की सत्ता बहुत बढ़ा दी गई है। चुनी हुई स्थितिपेलिटियो की जगह अब सरकार की नियत की हुई

म्यूनिसिपैलिटियाँ होती हैं। सरकार को सिर्फ साधारण कानूनों पर निर्भर न रह कर जरूरत पड़ने पर ग्राम तौर पर अपने हुक्मों से काम चलाने का अधिकार है। प्रधान मंत्री की ताकत का ज़रिया प्रतिनिधि सभा के स्थान में राजा माना जाता है। व्यवस्थापक सभा को सिर्फ प्रजा के भावों को जाहिर करने का ज़रिया समझा जाता है। उस का सरकारी शासन में हाथ नहा होता। अखबार और वकीलों को दण्ड कर रक्का जाता है क्योंकि फेसिज्म के सिद्धांत के अनुसार "सब कुछ राष्ट्र के भीतर है और राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं है। राष्ट्र ये द्वारा ही व्यक्ति का हित हो सकता है।" शायद इटली के राष्ट्रीय जीवन के गिरते हुए कर्ण को फौजदारी में डालने के लिए फेसिज्म की मंत्री जी ज़रूरत थी। फेसिस्टों का कर्ना है कि रिक्टर इमेनुअल और फेब्रि ने इटली को एक राष्ट्र बनाया, मेजिनी और गेरीनाल्डी ने इटली को राष्ट्रीय जीवन दिया और फेसिज्म ने इटली को राष्ट्रीय सरकार दी। इटली के राजनैतिक क्षेत्र में अब उस एक 'फेसिस्ट दल' ही का राज है। दूसरे सारे दल लुप्त हो गए हैं।

इस दल ने मुसोलिनी को इतना ऊँचा चढ़ा दिया है और उस की इतनी पूजा होने लगी है कि 'दल का राज होने के बजाय' 'मुसोलिनी का निरंकुश राज' है, कहा जाय तो भी अनुचित न होगा। यह स्थिति कब तक कायम रहेगी, अथवा इस का क्या परिणाम होगा आज निश्चय रूप में नहीं कहा जा सकता। मुसोलिनी ने पुराने रोमन सीज़रों की तरह अग्नीमीनिया राष्ट्र पर चढ़ाई कर के उस को हड़प लिया है और इटली राष्ट्र को एक 'मजबूत राष्ट्रीय सरकार' देने का अपना दावा ही पूरा नहीं कर दिया है बल्कि इटली राष्ट्र को एक साम्राज्य में बदल दिया है जिस में इटली के लोग उस पर दीनानों की तरह लट्टू दीप्तते हैं। कुछ दिन पहले का कमज़ोर और लचर इटली आज यूरोप के सर्व शक्तिमान राष्ट्र में ही नहीं गिना जाने लगा है, बल्कि यूरोप के मुग और तुर्क की कुंजी की उस के हाथ में आ गई दीप्तती है। मुसोलिनी के सारे स्वप्न अभी पूरे नहीं दीप्तते हैं और नई शक्ति और मान प्राप्त अपने मदोमत्त देशवासियों को वह कहाँ और ले जायगा अभी नहीं कहा जा सकता। उस ने पुराने रोमन सीज़रों की तरह सफेद घोड़े पर चढ़ कर हाल ही में अपने साम्राज्य लक्षियों में प्रविष्ट हो कर जो मायूस किया और इटली सरकार स्पेन में जो हरकतें कर रही है अथवा जो प्रयत्न मेडीटेरेनियन सागर में इटली का प्रभुत्व जमाने के लिए किए जा रहे हैं, उस से यह प्रतीत होता है कि इटली की नई नीति से यूरोप में दूसरा भयंकर महाभारत छिड़ जायगा। यदि यूरोप में दूसरा युद्ध छिड़ जा तो उस के बाद फिर भी इटली में फेसिस्ट राज्य कायम रहेगा या इस युद्ध में फेसिज्म और यूरोपीय सम्यता सभी भस्मीभूत हो जायँगी, नहा कहा जा सकता।

अभी तो चैन से गुजरती है,  
आकाश की खुदा जाने।

# बेल्जियम की सरकार

— १२३१ —

## १—राज-व्यवस्था

फ्रांस और जर्मनी के बीच में बसा हुआ बेल्जियम देश यूरोप का कुल क्षेत्रफल २८,००० वर्ग किलोमीटर है। पिछली यूरोप की लड़ाई में जर्मनी ने पहले-पहल बेल्जियम को ही धर दबोचा था और इसी देश की भूमि पर यूरोप के सैनिकों के गून की नदियाँ बही थीं। बेल्जियम, शार्लमेन, पंचम चार्ल्स और नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्यों का भाग रहा और स्पेन, आस्ट्रिया, फ्रांस, और हॉलैंड की गुलामी करने के बाद उसे स्वाधीनता मिली। इतने थकनों की दासता में रह कर भी बेल्जियम ने किसी तरह अपनी हस्ती कायम रखी और फ्रांस की राजक्रांति होने पर उस ने सक्रम से कर बेल्जियम की राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वाधीनता का एलान कर दिया। ७ फरवरी, सन् १८३० ई० का दिन बेल्जियम के इतिहास में मुनहरा दिन था। उस दिन स्वाधीन बेल्जियम की राज-व्यवस्था को राष्ट्र ने स्वीकार कर के मेक्सकोवर्ग के लियोपोल्ड के गिर पर स्वाधीन बेल्जियम की सीमित राजाशाही का ताज रक्ता था। हॉलैंड ने बहुत हाथ-पाँव पीटे। मगर दूसरे राष्ट्रों ने उस की परवाह न कर के बेल्जियम को स्वाधीन राष्ट्र स्वीकार कर लिया।

बेल्जियम की इस राज-व्यवस्था के अनुसार देश को नौ प्रांतों में बाँटा गया और उन के विभाग करने और सीमाएँ बदलने के लिए नया कानून बनाने की जरूरत होने की शर्त लगा दी गई; और नागरिकों को भी बहुत-से अधिकार दिए गए। 'कानून के सामने सब को एक' माना गया; 'जाति और वर्ग-भेद' को सरकार की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया; सब को 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' मानी गई; बिना वारंट किसी को चौबीस घंटे से

अधिक कौद रखने की और किसी के घर और माल में हस्तक्षेप करने की सख्त मनाई कर दी गई, धार्मिक स्वतंत्रता, अस्वाभावों की स्वतंत्रता, बोलने, मिलने और सरकार से विनती करने की स्वतंत्रता भी सब को दी गई। जिस प्रकार गंगा की जन्मदानी गंगोत्री है उसी प्रकार सारी राजशक्ति की जन्मदानी, इस राज व्यवस्था में, जनता को ठहराया गया और इस शक्ति का उपयोग केवल राज व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही करने की शर्त रखी गई। कानून बनाने का अधिकार राजा, सिनेट और प्रतिनिधि सभा को मिला कर दिया गया। इन तीनों में से किसी को भी मसविदे पेश करने का अधिकार दिया गया, मगर रूपए पैसे के मसविदे और फौज-सम्बन्धी कानूनों का विचार पहले प्रतिनिधि सभा के सामने होना जरूरी रखा गया। सरकार की कार्यकारिणी की सत्ता इंग्लैंड की तरह राजा में मानी गई, मगर फ्रांस के प्रमुख की तरह वह शासन के किसी काम के लिए जवाबदार नहीं समझा जाता है, और उस का कोई हुक्म जब तक उस पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर न हों बाकायदा नहीं होता है। शासन के कामों के लिए जवाबदार मंत्री होते हैं। न्याय का शासन अदालतें करती हैं। मगर कानूनों का अर्थ व्यवस्थापक-सभा करती है। अमेरिका की तरह वेलजियम की कोई अदालत किसी कानून को राज व्यवस्था के विरुद्ध बता कर और कानूनी नहीं ठहरा सकती है। वेलजियम की सरकार सीमित राजाशाही है। सरकार पर प्रजा का पूरा कब्जा है और व्यवस्थापक सभा को हर बात का आखिरी अधिकार है। इस राज व्यवस्था को संशोधित करने के लिए यह जरूरी होता है कि पहले व्यवस्थापक सभा यह तय करे कि किन बातों का राज-व्यवस्था में बदलना या जोड़ना जरूरी है। यह तय हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाएँ भग हो जाती हैं। फिर जो नई सिनेट और प्रतिनिधि-सभा चुन कर आती हैं उन के सामने वे बातें पेश की जाती हैं। दोनों सभाओं में अलग अलग तीन-चौथाई से कम सदस्य हाजिर होने पर इन बातों पर विचार नहीं हो सकता है, और हाजिर सदस्यों के तीन-चौथाई से कम मत किसी प्रस्ताव के लिए मिलने पर भी वह स्वीकार नहीं होता है।

## २—व्यवस्थापक-सभा

वेलजियम की व्यवस्थापक सभा की दो शाखाएँ हैं—एक सिनेट और दूसरी प्रतिनिधि-सभा।

‘सिनेट—हर एक प्रांत से कुछ सदस्यों को मतदार और कुछ को प्रांतिक काउंसिलें सिनेट के लिए इस हिसाब से चुनते हैं कि पाँच लाख से कम आबादी के प्रांतों की तरफ से तीन और दस लाख की आबादी से बड़े प्रांतों की तरफ से चार सदस्य सिनेट में बैठने के लिए जावें। मतदारां द्वारा सीधे सिनेट के लिए चुने जानेवाले सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या से आधा रखी गई है। सिनेट के सदस्य आठ साल के लिए चुने जाते हैं और उन में से आधे हर चार साल बाद नए चुने जाते हैं।

रहनेवाला, १२०० फ्रांक

की आमदनी की जागीर रखनेवाला होना चाहिए। जिस प्रांत में सिनेट की उम्मीदवारी के लिए रखे हो सड़नेवालों की संख्या '५००० की आवादी के लिए एक' के हिसाब से कम होती है, उस प्रांत में यह हिसाब पूरा करने के लिए दूसरे कम कर देनेवालों में से सब से अधिक कर देनेवालों के नाम भी सूची में जोड़ दिए जाते हैं। इन नए लोगों को जहाँ उन के नाम दर्ज होते हैं वहाँ से रखे होने का हक होना है। कॉंसिलों से जो सिनेट के लिए सदस्य चुने जाते हैं, उन के लिए यह मिलक्रियत की शर्त जरूरी नहीं है। मगर यदि वे उस कॉंसिल के—जो उन्हें चुनती है—सदस्य हों या दो वर्ष पहले तक भी सदस्य रह चुके हों तो यह सिनेट के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। सिनेट के लिए खड़े होने-वालों की उम्र कम से कम चालीस वर्ष होनी चाहिए। सदस्यों को सिनेट में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। बेलजियम के युवराजों को १८ वर्ष की उम्र से सिनेट में बैठने और कारवाई में भाग लेने और २१ वर्ष की उम्र से मत देने का अधिकार होना है।

**प्रतिनिधि-सभा**—प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का चुनाव चार वर्ष के लिए होता है और उन की आधी संख्या सिनेट की तरह हर दो वर्ष बाद नई चुनी जाती है। २५ वर्ष के ऊपर के सारे अधिकारप्राप्त मर्द नागरिकों को अपने रहने की कम्यून में एक वर्ष तक रह चुकने पर प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के चुनाव में मत देने का हक होता है। एक से अधिक मत देने का अधिकार भी लोगों का होता है। पिवाहित पुरुषों, बाल-बच्चों-वाले रूढ़ियों को, जिन की उम्र ३५ वर्ष के ऊपर होती है और जो पाँच फ्रांक से कम गृहस्थी का कर नहीं देते हैं, २५ वर्ष से ऊपर के उन लोगों को जिन के पास कम से कम २००० फ्रांक की कीमत की असल जागीर होती है, या इस कीमत की ज़मींदारी होती है, या जिन का नाम सरकार को कर्ज़ देनेवालों में होता है, या जिन का बेलजियम के सरकारी सेविंस बैंक में इतना रुपया होता है जिस से उन्हें कम से कम १०० फ्रांक का ब्याज मिलता हो, उन सब को चुनाव में एक-एक मत अधिक देने का अधिकार होता है। २५ वर्ष से ऊपर के उन लोगों को जिन के पास ऊँची शिक्षा प्राप्त करने का, या सेकेंडरी का ऊँचा दर्जा पास करने का अधिकार-पत्र होता है, अथवा जो ऐसे अधिकार या धर्म में होते या रह चुके होते हैं जिस में सेकेंडरी शिक्षा के ऊँचे दर्जे की योग्यता की जरूरत होती है, उन सब को दो-दो मत अधिक देने का अधिकार होता है। मगर किसी को तीन से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता है। सब मतदारों को मत के अधिकार का उपयोग करना जरूरी होता है और जो इस अधिकार का उपयोग नहीं करता है, उस पर २५ फ्रांक जुर्माने से ले कर मत देने और अधिकारी बनने के अधिकार तक छीन लेने का दंड सरकार कर सकती है। आवादी के हिसाब से कानून के अनुसार प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या तय कर दी जाती है। मगर चालीस हजार की आवादी के लिए एक प्रतिनिधि से अधिक संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। सदस्यों को बेलजियम के अधिकार-प्राप्त नागरिक, देश में रहनेवाला, और कम से कम २५ वर्ष की उम्र का होना चाहिए। सदस्यों को ५००० फ्रांक खालाना का भत्ता और सभा में आने-जाने के लिए मुफ्त रेल की सवारी दी जाती है।



### ३—राजा और मंत्री

सेक्स-कोथम के राजघराने को वेलजियम की गद्दी पर बैठने का मौलसी अधिकार है। राजा को कानूनों के अनुसार सिर्फ़ सीमित राजाशाही के अधिकार हैं और इन कानूनों के भीतर ही राजा को रहना पड़ता है। उस का कोई हुक्म बिना किसी मंत्री की सही के जायज़ नहीं माना जाता है। इंग्लैंड की तरह राजा मंत्रियों के हाथ का गुद्दा होता है। मंत्री प्रतिनिधि-सभा के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं और उन्हीं को सरकार के सारे अधिकार होते हैं। राजा मंत्रियों को नियुक्त करता और निकालता है सही। मगर वह उन्हीं को नियुक्त करता है जिन की प्रतिनिधि-सभा में बहुसंख्या होती और जब तक वह बहुसंख्या रहती है, तब तक उन को नहीं निकाल सकता है। उसी प्रकार राजा कानूनों के स्वीकार और अमल के लिए एलान करता है। मगर वह कानूनों को रोक या बंद नहीं कर सकता है। राजा जल और थल सेना का सेनाधिपति होता है और युद्ध, संधि और मैत्री करने के उसे अधिकार माने गए हैं। मगर जिन संधियों से वेलजियम के किसी नागरिक पर कोई व्यक्तिगत असर पड़ता है, वह बिना व्यवस्थापक-सभा के सामने लाए नहीं की जा सकती हैं। व्यवस्थापक-सभा की बैठकें आम तौर पर नवंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होती हैं। मगर राजा उन को पहले भी बुला सकता है। उस को दोनों सभाओं को मंग करने और सभाओं की बिना राय के एक बैठक में एक बार और अधिक से अधिक एक मास तक स्थगित कर देने के भी अधिकार हैं।

वेलजियम में परराष्ट्र, यह, कलाविज्ञान, खेती-बारी, उद्योग और भ्रम, न्याय, अर्थ, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, युद्ध, रेल इन दस विभागों के दस मंत्री होते हैं। इंग्लैंड की तरह प्रतिनिधि-सभा की बहुसंख्या के मंत्री नेता होते हैं। मगर फ्रांस की तरह उन्हें दोनों सभाओं में बोलने का अधिकार होता है। सभाओं को भी उन को सभा में हाज़िर रखने का अधिकार होता है। फ्रांस की तरह उन से प्रश्न पूछने और उन प्रश्नों पर चर्चा चला कर मंत्रियों पर विश्वास और अविश्वास दिखलाने का अधिकार भी सदस्यों का होता है। हर प्रतिनिधि-सभा शुरू में ही फ्रांस के चेंबर के ब्यूरो की तरह छः भागों में बंट जाती है। और हर महीने इन भागों के सदस्य पत्ती डाल कर बदलते रहते हैं। सारे मसविदे पहले इन भागों के पास जाँच के लिए भेजे जाते हैं। अगर किसी मसविदे की जाँच के लिए सभा कोई खास कमेटी बनाती है, तो वह उस के पास भेजा जाता है क्योंकि सभा को खास कामों के लिए खास कमेटियाँ बनाने का भी हक होता है। हर ब्यूरो अपना एक रिपोर्टर चुन लेता है। ब्यूरो के छः रिपोर्टरों और प्रतिनिधि-सभा के अध्यक्ष की एक 'केंद्रीय कमेटी' होती है जो अपना एक रिपोर्टर अलग चुनती है। सभा की दो चुनी हुई स्थायी कमेटियाँ रहती हैं। एक 'स्पष्ट-पैसे और हिसाब-किताब' की कमेटी और दूसरी 'खेती, उद्योग और व्यापार' की कमेटी।

### ४—न्याय-शासन

सारे वेलजियम के लिए सब से बड़ी एक अदालत जिस को फ्रांस की तरह सेसेशन

कोर्ट कहते हैं, देश की राजधानी ब्रूसेल्स में बैठती है। उस के जजों को राजा दो सूचियों में से चुन कर नियुक्त करता है। एक सूची खुद अदालत की तरफ से बना कर भेजी जाती है और दूसरी सिनेट भेजती है। इस अदालत के नीचे तीन अदालतें अपील की होती हैं, जिन के जजों को राजा उन्हीं अदालतों और प्रांतिक कौंसिलों की भेजी हुई दो सूचियों में से चुन लेता है। उन के बाद वे अदालतें आती हैं, जिन में मुकदमे लिए जाते हैं। उन के जजों को राजा खुद नियुक्त करता है। मगर उन के प्रधान और उपप्रधानों को अदालतों और प्रांतिक कौंसिलों को भेजी हुई सूचियों में से चुनता है। इन के निवाय और बहुत-सी फौजदारी की, सैनिक और व्यापारी अदालतें भी होती हैं। मगर फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों की तरह शासकी अदालतें बेल्जियम में नहीं होती हैं। जजों को जिदगी भर के लिए नियुक्त किया जाता है और बिना उन का अपराध, साधित किए उन को निकाला या मुक्तवी नहीं किया जा सकता है। उन का तबादला भी बिना उन की मर्जी या उन को दूसरा पद दिए नहीं किया जा सकता है।

### ५—राजनैतिक दल

पिछले यूरोपीय युद्ध तक बेल्जियम में 'कैथोलिक दल' और 'उदार दल' दो ही राजनैतिक दल जोरदार थे। कभी एक का मंत्रिमंडल होता था तो कभी दूसरे का। 'कैथोलिक दल' शुरू में जोरदार था। बाद में 'उदार दल', उस से जोरदार हो गया था। उन्नीसवीं सदी भर 'उदारदल' का ही प्रभाव बेल्जियम की राजनीति पर रहता था। मगर बीसवीं सदी में 'समाजवादी दल' का जोर बढ़ने से 'उदारदल' का जोर घट गया है। लड़ाई के बाद से किसी एक दल का 'मंत्रि-मंडल' बेल्जियम में नहीं होता है। फ्रांस की तरह यहाँ भी कई दलों का मिला कर आम तौर पर 'मंत्रि मंडल' बनाया जाता है। 'समाजवादी दल' भ्रमजीवियों की उन्नति करना चाहता है; मगर वह गरम विचारों और समष्टियादियों का घोर विरोधी है। एक 'समष्टिवादी दल' भी है। लड़ाई के बाद बेल्जियम के टुकड़े करके एक नया 'फ्लेमिश राष्ट्र' बनाने के उद्देश से एक 'सामना दल' भी बना था। मगर बेल्जियम के सब से ज़रूरतजन राजनैतिक दल, 'कैथोलिक दल' और 'समाजवादी दल' दो ही हैं।

## जर्मनी की सरकार

### १—साम्राज्य की राज-व्यवस्था

इटली की तरह जर्मनी भी बहुत-सी रियासतों में बँटा हुआ था और इन सब रियासतों को मिला कर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की कठिन समस्या इस देश को भी नज़रानी पड़ी थी। रोमन साम्राज्य की शक्ति का हास हो जाने पर जिस दिक्कत-बटी धागे में रियासतें बँधी थी, वह भी टूट गया था। उन्नीसवीं सदी के शुरू में लगभग तीन सौ से अधिक छोटी-बड़ी रियासतों पर खुदमुखतार राजाओं का निरंकुश राज्य हो गया था जो साम्राज्य के जिक्र पर मुँह चिढ़ाते थे और देश के हित से अपने हित को ही धिक् समझते थे। जर्मनी का आर्थिक जीवन संघों, नगरों, प्रांतों और राजाओं के जाले फँसा पड़ा था। आर्थिक क़रीब लोग गुलाम थे। नौकरशाही और सैनिकशाही का तूती लता था। लोग अज्ञान और उदासीनता में डूबे हुए थे। इंग्लैंड और फ्रांस की तरह जनैतिक जीवन के विकास के जर्मनी में कहीं कोई चिन्ह नहीं थे। नेपोलियन की झाड़्यों से जर्मनी को यह फायदा हुआ कि बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतें खत्म हो गईं और वियाना की कांग्रेस के सम्मेलन के अनुसार रोमन साम्राज्य के स्थान में जर्मनी में जर्मनी की बाकी बड़ी रियासतों के एक संघ का राज्य कायम हुआ। सन् १८१५ ई० जर्मनी आस्ट्रिया की अध्यक्षता में लगभग ३८ खुदमुखतार रियासतों का एक संघ था। संघ में शासन का कोई एक आम तरीका नहीं था। सब रियासतों में अपना-अपना अच्छा-बुरा चलता था। संघ की एक आम-सभा जरूर होती थी। मगर उस में विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि सिर्फ़ एलचियों की तरह आपस में मिल कर सलाह करने के लिए

थे। इस सभा का रियासतों पर कोई अधिकार नहीं था। धीरे धीरे प्रशिया की रियासत तृत्व में चुगीकरी के लिए एक आम योजना बनी और इस आर्थिक एकीकरण से जर्मनी के राजनैतिक एकीकरण में भी आसानी हुई। वियाना की कांग्रेस में निश्चय हुआ कि जर्मनी के सघ की सारी रियासतों को अपने अपने यहाँ लिखित राज-व्यवस्था और थापक समाएँ कायम करनी चाहिए। सन् १८१६ ई० से शुरू हो कर धीरे धीरे लगभग रियासतों को राजव्यवस्था दे दी गई थी और यह व्यवस्थाएँ पिछली यूरोप की लड़ाई कायम रही। यह राज-व्यवस्थाएँ प्रजा-सत्ता के उदार सिद्धांत पर नहीं गढ़ी गई थी जर्मनी की सघ से उड़ी दो रियासतें प्रशिया और आस्ट्रिया, ने अपने यहाँ कोई राज-व्यवस्था कायम नहीं की थी। जर्मनी में बहुत से उदार विचारों के लोग अपने देश में प्रजा-सत्ता व्यवस्थापन-सभाओं का राज देखना चाहते थे। मगर आस्ट्रिया के कठनीतिज्ञ मनी-नेख के प्रभाव ने सारे मध्य यूरोप को राहु की तरह ब्रस रक्खा था। जहाँ-कहाँ उदार-राजों के लोग जरा भी सिर उठाने का प्रयत्न करते थे, वहाँ उन को मेटरनिख के इशारे पर कुचल दिया जाता था।

फिर भी अदर अदर आम सुलगती रहती थी। स्वयं आस्ट्रिया की राजधानी वियाना तक में उपद्रव हो जाते थे। जब सन् १८४८ ई० में फ्रांस में राज्यक्रांति हुई तब भी वियाना में भी चारा और आम भड़क उठी। जहाँ-तहाँ रियासतें घबरा कर प्रजा को अधिकार-सभाएँ लगीं। आखिरकार सन् १८१५ ई० की संधियोजना की, राष्ट्र के विचार से, पुनर्घटनाओं का विचार करने के लिए प्रजा के ५८६ प्रतिनिधियों का—पचास हजार की आबादी वाले एक प्रतिनिधि के हिसाब से—कॉन्फर्ट में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में भर से सिर्फ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि ही आए थे और सरकार या राजाओं की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इस प्रकार की सभा जर्मनी के इतिहास में पहली ही बार पैठी थी। मगर इस सम्मेलन के सदस्य इतने विभिन्न विचारों के कि वे आपस में मिल कर शीघ्र ही कोई एक राज व्यवस्था नहीं तैयार कर सके। वे वर्षों तक छोटी छोटी बातों पर ही आपस में झगड़ते रहे। और इस बीच में रियासतों की ओर से प्रजा को दबा दिया जन सम्मेलन ने अपनी व्यवस्था तैयार कर के पेश की निरंकुश राजा गुराने लगे। इस सम्मेलन में करीब दो सौ प्रजातन्त्रवादी सदस्य थे। फिर भी नई राज-व्यवस्था में एक वैध साम्राज्य, दो-सभा की एक व्यवस्थापक-सभा, साधारण के मताधिकार और उत्तरदायी मंत्रिमंडल की व्यवस्था रखी गई थी। केवल रियासतों ने इस राज व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। मगर जिन बड़ी रियासतों की बिना मजूरी के इस राज व्यवस्था का सफल होना एक क्षण के लिए भी संभव नहीं था उन में से एक ने भी इस को स्वीकार नहीं किया था। जब सम्मेलन की ओर से तैयार की गई राजा को राजछत्र की भेंट की गई तो उसे ने उसे यह कह कर लेने से इन्कार दिया कि “राजछत्र अमीरों के और मेरे हाथों में है। प्रजा को मुझे राजछत्र देने का अधिकार नहीं है।” अस्तु, यहाँ पर इस राजनैतिक नाटक का पटाक्षेप हो गया और इस बाद सन् १८१८ ई० तक फिर जर्मनी में प्रजासत्ता ने सिर ऊँचा नहीं किया।

सन् १८४८ ई० की इस क्रान्तिकारी लहर का इतना अच्छा नतीजा जरूर निकला कि प्रशिया के राजा ने अपनी रियासत में सन् १८५० ई० में एक राज व्यवस्था कायम की, जिस के अनुसार दो सभा की एक व्यवस्थापक सभा स्थापित हुई, सर्ग साधारण के एक काफी भाग को मताधिकार मिला और बहुत से व्यक्तिगत अधिकार प्रजा के माने गए। यही राज व्यवस्था प्रशिया में लड़ाई के बाद तक कायम थी। जर्मनी भर में एक प्रशिया ही ऐसी रियासत थी जहाँ किसी क्रिस्म की राज-व्यवस्था कायम थी और जहाँ प्रजा के थोड़े बहुत कुछ अधिकार माने जाते थे। अस्तु ! जर्मनी को 'एक सुसंगठित और प्रभावशाली राष्ट्र बनाने का स्वप्न' देखनेवाले देशभक्तों की आँखें प्रशिया की ओर उसी तरह लगी रहती थी जिस प्रकार इटली में देशभक्तों की आँखें पीयडमोंट रियासत की तरफ लगी रहती थीं। दूरदर्शी देशभक्तों का विचार था कि जर्मनी को एक राष्ट्र और जर्मनी में प्रजा सत्तात्मक सरकार की स्थापना किसी जोरदार जर्मनी की रियासत के द्वारा ही की जा सकेगी और उन्हें ऐसी रियासत एक प्रशिया ही दीवनी थी। अतएव बहुत दिनों तक जर्मन राष्ट्र का एकीकरण और उत्थान तथा प्रशिया की उन्नति का जर्मनी में एक ही अर्थ समझा जाता था। प्रशिया का राजा विलियम प्रथम अपनी सेना का अच्छी तरह संगठन कर के तलवार के तल पर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। मगर प्रशिया की व्यवस्थापक सभा ने उस का साथ नहीं दिया। उस ने बिस्मार्क को अपना प्रधान बनाया। बिस्मार्क ने सारा निरोध कुचल कर फोज का अच्छी तरह संगठन किया और जिस तरह केसर ने इटली की रियासतों को मिला कर एक राष्ट्र बनाया था उसी तरह उस ने आस्ट्रिया को जर्मन सभ से निकाल कर जर्मन रियासतों को प्रशिया के नेतृत्व में एक जर्मन राष्ट्र में मिला कर जर्मनी में सन् १८६७ ई० में एक राज व्यवस्था की स्थापना की। इस राज व्यवस्था के मुख्य अंग चार थे। पहला 'प्रेसीडियम' अर्थात् राष्ट्र की अध्यक्षता प्रशिया के राजघराने में मानी गई। दूसरा अध्यक्ष की सहायता के लिए एक फेडरल चांसलर अर्थात् 'सचीव प्रधान' रखा गया। तीसरी एक 'बंडसराय' नाम की राष्ट्रीय कौंसिल थी जिस में सब रियासतों के प्रतिनिधि थे। चौथी एक 'रीशटाग' नाम की सभा थी जिस में देश भर के पुरुषों के मतों से चुने हुए प्रतिनिधि थे।

जर्मनी के दक्षिणी भाग की चार रियासतें इस नई सभ में सम्मिलित नहीं हुई थीं। सन् १८७० ई० में फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई छिड़ने पर जर्मनी में देश प्रेम का उषान आने पर यह रियासतें भी प्रशिया की अध्यक्षता में नए जर्मन सभ में मिल गईं और 'उत्तरी जर्मन सभ' के स्थान में एक नया 'जर्मन साम्राज्य' सन् १८७१ ई० में स्थापित हो गया और इस साम्राज्य के अध्यक्ष प्रशिया के राजा का खिताब 'केसर जर्मन' हो गया। नई रियासतों के मिलने से पिछली राज व्यवस्था में तनदीली करने की भी जरूरत हुई और इस लिए इस राज व्यवस्था में फेरफार करके एक नई राज व्यवस्था गढ़ी गई। इस राज व्यवस्था की ७८ शर्तों में उन सब बातों का जिक्र है जो ग्राम तौर पर इस प्रकार के दस्तावेजों में होती हैं। जर्मन साम्राज्य को यूरोप की सब से बड़ी सैनिक शक्ति बनाने के इरादे से सड़के, कर, तार और सेना इत्यादि केंद्रीय सत्ता

के हाथ में रक्ती गई जिम से विभिन्न रियासते जर्मन साम्राज्य की उद्देश-पूर्ति के मार्ग में आड़े न आ सके। व्यवस्थापक सभा के बहुमत से राज व्यवस्था में फेरफार किया जा सकता था। परन्तु राज व्यवस्था के किसी सशोधन के विरोध में बडसराथ में चौदह मत पड़ जाने पर वह सशोधन अस्वीकार हो जाता था। अकेले प्रशिया के बडसराथ में सत्रह मत होने से प्रशिया का विरोध होने पर किसी सशोधन का स्वीकार होना असंभव था। अगर प्रशिया किसी सशोधन के पक्ष में हो तो उस के विरुद्ध चौदह मत इकट्ठा करना मुश्किल होता था। सन् १८७३ ई० से १९१४ ई० तक इस राज व्यवस्था में वाक्यामदा सशोधन तो सिर्फ ग्यारह बार ही किया गया, मगर और सत्र देशों की तरह साधारण कानून और रिवाज इत्यादि द्वारा सरकार के रंग में फेरफार होते रहे।

पिछली लड़ाई तक जर्मन साम्राज्य में ६६ वर्ग मील की छोटी ब्रेमेन नगर की रियासत से ले कर प्रशिया की १३४६१६ वर्ग मील की बड़ी रियासत तक कुल मिला कर २५ रियासतें शामिल थीं। जर्मन साम्राज्य न तो पिछले राजाओं के सघ की तरह ही था और न प्रजा का बनाया हुआ ही था। पच्चीस रियासतों की बनाई हुई एक नई रियासत का नाम जर्मन साम्राज्य था। प्रभुता किसी एक रियासत में न रह कर जर्मन साम्राज्य की सरकार में थी। अर्थात् रीशदाग में प्रभुता नहीं थी, रियासतों की प्रतिनिधि बडसराथ में थी। नागरिकता, कर, भाषा, तोल, मुद्रा, पेटेंट, जल और थल सेना के सघ में हर प्रकार के कानून बनाने का पूरा अधिकार साम्राज्य को था। उसी तरह रियासतों को अपने बजट बनाने, पुलिस, मार्ग, जमीन और शिक्षा के सघ में हर तरह के कानून बनाने का पूरा अधिकार था। बीच के बाकी बहुत से विषयों में साम्राज्य और रियासतों दोनों का हाथ रहता था। मगर साम्राज्य के अधिकारों का क्षेत्र दिन दिन बढ़ता और रियासतों के अधिकारों का क्षेत्र घटता जाता था। परराष्ट्र, जलसेना, डाक और तार का सारा काम साम्राज्य की सस्थाएँ चलाती थीं। जाकी विषयों में साम्राज्य का काम रियासतों की सस्थाओं के द्वारा चलता था। सेना का नाम प्रशिया रियासत की सस्थाओं के हाथ में था। अमेरिका के संघीय राज्य का सारा राजकीय काम चलाने के लिए केंद्रीय सरकार की सस्थाएँ होती हैं। मगर जर्मनी में संघीय साम्राज्य की सरकार का बहुत-सा काम सहूलियत के लिए रियासतों की सस्थाओं के द्वारा ही चलाया जाता था। साम्राज्य की सरकार पर और चुगी लगाती थी और रियासतों की सरकारें उस को उगाती थीं। न्याय का शासन भी साम्राज्य के नाम पर नहीं होता था। रियासतों के न्यायाधीश और न्यायालय ही सारा न्याय का काम करते थे। साम्राज्य की सरकार में साम्राज्य की सस्थाएँ और रियासतों की सस्थाएँ दोनों ही शामिल थीं। जर्मन रियासतों का यह सघ कानून के अनुसार भग नहीं हो सकता था। साम्राज्य की सरकार को सघ से किसी रियासत को निकाल देने, किसी रियासत को विभाजित करने या उस को किसी दूसरी रियासत से मिलाने या बिना किसी रियासत की मर्जी के उस की हैसियत में किसी तरह का फेरफार करने का अधिकार नहीं था। किसी रियासत को भी साम्राज्य से अलग हो जाने अथवा अपनी हैसियत में फेरफार करने का अधिकार नहीं था। अगर कोई रियासत साम्राज्य के अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयत्न

करे तो बडसराथ की सलाह से साम्राज्य की सरकार को उस रियासत पर चढ़ाई करने के लिए सेनाएँ भेजने का अधिकार था ।

मगर सभ रियासतें बराबर की नहीं सम्झी जाती थीं । जितनी आयादी शेष चौकीस रियासतों की मिला कर नहीं थी उतनी अकेली प्रशिया की थी । प्रशिया ने सघ बनाने में मेहनत भी बहुत की थी । स्वभावतः प्रशिया का बहुत असर था । प्रशिया का राजा साम्राज्य का शहशाह था । प्रशिया की वोटें बडसराथ में सभ मसविदों को हरा सकती थीं । परराष्ट्र कमेटी को छोड़ कर बडसराथ की सब कमेटियों की अध्यक्षता प्रशिया के हाथ में थी । राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार साम्राज्य की सेना का संगठन और संचालन भी शहशाह और प्रशिया की रियासत के हाथ में रहता गया था । सन् १६४४ ई० तब न तो कोई जर्मन सेना थी और न कोई जर्मन युद्ध सचिव । सभ रियासतों में अलग अलग सेनाएँ थीं और उन का संगठन और संचालन प्रशिया की अध्यक्षता में होता था । कुछ दूसरी रियासतों ने भी सघ में मिलते वक्त अपने हाथ में कुछ अधिकार रखने की शर्तें कर ली थीं और उन शर्तों के अनुसार कुछ रियासतों को अपनी डाक, तार, कर और रेलवे पर अधिकार थे । रियासतों को दूसरे देशों में अपने अपने एलची भेजने का अधिकार भी था । मगर एक दो रियासतों को छोड़ कर लगभग सभी ने अपने अलग एलची भेजना बंद कर दिए थे ।

## २—शहशाह कैसर

जर्मन-साम्राज्य की राज व्यवस्था के अनुसार प्रशिया का राजा जर्मनी का शहशाह माना गया था । प्रशिया के राजा की हैसियत से उस की जो कुछ जागीर थी, उस के सिवाय शहशाह की हैसियत से उस को और कोई जागीर नहीं दी गई थी । शहशाह का न कोई अलग ताज था, न उस का कोई अलग खजाना, और न कोई उस का अलग दर्जा । प्रशिया के राजा को केवल कैसर का खिताब दे कर जर्मन-साम्राज्य का अधिपति या शहशाह मान लिया गया था । जिस नियम और क्रम के अनुसार प्रशिया के राजा गद्दी पर बैठते थे उस के सिवाय शहशाह की गद्दी के और कोई नियम नहीं थे । परंतु जो प्रशिया की गद्दी का मालिक होता था, वही जर्मन साम्राज्य की राज व्यवस्था के अनुसार जर्मनी का शहशाह होने का हकदार हो जाता था । कैसर की व्यक्तिगत और कुल की रक्षा के लिए कुछ नियम जरूर थे । कैसर किसी को जवाबदार नहीं था । उस पर न तो किसी अदालत के सामने मुकदमा चलाया जा सकता था और न उस को कैसर पद से न्युत किया जा सकता था । उस के शरीर पर हमला करनेवाले के लिए पाँसी की सजा रखी गई थी और उस पर शब्दों से हमला करनेवाले को कड़ा दंड ।

प्रशिया के साम्राज्य की सब से बड़ी रियासत होने से, और बडसराथ में प्रशिया के बहुत से मत होने से, तथा प्रशिया के राजा के जर्मनी के शहशाह होने से साम्राज्य की नीति ढालने का शहशाह को बहुत मौका रहता था । अगर जर्मनी की किसी दूसरी छोटी रियासत के राजा को जर्मन साम्राज्य का शहशाह चुना गया होता तो शहशाह का साम्राज्य की नाति निश्चय करने में इतना हाथ कदापि न रहता । शहशाह को बडसराथ और

रीशटाग की सभाएँ बुलाने, रोलने, स्थगित और बंद करने का अधिकार था। कानून के अनुसार रीशटाग को भंग कर के एक मास के भीतर नई रीशटाग का चुनाव कराने का अधिकार बंडसराथ को था। मगर वास्तव में रीशटाग को शहंशाह बंडसराथ की मर्ज़ी से भंग किया करता था। बंडसराथ में पास हो जानेवाले मसविदे रीशटाग के सामने शहंशाह के नाम में पेश किए जाते थे। कानून के अनुसार शहंशाह को मसविदे पेश करने का कोई हक नहीं था, मगर वास्तव में इस हक का खूब प्रयोग होता था। कानून के व्यवस्थापक-सभा में पास हो जाने पर अमल के लिए एलान करने का अधिकार शहंशाह को था, मगर उन को नामंजूर करने का अधिकार उस को नहीं था। किसी नियम की पाबंदी न होने की बुनियाद पर किसी कानून को एलान करने से इन्कार करने का हक शहंशाह को था। चांसलर की सही से आर्डिनेंस निकालने का अधिकार भी उसे था।

बंडसराथ के प्रस्ताव पर साम्राज्य की मुख्य अदालत के न्यायाधीश नियत करने और अपराधियों को क्षमा देने का हक शहंशाह को था और शहंशाह ही साम्राज्य के कानूनों पर अमल करवाता था। अगर कोई रियासत साम्राज्य के नियमों के विरुद्ध काम करती थी, तो शहंशाह बंडसराथ के सामने शिकायत पेश कर के बंडसराथ की मर्ज़ी से उस रियासत पर चढ़ाई के लिए सेनाएँ भेज सकता था। चांसलर और अन्य अधिकारियों को नियत करने और निकालने का काम भी शहंशाह का ही था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में साम्राज्य का प्रतिनिधि कैसर होता था। साम्राज्य के नाम पर युद्ध छेड़ने और सुलह करने और साम्राज्य की तरफ से एलची भेजने और एलची लेने का काम भी कैसर ही करता था। जर्मनी का दुनिया भर में साम्राज्य कायम करने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कैसर ने अपने इन अधिकारों का अंत में खूब प्रयोग किया था। राज-व्यवस्था के अनुसार बिना शहंशाह की मर्ज़ी के कोई संधि नहीं की जा सकती थी और अधिकतर संधियाँ उसी के प्रस्ताव पर होती थीं। मगर उन संधियों को पूरा करने के लिए जो ऐसे विषयों के संबंध में होती थीं जो साम्राज्य के कानूनों के क्षेत्र में आते थे बंडसराथ के मत और उन पर अमल के लिए रीशटाग के मत की जरूरत होती थी। युद्ध छेड़ने के लिए भी शहंशाह पर बंडसराथ के मत की शर्त रखी गई थी। परंतु साम्राज्य पर एकदम हमला होने पर शहंशाह बिना बंडसराथ की सलाह लिए फ़ौरन् लड़ाई शुरू कर सकता था। अगर शहंशाह को लड़ाई छेड़ना ही हो तो बंडसराथ में प्रशिया के लगभग एक तिहाई से अधिक मतों की सहायता से 'साम्राज्य पर आक्रमण' का बहाना आसानी से पैदा किया जा सकता था। अस्तु सन् १८१४ ई० का युद्ध छेड़ने के लिए इसी बहाने को काम में लाया गया था।

साम्राज्य की सेनाओं का सेनाधिपति भी शहंशाह ही माना गया था। संघ कायम होने के समय प्रशिया के सिवाय और किसी रियासत के पास कोई जल-सेना नहीं थी। बाद में प्रशिया की यही जल-सेना बढ़ कर साम्राज्य की बड़ी भारी जल-सेना हो गई। मगर वह हमेशा प्रशिया के अधिकारियों के ही हाथों में रही। हर एक रियासत की जल-सेना अलग-अलग थी और उन रियासतों के राजा अपनी-अपनी सेना के सेनापति माने गए थे। परंतु इन सेनाओं की भर्ती, संगठन, कवायद और व्यवस्था साम्राज्य के कानूनों के अनुसार होती



थी। इन सेनाओं की संख्या का निश्चय साम्राज्य की धारा-सभा करती थी और उन का खर्च साम्राज्य के खजाने से दिया जाता था। शहंशाह कैसर सारी सेनाओं का सेनाधिपति माना जाता था और उस को अधिकारियों को नियुक्त करने, सेनाओं का मुआयना करने, इकट्ठा करने और युद्ध के समय जिस तरह चाहे इस्तेमाल करने का अधिकार था। जर्मन-साम्राज्य का कोई युद्ध-सचिव नहीं था। प्रशिया का युद्ध-सचिव ही साम्राज्य का सारा काम चलाता था। इस प्रकार जर्मन-साम्राज्य की सारी महान् सेना लड़ाई के लिए एक-रूप संगठित सेना थी, और शहंशाह कैसर को उस को ले कर दुनिया पर चढ़ाई कर देने का अधिकार था, जैसा कि उस ने अभिमान में चूर हो कर सन् १९१४ ई० में करने का प्रयत्न किया।

### ३—चांसलर

जिस स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य में मंत्री-मंडल होता है, उस पर जर्मन-साम्राज्य में सिर्फ एक अधिकारी होता था, जिस को चांसलर कहते थे। चांसलर को शहंशाह नियुक्त करता था। चांसलर बंडसराय का अध्यक्ष होता था, और बंडसराय का सारा काम-काज उस की देख-रेख में होता था। शहंशाह का कोई हुक्म जब तक उस पर चांसलर की सही नहीं होती थी याकायदा नहीं समझा जाता था। शहंशाह के हुक्म पर चांसलर की सही हो जाने से हुक्म की जिम्मेदारी चांसलर की हो जाती थी। चांसलर बंडसराय का सदस्य होता था। अगर शहंशाह किसी ऐसे आदमी को चांसलर नियुक्त करना चाहता था, जो बंडसराय का सदस्य नहीं होता था तो उस को वह प्रशिया की सरकार की ओर से बंडसराय में जानेवाले प्रतिनिधियों में प्रशिया के राजा की हैसियत से आत्तानी से नामजद कर सकता था। बंडसराय में प्रशिया की सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से चांसलर दूसरे प्रशिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रशिया के राजा का प्रतिनिधि समझा जाता था। बंडसराय के अध्यक्ष की हैसियत से चांसलर बंडसराय की बैठकों की तारीखें निश्चित करता था। रियासतों और रीशटाग से बंडसराय के लिए जो कागजात आते थे वह सब उस के पास आते थे। हर अवसर पर वह बंडसराय का प्रतिनिधि समझा जाता था। जो मसविदे बंडसराय में पास हो जाते थे उन को शहंशाह के नाम से वह रीशटाग के सामने विचार के लिए पेश करता था और चांसलर की हैसियत से नहीं बल्कि बंडसराय के एक साधारण सदस्य की हैसियत से रीशटाग में वह मसविदों पर चर्चा में भाग लेता था। कानून पास हो जाने के बाद जब उन को चांसलर शहंशाह के नाम में एलान कर देता था तभी उन पर अमल हो सकता था।

शासन का अधिकतर काम रियासतों की सरकारों द्वारा चलता था। मगर सारे शासन की वागडोर का आखिरी सिरा चांसलर के हाथ में रहता था। शासन का सारा अधिकार शहंशाह के बाद चांसलर को ही होता था। शहंशाह उस को नियुक्त करता था। शहंशाह के सिवाय और उस को कोई निकाल नहीं सकता था। शहंशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से वह शासन का काम चलाता था। पश्चिम की सरकारों में उस की बराबरी का और कहीं कोई अधिकारी नहीं था।

चांसलर के नीचे साम्राज्य का शासन चलाने के लिए बहुत-से शासन विभाग होते थे। इन विभागों के अधिपति चांसलर नियुक्त करता था और वह चांसलर को शासन-कार्य के लिए जवाबदार होते थे। दूसरे देशों के मंत्रि मंडल के सदस्यों की तरह उन का चांसलर के साधियों का दर्जा नहीं माना जाता था। कई विभाग-पतियों को मंत्री का खिताब होने पर भी वह चांसलर को ही जवाबदार होते थे। जर्मन साम्राज्य के खास शासन विभागों में पर-राष्ट्र विभाग, उपनिवेश विभाग, गृह विभाग, अर्थ विभाग, जलसेना विभाग और डाक विभाग यह सात विभाग थे। रेल्वे, रैंक और कर्ज इत्यादि के शासन के लिए कई कमेटियाँ भी थीं। राज-व्यवस्था में शहशाह के हुक्म पर चांसलर की सही होने की शर्त में इस बात का जिक्र भी था कि चांसलर की सही हो जाने से जिम्मेदारी चांसलर की हो जाती है। मगर इस जिम्मेदारी का इंग्लैंड या फ्रांस की मंत्रियों की जिम्मेदारी के मुकाबले में कुछ अर्थ नहीं था। इंग्लैंड और फ्रांस में मंत्रियों की जिम्मेदारी का अर्थ यह होता है कि अगर व्यवस्थापक-सभा को मंत्रियों के काम में विश्वास न रहे तो मंत्रियों से व्यवस्थापक-सभा इस्तीफा ले सकती है। मगर जर्मन साम्राज्य के मंत्री सिर्फ चांसलर को जवाबदार होते थे और चांसलर शहशाह को। रीशलांड के चांसलर के विरुद्ध हो जाने पर भी उस को इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता था।

### ४—व्यवस्थापक-सभा : (१) बंडसराथ

जिस प्रकार चांसलर के मुकाबले का यूरोप में और किसी जगह कोई अधिकारी नहीं था उसी तरह बंडसराथ की तरह कोई दूसरी सभा भी नहीं थी। हाउस ऑफ़ लार्ड्स की तरह अथवा फ्रांस की सिनेट की तरह जर्मन साम्राज्य की बंडसराथ व्यवस्थापक-सभा की सिर्फ ऊपरी सभा नहीं थी। बंडसराथ जर्मन साम्राज्य की केंद्रीय सस्था थी और उस को कानून, शासन, परामर्श, न्याय और बूटनीति इत्यादि के बहुत से अधिनार थे। बंडसराथ के सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि होते थे जिन को रियासतों के राजा या सिनेट नियुक्त करती थी। बंडसराथ में कुल मत ६१ थे जिन में से राज-व्यवस्था के अनुसार प्रशिया के १७, बवेरिया के ६, सैक्सनी के ४, वर्टेबर्ग के ४, वेडन के ३, हेसे के ३, मेकलेंबर्ग श्वेरिन के २, ब्रूसविक के २, रीशलैंड के ३ और बाकी सत्रह रियासतों से एक एक। ब्रूसविक के दो मत और चाल्डेक रियासत का एक मत आपस में रियासतों के समझौते से, हमेशा प्रशिया को मिलते थे। रीशलैंड के गवर्नर को शहशाह नियुक्त करता था और गवर्नर बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करता था। अस्तु रीशलैंड के ये तीन मत भी प्रशिया के ही हाथ में रहते थे। मगर कानून में यह शर्त रक्ती गई थी कि रीशलैंड के यह तीन मत, प्रशिया का किसी मामले में इन तीन मतों को छोड़ कर बहुमत न होने पर, अथवा बंडसराथ में मत बराबर बंट जाने पर और राज-व्यवस्था में सशोधन के प्रश्नों पर प्रशिया के पक्ष में नहीं गिने जायेंगे। अगर जन-सख्या के हिसाब से रियासतों में मत बाँटे गए होते तो प्रशिया को एक तिहाई के स्थान में आधे से अधिक मत मिलते, क्योंकि प्रशिया की आबादी और सत्रह रियासतों से मिला

कर अधिक थी। निस्मार्क ने, दूसरी रियासतों के मन से, यह डर दूर करने के विचार से कि जर्मन साम्राज्य-संघ में प्रशिया का राज्य हो जावेगा, प्रशिया के मत कम रखे थे। मगर राज व्यवस्था में संशोधन न करने की शक्ति चौदह मंत्रों में रख कर उस ने प्रशिया के हितों को प्रशिया के हाथों में सुरक्षित रखा था।

जिस रियासत के उडसराय में जितने मत थे उतने प्रतिनिधि उस को उडसराय में भेजने का अधिकार होता था। रियासतों के प्रतिनिधियों की कानून के अनुसार एलची की हैसियत होती थी और शहशाह को उन की एलचियों की तरह रक्षा करनी होती थी। आम तौर पर प्रतिनिधि रियासतों के मंत्री और बड़े अधिकारी होते थे। सभा की हर एक नई बैठक के लिए नए प्रतिनिधि रियासतों से चुने जाते थे। मगर पिछली लड़ाई से कई साल पहले से उडसराय की बैठक बराबर वैठी ही रहती थी, इस लिए प्रतिनिधि किसी भी समय भेजे और बुलाए जा सकते थे। प्रतिनिधि उडसराय में अपनी राय के अनुसार मत नहीं देते थे। उन की सरकार की जैसी हिदायत होती थी उसी के अनुसार वह मत देते थे। फिर भी उडसराय बिल्कुल एक एलचियों की सभा या सिर्फ विचार करने की जगह ही नहीं थी। रियासतों के मत जिस तरफ पड़ते थे एक साथ पड़ते थे। रियासत के प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि भी अपनी रियासत की ओर से सारे मत दे सकता था, क्योंकि मत देने के लिए सारे प्रतिनिधियों के राजिर होने की जरूरत नहीं होती थी। प्रशिया के बीच मत हमेशा एक साथ पड़ने से प्रशिया की बात हर काम में चलती थी। कभी-कभी छोटी रियासतें मिल कर प्रशिया के प्रस्तावों को किसी विषय पर हरा भी देती थी।

उडसराय की सभा की बैठक शहशाह अर्थात् शहशाह के नाम पर चांसलर जन चाहे तब बुला सकता था। चांसलर या उस की गैरहाजिरी में जिस सदस्य को वह नियुक्त कर दे वह सभा का अध्यक्ष होता था। हर रियासत की तरफ से विचार के लिए मसविदे पेश किए जा सकते थे। शहशाह को विचार के लिए कोई मसविदा पेश करने का हक नहीं था। मगर शहशाह कोई मसविदा चाहता था तो प्रशिया के राजा की हैसियत से अपनी रियासत के प्रतिनिधियों द्वारा उस मसविदे को पेश करा सकता था। सभा की बैठक आम तौर पर उद होती थी। एकसर सभा खत्म होने पर सभा की कार्यवाही की एक मुस्तसर रिपोर्ट अखबारों को दे दी जाती थी। अगर सदस्या की इच्छा नहीं होती थी, तो वह रिपोर्ट भी नहीं भेजी जाती थी। आम तौर पर किसी मामले के निश्चय के लिए ६१ मतों की बहुसंख्या काफी होती थी। बराबर मत पेट जाने पर प्रशिया के प्रतिनिधियों को फैसला करने का अधिकार हो जाता था। दो बातों में ६१ मतों की सिर्फ बहुसंख्या से फैसला नहीं किया जा सकता था। एक तो राज-व्यवस्था में किसी संशोधन के विरुद्ध १४ मत होने पर वह संशोधन स्वीकार नहीं हो सकता था। दूसरे जल थल सेना और कुछ बरा के संघ में मतभेद होने पर अगर प्रशिया प्रचलित प्रणय की तरफदारी करता था तो उस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।

अधिकतर उडसराय का काम व्यवस्थापन-सभा की निचली सभा रीशट्राग के विचार के लिए मसविदे तैयार करना होता था। वह काम ज्यादातर उडसराय की कमेटियों

में होता था। बडसराय की चारह स्थायी कमेटियाँ थीं—आठ राज-व्यवस्था की शक्तों के अनुसार और चार स्थायी नियमों के अनुसार। सेना और कोट, जल सेना, चुगी और कर, व्यापार, रेल, तार और डाक, न्याय, हिसाब-किताब और परराष्ट्र-विषय की आठ स्थायी कमेटियाँ साल भर के लिए राज-व्यवस्था के अनुसार बना ली जाती थीं। बडसराय गुप्त मत डाल कर निश्चय कर देती थी कि किस कमेटी पर किस रियासत के प्रतिनिधि रहें और फिर उन कमेटियों पर प्रतिनिधि नामजुद करने का काम उन रियासतों पर छोड़ दिया जाता था। मगर 'जलसेना-कमेटी' के सारे सदस्यों और 'सेना और कोट-कमेटी' के एक को छोड़ कर और सत्र सदस्यों को शहशाह नियुक्त करता था। हर कमेटी में सात सदस्य और कम से कम पाँच रियासतों के प्रतिनिधि रहते थे। जलसेना-कमेटी में सिर्फ पाँच सदस्य होते थे। सत्र कमेटियों के अध्यक्ष प्रशिया के होते थे। एक सिर्फ 'परराष्ट्र-विषय-कमेटी' की अध्यक्षता व्हेरिया के हाथ में थी।

जर्मन-साम्राज्य की फेंद्रीय सस्था होने से बडसराय सत्र तरह का राज-कार्य करती थी और उस को सत्र तरह के बहुत से अधिकार थे। राज-व्यवस्था के अनुसार कानून बनाने का काम बडसराय और रीशटाग दोनों का था। मसविदे शुरू करने का काम रास-तौर पर रीशटाग का रहता गया था। मगर अमल में आम-तौर पर हमेशा बडसराय मसविदे पेश करती थी। अर्थ-सत्र की मसविदे तक पहले बडसराय में पेश होते थे। मसविदे बडसराय में तैयार और पास हो कर रीशटाग के पास विचार और मजूरी के लिए आते थे और कानून बन कर शहशाह के एलान करने से पहले फिर एक बार वे बडसराय के पास जाँच और विचार के लिए भेजे जाते थे। हर हालत में कानून बनने से पहले हर मसविदे की आखिरी मजूरी बडसराय में होती थी। यह कहना अनुचित न होगा कि रीशटाग की सिर्फ मजूरी होती थी और कानून बनाती बडसराय थी। साम्राज्य के कानूनों के शासन का कोई और कानूनी प्रबंध न होने पर बडसराय ही उन का शासन करती थी और जहाँ कहीं साम्राज्य के कानूनों में छुटियाँ नज़र आती थीं उन को आर्डर-नंसें के द्वारा पूरा करती थी। देश पर आक्रमण होने के सिवाय शहशाह अपने युद्ध छेड़ने, अपराधी रियासत पर हमला करने और साम्राज्य के कानूनों के क्षेत्रों में आनेवाले विषयों के सन्ध में सधियाँ करने के अधिकारों का बिना बडसराय की सलाह के प्रयोग नहीं कर सकता था। शहशाह की सलाह से बडसराय रीशटाग को भंग कर के नया चुनाव करा सकती थी। बडसराय के सदस्यों को अपनी रियासतों के हितों के संबंध में रीशटाग में जा कर चर्चा में भाग लेने का अधिकार था। बडसराय साम्राज्य का सालाना वजट तैयार करती थी, साम्राज्य की रियासतों का रकता जाँचती थी और 'शहशाही बैंक' और 'शह-शाही कर्ज-कमीशन' पर देख-रेख रखती थी। 'शहशाही अदालत' के न्यायाधीश शहशाह बडसराय की राय से नियुक्त करता था। रियासतों की अदालत में न्याय न मिलने पर उन अदालतों की अपीलें, साम्राज्य और रियासतों के झगड़े और व्यक्तिगत कानून के क्षेत्र में आनेवाले झगड़ों को छोड़ कर, रियासतों के आपस के झगड़े किसी एक पक्ष की शिकायत आने पर बडसराय के पास न्याय के लिए आते थे और उन पर बडसराय अदालत की

हैंसियत से विचार करती थी। किसी रियासत में जब कभी कोई ऐसा भगड़ा सड़ा होता था जिस के न्याय का प्रबन्ध उस रियासत की राज व्यवस्था में नहीं होता था, तो किसी एक पक्ष की प्रार्थना पर वह भगड़ा समझौते के लिए और अगर समझौता नामुमकिन हो तो साम्राज्य के कानूनों के अनुसार फैसले के लिए बडसराथ के सामने आता था। इतनी विभिन्न तारुत बडसराथ के हाथ में होने से स्वभावतः वेहें साम्राज्य की सब से शक्तिशाली सस्था थी। जर्मन-साम्राज्य के पक्षपाती कहते थे कि बडसराथ में सब रियासतों के सचिव होने से बडसराथ दुनिया की सब से अनुभवी और दक्ष धारा-सभा थी। वह यह भी मानते थे कि बडसराथ अन्य यूरोपीय व्यवस्थापक-सभाओं की 'ऊपरी सभाओं' की तरह संकुचित और अनुदार नहीं थी। परंतु यह कहना ठीक नहीं है। बडसराथ में रियासतों के राजाओं के नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि होते थे, जो स्वभावतः परिवर्तन के विरोधी होते थे। अस्तु बडसराथ प्रजासत्ता की पक्षपाती कभी नहीं हो सकती थी।

## ५—व्यवस्थापक-सभा : (२) रीशटाग

बडसराथ जिस प्रकार रियासतों की सरकारों की प्रतिनिधि थी, उसी प्रकार व्यवस्थापक सभा की 'निचली सभा' रीशटाग साम्राज्य की प्रजा की प्रतिनिधि समझी जाती थी। रीशटाग विभिन्न रियासतों की प्रजा की प्रतिनिधि नहीं मानी जाती थी बल्कि साम्राज्य की सारी प्रजा की सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि समझी जाती थी। जर्मन साम्राज्य में अगर प्रजा की धोड़ी बहुत आवाज़ कहीं थी तो वह रीशटाग में कही जा सकती थी। इंग्लैंड के 'हाउस ऑफ् कॉमन्स' या फ्रांस के 'चेंबर ऑफ् डेपुटीज़' की तरह शक्तिमान् सभा रीशटाग न होने पर भी वह दुनिया की महान धारा-सभाओं में से थी। राज व्यवस्था के अनुसार एक निश्चित तारीख पर सारे साम्राज्य में रीशटाग के लिए ३६७ प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। सारी जर्मनी को एक लाख की आबादी के चुनाव के जिलों में इस प्रकार बाँट दिया गया था कि कोई जिला दो रियासतों में फैला नहीं था। हर जिले से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। प्रतिनिधियों का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता था। दिवालियों, मुहताजों, नागरिकता के अधिकार छिन जानेवाले लोगों और सेना के नौकरों को छोड़ कर हर २५ वर्ष की उम्र के मर्द को अपने जिले में मत देने का अधिकार था। एक से अधिक मत कोई नहीं दे सकता था। कोई भी वाकायदा मतदार एक साल तक किसी रियासत में रह चुकने पर रीशटाग के लिए चुना जा सकता था। पाँच वर्ष खत्म होने से पहले ही रीशटाग भंग हो जाने पर साठ दिन के अंदर नया चुनाव हो कर भंग होने के नव्वे दिन के भीतर नई रीशटाग की सभा होना जरूरी था। हर चुनाव का जिला तहसीलों में बँटा हुआ था और हर तहसील के मतदारों की गणित्या तहसीलों में चुनाव से चार हफ्ते पहले सब के देखने के लिए रखा दी जाती थी। मतदारों के गुस्तरूप से मत देने का, कानून के अनुसार, खास इतजाम रक्खा गया था। अगर किसी उम्मीदवार को, जितने मत उस के जिले में पड़ते थे, उन की बहु-सख्या नहीं मिलती थी तो पंद्रह दिन बाद फिर मत पड़ते थे। दूसरी बार मत पड़ने पर

सिर्फ़ वे दो उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे जिन के पहले मत पर सत्र से अधिक मत मिलते थे। दूसरे मत पर दोनों में से जिस को अधिक मिलते थे वही चुन लिया जाता था। अगर दूसरे मत पर इत्तफ़ाक़ से दोनों को परस्पर परस्पर मत मिलते थे तो चिढ़ी डाल कर जिस का नाम निकलता था, वह चुना जाता था।

राज-व्यवस्था के अनुसार साल भर में एक बार रीशदाग की बैठके जरूर होती थीं। जिस समय पंडसराथ की बैठके न होती हों, उस समय रीशदाग की बैठक नहीं बुलाई जा सकती थी। जब शहशाह या चांसलर चाहे तब रीशदाग की सभा बुलाई जा सकती थी। शहशाह की ओर से सभा को बुलावा भेजा जाता था और शहशाह खुद या उस के नाम पर कोई उस का प्रतिनिधि उठे ठाट-बाट से सभा की बैठके खोलता था। रीशदाग की बिना मर्ज़ी के शहशाह तीस दिन तक रीशदाग की सभा मुलतवी कर सकता था और बडसराथ की सलाह से वह उस को भंग कर सकता था। रीशदाग की सभा में सदस्यों की अक्सर बहुत कम हाजिरी रहती थी। इस के शायद दो कारण थे। एक तो रीशदाग को अधिक सत्ता न होने से सदस्यों का उस के काम में अधिक दिल नहीं लगता था। दूसरे सदस्यों को खर्च के लिए भत्ता भी नहीं मिलता था। घरों से सभा-स्थल तक आने के लिए उन्हें सिर्फ़ रेल की सवारी मुफ़्त दी जाती थी। रिस्मार्क ने शुरू से ही सदस्यों के भत्ते का कट्टर विरोध किया था और समाजवादी सस्थाओं के अपने सदस्यों के गुज़ारे के लिए चढ़ा जमा करने पर, साम्राज्य की अदालत ने सदस्यों को इस प्रकार की सहायता देना तक गैरक़ानूनी करार दे दिया था। जब सभा में अक्सर कोरम तक मिलना असंभव हो गया तब सन् १६०६ ई० में बड़ी अनिच्छा से चांसलर ने रीशदाग के सदस्यों को ३००० मार्क सालाना साम्राज्य के खज़ाने से देना स्वीकार किया था।

रीशदाग अपने काम-काज के नियम खुद बनाती थी। रीशदाग का एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष और आठ मंत्री होते थे। चुनाव के बाद, रीशदाग की पहली बैठक में चार हफ़्ते के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव होता था। चार हफ़्ते बीत जाने पर पहली बैठकों के शेष समय के लिए दूसरा चुनाव होता था। रात में हर नई बैठकों के लिए नए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाता था। मंत्रियों का हर जलसे के शुरू में जलसे के पूरे समय के लिए चुनाव कर लिया जाता था। जिस दल की रीशदाग में बहुसंख्या होती थी उसी के यह सत्र अधिकारी चुने जाते थे। बैठक के प्रारंभ में सभा के सब सदस्यों को चिढ़ी डाल कर जहाँ तक मुमकिन होता था सात परस्पर के भागों में बाँट दिया जाता था। फ्रांस और इटली के व्युरो की तरह इन भागों का काम सदस्यों के चुनावों की जाँच और कमेटियाँ चुनना होता था। इटली के व्युरो हर दो मास और फ्रांस के हर एक मास बाद बदलते रहते थे। जर्मनी में वे सभा के पूरे समय के लिए चुने जाते थे। परंतु पचास सदस्यों के प्रस्ताव करने पर किसी समय भी सदस्यों की फिर से बाँट हो सकती थी। रीशदाग की एक 'चुनाव कमेटी' स्थायी होती थी। दूसरी कमेटियाँ जरूरत पड़ने पर सारे व्युरों से परावर-परावर के सदस्य ले कर, चुन ली जाती थीं। मगर अख़्तला में कमेटियों के सदस्यों की सूचियाँ दला के नेता जैसी बना देते थे उसी के अनुसार चुनाव हो जाता

या । कमेटियों का काम मसविदों पर प्राथमिक विचार करना, उन पर लोगों की गवाहियाँ लेना और रीशटाग के सामने रिपोर्ट पेश करना होता था । मगर सभी मसले कमेटियों के पास नहीं भेजे जाते थे ।

यूरोप की दूसरी व्यवस्थापक-सभाओं के ढंग पर सदस्य सभाभवन में अर्धचंद्राकार बैठते थे । सरकारी पक्ष के सदस्य अध्यक्ष की दाहिनी ओर और प्रजापक्षी सदस्य बाईं ओर बैठते थे । दाएँ-बाएँ दोनों ओर सामने की जगहें बडसराथ के सदस्यों के बैठने के लिए खास तौर पर रहती थीं । सभा का अध्यक्ष दलनदी से ऊपर माना जाता था और चर्चा में वह इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि पक्ष और विपक्ष में बोलनेवालों को एक दूसरे के बाद बराबर मौका मिलता रहे । सदस्य अपनी जगह या अध्यक्ष के सामने के चबूतरे से, जहाँ से चाहते थे अपनी इच्छा के अनुसार बोलते थे । तीस सदस्यों के प्रस्ताव पर 'चर्चा स्थगित' का प्रस्ताव लिया जा सकता था । रीशटाग की बैठकें कानून के अनुसार जनता के लिए खुली होती थीं । उस की चर्चा अखबारों में छपती थी । परन्तु स्थायी नियमों के अनुसार अध्यक्ष या दस सदस्यों के प्रस्ताव पर बंद बैठकें भी हो सकती थीं ।

जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक सभा दो सभा की व्यवस्थापक-सभा के सिद्धांत पर नहीं बनाई गई थी । जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक-सभा रीशटाग ही थी क्योंकि बडसराथ कानून बनाने के सिवाय और भी बहुत-सा ऐसा काम करती थी जो आम तौर पर यूरोप में व्यवस्थापक-सभा की किसी सभा को नहीं करना पड़ता । मगर चूँकि रीशटाग कानून बनाने का काम जर्मनी की अनोखी सस्था बडसराथ के नेतृत्व और दबाव में करती थी, रीशटाग का साम्राज्य की राजनीति पर बहुत कम असर रहता था । अधिकतर मसले पहले बडसराथ में ही पेश होते थे । रीशटाग के पास बाद में वे मसले विचार के लिए आने पर रीशटाग उन्हें कुछ दिन तक रोक या लटका जरूर सकती थी, मगर बिल्कुल उन को अस्वीकार नहीं कर सकती थी । रीशटाग के बडसराथ से आनेवाले मसलों को अस्वीकार करने का विचार दिखाने पर बडसराथ रीशटाग का भग करने की धमकी दे सकती थी । अस्तु, हमेशा रीशटाग को बडसराथ की बातें चुपचाप स्वीकार कर लेनी होती थीं । कार्य कारिणी पर भी रीशटाग का कोई दबाव या रोक नहीं थी । चांसलर और मंत्री कोई अपने कामों के लिए रीशटाग का जवाबदार नहीं होते थे । मंत्रियों से रीशटाग के सदस्य सवाल तक नहीं पूछ सकते थे । चांसलर से सवाल पूछे जा सकते थे । मगर वह सदस्यों के सवालों की इतनी कम परवाह करता था कि अक्सर जो दिन सवालों के लिए रक्ता जाता था उस दिन वह सभा में आने की भी तवलीफ नहीं करता था । प्रश्नों पर चर्चा के बाद कार्य कारिणी में विश्वास या अविश्वास बतलाने के प्रस्ताव का भी पीछे से नियम हो गया था । मगर इन प्रस्तावों का कार्यकारिणी पर अधिक असर नहीं होता था, क्योंकि जब तक शहशाह का विश्वास चांसलर पर रहता था तब तक उसे कोई हटा नहीं सकता था । रीशटाग के हाथ में सत्ता न होने से उस के सदस्यों को सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का ही काम अधिकतर रहता था । अस्तु बहुत से कमजोर चरित्र और तनियत के सदस्य सरकार

की खुशामद कर के अपना फायदा बनाने की विम में ही लगे रहते थे। बाद में तो देश के बहुत-से काबिल आदमियों ने रीशटाग में जाना तक छोड़ दिया था क्योंकि वे उस की निरी बातों की दूकान समझते थे। फिर भी लगातार कड़ी आलोचना कर के रीशटाग सरकार की नीति पर थोड़ा बहुत असर डाल सकती थी।

## ६—राजनैतिक दलबंदी और कायापलट

यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने के समय जर्मनी दुनिया के महान् राष्ट्रों में था। जर्मनी का उद्योग, व्यापार, धन दौलत, कृषि, विज्ञान, विद्वत्ता, कला, साहित्य, जल और थल सेना इत्यादि दुनिया की आँखें चौंधियाते थे। मगर सब तरह की इतनी तरक्की होने पर भी जर्मनी की सरकार निरी निरकुश थी। ऊपर से देखने में जर्मनी की सरकार इतनी निरकुश नहीं लगती थी। परन्तु वास्तव में वह दुनिया की दक्षियानूस से दक्षियानूस निरकुश सरकारों में से थी। फिर भी जर्मनी की सरकार का काम बड़ी दृढ़ता, होशियारी और योग्यता से चलाया जाता था और दुनिया की काबिल से काबिल सरकारों में उस की गिनती होती थी। लेखकों का कहना है कि जर्मनी की सरकार का शासन इतनी सुयोग्यता से चलता था कि अपने अच्छे से अच्छे दिनों में महान् रोम साम्राज्य या आजन्तल बृटिश साम्राज्य का शासन भी शायद ही चलता होगा। जर्मनी की सरकार के निरकुश रह जाने का मुख्य कारण यही हो सकता है कि अवसर आने पर प्रगतिशील राजनैतिक दलों के आपस में मेल न कर सकने से जर्मनी को एक और मजबूत राष्ट्र बनाने का काम प्रशिया की निरकुश सरकार और निरकुशता के कट्टर पुजारी बिस्मार्क के फौलादी हाथों में आ पड़ा था। बिस्मार्क ने अपनी सेना के जोर पर जर्मनी को बड़ा बनाया था। अस्तु, उस की सरकार का बल भी प्रजासत्ता के स्थान पर सेना की सत्ता पर ही फ़ायम रहा। जर्मन साम्राज्य की निरकुशता के वन से जंगरदस्त तीन स्थल कहे जा सकते थे। एक प्रशिया रियासत का 'होहेन जातेन' राजकुल जो जर्मन साम्राज्य की शहशाहियत का मालिक था। दूसरा 'जकर' नाम के बड़े बड़े ज़मींदारों और तालुक़ेदारों का दल। तीसरी प्रशिया के अधिकार में साम्राज्य की सुसंगठित महान् सेना। जर्मनी के लोगों की पर्मागरदारी की आदत और जर्मनी में जान बूझ कर फैलाए गए 'कल्तूर' का असर भी निरकुशता के लिए बड़ी उपयोगी चीज़ें थीं। जर्मन शब्द 'कल्तूर' का अनुवाद असम्भव है। इस एक शब्द में ज्ञान, सभ्यता, उत्साह, स्वभाव, महत्वाकांक्षा, सफलता और ध्येय सब का समावेश हो जाता है। पीढ़ियाँ तक जर्मनी के स्कूलों में बच्चों को एक 'कल्तूर' का पाठ दिया गया था। जर्मनी के नागरिकों के दिमाग में एक से विचार और दिलों में एक सा लोहा और लड़ाई भर दी गई थी। 'भगड़े से जीवन में प्रगति होती है' के सिद्धांत पर जर्मनी को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखनेवाले 'कल्तूर' से लीप्त जर्मनी की नई सत्तान सब राष्ट्रों से भगड़े का दिन-रात स्वप्न देखती थी।

पहले पहल हैद्देनजोर्न के राजकुल का स्वीटज़रलैंड के उत्तर में दसवीं सदी में जोर्न पहाड़ी पर एक किला था, जहाँ से वह अपनी जागीर पर शासन करता था। बाद



में यह तेजस्वी राजकुल बढ़ता-बढ़ता जर्मन साम्राज्य का शहशाह हो गया। इस राजकुल के राजा कठोर और कूटनीतिज्ञ होते थे और मित्र और शत्रु किसी के साथ व्यवहार में ज़रूरत पड़ने पर कुछ कसर नहीं उठा रखते थे। वे ईश्वर की ओर से अपने को राज्य का अधिकारी समझते, प्रजा सत्ता के विचारों को हिकारत से देखते और सेना को अपनी राजनीति का केंद्र मानते थे। कैसर विलियम दूसरा जो लड़ाई के शुरू होने पर जर्मनी का शहशाह था खुल्लमखुल्ला अपने व्याख्यानों में कहा करता था कि 'जर्मन जाति ईश्वर की चुनी हुई जाति है। जर्मन-साम्राज्य के शहशाह के रूप में मुझ में ईश्वर की आत्मा उत्तरी है। मैं उस का हथियार, उस की तलवार और उस का यारिस्त हूँ। जो मुझ में विश्वास नहीं करेंगे, उन का सर्वनाश। जर्मनी के प्रैरियों का सर्वनाश।' साम्राज्य भर की सेना कैसर के हाथ में थी। रियासतों या रीशटाग का सेना पर कुछ अधिकार नहीं था। सेना का उजड़ तक पाँच साल के लिए मजूर हो जाता था। सेना और अपने आप को कैसर दो कालिब और एक रूह की तरह मानता था और कहा करता था कि 'सेना ने जर्मन साम्राज्य बनाया है, व्यवस्था सभा की बहु उख्वायों ने नहीं।' सेना और सरकार के लगभग सभी अधिकारी 'जकर' वर्ग के होते थे। जिस प्रकार जर्मन साम्राज्य पर प्रशिया रियासत राज करती थी, उसी प्रकार प्रशिया के सिर पर इस 'जकर' वर्ग की लाठी रहती थी अर्थात् जर्मन-साम्राज्य की ही लगाम इस वर्ग के हाथ में थी। एक बार चांसलर केप्लीनी ने बाहर से जर्मनी में आनेवाले अनाज पर चुगी कम कर दी थी तो इस वर्ग ने शोरगुल मचा कर चांसलर तक को शहशाह से निकलवा दिया था। बाहर से आनेवाले अनाज पर चुगी उड़ी रहने से कि उन के अनाज की कीमत बढ़ी रही। यह जबरदस्त वर्ग हौहेनजौलर्न कुल और निरकुश राज्य का कट्टर पक्षपाती था।

निरकुश शासन के फायदा रहने का एक दूसरा यह भी कारण था कि प्रजापक्ष के दल आपस में मिल कर काम नहीं करते थे। जर्मनी के मजदूर और किसान मध्यम-वर्ग से मिल कर जकरों की निरकुशता का नाश करने का इस लिए प्रयत्न नहीं करते थे कि उन्हें भय था कि मध्यम-वर्ग का राज्य हो जायगा और उन को कुछ फायदा नहीं होगा। मध्यम वर्ग के लोग भी मजदूर और किसानों से मिलने से हिचकते थे, क्योंकि उन्हें समाजवाद के राज्य का भय लगता था। इंग्लैंड की तरह जर्मनी में राजनैतिक दलों की सरकार न होने से जर्मनी में सरकार की नीति निर्माण के लिए दल नहीं बनते थे। अपने हितों की रक्षा करने के लिए और अक्सर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोग दल बना लेते थे। राजनैतिक दल जर्मनी में सरकार की नीति की ग्रन्थि से अधिक आलोचना करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। अस्तु, राष्ट्रीय प्रश्नों पर दलबंदी का संगठन होने के बजाय स्थानिक छोटे छोटे प्रश्नों पर बहुत से दल बन गए थे। बड़े दलों में यूरोपीय लड़ाई शुरू होने से पहले, खास कर पाँच दल थे। 'अनुदार दल'<sup>१</sup>, 'मध्य-दल'<sup>२</sup>, 'राष्ट्रीय उदार दल'<sup>३</sup>, 'गरम दल'<sup>४</sup> और 'समाजवादी दल'। 'अनुदार दल' में अधिकतर पूर्व और

<sup>१</sup>कसरवेटिव। <sup>२</sup>सेंटर। <sup>३</sup>नेशनल लिबरल। <sup>४</sup>रेडिकल और सोशलिस्ट।

उत्तर-पूर्व प्रशिया के ज़मींदार लोग, उन के खेतों में काम करनेवाले मज़दूर और दूसरे नौकर और रेलवे के नौकर थे। इस दल की संख्या बहुत न होने पर भी यह दल सभ्यता से मुख्य या क्योंकि यह दल प्रशिया की सरकार का सभ्यता से ज़रूरत पड़ता था और इसी दल के लोगों ने साम्राज्य को बनाया था। यह दल स्वतंत्रता से अधिक सरकारी सत्ता में विश्वास करता था। और शाहशाह और अमीरों के अधिकारों का पक्ष ले कर हर प्रकार के राजनैतिक सुधारों का विरोध करता था। देश के बाहर से आनेवाले अनाज पर कड़ी चुगी, जल सेना का विस्तार, गल-सेना पर अधिक खर्च, उपनिवेशों का फैलाव और बाहर की दुनिया में जहाँ बने वहाँ जर्मनी की टाँग अड़ाने का यह दल घोर पक्षपाती था। इसी दल की नीति पर अमल करने से जर्मनी ने युद्ध के कुमार्ग पर चल कर आगे बड़े दिन देखे। कहा जाता है कि चुनाव में ज़मींदारों के घरानों के सरकारी अफसर नाजायज़ दबाव डाल कर इस दल के लिए और जहाँ इस दल के उम्मेदवार नहीं होते थे वहाँ मध्यदल के उम्मेदवारों के लिए लगभग दस लाख मत ले लेते थे। 'मध्यदल' में कैथोलिक सम्प्रदाय के लोग थे। इस में गरीब अमीर सभ्यता के लोग थे क्योंकि बिस्मार्क के आक्षेपों से कैथोलिक सम्प्रदाय के हितों की रक्षा करने के लिए ही इस दल का जन्म हुआ था। इस दल का कोई राजनैतिक प्रोग्राम नहीं था। परन्तु बिस्मार्क की 'कैथोलिकों पर आक्षेप' की नीति बदल जाने पर भी यह दल कायम रहा। इस में अधिकतर जर्मनी के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भाग के कैथोलिक-पथी मज़दूर और किसान होते थे। यह दल 'समाजवाद' का कट्टर विरोधी और सुधार की मीठी-मीठी बातें करने पर भी 'उदार दल' के मुकाबले में हमेशा 'अनुदार दल' की ही सहायता करता था।

'राष्ट्रीय उदार दल' में मध्यम-वर्ग के लोग और व्यापारी थे। इस दल का जोर देश के मध्य और पश्चिम भाग के उद्योगी क्षेत्रों में था। यह दल राजनैतिक सुधारों का पक्षपाती, शिक्षा और शासन में साम्प्रदायिक असर और सरकारी अधिकारियों का चुनाव में दस्तदाजी का विरोधी था। 'अनुदार दल' की तरह सेना, उपनिवेशों के फैलाव और कड़ी परराष्ट्र नीति का यह दल भी हामी था। मगर कारखानों में बने हुए माल पर कम चुगी और खेती के माल पर चुगी का पुन विचार वह चाहता था और सारे सरकारी पद ज़मींदारों के हाथ में ही होना उसे बहुत बुरा लगता था। 'गरम दल' भी मध्यम वर्ग के लोगों का दल था। मगर वह 'राष्ट्रीय उदार दल' की तरह कारखानेवालों और व्यापारियों के हाथ का कठपुतला नहीं था। वह और सब बातें 'उदार-दल' की तरह ही चाहता था। मगर माल पर सभ्य प्रकार की चुगी का विरोधी था और पूर्ण व्यवस्थापकी सरकार और सेना पर राजनैतिक सत्ता का अधिकार चाहता था।

'समाजवादी प्रजासत्तात्मक दल'<sup>१</sup> में सर्वसाधारण लोग थे। यही एक दल ऐसा था जिस का राष्ट्रीय कार्यक्रम था और जो सारे जर्मन साम्राज्य में फैला हुआ था। यह दल यूरोप भर में सब से अच्छा संगठित दल था। देश भर में जगह जगह पर इस दल की शाखाएँ थीं। हर साल हजारों सार्वजनिक सभाएँ दल की ओर से की जाती थीं और

<sup>१</sup> सोशलि डेमोक्रेटिक पार्टी।

लाखों पच्चे बँटि जाते थे। दल के ७५ अखबार थे जिन के दस-बारह लाख ग्राहक थे। यह दल राजनैतिक सुधारों की अधिक परवाह नहीं करता था और पूँजीशाही को जड़ से उखाड़ कर सब प्रकार का अत्याचार मिटाने के लिए श्रमजीवियों का समाजशाही राज्य स्थापित करने का पक्षपाती थी। इस दल की मुख्य माँगें यह थीं—बीस वर्ष के ऊपर के साम्राज्यवादी सब स्त्री-पुरुषों को मताधिकार, अनुपात-निर्वाचन, रीशटाग का दूसरे वर्ष चुनाव, प्रतिनिधियों को वेतन, प्रजा को मतविदे पेश करने और नामंजूर करने का अधिकार, स्थानिक स्वशासन, खालाना कर, सर्वसाधारण को सैनिक शिक्षा, स्थायी सेना की जगह पर एक जन-सेना, विग्रह और संधि का रीशटाग के द्वारा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का पंचायती फैसला, बोलने और मिलने की स्वतंत्रता का सर्वसाधारण को हक, औरतों की मदों से कम हैसियत बनानेवाले कानूनों का नाश, राष्ट्रीय खजाने से धार्मिक खर्च न होना, अनिवार्य और मुक्त शिक्षा, जनता के चुने हुए न्यायाधीशों द्वारा न्याय, मौत की सज़ा बंद, निरपराधियों को जेल हो जाने पर मुआवज़ा, मृतक संस्कार और दवादारु मुक्त, आमदनी, जायदाद और विरासत के करों से सारे करों का खर्च निकालना, परोक्ष करों और चुंगी-करों का नाश, मज़दूरों को आठ घंटे काम और बच्चों की मजदूरी बंद।

दल के कार्यक्रम के दो—एक सिद्धांती और दूसरा अमली—पहलू थे। कुछ लोग सिद्धांती पहलू पर अधिक जोर देते थे और कुछ अमली पर। अस्तु दल के अंदर भी कई फिरकें थे। एक फिरका विल्कुल वर्ग-विग्रह<sup>१</sup> और गैरसमाजवादियों से मिल कर काम न करने का पक्षपाती थी। दूसरा फिरका गैरसमाजवादियों से मिलने का विरोधी था मगर वैध उपायों से काम लेने का हामी था। तीसरा दल के सिद्धांतों से चिपटा रह कर पुनःविचार चाहता था। चौथा दल के प्रोग्राम की पुनर्घटना पर जोर देता था। पाँचवाँ फिरका साम्राज्यवादी समाजवादियों का था जो समाजवादी होते हुए भी जर्मन सेना, उपनिवेशों और व्यापार का फैलाव चाहते थे। समाजवादी दल के जितने नियमित सदस्य नहीं थे उस से कहीं अधिक उस को चुनाव में मत मिलते थे क्योंकि निरंकुशता को नीचा दिखाने की इच्छा रखनेवाले सभी लोग इस दल के लिए मत देते थे। रीशटाग में प्रवेश कर के इस दल के दो भाग हो गए-थे। एक का नाम 'बहुसंख्य समाजवादी-दल' हो गया था जो वैध उपायों से काम लेता, तथा सरकार के काम में भाग लेता था। दूसरा 'स्वतंत्र समाजवादी' कहलाता था जो पूर्ण समाजवादी सरकार कायम न होने तक सरकार का विरोध करने का हामी था। सरकार समाजवादियों को राजाशाही का दुश्मन और उस को उखाड़-कर फेंक देने के लिए पड़यंत्र रचनेवाला समझती थी और उन को हर प्रकार के सरकारी पदों, यहाँ तक कि प्रोफेसर के पद तक से—सदा दूर रखती थी। मगर लड़ाई शुरू होने के पहले सन् १९१२ ई० के चुनाव में रीशटाग में समाजवादी दल के ही सब से अधिक सदस्य आए थे। ३६७ सदस्यों में ११० समाजवादी, ६० मध्यदल, ४५ अनुदार दल,

४४ राष्ट्रीय उदार दल और ४१ गरम दल के सदस्य आए थे। बाकी दूसरे दलों के थे।

जर्मनी राजनैतिक सुधार की तरफ धीरे धीरे कदम उठाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में सन् १९१४ ई० की यूरोप की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ समय के लिए सरकार का विरोध एक दम उड़ हो गया। समाजवादी दल तक लड़ाई के रजट मजूर करने लगा। मगर सन् १९१७ के फ़रीव हवा का रुख बदला। प्रजा लड़ाई से ऊपर उठी। रूस की अचानक राज्यक्रांति और अमेरिका के युद्ध में शरीक हो जाने से लोगों की आँखें खुलीं और 'स्वतंत्र समाजवादी दल' ने कैसर के पदत्याग और लड़ाई उद कर के बिना मुआवजे की सधि की सुलभसुलहा माँग शुरू कर दी। रूस की राजक्रांति का जर्मनी की प्रजा पर प्रभाव देख कर लड़ाई में शीघ्र ही अपनी निश्चय हार समझ कर और अमेरिका के प्रमुख विल्सन का, 'जर्मनी में प्रजासत्तात्मक राज्य कायम न हो जाने तक जर्मनी से सधि की बातें न करने' का एलान सुन कर जर्मन सरकार डरी और वह जर्मनी में भी प्रजा सत्तात्मक शासन कायम करने के वादे और गारंटी करने लगी। 'बहुसंख्य समाजवादी दल' ने जब देखा कि लड़ाई में जीत की कोई संभावना नहीं है, और कैसर का निरंकुश राज्य किनारे आ लगा है तो उस ने भी सरकार का साथ छोड़ कर फौरन लड़ाई उद कर के प्रजासत्तात्मक शासन कायम करने की माँग शुरू कर दी। 'केथोलिक मध्य-दल' के नेता अर्ज़वरजर ने भी अपने दल की आवाज़ इन दलों में मिला दी। आखिरकार सरकार ने इस विरोध के सामने सिर झुका कर 'प्रजासत्तात्मक शासन कायम करने का विचार करने के लिए' एक कमीशन नियुक्त किया। मगर ब्रेस्ट लिटोव्स्क की सधि में रूस को नीचा दिया देने से और लड़ाई के मैदान में फिर अपनी जीत होते देख कर सरकार का रुख बदला, और प्रजासत्तात्मक शासन की बातों को भुलावे में डाल देने का प्रयत्न होने लगा। परन्तु निरंकुश जर्मन सरकार की यह आशाएँ बड़ी क्षणिक थीं। शीघ्र ही जर्मनी की लड़ाई के मैदान में फिर हारे होने लगीं और दुश्मनों की सेनाओं के जर्मनी में घुस आने की बात कुछ समय की बात लगने लगी। अस्तु कैसर ने धरा कर अपने सारे अधिकार प्रजा को दे देने और जर्मनी में प्रजासत्तात्मक व्यवस्थापकी राज कायम करने की घोषणा निकाल दी।

मगर अब कैसर के एलानों और वादों का किसी पर कुछ असर होने का वक्त नहीं रहा था। सेना की बुरी हालत हो गई थी। लड़ाई से जान बचाने के लिए हजारों आदमी भाग भाग कर जंगलों में जा छिपे थे। स्त्रियाँ घरों से खाना ले जा कर उन्हें वहाँ पिला आती थीं। सरकार में अब किसी के खिलाफ कुछ करने की ताकत नहीं रही थी। 'स्वतंत्र समाजवादी दल' के गरम भाग ने जो रूस के बोल्शेविकों का ढग अख्तियार करने के पक्ष में था, गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र के कारखानों में हड़तालें करा कर लड़ाई उद कराने का प्रयत्न किया और इन हड़तालों को सरकार ने कुचल दिया। मगर असंतोष की आग फैलती ही गई। बवेरिया रियासत धमकी देने लगी कि अगर जर्मन-साम्राज्य की तरफ से लड़ाई बंद कर के सधि की बातें न की जायँगी तो बवेरिया रियासत खुद सधि कर लेगी। जर्मनी की हार महीनों पहले भार्न के मैदान में ही निश्चय

हो चुकी थी। मगर सेना-विभाग ने यह बात सब से गुप्त रखी थी। परन्तु अग्रे सारे देश को साफ दीखने लगा था कि जर्मनी की हार में जरा भी शका नहीं है। 'सवमेरीन' के लगातार भयंकर हमलों से भी इंग्लैंड को भूखा मारने का इरादा पूरा नहीं हुआ था। ल्यूडेंडोर्फ को नई सेनाएँ मिलना बिल्कुल उद हो गई थी और मैदान की सेनाओं की थकावट और व्याकुलता देख कर उस के होश फाखटा हो उठे थे। इधर देश में लोग उकता कर प्रजासत्तात्मक शासन के लिए शोर मचाने लगे थे। कैसर ने झूठी हुई नैया को बचाने के लिए वेटेन रियासत के उदार राजकुमार मैक्स को चांसलर बना कर व्यवस्थापकी सरकार रचने की आज्ञा दी। राजकुमार मैक्स ने अपने मन्त्रि-मंडल में समाजवादियों को रखने का निश्चय कर लिया था। 'बहुसंख्या समाजवादी दल' ने अपने नेता शीडमैन को मैक्स के साथ काम करने के लिए चुना। राजकुमार मैक्स का खयाल था कि लड़ाई बंद करने का सब से अच्छा तरीका यह होगा कि बजाय जर्मनी की तरफ से सधि की प्रार्थना करने के जर्मनी का लड़ाई के बाद मित्र-राष्ट्रों से अच्छी तरह व्यवहार करने और उन को बहुत-सी रियासतें देने के इरादे का एलान कर दिया जाय। साथ-साथ इस बात का एलान भी कर दिया जाय कि अगर सधि में जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश की जायगी तो जर्मनी मरते दम तक लड़ेगा। मगर जब वह राजधानी बर्लिन में पहुँचा तो पहला एत उसे हिटनबर्ग के पास से यह मिला कि 'आज शाम तक या कल सुबह तक हर हालत में अस्थायी सधि' अवश्य हो जानी चाहिए।' ल्यूडेंडोर्फ अपनी सेना के अपनी आँख के सामने शीराजे निखरते हुए देख कर छटपटा रहा था और किसी तरह, किसी बहाने से, सेना को आराम देने के लिए कुछ अवकाश पाने के लिए हाथ पैर पटक रहा था। अदर से उस का अभी तक यह खयाल था कि अस्थायी सधि के बहाने थकी हुई जर्मन सेना को विश्राम देने और नई सेनाएँ लाने का वक्त मिल जायगा। उस ने भी राजकुमार मैक्स के पास यही सदेशा भेजा कि 'शत्रुओं की सेनाएँ चीनीस घटे के मोतर ही अवश्य भयंकर हमला शुरू करेंगी। तब अस्थायी सधि की बात करने से अभी चीनीस घटे पहले अपनी तरफ से सधि की बात चलाना जर्मनी के लिए उपयोगी होगा।' राजकुमार मैक्स ने सोचा कि सेनापतियों के हस्ताक्षर से सधि की प्रार्थना बिल्कुल हार के समान होगी। अस्तु उस ने समय रहते अपने हस्ताक्षरों से अस्थायी सधि की प्रार्थना भेज दी।

इधर सधि का विचार चल रहा था और उधर जर्मन-सेना के मद्दाय अफसर नए हमले के नक्शे बना रहे थे। अक्टूबर १९१८ में, जब कि जर्मनी की सेनाएँ फ्लैंडर्स के मैदान में पिट कर पीछे हट रही थीं और शीघ्र ही बिल्कुल हार और सर्वनाश निश्चय दीखता था, उस समय भी जल सेना के अधिकारियों ने आखिरी बार ब्रिटिश जल सेना पर घावा बोल कर विजय प्राप्त करने या लडते-लडते अथाह सागर में गर्क हो जाने की योजना की। जल-सेना के अधिकारियों का खयाल था कि जर्मनी की सेना हार कर जब बेलजियम से पीछे

हटेगी, तब वेम्स के दहाने से ऑगरेज़ों की सेना आ कर हॉलैंड में घुस कर पीछे से इस हटती हुई सेना पर हमला करेगी और अगर उस समय जर्मन जल-सेना बीच में आ जाय तो स्थल-सेना का बचाव हो जायगा। उन का यह भी खयाल था कि अगर एक बार भी ब्रिटिश जल सेना बाहर समुद्र में निकल आई और उस से जर्मन जल-सेना की मुठभेड़ हो गई तो ब्रिटिश जल-सेना की ताकत इतनी कुचल दी जायगी कि दुनिया की राजनीति ही बिल्कुल बदल जायगी। अस्तु उन्होंने एक ऐसा नक्शा बनाया कि जर्मन जल-सेना का एक बड़ा भाग फ्लैंडर्स के किनारे की तरफ जाय और एक भाग वेम्स नदी के दहाने की तरफ जा कर ऑगरेज़ों की सेना को बंदने से रोके। समुद्रों पर सफर करनेवाला बेड़ा आगे बढ़ कर लड़ाई में भाग ले और जल-सेनापति ट्रोया सेना का एक मजबूत भाग ले कर पीछे तैयार रहे। लड़नेवाले जहाज़ी बेड़े के आगे सब से पहले बारह 'जेपलिन'<sup>१</sup> जायें और जर्मनी की सारी सबमेरीन<sup>२</sup> ब्रिटिश जल सेना के दक्षिण मार्ग में कई पक्षियों में रहें और उन का क्षेत्र खूब फैला दिया जाय। जिस दिन हमला हो, उसी दिन रात को सारे टॉरपीडो<sup>३</sup> जहाज़ों को ले कर दुश्मन पर एकदम हमला कर दिया जाय। ६ अक्टूबर को राजकुमार मैक्स ने राष्ट्रों से सधि की बातें शुरू कर दी थीं। मगर जल-सेना के अधिकारियों ने इस बात का कुछ भी खयाल न कर के कि उन के ब्रिटिश सेना पर हमला करने से जर्मनी के भाग्य पर क्या असर होगा, ३० अक्टूबर को अपने नक़्शे के अनुसार हमला शुरू करने के लिए जहाज़ निकाले। मगर सौभाग्य से विप्राधियों ने हड़ताल कर दी और कहा कि "ऑगरेज़ हमारे देश पर हमला करेंगे तो हम जान पर खेल कर अपने देश की रक्षा करेंगे। मगर उन पर हमला करने के लिए हम नहीं जायेंगे।" इस विद्रोह के लिए कई अफसरों को फौरन् गोली से उड़ा दिया गया। मगर शीघ्र ही सैनिकों का विद्रोह कील और हँसर्ग की सारी जल-सेना में फैल गया और अधिकारियों को उसे दबाना असमय हो गया। गरम समाजवादियों और जर्मनी के 'स्यार्टासिस्ट्स' कहलानेवाले कम्युनिस्टों के स्वप्न की क्रांति शुरू हो गई। जिस 'लेनिनवाद की जहरीली हवा' को जर्मनी की निरंकुरा सरकार ने रूस की सरकार का नाश करने में सहायता दी थी उसी ने अब जर्मनी की निरंकुरा सरकार को हड़पने के लिए पैलना शुरू किया। मगर 'क्रांति, क्रांति' दिन रात चिल्लानेवाले दल भी इस अचानक क्रांति के लिए तैयार नहीं थे। उन के नेता आपस में एक विचार तक के नहीं थे। 'भेड़िया, भेड़िया' चिल्लानेवालों के सामने सचमुच भेड़िया आँ खड़ा हुआ और उन की समझ में नहीं आता था कि क्या करें। सेना से लौटनेवाले सैनिकों से कुछ राइफलें इत्यादि ले कर कम्युनिस्टों ने इकट्ठी कर ली थीं। मगर उन से गलियों में मोड़ा-सा धूस धड़ाका करने के सिवाय और किसी प्रकार की क्रांति नहीं की जा सकती थी। वॉर्लिन में सेना क्रांतिकारियों में शामिल हो गई। मगर वह बिल्कुल समझती नहीं थी कि

<sup>१</sup>जर्मनी के झास लड़ाई के विमान। <sup>२</sup>पानी के भीतर चलनेवाले जहाज़ के जहाज़। <sup>३</sup>जिन जहाज़ों से सिगार के शक का एक अस्त्र जहाज़ों पर फेंक कर जहाज़ों को फाड़ दिया जाता है।

उसे क्या करना है। सरकार का काम चलाने के लिए बर्लिन में रूस के दंग पर 'मजदूरों और सैनिकों की समितियाँ' धीरे-धीरे बन गई। मगर शीघ्र ही यह समितियाँ अपने आप को शासन के काम के अयोग्य पा कर शासन का काम पुराने अधिकारियों के हाथ में देने लगीं। प्रांतों और रियासतों में लोग इस से भी कहीं कम तैयार थे।

स्वभाव से अक्रान्तिकारी जर्मन जाति का क्रांति करने और राजाशाही को उलट कर प्रजातंत्र कायम करने का जर्मनी में एक अजीब दृश्य खड़ा हो गया था। सच तो यह है कि जर्मनी में प्रजा की तरफ से कोई खास तैयारी कर के क्रांति नहीं की गई थी। जिस सेना के बल पर जर्मन सरकार चलती थी उस का बल टूट जाने पर शासकों की एक दम कमर-सी टूट गई थी और उन्होंने ने चबरा कर कंधे झाल दिए थे। जल-सेना के विद्रोह से राजनैतिक क्रांति का कुछ संबंध नहीं था। राजकुमार मैक्स ने नोस्के नाम के सैनिकों को प्रिय रीशटाग के एक नेता को भेज कर जल-सेना को संतुष्ट कर दिया था। रूस के मैदानों से लौटनेवाली जल-सेनाओं में कुछ बोल्शेविक विचारों की महक जरूर थी। बरना जल-सेना सिर्फ लड़ाई से ऊब कर ही विद्रोह में शरीक हो गई थी। ७ नवंबर तक केवल सेना का ही विद्रोह नज़र आता था। मगर ७ और ८ नवंबर की रात को इस विद्रोह ने पूरी राजनैतिक क्रांति का रूप धारण कर लिया। बवेरिया की राजधानी म्युनिख में 'स्वतंत्र समाजवादियों' ने सरकार के विरोध में एक बड़ा जलूस निकाला और एक सभा कर के प्रजा की माँगों में कैसर के राजच्युत होने की माँग भी पेश की। सभा से लौटनेवाली भीड़ ने राजमहल के पास पहुँच कर पहरा देनेवाले संतरियों के हथियार छीन लिए और अख्त्यालय पर छापा मार कर हथियारों पर कब्ज़ा कर लिया। इन हथियारों को ले कर उन्होंने सैनिकों की बारकों पर हमला किया, क़ेदियों को जेल से छुड़ा दिया और पार्लामेंट भवन में घुस कर एक सभा की। दूसरे दिन सुबह म्युनिख की दीवारों पर 'स्वतंत्र समाजवादी' नेता कर्ट आइसनर का, 'बवेरिया के मजदूर किसान और सैनिकों की सोवियट' के पहले प्रमुख की हैसियत से, बवेरिया के 'स्वतंत्र हो जाने की घोषणा' का एलान चिपका दिया गया। बवेरिया का राजा अपने कुल को ले कर भाग गया। रीशटाग में समाजवादियों की कैसर के राजत्याग की माँग और देश में उठते हुए तूफान को देख कर शीडमैन ने 'राजकुमार मैक्स को सलाह दी कि व्यवस्थापक सरकार के कायम करने के साथ-साथ कैसर को राजत्याग करना भी जरूरी होगा। बवेरिया से भी इसी बात पर ज़ोर दिया गया और ६ नवंबर को समाजवादियों के प्रतिनिधियों ने चांसलर मैक्स के सामने इस बात की वाक्यावदा माँग रख दी। कैसर के सामने जब यह माँग रखी गई तो उस ने अपने राजत्याग से देश में अंधाधुंध खून खराबा और बोल्शेविज्म फैल जाने का डर बता कर अपनी इच्छा से राजत्याग करने से साफ़ इन्कार कर दिया। मगर समाजवादियों ने शीडमैन के द्वारा चांसलर के सामने अपना आखिरी फ़ैसला यह रक्खा कि अगर दूसरे दिन दोपहर तक कैसर का राजत्याग और युवराज का अपने राज्याधिकारों से त्यागपत्र नहीं आ जायगा तो समाजवादी सरकार से अलग हो जायेंगे। राजकुमार मैक्स ने भी इस माँग में अपनी आवाज़ मिला दी। सेना के अधिकारी कैसर के साथ महल में

अभी तक क्रांति को दबाने का विचार कर रहे थे। मगर उन को कोई सेना का ऐसा भाग नजर नहा आता था जिसकी सान्मति पर वे भरोसा कर सकें। कोई अधिकारी कहता था कि कैसर को एक साधारण नागरिक की तरह अपने घर चला जाना चाहिए। किसी का कहना था कि अपनी स्वामिभक्त फौजों के साथ उन का नेता बन कर कैसर को जाना चाहिए। एक राय यह भी थी कि उसको लड़ाई के मैदान में जा कर लड़ते-लड़ते मर जाना चाहिए। हमारी समझ से अगर इस राय पर कैसर ने अमल किया होता तो उस के लिए उड़ी इज्जत की बात होती। आखिरकार वही आना-कानी के बाद कैसर, प्रशिया के राजपद से त्यागपत्र न दे कर जर्मनी की शहशहियत का त्याग कर के जर्मनी छोड़ कर ६ नवंबर को फाउन्टेनबेर्ग के यहाँ हार्लैंड चला गया। उसी प्रकार युवराज ने भी किया।

अब जर्मनी में 'समाजवादी दल' के सिवाय और कोई ऐसी सगठित सत्ता नहा थी जो सरकार की स्थापना कर सकती थी। अस्तु चांसलर मैक्स ने 'यहुसत्या समानवादी दल' के नेता ईमर्ट को सरकार का काम सौंप दिया। उस ने तीन बहुत सख्या समाजवादी दल के प्रतिनिधि और तीन स्वतंत्र समाजवादी दल के प्रतिनिधि ले कर एक अस्थायी मंत्रिमंडल बनाया और रूत की नक़ल कर के उसको 'पीपल्स कमिसेरीज़' का नाम दिया। स्पार्टेसिस्ट्स नाम के कम्युनिस्ट दल को इस सरकार में शरीक नहीं किया गया था क्योंकि वह किसी प्रकार का समझौता न कर के तर्ग युद्ध ही चाहते थे। अस्थायी सरकार ने कायम होते ही ६ नवंबर की शाम को प्रजा के लिए एक इस प्रकार का एलान निकाला— 'भाइयो, अब जर्मनी की प्रजा को आजादी है। कैसर ने राजत्याग कर दिया है और युवराज ने भी अपने अधिकारों से त्याग पत्र दे दिया है। 'समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल' ने सरकार की बागडोर अपने हाथों में ले ली है और उस ने 'स्वतंत्र समाजी प्रजा सत्तात्मक दल' को सरकार में उपासी की हैसियत पर भाग लेने का न्यौता दिया है। नई सरकार एक नए व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव का प्रबंध करेगी, जिस में बीस वर्ष की उम्र से ऊपर के सब स्त्री और पुरुषों को उपासी की हैसियत से मत देने का अधिकार होगा। नया व्यवस्थापक सम्मेलन बन जाने पर अस्थायी सरकार अपने सारे अधिकार प्रजा के इन प्रतिनिधियों के हवाले कर के इस्तीफा दे देगी।' अस्थायी सधि कर के स्थायी सधि की शर्तें ठीक करना, प्रजा के राने के सामान का प्रबंध करना, सेनिकों को शीघ्र से शीघ्र अपने घरों को लौट जाने और रोजगार घरों में लग जाने की सुव्यवस्था करना सरकार ने अपने फौरन के काम बनाए और ११ नवंबर को नई सरकार ने मित्र-राष्ट्रों से अस्थायी सधि पर हस्ताक्षर कर दिए।

स्वतंत्र समाजवादियों के गरम भाग स्पार्टेसिस्ट्स के नेता कार्ल लीब्लेख्ट और रोजा लक्जमबर्ग ने इस अस्थायी सरकार के विरोध में एक घोर आंदोलन खड़ा

<sup>१</sup> सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी।

<sup>२</sup> इम्पेक्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी।



किया। हर जगह रूस के दंग पर 'सैनिकों और मजदूरों की कमेटियाँ' बन गईं, जो अंड-अंड माँगें और शासन में ऊटपटांग हस्तक्षेप करती थीं। ईबर्ट की सरकार को काफी मुसीबत का सामना था। बर्लिन में विलकुल अराजकता-सी फैल गई थी। स्पार्टेकिस्टों ने धमकी दे रखी थी कि अगर आगामी व्यवस्थापक-सम्मेलन में क्रांतिकारियों की बहुसंख्या हुई, तो सम्मेलन को मार कर तितर-बितर कर दिया जायगा। उन्होंने सरकार का साथ देनेवाले अखबारों के दफ्तरो पर हमला कर के उन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। परराष्ट्र विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने आप ही कुछ सैनिकों को भड़का कर अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार करा देना चाहा। सेना के एक डिवीजन ने सरकार से झगड़ा खड़ा कर लिया और सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ने लगे आखिरकार सरकार ने इस अराजकता को सेना की सहायता से दबाने का निश्चय किया। इस पर सरकार के तीन 'स्वतंत्र समाजवादी दल' के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। ईबर्ट ने नोस्के को, जो इस समय कील का गवर्नर था, और औगस्ट बिजल नाम के एक दूसरे समाजवादी नेता को अपनी सरकार में मिला लिया। सरकार से इस्तीफा दे कर निकल जानेवाले नेता दूसरे गरम समाजवादियों से मिल कर क्रांति का विचार करने लगे। ५ जनवरी को स्पार्टेकिस्टों ने करीब दो लाख आदमी बर्लिन की सड़कों पर इकट्ठे कर लिए और चार पाँच दिन तक थोड़ी-बहुत मारकाट और उत्पात भी होता रहा। नोस्के को जो कुछ सैनिक मिल सके थे उन का वह बर्लिन से कुछ दूर एक स्थान पर संगठन कर रहा था। ११ जनवरी को वह ३००० सुसंगठित सेना के ले कर बर्लिन में घुसा। दोनों ओर कुछ खून-खराबा हुआ। कार्ल लीबकनेख्ट और रोजा लक्जम्बर्ग मारे डाले गए और प्रजा से हथियार रखा लिए गए। आखिरकार शांति की स्थापना हुई और व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया।

१६ जनवरी सन् १९१९ की तारीख व्यवस्थापक सम्मेलन के चुनाव के लिए निर्दिष्ट की गई थी। बीस वर्ष से ऊपर की उम्र के सब जर्मन स्त्री और पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया था। डेढ़ लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से सारे जर्मनी को ३७ चुनाव के जिलों में बाँटा था और अनुपात-निर्वाचन की पद्धति तय की गई थी। साढ़े तीन करोड़ मतदारों में से ३०४१०००० मतदारों ने इस चुनाव में मत डाले। मर्द मतदारों में से ८२.४ फी सैकड़ा और औरतों में से ८२.३ फी सैकड़ा ने अपने मत-धिकार का उपयोग किया। अल्सास लोरेन पर फ्रांसीसीयों का अधिकार हो चुका था इस लिए वहाँ चुनाव नहीं हो सका।

पुरानी राज-व्यवस्था खत्म हो जाने पर पुराने राजनैतिक दलों की भी पुनर्घटना हुई। मगर अधिकतर इन दलों के नाम इत्यादि ही बदले। विचारों और सिद्धांतों में अधिक फेरफार नहीं हुआ। पुराने 'अनुदार दल' और उस के छोटे-मोटे साथियों ने अपनी पुनर्घटना कर के अपना नाम 'जर्मन राष्ट्रीय लोकदल'<sup>१</sup> रख लिया और काउंट वेस्टार्प और धेरन

<sup>१</sup>जर्मन नेशनल पीपलज़ पार्टी।

वैन गेम्प को अपना नेता बनाया। यह दल खुल्लमखुल्ला राजाशाही, सेनासत्ता और जर्मन-साम्राज्य के विस्तार का पक्षपाती था। मौका मिलते ही प्रजातन्त्र को उखाड़ फेंकने का इस का इरादा था। मगर हाल के लिए इस ने सेना को भुसगठित करने, बोलशेविज्म का विरोध करने और देश को ऐसी सधि नामज़ूर करने के लिए तैयार करना अपना कार्य कम बनाया जिस में जर्मनी के उपनिवेश जर्मनी के हाथों से निकल जाने या जर्मनी के दुनिया की एक बड़ी ताकत न रहने की शर्तें हों। पुराना 'राष्ट्रीय उदारदल'¹ एक नए 'जर्मन लोकदल'² में परिणित हो गया। इस दल का नेता डाक्टर स्ट्रेसमैन था। यह दल दिल से राजाशाही का पक्षपाती था और खुल्लमखुल्ला प्रजातन्त्र की सफलता में अपना अनिश्वास प्रकट करता था। मगर हाल में इस दल ने प्रजातन्त्र सरकार का साथ देना मजूर कर लिया था। यह दल व्यापारी वर्ग का होने से जर्मन राजनीति के सन्ध में इस के विचार जमींदारों के 'जर्मन राष्ट्रीय लोकदल' ने अधिक भिन्न नहीं थे। परन्तु राजशाही, सेनासत्ता और साम्राज्य के बारे में यह दल इस समय अधिक चखचख करने के बजाय चुप रहना पसंद करता था। पुराने 'कैथोलिक मध्यदल' का नाम 'क्रिश्चियन लोकदल'³ हो गया था। कैथोलिक लोगों के हितों की रक्षा करने के सिवाय इस दल का और कोई राजनैतिक कार्यक्रम नहीं था। इस दल के नेता अर्ज़वरजर और डाक्टर स्पाह्न ये जिन की अध्यक्षता में इस दल ने अस्थायी सरकार का साथ देने का एलान कर दिया था और अर्ज़वरजर ने ही बाद में नई सरकार के मन्त्रिमंडल का सदस्य बन कर भिन्न राष्ट्रों से सधि पूरी करने का सारा काम काज किया।

पुराने 'गरम-दल'⁴ और कुछ उदार-दल के लोगो का मिल कर एक नया 'जर्मन प्रजा सत्तात्मक दल'⁵ बन गया। वियोडोर वुल्फ, फ़ैरेड हॉउसमैन और प्रख्यात कानूनदाँ ह्यूगो प्रियस जिस ने आगे चल कर नई राज-व्यवस्था को गढ़ा, इस दल के नेताओं में थे। यह प्रजादल सार्वजनिक गरम-दलों में, जिन के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई थी, सब से नरम दल था। यह दल मध्यवर्ग के लोगों का था। मगर प्रजातन्त्र का पूरा पक्षपाती और धीरे-धीरे समाजवाद—खास कर प्राकृतिक संपत्ति पर समाज के कब्जे—का भी पक्षपाती था। अन्य गरम-दलों में 'बहुसंख्या समाजवादी दल' और 'स्वतंत्र समाजी-दल' जैसे के तैसे रहे। अस्थायी सरकार से मुठभेड़ के बाद स्वतंत्र समाजवादी दल के नए भाग स्पार्टिस्टस् अर्थात् बोलशेविक दंग के कम्यूनिस्टों की बिल्कुल ताकत कम हो गई थी। उन्होंने ने व्यवस्थापक सम्मेलन के चुनाव में भाग भी नहीं लिया।

चुनाव में 'जर्मन राष्ट्रीय लोक-दल' के ४२ सदस्य चुन कर आए और 'जर्मन लोक दल' के २१ सदस्य, अर्थात् राजाशाही में विश्वास रखनेवाले कुल ६३ सदस्य थे। कैथोलिक 'क्रिश्चियन लोक दल' के ८८ सदस्य चुने गए और 'जर्मन प्रजा सत्तात्मक दल' के ७५ सदस्य अर्थात् मध्यवर्ग के १६३ सदस्य आए। 'बहुसंख्या समाजवादी-दल' के १६३ सदस्य चुने गए और 'स्वतंत्र समाजवादी दल' के सिर्फ २२ सदस्य अर्थात् समाज

¹ नेशनल लिबरल पार्टी। ² जर्मन पीपल्स पार्टी। ³ क्रिश्चियन पीपल्स पार्टी।

⁴ रेडीकल पार्टी। ⁵ जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी।

शाही के पूर्ण पक्षपातियों के कुल १८५ सदस्य थे। समाजशाही के विरोधियों के कुल मिला कर २२६ सदस्य थे। दस सदस्य दूसरे छोटे-छोटे गुटों से चुन कर आए थे। चुनाव के इस फल को देख कर समाजवादियों की बड़ी निराशा हुई क्योंकि इस व्यवस्था-सम्मेलन में समाजशाही की सरकार जर्मनी में कायम करना असंभव था। समाजवादियों के आपस के झगड़ों से लोग उकता गए थे जिस से चुनाव में उन्हें बहुत सहायता नहीं मिली। आखिरकार ६ फरवरी सन् १९१९ ई० के दिन जर्मनी के वीमार नगर में, जिस का यूनान की संस्कृति और कला की खान राजधानी एथेंस से मुकाबला किया जाता था, जो क्रिस्ती जमाने में जर्मनी के जगप्रसिद्ध कवि गेटे और शिलर और संगीत-शास्त्री गाय और लिस्ट का कीर्ति-क्षेत्र और लगभग सौ वर्ष से अधिक तक विद्वत्ता का केंद्र रह चुका था, व्यवस्थापक-सम्मेलन की सभा राष्ट्रीय थियेटर में बैठी। सम्मेलन के सामने बड़ा कठिन काम था। शायद ही कोई इतने विभिन्न विचारों की सभा इतनी कठिन समस्याओं को एक साथ सुलझाने के लिए कभी बैठी होगी। जर्मनी की भाषी सरकार के बारे में सदस्यों के तरह-तरह के विचार थे। युद्ध की भयावनी हार की छाया में यह सम्मेलन बैठा था और सभी दल एक दूसरे के सिर पर लड़ाई की जिम्मेदारी रखते थे। फ्रांस से पराजित जर्मनी के लिए संधि की बुरी शर्तों की खबरें आ रही थीं। घर पर कम्युनिस्टों की हार हो जाने पर भी वे पिल्कुल मर नहीं गए थे और इधर-उधर हड़तालें और मारकाट कर रहे थे। सम्मेलन की बैठक के समय ही म्यूनिख में कुछ समय तक, बोलशेविकों का तृती योल उठा जिस से सारा देश बड़ी चिंता में पड़ गया। अस्तु इन सब आपत्तियों और संकटों के बीच में वीमार के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने जर्मनी के लिए एक नई राज-व्यवस्था तैयार करने में जो सफलता प्राप्त की वह बड़ी तारीफ की बात है। उस से जर्मनी घोर विपत्ति और बर्बादी से बच गया और नई जर्मनी का भविष्य बन गया।

### ७—प्रजातंत्र राजव्यवस्था

वीमार के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने अपना काम-काज चलाने के लिए रीशटाग में कार्लवार्ड के जो नियम थे उन्हीं का उपयोग किया। सम्मेलन के अधिकारी चुन लिए गए। बहुसंख्या समाजवादी दल, क्रिश्चियन लोक-दल और प्रजासत्तात्मक दल हर कार्लवार्ड में मिल कर काम करते थे। चार दिन के भीतर ही एक कानून पास कर के अस्थायी सरकार का बड़ा कर नियमित कर दिया गया जिस से स्थायी राज-व्यवस्था के बन जाने तक कोई दिक्कत न खड़ी हो। चांसलर की अभ्यक्षता में अस्थायी मंत्रि-मंडल को कार्य-कारिणी की पूरी सत्ता दे दी गई। सम्मेलन द्वारा प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव हो जाने पर प्रमुख को मंत्रि-मंडल नियुक्त करने का निश्चय भी किया गया और मंत्रि-मंडल को सम्मेलन के प्रति जवाबदार माना गया। मंत्रि-मंडल को मसविदे बना कर सम्मेलन के सामने पेश करने के काम में सलाह देने के लिए प्रजासत्तात्मक-शासन रखनेवाली सारी रियासतों के प्रतिनिधियों की एक 'रियासत कमेटी' कायम की गई। ईवर्ट को प्रजातंत्र का प्रमुख चुना गया और उस की प्रार्थना पर शोडमैन ने बहुसंख्या समाजवादी दल, क्रिश्चियन लोकदल,

और प्रजासत्तात्मक दल के नेताओं को ले कर मंत्रि-मंडल तैयार किया। ईबर्ट की निपट और जवाबदार और कानिकारी 'अस्थायी सरकार' को इस प्रकार एक अस्थायी मंत्रि मंडल की, निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदार सरकार बना कर, समालोचना और शोर-गुल की चिन्ता न कर के, सम्मेलन ने जल्दी से जल्दी राज-व्यवस्था गढ़ डालने का काम शुरू कर दिया। ३१ मार्च सन् १९१९ ई० को स्थायी राज-व्यवस्था २६२ मत के विरुद्ध ७६ मत से सम्मेलन में पास हुई थी और ११ अगस्त से यह राज-व्यवस्था अमल में आई। सम्मेलन ने कानून पास कर के जो अस्थायी व्यवस्था कायम की थी उस में नई राज-व्यवस्था बन जाने पर उस पर प्रजा के मत लेने को शर्त नहीं रखी गई थी। अस्तु सम्मेलन का मत ही आखिरी मत था और नई राज-व्यवस्था का अमल में रखने के लिए किसी नई सरकार की जरूरत नहीं थी। ईबर्ट ने नई राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार अधिकार की शपथ ले ली और मित्र-राष्ट्रों की अस्थायी सधि की मेजी हुई शर्तों के स्वीकार न करने के कारण शीडमैन के हस्तीफा दे देने पर जुलाई से गस्टेव बीर की अध्यक्षता में जो मंत्रि-मंडल चला आता था वही जैसा का तैसा कायम रहा। व्यवस्थापक-सम्मेलन ने ही नई राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा का रूप धारण कर लिया। अस्थायी सरकार ने सम्मेलन शुरू होने से पहले ही प्रोफेसर ह्यू गो प्रियस की अध्यक्षता में नई राज-व्यवस्था का मसविदा तैयार करने के लिए एक कमीशन नियत कर दिया था। बहस शुरू करने के लिए यह मसविदा सम्मेलन को बड़े काम का सामित हुआ और इसी मसविदे को फेरफार कर के आखिर को स्वीकार किया गया।

जर्मन प्रजातन्त्र की नई राज-व्यवस्था एक काफी बड़ा दस्तावेज है। उस में प्राक्कथन के साथ १८१ धाराएँ हैं। १०८ धाराओं के पहले अध्याय में सरकार के ढाँचे और कर्तव्यों का जिक्र है। ५७ धाराओं के दूसरे अध्याय में जर्मन नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का जिक्र है। १६ धाराओं के तीसरे अध्याय में अस्थायी और स्थायी नियम दिए गए हैं। सब से महत्व की बात इस राज-व्यवस्था के दस्तावेज में यह है कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए तथा स्वीकृत सामाजिक समुदायों के सदस्यों का आपस में संबंध ठीक रखने के लिए बहुत सी धाराएँ रक्खी गई हैं। पिछली जर्मन साम्राज्य की राज्य-व्यवस्था में, सब के जर्मन साम्राज्य के नागरिक होने और नागरिकों की विदेशियों से रक्षा करने के जिक्र के सिवाय, नागरिकों के किसी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकारों का कोई जिक्र नहीं था। प्रजातन्त्र की राज-व्यवस्था में उस के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों पर बहुत जोर दिया गया था। सब नागरिकों को कानून की नज़र में बराबर, औरतों-मर्दों के एक-से अधिकार और कर्तव्य, कुलीनता और अधिकार के कारण किसी को कोई खास अधिकार नहीं, सब को एक राष्ट्र का नागरिक, देश में बसने, देश के बाहर जाने और देश में घूमने-फिरने का सब को एक सा अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न, हर एक नागरिक के घर को उस का पवित्र देवालय यानी उस में घुसने का किसी को अधिकार नहीं, सब को विचार प्रगट करने की स्वतंत्रता और अल्प संख्या जातियों को स्कूलों, अदालतों और शासन में अपनी भाषाओं के इस्तेमाल करने का

अधिकार माना गया था।

‘सामुदायिक जीवन’ नाम के अध्याय में शांतिपूर्वक समा करने, कानून के अविरोध सस्थाओं में सम्मिलित होने और सरकार को अर्जों पेश करने का सब का अधिकार माना गया है। राष्ट्र और चुगियों को व्यक्तिगत सहायता देने, अपनी हैसियत के मुआफिक सार्वजनिक करों का बोझ उठाने और कानून के नियमों के अनुसार सेना में सेवा करने का सभी नागरिकों का कर्त्तव्य माना गया था। माताओं की रक्षा, बहुत से बच्चोंवाले उलों की सहायता, नौजवानों का दुरुपयोग रोकने और उन के नैतिक, मानसिक और शारीरिक हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने का वादा किया गया। दूसरे ‘धर्म और शिक्षा’ से संबंध रखनेवाले भागों में सब को धार्मिक विश्वास और उपासना और धार्मिक सस्थाओं में संगठित होने की स्वतंत्रता मानी गई थी। राष्ट्र की ओर से किसी पथ को माली सहायता देना या किसी पथ को राष्ट्रीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया। कला, विज्ञान और शिक्षा नि शुल्क रखी गई और शिक्षा के लिए देश, राष्ट्र और जाति का सहकार और स्कूलों में हाजिरी अनिवार्य मानी गई। आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद १८ वर्ष की उम्र तक स्कूलों में जर्मन राष्ट्रीय संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय भावभाव के भाव से नैतिक शिक्षा, नागरिकता का भाव और व्यक्तिगत तथा औद्योगिक कुशलता सिखाना आवश्यक रक्खा गया।

इसी भाग के आखिरी हिस्से में ‘आर्थिक संगठन और आर्थिक-जीवन’ का भी जिक्र किया गया। आर्थिक जीवन के मूल सिद्धांतों में न्याय को ध्येय मन, किसी को अन्याय न हो तहाँ तक आर्थिक स्वतंत्रता, इकरार पट्टे की स्वतंत्रता, सुदखोरी की मुमानियत, व्यक्तिगत मिलकियत का अधिकार, सरकार को मिलकियत पर सिर्फ प्रजा के फायदे और कानून के अनुसार कब्जा करने का अधिकार और सरकार को भाग दे देने के बाद व्यक्तियों को विरासत का अधिकार माना गया। जमीन को बटवारा और जमीन के इस्तेमाल की देय भाल सरकार का काम माना गया, जिस से जमीन का दुरुपयोग न हो सके और हर जर्मन नागरिक को एक स्वस्थ रहने का स्थान अवश्य मिल सके। जमीन में व्यक्तिगत मिलकियत कायम रही। मगर जमीन के मूल्य में ‘जिना कमाई बढ़ती’<sup>१</sup> सार्वजनिक फायदे के लिए चली जाने की शर्त रखी गई। सरकार को सारी जमीन पर भी सामाजिक कब्जा कर सकने का अधिकार रक्खा गया। सब प्रकार की खानों और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी प्राकृतिक चीजों पर उदाहरणार्थ जल शक्ति इत्यादि पर सरकार का अधिकार माना गया। इस प्रकार के व्यक्तिगत व्यापार और उद्योगों को जिन का सामाजिक नियन्त्रण हो सकता है उचित मुआवजा दे कर अपने हाथ में कर लेने का भी सरकार को अधिकार रक्खा गया। श्रमजीवियों पर सरकार की रक्षा खास तौर पर रखी गई, उन को अपने हितों के बचाव और बढ़ाव के लिए अपना संगठन करने का अधिकार दिया गया। छोटी छोटी श्रमजीवियों की कौंसिलों से ले कर एक ऐसी ‘राष्ट्रीय श्रम कौंसिल’ तक की योजना रखी गई, जिस को राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा के सामने सामाजिक और आर्थिक मतविदों के प्रस्ताव भेजने और व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश होने से पहले इस विषय के सरकारी

मसविदों पर विचार करने का अधिकार दिया गया। जर्मन राज-व्यवस्था रुस के समाजवादी विचारों की एक प्रकार से छाया है और इसी की नकल इटली की राज व्यवस्था में भी की गई है।

राज-व्यवस्था में संशोधन और परिवर्तन व्यवस्थापक-सभा में उसी दंग से करने की शर्त रखी गई, जिस तरह दूसरे कानून स्वीकार किए जाते हैं। मगर इस काम के लिए व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों की संख्या के दो तिहाई भाग की सभा में हाज़िरी और जितने मत पड़ें, उस के दो-तिहाई मत-संशोधनों की स्वीकृति के लिए जरूरी रखे गए। व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओं में से अगर एक किसी संशोधन को स्वीकार न करे तो मत पड़ने के बाद दो सप्ताह का समय दिया जाय और इस दो सप्ताह के भीतर अगर स्वीकार न करनेवाली सभा प्रजा का मत लेने की इच्छा प्रगट करे तो प्रजा के मत से उस का फैसला हो। अगर इस प्रकार की कोई इच्छा प्रगट न की जाय तो दो सप्ताह खतम होने पर प्रजातन्त्र का प्रमुख कानून को अमल करने के लिए एलान कर दे। प्रजा को सीधा संशोधन का प्रस्ताव करने और उस पर मत करने का भी अधिकार दिया गया। हर हालत में किसी भी फैसले के लिए बाकायदा मतदारों के बहुमत की जरूरत रखी गई। इस संयम में जर्मनी की राज-व्यवस्था सिर्फ स्विट्ज़रलैंड से मिलती-जुलती है।

प्रियत कमीशन के मसविदे में प्रशिया को सात-आठ रियासतों में बाँट देने और शेष छोटी-छोटी रियासतों को भी इतनी ही रियासतों में बाँट कर, इस प्रकार करीब पंद्रह रियासतों के नए जर्मनी को दो सभा की व्यवस्थापक-सभा के एक प्रजातन्त्र राष्ट्र में संगठित करने की व्यवस्था की गई थी। परंतु व्यवस्थापक-सम्मेलन ने, सधि की शर्तों को पूरा करने के लिए जो सीमाओं में फेरफार करने पड़े उन को छोड़ कर, सब रियासतों की सीमाएँ जैसी की वैसी क़ायम रखीं। साम्राज्य की तरह इन रियासतों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। सारी रियासतों में सार्वजनिक मतानुसार निर्वाचित प्रजातन्त्र सरकार और जमाबदार मंत्रि-मंडल होने की क़ैद रखी गई। रियासतों की बिना इच्छा उन की सीमाओं में फेरफार करने और नई रियासतें क़ायम करने का अधिकार राष्ट्रीय जर्मन सरकार के हाथ में रखा गया। पुराने जर्मन साम्राज्य की तरह जो ताकतें जर्मन प्रजातन्त्र की सरकार को नहीं दी गईं वे रियासतों में बाँकी मानी गईं हैं। मगर नई राष्ट्रीय सरकार को इतनी ज़्यादा ताकतें दी गईं कि इस राज-व्यवस्था केंद्रीय सरकार को ही जोरदार बनाने के क़मान का साफ पता लगता है। अंतर्राष्ट्रीय में औपनिवेशिक, नागरिकता, परदेशियों के देश में आ कर बसने, देशीकरण, निर्वासन राष्ट्रीय रक्षा, मुद्रण, व्यापारी चुगी कर, डाक तार और टेलीफोन के संबंध के सारे अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय सरकार को दिए गए। राष्ट्र के सारे कर्तों पर भी राष्ट्रीय सरकार ही का अधिकार रखा गया। सिर्फ एक शर्त यह रखी गई कि अगर राष्ट्रीय सरकार किसी ऐसे कर्त को लेना चाहे जो पहले कोई रियासत लेती थी तो उस को उस रियासत के खर्च का खयाल जरूर रखना चाहिए। अपनी आमदनी की नुकसान से रक्षा करने, दुबारा कर्तों, कर्तों का अधिक जोर, एक रियासत

के दूसरे रियासत के खिलाफ करें, तथा व्यापारी माल पर रियायती करों को रोकने के लिए रियासती करों को जायज ठहराने और उन को इकट्ठा करने के नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रीय सरकार को दिया गया। माल और फौजदारी के कानून, ज़ात्ता कानून, अखबार, गरीबों को मदद, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सब प्रकार का बीमा, मजदूरी के कानून, पेंशन, तोल और माप, कागज़ी मुद्रा, सराफी उद्योग, खानों, रेलों और सड़कों, जल-पर्यटन और मच्छीमारी के स्थानों के संबंध में सब अधिकार और प्राकृतिक संपत्ति और व्यापार-धंधों में सामाजिक प्रबंध कायम करने के सारे अधिकार भी राष्ट्रीय सरकार को दिए गए। जहाँ तक राष्ट्रीय सरकार हस्तक्षेप न करे, वहाँ तक और सब बातों में रियासतों का अधिकार माना गया।

राष्ट्रीय सरकार के कानूनों के रियासती कानूनों के ऊपर माना गया और किसी रियासती कानून और राष्ट्रीय सरकार के कानून में विरोध होने पर न्याय का अधिकार बड़ी राष्ट्रीय अदालत को दिया गया। राष्ट्रीय कानूनों का अगर कोई रियासत पालन न करे तो प्रजातंत्र के प्रमुख के तलवार के जोर से उस रियासत से कानूनों के पालन कराने का अधिकार भी दिया गया। इस राज व्यवस्था के अनुसार 'सारा राजनैतिक अधिकार, राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय सरकार का, और रियासतों के मामलों में रियासतों की व्यवस्थाओं के अनुसार रियासतों का' माना गया। रियासतों को राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा में अपने एलची भेज कर अपने मंत्रि-मंडलों की राय पेश करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व उसी प्रकार कायम रक्खा गया जिस प्रकार पुरानी बंडसराय में था। सारे संघीय राष्ट्रीय में प्रभुता राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्र के विभिन्न भागों में, राज-व्यवस्था के अनुसार, बाँट दी जाती है और एक अंग के बिना दूसरे की मर्जी के इस प्रभुता की रूप-रेखा में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। इस सिद्धांत की कसौटी पर कसने से जर्मन प्रजातंत्र की इस राज-व्यवस्था को संघीय नहीं कहा जा सकता।

## ८—व्यवस्थापक-सभा : (१) रीशटाग

साम्राज्य की सरकारी संस्थाओं में रीशटाग ही सिर्फ एक ऐसी संस्था थी जिस में कुछ प्रजा की आवाज थी। अतएव प्रजातंत्र की सरकार में रीशटाग को कायम रक्खा गया। उस के चुनाव के ढंग और उस की सत्ता में जरूर बहुत फेरफार हो गया। बीस वर्ष के ऊपर के सब स्त्री-पुरुषों को अनुपात-निर्वाचन के अनुसार रीशटाग के चुनाव में मत देने का अधिकार दे दिया गया। रीशटाग का जीवन चार साल का नियत किया गया। परंतु समय पूरा होने से पहले भी प्रजातंत्र के प्रमुख को रीशटाग भंग कर देने का अधिकार रक्खा गया। मगर एक ही कारण पर एक बार से अधिक वह रीशटाग को भंग नहीं कर सकती थी। रीशटाग के चुनाव-संबंधी झगड़े तय करने के लिए एक 'चुनाव कमीशन' रक्खा गया जिस में कुछ रीशटाग द्वारा निर्वाचित रीशटाग के सदस्य और कुछ प्रजातंत्र के प्रमुख द्वारा नियत किए हुए शासकी अदालत के सदस्य रखे गए। सभा को अपने अधिकारियों

को चुनने और अपने काम-काज के नियम खुद बनाने का अधिकार दिया गया और सभासदों को अन्य धारा-सभाओं के सदस्यों की-सी सुविधाएँ दी गईं। रीशदाग को शासन के कानून बनाने और कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखने के अधिकार दिए गए। राज-व्यवस्था में संशोधन भी रीशदाग स्वीकार कर सकती थी। मगर उस की स्वीकृति को प्रजा के मत से बदला और संशोधनों को प्रजा की ओर से भी पेश और मंजूर किया जा सकता था। कानून बनाने का भी रीशदाग को इन्हीं शर्तों में अधिकार दिया गया।

रीशदाग की सभा में मसविदे मंत्रि मंडल अथवा सभा के सदस्यों की ओर से पेश किए जा सकते थे। रीशदाग में मसविदे पास हो जाने के चौदह दिन बाद, व्यवस्थापक सभा की दूसरी सभा के विरोध न करने पर, कानून बन जाने से या दूसरी सभा के किसी मसविदे का विरोध करने पर अगर रीशदाग उस पर पुनः विचार कर के उसे दो तिहाई संख्या से फिर स्वीकार करने पर और प्रजातन्त्र के प्रमुख का ऐसी हालत में प्रजा का मत लेने के अपने अधिकार का उपयोग न करने पर मसविदे का राष्ट्रीय कानून हो जाने की शर्त रखी गई। जिन मसविदों पर व्यवस्थापक सभा की दोनों शाखाओं का मत न मिले उन पर प्रजा का मत लेने का प्रजातन्त्र के प्रमुख का अधिकार दिया गया। किसी स्वीकृत कानून का, रीशदाग के एक तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर, अमल के लिए एलान रोक देने और उस के बाद राष्ट्र के मतदारों के बीचों भाग की अर्जों आने पर उस पर प्रजा के मत लेने का अधिकार भी प्रमुख को दिया गया। परंतु रीशदाग से स्वीकृत कानून प्रजा के मत से उसी हालत में रह हो सकता था जब कि राष्ट्र भर के रजिस्टरशुदा मतदारों की बहुसंख्या मत देने में भाग ले और मत देनेवालों की बहुसंख्या उस को स्वीकार करने के लिए मत दे। प्रजा की तरफ से भी मसविदे पेश और मंजूर हो सकते थे। देश के मतदारों के दूसरे भाग के हस्ताक्षरों से कोई कानूनी मसविदा पेश होने पर मंत्रि-मंडल को वह मसविदा थर्नी राय के साथ रीशदाग के सामने रखने की शर्त रखी गई। अगर रीशदाग उस को स्वीकार करे तो वह मसविदा कानून बन जायगा और अगर रीशदाग उस को स्वीकार न करे तो उस पर प्रजा के मत लिए जायेंगे।

## ( २ ) रीशराथ

जर्मन प्रजातन्त्र की व्यवस्थापक सभा की दूसरी सभा का नाम रीशराथ था। पुरानी बंडसराथ की तरह इस सभा में भी प्रजा के प्रतिनिधि नहीं, रियासतों के प्रतिनिधि आते थे। रियासतें जितने प्रतिनिधि चाहें भेज सकती थीं। मगर उन के मत पहले की तरह निश्चित होते थे। दस लाख से कम आबादी की हर रियासत का रीशराथ में एक मत होता था और इस से अधिक आबादी की रियासतों का, हर अधिक दस लाख या उस के भाग के लिए, अगर वह भाग सत्र से छोटी रियासत के बराबर हो तो रीशराथ में एक प्रतिनिधि होता था। मगर किसी एक रियासत के सब मतों के दो तिहाई से अधिक मत रखने का हक नहीं था। यह आखिरी शत प्रशिया का अक्षर कम करने के लिए रखी गई थी, क्योंकि उसी एक रियासत पर इस शर्त का असर पड़ता था। हर



मर्दुमशुमारी के गद्द रीशराय मतों का रियासतों में नए सिरे से बटवारा करती थी। रीशराय में प्रतिनिधि बन कर आमतौर पर रियासतों के मन्त्रि मंडल जाते थे।

रीशराय के राज व्यवस्था में सशोधन और कानून बनाने की सत्ता थी। रीशराय में स्वीकृत सशोधनों को एक दम नामजूर कर देने का अधिकार रीशराय को नहीं था। रीशराय के राज व्यवस्था में किए हुए रीशराय के सशोधन पसंद न हों तो वह सिर्फ उन को प्रजा का मत लेने के लिए लौटा सकती थी। कानूनी मसविदों पर रीशराय मन्त्रि मंडल के साथ विचार करती थी। जिस मसविदों को मन्त्रि मंडल रीशराय के आगे विचार के लिए रखना चाहता था, उन को पहले उसे रीशराय के सामने विचार के लिए रखना जरूरी होता था, चाहे रीशराय के विचारों पर बाद में मन्त्रि मंडल अमल न करे। रीशराय अपने मसविदे भी मन्त्रि-मंडल के पास भेज सकती थी और मन्त्रि मंडल को उन्हें रीशराय के सामने पेश करना पड़ता था चाहे वह मसविदे मन्त्रि-मंडल के पसंद हों या न हों।

रीशराय के किसी मसविदे को पास कर देने के बाद रीशराय उस को फिर रीशराय के पास विचार के लिए भेज सकती थी। अगर दोनों सभाओं की राय मिल जाती थी तो मसविदा कानून बन जाता था। अगर दोनों सभाओं की राय नहीं मिलती थी और रीशराय में रीशराय के खिलाफ दो तिहाई मत होते थे तो भी यदि प्रजातन्त्र का प्रमुख अपने अधिकार का प्रयोग कर के मसविदा प्रजा के मत के लिए न भेजे और प्रजा उसे अस्वीकार न कर दे, तो वह मसविदा कानून बन जाता था। अगर रीशराय के रीशराय से लौट कर आनेवाले अपने सशोधित मसविदे को फिर दो तिहाई से कम मतों से अस्वीकार न करने पर जब तक प्रमुख उस मसविदे पर प्रजा की राय न ले और प्रजा उस को स्वीकार न करे, तब तक वह मसविदा कानून नहीं बनता था। अस्तु रीशराय को मसविदे पेश करने और उन का पास होना कुछ दिन के लिए सिर्फ रोक देने के अधिकार थे। रीशराय से मजूर मसविदों को नामजूर कर देने की रीशराय की सत्ता नहीं थी। रीशराय दूसरे देशों की व्यवस्थापक सभा की ऊपरी सभा की तरह रोक और निगरानी का आत्म काम करती थी। वह रीशराय के बराबर की धारा-सभा नहीं थी।

## ६—प्रमुख और मन्त्रि-मंडल

जर्मन प्रजातन्त्र का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सिरताज माना गया था। अगर सरकार का सारा काम एक मन्त्रि-मंडल करता था, जिस को प्रमुख नियुक्त करता था और जो रीशराय के सरकार के सारे काम के लिए जवाबदार होता था। प्रमुख का चुनाव प्रजा के मतदार फ्रांस की तरह सात वर्ष के लिए करते थे और वह तितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव के लिए-खड़ा हो सकता था। प्रजातन्त्र का कोई उपप्रमुख नहीं चुना जाता था। अगर समय पूरा होने से पहले प्रमुख की जगह खाली हो जाती थी, तो सात साल के लिए दूसरा प्रमुख चुन लिया जाता था। रीशराय के दो तिहाई मतों और प्रजा के मतदारों के सारे नागरिकों के सिर्फ बहुमत से प्रजातन्त्र के प्रमुख को मुञ्चत्तल कर देने का अधिकार दिया गया था। प्रमुख, चांसलर और मंत्रियों पर, रीशराय, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए,

राष्ट्र की सभ से उड़ी अदालत के सामने मुकदमा चला सकती थी। प्रमुख से प्रजा इस्तीफा भी रखा सकती थी। प्रमुख को अन्य देशों के प्रजातन्त्र के प्रमुख की तरह बहुत से अधिकार दिए गए थे। उस को राष्ट्र के सभ अधिकारियों को नियुक्त करने और निकालने, कानूनों का पालन कराने और अमन कायम रखने, एलचियों को भेजने और लेने, रीशटाग की मजूरी से सधियाँ करने, सेनाओं का संचालन करने, अपराधियों को क्षमा करने और सास हालता में रीशटाग के फेसलों पर प्रजा का मत लेने के अधिकार दिए गए थे। परन्तु प्रजातन्त्र के प्रमुख का कोई हुक्म तब तक वाक्यावदा न होने की कौद रक्ती गई थी जब तक उस पर चांसलर या उचित मंत्री के हस्ताक्षर न हों। मंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाने से जवाबदारी मंत्रियों की हो जाती थी।

मन्त्रि मंडल का प्रधान चांसलर होता था। परन्तु जर्मन प्रजातन्त्र का चांसलर जर्मन साम्राज्य के चांसलर की तरह मंत्रियों के दर्जे से भिन्न नहीं होता था। दूसरे देशों के मन्त्रि मंडलों के प्रधान मंत्री की सी हैसियत उस की भी होती थी। चांसलर को प्रमुख नियत करता था। चांसलर अपने मन्त्रि मंडल के मंत्रियों को चुनता था और उन की नियुक्ति प्रमुख करता था। प्रधान मंत्री और मन्त्रि-मंडल के अधिकार में रहने की राज-व्यवस्था में यह शर्त रक्ती गई थी कि उन पर रीशटाग का विश्वास रहना चाहिए। जब रीशटाग उन में अविश्वास का प्रस्ताव पास करे उसी समय सब मंत्रियों को तुरत इस्तीफा दे देना चाहिए। इंग्लैंड, फ्रांस और इटली इत्यादि में इस शर्त का पालन रियाज और सहूलियत पर होता है। मगर यूरोप भर में जर्मनी ही एक ऐसा देश है, जहाँ की लिखित राज-व्यवस्था में यह शर्त रक्की गई है। चांसलर और मंत्रियों को रीशटाग के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाना चाहिए या गहर से भी यह चुने जा सकते हैं, इस सबध में यूरोप की और राज व्यवस्थाओं की तरह जर्मनी की राज-व्यवस्था में भी कोई जिक्र नहीं है। मगर जिस तरह उन देशों में यह रियाज पड़ गया है कि मंत्री या तो व्यवस्थापक-सभा के मंत्री चुने जाने के समय सदस्य होते हैं या चुन जाने के बाद जल्दी से जल्दी सदस्य बन जाते हैं, उसी प्रकार जर्मनी में भी यह रियाज जरूर हो जायगा। राज व्यवस्था के अनुसार चांसलर और मंत्रियों को रीशटाग की सभा की बैठकों और कमेटियों की बैठकों में भाग लेने और मताधिकार देना करने तथा रीशटाग की सभा और कमेटियों की बैठकों में भाग लेने और प्रस्ताव रखने का अधिकार होता था।

कार्यकारिणी पर रीशटाग का अकुश रखने के लिए मंत्रियों पर कानून के विरुद्ध काम करने पर अभियोग चलाने का अधिकार भी रीशटाग को दिया गया था। रीशटाग के सदस्यों के पॉचवें भाग की माँग पर कार्यकारिणी की कार्यवाहियों की जाँच करने के लिए एक कमिटी बनाई जा सकती थी, जिस के सामने जरूरत के मुताबिक सब अधिकारी गवाही देने और सारे कागजात रखने के लिए मजबूर होते थे। रीशटाग के सौ सदस्य प्रजातन्त्र के प्रमुख, चांसलर या किसी मंत्री पर मुकदमा चलाने का सवाल उठा सकते थे और रीशटाग के दो तिहाई मत उस के पक्ष में होने पर राष्ट्र की सब से बड़ी अदालत के सामने मुकदमा चलाया जा सकता था।

## १०—नई दलबंदी

प्रजातंत्र राज व्यवस्था के अमल में आने के बाद नई जर्मन सरकार को लड़ाई के हार के नतीजों का सामना करना था। सब से कठिन समस्या सरकार के सामने मित्र-राष्ट्रों से संधि की थी। मित्र राष्ट्र—खास कर फ्रांस और बेल्जियम—जर्मनी की ताकत को सदा के लिए कम करने और उस से जितना बने उतना लड़ाई का मुआवजा लेने पर तुले हुए थे। हारे हुए देश के लिए विजेता राष्ट्रों से संधि में ऐसी शर्तें प्राप्त कर लेना जिस से जर्मनी तबही से बच कर जल्द से जल्द फिर एक बड़ी शक्ति बन जाय कोई हँसी खेल का काम नहीं था। नई प्रजातंत्र सरकार के सामने सब से पहली समस्या यह थी।

शीड्मैन की अस्थायी संधि की शर्तें मंजूर न होने से उस ने इस्तीफा दे दिया था और उस के स्थान में बौथर नाम का दूसरा समाजवादी नेता चांसलर के स्थान पर आ गया था। बौथर की सरकार के संधि पर हस्ताक्षर करने पर जमींदारों और पूँजी-पतियों के पुराने अनुदार-दल ने फिर सिर उठा कर प्रजातंत्र सरकार के विरुद्ध शोर मचाना शुरू कर दिया। एक मजदूर का प्रजातंत्र के प्रसुत<sup>१</sup> पद और मजदूर सभ के एक अधिकारी का चांसलर की गद्दी पर होना इन अभिमानियों की आँखों में खलता था। सेना से निकले हुए हजारों अफसर बेकार इधर-उधर मारे मारे फिर रहे थे। उन्होंने ने ल्यूडोविक से मिल कर और बर्लिन के कमांडर लुटविज से पइयत्र रच कर डाक्टर केप नाम के मनुष्य की अध्यक्षता में 'जंकर' दल के धन की सहायता से सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी थी। संधि की शर्तों के कारण मजदूरों की गाँठ कटती थी और उद्योग-धंध पर सामाजिक नियंत्रण करने का वादा पूरा न करने से भ्रमजीवियों की नज़रों में भी समाजवादी सरकार गिर गई थी। अस्तु विद्रोहियों का खयाल था कि भ्रमजीवी भी विद्रोह में उन का साथ देगे। सरकार को इस विद्रोह की तैयारी की खबर लगते ही युद्ध-सचिव नोत्के ने लुटविज को एकदम बर्खास्त कर दिया और केप की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। मगर पुलिस के अधिकारियों ने केप को गिरफ्तार नहीं किया और लुटविज ने अपना पद नहीं छोड़ा। तब, सरकार को मालूम हुआ कि विद्रोह की तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। बर्लिन में रहना सुरक्षित न समझ कर सरकार एक मंत्री को खबर भेजने के लिए राजधानी में छोड़ कर, दूसरे नगर में चली गई। केप ने बर्लिन में घुस कर अपने आप को चांसलर और लुटविज को युद्ध-सचिव एलान कर दिया। सरकार की सेना और पुलिस ने किसी का साथ नहीं दिया। समाजवादी ईबर्ट की सरकार ने 'मजदूर-सभों के द्वारा बर्लिन में आम हड़ताल का एलान करा दिया। पानी, गैस, बिजली, रेल, ट्राम सब एकदम बंद हो गईं। प्रजा ने भी केप का साथ नहीं दिया। हार कर विद्रोही बर्लिन छोड़ कर चले गए। मगर सरकार को मालूम हो गया कि उस से काफी लोग असंतुष्ट हैं। अस्तु, बर्लिन में लौट कर बौथर की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और कुछ दिन काम चलाने के लिए एक दूसरे समाजवादी नेता हरमेन मुलर ने २७ मार्च सन् १९२० को नया

<sup>१</sup> ईबर्ट जिन यनाने का काम करता था।

मन्त्रि-मंडल कायम किया।

ईबर्ट ने सोचा कि पुरानी व्यवस्थापक सभा का, नई राज-व्यवस्था बना चुकने के बाद भी बहुत दिनों तक कायम रहना ठीक नहीं है। इस लिए उस ने ६ जून सन् १९२० को नया चुनाव मुक़र्रर कर दिया था। इस चुनाव में 'बहुसंख्या समाजवादी दल' के पिछले १६५ सदस्यों के स्थान में सिर्फ ११२ ही सदस्य चुने गए। 'श्रमता समाजवादियों' के २२ से बढ़ कर ८१ सदस्य चुने गए। 'अनुदार-दल' के ४२ से बढ़ कर ६६ सदस्य और 'जर्मन लोकदल' के २३ से बढ़ कर ६२ सदस्य। 'मध्यदल' के ६० से घट कर ६८ और 'प्रजा सत्तात्मक दल' के ७५ से घट कर ४५ सदस्य रह गए। २० जून को फेहरेनगाल ने 'प्रजा सत्तात्मक दल,' 'मध्य-दल' और 'लोक दल' में से मिला कर एक नया मन्त्रि मंडल तैयार किया। मिन राष्टों की उनाई हुई सधि पर आखिरी हस्ताक्षर करने से इस मन्त्रि-मंडल ने इन्कार कर दिया। अस्तु इस मन्त्रि मंडल को भी इस्तीफा दे देना पड़ा और डाक्टर विथ ने प्रजा-सत्तात्मक दल, मध्य-दल और समाजवादी दल में से मिला कर ४ मई १९२१ ई० सन् को एक नया मन्त्रि मंडल तैयार किया।

मिन राष्टों ने जर्मन सरकार के सधि पर आखिरी हस्ताक्षर न करने पर जर्मनी को अल्टीमेटम दे दिया था, और वे रूढ़ पर कब्ज़ा कर लेने की धमकियाँ दे रहे थे। अस्तु विथ सरकार ने अल्टीमेटम की मियाद ख़तम होने से पहले ही ११ मई को सधि पर हस्ताक्षर कर दिए। डाक्टर विथ का विश्वास था कि सधि की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वे पूरी न की जा सकेंगी। मगर सधि पर सही करने से इन्कार कर देने के उजाय वह शर्तें पूरी करने का पूरा प्रयत्न कर के मिन राष्टों को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि जर्मन सरकार मिन-राष्ट्रों को धोखा नहीं देना चाहती है, बल्कि सधि की शर्तें बाक़ई ऐसी हैं कि उन का जर्मनी से पूरा होना असंभव है। सरकार के सधि पर हस्ताक्षर करते ही सरकार के विरोधियों ने विर सिर उठाया और स्वेरिया और सैक्सनी की रियासतें सरकार के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बन गईं। कैप के पक्ष के लोग दब तो गए थे परंतु भीतर ही भीतर वह सरकार के विरुद्ध प्रयत्न कर रहे थे। 'अनुदार-दल' को भी अभी तक प्रजातन्त्र को उखाड़ कर राजाशाही स्थापन करने की आशा थी और इस विचार के लोगों की बहुत-सी गुप्त सस्थाएँ कायम हो गई थीं। इन गुप्त सस्थाओं की ओर से राजनैतिक नेताओं की हत्याएँ शुरू कर दी गईं। मध्य-दल का अत्यंत कारिल नेता अर्जबर्नर, जिस का शुरू से आखिर तक सधि में बड़ा हाथ रहा था, मार डाला गया। इस पर प्रजा में सरकार के विरोधियों के खिलाफ बड़ा रोष पैला और रीशटाग ने सरकार को उन को दबाने के लिए विशेष अधिकार सौंप दिए। इतने में मन्त्रि-मंडल के एक सदस्य रायनाउ की हत्या भी कर डाली गई और विथ सरकार ने भी १६ नवंबर सन् १९२२ ई० को इस्तीफा दे दिया।

अन की बार 'लोकदल' के एक अमीर व्यापारी सदस्य क्यूनो ने लोकदल, मध्यदल और प्रजासत्तात्मक दल को मिला कर एक मन्त्रि मंडल तैयार किया। उधर मुग्रावजे की किश्त वक्त पूरा हो जाने पर भी न पहुँचने से फ्रांस ने रूढ़ पर कब्ज़ा कर लिया। अस्तु, सब दलों ने भेद भाव भूल कर क्यूनो की सरकार का साथ दिया और जर्मन सरकार ने रूढ़

मन्त्रासासना का खलाफ़ जमना का सत्याग्रह शुरू कर दिया। परंतु प्रजातंत्र के विरोधियों ने इस मौके को अच्छा समझ कर फिर कान खड़े किए। डाक्टर काहर ने बवेरिया के जमींदारों के रूप की सहायता से प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए एक खुला आंदोलन बढ़ा कर दिया। हिटलर नाम के एक दूसरे प्रजातंत्र के विरोधी ने बवेरिया में इटली के फ़ैसिज़्म के ढंग का, 'राष्ट्रीय समाजवाद' का आंदोलन उठाया। क्यूनो सरकार को भी आखिरकार कुछ ही दिन में इस्तीफ़ा दे देना पड़ा और उस की जगह पर लोकदल के नेता डाक्टर स्ट्रेसमैन ने समाजवादियों की सहायता से १२ अगस्त सन् १९२३ ई० को नया मन्त्रि-मंडल बनाया।

डाक्टर स्ट्रेसमैन बड़ा योग्य पुरुष था। परंतु उस के सामने काम भी बड़ा कठिन था। रूढ़ में मित्र-राष्ट्रो से झगड़ा निवटाना था, घर का कलह और विद्रोह—खास कर बवेरिया और सेक्सनी का विद्रोह—दूर कर के जर्मनी के सिक्के मार्क की मिट्टी पलीत होने से बचानी थी। काहर ने बवेरिया में प्रजातंत्र शासन उखाड़ कर एक त्रिमूर्ति का शासन फ़ायम करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था। उस का खयाल था कि बवेरिया में सफलता हो जाने पर दूसरे स्थानों पर लोग आप से आप बवेरिया का अनुकरण कर लेंगे। हिटलर सन् १९२१ से 'राष्ट्रीय समाजवादी दल' का नेता था। उस ने नौजवानों में उसाह भर दिया था और 'बंडऑर्बर्लैंड' नाम का स्वयंसेवकों का एक दल भी उस के पास था। उस ने भी इसी समय मुसोलनी की रोम पर कूच की तरह 'बर्लिन पर कूच' की तैयारी शुरू की। हिटलर को फ़िक्र हुई कि कहीं काहर आगे न निकल जाय। अस्तु उस ने काहर को एक जगह पर मकड़ कर, पिस्तौल दिखा कर ल्यूडैनडोर्फ की सहायता से, एक ऐसे एलान पर दस्तखत करा लिए जिस में काहर के नाम से हिटलर की मदद करने के लिए जनता से अपील की गई थी। उस के बाद हिटलर ने सौरन अपने सैनिक इकट्ठे करके, अपने आप को बवेरिया का प्रमुख एलान कर दिया और बवेरिया के सारे मंत्रियों को गिरफ़्तार कर लिया। दूसरे दिन सबेरे ल्यूडैनडोर्फ और हिटलर अपनी सेना का एक जलूस बना कर राजधानी में से निकले। मगर सरकारी फ़्रीन से मुकाबला होते ही हिटलर के सैनिकों में भगदड़ पड़ गई। ल्यूडैनडोर्फ धोड़ा बढ़ा कर एक तरफ़ चला गया और हिटलर भाग गया।

डाक्टर स्ट्रेसमैन ने आधे दिन के उपद्रवों को दबाने और सरकार को मजबूत करने के लिए रीशटाग से सरकार के लिए खास अधिकारों की प्रार्थना की और रीशटाग ने उस की प्रार्थना मंजूर की। सेनाधिपति जेनरल स्टीकट को जो 'लोहे का मौन मनुष्य' कर के प्रख्यात था नए अधिकारों के अनुसार सरकार की तरफ़ से सारे जर्मनी का 'स्वाधीन सैनिक शासक' बना दिया गया। उस ने अधिकार हाथ में आते ही कम्युनिस्ट और क्रिस्ट दलों को गैर-कानूनी ठहरा दिया। मगर इसी बीच में समाजवादियों ने सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जिस से डाक्टर स्ट्रेसमैन को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। डाक्टर मार्क्स ने, समाजवादियों को छोड़ कर, नवंबर सन् १९२३ ई० में एक नया मन्त्रि-मंडल

बनाया जिस में उस ने स्ट्रैस्मैन को परराष्ट्र-सचिव और लूथर को ग्रंथ-सचिव रखा। बवेरिया का विद्रोह दबा दिया गया था। काहर अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे कर हट गया था। ल्यूडेनडोर्फ और हिटलर पर बवेरिया की अदालत में मुकदमा चलाया गया जिस में ल्यूडेनडोर्फ को तो उस की पुरानी सेवाओं का खयाल कर के छोड़ दिया गया मगर हिटलर को पाँच वर्ष तक किले में नज़रबंदी की सज़ा हुई। मगर उस से वह सज़ा भुगवाई नहीं गई। सब जगह शांति स्थापित हो गई थी। अस्तु, १५ फरवरी सन् १९२४ ई में निरोप अधिकारों के कानून की मियाद खत्म होने पर फिर से उस को नया नहीं किया गया। इधर रूढ़ का सत्याग्रह और जर्मनी से किश्ते बराल करने का तरीका तय करने के लिए 'डॉज कमीशन' नियुक्त हो गया था। अस्तु रूढ़ का सत्याग्रह भी बंद कर दिया गया।

डॉज कमीशन ने जर्मनी की आर्थिक दशा का ध्यान रखते हुए मुयावजा अदा करने के लिए सहूलियतें दी और जर्मनी के पैदावार के जरियों—अर्थात् रूढ़ जैसे स्थानों पर—मित्र राष्ट्रों का हाथ न रखने का फर्ज़ बताया। इंग्लैंड में इस समय पर समाजवादी नेता रैमसे मेकडानेल्ड प्रधान मंत्री था और फ्रांस में समाजवादी नेता हैरियट प्रधान-मंत्री था। जर्मन सरकार के लिए मित्र राष्ट्रों से मुयावजे के विषय पर समझौता करने के लिए यह अश्रद्धा बल्ल था। मगर डॉज कमीशन की रिपोर्ट निकलने से पहिले ही रीशदाग के भीतर और बाहर राष्ट्रवादियां ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिस से चांसलर को सरकार के लिए बहुत सख्ता का भरोसा नहीं रहा। अस्तु उस से रीशदाग को भग करा के नए चुनाव का एलान करा दिया। इसी चुनाव के तूफान में 'डॉज रिपोर्ट' प्रगट हुई। चुनाव के बाद भी रीशदाग में मित्र-राष्ट्रों से समझौते के पक्षपातियों की बहुसंख्या क्रायम रही। मगर उन की सख्या पहले से घट गई और राष्ट्रवादियों की सख्या बहुत बढ़ गई। डॉज रिपोर्ट पर अमल करने के लिए प्रजातन्त्र की राज व्यवस्था की शर्तों का सशोधन करने के लिए जिन दो तिहाई मतों की रीशदाग में सरकार को जरूरत थी वह सरकार के पक्ष में नहीं थे। अस्तु, बड़ी मुश्किल से मत्रि-मंडल ने डॉज रिपोर्ट पर अमल करने के लिए आवश्यक कानूनों को रीशदाग में स्वीकार कराया।

डॉज रिपोर्ट की शर्तों पर अमल करने के सबब में मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों और जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों का लंदन में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के ही पहली सच्ची सधि सम्पन्ना चाहिए। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप रूढ़ से फ्रांस की सेनाएँ हटा ली गई जिस से जर्मनी के राजनैतिन और आर्थिक जीवन में कुछ स्थिरता आना शुरू हुई। सब प्रकार के तूफानों को केल कर अत्र जर्मन प्रजातन्त्र भी इतना मजबूत हो चुका था कि उस के विरोधियों को, प्रजातन्त्र को उखाड़ कर फेंक देने के विचार धीरे धीरे बदल कर, सरकार के काम में भाग लेना ही उचित लगने लगा था। फिर भी रीशदाग में पुराने असंतोषियों की अभी तक भरमार थी। जर्मनी को अपने भविष्य की सुचारु पुर्नघटना करने के लिए सरकार की जी जान से मिल कर सहायता करनेवाली रीशदाग की जरूरत थी। डाक्टर मार्क्स को पुरानी रीशदाग की सहायता पर अधिक भरोसा नहीं रहा था। अस्तु उस ने प्रमुख ईवर्ट को सलाह दे कर २० अक्टूबर सन् १९२४ ई० से रीशदाग भग करा के ७

दिसंबर को नए चुनाव की तारीख नियत करा दी। मार्क्स को जैसी आशा थी नए चुनाव का नतीजा वैसा ही आया। सरकार के विरोधियों की कड़ी हार हुई। कम्यूनिस्ट दल के ६२ से घट कर ४५ और 'राष्ट्रीय समाजवादियों' के ३२ से, घट कर सिर्फ १४ सदस्य रीशटाग में रह गए। ठंडे विचार के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई। फिर भी समाजवादियों को सत्रह लाख और सब प्रकार के दूसरे राष्ट्रवादियों को पाँच लाख मत पिछले चुनाव से देश भर में अधिक मिले। परंतु इन दलों ने सरकार का विरोध करना छोड़ कर सरकार में श्रव भाग लेना निश्चय कर लिया था।

इसी बीच में प्रमुख ईबर्ट का देहांत हो गया। उस के मर जाने पर पहली बार राज-व्यवस्था की शर्त के अनुसार प्रजा के मतों से प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने का अवसर आया। अस्तु, सारे देश में हलचल मच गई। मगर जर्मनी के एक अत्यंत महान् पुरुष के प्रमुख-पद के लिए उम्मीदवार होने पर सब को दिलासा हो गया। हिंडनबर्ग को बहुत से लोग ल्यूडो-डोर्फ की तरह पुरानी राजाशाही का पक्षपाती समझते थे और इसी लिए उस के उम्मीदवार बनने पर समाजवादी-दल, मध्य-दल और दूसरे मध्यवर्ग के दलों ने उस का विरोध भी किया। मगर हिंडनबर्ग ने ल्यूडेनडोर्फ की तरह किसी पडयंत्र इत्यादि में कभी कोई भाग नहीं लिया था। प्रमुख चुने जाने के बाद भी उस ने प्रजातंत्र के प्रति वफादार रहने की शपथ ले कर, हमेशा शपथ का ईमानदारी से पालन किया, और राजाशाही में विश्वास रखने-वालों को प्रजातंत्रवादियों से मिलाने का सदा प्रयत्न किया। मगर मार्क्स नए चुनाव के बाद मंत्रिमंडल न बना सका और मध्यवर्ग के दलों की सहायता से लूथर चांसलर बना। राष्ट्रवादियों का सरकार में भाग लेना और हिंडनबर्ग का प्रमुख होना सब के लिए जर्मनी में शांति और स्थिरता के चिह्न थे। फ्रेप और काहु विद्रोहों को रखनेवाले केप्टन एरहार्ट तक ने देश-भक्तों की संस्थाओं से व्यर्थ का विरोध बंद कर के सरकार का साथ देने की प्रार्थना की। कैसरवाद के अखंड पुजारियों की प्रवृत्ति में यह परिवर्तन भी बड़े मार्के का था। जर्मनी के गविष्य में, देश के भीतर और बाहर, सब का विश्वास बढ़ने लगा था। लूथर और स्ट्रेस्मैन के प्रयत्नों से जर्मनी की लोकानों में मित्र-राष्ट्रों से संधि के हो जाने के बाद, जर्मनी लीग ऑफ नेशंस में भी शामिल हो गया। मगर इस संधि के परिणामस्वरूप लूथर के मंत्रि-मंडल का सहायक 'जर्मन राष्ट्रीय लोकदल' सरकार का साथी नहीं रहा और मंत्रि-मंडल को 'मध्यदलों' का बनाने के लिए मंत्रि-मंडल में फेरफार करना पड़ा। परंतु मई, सन् १९२६ ई० में लूथर को इस्तीफा दे देना पड़ा और 'मध्यदल,' 'ध्वेरेियन लोकदल,' 'राष्ट्रीय जर्मन लोकदल' और 'प्रजा-सत्तात्मक दल' की सहायता से फिर मार्क्स ने नया मंत्रि-मंडल बनाया जिस में डाक्टर स्ट्रेस्मैन परराष्ट्र-सचिव के स्थान पर रहा। यह मंत्रि-मंडल भी दिसंबर सन् १९२६ से अधिक न चला। दूसरा मंत्रि-मंडल 'प्रजा-सत्तात्मक दल' को छोड़ देने वाले नेता गेस्लर ने बनाया और वह जनवरी सन् १९२८ तक कायम रहा। उस के बाद कई मास तक किसी भी मंत्रि-मंडल को व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या मिलना दुर्लभ हो गया, और उसे ३१ मार्च सन् १९२८ को भंग कर के नए चुनाव का एलान कर दिया गया। बीस मई को होने वाले इस चुनाव में सरकार-

पक्षी दलों की बुरी तरह से हार हुई और 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' के सदस्य सत्र से अधिक संख्या में चुन कर आए। 'समष्टिवादी दल' की भी ताकत बढ़ गई।

समाजी प्रजासत्तात्मक दल के नेता हरमेन मुलर ने नया मंत्रिमंडल 'प्रजासत्तात्मक दल' और बेवेरियन लोस-दल की सहायता से बनाया। इस में भी पर-राष्ट्र सचिव डाक्टर स्ट्रेस्मैन ही रहा। इस मंत्रिमंडल ने, 'यंग प्लान' की योजना के अनुसार जर्मनी की मित्र राष्ट्रों को मुआवजा अदा करने की बातचीत चला कर, सन् १९२६ की पेरिस कान्फ्रेंस और सन् १९२६-२७ ई० की दो हेग कान्फ्रेंसों में मित्र राष्ट्रों से एक नया समझौता किया। मगर तबतब सन् १९२६ ई० में ही स्ट्रेस्मैन का स्वर्गवास हो गया और उस के स्थान पर, लोकदल का एक दूसरा सदस्य डाक्टर फ्रिट्ज परराष्ट्र सचिव के स्थान पर आ गया। 'जर्मन राष्ट्रीय दल' के नेता डाक्टर ह्यू जेनरर्स ने 'राष्ट्रीय समाजवादी दल' के नेता हिटलर से मिल कर 'यंग प्लान' की योजना को नामजूर कर देने के लिए जर्मनी में घोर आंदोलन उठाया। फिर भी कुछ बहुसंख्या से 'यंग प्लान' की योजना व्यवस्थापक सभा में मंजूर हुई। पर जर्मनी में आर्थिक संकट न घटा और देश में बेकारी बढ़ती ही गई। इस सरकार को भी हस्तीका देना पड़ा और 'मध्यदल' के नेता ब्रूनिंग ने मार्च सन् १९३० में नया मंत्रिमंडल बनाया। इस मंत्रिमंडल के सहायकों की भी व्यवस्थापक सभा में बहुसंख्या न थी। मगर 'राष्ट्रीय लोसदल' के विरोध न करने से यह मंत्रिमंडल फौरन ही नहीं निकाला गया। ब्रूनिंग ने अपने आर्थिक सुधारों को व्यवस्थापक सभा के सामने न रख कर उन को जर्मन राज-व्यवस्था में दिए हुए संकट के समय प्रमुख के फरमानी कानून जारी करने के विशेष अधिकार का प्रयोग कर के जारी कर दिया। व्यवस्थापक सभा में 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' और समष्टिवादी दल' ने मिल कर इस बात पर सरकार का विरोध किया। अस्तु, ब्रूनिंग ने व्यवस्थापक सभा मग करा दी और ३० सितंबर सन् १९३० नए चुनाव के लिए निश्चित कर दी। इस चुनाव में नरम और गरम दलों ने मिल कर सरकार की नीति को बड़ी निंदा की। इस चुनाव के बाद हिटलर के 'राष्ट्रीय समाजवादी दल' की, जो नाज़ी कहलाने लगे थे, वक़ायक ताकत बढ़ गई। 'समष्टिवादी-दल' की ताकत भी बढ़ी। बहुत-से पुराने दल मिट गए थे और कई नए दल अखाड़े में आ गए थे। मगर 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' की सहायता से ब्रूनिंग ने ही फिर भी मंत्रिमंडल बनाया और प्रजातन्त्र के प्रमुख के विशेष अधिकारों की सहायता से उस ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने और मित्र-राष्ट्रों को खुश कर के उन से जर्मनी का 'मुआवजों का बोझ कम कराने के प्रयत्नों की' नीति जारी रखी।

सन् १९३० ई० के चुनाव के बाद से सरकार-पक्षी सजीदा और नरम विचारों के दलों की शक्ति कम होने लगी और गरम और सरकारी नीति के विरोधी दलों का प्रभाव बढ़ने लगा। राजाशाही के पक्षपातियों में प्रजातन्त्र के सब से कट्टर दुश्मन मिलते थे, जो मौक़े के विचार से प्रजातन्त्र के साथी थे। उन का अभी तक सेना और राजा की बुद्धिमत्ता में विश्वास था। मगर उन के हाथ में प्रजातन्त्र को उखाड़ कर फेंक देने के लिए ताकत नहीं थी। प्रजातन्त्र के विरोधियों की ताकत उन के आपस के झगड़ों के कारण भी कम थी।



‘राष्ट्रीय समाजवादी दल’ और राजाशाही के पक्षपाती दोनों अपनी अलग-अलग वाँसुरियाँ बजाते थे। फिर भी प्रजातंत्र के विरोधियों का सब से बड़ा दल ‘राष्ट्रीय समाजवादी दल’ ही था। रोम पर मसोलनी की कूच की तरह ‘राष्ट्रीय समाजवादियों’ की बर्लिन पर सफल कूच की कोई बहुत संभावना तो नहीं दिखाई देती थी। मगर इतिहास में बहुत-सी असंभव लगने वाली बातें संभव हो चुकी हैं। जिन राष्ट्रीय समाजवादियों की सन् १९२४ के चुनाव में बिल्कुल ही सख्या कम हो गई थी, उन की सन् १९३० ई० से यथायक बहुत ताकत बढ़ गई। प्रमुख हिंडनबर्ग का सन् १९३२ ई० में अधिकार-समय पूरा होने पर जब चांसलर ब्रूनिंग ने रीशदाग में कानून पास कर के हिंडनबर्ग का अधिकार-समय कुछ दिन के लिए बढ़ाने की बात चलाई, जिस से कि ब्रूनिंग की जर्मनी के मुआयजा अदा करने की असंभावना पर मित्र-राष्ट्रों से चलाई हुई बातचीत में अच्छी सफलता मिल सके, तो हिटलर ने उस के प्रस्ताव को रीशदाग में स्वीकार नहीं होने दिया। बाद में प्रमुख के चुनाव में हिंडनबर्ग के मुकाबले में हिटलर स्वयं राड़ा हुआ। उस का कहना था कि “जर्मनी को मित्र राष्ट्रों से मिल कर काम करने से कुछ फायदा नहीं हुआ। लीग ऑव नेशंस का सदस्य हो जाने पर भी जर्मनी को अन्य राष्ट्रों के बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। स्ट्रेस्मैन ने मित्र-राष्ट्रों से मिल कर काम करने से जर्मनी को आर्थिक लाभ होने का विश्वास दिला कर सन् १९२३ से जर्मन सरकार को जिस नीति के मार्ग पर रखा उस से जर्मनी को कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा जर्मनी आर्थिक संकट में पड़ गया।”

इसी चुनाव के जमाने में पूँजीपतियों को अपने पक्ष में मिलाने की शरज से हिटलर ने हुत्सेलडोर्फ नगर में ६०० बड़े-बड़े कारखाने वालों को एक दायत में ढाई घंटे तक अपना कार्यक्रम समझाया। मगर आर्थिक और परराष्ट्र नीति पर उस के निश्चिन्न विचार सुन कर पूँजीपतियों को उस की बातों में अधिक श्रद्धा नहीं हुई। उस के दल के एक दूसरे नेता ने दल का कार्यक्रम इस प्रकार बताया, “हिटलर दल प्रजातंत्र का प्रमुख ‘मार्शल आर्म् दि रीश’ नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जिस की अभ्यक्षता में एक जनदल का संगठन किया जायगा जिस में लोग सैनिक सेवा करने के कर्तव्य के सिद्धांत के बजाय ‘अधिकार’ के सिद्धांत पर शामिल होंगे। ईसाई धर्म के सिवाय और किसी धर्म को नहीं माना जायगा। रोमन कानून और ‘सुवर्ण-कला मुद्रण’ (गोल्ड स्टैंडर्ड कैरेंसी) खत्म कर दिए जायेंगे। ‘मेहनत की योग्यता’ के सिद्धांत पर एक नया मुद्रण चलाया जायगा। विदेशी व्यापार पर कड़ी चुंगी लगाई जायगी, जिस से सरकार को ३०,००,००,००० मार्क का फर मिलेगा और इस फर की सहायता से जर्मनी का सारा ऋण बहुत शीघ्र पटा दिया जायगा। लड़ाई से अब तक जर्मन सरकार की नीति निश्चय करनेवालों पर मुकदमा चलाया जायगा और जो अपराधी ठहरेंगे उन को फाँसी दी जायगी।” एक स्थान पर व्याख्यान देते हुए हिटलर ने कहा कि, “आजकल जर्मनी पर राज करनेवाले दल चाहे अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हों अथवा न हों ‘राष्ट्रीय समाजवादी दल’ जर्मनी के अन्य सब-राजनैतिक दलों को मिट्टी में मिला देगा और उन की मिट्टी से एक नए जर्मन राष्ट्र की मीनार तैयार करेगा। जर्मनी की काति से ही जर्मनी की सारी आपत्तियाँ शुरू हुई हैं। जो

राजनैतिक दल आजकल जर्मनी के भाग्य विधाता बन रहे हैं, इन सब का उस क्रांति में भाग था। अस्तु उन सब को साक में मिला देने की जरूरत है। चांसलर ब्रूनिंग कहता है कि आनेवाली लूज़ान कान्फ्रेंस में जर्मनी को मुआवज़े में रियायतें मिलेंगी। मैं कहता हूँ कि अगर ब्रूनिंग का यह विचार है तो लूज़ान कान्फ्रेंस होवेगी ही नहीं। अगर ब्रूनिंग की सरकार खुद निकलने को राज़ी नहीं होगी तो हम उसे उठा कर फेंक देंगे। मैं जो कहता हूँ उस में आप को ज़रा भी सदेह नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेरे यहां खड़ा होने में आप को ज़रा भी सदेह नहीं होना चाहिए।”

हिंडनबर्ग को प्रमुख पद के लिए फिर खड़ा होने की बीच लाख हस्ताक्षरों की एक श्रृंखला के द्वारा प्रजा की तरफ से प्रार्थना की गई थी, और उस ने अपनी दस वर्ष की अवस्था का खयाल छोड़ कर देश को बचाने के लिए फिर प्रमुख पद के लिए खड़ा होना स्वीकार कर लिया था। हिंडनबर्ग पर देश और विदेश में सब को बहुत विश्वास था। चांसलर ब्रूनिंग के, जो स्ट्रेस्मैन की नीति का मज़बूती से पालन कर रहा था, उकता कर कई बार इस्तीफ़ा रख देने पर हिंडनबर्ग ने ही उसे रोक रक्खा था। हिटलर के हलज़ामों के उत्तर में ब्रूनिंग ने कहा कि “जर्मनी और दुनिया के आर्थिक बर्षों का एक कारण वारसेलज़ की संधि की शर्तें हैं। इन शर्तों के कारण पाँच वर्ष तक जर्मनी में आर्थिक जीवन की पुनर्घटना करने के सारे प्रयत्न अक्षरफल गए। जर्मनी की मुद्रा की जो अप्रयोगिता हुई, वह सभी को मालूम है। जर्मन प्रजातंत्र की सरकार का इस में कोई दोष नहीं था। बकवाद करना, हलज़ाम लगाना बहुत आसान है। मगर जो ज़िम्मेदार शख्स है वे जानते हैं कि जर्मनी का भीतरी आपत्तियों से छुटकारा सफल पर-राष्ट्रनीति पर निर्भर है। जिस समय अन्य राष्ट्रों से अच्छा पैसला करने के लिए सारे जर्मनी को मिल कर जोर लगाने की जरूरत है, उस समय दुर्भाग्य से हिटलर ने वित्तावादा खड़ा कर के देश के भीतर ही कगड़ा शुरू कर दिया है।” ब्रूनिंग का कहना शायद सच था। इस ने हमलों और गालियों की परवाह न कर के जर्मन सरकार की नाव इस होशियारी से चलाई थी कि अन्य राष्ट्र भी मानने लगे थे कि अगर जर्मनी के सिर पर से मुआवज़ों का बोझ कम नहीं किया जायगा तो उस की नाव डूब जायगी। दुनिया भर में सब से बड़े हवाई जहाज़ फ्रांक ज़ेपलिन के कमांडर डाक्टर ह्यूगो ऐक्नर ने, जिस की अपने हुनर में सफलता, दारे हुए जर्मनी के नाज़ की एक चीज़ थी, रेडियो पर जर्मनी से हिंडनबर्ग और ब्रूनिंग को सहायता करने की प्रार्थना करते हुए कहा, “क्या हम जर्मनों की राजनैतिक बुद्धि का चिट्ठुल दिवाला पिट गया है कि जिस मुआवज़े के सफल समझौते पर जर्मनी का भविष्य और भाग्य निर्भर है, उसी समझौते की चर्चा के समय सरकार की पूरी तरह सहायता करके उसे मज़बूत करने के बजाय सरकार पर हमले कर रहे हैं। जर्मनी के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दलबदी के जोश में हम देश का हित भूल जा रहे हैं।” इस प्रसंग पर प्रजा पर अघर पाठक सोच सकते हैं। हिटलर आंदोलन का मुक़ाबला करने के लिए बहुत से दलों, मज़दूर सभों, अखाड़ों, प्रजा तन और अन्य संस्थाओं ने मिल कर ‘फौलादी मुक़ाबला’ नाम का एक संगठन तैयार किया और २१ फरवरी सन् १९३२ ई० को जर्मनी

भर में प्रजातन्त्र सरकार के पक्ष में हजारों सभाएँ की गईं और जलूम निकाले गए। प्रमुख के चुनाव में हिटलरवादी को सब से अधिक मत मिले। मगर चुनाव में पड़नेवाले सारे मतों के आधे से अधिक मत हिटलरवादी को न मिलने से राज व्यवस्था की शर्त के कारण उस का चुनाव नहीं हो सका। दूसरे चुनाव में हिटलरवादी को १,६३,६७,६८८ मत मिले, हिटलर को १,३४,१६,६०३ मत मिले, और समष्टिवादी उम्मीदवार गैलमान को ३,४८,६०० मत। हिटलरवादी का चुनाव हो गया। मगर धार्मिकता के मजबूत भागों में बँधे हुए 'कैथोलिक मध्यदल' और मजदूर सघों के कारण मजबूत 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' को छोड़ कर हिटलर के नाज़ीदल और 'समष्टिवादी दल' की क्रांति की चुनौती के मुकाबले में सारे दूसरे दल इस चुनाव में लुप्त हो गए। 'कैथोलिक मध्यदल' और 'समाजी प्रजासत्तात्मक-दल' की सहायता से हिटलरवादी चुन अवश्य लिया गया मगर उस के लिए मत डाल कर 'प्रजातन्त्र को कायम रखने और सजीदा पर-राष्ट्रनीति कायम रखने के लिए मत देनेवालों से, इतने प्रयत्नों के बाद भी, इस नीति के विरुद्ध क्रांति में भेदा रखनेवाले नाज़ी और समष्टिवादी' दलों के दोनों सदस्यों को मत देनेवालों की संख्या अधिक रही। ब्रूनिंग के हिटलरवादी से विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की फिर प्रार्थना करने पर हिटलरवादी ने वैसा करने से इन्कार कर दिया और ब्रूनिंग मन्त्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। हिटलर ने एलान किया कि जब तक उस के दल की व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या न होगी, तब तक न तो वह स्वयं चांसलर बनेगा और न किसी दूसरे मन्त्रिमंडल में मन्त्रि-पद ग्रहण करेगा। समाजवादी-दल के व्यवस्थापक-सभा में सब से अधिक सदस्य थे। मगर किसी भी दल की सरकार न बनाई जा सकी। हिटलरवादी ने अपने 'आपत्ति-काल के विशेष अधिकारों' का प्रयोग कर के तीन मन्त्रियों का एक अस्थायी मन्त्रिमंडल, व्यवस्थापक सभा का नया चुनाव होने तक, काम चलाने के लिए रख दिया। फिर प्रशिया रियासत के चुनाव में भी जिस को जर्मन राजनीति की कुजी माना जाता है, नाज़ियों की जीत हुई। देश भर में नाज़ियों और समष्टिवादियों की जगह-जगह पर, उसी प्रकार मार-काट छिड़ गई जिस प्रकार लड़ाई के बाद इटली में फेसिस्ट और समष्टिवादियों या समाजवादियों में होती रहती थी।

सन् १९३३ ई० के चुनाव में नाज़ीदल की जोरदार जीत हुई और उस ने सरकार की बागडोर अपने हाथ में आते ही साफ़ एलान कर दिया कि दूसरे किसी दल को जिंदा नहीं रहने दिया जायगा। कम्युनिस्ट दल को गैरकानूनी ठहरा दिया गया और उस दल के जो ८१ प्रतिनिधि रीशटाग में चुन कर आए थे उन को रीशटाग में बैठने नहीं दिया गया। इस के कुछ ही दिन बाद समाजवादी दल को भी गैरकानूनी ठहरा दिया गया और उस के तमाम प्रतिनिधियों को सरकारी घारा-समाजों और चुगियों इत्यादि से हटा दिया गया और इस दल के सारे अखबार बंद कर दिए गए और उन की सारी जायदाद भी जब्त कर ली गई। इस के बाद रहे सड़े राजनैतिक दल कुछ ही हफ्ते में अपने आप लुप्त हो गए। जुलाई १९३३ में एक कानून पास कर के नाज़ी दल के सिवाय दूसरे दलों का बनना गैरकानूनी ठहरा दिया गया। इस के बाद जो चुनाव हुए उस में सिर्फ नाज़ी दल के उम्मीदवारों की ही सूचियों के लिए मत दिए जा सकते थे। विरोध

ज़ाहिर करने का सिर्फ़ एक जरिया था कि मत डालते वक्ता पचाँ ख़राब कर दिया जाय ।

वीमार राज-व्यवस्था को क़ानून बना कर रद्द तो नहीं किया गया, मगर यह मृतप्राय कर दी गई । ४ मार्च १९३३ ई० को राज-व्यवस्था के लिए ज़रूरी तीन चौथाई सदस्यों के मतों से रीश्टाग में एक राष्ट्र और जनता की भीमारियाँ दूर करने के लिए क़ानून 'पास किया गया' जिस में सरकार को राज व्यवस्था की दूसरी सारी सस्थाओं के ऊपर पूरी सत्ता दे दी गई । इस क़ानून की पहली धारा के अनुसार सरकार को राज-व्यवस्था की दूसरी सस्थाओं के बिना सहकार के हर किस्म के क़ानून बनाने का अधिकार है । यहाँ तक कि सरकार राजव्यवस्था के विरुद्ध भी क़ानून बना सकती है । इस क़ानून की तिथि १ अप्रैल सन् १९३७ ई० तक रक्की गई, और इस का उपयोग फ़ेनल हिटलर मनि-मंडल ही कर सकता था । वीमार राज व्यवस्था की धारा ४८ के अनुसार प्रजातन्त्र के प्रमुख को अपने हुक्म से आपत्ति के समय क़ानून जारी करने की शर्त फ़ायम रही । मगर उस का कुछ अर्थ नहीं रहा, क्योंकि प्रजातन्त्र के प्रमुख के हस्ताक्षरों के साथ चाणलर के हुक्म की शर्त उस में जोड़ दी गई । रीश्टाग का भी पहले की तरह क़ानून बनाने का अधिकार फ़ायम रहा मगर यह मान लिया गया कि वह अपने इस अधिकार का उपयोग सरकार की मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं करेगी । इस क़ानून के अनुसार सरकार का कोई भी काम जिस से वीमार राज-व्यवस्था के अनुसार निश्चित प्रजा के अधिकारों या किसी दूसरे प्रकार के राजनैतिक अथवा सामाजिक संगठन पर प्रहार पड़ता हो क़ानूनी ठहरा दिया गया । अस्तु, वीमार राजव्यवस्था अब सिर्फ़ वहीं तक फ़ायम है जहाँ तक कि सरकारी हुक्मों और अमलों से उस की धाराओं पर असर नहीं पड़ा है ।

वीमार राज व्यवस्था में किसी से जिस के माता पिता जर्मन जाति के हों या जो जर्मनी में बस गया हो जर्मन नागरिकता का अधिकार नहीं छीना जा सकता था । मगर सन् १९३३ ई० के एक क़ानून से सन् १९१८ ई० के बाद जर्मन नागरिक बननेवाले 'सामान्य राजनैतिक दृष्टि से अनुचित लोगों और उन लोगों के जो 'देश के प्रति अपना कर्तव्य न कर के दूसरे देशों को चले गए' नागरिकता के अधिकार छीन लेने की इजाजत भी सरकार को दे दी गई । दूसरे कई क़ानूनों से विदेशी जानियों के जर्मनी में रहनेवाले लोगों के जर्मनी के राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने की भी रोकथाम कर दी गई । यह भी कहा जाता था कि आगे चल कर नागरिकता के अधिकार सिर्फ़ उन्हीं को रहेंगे जो कुछ खास राजनैतिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे, जैसे कि मेहनत मजदूरी करने का कर्तव्य ।

जैसा कहा जा चुका है, समाधिवादी अर्थात् कम्यूनिस्ट दल, समाजवादी अर्थात् सोशलिस्ट दल तो ग़ैरक़ानूनी ठहरा कर रद्द कर दिए गए और दूसरे रहे-सहे दल या तो ख़ुद हो गए या नाज़ी दल में मिल गए । 'राष्ट्र और प्रजा की भीमारियाँ दूर करने के लिए जो 'क़ानून' बनाया गया उस में प्रजा के प्रतिनिधियों के लिए रीश्टाग फ़ायम तो रक्की गई, मगर रीश्टाग की बिना चलाह लिए ही सरकारी क़ानून जारी हो जाने को जायज़ मान कर रीश्टाग के सामने सरकार सिर्फ़ अपनी नीति की रिपोर्टें रखने लगी । सरकार की तरफ़ से जो एलान हुए उन में कहा गया कि प्रजातन्त्र की नीति फ़ायम रखने के लिए

सरकार आप खास कामों पर प्रजा की राय लेगी। बाद में एक कानून बना कर सरकार को किसी भी विषय पर सीधा प्रजा से राय लेने के लिए हवाले का अधिकार भी दे दिया गया। ७ अप्रैल सन् १९३३ ई० को तमाम जर्मन रियासतों को राष्ट्र से एक करने के लिए एक कानून बनाया गया जिस से बिस्मार्क के समय से राज-व्यवस्था के मूल फ्रेडरल सिद्धांत पर ही कुठाराघात कर दिया गया। इस कानून के अनुसार रियासतों में प्रतिनिधि सरकार की संस्थाएं तोड़ दी गईं और राष्ट्रीय रीश सरकार की तरफ से हर रियासत में एक रीश कमिश्नर नियत कर दिया गया जिस को सब तरह के पूरे अधिकार दे दिए गए। इन रीश कमिश्नरों का काम रियासतों में चांसलर की नीति के अनुसार सारा सरकारी काम चलाना है, और प्रशिया रियासत का रीश कमिश्नर स्वयं चांसलर है। बीमार राज-व्यवस्था के अनुसार रीशराट सभा में विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि आते थे जो रीशराट के फैसलों के विरुद्ध राय दे कर उन फैसलों को रद्द कर सकते थे और इस प्रकार रीशराट के फैसले रद्द हो जाने पर वह फिर कानून तभी बन सकते थे जब उन पर रीशराट पुनः विचार कर के उन को फिर से दो-तिहाई सदस्यों के मतों से स्वीकार करती थी। मगर नाज़ी राज-व्यवस्था में रीशराट को कायम रख कर भी रियासतों में प्रतिनिधि राज रह कर देने से रीशराट बिल्कुल एक बेकाम संस्था हो गई है। इसी प्रकार बीमार राज-व्यवस्था में दस विभिन्न व्यापार और उद्योग की शाखाओं के ३२६ प्रतिनिधियों की जो एक अर्थ-समिति बनाई गई थी, उस के सदस्य भी एक कानून बना कर घटा कर अधिक से अधिक साठ कर दिए गए और उन को नियुक्त करने का अधिकार सरकार की राय से प्रमुख को दे दिया गया। नित्य जर्मन सरकार में इसी प्रकार की तबदीलियाँ की जा रही हैं, जिस से जाहिर है कि नाज़ी दल भी फेसिस्ट सरकार का रंग पकड़ रहा है।

परंतु नाज़ी सरकार और फेसिस्ट सरकार में अंतर है। नाज़ी सरकार में व्यक्तियों के नेतृत्व पर जोर दिया जाता है और फेसिस्ट सरकार में सामूहिक अधिकार पर। जर्मनी में राष्ट्र का नेता हिटलर को माना जाता है और उस के नीचे बहुत-से छोटे-छोटे हिटलर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंगों के नेता हैं। परंतु इटली में राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंगों पर सामूहिक नियंत्रण रहता है। हाँ, इस तमाम राष्ट्रीय नियंत्रण के ऊपर मसोलनी का अधिकार अवश्य माना जाता है। वह जिस काम में चाहे दखल दे सकता है। नाज़ी और फेसिस्ट सरकार में यह बहुत बड़ा अंतर है। यह ज़रूर सच है कि सन् १९३४ ई० तक भी इटली में सामूहिक नियंत्रण पूरी तरह अभल में नहीं आ सका था और सरकार का संबंध मजदूरों के मुकाबले में मालिकों से ही अधिक रहता था। जर्मनी में भी उसी तरह ताकत मालिकों के हाथों में रही। मगर जर्मनी की सरकार में फ़ौजी गुट का बहुत हाथ रहा जिस की इच्छा के अनुसार ही उद्योग-धंधों के मालिक चल सकते हैं। इटली में फेसिस्ट दल फ़ौजी गुट और उद्योग-धंधों के मालिक दोनों के मेल से शासन चलाता है। मगर जर्मनी में फ़ौजी गुट का उद्योग-धंधों के ऊपर पूरा अधिकार है और उस की मर्जी के अनुसार ही उद्योग-धंधों को चलना पड़ता है।

जर्मनी के फ़ौजी गुट का कहना है कि पिछली यूरोप की लड़ाई में जर्मनी की

लड़ाई के मैदान में हार नहीं हुई। खाने-पीने और लड़ाई के सामान की कमी की वजह से जर्मनी को हथियार रख देने पड़े। अस्तु, वह जर्मनी में यह चीजें पैदा करना चाहते हैं जिस से दूसरी लड़ाई में जर्मनी को इस सामान के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। देश के भीतर ही पैदा होनेवाली चीजों से सारे ज़रूरत के सामान बनाने के लिए जैसे कि कोयले से पेट्रोल और चूने से खर बनाने के लिए खर्च का कुछ भी खयाल न कर के बेहद कोशिश की जा रही है। उद्योग-धंधों के मालिकों को इस प्रकार के उद्योगों में अपना रुपया लगाने के लिए अधिक मुनाफ़े का लालच देने के लिए ज्यादा रुपया गढ़ कर चीजों की कीमतें तेज़ की जा रही हैं; मज़दूरों की मज़दूरी घटाई जा रही है; रहन-सहन नीचा किया जा रहा है। देश के बाहर से कोई माल जर्मनी में बिना सरकार की इजाज़त के नहीं घुस सकता। जहां तक बनता है बाहर का माल देश में नहीं आने दिया जाता और सरकार दूसरे देशों से व्यापारी संधियों के द्वारा माल का तबादला करती है। देश के भीतर मज़दूरी का दर कम होने और रहन-सहन नीचा होने से भी बाहरी माल की माँग कम रहती है और देशी व्यापारियों को उद्योग में अधिक मुनाफ़े का लालच रहता है। परंतु साथ ही जर्मन सरकार ने हिस्सेदारों को एक खास हद से ज्यादा मुनाफ़ा बाँटना फ़ानूतन नाजायज़ कर दिया है और इस खास मुनाफ़े से ऊपर जो कुछ रुपया बचता है वह व्यापारी पेटियों को सरकार को कर्ज़ दे देना होता है, जिसे सरकार सड़कों इत्यादि तथा इमारती कामों में लगाती है, जिस से लोगों में बेकारी न बढ़े।

परंतु नाज़ी सरकार की यह नीति उन तमाम बादों और प्रोग्राम से बहुत भिन्न है जो नाज़ी दल के ताक़त में आने से पहले इस दल की तरफ़ से उस के नेताओं ने किए थे। राष्ट्रीय समाजवादी कहलानेवाले नाज़ी दल के कामों में राष्ट्रीयता और साम्राज्यशाही तो दीखती है; परंतु उस में समाजवाद की कहीं झलक भी नहीं दीखती। ताक़त में आने से पहले नाज़ी दल अपने को समाजवादी और बड़े व्यापारियों का दुश्मन कहता था। परंतु अब बड़े व्यापारी और उन की व्यापारिक संघों का ही नाज़ी दल अपनी नीति को पूरा करने के लिए सब से बड़ा हथियार समझता है। मज़दूरी या रहन-सहन ऊँचा करने और मुनाफ़ा कम करने के बजाय नाज़ी दल मज़दूरी और रहन-सहन को नीचा रख कर उद्योग-धंधों के मालिकों को अधिक मुनाफ़े का लालच दे कर उद्योग-धंधे बढ़ाने के लिए उत्साहित करता है। जनता के हाथों में खरीदने की ताक़त न बाँट कर यह दल इस ताक़त को बड़े व्यापारियों और सरकार के हाथों में इकट्ठी कर रहा है। सरकार के द्वारा बड़े-बड़े व्यापारों का सामाजिक हित में संगठन न कर के नाज़ी सरकार निजी व्यापार को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है, और उन तमाम जायदादों और व्यापारों को जो देयालिया हो कर पिछली आपत्ति में सरकार के हाथों में आ गए थे फिर व्यापारियों को वापस कर रही है।

नोट—हिटलर ने अब आस्ट्रिया को भी जर्मन रीश में शामिल कर लिया है। अतएव अब यहाँ की सरकार भी इसी बंग की हो जायगी।

# स्विट्ज़रलैंड की सरकार



## १—राज-व्यवस्था

जर्मनी और इटली के बीच में बसे हुए देश स्विट्ज़रलैंड की सरकार राजनीति शास्त्र का अध्ययन करनेवाला के लिए सदिया से ज्ञान का कुंड रही है। भारतवर्ष के राजनैतिक भविष्य की चिन्ता करनेवाले भा स्विट्ज़रलैंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूरोप में सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड की जमीन पर ही सघीय सरकार <sup>१</sup> का प्रयोग अच्छी तरह आजमाया गया। इसी देश में सार्वजनिक 'प्रस्तावना' <sup>२</sup> और सार्वजनिक 'हवाले' <sup>३</sup> की अद्वितीय प्रजा-सत्तात्मक संस्थाओं का जन्म हुआ तथा स्विट्ज़रलैंड में ही अनुपात निर्वाचन की पद्धति को पहली सफलता मिली। सार्वजनिक पचायतों के द्वारा सरकार का काम अभी तक इस देश में बहुत जगह पर चलाया जाता है। सघीय राष्ट्र, प्रत्यक्ष सरकार <sup>४</sup> और अनुपात निर्वाचन इत्यादि को अन्य तो यूरोप में सभी समझते हैं। मगर एक समय था जब कि यह संस्थाएँ स्विट्ज़रलैंड की ही विशेषता थीं। बहुत से राजनीति के विद्वानों और लेखकों का कहना है कि प्रजासत्ता को स्विट्ज़रलैंड के बराबर कहीं विकास और कार्य का क्षेत्र नहीं मिला। इस का मुख्य कारण स्विट्ज़रलैंड की प्राकृतिक दशा को भी कहा जा सकता है। एक तो स्विट्ज़रलैंड १५६७६ वर्ग मील का छोटा <sup>५</sup> सा देश है अर्थात् लगभग जयपुर रियासत के बराबर, यानी हमारे समुत्तम प्रांत के विषट्वातवें भाग के बराबर है। दूसरे यह देश पहाड़ी प्रदेश होने से छोटे-छोटे भागों में बंटा हुआ है जिस से स्थानिक भेदों के कारण देश की सरकार ने स्वभावतः सघीय रूप धारण कर लिया।

<sup>१</sup> फ़ेडरल गवर्नमेन्ट । <sup>२</sup> इनीशियेटिव ।

<sup>३</sup> रेफ़रेन्डम । <sup>४</sup> डायरेक्ट गवर्नमेन्ट ।

छोटे-छोटे भागों में तरह-तरह के राजनैतिक प्रयोग करना आसान होने की वजह से स्विट्जरलैंड बहुत-सी नई राजनैतिक सस्थाओं का जन्मदाता बन गया। पहाड़ी प्रदेशों का कठोर जीवन हमेशा से स्वतंत्रता, समता और प्रजासत्ता के भावों और विचारों का उत्तेजक रहा है। अस्तु स्विट्जरलैंड में बहुत पहले ही प्रजातन्त्र राज्य का कायम हो जाना एक प्रकार से आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती।

भारतवर्ष की बहुत सी भाषाओं, धर्म और जातियों की समस्या का मन में हिमालय खड़ा करके जो लोग हमारे देश के भविष्य के विषय में निराश हो उठते हैं वे स्विट्जरलैंड से इस विषय में पाठ ले सकते हैं। भारतवर्ष के १/१२ भाग के बराबर सिर्फ ३७५,३२६३ की आबादी के इस देश में सन् १६१० ई० की मर्दुमशुमारो के अनुसार ६६ फी सदी लोग जर्मन-भाषा भाषी थे, २१.१ फी सदी फ्रेंच-भाषा-भाषी, ८ फी सदी इटैलियन भाषा-भाषी और एक फी सदी सिंधी और कच्छी की तरह एक प्रकार की स्थानिक भाषा रोमाश बोलनेवाले थे। स्विट्जरलैंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी पट्टह कैंटनों<sup>१</sup> में अधिकतर जर्मन भाषा बोली जाती थी। छोर के पाँच पश्चिमी कैंटनों में फ्रेंच और दक्षिण के सिर्फ एक कैंटन में इटैलियन का जोर था। यही हाल धर्मों का भी था। देश भर में ५६.७ फी सदी प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग थे, ४२.८ फी सदी रोमन कैथोलिक संप्रदाय के थे और ५ सदी यहूदी थे। इटैलियन करीब करीब सभी रोमन कैथोलिक पय के थे। परन्तु फ्रांसीसी और जर्मनों में जाति और धर्म के एक ही भाग नहीं थे। जिस प्रकार बंगाली, पंजाबी, सिंधी और तामिल भाषा भाषी हिंदू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई सभी होते हैं उसी प्रकार स्विट्जरलैंड की जर्मन और फ्रांसीसी जातियों में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, और यहूदी सब थे। दस कैंटनों में प्रोटेस्टेंटों की संख्या अधिक थी और बारह कैंटनों में कैथोलिकों की अधिक थी। परन्तु यह सब लोग आपस में मिल कर स्विट्जरलैंड के नागरिक बन कर रहते हैं और जाति और धर्म का भेद उन की राजनीति में समस्याओं के पहाड़ नहीं खड़े करता। इसी प्रकार आर्थिक भेद भी हैं। सारा देश कृषि और पशु-पालन पर निर्भर रहता है। मगर उत्तर और पश्चिम के कई प्रांतों में उद्योग धर्मों का बहुत जोर है। कृषि और उद्योग के अलग अलग हित अन्तर स्विट्जरलैंड की राजनैतिक समस्याओं का कारण बन जाते हैं। मगर उद्योग के कारखाने अधिकतर छोटे छोटे होने और औसतन बीस एकड़ जमीन से अधिक के स्विट्जरलैंड में मालिक न होने से लोगों में स्वतंत्रता और प्रजासत्ता की भाक्ति अधिक है।

लूजर्न झील के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर की निर्जन तराइयों में बसी हुई तीन व्यूटानिक जातियों ने तेरहवीं सदी के अंत के करीब हैम्बर्ग के सरदारों की लूट से अपनी रक्षा करने के लिए आपस में एक कौल किया था। इस 'कौल' के शुरू के शब्दों इस प्रकार थे, "ईश्वर के नाम में जरूरी अमन चैन कायम करने के लिए कौल करार कर से इज्जत आबरू और प्रजा के मुद्दे की वृद्धि होती है। अस्तु, सब यादमियों को मालूम हो कि उरी की तराई के लोगों ने, स्वीज की तराई की प्रजासत्ता, और निडवाल्डन तराई की पहाड़ी जाति ने, बुरे समय को देख कर, अपनी और अपने समों की अन्धरी तरह रक्षा कर



सकने के लिए, एक दूसरे की आपस में हाथ पैर से सहायता, सलाह और हर प्रकार से, जान और माल से, तराइयों के भीतर और बाहर, पूरी ताकत और प्रयत्न से, अपने में से किसी पर अत्याचार करनेवाले या किसी का नुकसान या अपमान करनेवाले के मुकाबले में मदद करने की श्रद्धा के साथ शपथ खाई है। और हर एक जाति ने हर प्रकार से, अपने खर्च पर, जब दूसरे पर सकुट पड़े तब उस की मदद के लिए दौड़ने और नुकसान करने वालों के हमलों से उस की रक्षा करने और नुकसान का बदला लेने का वादा किया है।”

स्विट्जरलैंड राष्ट्र की प्रजासत्ता का यह ‘कौल-करार’ श्रीगणेश कहा जा सकता है। बाद में धीरे धीरे तीन जातियों की इस सभ में और भी ग्रामीण जातियाँ और शहर शामिल होते गए। सन् १३५३ ई० में तीन से बढ़ कर आठ कैंटनों की यह सभ हो गई थी और सन् १५१३ ई० में इस सभ में तेरह कैंटन थे। पंद्रहवीं सदी में यह सभ मध्य-यूरोप में एक शक्ति हो गई थी। उस काल के प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिकों के झगड़ों का सभ पर असर होने का बड़ा भय था क्योंकि आधे कैंटन प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के और आधे रोमन कैथोलिक पथ के थे। परंतु अपनी अपनी रक्षा के हित के विचार ने सभ को कायम रक्खा। सन् १६४८ ई० में वेस्ट-फेलिया की संधि में इस सभ को यूरोप का एक स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया। सभ के भीतर की जातियों की राजनैतिक समस्याएँ आपस में एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। ग्रामीण कैंटनों में पालिस प्रजासत्ता थी। प्रजा की सार्वजनिक सभाओं के द्वारा सरकार का काम चलाया जाता था। कुछ नगरों में थोड़े से अमीर-उमरावों के हाथ में सरकार थी और कुछ नगरों में अमीरों के साथ प्रजा का भी हाथ सरकार में रहता था। चूंकि सभ सिर्फ आन्तरिक और रक्षा के लिए बनी थी, भीतरी मामलों में कैंटनों को अपना-अपना कामकाज करने की पूरी आजादी होती थी। सभ की सभा सिर्फ बाहरी बातों और उन बातों पर विचार करने के लिए होती थी जिन बातों का सन कैंटनों से संबंध होता था। कैंटनों से सभा में आनेवाले प्रतिनिधि अपने अपने कैंटनों की हिदायतों के अनुसार कार्यवाही में भाग लेते थे। सभ की कोई केंद्रीय कार्यकारिणी नहीं थी। कुछ कैंटनों के पास लड़ाई में जीती हुई जागीरे भी थीं। इन जागीरों के लोगों पर यह कैंटन राज्य करते थे और उन की प्रजा को वे वही स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं थे जिस को वे अपना अधिकार समझते थे।

फ्रांस की राजक्रांति से स्विट्जरलैंड में भी उथल-पुथल हुई। सन् १७६८ ई० में फ्रांस की सेना ने स्विट्जरलैंड में घुस कर मारकाट की और स्विट्जरलैंड की इस पुरानी राज-व्यवस्था को भग कर दिया। स्विट्जरलैंड को सभ्य बनाने के लिए उत्सुक नेपोलियन ने सभ के ढीले बंधनों के स्थान में फ्रांस के ढंग की स्विट्जरलैंड में एक कड़ी केंद्रीय नौकरशाही राज व्यवस्था कायम कर दी। जिस का नाम उस ने ‘हेल्वेटिक प्रजातंत्र’ रक्खा। इस प्रजातंत्र की लिखित राज व्यवस्था में दो सभा की व्यवस्थापक सभा की एक केंद्रीय सरकार, कैंटनों की आबादी के अनुसार अप्रत्यक्ष ढंग पर चुने हुए प्रतिनिधियों की एक ‘ग्रांड कौंसिल’ और हर कैंटन से चार चार सदस्यों की एक सिनेट, कौंसिल और सिनेट के द्वारा निर्वाचित डाइरेक्टरी नामक फ्रांस की तरह एक कार्यकारिणी और डाइरेक्टरी के पाँच सदस्यों के साथ मिल कर काम करने के लिए चार नियुक्त विभाग-पतियों की योजना की गई थी। स्थानिक शासन के

लिए फ्रांस के डिपार्टमेंटों की तरह देश को तेईस कैंटनों में बाँटा गया था। हर कैंटन के लिए एक निर्वाचित धारा-सभा और केंद्रीय सरकार की ओर से शासन चलाने के लिए नियुक्त एक प्रीफेक्ट की योजना की गई थी। सर्वदेशीय नागरिकता, सार्वजनिक मताधिकार, बोल और लेख की स्वतंत्रता, सर्वदेशीय फौजदारी के कानून, सिक्कों और डाक इत्यादि के बहुत से जरूरी सुधार भी किए गए। मगर फ्रांसीसियों का शासन स्वतंत्रता प्रेमी स्विट्जरलैंड के लोगों को पसंद नहीं था। अस्तु इस राज-व्यवस्था के विरुद्ध चारों तरफ विद्रोह और बखेड़े होने लगे। लाचार हो कर नेपोलियन ने बर्न में बड़े लोगों की एक सभा बुलाई और उस की राय से सन् १८०२ ई० में एक दूसरी राज-व्यवस्था स्थापित की। मगर प्रजा ने बीस हजार वोट से इस नई राज व्यवस्था को भी नामजूर किया। फिर भी नेपोलियन की शक्ति का नाश होने तक अर्थात् सन् १८१५ ई० तक यही राज-व्यवस्था कायम रही। नेपोलियन के बाद सन् १८१५ ई० में सारे कैंटनों ने आपस में मिल कर एक 'संघीय करार' किया जिस के अनुसार सन् १७९८ की राज व्यवस्था पुनः स्थापित की गई पुरानी संघीय सभा जिस में हर कैंटन का एक मत होता था फिर कायम हो गई। परंतु इस सभा को श्रय की वार किसी भी जिले में बखेड़ा होने पर सेना में भेजने का अधिकार भी दिया गया, और तीन-चौथाई कैंटनों की मर्जी से सभा युद्ध और संधि भी कर सकती थी। ज्यूरिच, लूज़र्न और बर्न की कैंटनों की कार्य कारिणियों को दो-दो वर्ष के लिए वारी-वारी से संध की कार्य कारिणी का काम सौंपा गया।

सन् १८३० ई० के बाद से यूरोप में उठनेवाली क्रांतिकारी लहर ने स्विट्जरलैंड में भी विप्र किया था। सन् १८४३ ई० में केथोलिक-पथी स्विट्जरलैंड के सात कैंटनों ने अपने हितों की रक्षा करने और संध की इस प्रकार पुनर्घटना का विरोध करने के लिए, जिस से केथोलिक प्रभाव और अधिकार कम हों, आपस में 'सोडरबंड' नाम की एक मैत्री स्थापित कर ली थी। सन् १८४७ ई० में बर्न में होने वाली 'संघीय सभा' ने इस मैत्री को अस्वीकार किया। परंतु मैत्री बनाने वाले कैंटनों ने सभा की बात नहीं मानी। अस्तु, उन्नीस दिन तक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कैंटनों का आपस में घनघोर संग्राम हुआ और इस मैत्री का भंग २ के नष्ट कर दिया गया। फ्रांस के राजा लुई को गद्दी से उतार कर फेंकने के एक हत्ता पहले स्विट्जरलैंड की 'संघीय सभा' ने एक नई राज व्यवस्था स्वीकार की और सन् १८७४ ई० में स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार को और भी मजबूत बनाने के लिए इस राज-व्यवस्था को बदल कर एक नई राज-व्यवस्था रची गई, जो आज तक स्विट्जरलैंड में कायम है।

स्विट्जरलैंड की सरकार संघीय <sup>१</sup> है। प्रमुखा <sup>२</sup> राष्ट्र के समुचित मतदारों की है। राष्ट्रीय सरकार और कैंटनों की सरकार में राष्ट्र के मतदारों ने सत्ता बाँट दी है, अर्थात् संघीय और कैंटन—दोनों सरकारों—का आधार प्रजा ही है। यह सच है कि जो सत्ता संघीय सरकार को कानूनों में नहीं दी गई है, उस का कैंटनों की सरकारों में समावेश माना गया है। परंतु प्रमुखा न संघीय सरकार की है और न कैंटनों की सरकार की, बल्कि राष्ट्र के मतदारों की मानी गई है। स्विट्जरलैंड की राज-व्यवस्था में कैंटनों की भूमि और प्रमुखा

की रक्षा का—जहाँ तक सघीय सरकार की प्रभुता के अलावा उन को प्रभुता है—सघीय सरकार को जिम्मेदार माना गया है। कंटनों को अपनी राज-व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सरकार से मदद माँगने का हक है, और अगर उन की राज-व्यवस्था में सघीय राज व्यवस्था की शर्तों के खिलाफ कोई शर्तें न हों और उन में प्रजातन्त्र शासन के अनुसार लोगों को अधिकार प्राप्त हो और उन की राज-व्यवस्थाओं को प्रजा ने स्वीकार किया हो, और प्रजा के बहुमत को उन राज-व्यवस्थाओं के बदलने का अधिकार हो, तो सघीय सरकार को कंटनों को उन की राज-व्यवस्था की रक्षा के लिए मदद करना फर्ज माना गया है। अस्तु कंटनों की राज व्यवस्थाएं अमल में आने से पहले उन की सारी शर्तें और उन में संशोधन सघीय व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं में भी स्वीकार होने की राष्ट्रीय राज व्यवस्था में शर्तें रखी गई हैं। राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा कंटन की राज व्यवस्था की किसी भी शर्त को रद्द कर सकती है। कंटनों को आपस में किसी प्रकार की राजनैतिक सधियाँ करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मगर वे कानून, शासन और न्याय के आपस में रिवाज कायम कर सकते हैं, बशर्ते कि सघीय अधिकारियों की राय में उन में कोई बात सघीय राज व्यवस्था के विरुद्ध अथवा और किसी कंटन के हित के प्रतिकूल न हो। कंटनों के आपस के झगड़े न्याय के लिए सघीय सरकार के पास जाते हैं, और कंटनों को एक-दूसरे पर चढ़ दौड़ने का अधिकार नहीं है। सघीय सरकार को अपनी इच्छा से किसी भी कंटन में शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार है, चाहे कंटन के अधिकारी सघीय सरकार से इस प्रकार के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करें अथवा न करें।

सघीय सरकार को पाँच विषयों में खास कर पूरी सत्ता दी गई है—पर-राष्ट्रनीति, सेना, अर्थ, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएँ<sup>१</sup> और दूसरी देश की आन्तरिक सेवाएँ। सीमा, पुलिस के व्यवहार, और सार्वजनिक मिलकियत के प्रबंध के विषयों में, खास हालातों में, कंटनों को भी दूसरे राष्ट्रों से सधियाँ करने की इजाजत है। अन्यथा परराष्ट्र विषयों पर पूरा अधिकार सघीय सरकार का ही रहता है। उसी को दूसरे राष्ट्रों को एलची भेजने और दूसरे राष्ट्रों से एलची लेने, युद्ध छेड़ने, सधि करने और चुगो, व्यापार और दूसरे विषयों की सधियाँ करने का हक है। शांति के समय में स्विट्ज़रलैंड में न तो कोई सेना रहती है और न कोई सेनाधिपति। लड़ाई के समय में सत्र नागरिकों का सैनिक-सेवा करने का फर्ज माना गया है। राज व्यवस्था में स्थायी सेना न रखने की शर्तें रखी गई हैं। परन्तु दस वर्ष की उम्र से उन्नीस वर्ष की उम्र तक स्विट्ज़रलैंड के स्कूलों में सत्र नौजवानों को सैनिक शिक्षा दी जाती है। उस के बाद जो सेना के काम के योग्य होते हैं, उन सत्र को बीस वर्ष की उम्र से अड़तालीस वर्ष की उम्र तक, जरूरत पड़ने पर, जब चाहे वन सरकार सैनिक-सेवा के लिए बुला सकती है। परन्तु शांति-काल में ग्राम तौर पर किसी को पसठ दिन से अधिक लगातार अपने घर से दूर नहीं रखा जाता है। सारा समय सैनिक-सेवा में विमानवालों की देश भर में दो-तीन सौ से अधिक संख्या नहीं होती है। ससार के अन्य राष्ट्र भी अगर स्विट्ज़रलैंड की तरह ही अपनी सेनाओं का प्रबंध रचे तो दुनिया से

<sup>१</sup>पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़। <sup>२</sup>इंटरनेल सर्विसेज़।

सुमकिन है लड़ाई का नाम मिट जाय ।

आर्थिक अधिकारों में सघीय सरकार का मुद्रा गढ़ने और नोट निकालने का इजारा माना गया है । कुछ दिनों से समाजशाही की तरफ प्रवृत्ति बढ़ने से सरकार ने बहुत से सार्वजनिक उपयोग के धंधों और जरूरतियों पर भी अधिकार कर लिया है । डाक, तार, टेलीफोन और रेलें सब सरकारी हैं । बारूद और शस्त्र के बनाने का इजारा भी सिर्फ सरकार को है । व्यापार सबधी सब प्रकार के कानून और नियम बनाने का अधिकार सघीय सरकार को दिया गया है । मगर करों के सबध में एक जरूरी बँद रक्खी गई है । स्विट्ज़रलैंड की आर्थिक नीति इस सिद्धांत पर रची गई है कि सघीय सरकार का खर्च अप्रत्यक्ष करों की आमदनी से चलाया जायगा और कैंटनों की सरकारों का प्रत्यक्ष करों की आमदनी से । प्रारंभ में सघीय सरकार को सिर्फ देश के भीतर आनेवाले और देश से बाहर जानेवाले माल पर चुगी कर लगाने का अधिकार दिया गया था और उस में भी यह शर्त रक्खी गई थी कि देश के कृषि और उद्योग-व्यवसाय के लिए और प्रजा की जिंदगी के लिए आवश्यक बाहर से आनेवाली चीजों और देश से बाहर जानेवाले माल पर कम से कम कर सरकार को लगाना चाहिए । इन चुगी-करों की आमदनी, सार्वजनिक मिलक्रियत की आमदनी, डाक, तार और बारूद के इजारे का मुनाफा और सैनिक सेवा से बरी होने के, फौटनों द्वारा लगाए हुए, कर की आधी आमदनी सघीय सरकार के खर्च के लिए रक्खी गई थी । अगर इस से सरकार का खर्च न चल सके तो सरकार को कैंटनों की संपत्ति और उन की कर भरने की योग्यता के अनुसार उन से चौथ लेने का अधिकार भी था । चुगी कर से काफी आय हो जाने से सरकार को आज तक कभी कैंटनों से चौथ लेने की जरूरत नहीं पड़ी है । पिछली लड़ाई के ज़माने में अधिक खर्च की जरूरत पड़ने पर राज-व्यवस्था में सशोधन कर के सघीय सरकार को, सिर्फ एक बार आमदनी और मिलक्रियत पर कर लगाने और जब तक चाहे तब तक व्यापारी कागजों पर स्ट्याप लगा कर कर वसूल करने, मगर स्ट्याप के कर का पाँचवाँ भाग कैंटनों को लौटा देने—का अधिकार दिया गया था । चुगी, डाक, तार, टेलीफोन, बारूद के इजारे का शासन सघीय सरकार अपने अधिकारियों और अपने विभागों के द्वारा करती है । मगर रेल, जलशक्ति, तोल और माप, शिक्षा, सेना से मुक्ति<sup>१</sup>, और सघीय बैंक का शासन जर्मन साम्राज्य की तरह स्विट्ज़रलैंड की सघीय सरकार कैंटनों के अधिकारियों के मेल से करती है । एक तो इस ढंग से खर्च में कमी होती है, और दूसरे सघीय सरकार को अपने कानून बनाने के बहुत से अधिकार सौंप देनेवाले कैंटनों को कानूनों को अमल में लाने का अधिकार मिल जाने से उन को सतोष रहता है ।

स्विट्ज़रलैंड की राज-व्यवस्था के अनुसार कैंटन का हर एक नागरिक स्विट्ज़रलैंड का नागरिक होता है । भिन्न भिन्न कैंटनों में नागरिक बनने के लिए भिन्न भिन्न शर्तें हैं । कैंटन की सरकारों को किसी नागरिक को देश निकाला करने या उस के अधिकार छीन लेने का हक नहीं है । एक कैंटन दूसरे कैंटन के नागरिक के साथ कानून

<sup>१</sup> मिलिटरी एक्ज़ेम्पशन ।

और न्याय के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है, जैसा कि अपने नागरिक के साथ करता है। राज-व्यवस्था में सब नागरिकों को कानून की नजर में एक, स्विट्जरलैंड की जागीर में कहीं भी बसने का हक, सरकार से प्रार्थना करने का हक, गैरकानूनी और सरकार के लिए खतरनाक सस्थाओं के विनाश सस्थाएँ संगठित करने का हक, लेख स्वतंत्रता, खतों और तारों को गुप्त भेजने का हक और कर्जों के लिए गिरफ्तार न किए जा सकने का हक माना गया है। धार्मिक मामलों में सब को पूरी स्वतंत्रता है। किसी को उस के धार्मिक विश्वास के कारण किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है और न उस को किसी खास सस्था का सदस्य होने, धार्मिक शिक्षा लेने, और धार्मिक काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। किसी नागरिक से सरकार कोई ऐसे कर नहीं वसूल कर सकती है जो किसी ऐसे धर्म के काम में आते हों जिस को वह नागरिक न मानता हो।

## २-स्थानिक सरकार

### ( १ ) शासन क्षेत्र

स्विट्जरलैंड की सरकार का ढाँचा स्थानिक राजनैतिक सस्थाओं, विद्वांतों और रिवाजों पर बना है। अस्तु संधीय सस्थाओं को अच्छी तरह समझने के लिए उन के अध्ययन से पहले स्थानिक सस्थाओं का अध्ययन करना उचित होगा। हिंदुस्तान के गाँवों की तरह स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जीवन की इकाई 'कम्यून' कही जा सकती है। जिस प्रकार किसी जमाने में हिंदुस्तान में ग्राम की पंचायतों के द्वारा ग्राम निवासी अपना सार्वजनिक जीवन नियंत्रित करते थे, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में बहुत प्राचीन काल से कम्यून में रहनेवाले सब नागरिक एक दूसरे के बराबर समझे जाते हैं, और सब सार्वजनिक जीवन में भाग लेते हैं। भारतवर्ष का ग्राम जीवन तो आज-कल दुर्भाग्य से हमारी राजनीति में उतने महत्व का नहीं रहा है। मगर स्विट्जरलैंड में कम्यून राजनैतिक जीवन की इकाई और स्थानिक राजनीति का केंद्र अभी तक है। स्विट्जरलैंड में छोटी-बड़ी क़रीब ३१६४ कम्यून हैं। स्विट्जरलैंड का नागरिक बनने के लिए किसी एक कम्यून का सदस्य बनना जरूरी होता है। किसी भी कम्यून के सदस्य को कैंटन की सरकार की इजाज़त से कैंटन और सब दोनों की नागरिकता के अधिकार एक साथ मिल जाते हैं। शिक्षा, पुलिस, गरीबों को सहायता और पानी का प्रबंध इत्यादि स्थानिक काम-काज का बहुत-सा भाग कम्यून करती हैं। मगर कभी-कभी यह काम कम्यून कैंटन के अधिकारियों की सहायता से भी चलाती हैं। ग्राम-तौर पर कम्यूनो के पास मिलकियत भी होती है और गाँव की कम्यून सार्वजनिक जंगलों और चरागाहों की देख माल करती हैं। जर्मन मापा मापी गाँवों और छोटे-छोटे नगरों की कम्यून में नागरिकों की एक सार्वजनिक सभा के द्वारा सारा प्रबंध चलता है। फ्रांसीसी भाषा मापी बड़ी कम्यूनो में सार्वजनिक सभा एक पंचायत चुनने और छोटे अधिकारियों को नियुक्त करने का काम करती है। शासन चलाने का काम पंचायत के लिए छोड़ दिया

१ गाँव या क़स्बे की तरह देश का छोटा भाग।

जाता है। पचायत के प्रधान को खास अधिकार और एक हद तक शासन का काम चलाने की स्वतन्त्रता होती है।

अठारहवीं सदी के आखिर तक कई कम्यून एक प्रकार की छोटी छोटी खुदमुस्तार रियासतों की तरह थीं। बाद में वे मिल कर नया कैंटन बन गई थीं। शहरों में कम्यून चुगी का रूप धारण कर लेती है। चुगियों की सभाएँ ग्राम तौर पर तीन साल के लिए चुनी जाती हैं और शहर का सारा काम काज वहीं चलाती हैं। स्विट्जरलैंड में चुगियों के अधिकारियों के वेतन कम होते हैं, काम-काज की देसमाल अच्छी और क्रिपायत से की जाती है, और प्रजा से वर भी यह चुगियाँ अधिक नहीं लेती हैं। इन चुगियों के खिलाफ नए-नए कार्यक्रम बहुत से बनाने और कभी-कभी नौकरियाँ देने में रियायते करने की शिकायतें तो सुनी जाती हैं, मगर बड़े से बड़े शहरों की चुगियों तक के अधिकारियों या सदस्यों के खिलाफ स्विट्जरलैंड में कभी बेईमानी की शिकायत सुनने में नहीं आती है। चुगियों में और उन से भी अधिक गाँव की कम्यून में सर्व बहुत हाथ दना कर किया जाता है। पाठशालाओं के शिक्षकों का चुनाव भी प्रजा ही करती है। मगर वे थोड़े ही समय के लिए चुने जाते हैं। शहरों की चुगियों के चुनाव में दलबन्दी जरूर होती है। मगर अक्सर सभी दलों के सदस्य चुन लिए जाते हैं जिस से झगड़े टल जाते हैं। गाँव की कम्यून के चुनाव में राजनैतिक दलबन्दी नहीं होती है। स्विट्जरलैंड में स्थानिक स्वराज्य की बड़ी महत्ता मानी गई है क्योंकि वहाँ की सरकार की नींव इस स्थानिक स्वराज्य पर होने के साथ-साथ स्थानिक स्वराज्य में प्रजा को जो राजनैतिक काम काज की शिक्षा मिलती है उस से प्रजातन्त्र-संस्थाओं की सफलता से चलाने में बड़ी सहायता मिलती है। स्विट्जरलैंड के लोग स्थानिक स्वराज्य पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि उन का विश्वास है कि स्थानिक स्वराज्य के जरिए से ही प्रजा को सार्वजनिक काम की शिक्षा मिलती है, लोगों में नागरिकता के कर्तव्यों का प्रचार होता है, और स्थानिक प्रजा को प्रस्तावना<sup>१</sup> की सत्ता रहने से केंद्रीय सरकार में ही सत्ता केंद्रीभूत नहीं हो जाती है, जिस से सरकारी संस्थाओं को समाज के हित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कम्यून के ऊपर स्थानिक शासन में 'कैंटन'<sup>२</sup> का दर्जा माना गया है। स्विट्जरलैंड के पचीस कैंटनों में मुद्रतल्लिण भाषा, रिवाज, आबादी और लार्ड-चौड़ाई के कारण कई तरह का शासन चलता है। कैंटनों को शासन की सहूलियत के लिए 'वेजिक' नाम के जिलों में बाँटा गया है। उन कैंटनों की अलग अलग राज व्यवस्थाएँ हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार सघीय होने से सघीय सरकार की शेष सत्ता सघ के सदस्यों अर्थात् कैंटनों में मानी गई है, और सघीय सरकार की राज व्यवस्था में कैंटनों की विभिन्न व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने की शर्त रखी गई है। फिर भी कैंटनों की राज व्यवस्थाएँ धीरे धीरे एक-ही होती जाती हैं। सघीय सरकार की देस रेस में सारे कैंटनों में एक ग्राम शिक्षा प्रणाली कायम हो गई है। इस शिक्षा प्रणाली का संचालन, धार्मिक संस्थाओं और सरकार का रिश्ता ठीक रखने, व्यापार और तिजारत की शर्तें तय करने, वचों की मजदूरी और मजदूरों को मुआवजे,

बगैरह से संबंध रखनेवाले संधीय सरकार के कानूनों को बढ़ाने और विस्तृत करने, सड़के, रेलें और बेंकों को बनाने और सहायता देने, अस्पताल, पागलखाने, स्वास्थ्यगृह और जेलखाने बनाने और चलाने, शराब की तिजारत का इंतजाम करने, शरीरों की मदद और स्वास्थ्य के कानून बनाने, कानून बना कर और खास खेती के उपयोगी कामों को माली सहायता दे कर खेती की उन्नति करने, बहुत-से कर लगाने, पुलिस रखने और अपनी अदालतों और जजों के द्वारा न्याय-शासन करने, विदेशियों को नागरिकता के अधिकार देने, आपस के कैंटनों से कानून, शासन और न्याय-संबंधी फरार करने, और पड़ोसी रियासतों से सीमा और पुलिस-संबंधी व्यवहार के लिए समझौते करने इत्यादि का काम कैंटन की सरकारें करती हैं। कैंटन के कानूनों के सिवाय संधीय सरकार के कानूनों के एक बड़े भाग का संचालन भी कैंटन ही करते हैं। पहले सामाजिक और आर्थिक कानूनों को भी अधिकतर कैंटनों की सरकारें ही बनाती थीं। अब संधीय सरकार ने इस संबंध में देश भर में एक-सा अमल करने के लिए अपने हाथ में सत्ता ले ली है।

## ( २ ) कानून-रचना

कैंटनों में सारे मताधिकार प्राप्त नागरिकों की सार्वजनिक सभाएँ कानून बनाने, कर लगाने और खर्च करने और अधिकारियों को चुनने का काम करती हैं। ग्यारह कैंटनों में कुछ खास क्रिस्म के कानूनों को, कैंटनों की धारा-सभा में भंजूर हो जाने के बाद और उन पर अमल होने से पहले, मताधिकारी प्रजा के मतों के 'हवाले' के लिए भेजा जाता है। सिर्फ़ फ्रीबर्ग नाम के एक कैंटन में यूरोप के दूसरे देशों की तरह प्रतिनिधि-सभा कानून बनाती है।

मताधिकारी नागरिकों की सार्वजनिक-सभा के द्वारा कानून बनाने और शासन चलाने की पद्धति स्विट्ज़रलैंड की एक अनोखी चीज़ है। इस पद्धति के कारण इस देश में खालिस और प्रत्यक्ष प्रजासत्ता कायम हो गई है। स्विट्ज़रलैंड के मन को लुभानेवाले प्राकृतिक दृश्यों में 'खालिस' और 'प्रत्यक्ष प्रजासत्ता' का यह दृश्य घेने में सुहागे की तरह है। स्विट्ज़रलैंड में नागरिकों की कानून बनानेवाली सार्वजनिक सभा को 'लैंड्सगेमींद' कहते हैं। इस की ऐतिहासिक उत्पत्ति का बिल्कुल ठीक इतिहास नहीं बताया जा सकता। तेरहवीं सदी के मध्य भाग में उरी नाम के कैंटन में पहले-पहल एक ऐसी सभा का जिक्र मिलता है। सन् १२६४ ई० में श्वइज़ नाम के कैंटन में एक ऐसी सभा के ज़रूरी कानूनों को बनाने का हाल मिलता है। नेपोलियन की स्विट्ज़रलैंड में दस्तंदाज़ी के समय को छोड़ कर उरी और अंडर-वाल्डन में सन् १३०६, ग्लैरस में सन् १३८७ और ग्रेपेंजेल में सन् १४०३ ई० से बराबर ऐसी सभाएँ कायम थीं। सत्रहवीं सदी के प्रारंभ में देश भर में इस प्रकार की ग्यारह सभाएँ काम करती थीं, और उन्नीसवीं सदी के शुरू में ऐसी आठ सभाएँ रह गईं थीं। सन् १८४८ ई० में दो और कैंटनों में यह पद्धति बंद हो गई, और तब से छः कैंटनों में यह सभाएँ रह गई हैं। जिन कैंटनों में यह पद्धति उठ गई उन का क्षेत्रफल और आबादी इतनी बड़ी थी कि लोगों को एक स्थान पर एकत्र हो कर सभा का काम सहूलियत से चलाना मुश्किल होता था। जिन कैंटनों में यह प्रथा अभी तक कायम है, उन का क्षेत्रफल इतना छोटा

हे कि सभा में आने के लिए किसी को दस-पंद्रह मील से अधिक नहीं चलना पड़ता है, और उन की आयादी भी कम है। मगर सार्वजनिक सभा के द्वारा शासन चलाने की इस पद्धति का कारण सिर्फ एक चेन्नल और आबादी ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन कैंटनों में यह प्रथा जारी है, उन से बहुत छोटी छोटी यूरोपीय रियासतों में कोई ऐसी सभाएँ नहीं हैं और प्रतिनिधि शासन की पद्धति चलती है।

'लांदस्गेमीद' की सभा में सारे मताधिकारी मर्दे' का आना कानूनन फर्ज माना जाता है। कहीं-कहीं तो बिना किसी पास बजह के सभा में न आनेवालों को जुर्माना भी देना पड़ता है। मगर फिर भी आमतौर पर वही लोग आते हैं, जिन की आने की तयियत होती है। मुख्तलिफ कैंटनों में मुख्तलिफ, ३६ फी सदी से ७५ फी सदी तक हाजिरी का औसत रहता है।

साल में एक बार—ज़रूरत पड़ने पर अधिक बार भी—ग्राम तौर पर अप्रैल या मई मास के किसी इतवार के दिन किसी खुले मैदान या चरागाह में, जहाँ छाया और पानी का सुभीता होता है, कैंटन के नागरिकों की सार्वजनिक सभा जुड़ती है। यह सभा दूसरी सार्वजनिक सभाओं से इस बात में भिन्न होती है कि दूसरी सभाएँ सिर्फ किसी विषय पर अपना मत प्रगट करती हैं और यह सभा जो मत प्रगट करती है उस पर अमल भी कराती है। इस सभा में जो कुछ बहुसंख्या पास करती है वह किसी कानून को पास करने के लिए सिफारिश या मर्ग नहीं होती है, बल्कि वही कानून हो जाता है। सभा-स्थल के बीच में एक स्थायी मंच बनाया जाता है। जिस पर कैंटन का मुख्य अधिकारी, जिस को लेंडमान कहते हैं, चढ़ कर बैठता है। वही सभा का प्रधान होता है और उस के सामने कैंटन के मर्द, स्त्री और बच्चे काले कपड़े पहिन कर इकट्ठे होते हैं। मताधिकार प्राप्त मर्द सभा के अंदर बैठते और स्त्री-बच्चे उन के चारों ओर रहते हैं। किसी किसी जगह बच्चों को बचपन ही से राजनीति का ज्ञान देने के लिए उन के बैठने के लिए सब से आगे स्थान रक्खा जाता है। किसी ज़माने में मतदारों का तलवारें बाँध कर आने का रिवाज भी था। मगर अब सिर्फ सभा का प्रधान तलवार बाँध कर आता है। सभा में आनेवाले एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। अस्तु, किसी ऐसे मनुष्य को, जिस को मताधिकार न हो, मत देना मुश्किल होता है। सभा के प्रारंभ में ईश्वर-प्रार्थना के बाद प्रधान का व्याख्यान होता है और उस के बाद दूसरी कार्रवाई होती है। मुख्तलिफ कैंटनों में इन सार्वजनिक सभाओं को मुख्तलिफ अधिकार हैं। मगर ग्राम तौर पर कैंटन की राजव्यवस्था में संशोधन या बिल्कुल परिवर्तन करने, सब प्रकार के कानून बनाने, प्रत्यक्ष कर लगाने, सार्वजनिक फर्जा लेने, सार्वजनिक जागीर देने, सार्वजनिक रियायते देने, विदेशियों को नागरिक बनाने, कैंटन के अधिकारियों को चुनने, नए पद बनाने और पदाधिकारियों का वेतन तय करने के अधिकार इन सभाओं को होते हैं। सूडम में यह सभा स्विट्ज़रलैंड में ग्राम कानून की जन्मदायिनी और शासन का प्रबध और देख-रेख करनेवाली होती है। सभा का काम-काज बड़ी गंभीरता से किया जाता है, यद्यपि बीच-बीच में चुटकुले और हँसी-मजाक होते



रहते हैं। मगर जोशीली से जोशीली चर्चा चलने पर भी कभी इन सभाओं में शोर गुल नहीं मचता है।

सभा पाँच या अधिक सदस्यों की एक कार्यकारिणी और उस का प्रधान लेंदमान चुनती है। एक सलाहकार समिति भी चुनी जाती है जिस में कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा कम्पूनों अथवा अन्य स्थानिक जिलों की प्रजा के प्रतिनिधि लिए जाते हैं। इस सलाहकार समिति को 'लेंद्रात' या 'कतस्नात' के नाम से पुकारते हैं। इस समिति का मुख्य काम उन प्रस्तावों पर विचार करना होता है। जो या तो लेंद्रात के स्वयं होते हैं या लेंद्रात के पास नागरिकों के द्वारा सभा के सामने पेश होने के लिए भेजे जाते हैं। पाँच कैंटनों में किसी भी एक मताधिकारी को किसी कानून का प्रस्ताव भेजने का हक होता है। एक कैंटन—बाहरी ऐपेंजेल—में कानूनी प्रस्ताव भेजने के लिए ६५ मतदारों के दस्तखतों की जरूरत होती है। ग्लेरस और भीतरी ऐपेंजेल में कैंटन की राज-व्यवस्था के सशोधन का प्रस्ताव तक एक मतदार ही भेज सकता है। दूसरे कैंटनों में राज-व्यवस्था के सशोधन का प्रस्ताव भेजने के लिए पचास से पाँच सौ तक इस्तादरों की जरूरत होती है। सारे प्रस्ताव लिख कर लेंद्रात के पास आना और सार्वजनिक सभा होने से पहले लेंद्रात का उन पर विचार कर लेना जरूरी होता है क्योंकि सभा के सामने उन प्रस्तावों को स्वीकार, सशोधन या अस्वीकार करने के लिए लेंद्रात को सिफारिश करनी होती है। उरी और ग्लेरस में सार्वजनिक सभा में भी प्रस्ताव और सशोधन पेश किए जा सकते हैं। सभा में बहुसंख्या के मत से सब प्रस्ताव पास होते हैं, और जब तक पक्षों की माँग नहीं होती है तब तक हाथ उठा कर ही मत प्रगट किए जाते हैं। सारे कैंटनों की सार्वजनिक सभाओं में हर विषय पर बहस की पूरी आजादी होती है। मगर एक सब से बड़े कैंटन—बाहरी ऐपेंजेल—की सार्वजनिक सभा में चुनाव के सिवाय और किसी विषय पर चर्चा नहीं होती है। सार्वजनिक सभाओं को कैंटन के शासन में लगभग सभी कुछ सियाह-सफेद करने का हक होता है। देखने में यह खालिस प्रजा-सत्ता का शासन बड़ा सुंदर लगता है। बहुत से लोग इस शासन-पद्धति को आदर्श-पद्धति मानते हैं। मगर इस शासन-पद्धति पर वहाँ ही अच्छी तरह अमल हो सकता है, जहाँ का क्षेत्रफल छोटा हो, आबादी कम हो, हितों का अधिक संघर्ष न हो, सरकार का काम-काज सादा हो, और लोगों में काफी राजनैतिक जागरूकता हो। इस पद्धति के खिलाफ एक आरोप यह हो सकता है कि एक ही सत्ता को सरकार की सारी सत्ता सौंप देने से बहुसंख्या के अत्याचार का डर रहता है। परंतु स्विट्ज़रलैंड के जिन कैंटनों में यह पद्धति अभी तक कायम है, वहाँ बड़ी सफलता से काम-काज चलता है और उस के मिटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। फिर भी दो सौ वर्ष पहले जितना स्विट्ज़रलैंड में इस पद्धति का प्रचार या उस से अन-करीब आधा रह गया है। राजनीति शास्त्रियों की राय में स्विट्ज़रलैंड के अनुभव से सिर्फ यही बात सिद्ध होती है कि खालिस प्रजासत्ता की शासन-पद्धति सफलतापूर्वक स्थानिक शासन में चल

सकती है। स्विट्ज़रलैंड में भी अब दिन दिन शासन पद्धति का मुकाबल प्रतिनिधि शासन या मिश्रित 'प्रजा प्रतिनिधिशासन' की ओर ही अधिक होता जाता है।

जिन कैंटनों में मतदारों की सार्वजनिक सभाएँ कानून नहीं बनाती हैं उन में चुने हुए प्रतिनिधियों की धारा-सभाएँ होती हैं। इन धारा सभाओं को बड़ी सभा के नाम से पुकारते हैं और इन के सदस्यों का चुनाव २० वर्ष की उमर के ऊपर के मर्द नागरिकों के मतों से सीधा होता है। मुन्तलिक कैंटनों में ३५० से लेकर ३००० की ग्रासदी तक के लिए एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अतएव कैंटनों की धारा-सभाएँ काफी बड़ी होती हैं। कुछ ही धारा सभाएँ ऐसी हैं जिन के सदस्यों की संख्या सी से कम हो, कई की संख्या तो दो सौ से अधिक तक है—ज्यूरिख की धारा सभा में २२३ सदस्य हैं। इन धारा सभाओं की जिंदगी एक साल से लेकर छ' साल तक होती है। अधिकतर कैंटनों में धारा सभाओं की जिंदगी तीन-चार साल की होती है और यह धारा-सभाएँ आम तौर पर साल भर में दो बार बैठती हैं। कहीं कहीं धारा सभाओं की अधिक बैठके भी होती हैं। सार्वजनिक 'प्रस्तावना' और 'हवाले' की शर्तों के अंदर काम करने के सिवा यह सभाएँ दुनिया की दूसरी धारा-सभाओं की तरह ही काम करती हैं। उन की बहसें और फैसले बड़े गंभीर होते हैं, और कई तो ध्यान-ध्यान में स्विट्ज़रलैंड की राष्ट्रीय धारा सभा का मुकाबला करती हैं। उन की यह सभा और मुवाहिसे विस्तार से स्विट्ज़रलैंड के अखबारों में छपते हैं, जिस से पता चलता है कि प्रजा उन के काम में काफी दिलचस्पी लेती है। कैंटनों की धारा सभाओं की जल्द सज़ा रोखने के लिए किसी कैंटन में दो सभा की धारा-सभा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जरूरत के अनुसार उन के फैसलों पर प्रजा खुद विचार करती है। बहुत से कैंटनों में चुनाव अनुपात निर्वाचन की पद्धति से होता है। मगर फ्रांस और बेलजियम में जिस अनुपात निर्वाचन की पद्धति का प्रचार है, उस में और स्विट्ज़रलैंड की पद्धति में इतना फर्क है कि स्विट्ज़रलैंड में मतदार अपने सारे मत एक ही उम्मीदवार को दे सकता है। जहाँ लादसगेर्माद नाम की सार्वजनिक सभाएँ नहीं हैं, वहाँ भी 'हवाले' और 'प्रस्तावना' की संस्थाओं के जरिए से स्विट्ज़रलैंड की प्रजा का कानून बनाने में हाथ रहता है। इस विषय में स्विट्ज़रलैंड दुनिया के दूसरे देशों से भिन्न है। अस्तु इन सभाओं को भी अच्छी तरह समझने की जरूरत है। प्रजासत्ता का अध्ययन करनेवालों को, स्विट्ज़रलैंड में प्रजा के कानून बनाने का काम करते देख कर, जन-बुद्धि, जन-हृदय और जन आत्मा के पहिचानने का अच्छा मौका मिलता है। सत्र से पहले स्विट्ज़रलैंड के इतिहास में सोलहवीं सदी में ग्राउडन और वालिस की तराइयों में सार्वजनिक मत के सत्र में 'हवाले' शब्द के प्रयोग का जिक्र मिलता है। इन तराइयों में गाँवों और समुदायों की छोटी छोटी सभे कायम थीं, जिन में सार्वजनिक हित के काम गाँवों के प्रतिनिधि सभाओं में मिल कर चलाते थे। परंतु इन सभाओं को किसी जरूरी नियम पर आखिरी निश्चय करने का अधिकार नहीं होता था। अस्तु सारे जरूरी प्रश्नों को प्रतिनिधि अपने चुननेवाली प्रजा के सामने विचार के लिए पेश करते थे, और मतदारों की बहुसंख्या जिस बात को स्वीकार करती थी वही प्रतिनिधियों की दूसरी सभा में मंजूर की जा सकती थी। सन् १७६८ ई० के

फासीसी आक्रमण तक यह प्रथा चालू थी। बाद में भी सन् १८१५ ई० में फिर फ्रांज़न में इस प्रथा का पुनर्जीवन हुआ।

आजकल स्विट्जरलैंड में 'हवाले' की सस्या जिस रूप में कायम है उस का जन्म उन्नीसवीं सदी में ही हुआ। सन् १८३० ई० में सेंट गालेन की राज व्यवस्था की पुनर्घटना के समय 'खालिस प्रजासत्ता' और 'प्रतिनिधि सरकार' के पक्षपातियों में एक समझौते के तौर पर यह फैसला किया गया था कि मतदारों की एक काफी सख्या की तरफ से माँग आने पर सारे कानूनों पर प्रजा का मत लिया जा सकता है। परन्तु फिर धीरे धीरे इस प्रथा का प्रचार बढ़ा और सन् १८४८ ई० में स्विट्जरलैंड की यह कायम होने पर पाँच जर्मन-भाषा भाषी कैंटनों में 'इख्तियारी हवाले' का रिवाज हो गया। आजकल सात कैंटनों में 'इख्तियारी हवाला' चलता है अर्थात् उन कैंटनों में मतदारों की एक विशेष सख्या को किसी कानून पर सरकार को मतदारों के मत लेने के लिए मजबूर करने का इख्तियार होता है। ग्यारह कैंटनों में 'लाचारी हवाला' चलता है अर्थात् सभी कानूनों पर प्रजा का मत लेने के लिए सरकार लाचार मानी गई है।

प्रजा की तरफ से हवाले की माँग धारा-सभा से कानून पास होने के आमतौर पर तीस दिन के अंदर पेश होनी चाहिए। माँग की अर्जा कैंटन की कार्यकारिणी सभा के पास भेजी जाती है और अर्जा पहुँचने के तीस दिन के भीतर कार्यकारिणी को उस प्रश्न पर प्रजा के मत पडने के लिए तारीख निश्चित कर देनी होती है। अर्जा पर ५०० से ले कर ६००० मतदारों के अर्थात् मुख्तलिफ कैंटनों में सारे मतदारों के बारहवें भाग से पाँचवें भाग तक के हस्ताक्षर होने की फेद रखी गई है। धारा-सभा से मज़ूर कानूनों को अस्वीकार करने के लिए भी भिन्न भिन्न कैंटनों में मतों की भिन्न भिन्न सख्या की जरूरत होती है। कहीं मत देनेवालों की बहुत सख्या काफी होती है, कहीं सारे मताधिकारी नागरिकों की बहुत सख्या की जरूरत होती है। प्रजा का मत कानून के खिलाफ होने पर कार्यकारिणी उस को धारा सभा के पास वापस भेज देती है और धारा सभा मतों को जाँच कर अपने कानून को रद्द ठहरा देती है।

'प्रस्तावना' के लिए इस का उल्टा अमल करना पड़ता है। सार्वजनिक प्रस्तावना की पद्धति में धारा-सभाओं से पास हो कर ऊपर से ही कानून प्रजा के ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। नीचे से प्रजा को भी कानूनों के मसविदों की प्रस्तावना करने का अधिकार होता है। जिन नागरिकों को कोई नया कानून बनाने में दिलचस्पी होती है, वह उस कानून का मसविदा तैयार कर के या एक अर्जा में वे सारी बातें लिख कर जो वह उस कानून में चाहते हैं, और उस कानून को मज़ूर करने की जरूरत के कारण लिख कर, प्रजा के पास हस्ताक्षरों के लिए ले जाते हैं। दूसरे नागरिक उस मसविदे की तार्ईद अर्जा पर अपने दस्तखत कर के या ज़बानी भी कर सकते हैं। ज़बानी तार्ईद कम्प्यूनों की सभाओं में एकत्र हो कर या अर्जा लेनेवाले सरकारी अधिकारियों के पास जा कर ज़बानी एलान कर के की जा सकती है। अगर कई कम्प्यूनों की सभाओं में मिला कर मसविदे की तार्ईद के लिए जरूरी सख्या मतों की पड़ जाती है तो वह सख्या अर्जा पर उतने दस्तखतों के बराबर ही समझी

जाती है। दस्तखतों का तरीका अख्तियार किया जाने पर सारे ताईद करनेवालों को, एक सरकारी अपसर के पास जा कर अपना दस्तखत करने का हक दूसरे चुनावों में मताधिकार के हक की तरह साबित करना होता है। इस के लिए उन से किसी प्रकार की पीस नहीं ली जाती है। इख्तियारी हवाले के लिए जितने मतों की जरूरत होती है उतने ही मतों की जरूरत 'सार्वजनिक प्रस्तावना' के लिए भी होती है। आवश्यक दस्तखत हो जाने पर अर्जों कैंटन भी धारा सभा के पास जाती है और एक निश्चित समय के तदर धारा सभा उस पर विचार कर के प्रार्थना के अनुसार पूरा मसविदा तैयार करती है। धारासभा उसी विषय पर अपने विचारों के अनुसार, दूसरा मसविदा तैयार कर के भी साथ साथ प्रजा के मतों के लिए पेश कर सकती है। मसविदे की आवश्यकता और अनावश्यकता के विषय में भी प्रजा के सामने धारासभा अपना मत रख देती है, जिस से मतदारों को राय देने में आसानी हो जाती है। इस के बाद मसविदे पर प्रजा के मत लिए जाते हैं। बहुसंख्या के मतों से मसविदा मंजूर हो जाने और कार्यकारिणी के एलान कर देने पर कानून बन जाता है। कैंटन की राज व्यवस्था में संशोधन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। जब किसी कैंटन की राज व्यवस्था की विलुप्त पुनर्घटना की जाती है तो पहले इस बात पर प्रजा का मत लिया जाता है कि पुनर्घटना की आवश्यकता है या नहीं, और अगर है तो उस को धारासभा करे या इस काम के लिए एक नया 'प्रतिनिधि-सम्मेलन' बुलाया जाय। अगर पुनर्घटना का काम धारासभा पर ही छोड़ने का निश्चय होता है तो अक्सर धारासभा का नया चुनाव किया जाता है, जिस से इस काम में नए लोग भी शामिल हो सके। धारासभा या व्यवस्थापक सम्मेलन के निश्चयों पर अमल करने के लिए मतदारों की बहुसंख्या की मंजूरी की जरूरत होती है।

जहाँ 'लाचारी हवाला' चालू है वहाँ भी प्रजा ने—जैसा कि कुछ लोग डरते हैं—इस उक्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। न जिन कैंटनों में 'इख्तियारी हवाला' चालू है वहाँ ही दलबंदी या छेड़छाणी के लिए हवाले की माँग की जाती है। यह भी हो सकता है कि इन कैंटनों की धारासभाओं का दिल और दिमाग प्रजा से इतना मिला रहता है कि प्रजा से अगील करने की आमतौर पर जरूरत ही नहीं होती। जहाँ सारे कानूनों पर प्रजा का मत लेने के लिए सरकार लाचार मानी गई है, वहाँ भी सारे कानूनों पर प्रजा का मत शायद प्रजासत्ता के सिद्धांतों की पूर्ति के लिए ही लिया जाता है, न कि इस लिए कि उन कैंटनों की प्रजा अनिश्चित और कैंटनों की प्रजा के अपनी धारासभा पर कम विश्वास रखती है। संघीय हवालों से कैंटन के हवालों में भाग लेनेवाली प्रजा का औसत कम रहता है—खास कर उन कैंटनों में जहाँ उन कानूनों पर हवाला लिया जाता है। धार्मिक प्रश्न पर लोग दूसरे प्रश्नों से अधिक संख्या में मत देने आते हैं और अधिकतर सरकारी खर्च बढ़ानेवाले कानूनों को ही प्रजा हवालों में नामजूर करती है।

इस सस्या की जड़ एक तो 'प्रजा की प्रभुता' के राजनैतिक सिद्धांत को कहा जा

सकता है जिस सिद्धांत का पहले-पहल जन्म स्विट्ज़रलैंड में नहीं बल्कि फ्रांस में हुआ था। दूसरी इस संस्था की जड़ स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ी जातियों की उस प्रथा को कह सकते हैं जिस के अनुसार गाँव के सब लोग जुट कर सार्वजनिक सभाओं में सारे कानूनों को मंजूर करते थे, जिस का जिक्र पहले किया जा चुका है। गाँवों की आबादी बढ़ जाने पर जब लोगों का एक जगह जुट कर मत देना, कठिन होने लगा होगा तब सुभीते के लिए इस प्रथा का प्रचार हुआ होगा। प्रजा कानूनों को बनाने में खुद भाग लेने से कानूनों को अपने कानून समझती है और उन पर अमल अधिक, खुशी से करती है। स्विट्ज़रलैंड में तो नहीं मगर संयुक्त-राज्य अमेरिका में इस संस्था के प्रचार के लिए इस कारण भी जोर दिया जाता है कि उस देश के कुछ लोगों की राय में प्रतिनिधि-संस्थाएँ प्रजा की ठीक-ठीक इच्छा प्रकट नहीं करती हैं। परंतु स्विट्ज़रलैंड की धारा-सभाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है। हाँ, इस बात पर जोर अवश्य दिया जाता है कि प्रतिनिधियों से खुद प्रजा अपने हितों को अच्छी तरह समझती है, और अपने हाथ से बनाए हुए कानूनों पर लोग खुशी से अमल करते हैं। संघीय सरकार की सत्ता के बेजा पैलाव और सरकार के पूँजीपतियों के चंगुल में पड़ कर विगड़ जाने की दवा भी प्रजा के हाथ में इस संस्था से रहती है। इस संस्था के कारण प्रजा में राजनैतिक ज्ञान और जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि कानून बनाने का सर्वसाधारण को अधिकार होने से सभी राजनैतिक प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं, और जो काम पहले सिर्फ वकीलों और राजनीतिज्ञों की एक पदी-लिखी टोली पर छोड़ दिया जाता था उस में साधारण आदमी भी भाग लेते हैं। संस्था के हवाले के कारण राजनैतिक दलबंदी का भी जोर कम रहता है। आम लोग किसी दल या नेता के विचार से ही मत न दे कर मसविदे की भलाई-बुराई पर विचार कर के भी मत देते हैं क्योंकि धारासभा के सदस्यों को अपने दल के साथ मत देने में जिन व्यक्तिगत फायदों का लोभ रहता है वह लोभ आम लोगों को नहीं रह सकता है। सर्वसाधारण को जो कुछ भी फायदा और नुकसान हो सकता है, वह सिर्फ उस कानून की भलाई और बुराई से हो सकता है। इस लिए वे सिर्फ कानून की भलाई और बुराई पर ही विचार कर के मत देते हैं। वैसे भी स्विट्ज़रलैंड में दलबंदी का जोर कम है, जिस से आम लोगों की आदत स्वतंत्रता से मत देने की हो गई है। इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका में इस प्रकार का सार्वजनिक मत बिना दलबंदी के प्रगट ही नहीं किया जा सकता है। अन्य देशों में धारासभा के कानूनों को अस्वीकार करने का जो अधिकार राजछत्र या प्रमुख के हाथों में रखा जाता है, वही स्विट्ज़रलैंड में सीधा प्रजा के हाथ में रखा गया है। प्रजा-सत्तात्मक राज्य में आखिरी फैसला, राष्ट्र की प्रभुता और राष्ट्र की सारी सत्ता की जन्मदात्री, प्रजा के हाथ में रहना उचित भी है।

मगर 'हवाले' के विरोधियों का कहना है कि इस पद्धति से धारासभा की हेतुियत और अधिकार कम होता है, क्योंकि धारासभा का मंजूर किया हुआ कानून प्रजा के मतों से नामंजूर हो जाने पर प्रजा के दिल में धारासभा के लिए सम्मान नहीं रहता है जिस से धारासभा को भी अपनी जिम्मेदारी का खयाल कम हो जाता है। धारासभा जिन कानूनों

को गैरज़रूरी समझती है उन के विरोध की भी उसे फ़िज़ नहीं रहती, क्योंकि वह समझती है कि प्रजा उन को नामज़ूर कर ही देगी। उसी प्रकार बहुत से ऐसे क़ानूनों को जिन को वह आवश्यक भी समझती है, प्रजा को नाज़ कर देने के डर से पेश नहीं करती। दूसरा कारण विरोधी यह देते हैं कि जो साधारण लोग हवाला में मत देने आते हैं वे हर एक उस प्रश्न को जिस पर वह मत देते हैं समझने के नाक़ाज़िल होते हैं। तीसरे, हवाला में मतदारों की अधिपत्त सख्या के भाग न लेने से भी मालूम होता है कि या तो अधिकतर नागरिकों को इन अधिकारों की ज़रूरत नहीं मालूम होती है, या वह अपने आप को इस फ़र्ज़ के नाक़ाज़िल समझते हैं। न आनेवाला की तादाद दिन-ब-दिन घटती भी नहीं है, जिस से यह साबित होता है कि इस सस्था से राजनैतिक ज्ञान की भी वृद्धि नहीं होती है। एक तो साधारण मनुष्य क़ानून की तमाम ग़रीबीयों नहीं समझता है। उस के दिमाग में एक आध बात जम जाती है और वह इधर-उधर की बातों में चकरा कर किसी भी क़ानून की एक आध बुराई के कारण उस सारे क़ानून के खिलाफ़ मत दे देता है, जिस में अगर वह समझ और सोच करता तो उसे बहुत सी अच्छाइयाँ नज़र आती और उस ने उसे नामज़ूर न किया होता। दूसरे यह भी देखा गया है कि एक मसज़िदे को नामज़ूर कर देने के बाद साधारण मनुष्य की फिर दूसरे सामने आनेवाले सभी मसज़िदों को नामज़ूर कर देने की वृद्धि हो जाती है। यह भी कि मतदारों को 'हाँ' या 'ना' में ही निश्चय करने का मौक़ा होने से अक्सर ख़राब मसज़िदों के साथ पेश होने वाले अच्छे मसज़िदे भी भेड़चाल में नामज़ूर हो जाते हैं। एक दलील हवाले के विरोधी यह भी देते हैं कि साधारण नागरिक को राजनीति के अलावा और भी बहुत सा काम रहता है। उस को आए दिन की हवाले और चुनाव की छेड़खानी अच्छी नहीं लगती। बार-बार के हवालों से उसे बहुत ख़र्च और परेशानी उठानी पड़ती है। अस्तु ज़ल्दबाज़ी और लापरवाही में वह वे समझे यूँके मत डाल आता है। जहाँ गैरज़रूरी के लिए जुर्माना देना होता है, वहाँ बहुत से मतदार आ कर चुनाव के बक्स में कोरा पर्चा ही डाल जाते हैं, क्योंकि उन का कोई मत ही नहीं होता है, जो वे दे। हवाले के विरोधियों का कहना कि भारासभा में कोई क़ानून सिर्फ़ थोड़ी-सी बहुसख्या से पास होने पर साधारण मनुष्य यह तलाश नहीं करते हैं कि कितने मत क़ानून के पक्ष में थे और कितने विपक्ष में। वे उस को धारा सभा से मज़ूर मान कर सतोप से मज़ूर कर लेते हैं। परंतु जनसाधारण के खुद मत देने पर अगर कोई क़ानून सिर्फ़ थोड़ी-सी बहुसख्या से ही पास होता है तो विरुद्ध पक्ष में मत देनेवालों के सिर्फ़ थोड़े से मतों से हार जाने के कारण चिढ़ कर क़ानून के विरोधी बन जाने की सम्भावना रहती है। मगर स्विट्ज़रलैंड में अभी तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है। वहाँ हमेशा अल्पसख्या बहुसख्या का निश्चय खुशी से मानती है क्योंकि शायद वह समझती है कि स्वतंत्र सरकार इसी नियम पर चल सकती है। हवाले के इन विरोधियों की और भी कई बातें इसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड के अनुभव से ठीक नहीं ज़ँचतीं। उन की बहुत-सी शिकायतें सत्य भी हैं, मगर वही शिकायतें प्रतिनिधि पद्धति के खिलाफ़ भी की जा सकती है।

हवाले की पद्धति से पारसभा और कार्यकारिणी का काम भी पृथक् रहता है।

गर्भकारिणी और धारासभा के बनाए हुए कानून 'हवाले' में नामंजूर हो जाने पर भी स्विट्ज़रलैंड में धारासभा और कार्यकारिणी अपना-अपना काम करती रहती हैं। इंग्लैंड में कार्यकारिणी का कोई जरूरी कानून धारासभा में नामंजूर हो जाने पर कार्यकारिणी इस्तीफा दे देती है। मगर स्विट्ज़रलैंड में कानून बनाने की सत्ता प्रजा हाथ में होने से धारासभा का काम सिर्फ कानून तैयार करना समझा जाता है, और कार्यकारिणी अथवा धारासभा के सदस्यों को जरूरत पड़ने पर उसी प्रकार नामंजूर कर देती है जैसे कोई व्यापारी अपने मुनीम की बनाई हुई योजना को नामंजूर कर देता है। मालिक के योजना नामंजूर कर देने पर जिस प्रकार मुनीम को इस्तीफा दे कर भाग जाना जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार अपने सदस्य को नामंजूर हो जाने पर स्विट्ज़रलैंड में कार्यकारिणी या धारासभा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझी जाती है। स्विट्ज़रलैंड में जिस कार्यकारिणी और धारासभा के कानूनों को प्रजा नामंजूर करती है उसी को चुनाव होने पर फिर चुन लेती है। जब तक किसी कार्यकारिणी या धारासभा के सदस्यों की मानदारी और काम में लोगों को भरोसा रहता है तब तक स्विट्ज़रलैंड में उन को बदला नहीं जाता है। इंग्लैंड या अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। वहां जिस कार्यकारिणी या धारासभा के बहुत-से कानून लोगों को पसंद नहीं होते हैं उसका दूसरे चुनाव में चुनावाना असंभव होता है। स्विट्ज़रलैंड में किसी कानून के पास होने या न होने पर जनैतिक दलों का भाग्य निर्भर रहने से दलबंदी को उत्तेजना कम रहती है। धारासभा ने प्रजा के भावों का ध्यान रख कर चलना होता है और प्रजा की मर्जी से ही सरकार का बहुत कुछ काम होता है। स्विट्ज़रलैंड में कहीं इस पद्धति को उठा देने का जिद्द या माँग नहीं है। प्रजा अपने इस अधिकार की कदर करती है। अधिकतर कैंटनों में लाचारी हवाला होने पर भी कुछ विद्वानों की राय 'इच्छित्यारी हवाले' के ही पक्ष में है, क्योंकि उन की राय में आए दिन के जबरदस्ती हवालों में मत देने से लोग तंग आ जाते हैं और सोच-विचार कर ठीक-ठीक मत नहीं देते हैं। हवाले की सफलता का कारण स्विट्ज़रलैंड की प्राकृतिक दशा भी कही जा सकती है क्योंकि छोटी-छोटी आबादी के स्थानों में, जहां दलबंदी का बहुत जोर नहीं होता है, यह पद्धति खास तौर पर सफल हो सकती है।

'हवाले' से प्रजा को सिर्फ किसी नापसंद कानून को नामंजूर करने का अधिकार होता है। किसी नई जरूरत के लिए नए कानून बनाने की इच्छा प्रकट करने का अधिकार प्रजा को 'प्रस्तावनों' से रक्खा गया है। 'हवाला' प्रजा के हाथ में अपनी प्रतिनिधि-सभा के काम का इलाज है, तो प्रस्तावना प्रतिनिधि-सभा की नाकामी का इलाज है। हवाले से धारासभा की गलतियों को प्रजा संभाल सकती है और प्रस्तावना से धारासभा के किसी प्रश्न पर चुप रहने से प्रजा खुद उस प्रश्न को उठा सकती है। प्रजा द्वारा कानून बनाने के सिद्धांत का 'प्रस्तावना' पद्धति एक स्वाभाविक फल है। अगर प्रजा के हाथ में 'प्रस्तावना' की ताकत न हो तो किसी ऐसे प्रश्न पर कानून बनाने के लिए जो धारासभा को पसंद न हो, अखबारों और सार्वजनिक समारोहों में कितना ही शोर मचाने पर भी, धारासभा कुछ

प्रयत्न न करके बेफिक्री से कानों में तेल डाल कर बैठ सकती है। प्रस्तावना की पद्धति से प्रजा, धारासभा पर ही निर्भर न रह कर, खुद उस प्रश्न को उठा सकती है। गैर-जरूरी या महज़ छेड़खानी के लिए किसी मसविदे की प्रस्तावना होने पर स्विट्ज़रलैंड में प्रजा उस को आमतौर पर नामज़ूर कर देती है। मगर कभी-कभी बहुत ज़रूरी विषयों पर, धारा सभा का कड़र विरोध होने पर भी, प्रजा की तरफ से मसविदों की प्रस्तावना होती है, और प्रजा उन को स्वीकार करती है। कुछ राजनीतिज्ञों का 'हवाले' से अधिक 'प्रस्तावना' के खिलाफ विरोध है। उन का कहना है कि 'हवाले' के लिए जो कानून भेजे जाते हैं उन पर तो धारासभा विचार भी कर चुकी होती है और वे 'कार्यकारिणी समिति' के दत्त मनुष्यों के गढ़े हुए भी होते हैं। मगर जो कानून 'प्रस्तावना' में प्रजा की तरफ से आते हैं उन पर कहा पहले अच्छी तरह न तो विचार ही हो चुका होता है, और न वे, होशियार और अनुभवी मनुष्यों के द्वारा गढ़े ही गए होते हैं। ऐसे कानूनों के मज़ूर हो जाने पर उन पर अमल में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उन के गढ़नेवालों के कार्यकारिणी या धारासभा के सदस्यों की तरह अमली दिक्कतों का ज्ञान न रहने से उन कानूनों में अमली कमिया रह जाती हैं। दूसरे मौजूदा कानूनों के खेन में दखल देनेवाले कानून भी प्रजा के अज्ञान से प्रस्तावना के द्वारा पेश हो कर पास हो सकते हैं। मगर पहले जितना 'प्रस्तावना' का विरोध किया जाता था अब उतना नहीं होता है। स्विट्ज़रलैंड का इतिहास, स्विट्ज़रलैंड की प्रजा की देशभक्ति और स्थानिक स्वराज्य की पुरानी आदत के कारण और स्विट्ज़रलैंड के लोगों की आर्थिक स्थिति में एक दूसरे से बहुत फर्क न होने से यहाँ की भूमि खालिस प्रजासत्ता के पौदों के लिए आज तक तो बड़ी उपजाऊ साबित हुई है। आगे का हाल कहना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में हितों का संघर्ष बढ़ रहा है। कौन कह सकता है कि इटली या जर्मनी की तरह स्विट्ज़रलैंड में हित संघर्ष का घटाटोप समाम छिड़ जाने पर यह सहाय्य उस नई कसौटी पर कैसी उतरेंगी ?

### ( ३ ) कार्यकारिणी

कैंटनों की कार्यकारिणी सत्ता एक समिति के हाथ में होती है। मुखतलिफ कैंटनों में पाँच से तेरह तक, मुखतलिफ संख्या की, यह समिति होती है। इस समिति को 'शासन समिति' या 'छोटी कौंसिल' या 'स्टेट कौंसिल' के नाम से पुकारते हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव दो कैंटनों को छोड़ कर और सब कैंटनों में अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार एक से लेकर पाँच बरस तक के लिए प्रजा खुद करती है। फ्रीबर्ग और बेले नाम के दो कैंटनों में उन का चुनाव वहाँ की धारासभाएँ करती हैं। कार्यकारिणी समिति का एक प्रधान चुना जाता है जिस को आमतौर पर 'लैंडमान' कहते हैं। लैंडमान हर स्टेमरिवाज के काम में कैंटन की सरकार का सिरमौर और कैंटन का प्रतिनिधि समझा जाता है। मगर उस को समिति के दूसरे सदस्यों से न तो कोई अधिक अधिकार ही प्राप्त होते हैं, और न और किसी बात में वह उन से भिन्न समझा जाता है। 'कार्यकारिणी समिति' या 'शासन-समिति' का काम कानूनों को अमल में लाना, शांति



और सुव्यवस्था कायम रखना, कानूनी मसविदे तैयार करना, कम्प्यूनों के शासन की देख-रेख करना और हर प्रकार से कैंटनों के हितों की रक्षा करना होता है। शासन का काम चलाने के लिए अर्थ, शिक्षा, न्याय, पुलिस, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, कृषि इत्यादि के विभाग कार्यकारिणी के सदस्यों में बाँट दिए जाते हैं। 'कार्यकारिणी समिति' का मुख्य काम धारासभा अथवा प्रजा के बनाए हुए कानूनों और उन के हुक्मों पर अमल करना होता है। समिति के सदस्यों को कैंटन की धारासभा में जा कर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। मगर उन को वहाँ मत देने का अधिकार नहीं होता है। कुछ छोटे अधिकारियों को नियुक्त करने और एक हद तक अपनी मर्ज़ों के अनुसार खजाने का खर्चा खर्च करने का भी अधिकार समिति को कई कैंटनों में है। कानूनों की व्याख्या करने और कहीं-कहीं सार्वजनिक कर और आर्थिक प्रश्नों पर अपील सुनने का काम भी यह समिति करती है।

शासन का काम चलाने के लिए सब छोटे कैंटनों को छोड़ कर और सब कैंटन जिलों में बटे हुए हैं, जिन को बेट्सिर्क कहते हैं। हर बेट्सिर्क में एक बेट्सिर्क मान या प्रीफेक्ट होता है। इस अधिकारी को मुख्यतः लिफ्ट कैंटनों में कार्यकारिणी समिति या धारासभा या प्रजा चुनती है। परंतु हर हालत में वह कैंटन की सरकार का ही प्रतिनिधि माना जाता है। किसी-किसी कैंटन में बेट्सिर्कमान की शासन-कार्य में सहायता करने के लिए प्रजा की चुनी हुई सभाएं भी होती हैं। श्वेज़ कैंटन के छः के छः जिलों में इस प्रकार की सभाएं हैं। इस कैंटन में सन् १७६८ ई० के पूर्व एक सार्वजनिक सभा के द्वारा शासन चलता था। बाद में यहाँ वह प्रथा बंद हो गई या शायद उसी पद्धति ने यह दूसरा रूप धारण कर लिया जिस से इस कैंटन की पुरानी एक सार्वजनिक सभा के स्थान में हर जिले में दो सभाएं बन गईं। मगर इस एक कैंटन के ही सारे जिलों में इस प्रकार की सभाएं हैं। दूसरे कैंटनों में नहीं है। बेट्सिर्कमान के अधिकार का काल भी उतना ही होता है जितना उस कैंटन के लैदमान का होता है। मगर समय पूरा हो जाने के बाद वह फिर चुना जा सकता है। उस का काम भी कानूनों, कार्यकारिणी समिति के आदेशों और न्यायाधीशों के फैसलों के अमल में लगाना, सार्वजनिक शांति और सुव्यवस्था कायम रखना, और कम्प्यूनों के शासन और अपने मातहत अधिकारियों और गावों के मुखियों की कार्यवाई की देख-रेख करना होता है। श्वेज़ कैंटन के बेट्सिर्क की सभाओं में सब थालिश नागरिक मर्द भाग लेते हैं। यह सभाएं जिले के अधिकारियों और कुछ न्यायाधीशों को चुनती हैं और कैंटन की सभाओं की तरह अपने जिलों में कर लगाने और उन के खर्च करने का काम भी करती हैं। स्विट्ज़रलैंड में स्थानिक-शासन की सब से छोटी इकाई कम्प्यून है जिस का जिक्र इस अध्याय के शुरू में ही हो चुका है।

### ( ४ ) न्याय-शासन

हर कैंटन का अपना-अपना न्यायशासन भी अलग होता है। न्यायाधीशों को सीधा प्रजा या धारासभा चुनती है। दीवानी के लिए हर कम्प्यून में एक 'जस्टिस ऑफ़

दि पीस' की अदालत होती है जिस के न्यायाधीश को अक्सर रिचवर्ड भी कहते हैं क्योंकि हर मुकदमे में उस का पहला फर्ज बीच में पड़ कर लड़नेवालों में आपस में बीच बिचाव कर देने की कोशिश करना होता है। जब इस प्रकार झगडा नहीं पड़ता है, तब वह उस पर न्यायाधीश की तरह अपनी अदालत में निचार करता है। उस को छोटे छोटे मुकदमों पर ही विचार करने का अधिकार होता है।

इस अदालत के ऊपर जिले की अर्थात् वेस्ट्रिक की अदालत होती है। उस में पाँच से सात तक प्रजा के चुने हुए न्यायाधीश होते हैं। जिले की अदालतों के ऊपर कैंटन की अदालत होती है। जिन में सात से तेरह तक ग्राम तोर पर धारा उभा के चुने हुए न्यायाधीश होते हैं। जिले की अदालतों की अपीलें कैंटन की अदालतों में जा सकती हैं। मगर इन अदालतों को किसी कानून को राज व्यवस्था के खिलाफ ठहराने का हक नहीं होता है। फौजदारी के मुकदमों के लिए हर जिले में अलग अदालत होती है जिन में चाक्यात पर राय देने के लिए न्यायाधीशों के साथ प्रजा की चुनी हुई ग्राम तोर पर छ से नौ आदमियों तक की जूरी भी बैठती है। चाक्यात पर फैसला हो जाने के बाद इन अदालतों की अपीलें भा कैंटन की अदालतों के पास जा सकती हैं। तीन कैंटनों में व्यापारिक झगडों का फैसला करने के लिए खास व्यापारी अदालतें हैं। इन में एक दो न्यायाधीश और दो से पाँच तक व्यापारी मामलों को अच्छी तरह समझनेवाली व्यापारी न्याय करने के लिए बैठते हैं। खास अदालतों में इन अदालतों की अपीलें भी साधारण अदालतों में जा सकती हैं। नौ कैंटनों में मालिका और मजदूरों के झगडा का फैसला करने के लिए उद्योगी अदालतें भी हैं। इन में दोनों पक्ष के आदमी न्यायाधीश का काम करते हैं। इस प्रकार की अदालतों में झगडे बड़ी जल्दी और अक्सर बिना किसी खर्च के पट जाते हैं।

## ३—संघीय सरकार

### ( १ ) व्यवस्थापक-सभा

( १ ) नेशनल राय—स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापक सभा को 'नेशनल एसंबली' अर्थात् 'राष्ट्रीय सभा' कहते हैं। दुनिया की दूसरी संघीय सरकारों की तरह इस देश की व्यवस्थापक सभा की भी दो शाखाएँ हैं। एक को 'नेशनल राय' या 'नेशनल कौंसिल' कहते हैं और दूसरी को 'स्टाडराय' या 'कौंसिल ऑफ़ स्टेट्स'। संघीय सरकार की सारी सत्ता नेशनल एसंबली में मानी गई है। कार्यकारिणी और न्याय विभाग को भी व्यवस्थापक सभा ही के आधीन माना गया है।

'नेशनल कौंसिल' का मुक़ाबला इंग्लैंड के 'हाउस ऑफ़ कॉमन्स' से किया जा सकता है। 'नेशनल कौंसिल' के सदस्य प्रजा के सीवे और गुप्त मतों से तीन साल के

लिए चुने जाते हैं। हर कैंटन से बीस हजार आयादी या उस के अधिक भाग के लिए एक सदस्य चुना जाता है। मगर हर हालत में कम से कम हर कैंटन से एक सदस्य अवश्य चुने जाने की केंद्र रखी गई है। हर मर्दुमशुमारी के बाद सघीय सरकार चुनाव के नए जिले बनाती है और आयादी के अनुसार कैंटनों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई-बढ़ाई जाती है। प्रारंभ में 'नेशनल कोन्सिल' में १२० प्रतिनिधि थे, सन् १६१० ई० की मर्दुमशुमारी के बाद उन की संख्या बढ़ कर १८६ हो गई थी। वर्न के नेशनल कौंसिल में ३२ प्रतिनिधि थे, ज्यूरिच के २५ प्रतिनिधि, बाड के १६ और उरी और जग जैसे छोटे छोटे कंटनों के सिर्फ एक-एक ही प्रतिनिधि थे। आम तौर पर चुनाव के एक जिले से दो या तीन या चार प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बीस वर्ष के ऊपर के सत्र मर्द नागरिक—जिन के नागरिकता के अधिकार कैंटनों ने छीन न लिए हों—'नेशनल कौंसिल' के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अक्टूबर के आखिरी रविवार के दिन, सारे 'स्विट्जरलैंड' में जगह जगह पर 'नेशनल कौंसिल' के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चुनाव में सफलता के लिए हर उम्मीदवार को मतों की बहुसंख्या अर्थात् सारे मतों की आधी से अधिक संख्या की जरूरत होती है। परंतु पहली बार पचें पड़ने पर अगर किसी उम्मेदवार को इतने मत नहीं मिलते हैं, तो दो-तीन हफ्ते बाद फिर दूसरी बार चुनाव होता है। और इस दूसरे पचें पर जिस को सत्र से अधिक मत मिलते हैं उस को चुन लिया जाता है। सिर्फ एक पादरी लोग उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। दूसरे मतदारों में से कोई भी कौंसिल की मेजरी के लिए खड़ा हो सकता है।

'नेशनल कौंसिल' के सदस्यों को सभा में हाज़िर रहने के दिनों के लिए फी दिन के लिए गीस फ्रांक भत्ता और आने जाने का सफर खर्च मिलता है। सभा में बैठने से आनेवालों का भत्ता काट लिया जाता है। 'नेशनल कौंसिल' की हर एक साधारण और असाधारण बैठक शुरू होने पर सभा अपने सदस्यों में से एक सभा का अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और चार मंत्री चुन लेती है। मगर यह शर्त रखी गई है कि जो चुनाव की सभा के अध्यक्ष के स्थान पर बैठता है उस को उसी सभा की बैठक के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है, न उपाध्यक्ष को लगातार दो बैठका में उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। इस शर्त को रखनेवालों ने शायद यह सोचा होगा कि साल भर में नेशनल कौंसिल की एक ही बैठक हुआ करेगी। मगर काम बढ़ जाने से अब साल भर में सभा की दो बार बैठकें होती हैं। एक बार बैठकें जून के पहले सोमवार और दूसरी बार दिसंबर के पहले सोमवार से शुरू होती हैं। परंतु इन दोनों सालाना बैठकों को व्यवस्थापक कल्पना में एक ही बैठक मान लिया गया है, और साल भर तक एक ही अधिकारी सभा का काम चलाते हैं। उपाध्यक्ष और मंत्रियों के चुनाव में अध्यक्ष अन्य साधारण सदस्यों की तरह भाग लेता है। परंतु प्रस्तावों और मसविदों पर जब सभा के सदस्य बराबर बराबर दोनों तरफ बँट जाते हैं, तभी गोंठ पड़ जाने पर, वह अपना मत देता है, आम तौर पर नहीं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों को मिला कर एक न्यूरो बन जाता है, जो सभा की कमेटीयों को चुनता, मत गिनता और सभा का सारा काम काज चलाता है।

(२) स्टैंडराय—'स्टैंडराय' या 'कौंसिल ऑफ़ स्टेट्स' में ४४ सदस्य होते हैं।

हर एक छोटे-बड़े कैंटन से इस सभा के लिए दो-दो सदस्य चुने जाते हैं<sup>१</sup>। सदस्यों के चुनाव की शर्तें, ढंग, और उन के सदस्य रहने का काल और भत्ता मुख्यतः लिफ कैंटन अपनी अपनी इच्छानुसार तय करते हैं। अधिकतर कैंटनों में सदस्यों को खारी भत्ताधिकारी प्रजा चुनती है। मगर सात कैंटनों में उन को कैंटनों की धारासभाएं चुनती हैं। पाँच पूरे कैंटन और सारे आधे कैंटन सदस्यों को सिर्फ एक साल के लिए चुनते हैं। एक कैंटन दो साल के लिए चुनता है; एक चार साल के लिए और धाक्री तीन साल के लिए। अतः इस विषय में कैंटनों की फारवाँ में समता नहीं होती है। स्टैंडराय के सदस्यों का भत्ता भी कैंटनों के खजानों से दिया जाता है। ग्राम तौर पर यह भत्ता उतना ही होता है जितना कि संघीय खजाने से नेशनलराय के सदस्यों को मिलता है। मगर इस में भी मुख्यतः लिफ कैंटनों में कुछ न कुछ भेद रहता है। अतः स्टैंडराय सिद्धांत के सिवाय चाल-ढाल में भी बिल्कुल संघीय संस्था हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट के ढंग पर, संघ के सदस्य प्रांतों से दो दो प्रतिनिधि ले कर, स्विट्ज़रलैंड की स्टैंडराय बनाई गई है। मगर अमेरिका की सिनेट की तरह महस्य का स्थान देश की राजनीति में स्टैंडराय को नहीं है। फिर भी 'हाउस ऑफ़ लार्ड्स' की तरह बिल्कुल कमजोर संस्था भी यह नहीं है। स्टैंडराय का संगठन नेशनल राय का-या ही है। पहले इस संस्था का अधिक महस्य था। परन्तु धीरे-धीरे यह नष्ट हो गया है। चतुर और महत्वाकांक्षी लोग स्टैंडराय की बजाय नेशनलराय में ही जाना अधिक पसन्द करते हैं। कानून स्टैंडराय को नेशनलराय के बराबर सत्ता होती है। अकसर नेशनलराय के भेजे हुए मंत्रियों को स्टैंडराय नामंजूर कर देती है। मगर प्रस्तावना और स्वतंत्रता में वह नेशनलराय का मुकाबला नहीं कर सकती है।

( ३ ) काम-काज—नेशनल एसेंबली को संघीय सरकार की सब प्रकार की सत्ता का पूरा उपयोग करने का अधिकार है। कानून बनाने के साथ-साथ शासन और न्याय-संबंधी काम भी व्यवस्थापक-सभा करती है। संघीय मंत्रि-मंडल, राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों, चांसलर और राष्ट्रीय सेना के कमांडर इन् चीफ को व्यवस्थापक-सभा चुनती है। संघीय कार्यकारिणी के रिक्ताफ शिकायतों और संघीय सरकार के मुख्यतः लिफ विभागों के आपस के झगड़ों का न्याय करने में व्यवस्थापक-सभा अदालत का काम करती है।

कानून बनाने और खास तौर पर संघीय सरकार के अधिकारियों को चुनने और समर्थित करने, उन का चेतन निश्चित करने, दूसरे देशों से संधियाँ और कैंटनों के आपस के समझौतों को मंजूर करने, सालाना राष्ट्रीय आय-व्यय तय करने, और ज़रूरत पड़ने पर व्यवस्थापक-सम्मेलन का रूप धारण करके राज-व्यवस्था के संशोधन करने का काम भी

<sup>१</sup>पूरे कैंटन स्विट्ज़रलैंड में २२ ही हैं। मगर तीन कैंटनों के दो-दो कैंटन करके २५ बना दिए गए हैं। मगर स्टैंडराय के चुनाव में उन के दोनों भागों को मिला कर एक कैंटन माना जाता है और इस लिए चुनाव के लिए २२ ही कैंटन माने जाते हैं।

नेशनल ऐसेंबली ही करती है। कानून पास करने का काम व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाएं अपनी अलग-अलग बैठकों में करती हैं और किसी कानून को पास होने के लिए दोनों सभाओं में अलग-अलग बहुमत मिलने की जरूरत होती है। संघीय सरकार के अधिकारियों को चुनने के लिए और क़राड़ों का न्याय करने के लिए न्यायालय की तरह जब व्यवस्थापक-सभा की बैठक होती है, तब नेशनलराय और स्टैंडराय दोनों के सदस्य मिल कर एक सभा में बैठते हैं और इस सभा में हर एक बात की मंजूरी के लिए सब के मिल कर बहुमतों की जरूरत होती है। सभाओं में भाषण और इच्छानुसार मत देने की सब सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता होती है। दोनों सभाओं के किसी प्रतिनिधि के निर्वाचनक्षेत्र के मतदार अपनी हिंदायतों के अनुसार उस प्रतिनिधि को मत देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। व्यवस्थापक-सभा के किसी सदस्य को, जब तक वह सदस्य रहता है तब तक, किसी सख्त अपराध के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

संघीय सरकार की 'कार्यकारिणी' समिति, जिस को 'फेडरल कौंसिल' कहते हैं, व्यवस्थापक-सभा की बैठकें शुरू होने पर, दोनों सभाओं के अध्यक्षों के पास उन सारे प्रश्नों की एक सूची बना कर, जो उस के पास व्यवस्थापक सभा के सामने रखने के लिए आते हैं और उन प्रश्नों पर अपनी मीमांसा लिख कर भेज देती है। इस सूची में वे सारे प्रश्न आ जाते हैं जो फेडरल कौंसिल के पास उस की राय के लिए भेजे जाते हैं, या जिन नए प्रश्नों को किसी कैंटन की सरकार या कोई व्यक्ति नेशनल ऐसेंबली के सामने लाना चाहते हैं। दोनों अध्यक्ष मिल कर आपस में तय करते हैं कि कौन-सी सभा किस प्रश्न पर विचार करेगी और इस फैसले को वह दोनों अपनी-अपनी सभाओं के सामने पहले या दूसरे दिन की बैठक में रख देते हैं। नेशनलराय का अध्यक्ष सभा की बैठक होने से पहले सभा की एक-दो कमेटियों को भी बुला लेता है जिस से कि उन कमेटियों की रिपोर्ट सभा के बैठते ही बहस शुरू करने के लिए तैयार रहे। मसविदों पर चर्चा के समय कोरम के लिए सभा की बहुसंख्या की हाज़िरी की जरूरत होती है; मगर उन के मंजूर होने के लिए, जितने मत पड़े उन की बहुसंख्या की जरूरत होती है। एक सभा में मसविदा पास हो जाने पर उस सभा के अध्यक्ष और मंत्री उस पर दस्तखत कर के दूसरी सभा के पास विचार के लिए भेज देते हैं। दूसरी सभा के उस को जैसा का वैसा पास करने पर वह मसविदा फिर पहली सभा के पास आता है और वह सभा उस को कानून एलान करने के लिए फेडरल कौंसिल के पास भेज देती है। अगर दूसरी सभा उस में संशोधन करती है तो वह फिर विचार के लिए पहली सभा के पास आता है और पहली से फिर दूसरी के पास जाता है और इसी प्रकार दोनों सभाओं के पास आता-जाता रहता है जब तक कि दोनों सभाओं की राय एक नहीं हो जाती है, या मतभेद की बात मसविदे में से निकाल नहीं दी जाती है। मतभेद होने पर जब मसविदे पुनः विचार के लिए सभाओं के पास जाते हैं तब उन की सिर्फ़ उन बातों पर ही बहस होती है जिन पर दोनों सभाओं का मतभेद होता है—दूसरी बातों पर नहीं।

'फेडरल कौंसिल' अर्थात् स्विट्जरलैंड के मंत्रि-मंडल के सदस्यों को दोनों

सभाओं में जा कर बोलने और जिस विषय पर चर्चा चल रही हो उस पर अपने प्रस्ताव पेश करने का हक होता है। उन से शासन के काम-काज के बारे में सदस्य सवाल-पूछ सकते हैं जिस का उन को उसी दिन या दूसरे दिन की बैठक में जवाब देना पड़ता है। गर्मियों में रोज़ सुबह साठ गंजे और जाड़ों में नौ बजे सभाओं की बैठकें शुरू हो जाती हैं। ग्राम तीर पर रोज़ पाँच घंटे उन की बैठकें होती हैं। सदस्यों को काली पोशाक पहन कर सभाओं में आना होता है और हाज़िरी के वक़्त अपने नाम की पुकार होने पर जवाब देना या अप्पत्त के सामने गेरहाज़िरी की वजह पेश करनी होती है। गेरहाज़िर सदस्य के नाम कार्रवाई की किताब में लिख लिए जाते हैं, और अगर हाज़िरी होने के पक्ष में घंटे के अंदर नहीं आते हैं, तो उन का उस दिन का भत्ता ज़न्त हो जाता है।

सभाओं का काम 'फेडरल कौंसिल' के भेजे हुए किसी प्रस्ताव, मसविदे, या रिपोर्ट दूसरी सभा से आये हुए किसी कागज़, किसी कमेटी की रिपोर्ट, किसी सदस्य के प्रस्ताव या किसी अर्ज़ों पर चर्चा से शुरू हो सकता है। अप्पत्त हर रोज़ सभा का कार्यक्रम पहले से बना लेते हैं और उसी के अनुसार काम शुरू होता है। हर एक प्रस्ताव और रिपोर्ट सभा के सामने जर्मन और फ्रेंच दो भाषाओं में पढ़ी जाती है। रिपोर्ट देनेवाली कमेटी के सदस्य उस के बाद उठ कर अपनी राय विस्तार से समझा सकते हैं और फिर उस पर बहस शुरू होती है। सभा के सदस्य अपनी जगहों से बोलते हैं। एक प्रश्न पर एक सदस्य तीन बार से अधिक नहीं बोल सकता है। किसी सदस्य को लिखा हुआ व्याख्यान पढ़ा की इजाज़त नहीं होती है। चर्चा शुरू हो जाने के बाद जिन सदस्यों को चर्चा में भाग लेना होता है वह सभा के अध्यक्ष के पास अपने नाम लिख कर भेजते जाते हैं और जिस क्रम में उस के पास नाम पहुँचते हैं उसी क्रम में वह सदस्यों को बोलने का मौक़ देता है। सदस्य फ्रेंच, जर्मन, या इटालियन भाषा में बोल सकते हैं। ग्राम तीर पर स्विट्ज़रलैंड के पड़े लिखे लोग कम से कम इन में से दो भाषाएँ जानते हैं। मगर किसी सदस्य की माँग पर सभा का अनुवादक व्याख्यान का सार इन में से किसी भाषा में समझा सकता है।

हर मसविदा पेश होने पर पहले केवल इस बात पर मत लिए जाते हैं कि उस विषय पर विचार किया जायगा या नहीं। विचार करने का निश्चय हो जाने पर फिर इस बात पर विचार किया जाता है कि उस मसविदे पर फौरन ही विचार किया जायगा, कुल मसविदे पर इकट्ठा विचार किया जायगा, या उस के अलग-अलग भागों पर विचार किया जायगा। किसी प्रश्न पर विचार करने का निश्चय करने के बाद उस सत्र के प्रस्ताव को 'फेडरल कौंसिल' के पास भेज दिया जाता है और 'फेडरल कौंसिल' दूसरे मौजूदा कानूनों का लिहाज़ रखते हुए उस विषय पर उचित मसविदा बना देती है। इस प्रकार जो बातें जल्दी में सदस्यों की आँख से बच जाती हैं उन को सब प्रकार के कानूनों की अगल में लानेवाले अनुमती और चतुर लोगों की या कमेटी ठीक कर के व्यवस्थापक सभा की इच्छानुसार कमबद्ध ढंग में रख देती है। सब प्रकार के काम-काज पर विचार करने के लिए सभाओं की कमेटियाँ भी

आवश्यकतानुसार बनाई जाती हैं। मगर किसी मसविदे को किसी रमेटी के विचार के लिए सभा की राय ही से भेजा जाता है। रमेटियों का चुनाव सभा के सदस्यों के खुले या गुप्त मतों से होता है अथवा अभ्यक्त और मत्रियों का न्युरो उन को नियुक्त कर देता है। 'स्टेंडराथ' की रेलें और सेना इत्यादि कुछ खास विषयों की स्थायी कमेटियां हर साल नई चुनी जाती जाती हैं। सभाओं की बैठकों का समय कम होता है और काम की भरमार अधिक होती है, इस लिए वक्त का बहुत ख्याल रख कर काम चलाना पड़ता है। दोनों सभाओं के काम काज के नियम लगभग एक ही से होते हैं। उन में हर मामले की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करने और उस पर अच्छी तरह नद्स का मौका देने का खास ख्याल रक्ता जाता है।

किसी मसविदे या प्रस्ताव पर होती हुई चर्चा को बंद करने के लिए सभा में हाजिर सदस्यों के दो तिहाई मतों की जरूरत होती है। मगर जब तक कोई ऐसा सदस्य जिस ने चर्चा में भाग न लिया हो कोई सशोधन पेश करने और उस को समझाने की इच्छा जाहिर करता है तब तक चर्चा बंद करने का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ग्राम तौर पर सभाओं की बैठकें दर्शकों के लिए खुली होती हैं। मगर 'फेडरल कौंसिल' अथवा दस सदस्यों के प्रस्ताव पर सभाओं की बैठकें बंद भी हो सकती हैं। व्यवस्थापक सभा की कार्यवाई के सब कागजात एक फेडरल चांसलर नाम का अधिकारी अर्थात् सधीय सरिश्तेदार या मुहाफिज दफ्तर रखता है जिस को व्यवस्थापक-सभा 'फेडरल कौंसिल' के चुनाव के समय चुनती है। यह अधिकारी 'फेडरल कौंसिल' अर्थात् मनि मडल का सदस्य नहीं होता है। एक नायब सरिश्तेदार या मुहाफिज दफ्तर की नियुक्ति भी फेडरल कौंसिल करती है। मुहाफिज दफ्तर के नेशनलराथ के काम काज में मशगूल रहने पर स्टेंडराथ का काम सँभालने का भार नायब पर रहता है। मगर नायब की ज़िम्मेदारी दोनों सभाओं के काम के लिए होती है। व्यवस्थापक सभा की जिन दिनों बैठकें नहीं होती हैं, उन दिनों 'चांसलर 'फेडरल कौंसिल' के मंत्री की तरह काम करता है; कौंसिल की बैठकों में जाता है और कागजात और आदेश तैयार करता है। कानूनों के एलानों पर फेडरल कौंसिल के मंत्री की हैसियत से चांसलर के दस्तखत भी रहते हैं।

जैतनों की तरह उस ने भी जाचारी और इख्तियारी हवाले का प्रयोग होता है। सधीय राज व्यवस्था के सशोधन के लिए लाचारी हवाले का प्रयोग होता है। इख्तियारी हवाला साधारण कानूनों के लिए काम में आता है। सधीय व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाएँ अगर सधीय राज व्यवस्था की निम्नकुल पुनर्घटना करने के लिए सहमत होती हैं, तो वे नई राज-व्यवस्था को गढ़ कर उसी तरह पास कर लेती हैं, जिस तरह वे किसी और साधारण कानून को बना कर पास करती हैं। नई राज व्यवस्था के इस प्रकार व्यवस्थापक सभा से पास हो जाने के बाद आखिरी मजूरी के लिए उस पर प्रजा के मत ज़रूर लिए जाते हैं। अगर दोनों सभाएँ राज-व्यवस्था की पुनर्घटना के प्रश्न पर सहमत नहीं होती हैं या पचास हजार मतदारों की तरफ से पुनर्घटना की माँग आती है तो पहले इस प्रश्न पर प्रजा के मत लिए जाते हैं कि पुनर्घटना की ज़रूरत है या नहीं। अगर प्रजा पुनर्घटना के पक्ष में मत देती है तो व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव होता है, और नई चुनी हुई व्यवस्थापक-सभा

पुनर्घटना का काम हाथ में लेती है। राज व्यवस्था के किमी अंग का सशोधन व्यवस्थापक-सभा उसी प्रकार कर सकती है जिस प्रकार वह साधारण कानून बनाने का काम करती है। मगर उस पर भी प्रजा का मत लिया जाता है। अथवा सशोधन के प्रस्ताव पर पचास हजार मतदारों की अर्जों आने पर व्यवस्थापक-सभा विचार करती है, और अगर वह उस से सहमत होती है, तो उस पर प्रजा का मत लेती है। अगर प्रस्तावना का कोई निश्चित रूप न हो कर अर्जों में महज आम बातें होती हैं, तो धारा-सभाएं खुद प्रस्ताव का निश्चित रूप बना लेती हैं। अगर व्यवस्थापक सभा सशोधन के प्रस्ताव के विरुद्ध होती है तो वह उस प्रस्ताव को अपनी मजबूरी की सिफारिश या उसी विषय पर उस की बजाय अपने दूसरे प्रस्ताव के साथ प्रजा के मतों के लिए भेज देती है। हर हालत में राज व्यवस्था के हर प्रकार के सशोधन के लिए मत देनेवाले नागरिकों की बहुसंख्या के साथ साथ कैंटनों की बहुसंख्या की भी मजूरी की ज़रूरत होती है। सन् १८७४ ई० से सन् १९१७ ई० तक स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापक-सभा ने अपनी राज व्यवस्था में इक्कीस सशोधन किए थे, और पचास सशोधनों को छोड़ कर और सत्र प्रजा और कैंटनों की बहुसंख्या से मजूर हुए थे।

साधारण कानूनों पर इख्तियारी हवाला लिया जाता है। जरूरी और व्यक्तिगत कानूनों को छोड़ कर और सब कानून और प्रस्ताव व्यवस्थापक-सभा में पास होने के बाद ६० दिन तक मुलतवी रखे जाते हैं, जिस से कि प्रजा को अगर वह चाहे तो हवाले की अर्जों भेजने का मौक़ा रहता है। इस दर्मियान में अगर तीस हजार मतदारों के हस्ताक्षरों की एक अर्जों में या आठ कैंटनों की धारासभाओं की ओर से किसी कानून के विषय में फेडरल कौंसिल के पास हवाले की मांग पेश हो जाती है, तो फेडरल कौंसिल को मांग का बाकायदा एलान होने के चार हफ्ते के अंदर उस कानून पर प्रजा का मत लेना होता है। अगर सारे कैंटनों से मत डालनेवालों की संख्या की बहुसंख्या उस कानून के पक्ष में मत देती है तो फेडरल कौंसिल उस कानून को अमल के लिए एलान कर देती है। अगर मत देनेवालों की बहुसंख्या उस के खिलाफ होती है तो वह कानून रद्द करार दे दिया जाता है। अगर हवाले की मांग नहीं की जाती है, तो ६० दिन का अर्सा खत्म होने पर आप से आप कानून अमल में आ जाता है। कैंटनों की तरह सब में भी प्रजा अपने इस अधिकार का गाढ़े-गाढ़े ही उपयोग करती है। सन् १८७४ ई० से सन् १९०८ ई० तक व्यवस्थापक-सभा से २६१ ऐसे प्रश्न मजूर हुए थे जिन पर इख्तियारी हवाला लिया जा सकता था। मगर सिर्फ तीस प्रश्नों पर हवाले की मांग हुई थी, और तीस में से सिर्फ उन्नीस को प्रजा ने नामजूर किया था।

सन् १८४८ ई० की स्विट्ज़रलैंड की राज व्यवस्था में यह योजना थी कि राज व्यवस्था की बिल्कुल पुनर्घटना की प्रस्तावना पचास हजार मतदार कर सकते थे। राज व्यवस्था में एक दो कोई खास सशोधन करने का अधिकार प्रजा को नहीं था। सन् १८६१ ई० से खास सशोधनों की प्रस्तावना करने का अधिकार भी प्रजा को दे दिया गया था। अब पचास हजार मतदार, जब चाहें तब व्यवस्थापक सभा को उस की मजूरी हो या न हो, राज व्यवस्था में प्रस्तावित सशोधनों पर प्रजा का मत लेने के लिए मजबूर कर सकते



है। व्यवस्थापक-सभा उन सशोधनों के विरुद्ध होने पर अधिक से अधिक उन को नामजूर करने की प्रजा से सिफारिश कर सकती है या उन सशोधनों के स्थान पर अपने सशोधन पेश कर सकती है। जन प्रस्तावना का अधिकार प्रजा को दिया गया था, तब कुछ लोगो का ख्याल था कि प्रजा के हाथ में राज व्यवस्था के सशोधन की सत्ता चले जाने से ऊटपटाँग सशोधन पेश होने लगेंगे और राज व्यवस्था खतरे में पड़ जायगी। मगर यह डर व्यर्थ साबित हुआ है, क्योंकि तीन वर्ष के अंदर सिर्फ दस राज व्यवस्था के सशोधन प्रजा की तरफ से आए और उन में से भी सिर्फ चार ही को प्रजा ने मजूर किया। स्विट्जरलैंड में प्रजा के राज काज में हिस्सा लेने के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि साधारण लोग इतने गैरजिम्मेदार नहीं होते जितना कि आमतौर पर उन को समझा जाता है।

शुरू शुरू में एक सशोधन जरूर ऐसा प्रजा ने पास कर दिया था, जिस को इस सत्ता का दुसपयोग कह सकते हैं। यह सन् १८६३ ई० का एक राज व्यवस्था में सशोधन था जिस के अनुसार राज व्यवस्था में यह शर्त रख दी गई थी कि 'स्विट्जरलैंड में पशुओं को बिना पहले बेहोश किए उन की, यहूदियों के दग से गला काट कर खून बहा कर, हत्या नहीं की जा सकती है।' यह सशोधन पेश हुआ तो पशु-सकट हरण सभा के आंदोलन के कारण था, मगर अधिकतर उस के पीछे यहूदियों के खिलाफ लोगों का आम घुरजा और व्यापारी जलन थी। अन्यथा कस्बाबखानों के नियम की राज व्यवस्था में घुसने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर इस सशोधन पर अमल करने के लिए कानून नहीं बनाए गए और अधिकतर कैंटनो में यह सशोधन मुर्दा ही रहा है। हवाला और प्रस्तावना दोनों ही स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के अमल में उपयोगी साबित हुए हैं। अभी तक दोनों का उपयोग सिर्फ राज व्यवस्था की शर्तों का सशोधन करने के लिए ही होता है। सन् १९०६ ई० में 'फेडरल कौंसिल' ने सारे कानून और प्रस्तावों की प्रस्तावना और हवाले का अधिकार पचास हजार मतदारों को दे देने की एक आयोजना रखी थी। मगर वह योजना व्यवस्था-पर सभा में स्वीकार नहीं हुई थी। प्रस्तावना और हवाले का क्षेत्र बड़ा देने की बातें बहुत दिनों से स्विट्जरलैंड के सुधार में चलती हैं, और मुमकिन है कि उस का क्षेत्र शीघ्र ही बढ़ा दिया जाय, क्योंकि उस में दिक्कत और खर्च इतना नहीं होता है जितना उस से फायदा होता है।

## (२) कार्यकारिणी

**फेडरल कौंसिल और प्रमुख**—स्विट्जरलैंड की राज-व्यवस्था में राष्ट्र की कार्य-कारिणी सत्ता सात आदमियों की एक 'संघीय समिति'—फेडरल कौंसिल—में रखी गई है। इस समिति के सदस्यों को हर नई नेशनलराय के चुनाव के बाद व्यवस्थापक सभा की दोनों शाखाओं के सदस्य एक सभा में इकट्ठे बैठ कर तीन वर्ष के लिए चुनते हैं। नेशनलराय की उम्मीदवारी का अधिकारी हर एक स्विट्जरलैंड का नागरिक फेडरल कौंसिल के लिए रड़ा हो सकता है। मगर एक कैंटन से दो सदस्यों का अथवा एक ही जुटुव या नज़दीक



म बाँट दिया जाता है। एक 'राजनीतिक विभाग' होता है जिस में परराष्ट्र विषय और नागरिकता, सघीय चुनाव और प्रवास के कानून बनाने का काम भी आ जाता है। यह विभाग, न्याय और पुलिस विभाग, सेना विभाग, कर और अर्थ विभाग, डाक और रेल-विभाग, व्यापार-विभाग, उद्योग विभाग, और कृषि विभाग छ। दूसरे शासन विभाग होते हैं। इन विभागों के प्रमुख 'फेडरल कौंसिल' के सात सदस्यों में ग्राह्य होता है। राज व्यवस्था में साफ-साफ लिखा है कि, "विभागों का बाँट सिर्फ शासन की सहूलियत के लिए किया जाता है और शासन के हर प्रश्न का पेमला फेडरल कौंसिल मिल कर करेगी।" आमतौर पर 'फेडरल कौंसिल' के वही सदस्य, जब तक उन की काम करने की इच्छा रहती है, बार बार चुन लिए जाते हैं। सरकार का काम बढ़ जाने से आज छल विभागों की देख रेख रखनेवाले सदस्यों को पहले से कुछ अधिक निश्चय की स्वतंत्रता रहती है। कौंसिल का फोरम चार सदस्यों का होता है और कोई सदस्य बिना बजह रतलाए कौंसिल की किसी बैठक से गैरहजिर नहीं हो सकता है। पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने के प्रश्नों को छोड़ कर और सब प्रश्नों पर फेडरल कौंसिल में जवानी मत लिए जाते हैं। सभा की बैठकों की कार्यवाही का सार प्रजातन्त्र के सरकारी गजट में बराबर छपता है।

स्विट्जरलैंड की फेडरल कौंसिल देखने में इंग्लैंड या फ्रांस के मन्त्रि मंडल की तरह लगती है, परन्तु उस को वास्तव में उस तरह का मन्त्रि मंडल नहीं कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड में मन्त्रि मंडल की सरकार नही होती है क्योंकि यद्यपि कौंसिल मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक सभा के सामने रखती है, और कौंसिल के सदस्य व्यवस्थापक-सभा में जा कर बहस में भाग लेते हैं—फिर भी, वह व्यवस्थापक सभा के न तो सदस्य होते हैं, न वे किसी एक दल के सदस्य या एक नीति या एक विश्वास के माननेवाले होते हैं, न उन सब का ज़रूरी तौर पर हर प्रश्न या मसविदे पर एक मत होता है, और न उन के मसविदे व्यवस्थापक सभा में नामज़ूर हो जाने पर वह अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। एक बार फेडरल कौंसिल के एक पुराने सदस्य ने अपने मसविदे के प्रजा के नामज़ूर कर देने पर इस्तीफा दे दिया था तो स्विट्जरलैंड भर में इस बात पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया गया था। स्विट्जरलैंड की फेडरल कौंसिल असल में वही व्यवस्थापक सभा की एक कार्यवाहक समिति होती है, फ्रांस और इंग्लैंड में कार्यकारिणी की सत्ता प्रमुख और राजछत्र की होती है, और मन्त्रि मंडल के सदस्यों की कार्यकारिणी का यह सिरताज नियुक्त करता है। मगर स्विट्जरलैंड की कार्यकारिणी समिति को वही व्यवस्थापक सभा नियुक्त करती है और कार्यकारिणी का हर एक सदस्य अलग अलग नियुक्त किया जाता है। मगर समिति के सदस्य अपने मत भेदा को समिति के अंदर ही तय करके हमेशा बाहर एक मत से काम करने की कोशिश करते हैं। अस्तु, फेडरल कौंसिल की राय को सब वज़न देते हैं।

सिर्फ रोज़मर्रा के ज्ञान्ते का शासनकाय ही 'फेडरल कौंसिल' का करना होता है। दूसरे देशों के मन्त्रि मंडलों की तरह व्यवस्थापक सभा को नाम पकड़ कर चलानेवाली यह समिति नहीं होती है। उस के सिर पर बैठनेवाली नेशनल ऐसेंबली उस के मामूली

शासन के काम में भी हस्तक्षेप कर के उन को रद्द कर सकती है, और 'फेडरल कौंसिल' कुछ नहीं कर सकती। सारी सत्ता ऐसंबली में ही होती है, और फेडरल कौंसिल और नेशनल ऐसंबली में किसी विषय पर मतभेद होने पर जिस नीति का ऐसंबली आदेश करती है, उसी पर कौंसिल चलती है। स्विट्ज़रलैंड में कार्यकारिणी और धारासभा में सन्ध तो उतना ही निरुद्ध का रहता है जितना कि मजिस्ट्रेट की सरकार के देशों में रहता है। मगर स्विट्ज़रलैंड के इस सन्ध और उन देशों के ऐमे ही सन्ध में बहुत अंतर होता है। फेडरल कौंसिल को कार्यकारिणी, कानून बनाने और न्याय शासन तीनों प्रकार के काम करने होते हैं। कार्यकारिणी की हैसियत से उस को व्यवस्थापक सभा के पास किए हुए मार कानूनों और प्रस्तावों तथा सघीय अदालत के सारे फैसलों को अमल में लाना होता है। उस को देश के गहरी हितों पर नजर रखना और दूसरे राष्ट्रों से सन्ध ठीक रखना होता है। देश की भीतरी-बाहरी रक्षा का प्रबंध रखना, कुछ ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना जिन की नियुक्ति का अधिकार किसी और को नहीं होता है, राष्ट्र का आय-व्यय तय करना, बजट तैयार करना और हिसाब कितान ठीक रखना, सारे सघीय अधिकारियों के काम की निगरानी रखना, सघीय राज व्यवस्था और कंट्रोलों की राज व्यवस्थाओं को अमल में कायम रखना, और सघीय सेना की व्यवस्था और प्रबंध करना इत्यादि फेडरल कौंसिल के शासन कार्य में आता है। कानूनी क्षेत्र में कौंसिल का काम ऐसंबली में नए-नए प्रस्ताव और मसविदे रखना, कंट्रोल और व्यवस्थापक सभा की ओर से राय के लिए भेजे हुए मसविदों पर अपनी राय जाहिर करना इत्यादि होता है। व्यवस्थापक सभा की हर बैठक में फेडरल कौंसिल को अपने शासन और देश की भीतरी और बाहरी स्थिति की एक रिपोर्ट भी दाखिल करनी होती है। शासन सन्ध जो मुकदमे सघीय अदालत के सामने नहीं दायर किए जा सकते हैं, उन को फेडरल कौंसिल खुद सुनती है, और उन की अपील नेशनल ऐसंबली के पास जाती है। सन् १९१४ ई० में स्विट्ज़रलैंड की राज व्यवस्था में एक संशोधन किया गया जिस के अनुसार शासन सन्ध मुकदमों पर विचार करने के लिए शासकी अदालत कायम करने की योजना की गई।

### (३) न्यायशासन

स्विट्ज़रलैंड की अन्य अनूठी बातों की तरह वहां का न्यायशासन भी एक तरह से अनूठा है। स्विट्ज़रलैंड में न्यायाधीशों को भी प्रजा के प्रतिनिधि चुनते हैं। न्याय विभाग का संगठन तो बहुत सरल और सीधा है मगर उस का काम बड़ा कठिन और टेढ़ा है। स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय या 'सघीय अदालत' है। यह राष्ट्रीय अदालत सन् १८४८ ई० में कायम हुई थी। इस अदालत में आजकल चौनीस न्यायाधीश और नौ एवजी-न्यायाधीश होते हैं जिन का चुनाव छ साल के लिए सघीय व्यवस्थापक सभा करती है। नेशनलराय की उम्मीदवारी के लिए खड़ा हो सकनेवाला कोई भी नागरिक

राष्ट्रीय अदालत का न्यायाधीश चुना जा सकता है। मगर व्यवस्थापक सभा को इस बात का खयाल रखने का फर्ज माना गया है कि न्यायाधीशों में जर्मन, फ्रेंच, और इटैलियन तीनों भाषाओं के जाननेवालों की काफी संख्या रहनी चाहिए। अदालत के प्रधान और उपप्रधान को भी दो वर्ष के लिए व्यवस्थापक सभा ही नियुक्त करती है। मगर अदालत अपने दूसरे अधिकारियों को खुद नियुक्त करती है। इस अदालत के न्यायाधीश व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं, न वह कोई और पद ल या कोई और धारा कर सकते हैं। उन को पंद्रह हजार फ्रांक सालाना का वेतन मिलता है।

राष्ट्रीय अदालत लूज़ान नगर के एक सुंदर भवन में बैठती है। दीवानी और फौजदारी के मुकदमों, सच और कंटनों के बीच के मुकदमों, किसी संस्था या व्यक्ति के मुद्दे होने पर और तीन हजार फ्रांक से अधिक का मुकदमा होने पर उस संस्था या व्यक्ति और सच के बीच के मुकदमों, कंटनों के एक दूसरे से मुकदमों, और तीन हजार फ्रांक से अधिक के मुकदमों होने पर मुद्दे और मुद्दालय की मर्जों से कंटना और किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति के बीच के मुकदमों, राष्ट्रीय अदालत की अधिकार सीमा में आते हैं। राज व्यवस्था में, कानून बना कर, राष्ट्रीय अदालत की अधिकार सीमा को बढ़ाने का अधिकार सच को दिया गया है। उस के अनुसार कर्जा और दिवाला इत्यादि दीवानी के मामलों में उस की अधिकार-सीमा का कई बार विस्तार भी किया गया है। कंटनों की अदालतों से दोनों पक्षों की मर्जों से आई हुई अपीलें भी यह अदालत सुनती है। दीवानी के मुकदमों का फैसला करने के लिए राष्ट्रीय अदालत अपने न्यायाधीशों में से आठ-आठ न्यायाधीशों की दो छोटी छोटी अदालतें बना देती है। एक का अध्यक्ष राष्ट्रीय अदालत का प्रधान होता है और दूसरी का अध्यक्ष उपप्रधान होता है। राष्ट्रीय अदालत के तीन न्यायाधीशों की एक अदालत बन कर कर्जों और दिवालों के मुकदमों को सुनती है। फौजदारी के सच में इस अदालत की अधिकार-सीमा इतनी विस्तृत नहीं है। प्रजातन्त्र के प्रति राजद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ अपराध, इस प्रकार के राजनीतिक अपराध जिन में सच की सेना को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़े और सघीय सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सरकार के अदालत से प्राथना करने पर मुकदमों राष्ट्रीय अदालत के सामने पेश होते हैं। इन मुकदमों में वाक्यात का फैसला करने के लिए अदालत को बारह आदमियों की एक ज़री भी चुन लेनी होती है। दूसरी तरह के फौजदारी के मुकदमों को भी कंटनों की सरकारें सघीय व्यवस्थापक-सभा की राय से सघीय अदालत के पास भेज सकती हैं। फौजदारी के मुकदमों सुनने के लिए सघीय अदालत के न्यायाधीशों में पाँच पाँच या अधिक न्यायाधीशों और दो दो एवजी न्यायाधीशों की हर साल चार अदालतें बना दी जाती हैं। स्विट्ज़रलैंड को फौजदारी के मुकदमों के न्याय के लिए चार हल्कें में बाँट दिया गया है। हर हल्के में इन चार में से एक अदालत उस हल्के के मुकदमों सुनने के लिए बैठती है। सच और कंटनों की अधिकार सीमा के फगड़े, कंटनों के आपस के अधिकार-सीमा के फगड़े, नागरिकों के राज-व्यवस्था में दिए हुए अधिकारों को उल्लंघन करने की शिकायतें, कंटनों की आपस की सघियों के तोड़ने के सच में व्यक्तियाँ

की शिकायते 'संघीय अदालत' सार्वजनिक कानून संधी अपनी अधिकार सीमा के अंदर सुनती है। राष्ट्रीय अदालत को कैंटन के किसी कानून को, स्विट्ज़रलैंड की राज-व्यवस्था के खिलाफ़ करार देने का हक़ है। मगर किसी संघीय कानून को वह राज-व्यवस्था के खिलाफ़ नहीं ठहरा सकती है। संघीय अदालत को अपने फैसलों पर अमल के लिए कैंटन की सरकारों पर निर्भर रहना होता है। संघीय सरकार का देश भर के लिए एक जायज़ा फ़ौजदारी और एक जायज़ा दीवानी है।

## (४) सेना-संगठन

अनूठी राजनीतिक सस्थाओं की पान स्विट्ज़रलैंड की सेना का संगठन भी अनूठा है। हमेशा से यूरोप के इतिहास में स्विट्ज़रलैंड के सैनिक मशहूर रहे हैं। अपने देश की सेना और विदेशों की सेवा दोनों में स्विट्ज़रलैंड के सैनिकों ने यूरोप के रणक्षेत्रों में प्रख्यात सेनाओं को पददलित करके यूरोप को युद्ध विनाश में पाठ दिए हैं। मगर स्विट्ज़रलैंड के अंदर हमेशा से सेना-संगठन राष्ट्रीय सरकार के हाथ में न रह कर कैंटनों की सरकारों के हाथ में रहता था। हर कैंटन की सेना और पताका अलग अलग होती थी और दस्तों में आमतौर पर रिश्तेदार और पंगेसी होते थे। हर सेना के अपने अपने अलग नियम होते थे और किसी सैनिक के बुजदिली दिखाने, सेना से भागने या और कोई नियम तोड़ने पर उस के गाँववाले ही उस का फँसला करते थे और अपराधी साबित होने पर उस को पाँसी पर चढ़ा देते थे और उस का माल अस्वाभाव ज़ब्त कर लेते थे। हमेशा से कैंटन सेना को संघीय सरकार के हवाले करना नापसंद करते थे क्योंकि संघीय सरकार के हाथ में सेना की ताकत चली जाने से उन को अपनी स्थानिक स्वाधीनता के ख़टाई में पड़ जाने का भय रहता था। कई बार सेना को संघीय सरकार के प्रयत्न में दे देने के प्रस्ताव हुए और हर बार उन को प्रजा ने नामज़ूर कर दिया।

हमेशा से स्विट्ज़रलैंड में स्थायी सेना नहीं रही है। नेपोलियन के अधिकार के कुछ काल के लिए अग्रिम स्विट्ज़रलैंड को स्थायी सेना रखने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अभी तक किसी कैंटन को, सरकार की खास इजाजत के बिना, तीन सौ से अधिक सेना रखने का अधिकार नहीं है। मगर स्विट्ज़रलैंड के हर नागरिक को सैनिक शिक्षा लेनी होती है और देश को जोरूरत होने पर हर नागरिक को लड़ाई में कानूनन जाना पड़ता है। संघीय सरकार नागरिकों की सेना में सेवा के नियम और सेना शिक्षा, क़ायद, वर्दी, हथियार और दस्तों के बनाने के नियम बनाती है। युद्ध-काल में देश भर की सारी सेना पर राष्ट्रीय सरकार का क़ब्ज़ा और अधिकार हो जाता है। कैंटनों की सरकारें आमतौर पर सेनाओं को उठाने, मेजर के पद तक के अधिकारियों को नियुक्त करने और तरक्की देने और अपनी सेनाओं को, संघीय सरकार के नियमों के अनुसार, वर्दी और हथियार देने का काम करती हैं। संघीय सरकार के कानून के अनुसार कैंटन की सरकारें प्रजा से सेना कर भी उगाती हैं। कारतूस, हथियार तोप बनाने के कारख़ाने और बारूद बनाने का इज़ारा संघीय-सरकार के हाथ में रहता है।

देश भर के सारे नागरिकों को सैनिक शिक्षा ले लेने के बाद राष्ट्रीय-सेना के तीन भागों में उम्र के अनुसार बाँट दिया जाता है। बीस और बत्तीस वर्ष के बीच के सारे नागरिक राष्ट्र की लड़नेवाली सेना के सदस्य होते हैं। उस के बाद तैंतीस और चवालीस वर्ष की उम्र के बीच के लोगों को 'प्रथम सहायक-सेना' होती है। इन्हें छोड़ कर सवह और पचास वर्ष के बीच के सारे नागरिकों की 'दूसरी सहायक-सेना' होती है, जिस को बिल्कुल भयंकर आपत्ति के काल में लड़ाई के लिए बुलाया जाता है। नागरिक सैनिक अपने हथियार और नर्दी इत्यादि सारा सामान अपने घर में रखता है। मगर उस को हथियार और नर्दी हमेशा साफ-सुधरे और लेख रखने पड़ते हैं। हर हफ्ते काफ़ी निशाने लगा कर उसे अपनी निशानेबाजी भी ठीक रखनी होती है; वना उस पर जुर्माना हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड के हर गाँव के बाहर निशानेबाजी के मैदान होते हैं, जहाँ हर रविवार को नागरिक सैनिक निशानेबाजी करते नजर आते हैं। निशानेबाजी के दमल भी होते हैं, जिन में सरकार की तरफ़ से इनाम बाँट कर निशानेबाजी की कला को उत्तेजना दी जाती है। दस वर्ष से पंद्रह वर्ष की उम्र तक हर लड़के को, चाहे वह किसी स्कूल में पढ़ता हो या न पढ़ता हो, सैनिक कयायद की शिक्षा लेनी होती है। बाद में हर सैनिक-शिक्षाप्राप्त नागरिक का पता और ठिकाना सरकारी दफ्तर में हमेशा रहता है, जिस से ज़रूरत पड़ने पर उस को फ़ौरन बुलाया जा सके। अस्तु, स्विट्ज़रलैंड के सारे नागरिकों की एक सेना ही सम्भलना चाहिए। तीन से पाँच लाख तक आदमी स्विट्ज़रलैंड में इस प्रकार हमेशा लड़ाई के मैदान में तैयार रहते हैं। यह यूरोप के दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले में कोई बड़ी सेना नहीं, मगर इस छोटे से राष्ट्र के लिहाज से काफ़ी बड़ी सेना है। स्विट्ज़रलैंड के इस सेना-संगठन के ढंग से देश को नीजवानों की जवानी स्थायी-सेना की बेकार और अशुभक सेना नहीं गँवानी पड़ती है, और राष्ट्रीय खजाने का ख़र्चा भी इस अशुभक काम में नष्ट नहीं जाता है। सेना-सेवा में बेकार हो जानेवालों को उन की और उन के बाल-बच्चों की गुजर-बस्त के लिए सरकार पेंशन ज़रूर देती है। मगर यह स्वाभाविक है और इस में अधिक ख़र्चा ही खर्च होता है। यूरोप के कई नए राष्ट्रों ने भी स्विट्ज़रलैंड के सेना-संगठन का यह तरीका अख्तियार किया है।

### ४—राजनैतिक-दल और सरकार

छद्मसर्वी सदी के पूर्वार्द्ध में स्विट्ज़रलैंड की प्रजा के सामने सब से ज़रूरी दो न थे। एक तो कैंटनों की सरकार को प्रजा-सत्तात्मक बनाने का प्रश्न था। दूसरा उन कारों को मिला कर एक मजबूत संघीय सरकार बनाने का प्रश्न था। इन दोनों बातों के पाती लोगों का दल स्विट्ज़रलैंड में 'उदारदल' कहलाता था। सन् १८४८ ई० में नए स्विट्ज़रलैंड की इन्हीं लोगों ने रचना की थी और इसी दल का उन नई राजनैतिक धारों पर अधिकार हो गया था। 'उदारदल' का स्विट्ज़रलैंड की राजनैतिक संस्थाओं बहुत दिन तक अधिकार रहा। अनुदार राजनैतिक विचारों के कैथोलिक-संघी लोग एक बूत संघीय सरकार को नापसंद करते थे। वे इस दल के विरोधी थे। इन लोगों के दल

का 'कैथोलिक अनुदारदल' कहते थे। अस्तु, सन् १८४८ ई० के बाद कुछ वर्षों तक स्विट्ज़रलैंड में यही दो राजनैतिक दल थे और इस काल के मुख्य राजनैतिक प्रश्न केंद्रन की सरकारों के अधिकारों से सम्बन्ध रखते थे।

शुरू के कुछ दिन बाद ही 'उदार दल' में नरम और गरम प्रकृतियाँ दीखने लगी थीं। नई नई सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ जैसे-जैसे सामने आने लगीं, वैसे वैसे नरम और गरम प्रकृतियों के लोग अलग अलग होते गए। अतः में गरम विचार के लोगों ने 'उदार-दल' से बिल्कुल अलग हो कर सन् १८७० ई० में एक नया 'गरम दल' बना लिया। इस नए 'गरम दल' ने ही सन् १८७४ ई० में स्विट्ज़रलैंड की राज-व्यवस्था में संशोधन कर के, पुराने 'उदार-दल' के बहुत विरोध करने पर भी, स्थायी शासन में 'अख्तियारी हथाले' की शर्त जोड़ दी थी। इस सफलता के बाद 'गरम दल' का तृतीय धोलने लगा और बाद में एक नए 'समाजवादी दल' के बन जाने के बाद भी यही दल सत्ता से जोरदार रहा। 'अनुदार-दल' में किसी प्रकार का मतभेद न पड़ने से वह जैसा का तैसा कायम रहा।

आजकल स्विट्ज़रलैंड में चार मुख्य राजनैतिक दल हैं। 'कैथोलिक अनुदार दल', 'उदार प्रजासत्तात्मक दल' या 'उदार-दल', 'स्वतंत्रप्रजासत्तात्मक' या 'गरम दल', और 'समाजी प्रजासत्तात्मक' या 'समाजवादी दल'। कैथोलिक दल खास तौर पर कैथोलिक संप्रदाय के हितों की चिन्ता रखता है। कैथोलिक संप्रदाय के मजदूरों की समस्याओं के जोर देने पर अब यह दल मजदूरों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देने लगा है। इस दल के लोगों में आपस में और सब दलों से कम मतभेद रहता है और इस दल का संगठन दूसरे सब दलों से सुसंगठित और सुदृढ़ है। जिन केंद्रों में कैथोलिक लोगों की अधिक आबादी है उन में तो इस दल का असर राज्य है ही, दूसरे बहुत से शहरों में भी इस का काफी जोर है। 'उदार दल' में अधिकतर व्यापारी और दूसरे उदार विचारों के धनी और मानी लोग होते हैं। यह लोग अपने उदार विचारों पर गर्व करते हैं। मगर उन की बातें आज कल बहुत कम लोच सुनते हैं। उदार दल का स्विट्ज़रलैंड में भी वही हाल है जो आज-कल उदार दल का इंग्लैंड में है या जो उसी नाम के दल, का भारतवर्ष में हाल है।

'गरम दल' सरकारी केंद्रीकरण और प्रजा-राज का पक्षपाती और राजनीति में साम्राज्यिकता का विरोधी है। इस दल में किसानों से लेकर धनवानों तक सब प्रकार के लोग हैं। इस दल के सदस्यों की संख्या सब दलों से अधिक है और वह सारे देश में फैले हुए हैं। 'समाजवादी दल' का जोर उन नगरों में अधिक है जो उद्योग धंधों के केंद्र हैं—जैसे कि ज्यूरिच और बर्न। यह लोग अपने दूसरे देशों के श्रमियों के पीछे चलने का प्रयत्न करते हैं और उन के, खासकर जर्मनी के, अंतर में रहते हैं। मगर स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका या इंग्लैंड की तरह शरीरों की शरीरी और अभीरो की अभीरी में इतना जमीन-आसमान का फर्क नहीं होता है जिस से ईर्ष्या और कलह की अधिक मैदान मिल सके। छोटे छोटे जमींदारों और पूँजीगालों की ही संख्या वहां अधिक है और आमतौर पर लोग खाते-पीते होते हैं। अस्तु 'समाजवादी दल' का जोर वहां इतना नहीं बढ़ा है जितना कि



अड़ोस-पड़ोस के देशों में बढ़ गया है।

सन् १८७४ ई० के बाद बहुत वर्षों तक किसी भी दल की स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या नहीं रहती थी। मगर 'गरम दल' के सदस्यों की सब से अधिक संख्या रहने से गरम दल ही की बात अधिक चलती थी। फिर भी स्टेंडराय में आज तक गरम दल की बहुसंख्या कभी नहीं होने पाई है, क्योंकि बहुत में कैथोलिक आबादी के कैंटन सिर्फ कैथोलिक दल के सदस्यों की ही चुनते हैं। परन्तु आजकल भी नेशनल राय में गरम दल की ही आमतौर पर अधिक संख्या रहती है। सन् १९१७ ई० के चुनाव के पहले नेशनल राय के कुल १८६ सदस्यों में से १०८ सदस्य गरम दल के थे और स्टेंडराय के ४४ सदस्यों में से २१ गरम दल के थे। 'कैथोलिक अनुदार दल' 'उदार दल' और 'समाजवादी दल' के नेशनल राय में ३६, १३ और १८ सदस्य तथा स्टेंडराय में १६, १ और १ सदस्य थे। सन् १९१६ ई० में अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से चुनाव होने पर 'गरम दल' के नेशनल राय में ६३ सदस्य रह गए थे और 'कैथोलिक अनुदार दल' के ४१; 'उदार दल' के सिर्फ ६ सदस्य और 'समाजवादी दल' के ४१ सदस्य थे। सब से अधिक सदस्य फिर भी 'गरम दल' ही के थे।

सन् १९१६ ई० के चुनाव में गरम दल के एक भाग ने अलग हो कर 'किसान, मजदूर और मध्यमवर्ग दल' नाम का एक नया दल बना लिया था जो सरकार का पक्षपाती दल था मगर 'गरम दल' से अधिक अनुदार और कृषि-सुधार का कट्टर पक्षपाती था। इस दल का कार्य-क्रम कृषि और उद्योग के हित के लिए खास कानून बनाना और देश की रक्षा का मजबूत प्रबंध करना है। इसी चुनाव के बाद से समाजवादी दल को भी असफलता मिलना प्रारंभ हुई। 'समाजवादी दल' प्रत्यक्ष करो, स्वतंत्र व्यापार और स्त्रियों के मताधिकार का पक्षपाती है। गरम दल के कुछ कट्टर समाजवादियों ने उस दल से अलग हो कर एक 'समाजवादी राजनैतिक दल' नाम का दल भी बना लिया है। यह दल केंद्रीकरण, समाजशाही और सरकार के द्वारा आर्थिक जीवन के संचालन का पक्षपाती है। एक कम्युनिस्ट दल अर्थात् 'समष्टिवादी दल' भी उठ खड़ा हुआ है। सन् १९२५ ई० के चुनाव के बाद विभिन्न दलों के सदस्यों की नेशनल ऐसेंबली में निम्नलिखित संख्या थी:—

### स्टेंड राय

### नेशनल राय

दल	प्रतिनिधि संख्या	प्रतिनिधि संख्या
गरम दल	२१	५६
कैथोलिक अनुदार दल	१८	४२
समाजवादी दल	२	४६
किसान, मजदूर और मध्यमवर्ग दल	१ -	२०
उदार दल	१	७

दल	प्रतिनिधि संख्या	प्रतिनिधि संख्या
समाजवादी राजनैतिक दल	१	५
कम्प्यूनिस्ट दल	०	३
अन्य छोटे मोटे समूह	०	३
<hr/>		<hr/>
कुल	४४	१६८

स्विट्ज़रलैंड के सारे दलों का संगठन लगभग एक-सा ही होता है। वहाँ के राजनैतिक दल छोटे-छोटे स्वाधीन समूहों की सघों की तरह होते हैं। स्थानिक समूहों के प्रतिनिधियों की कम से कम साल भर में एक सभा होती है। बड़े दलों की सभाओं में तीन चार सौ तक प्रतिनिधि आ जाते हैं। यह सभा दल के अधिकारियों की रिपोर्ट सुनती है, दल के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक-सभा में कार्रवाई की जाँच करती है, और विभिन्न विषयों पर खूब बहस कर करार अपने प्रतिनिधियों की आगाही के लिए प्रस्ताव पास करती है। इस सभा को दल के संघ में सब अधिकार होते हैं। मगर चुनावों के लिए दल के उम्मीदवारों को सभा नहीं चुनती है। मुख्तलिफ़ स्थानों पर दलों की जो टोलियाँ रहती हैं, वही अपने-अपने उम्मीदार चुनती हैं। साल भर का काम चलाने के लिए सभा या कैंटनों की संस्थाओं की तरफ से तीस या पैंतीस आदमियों की एक केंद्रीय कमेटी चुन ली जाती है। इस कमेटी का एक अध्यक्ष, एक मंत्री और एक कोषाध्यक्ष होते हैं। कमेटी का आम काम चलाने के लिए एक छोटी उप समिति भी होती है जो अक्सर मिलती रहती है।

कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड की राजनीति की अनुकूलता और दृढ़ता का कारण यह है कि वहाँ शुरू से एक दल का ही बोलवाला रहा है। स्विट्ज़रलैंड में जाति-भेद, धर्म-भेद, भाषा-भेद और अन्य आर्थिक हितों के भेदों के कारण बहुत से राजनैतिक दलों के बनने के लिए जितना मसाला है, उतना यूरोप के और किसी देश में नहीं मिलता। मगर आश्चर्य की बात है कि स्विट्ज़रलैंड में राजनीति की नाव जिस शांति से खेई जाती है, उतनी यूरोप के और किसी देश में नहीं चलती है। यूरोप के अन्य देशों में एक दल के नेता की चुनाव में हार हो जाने पर दूसरे दल में खुशियाँ मनाई जाती हैं। मगर स्विट्ज़रलैंड में जब दलों को खाल रहता है कि किसी भी दल के मुख्य नेता की हार न हो जाय। पिछली यूरोप की लड़ाई में कुछ क्षण के लिए फ्रांसीसी भाषा-भाषी नागरिकों ने फ्रांस के प्रति और जर्मन भाषा-भाषियों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। मगर फौरन ही फिर सब नागरिक अपनी परराष्ट्रनीति में पुरानी निष्पक्ष नीति का अचलबन करने लगे थे। परराष्ट्रनीति पर स्विट्ज़रलैंड में कभी दलबन्दी सुनने में नहीं आती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का न तो कोई साम्राज्य है और न कोई उपनिवेश। उस की नीति अपने अड़ोस-पड़ोस के सब राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहने की है। दूसरे देशों के जिन राजनीतियों पर उन के देशों में अत्याचार होता है, उन को भाग कर स्विट्ज़रलैंड में सुरक्षित रहने का बहुत दिनों से अधिकार और रिवाज चला आता है। मगर इस

प्रकार के भागे हुए लोगों में से कोई स्विट्जरलैंड में बैठ कर अन्य राष्ट्रों के खिलाफ पड्यन न रच सके, इस बात तक का स्विट्जरलैंड की सरकार बड़ा खयाल रखती है। स्विट्जरलैंड में सारी राजनैतिक दलबंदी घरेलू प्रश्नों पर ही होती है। मगर उस में भी इतनी कड़वाहट और रार देने में नहीं आती है, जितनी यूरोप के और देशों में। इस का मुख्य कारण शायद यह कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में राजनीति से किसी को किसी प्रकार के ज़ाती फायदे का खयाल नहीं रहता है।

इंग्लैंड या अमेरिका की तरह स्विट्जरलैंड के राजनैतिक दलों के पास चुनाव की लड़ाइया लड़ने के लिए बड़े बड़े कोष भी नहीं रहते हैं। वहां चुनावों में उम्मीदवारों को बहुत रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। सन् १९१८ ई० से पहले इंग्लैंड में कानून के अनुसार एक उम्मीदवार को चुनाव में जितना रुपया खर्च करने का अधिकार था, उतने रुपए में स्विट्जरलैंड की नेशनल राय के सारे सदस्यों का चुनाव हो जाता है। निर्वाचनक्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं को चुनाव से कुछ पहले से दान इत्यादि दे कर, या इसी प्रकार किसी और ढंग से, उन क्षेत्रों को चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा तैयार किए जाने का रिवाज भी स्विट्जरलैंड में कहीं दिखाई नहीं देता है। न स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों को अपने निर्वाचनक्षेत्र के लोगों की उम्र प्रकार लगातार सेवा और सहायता करनी पड़ती है जैसी विकास में डिपुटियों को करनी पड़ती है। मंत्रियों के लिए मत दे कर चुनावों में अपनी सहायता करनेवालों के लिए कोई सदस्य किसी प्रकार का खिताब या समझे भी नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक सेवा के लिए प्रजा के हृदय में मान के सिवाय और कोई तमगा या खिताब मिलने की प्रथा ही नहीं है। स्विट्जरलैंड में सदस्यों को अपना समय देने के सिवाय राजनीति में भाग लेने के लिए और कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। आमतौर पर निर्वाचनक्षेत्र में रहनेवाले या वहां के किसी कुटुंब के रिश्तेदार ही को वहां से दल का उम्मीदवार चुना जाता है। बाहर के आदमी को उम्मीदवार नहा चुना जाता है। स्विट्जरलैंड में दूसरे देशों से मतदार अधिक स्वाधीन होने से सारे राजनैतिक दल अच्छे और योग्य आदमियों ही को उम्मीदवार बनाते हैं। राजनैतिक मतभेद का विचार न करके मतदार उसी उम्मीदवार को अपना मत देना अधिक पसंद करते हैं जिस को वह जानते हैं, और जिस की योग्यता और कर्तव्य बुद्धि में उन्हें विश्वास होता है। अक्सर मुख्य राजनैतिक दलों के नेता मिल कर दलों के सदस्यों को रख्या के अनुसार सन दलों से अच्छे अच्छे उम्मीदवार ले लेते हैं और इस प्रकार आपस में पैसला कर लेने से बहुत से निर्वाचनक्षेत्रों में चुनाव की नौबत तक नहीं आती है। इस ढंग से बहुत-से ऐसे योग्य और सुचरित्र लोगों की सेवा का लाभ भी देश को मिल जाता है जिन का दलबंदी के झगड़े में चुनाव होना अशक्य होता है। किसी किसी चुनाव में तो नेशनल राय के आवे में अधिक सदस्य बिना चुनाव के झगड़े के चुन लिए जाते हैं। इसी प्रकार 'फेडरल काउंसिल' के सदस्य और दूसरे मुख्य अधिकारी भी सारे मुख्य दलों के योग्य और अच्छे आदमियों में से चुन लिए जाते हैं। सन् १९२७ ई० की ही 'फेडरल काउंसिल' को ले लीजिए। उस में 'गर्म दल' और 'कैथोलिक अनुदाग दल' दो दलों के सदस्य थे।

प्रमुख और चासलर गरम दल के थे। स्ट्रेड राय का अध्यक्ष कैथोलिक अनुदार दल का था और नेशनल राय का अध्यक्ष 'किसान, मज़दूर और मध्यमवर्ग' दल का था।

स्विट्जरलैंड में दलबंदी का बहुत जोर न होने के बहुत से कारण हैं। एक तो करीब पचास वर्ष से वहां कोई राजनीति का ऐसा नुक़ील प्रश्न नहीं उठा है—जैसा कि फ्रांस में 'राजाशाही या प्रजाशाही' का प्रश्न था—जिस पर प्रजा में घोर मतभेद होने के कारण लड़ाके राजनैतिक दल बनते। दूसरे प्रजासत्ता का स्विट्जरलैंड में अखंड राज्य जन्म चुका है और परराष्ट्रनीति या उपनिवेशनीति का वहां कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तीसरे ग्राम लोग खाते पीते होने से और लोगों के आर्थिक जीवन में काफी समता होने से आर्थिक हित-संघर्ष नहीं बढ़ा है और सामाजिक कलह ने वह भयंकर रूप नहीं धारण कर लिया है, जो अइस-अइस के देशों में दीखता है। स्विट्जरलैंड में 'समाजवादी दल' में लोग ईर्ष्या चिढ़, घृणा या भूख के कारण शामिल न हो कर अधिकतर विचारों और विश्वासों के कारण ही शामिल होते हैं और इसी लिए वहां के राजनैतिक जीवन में कड़वाहट पैदा नहीं होती। स्विट्जरलैंड में धार्मिक और संप्रदायिक मतभेद की भी टक्करें नहीं होती हैं, क्योंकि कि मुखलिफ़ कैटनों को, अपनी अपनी आजादी के धार्मिक विचारों के अनुसार, धार्मिक मामलों की व्यवस्था करने की इजाजत है। स्विट्जरलैंड में राजनैतिक नेता भी इतनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ रखनेवाले नहीं होते हैं, जितने दूसरे देशों में होते हैं। न स्विट्जरलैंड के लोग ही किसी नेता पर लट्टू हो कर उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं। अस्तु, विभिन्न नेताओं के पुजारियों की दल-बंदी और झगड़े भी वहां नहीं होते हैं। स्विट्जरलैंड में राजनीति का ग्राम लोग इग्लैंड के बहुत से लोगों की तरह केवल रिलवाड ही नहीं समझते बल्कि उस में गंभीरता और विचार से काम करते हैं। दल के सदस्यों को दल के नेताओं का साथ देने से स्विट्जरलैंड में जाति फायदों का भौका नहीं रहता है, क्योंकि न तो वहां इतनी बहुत सी सरकारी नौकरियां ही होती हैं और न उन में अधिक वेतन ही मिलता है। बड़े-बड़े प्रश्नों का फैसला 'हवाले' और 'प्रस्तावना' द्वारा प्रजा खुद कर सकती है जिस से किसी राजनैतिक दल को व्यवस्थापक सभा या फेडरल काउंसिल में अधिकार जमाने की इतनी इच्छा नहीं रहती है, जितनी दूसरे देशों में क्योंकि किसी एक दल का सरकार पर अधिकार जन्म जाने पर राष्ट्र का कोई बड़ा हानि या लाभ नहीं निर्भर रहता है। अस्तु, करीब पचास वर्ष तक सभ में एक ही दल का सरकार पर असर रहा और दूसरे दलों ने उस दल का जोर तोड़ने का प्रयत्न न करके, हमेशा उस पर कड़ी नज़र रख कर उस की उन बातों को ही नामजूर कराने की कोशिश की, जिन को वह हानिकारक समझते थे। उस दल ने भी कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दूसरे दलों को विरोध के लिए नष्ट उमाड़ा। स्विट्जरलैंड के चारों ओर जबरदस्त सैनिक राष्ट्र होने के कारण भी स्विट्जरलैंड के लोग आपस में फूट करके, अपनी शक्ति कम करने में इच्छुते हैं और उन में एक इस प्रकार की स्वदेश भक्ति पैदा हो गई है, जिस के कारण देश हित के ध्यान से वह छोटी-छोटी बातों पर कलह और राय मचाना पसंद नहीं करते हैं। इन्हीं सब विभिन्न कारणों से स्विट्जरलैंड में राजनैतिक दलबंदी का बहुत जोर नहीं है।

स्विट्ज़रलैंड में दूसरे बहुत से यूरोपीय देशों की तरह बहुत से ऐसे आदमी भी नहीं होते हैं जो सिर्फ राजनीति की ही अपना पेशा बना लेते हैं। राजनीति में भाग लेने-वाले अपना काम धंधा करने के साथ-साथ राजनीति में दिलचस्पी होने के कारण ही राजनीति में भाग लेते हैं, बरना जितना भत्ता व्यवस्थापक-सभा के सदस्य को मिलता है; उस से कहीं अधिक हर सदस्य मूर्जे से किमी और घंटे में कमाने की योग्यता रखता है। किसी वकील, डाक्टर या व्यापारी का राजनीति में नाम और इज्जत हो जाने से घधा भले ही बढ जाय, मगर उस विचार से शर्मद ही कोई स्विट्ज़रलैंड में राजनीति के मैदान में उतरता है। दिलचस्पी, सेवाभाव और प्रजा का सम्मान प्राप्त करने की लालसा ही अधिकतर लोगों को राजनीति के मैदान में लाती है। व्यवस्थापक-सभा में आम तौर सभी वर्गों के लोग होते हैं, मगर अधिकतर पढे लिखे विद्वान, वकील या पुराने सरकारी अफसर होते हैं। सदस्यों को आम लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, बेईमानी या रिश्वत खोरों की शिकायत बिल्कुल ही कम सुनने में आती है। व्यवस्थापक सभा की बैठकें बड़ी सादी होती हैं। इंग्लैंड या फ्रांस की व्यवस्थापक-सभाओं की शान स्विट्ज़रलैंड में देखने को नहीं मिलती, न स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापक-सभा की चर्चाओं में एक दूसरे दल के सदस्यों या फेडरल काँसिल के सदस्यों के खिलाफ उतनी कड़वाहट और आक्षेप सुनने को मिले। सब सदस्य गंभीरता, विचार और शांतिपूर्वक देश के हित से प्रश्नों पर विचार करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की टाँग घसीटने का प्रयत्न कम होता है। स्विट्ज़रलैंड के राजनैतिक जीवन की पवित्रता सचमुच अनुरूपीय है।

स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों की नस नस में स्वाधीनता के भाव भरे रहते हैं। साधारण मजदूर और किसान तक सोचने का प्रयत्न करता है। वह 'अधा बन कर किसी के पीछे नहीं चल पड़ता है। अपने अधिकारों के साथ साथ उस को अपने कर्तव्य का भी ध्यान रहता है। वह दूसरे के विरुद्ध विचारों की इज्जत करना और शांति से बहस और समझौता करना जानता है और जरा-जरा से मतभेद पर लड्ड ले कर दूसरों का सिर तोड डालने को तैयार नहीं हो जाता है। दूसरी और सब बातों में एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न स्विट्ज़रलैंड के लोग भी राजनीति में घुल-मिल कर काम करते हैं। अधिकतर लोगों का पेशा खेती शरी होने से उन में किसानों का पुरातन प्रेम और अनुदारता जरूर होती है। मगर बहुत ज़माने से स्थानिक स्वशासन होने से लोगों में स्वाधीनता, विचारशीलता और कर्तव्यपरायणता के साथ साथ किसी की बातों में न आ कर हर प्रश्न की अच्छाई-बुराई पर विचार करने की आदत हो गई है। स्विट्ज़रलैंड का इतिहास और बहुत से देशों की तरह थोडे से महान् पुरुषों के जीवन की रामरुहानी नहीं है। इस देश का इतिहास इस देश की प्रजा का इतिहास है। स्विट्ज़रलैंड में प्रजा की प्रभुता है, मगर प्रभुता के गर्व ने प्रजा का सिर नहीं फिरा दिया है—जिस का आम तौर पर साधारण मनुष्यों में भय रह सकता है। फ्रांस की तरह स्विट्ज़रलैंड की प्रजा विचारों के उमार से पागल बन जाना भी नहीं जानती है। समाजवाद की हाल में जो स्विट्ज़रलैंड में हवा उठी है, वह अधिकतर जर्मनी से आए हुए मजदूरों की करतूत है। मगर वह भी अभी तक हवा ही रही है। आम आदमियों को स्विट्ज़रलैंड में अपने

देश की राजनीति में अन्य देशों से अधिक दिलचस्पी रहती है, क्योंकि स्थानिक स्वशासन ने उन में राजनैतिक जागृति पैदा कर दी है। आम तौर पर लोग सरकारी सत्ता के नेंद्रीकरण और समाजशाही दोनों के पक्षपाती नहीं हैं, मगर देश को लाभ होता दीखने पर वह दोनों के लिए तैयार हैं। राजनीति में शांत और स्वच्छ जीवन को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक कैंटन को छोड़ कर और कहीं देश भर में पॉली की सज़ा किसी को नहीं दी जाती है। शराबखोरी के विरुद्ध बहुत से लोग होने पर भी, किसी को दुःख न देने के विचार से, शराब पीना 'ग्रंम' रिका की तरह ज़ुर्म नहीं बना दिया गया है। अंगरेजों तक को यह देख कर आश्चर्य होता है कि खालिस प्रजासत्ता की हामी स्विट्ज़रलैंड की प्रजा अपनी कार्यकारिणी पर इतना विश्वास करने को तैयार रहती है कि उस को इंग्लैंड की कार्यकारिणी से भी अधिक सत्ता देती है।

स्विट्ज़रलैंड के आम लोग चतुर और आम तौर पर सच्चे और ईमानदार होते हैं, न तो वे किसी पर जल्दी से विश्वास ही कर लेते हैं और न अविश्वास ही। वे अपने राजनीतियों में गंभीरता, धीरता, दृढ़ता और सचाई देखने की काशिश करते हैं। देश के मशहूर अखबारों में किसान दल के २, समावादी दल के ६, उदार दल के ३, गरमदल के ८, कम्युनिस्ट दल के २, कैथोलिक अनुदार दल के ७ और ४ स्वतन्त्र अखबार हैं। मगर कम्युनिस्ट अखबारों को छोड़ कर और किसी दल के अखबार में दूसरे दलों या उन के नेताओं पर अनुचित आक्षेप नहीं किए जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड के कई अखबारों की राय का तो यूरोप भर में बड़ा मान होता है और वह हर जगह पढ़े जाते हैं। आवादी के लिहाज से यूरोप के और किसी देश में इतने अखबार नहीं हैं, जितने स्विट्ज़रलैंड में। मगर शायद हालैंड और नावें को छोड़ कर और किसी यूरोपीय देश के अखबारों में इतनी गंभीर टीका टिप्पणी नहीं होती है। इस देश के अखबार किसी को डरा कर चौप बसल या किसी पर व्यक्तिगत विचारों से आक्षेप कभी नहीं करते हैं। अस्तु, स्विट्ज़रलैंड की राजनैतिक सस्थाओं का संचालन बड़ी सहूलियत से होता है। इस का मुख्य कारण दलबंदी का न होना और स्थानिक स्वशासन से उत्पन्न हुई प्रजा की जागृति ही है, नहीं तो स्विट्ज़रलैंड की राजनैतिक सस्थाओं से सिर्फ उन के सगठन के कारण यह फल नहीं मिल सकते थे। आम तौर पर सघीय-राजव्यवस्थाओं में सघीय सरकार और सघ की सदस्य सरकारों के अधिकारों का जितना खुलासा किया जाता है उतना स्विट्ज़रलैंड की राजव्यवस्था में खुलासा नहीं किया गया है। बहुत-सी बातों में सघ और कैंटनों को एकसे अधिकार दिए गए हैं और सघ को कैंटनों के कानूनों को राजव्यवस्था के खिलाफ ठहरा देने का भी अधिकार दिया गया है। दूसरे देशों में इस प्रकार की राजव्यवस्था से आए दिन झगड़े हो सकते थे। मगर स्विट्ज़रलैंड में जब सघ या कैंटनों के अधिकार के विषय में शका खड़ी होती है तो आपस में सहूलियत से विचार और समझौता कर के काम निकाल लिया जाता है। हमेशा से इसी प्रकार काम होता आया है। सघ और कैंटनों में हर जगह सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में न दे कर कई आदमियों की समितियों के हाथ में रखी गई

है दूसरे देशों से स्विट्ज़रलैंड की सरकार में यह भी एक और खास फर्क है। स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों को हमेशा प्रजा की कड़ी नज़र में काम करना होता है। यहाँ सब पर जनमत का एक-सा अंकुश रहता है। अस्तु धारा-सभा पर अन्य देशों की तरह रोक-थाम रखने की स्विट्ज़रलैंड की राज-व्यवस्था में योजना नहीं की गई है क्योंकि 'हवाले' और 'प्रस्तावना' के द्वारा प्रजा जब चाहे तब धारा-सभा के फैसलों को उलट-पलट सकती है।

स्विट्ज़रलैंड की सरकार और उस की नीति में आश्चर्यजनक स्थिरता और दृढ़ता देखने में आती है। यहाँ कानून भी वही बनाए जाते हैं जिन को प्रजा चाहती है और जो ग्रामतौर पर लाभदायक होते हैं। शासन बहुत सस्ता है क्योंकि खर्च में बड़ी मितव्ययता की जाती है। हमेशा इस बात का खयाल रखा जाता है कि जो रुपया खर्च होता है उस का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। सब प्रकार की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। न्याय-शासन भी बहुत सीधा और सस्ता है। पहाड़ी प्रदेश होते हुए भी स्विट्ज़रलैंड में सड़को इत्यादि की और दूसरे सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था बड़ी सुंदर है। चुंगियों का काम भी यहाँ शुद्धता और योग्यता से चलता है। स्थानिक-शासन का बहुत-सा काम लोग मुफ्त में करते हैं। देश की रक्षा का भी काफी प्रबंध है। प्रजा हमेशा देश के लिए तलवार बांध कर मैदान में उतर आने को तैयार रहती है। एक दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सब आदर करते हैं। सार्वजनिक जीवन ऊँचे दर्जे का होता है और राजनीति को शतरंज का खेल नहीं समझा जाता है। अस्तु, यह सब स्विट्ज़रलैंड की सरकार की खास खूबिया कही जा सकती है।

स्विट्ज़रलैंड की कई संस्थाएँ दूसरे देशों के लिए आदर्श बन सकती हैं। एक तो सरकार की कार्यकारिणी सत्ता को एक आदमी के हाथ में न रख कर कई आदमियों की कमेटी में रखना, दूसरी हवाला और प्रस्तावना की संस्था। मुमकिन है स्विट्ज़रलैंड में एक दिन दलबंदी का जोर बढ़ जाने पर 'फ़ेडरल कौंसिल' का काम कठिन बन जाय और वह भी दूसरे देशों के मंजि-मंडल की तरह एक दल की समिति हो जाय। फिर भी स्विट्ज़रलैंड की 'फ़ेडरल कौंसिल' के काम-काज से बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है। 'हवाले' और 'प्रस्तावना' के बारे में तो अधिक कहना ही व्यर्थ है। प्रजा के हाथ में सत्ता रखने के लिए इस से बढ़ कर अभी तक दूसरी संस्था दुनिया में देखने में नहीं आई है। छोटे-छोटे ज़मीन के मालिकों और स्थानिक स्वशासन के प्रचार से भी स्विट्ज़रलैंड की सरकार अच्छी बन गई है।

स्विट्ज़रलैंड की सरकार में सब मीठा ही मीठा नहीं है। दोष भी हैं; मगर दूसरे देशों की सरकारों के वैसे ही दोषों के सामने स्विट्ज़रलैंड की सरकार के दोष बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। एक मनोरंजक उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी। राजनीति का प्रख्यात लेखक लार्ड ब्राइस एक स्थान पर लिखता है कि, "एकबार मैं ने स्विट्ज़रलैंड के एक सच्चे विद्वान् से पूछा, 'आप के देश की सरकार में दोष भी अवश्य ही होंगे। क्या आप मुझे दोष बताने की कृपा करेंगे?' कुछ विचार के बाद वह विद्वान् बोला— 'हमारे देश में आप के देश के शाही कमिशनरों और पार्लियमेंट की कमेटियों की तरह बहुत

से कठिन प्रश्नों पर विचार कर के अपना मत देने के लिए कमेटियां नियुक्त की जाती हैं। यह कमेटियां अक्सर गर्मियों में पहाड़ पर किसी सुंदर होटल में जा बैठती हैं और वहां बैठ कर अपना काम करती हैं। ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं होता है। फिर भी हम लोग समझते हैं कि यह कमेटियां सार्वजनिक खर्चों पर ज़रूरत से अधिक दिन तक मजे उड़ाती हैं। यह निंदनीय बात है।”

लार्ड ग्राइस लिखता है कि, “मैंने आश्चर्य-चकित हो कर उस विद्वान् से कहा कि, ‘जनाब, अगर मज़ाक नहीं कर रहे हैं और अपनी सरकार का काला से काला काम आप इसी को कह सकते हैं तो मैं आप के देश को मस्तक नवाता हूं और आप धन्य हैं जो उस में पैदा हुए।’ चाहे और कितने ही दोष स्विट्ज़रलैंड की सरकार में हों मगर उस का एक सय से बड़ा गुण उस को संसार की आंखों में ऊँचा उठाने के लिए काफी है। स्विट्ज़रलैंड ने यह बात प्रत्यक्ष कर के दिखला दी है कि, ‘प्रजा अपना शासन अपने हित



# सोवियट सरकार

## राज-व्यवस्था

प्रजासत्ता की रान स्विट्जरलैंड की सरकार का परिचय हो जाने के बाद हम अब एक ऐसे दूसरे देश की सरकार का परिचय देते हैं जहाँ प्रजा-सत्ता कायम करने का एक नया ही रास्ता निकाला गया है। बोल्शेविज्म के भूत को खड़ा करनेवाले रूस के बारे में आप ने तरह तरह की बातें सुनी होंगी। चारों ओर उस की चर्चा सुनाई देती है। यह देश यूरोप से ले कर एशिया तक, दोनों महाद्वीपों में दुनिया के लगभग सातवें हिस्से पर फैला हुआ है। ठंडे से ठंडे और गर्म से गर्म, खुरखेड़ और बजर सब तरह के भाग और नाना प्रकार की भाषा, संस्कृत और धर्मवाली जातियाँ इस विशाल देश में मिलती हैं। हमारे देश की विभिन्नताएँ और भेद इस देश की विभिन्नताओं और भेदों के मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। यूरोप और एशिया की दुनियाओं के बीच में रूस की अपनी एक अलग दुनिया है। इस देश में पहले निरी निरंकुश राज शाही थी। मास्को की नवाबी ने, अपनी तलवार के जोर से मंगोलों को रूस से निकाल कर, अपना अधिकार, हमारी शेखचिह्नी की कहानियों के परियों के पहाड़ कोह काफ और यूराल पर्वत तक, जमा लिया था। चौदहवीं सदी से बीसवीं सदी तक, छ सौ वर्ष तक, मास्को के जारों का निरंकुश राज्य रूस पर रहा। इस बीच में प्रतिनिधि शासन चलाने के कई बार प्रयत्न हुए। पहले-पहल जार आइवन चतुर्थ ने सोलहवीं सदी में ज़ेमस्को सोबोर नाम की एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि व्यवस्थापक सभा बुलाई थी। इस में प्रजा के प्रतिनिधि नहीं अमीर उमराव ही अधिक होते थे। मगर सत्रहवीं सदी में जार पीटर महान ने ज़ेमस्को सोबोर को बदल दिया। अठारहवीं सदी में कैथरीन द्वितीय ने १६४ प्रतिनिधियों का क़ानून बनाने के लिए 'मांड

कमीशन' बनाया था। मगर वह कोई व्यवस्थापक-सभा नहीं थी और उस का काम पूरा होने से पहले ही उस को बंद कर दिया गया। बाद में ऐलेक्जेंडर द्वितीय ने उन्नीसवीं सदी में एक व्यवस्थापक-सभा कायम करने का इरादा जाहिर किया था। मगर उस राज व्यवस्था का एलान निकालने के निश्चित समय से २४ घंटे पहले ही उस का खून कर डाला गया। सिर्फ स्थानिक शासन में जो कुछ प्रतिनिधित्व था वह भी। केथरीन द्वितीय ने प्रतिनिधियों की हूमा अर्थात् चुगियों को कायम किया था जिन में सब वर्गों के प्रतिनिधि होते थे। ऐलेक्जेंडर द्वितीय ने न्याय शासन को ठीक किया और चुगी शासन को मजबूत किया था और जिले और प्रांत में जेमस्टवोज नाम की प्रतिनिधि-सभाओं की स्थापना की थी जिन को कानून बनाने और आय-व्यय के काफी अधिकार थे। राक़ी सभी प्रकार से बीसवीं सदी के प्रारंभ तक रूस में निरंकुश जारशाही ही थी।

मगर जारशाही पर चारों तरफ से हमले हो चले थे। सरकार का व्यापारियों की तरफ झुकाव होने से ज़मींदार और किसानों का दिल सरकार की तरफ से हट गया था। जेमस्टवोजें भी जहा तहा सरकार में सुधार और राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की माँगें कर रही थीं। उद्योग धंधों में काम करनेवाले मजदूर समाजवाद की तरफ जा रहे थे। सन् १८६८ ई० में उन का दूसरे पश्चिमी देशों की तरह एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक मजदूरदल' भी कायम हो गया। मध्यम श्रेणी के पढ़े लिखे लोग और उद्योग धंधों से सबंध रखनेवाले लोग भी यूरोप के दूसरे प्रजासत्तात्मक देशों की तरह रूस की सरकार का सगठन चाहते थे और इस प्रकार के कुछ लोगों ने मिल कर 'मुक्तिकारी सब' नाम का एक राजनैतिक दल भी बना लिया था। रूसी सरकार के अधीन फिनलैंड और पोलैंड इत्यादि जैसे देशों के गैर रूसी लोग भी अपना किसी प्रकार रूस की सरकार से पिंड छुड़ा लेना चाहते थे।

रूस और जापान के युद्ध में पुराने महारथी रूस के जब नए जापान ने दाँत खट्टे कर दिए, तब एशिया की दनी हुई जातियों के मन ही में आनंद और आशा की हिलोर नहीं आई थी बल्कि रूस की सीमा के अंदर रहनेवाले रूसी सरकार के सारे विरोधियों के घरों में भी अपनी सरकार की कमज़ोरी जान कर ज़रन होने लगा था। सारी जेमस्टवोजों और हूमाओं के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन ने इस मौके को अच्छा समझ कर जार से एक अर्ज़ी में एक व्यवस्थापक सम्मेलन बुलाने और एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा स्थापित करने की प्रार्थना की थी। सरकार के टाल मटोल करने पर देश में उत्साह और दमे पड़े होने लगे। अस्तु सन् १९०५ ई० में रूस की सरकार ने एक शाही हूमा<sup>१</sup> नाम की राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा स्थापित कर दी थी, जिस की बिना अनुमति के कोई कानून अमल में नहीं आ सकता था। सब बालिग मर्दों को मतधिकार दे दिया गया था।

मगर कठिनाइयों से सरकार के हाथ खाली होते ही रूस की सरकार ने फिर रंग बदला। सुधार और प्रतिनिधि सरकार के पक्षपातियों के, बहुत से दल बन जाने और आपस के मतभेदों और झगड़ों के कारण शक्ति कम हो गई थी। बड़े बड़े ज़मींदारों और

और उल्टी बुद्धिवालों ने पुरानी ढंग की सरकार के लिए हाय-हाय मचा दी थी। अस्तु; सरकार ने १९०६ ई० ही में 'शाही डूमा' को व्यवस्थापक-सभा की निचली सभा का स्थान दे दिया और उस के साथ 'साम्राज्य कौंसिल' नाम की एक दूसरी सभा को जोड़ दिया जिस के आधे सदस्य जार स्वयं नियुक्त करता था और आधे अप्रत्यक्ष ढंग से कुछ खास वर्ग चुनते थे। साम्राज्य के मूल कानूनों, चांससमाजों के संगठन, सेना और परराष्ट्र विषय पर व्यवस्थापक-सभा के चर्चा करने की मनाही कर दी गई। पहली डूमा के बैठने पर जय उस ने व्यवस्थापकी सरकार कायम करने के इरादे से कुछ प्रश्न उठाए तो फौरन उस को भंग कर दिया गया। नए चुनाव के बाद दूसरी डूमा का भी वही हाल हुआ। तीसरा चुनाव होने से पहले सरकार ने बहुत से लोगों से मताधिकार छीन लिए और चुनाव में दिन-बढ़ाड़े दस्तंदाजी कर के सरकार के विद्वुओं को चुनवा लिया। अतएव तीसरी डूमा सरकार की तरफदार थी। यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने पर चौथी डूमा चल रही थी और रूस में निरंकुश जारशाही और नौकरशाही का राज्य कायम था।

लड़ाई छिड़ने पर 'समाजी प्रजासत्तावादियों' को छोड़ कर अन्य सब राजनैतिक-दलों ने रूस में सरकार का साथ देने का निश्चय किया था। मगर जार निरा-बेयकूफ था। वह अपनी स्त्री की उँगलियों पर नाचता था और उस की स्त्री रासपुटिन नाम के एक भयंकर मुल्ले के इशारों पर काम करती थी। मंत्री और सरकार के दूसरे दरबारी सलाह-कार भी बेयकूफ, उल्टी बुद्धि के और बेईमान थे। यहा तक कि वे रूस के दुश्मनों से रूस के खिलाफ पड़्यून रच कर अपनी जेबें भर रहे थे। अतीजा यह हुआ कि लड़ाई के पहले ही वर्ष में सरकार के निकम्मे इंतजाम और जानी-बूझी लापरवाही से रूस के असंख्य सैनिक लड़ाई के मैदान में खप गए, देश के हर भाग में प्रजा संकट में पड़ गई और पोलैंड पर जर्मनी ने कब्जा जमा लिया। राजनैतिक दलों ने यह भयंकर हालत देख कर जार से फौरन सरकार में सुधार करने की माँग की। मगर सरकार ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार किसी की कोई बात सुनना पसंद नहीं किया। उल्टा सब प्रकार की माँग करनेवालों को कुचल डालने का निश्चय कर लिया।

सरकार की इस अंधी जिद्द का परिणाम वही हुआ जो सार्वजनिक आंदोलन के खिलाफ सरकार की दृढ़ का परिणाम हमेशा से इतिहास में होता चला आया है। मन् १९१७ ई० की फरवरी में शाही डूमा की बैठक हुई। सरकार ने डूमा की माँगों के उत्तर में दो हफ्ते बाद डूमा की बैठक स्थगित करने का एलान कर दिया। डूमा ने अन्तर् बैठक बंद करने से इन्कार कर दिया और अपने आप को देश की सर्वोपरि और एकमात्र व्यवस्थापक-सभा एलान कर दिया। विद्रोह की आग भड़क कर राजधानी की रैन्ना और मजदूरों में फैल गई। डूमा के नेता अधिकतर उद्योग-धंधों के लोग थे। वे मजदूरों और सैनिकों को उनके विरुद्ध थे और सरकार में सुधार कर के आनेवाली क्रांति को रोक देना चाहते थे। मगर सरकार किसी की क्यों सुनती है! आति की स्वास्तर चले लख पैल गई। रूस के सैनिक भी क्रांतिकारियों से जा मिले जेलखाने टोड़ डाले नद और हैरिने से ले के दिया गया। सरकारी अफसर जहाँ हाथ नै पड़े नद डाले नद सा दंड डाले

दिए गए। लड़ाई के मैदान से रूसी सेना ने निकम्मी जारशाही के अंत पर बधाई का संदेश भेजा। जारशाही का किला प्रजा के रोष की आँधी में बालू के महल की तरह देखते देखते उड़ गया। जार ने अपने खानदान का राज बचाने के विचार से खुद राजगद्दी से उतर कर राजगद्दी अपने भाई ग्राइज़्यूक माइकेल को दे दी। मगर माइकेल ने प्रजा की खुली प्रार्थना के बिना राजगद्दी पर बैठने से इन्कार कर दिया। झूमा के चुने हुए और झूमा के प्रति जवाबदार मन्त्रि मंडल की, वैध प्रजासत्तावादी शाहजादा ल्योव की अध्यक्षता में, एक अस्थायी सरकार कायम हो गई और माइकेल ने देश से इसी सरकार को सहायता करने की प्रार्थना की। जार को मय उस के बाल उन्चों के बुरी तरह घाद में फँस कर दिया गया और जारशाही और जार के चक्रवर्ती राज्य की हमेशा के लिए दुनिया से जड़ खोद कर फेंक दी गई। क्रांति की लहलुहान की दुःखप्रद कहानी से हमारे इस ग्रंथ का अधिक संबंध नहीं है। दुनिया को हिला डालनेवाले क्रांति के दस दिनों में रूस की दुनिया ही उलट गई थी। मगर नई राज व्यवस्था को समझने के लिए उन दलों के सिद्धांतों और कुछ हाल को जान लेना जरूरी है जिन की नई राज-व्यवस्था के गढ़ने में हाथ था।

अस्थायी सरकार अधिकतर मध्यमश्रेणी के लोगों की सरकार थी। वह यूरोप के अन्य देशों की तरह रूस की सरकार की भी व्यवस्था करना चाहती थी। मगर मजदूरों और सेनिकों में समाजवादी विचार फैल चुके थे और वे 'मजदूरों, किसानों और सेनिकों' की सरकार चाहते थे। समाजवादियों में भी दो दल थे। एक 'समाजी क्रांतिकारी' कहलाता था और दूसरा 'प्रजासमाजी प्रजासत्तात्मक दल'<sup>१</sup> कहलाता था। 'समाजी क्रांतिकारी दल' ज़मींदारी को नष्ट कर के जमीन पर छोटे छोटे किसानों का क़ब्ज़ा और सरकार के सिद्धांतों पर इपि का हामी था। इस में अधिकतर किसान लोग थे। 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' शहरों के मजदूरों का दल था और वह यूरोप के दूसरे समाजवादी दलों की तरह मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार वर्ग संघर्ष का माननेवाला था। दोनों दलों में गरम और नरम लोग थे। 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' में नरम लोग 'मेशेनिकी' और गरम लोग 'बोर्जोविकी' कहलाते थे। मेशेनिकी लोगों का विचार था कि समाजशाही धीरे धीरे ही स्थापित हो सकती है और उस के उगाने के लिए दूसरे प्रगतिशील दलों से मिलकर चाना चाहिए। बोर्जोविकी कम्युनिस्ट थे अर्थात् एक दम क्रांति कर के समाजशाही स्थापित कर देने के पक्षपाती थे।

'बोर्जोविकी' का रूसी भाषा में वास्तव में अर्थ 'बहुसंख्या' है और 'मेशेनिकी' का अर्थ 'अल्प संख्या' है। शुरू से समाजवादियों में मेशेनिकी विचार के ही लोग हमेशा अधिक संख्या में थे। और मजदूरों की सोचिए<sup>२</sup> तक में कम्युनिस्टों का बहुत कम असर

<sup>१</sup> इन दलों का पूरा हाल आगे बताया जायगा।

<sup>२</sup> रूस देश में सोवियट मजदूरों, किसानों और सेनिकों इत्यादि की संघों अर्थात् पचायतों को कहते हैं।

था। मगर कम्यूनिस्ट समूह के नेता लेनिन और ट्रोत्स्की बड़े होशियार थे। अस्थायी सरकार में भाग न लेने से उन के लिए पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। अस्तु, उन्होंने एक बड़ा जुमाने वाला कार्यक्रम जनता के सामने रख कर बाद में प्रजा के दिल और दिमाग पर शीघ्र ही कब्जा जमा लिया था। उन के कार्यक्रम में फौरन् लड़ाई बढ़ कर के 'मजदूरों और किसानों' के प्रतिनिधियों के द्वारा सधि करना, राष्ट्रीय क्रजों को साफ नामजूर करना, जमींदारों से जमीन छीन कर उस पर किसानों की पचायतों का अधिकार करना, कारखानों और खानों पर फौरन् मजदूरों की पंचायतों का कब्जा करना, सारे हजारों पर राष्ट्र का कब्जा, सारी पैदावार और रैश्वर्य पर सरकार का नियन्त्रण और एकमात्र उद्योगीवर्ग या मजदूरपेशा लोगों की पचायतों के हाथ में सरकार की लगाम इत्यादि की ऐसी बात थीं, जो रूस के लड़ाई, गरीबी, निरकुशता और कुशासन से थके हुए आम लोगों को जुमाने वाली थीं। बोलशेविकों ने धीरे धीरे बड़ी होशियारी से इस कार्यक्रम का प्रचार कर के सोवियटों पर अपना अधिकार जमा लिया था। नवंबर सन् १९०७ ई० में तीसरी सोवियटों की कांग्रेस में बोलशेविकी विचारवालों को मेशेविकी विचारवालों से सात सौ अधिक मत मिले और उन्होंने ने सभी से वे बोलशेविकी अर्थात् बहुसंख्या और दूसरा दल मेशेविकी अर्थात् अल्पसंख्या कहलाने लगा। जुनाय की रात को ही बोलशेविकों ने 'अस्थायी सरकार' पर अपना अधिकार कर लिया। उन की लाल पलटन ने जा कर सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अस्थायी सरकार के सदस्यों को कैद कर लिया। सरकार का प्रधान कैरेंसकी किसी तरह बच कर भाग गया। दूसरे दिन की 'तीसरी अगिल रूसी सोवियट कांग्रेस' में रूस में 'रूसी समाजशाही संधीय सोवियट प्रजातन्त्र' स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी गई और सरकार का सारा काम काज प्रजा के नियुक्त किए हुए कमिश्नरों की एक समिति के हाथ में सौंप दिया गया। लेनिन इस समिति का प्रधानमंत्री और ट्रोत्स्की परराष्ट्र-विभाग का कमिश्नर बनाया गया था। बोलशेविकों ने दृढ़नीति और डंडे के जोर से 'अस्थायी सरकार' पर अपना अधिकार कर लिया था। पहली अस्थायी सरकार ने रूस की नई राज व्यवस्था बनाने के लिए सारे रूस के प्रतिनिधियों का एक व्यवस्थापक सम्मेलन बुलाया। मगर इस सम्मेलन को तारीख के पहले ही बोलशेविकों ने अपना अधिकार जमा लिया और सम्मेलन मिलने पर उस में बहुसंख्या अपने पक्ष में न देख कर लेनिन ने उसे भग कर दिया था।

बोलशेविकों अर्थात् कम्यूनिस्टों का जिन को हिंदी में समष्टिवादी कहना उचित होगा, विश्वास है कि "जहां समाजशाही कायम करने का प्रयत्न किया जायगा वहां तलवार के जोर से अधिकार प्राप्त कर के मजदूर पेशा लोगों का एकमात्र निरकुश अधिकार कायम करने की जरूरत होगी।" उन का खयाल है कि आजकल की पूँजीशाही देशों की सरकारें प्रजासत्ता की दुहाई देती हैं। मगर सिर्फ़ अमीर वर्ग के हितों का खयाल रखती हैं। प्रजा भुलावे में पड़ी रहती है कि सत्ता उस के हाथ में है और वास्तव में सत्ता जमींदारों और कारखानों और बैंकों के मालिकों के हाथ में रहती है। पैदावार के जरियों पर इन लोगों का अधिकार होने से यह लोग मजदूर पेशा की कमाई को अर्थात् उन की ज़िंदगी

को ही अपने हाथ में रखते हैं। शिक्षा इत्यादि पर उन का विलुप्त इजारा न होने पर धन-संपत्ति के कारण उन को साधारण प्रजा के मुक्ताबले में शिक्षा का भी अधिक सुभीता और मौका रहता है। धनवान वर्ग की हुक्म चलाने की आदत, उन की विद्वत्ता और उन के रहन-सहन को देखकर साधारण मजदूर पेशा लोग चौंधिया जाते हैं। धनवान लोगों के हाथों में स्थूल होने से यह वर्ग उन में जीवन, समाज और धन धाम के सन्ध में अपने विचारों का प्रचार करके साधारण लोगों के दिमाग में बचपन ही से उन विचारों को भर देता है। सरकार का काम-काज चलायेवाला अधिकारी वर्ग भी आमतौर पर इसी वर्ग का होता है। अखबारों पर भी पूँजीपतियों का कब्जा होने से अखबार अधिकतर धनवानों के हित की ही बातें करते हैं और खबरों को तोड़ और विचारों को मोड़ कर साधारण आदमियों के विचार खराब करते और उन की राजनैतिक राय का रूप बदल देते हैं। अस्तु प्रजासत्ता में सर्वसाधारण को मताधिकार होने पर भी बहुसंख्या की राय को धनवान वर्ग ही जैसा चाहता है वैसा नचाता है।”

अपने इस विश्वास के कारण समष्टिवादी, पूँजीशाही राष्ट्रों की प्रजासत्तात्मक संस्थाओं के द्वारा, समाजशाही की स्थापना करना मृगवृष्णा के समान मानते हैं। वह मानते हैं कि प्रजा की बहुसंख्या के हाथ में सत्ता उसी हालत में आ सकती है अर्थात् प्रजासत्ता उसी समय क़ायम हो सकती है, जब कि पैदावार के जरियों पर मजदूर और किसानों का, जिन की हर जगह बहु-संख्या होती है, कब्जा हो जाय। अतएव वह धनवानों के हाथ से लड़ कर ज़बरदस्ती पैदावार के जरियों<sup>१</sup> को छीन लेना और उन पर मजदूर पेशा का कब्जा जमा कर निरकुश मजदूर पेशाशाही<sup>२</sup> क़ायम करना और धनवान वर्ग को मजदूर पेशावर्ग का जाति बैरी मान कर उन को कुछ भी अधिकार और सत्ता में हिस्सा न दे कर तब तक कुचलते चले जाना ही प्रजासत्ता स्थापित करने का एकमात्र जरिया मानते हैं जब तक कि पूँजीशाही विलुप्त नेस्तनाबूद हो कर मिट्टी में न मिल जाय और एक सिर्फ हाथ पैर या दिमाग से मिहनत कर के रोटी कमाने वाला मजदूर पेशावर्ग ही दुनिया में न रह जाय। समष्टिवादी यह भी मानते हैं कि मजदूर पेशाशाही कायम करने और पूँजीशाही को ध्वंस करने के लिए तलवार का या आजकल की भाषा में बंदूक और बंदूक का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा, क्योंकि धनवान वर्ग आखिर दम तक अपने अधिकार के लिए जी तोड़ कर लड़ेगा और अपनी सेना और हथियारों का मजदूर पेशावर्ग के खिलाफ उपयोग करेगा। बोल्शेविक रूस का प्रख्यात लेखक बुखारिन अपनी ‘समष्टिवाद की वर्णमाला’<sup>३</sup> नाम की पुस्तक में साफ साफ लिखता है कि “आजकल का समाज ऐसे दो वर्गों का बना है जिन के हित एक दूसरे के विरुद्ध हैं—धनवान और मजदूर पेशावर्ग। अगर भेड़िये और भैंसे मिल कर रह सकते हैं, तो यह दोनों वर्ग भी मिल कर रह सकते हैं।

<sup>१</sup> कारखाने, बैंक और ज़मीन।

<sup>२</sup> डिक्टेटोरशिप अथ दि प्रोलिटेरियट।

<sup>३</sup> ‘पृ० बी० सी अन्व् कम्प्यूनिज़्म’।

मेड़ियों को मेड़े हड़पने में मज्जा आता है इस लिए मेड़ों को अपनी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। मेड़ियों और मेड़ों के मेल का स्वप्न देखना मूर्खता है। यह दोनों वर्ग कभी एक न होंगे।

इस प्रकार के सिद्धांत और विचार रखने वाले लेनिन के 'समष्टिवादी दल' के हाथ में रूस की सरकार आ जाने पर स्वभावतः उन के नेतृत्व में रूस की जो नई राज-व्यवस्था बाद में तैयार की गई वह वर्गयुद्ध के विचार अर्थात् मेड़ियों की जाति को नष्ट करने के विचार से बनाई गई है। प्रजासत्ता के सिद्धांत के अनुसार सब नागरिकों को एक से अधिकार न दे कर इस राज-व्यवस्था में सिर्फ मजदूर-पेशा वर्ग के अधिकार माने गए हैं। सब नागरिकों के एक से अधिकार होने का एलान भी है, इस राज-व्यवस्था में ज़रूर, मगर वह सिर्फ जाति और राष्ट्रीय भेदों को न मानने के लिए है। नागरिकता के अधिकार अर्थात् चुनावों में मत देने और चुनाव में उम्मीदवार होने और पदों पर नियुक्त होने का अधिकार सिर्फ समाज को लाभकारी मजदूरों या पेशों के द्वारा रोटी कमाने वालों, इस प्रकार के मजदूर पेशा लोगों की घर-गृहस्थी ठीक रख कर उन के काम में मदद करने वालों, किसान और खेती-बारी का काम करनेवाले उन लोगों को जो नफा पैदा करने के लिए मजदूर नहीं रखते हैं, रूस सरकार की जल और रेल सेना में काम करने वालों और इन्हीं श्रेणियों के उन लोगों को, जो किसी तरह मेहनत करने के नाकाबिल हो गए हों, उन्हीं को दिया गया है। इन श्रेणियों के परदेशी लोगों को भी रूस में मेहनत मजदूरी करने पर यही अधिकार होते हैं। मगर जो लोग मजदूरों को रख कर मुनाफ़ा पैदा करते हैं, या जो सूत और किराए पर गुज़र करते हैं, या जो व्यापारी, सौदागर और दलाल होते, या धंधू और पुजारी होते हैं अथवा जो ज़ार की पुरानी पुलिस के नौकर या आयुर्वेद थे, उन लोगों को कोई मताधिकार राज-व्यवस्था में नहीं दिया गया है। अस्तु, पुराने धनिक-वर्ग और मध्यम-वर्ग को रूस की राज-व्यवस्था में कोई राजनैतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं।

दसवीं जुलाई सन् १९१८ ई० के 'पाँचवीं अखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेस' में जो रूस की 'अस्थायी राज-व्यवस्था' मंज़ूर हुई थी उस के पहले अध्याय में रूस को 'मजदूरों, सेनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियटों का प्रजातंत्र' और इन्हीं सोवियटों में राष्ट्र की सारी केंद्रीय और स्थानिक सत्ता होने तथा रूसी सोवियट प्रजातंत्र को बराबर की हैसियत की आज़ाद क्रौमों के राष्ट्रीय सोवियट प्रजातंत्रों की एक संघ एलान किया गया था। दूसरे अध्याय में मेड़ियों की जाति को ध्वंस कर के संसार में समाजशाही की ध्वजा पहराने के इरादे को पूरा करने के लिए राष्ट्र की ज़मीन, जंगलों, खानों, रेलों, बैंकों और तमाम पैदावार और वटाव के ज़रियो पर मजदूर पेशा लोगों की सोवियट सरकार का बिना मुआवज़े के कब्ज़ा हो जाने का एलान था। 'दूसरे देशों की पूंजीशाही को धक्का पहुँचाने के लिए ज़ारशाही ने रूस के नाम पर जो कर्ज़ दूसरे देशों से लिए थे उन को भी इस अध्याय में नामंजूर किया गया था। इसी अध्याय में 'समाज को उपयोगी काम-धंधा करना' सब नागरिकों का कर्ज़ तथा मजदूर पेशाशाही की अखंड सत्ता

क्रायम करने और धनिकवर्ग के हमलों से उस की रक्षा करने के लिए सब मजदूर और किसानों का हथियार बाँधना पर्ज माना गया था और धनिकवर्ग को हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। 'मजदूर और किसानों की एक समाजवादी लाल पल्टन' क्रायम करने की योजना भी इस अध्याय में रखी गई थी। तीसरे अध्याय में, 'सत्तार को पूजीशाही के उन झगड़ों और लड़ाइयों से सदा के लिए मुक्त करने के विचार से, जिन्होंने पृथ्वी को मनुष्य के खून से लाल कर दिया है', ज़ारशाही को सारी गुप्त संधियों का भंडाफोड़ कर के ख़द माना गया था और दुनिया के सारे राष्ट्रों से वसंतरी की संधियाँ और मैत्री करने के इरादे का एलान था। एशिया और दूसरे उपनिवेशों के मजदूर पेशा वर्ग पर यूरोप की पूजीशाही के राज का विरोध किया गया था और फिनलैंड इत्यादि रूसी साम्राज्य के अधीन देशों की स्वाधीनता का एलान किया गया था। चौथे अध्याय में धनिकवर्ग को ध्वंस करने के उद्देश्य से, मजदूर पेशा वर्ग की रूस में उन पर चढ़ाई के समय, सोवियट सरकार की सारी सत्ता सिर्फ मजदूर पेशा वर्ग की सच्ची प्रतिनिधि-संस्थाओं—मजदूरों, सेनिकों और किसानों की सोवियटों के ही हाथ में रखने तथा रूस के अंदर रहनेवाली सारी विभिन्न जातियाँ की, स्वतन्त्रता और स्वेच्छा की इज्जत पर, एक सच्ची और ठिकाऊ सभ बनाने के उद्देश्य से, रूस के 'सोवियट प्रजातन्त्रों की सभ' के सिर्फ मूल सिद्धांतों को रचने और विभिन्न जातियों के इस सभ में शरीक होने की शर्तों का निश्चय उन जातियों की 'मजदूर और किसानों की सोवियटों को कामेसों' पर छोड़ देने के निश्चय का एलान था। पाँचवें अध्याय में, सोवियट राज व्यवस्था के मूल सिद्धांत और पहले चार अध्यायों की तरह बहुत सी ग्राम प्रचार के मतलब की बातें थी। खास बातों में एक तो रूस की विभिन्न जातियों को अपनी 'स्थानिक सोवियटों की कामेसों और उन 'कामेसों की कार्यकारिणी' की सरकारें क्रायम करने का अधिकार माना गया था। दूसरे रूसी समाजशाही सघीय 'सोवियट प्रजातन्त्र' की सारी सत्ता 'अखिल रूसी सोवियटों की कामेस' और कामेस की बैठकों के बीच में, 'अखिल रूसी सोवियटों की कामेस की केंद्रीय कार्यवाहक समिति' में मानी गई थी। मजदूर और किसानों को ग्रखनारों, रितालों और नितालो द्वारा स्वतन्त्रता से अपने विचार प्रकट करने के लिए सरकार की तरफ से प्रेस और छापने का सामान मुफ्त देने और उन की सभाओं के लिए सारे सभा करने लायक स्थान, मेज़, कुर्तियाँ, रोशनी और गर्मी का इतज़ाम कर देने की भी योजना कर दी गई थी।

इस 'अस्थायी राज व्यवस्था' के सिद्धांतों और स्वरूप पर, रूस देश के विभिन्न भागों की सोवियटों की कामेसों में विचार हो जाने के बाद, ३० दिसंबर सन् १९२२ ई० को मोस्को में ट्रान्स्-काकेशिया प्रजातन्त्र, सुकरेन प्रजातन्त्र और रूसी समाजशाही सघीय-सोवियट प्रजातन्त्र की सभ की कामेस की बैठक में सब सोवियट प्रजातन्त्रों की एक 'समाज-शाही सोवियट प्रजातन्त्रों की सभ' क्रायम करने का निश्चय कर के एलान किया गया था कि, 'सोवियट प्रजातन्त्रों के क्रायम होने के समय से दुनिया, पूजीशाही और समाजशाही की, दो दुनियाओं में बँट गई है। पूजीशाही की दुनिया में राष्ट्रीय असमानता और



वैर-भाव, उपनिवेशों की गुलामी, राष्ट्रीय अत्याचार और लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, समाजशाही की दुनिया में एक-दूसरे का विश्वास और शांति, राष्ट्रीय स्वाधीनता और समानता और विभिन्न जातियों के भ्रातृभाव से आपस में मिल कर शांति से रहने का दृश्य मिलता है। पूंजीशाही दुनिया को अपनी आर्थिक लूट की पद्धति को जारी रखते हुए मुक्तलिप्त जातियों की स्वाधीनता का प्रश्न मुलस्काना असंभव हो गया है। और विभिन्न राष्ट्रों का वैर-भाव इतना बढ़ गया है कि पूंजीशाही दुनिया की हस्ती खतरे में है। निम्न सोवियट सरकारों में, मजदूरपेशा-शाही की पद्धति पर, जिस से राष्ट्रीय अत्याचारों की जड़ ही फट जाती है। विभिन्न जातियों में परस्पर विश्वास और भ्रातृ-भाव कायम करना मुमकिन साबित हुआ है। इस भ्रातृ-भाव और परस्पर विश्वास के कारण ही सोवियट प्रजातंत्र आज तक, भीतरी और बाहरी साम्राज्यशाही हमलों की टक्करों को सहते हुए, गृह-युद्ध को मिटा कर अपनी हस्ती कायम रख और शान्तिमय आर्थिक रचना प्रारंभ कर सके हैं। मगर यूरोपीय युद्ध के बाद की विगड़ी हुई दशा<sup>१</sup> फिर से बनाने के लिए विभिन्न प्रजातंत्रों के अलग अलग प्रयत्न काफी न होने और बाहरी पूंजीशाही हमलों का मिल कर मुकाबला करने और मजदूरपेशा-वर्ग का खानदान दुनिया भर में फैला होने से, सारे सोवियट प्रजातंत्रों के मजदूरपेशा लोग एक समाजशाही खानदान में मिल जाने के लिए मजबूर होते हैं। अस्तु; सारे सोवियट प्रजातंत्र मिल कर एक 'संयुक्त समाज शाही सोवियट संघ' नाम का राष्ट्र बनाते हैं जिस से बाहरी और भीतरी उन्नति के साथ ही विभिन्न जातियों को अपने राष्ट्रीय विकास की स्वतंत्रता भी रहे। समाजशाही प्रजातंत्रों की यह संघ सच सदस्यों की मज्जा से बनती है। इस संघ के सब सदस्य बराबर हैं और हर एक सदस्य को जब चाहे तब, संघ से अलग हो जाने और दूसरे समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों को इस संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता है।

इस एलान या प्रस्तावना के बाद 'समाजशाही' 'सोवियट प्रजातंत्रों की संघ' की जो राज-व्यवस्था बनी उस को ग्यारह अध्यायों में बाँटा गया है। पहले अध्याय में संघ की 'सर्वोपरि अधिकार संस्थाओं' के अधिकार-क्षेत्र का वर्णन है। दूसरे अध्याय में 'संयुक्त प्रजातंत्रों' और 'संघ' के नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं। तीसरे अध्याय में 'संघ की सोवियटों की कांग्रेस' का संगठन, सत्ता और काम, चौथे अध्याय में 'संघ की केंद्रीय कार्य-वाहक समिति' का संगठन, सत्ता और काम का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में 'कार्यवाहक समिति' के 'प्रेसीडियम' और छठे में संघ की 'जनपंचायतों की दलित'<sup>२</sup> की योजना है। सातवें अध्याय में संघ की अदालत, आठवें अध्याय में 'जनपंचायतों'<sup>३</sup> नवें में 'संयुक्त

<sup>१</sup> लड़ाई में हज़ारों आदमी काम या घने और चड़े जंगल में बहुरंग्य खेत बहार हो गए और कारखाने इत्यादि बंद हो गए थे। सारा देश का आर्थिक जीवन ही टूट-पुलट हो गया था।

<sup>२</sup> काउंसिल आफ दि पीपुल कमीसरीज़।

<sup>३</sup> पीपुल्स कमोसरीज़ ऑफ़ युनाइटेड स्टेट्स सोवियटियन रियाइमैंट।

राज्य राजनैतिक विभाग', दसवें अध्याय में 'समुक्त प्रजातन्त्रों' और ग्यारहवें अध्याय में सघ के चिह्न, झंडे और राजधानी का जिक्र है।

सघीय सरकार की अधिकार सीमा में परराष्ट्रों से सघ, सघ की सीमाओं में फेर पार नए प्रजातन्त्रों का सघ में दाखिला, युद्ध और सधि, परदेशों से कर्ज लेना, अंतर-राष्ट्रीय सधियों को मंजूर करना, देश के भीतर और बाहर के व्यापार का नियन्त्रण, डाक, सार, सड़कें, सघ का बजट और 'मुद्रा और सार' की पद्धतियों की स्थापना के विषय रखे गए हैं। बाहरी देशों से सारा व्यापार सोवियट सरकार खुद या उस से अधिकार प्राप्त तत्प्राप्त ही करती है। यहां तक सोवियट सघ की राज-व्यवस्था में और दूसरी सघीय राज-व्यवस्थाओं में बहुत कम फर्क मालूम होता है। फिर भी दो खास बातें मिलती हैं। एक तो सघ के भीतर की सारी तिजारत और व्यापार का अर्थात् सारे समुक्त प्रजातन्त्रों की तिजारत और व्यापार का नियन्त्रण सघ के हाथ में होना और दूसरी लगभग सारे करों पर सघ का कब्जा होना। समुक्त प्रजातन्त्रों और उन के प्रांतों को भी थोड़े से कर लगाने का अधिकार है। मगर ये अमल में उस अधिकार का बहुत कम प्रयोग करते हैं। अधिकतर उन का खर्च सघ के करों के भेजे हुए भाग ही से चलता है। कृषि, व्यापार, ग्रामदनी, व्यापारी, चुगी इत्यादि के सारे मुख्य कर सघ के होते हैं। परंतु उन की आय सघ और प्रजातन्त्रों में बँट जाती है। सघीय राज-व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी ग्राम शक्तें रक्षित जाती हैं जिन से सारी सघ में एक प्रकार की समता दीसती है। ग्रामतौर पर सघीय राज-व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकारों इत्यादि का भी वर्णन होता है। अस्तु, 'सोवियट सघ' की राज-व्यवस्था में 'सघ' को कुछ ऐसे सिद्धांत कायम करने का अधिकार दिया गया है, जिन पर सघ के सार्वजनिक जीवन के विभिन्न विभागों को एक-सा अमल करना चाहिए। सघ के आर्थिक जीवन का तरीका और चलन, और इस संध में रियासतें देने का हक सघी सरकार को दिया गया है। ज़मीन के बाँट और इस्तेमाल, रानों, जगलों, और सघ के सारे जलमार्गों के इस्तेमाल के उसूलों, न्यायालयों की स्थापना और संचालन और दीनानी और फौजदारी के सघीय कानूनों के उसूलों, मजदूरी के तात्त्विक कानूनों के उसूलों, राष्ट्रीय शिक्षा के ग्राम उसूलों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रक्षा के उसूलों को बनाने का अधिकार भी सघ को दिया गया है। सघ की तरफ से इन उसूलों को समुक्त प्रजातन्त्रों में कायम करने की, सौभाग्य से, ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विभिन्न सोवियट प्रजातन्त्र एक ही समाजशाही के सिद्धांतों पर बने थे। अस्तु, उन का ढाँचा भी एक ही सा था। राज-व्यवस्था में सघ को इन उसूलों को बनाने का अधिकार रखने का केवल इतना ही अर्थ है कि इन उसूलों को, सारी सघ की निना अनुमति के, नष्ट नहीं किया जा सकता है, मगर इस संध से सघ के विभिन्न समुक्त प्रजातन्त्रों की 'इच्छा होने पर सघ से अलग हो जाने की स्वतंत्रता' राज-व्यवस्था में दे कर जो प्रजातन्त्रों की स्वाधीनता पर जोर दिया गया है, वह एक प्रकार से मिटती जाती है, क्योंकि वास्तव में प्रजातन्त्रों को किसी विभाग में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती है। सघ को सघ के सिद्धांतों के एक नमूने पर चलना होता है। अस्तु, सोवियट

संघ को दुनिया के सब संघीय राष्ट्रों से अधिक 'केंद्रीय संघ' कहा जा सकता है।

संघ की अधिकार-सीमा में आनेवाली दूसरी बातें साधारण हैं। 'प्रवास और निवास,'<sup>१</sup> 'तोल और माप, अंक,'<sup>२</sup> विदेशियों की नागरिकता के अधिकारों के कानून और अपराधियों को आम माफ़ी के अधिकार का अमल दूसरी केंद्रीय सरकारों की तरह संघ के अधिकार में रक्खा गया है। संघ को 'प्रजातंत्रों की कांग्रेस', 'कार्यवाहक समितियों' अथवा 'जन संचालकों की समितियों' के उन सारे निश्चयों को रद्द कर देने का अधिकार भी दिया गया है, जिन को संघ अपनी राज-व्यवस्था के प्रतिकूल मानती हो।

संघ की सदस्य सरकारों को बराबरी का स्थान देने के लिए संघ की संस्थाओं में एक 'जातियों की सभा'<sup>३</sup> रक्खी गई है। इस सभा में सारे संयुक्त 'प्रजातंत्रों' के पाँच-पाँच प्रतिनिधि और 'स्वतंत्र क्षेत्रों'<sup>४</sup> के एक-एक प्रतिनिधि होते हैं। इस सभा का काम विभिन्न जातियों के राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना है। रूसी 'सोवियट संघ' में, सारी 'सोवियट संघ' की ७४ फीसदी आबादी होने से, उस का ही सोवियट संघ पर अधिकार हो जाने की शंका दूर करने के लिए यह सभा रक्खी गई है। दूसरी 'संघ सभा'<sup>५</sup> में संघ आबादी के अनुसार प्रतिनिधि होते हैं और वह सारी संघ की सम्मिलित प्रजा की प्रतिनिधि होती है। इन दोनों सभाओं को बराबर के अधिकार होते हैं; क्योंकि संघ के कानूनों को बनाने के लिए दोनों की मंजूरी जरूरी होती है। संयुक्त प्रजातंत्रों को अपने-अपने बजट पर अधिकार होता है; मगर यह सारे विभिन्न बजट संघ के बजट का ही भाग माने जाते हैं और उन के लिए संघीय कार्यकारिणी की मंजूरी की जरूरत होती है। मगर अमल में यह मंजूरी सिर्फ़ नाम की होती है। फिर भी इन बजटों पर यहस होती है और इस संबंध में भी प्रजातंत्रों को पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। प्रजातंत्रों को सिर्फ़ एक शासन-कार्य में अवश्य स्वतंत्रता होती है। यना संघ के बनाए हुए उसलों की हद के अंदर ही प्रजातंत्रों को कानून बनाने का अधिकार होता है और सारे बड़े मामलों में कानून बनाना संघ का काम माना गया है। परराष्ट्र-विभाग, युद्ध, विदेशी व्यापार, डाक, तार और मार्ग के संघीय विभागों और मंत्रियों को छोड़ कर दूसरे सब विभाग और उन के मंत्री संयुक्त प्रजातंत्रों में भी होते हैं। कृषि, यह, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक-हितकार्य के विभाग सिर्फ़ शासन-विभाग होने से संयुक्त प्रजातंत्रों में ही होते हैं और बराबरी उन के सानी विभाग संघ में नहीं होते हैं। संयुक्त प्रजातंत्रों को अपनी संस्कृति के विकास में पूर्ण स्वतंत्रता और शासन में बहुत कुछ स्वतंत्रता तथा कानून बनाने में एक हद तक स्वतंत्रता दी गई है। सरकार की आम नीति और परराष्ट्रों से संबंध इत्यादि संघ का काम है। 'रूसी समाजशाही संघीय सोवियट प्रजातंत्र' के स्थान में रूस की स्थायी राज-व्यवस्था में 'समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ' बनाई गई है, क्योंकि रूस की समष्टिवादी सरकार 'दुनिया के मज़दूरपेशा लोगों के एक खानदान' में विश्वास रखती है और मानती है

<sup>१</sup> माइग्रेशन पॉइंट सेटिलमेंट ।

<sup>२</sup> स्टैटिस्टिक्स ।

<sup>३</sup> ग्रैंडो नोमस टैरिटरीज़ ।

<sup>४</sup> कौंसिल ऑफ़ नेशनलटीज़ ।

<sup>५</sup> यूनियन कौंसिल ।

कि धीरे-धीरे, एक के बाद दूसरे राष्ट्रों में जैसे-जैसे मज़दूरशाही स्थापित होती जायगी वैसे-वैसे, वे सोवियट-पद्धति को कबूल कर के 'समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ' में शामिल होते जायेंगे जिस से आखिरकार एक दिन दुनिया में मज़दूरशाही अर्थात् समाजशाही या सच्ची प्रजासत्ता का अधिकार स्थापित हो जायगा और पूँजीशाही अर्थात् थोड़े-से धनवानों की भेड़ियाशाही का दुनिया से हमेशा के लिए नाम-निशान मिट जायगा। रूस की इस राज-व्यवस्था के मूलतंत्रों को मानने या बदलने का अधिकार सिर्फ संघ की सोवियटों की कांग्रेस को है। संयुक्त प्रजातंत्रों के अधिकारों की हिफाजत संघ करती है। सारी संघ में सब को एक से नागरिकता के अधिकार हैं और जिन संयुक्त प्रजातंत्रों की राज-व्यवस्था संघ की राज-व्यवस्था से भिन्न है उन को अपनी राज-व्यवस्था में तबदीली कर के संघ के अनुधार बना लेने की शर्त रक्खी गई है। संघ की सरकार का संगठन नीचे से ऊपर को पिरामिड<sup>१</sup> के ढंग पर है। उस की बुनियाद गाँवों और शहरों की सोवियटों पर है। गाँव पहले अपनी सोवियट चुनता है। गाँव की सोवियट बोलोस्ट<sup>२</sup> अर्थात् ताल्लुका सोवियटों की कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुनती है। गाँव की सोवियटें यूएचड अर्थात् जिला सोवियट कांग्रेस के लिए भी, अपने हर दस सदस्यों के लिए एक के हिसाब से, प्रतिनिधि चुनती हैं। सब से जरूरी म्यूबरनिया<sup>३</sup> अर्थात् प्रांतिक सोवियट कांग्रेस होती है जिस को उस क्षेत्र की शहरों की सोवियटें और ताल्लुका सोवियट कांग्रेसें चुनती हैं।

## शहरी और देहाती सोवियटें

हम कह चुके हैं कि 'समाजशाही सोवियट संघ' की राजनैतिक इमारत का बुनाव पिरामिड की तरह नीचे से ऊपर की तरफ ढलता चला गया है। उस की बुनियाद शहरों और गाँवों की सोवियटों की दो ईंटों से बनी है। अस्तु, सोवियट संघ की केंद्रीय संस्थाओं के अध्ययन के पहले उस की बुनियादी संस्थाओं शहर और गाँव की सोवियटों का अध्ययन कर लेने पर हम को सोवियट संघ के राजनैतिक संगठन को अच्छी तरह समझने में भी बड़ी सहायता हो जायगी जो डिस्ट्रिक्ट्स की सरकार के अध्याय में केंद्रीय शासन के अध्ययन से पहले स्थानिक शासन के अध्ययन से हो गई थी।

शहरों की सोवियटों में अधिकतर कारखानों और दूसरे मुक्तलिफ उद्योगों और धंधों की सोवियटें होती हैं। नाकि के पहले रूस में कारखानों का भी वैसा ही बुरा हाल था जैसा रूस की सरकार का था। उन में भी वैसी ही नादिरशाही चलती थी। कारखाने के मालिक कारखानों पर कड़वाकों का हमेशा पहरा रखते थे। कोई मज़दूर कभी शराब पी लेता था या किसी दिन काम पर देर से आता था या गैरहाजिर हो जाता था तो कड़वाकों के कौड़ों से उस की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। अब रूस के कारखानों में काम करने-

<sup>१</sup> पिरामिड मिथ में बनी हुई एक श्वास तरह की क्रयें हैं, जो नीचे बुनियाद पर फैली हुई और ऊपर को ढलती हुई एक नोक में इस प्रकार खत्म होती हैं।

<sup>२</sup> म्यूबरनिया ।

वालों की हुक्मत चलती है, क्योंकि सोवियट संघ के शहरों में प्रजाशाही कारखानों से शुरू होती है। हर कारखाने में एक चुनी हुई कमेटी या काँसिल होती है, जिस को 'काम कमेटी' कहते हैं। इन कमेटियों के तीन काम होते हैं। एक तो मजदूरों की तरफ से यह कमेटियाँ कारखाने के प्रबंधकों से सारी बात-चीत करती हैं। दूसरे वे कारखाने की सामाजिक संस्थाओं पालनाघर, औषधालय स्कूलों इत्यादि का प्रबंध करती हैं। तीसरे सोवियटों के चुनावों में इन कमेटियों का निश्चय महत्व का होता है। पहले सोवियट सिर्फ 'हड़ताल कमेटियों' को कहते थे। मगर इन हड़ताल कमेटियों ने रूस की क्रांति में प्रजा की सेना का काम दिया था। अतः, बाद में 'कारखाने की सोवियटों' का रूस की सरकार में बड़ा ज़रूरी स्थान बन गया।

'काम कमेटी' के चुनाव के मुख्तलिफ़ कारखानों में मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। बड़े कारखानों में दस-दस पाँच-पाँच मजदूर मिल कर अपना एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं और इन प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होता है, जिस में 'काम कमेटी' का चुनाव होता है। छोटे कारखानों में सारे मजदूरों की सभा 'काम कमेटी' को चुनती है। सभा में कारखानों के निम्न विभागों के मजदूरों को अपने-अपने विभागों से उम्मीदवारों के नाम पेश करने का हक़ होता है। उदाहरणार्थ कपड़े के कारखाने में सूत कातनेवाले विभाग के आदमी अपने उम्मीदवार और कपड़ा बुननेवाले विभाग के आदमी अपने उम्मीदवारों के नाम पेश कर सकते हैं। सभा में हाथ उठा कर मत लिए जाते हैं। और आगे से कम मत मिलनेवालों उम्मीदवारों को चुना नहीं जाता है 'काम कमेटी' के प्रधान मंत्री और कुछ सदस्यों को कारखाने में मजदूरों के काम से बरी कर दिया जाता है। और यह सारा समय कारखाने में काम करनेवालों की सेवा और हित रक्षा के कामों में बिताते हैं। मगर उन को कारखाने से वेतन बराबर मिलता रहता है। कमेटी के दूसरे सदस्य कारखाने में काम करते रहते हैं और कमेटी की बैठकों में भी भाग लेते हैं। मुख्तलिफ़ कारखानों की 'काम कमेटियों' में मजदूरों की संख्या के अनुसार सदस्यों की मुख्तलिफ़ संख्या होती है। 'काम कमेटी' का दफ़्तर कारखाने की इमारत में ही होता है और उस का सारा काम-काज कई छोटी-छोटी कमेटियों में बाँट दिया जाता है। 'काम कमेटी' के कुछ सदस्यों की एक कमेटी और उतने ही कारखानों का प्रबंध करनेवाले अधिकारियों की एक कमेटी को मिला कर एक 'कमिशन का कमीशन' बनाया जाता है। मजदूरों की सारी शिकायतों के पहले इस कमीशन पर उन के जो सदस्य होते हैं, वे जाँच करते हैं और जाँच के बाद जिन शिकायतों को वे वाजिब समझते हैं उन को ही इस कमीशन के सामने रखते हैं। शौर-वाजिबी तरीके पर मजदूरों से बर्खास्त करने तरक्की ठीक तरह पर न करने या काफ़ी मजदूरी न देने इत्यादि की हर किसम की व्यक्तिगत और सामूहिक, शिकायतें कमीशन के सामने आती हैं। जिन शिकायतों का फ़ैसला इस कमीशन में मजदूरों की दृष्टि से संतोषजनक नहीं होता है उन की मजदूरों की तरफ से 'मजदूर संघ' के पास अपील होती है। 'मजदूर संघ' उन शिकायतों को अपने ज़िले की 'फ़ैसला पचावत' के सामने

रखती है। वहाँ भी सतोषजनक फैसला न होने पर एव 'राष्ट्रीय फैसला पचायत'¹ के सामने उन शिकायतों की अपील जा सकती है।

'काम कमेटी' की एक 'उपसमिति' मजदूरों की योग्यता² बढ़ाने का काम भी करती है। इन उपसमिति को कारखाने के प्रबंध की वाहिली और गलतियाँ रतलाने, कारखाने के मजदूरों की तरफ से आनेवाली नई सूझों और प्रस्तावों को अमल में लाने, ज़रूरत पड़ने पर प्रबंध संचालकों के साथ बैठ कर विचार करने और प्रबंध चलाने वाले अधिकारियों की बदइतज़ामी या बदसलूकी की समालोचना करने का हक होता है। सोवियट संघ के कारखानों और सेना में मजदूरों का व्यवहार पर यहाँ जोर दिया जाता है। ज़ार शाही के ज़माने के वे बात या ज़ार ज़ार-सी बात पर लात और घूसे श्रम रूस के कारखानों में इतिहास की बात हो गई है। जहाँ अभी तक यह बातें थोड़ी बहुत चलती हैं वहाँ मजदूरों का ही दोष मानना चाहिए, क्योंकि वे अपनी ही कमज़ोरी और कायरता के कारण शिकायत करने से डरते हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि रूस के कारखानों में आजकल भी मजदूर बड़ी व्यवस्था पसंद करते हैं, मगर अधिकारी कारखाने में कड़ी व्यवस्था रखने के साथ ही मजदूरों से श्रम नभ्य व्यवहार करते हैं। 'काम कमेटी' के सरकार से कारखानों के सुप्रबंध और सुसंचालन में भी बड़ा फायदा होता है, क्योंकि सोवियट कारखानों के मैनेजर्स को सत्ता और अच्छा माल निकालने के साथ-साथ मजदूरों को हमेशा सतुष्ट रखने का दयालु रस्ता पड़ता है। कारखानों के मैनेजर्स की नियुक्ति तक सरकार 'मजदूर संघों' की सलाह से करती है। मजदूर संघों कारखानों की 'काम कमेटी' की सलाह पर अमल करती हैं। अतः, मैनेजर की गर्दन पर हमेशा से मजदूरों का हाथ रहता है और उस को मजदूरों के साथ संभाल पर चलना होता है।

'काम कमेटी' अपनी सामाजिक संस्थाओं के काम पर अभिमान करती है। इन 'सामाजिक संस्थाओं' का काम चलाने के लिए मजदूर अपने वेतन का एक अच्छा भाग देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इन्हीं संस्थाओं के द्वारा उन का जीवन फलता-फूलता और हरा भरा होता है। उदाहरणार्थ गर्भवती स्त्रियों को बच्चा पैदा होने से दो मास पहले से काम पर से छुट्टी मिल जाती है और बच्चा पैदा होने के दो मास बाद तक वे काम पर नहीं जाती हैं। इस लंबे समय में उन्हें बच्चा कारखाने से पूरी तक़्क़ीद तो मिलती ही रहती है, मगर दूसरा महीना खत्म होते ही वे बच्चे को मज्ने से कारखाने के 'पालनाघर'³ में रख कर रोज़ कारखाने में अपना काम कर सकती हैं। 'पालनाघर' में बच्चों के लालन पालन के लिए दोशियार दाइयाँ रहती हैं, और एक डाक्टर भी रोज़ बच्चों को देखने के लिए आता है। जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है, तब तक माँ को बीच-बीच में दूध पिलाने के लिए आध आध घंटे की छुट्टी मिलती है। 'पालनाघर' के बाद बच्चा कारखाने के किंडरगार्टन स्कूल में शिक्षा पाता है। किंडरगार्टन स्कूल के बाद बच्चे राष्ट्रीय स्कूल में जाते हैं। सोलह वर्ष की उम्र से लड़के कारखाने में काम कर सकते हैं। मगर सोलह से अठारह वर्ष की उम्र तक उन को सिर्फ़ छ घंटा काम करना होता है। रास हुनरों के

लिए जवान उम्मीदवारों को साढ़े तीन साल 'कलामदन'<sup>१</sup> में गुजारने पड़ते हैं। साल में दो बार नौजवानों का श्रद्धांजलि तरह डाक्टरी मुआयना भी होता है। जिन की तंदुरुस्ती ठीक नहीं होती है उन को सहल काम दे दिया जाता है या किसी 'स्वास्थ्यग्रह'<sup>२</sup> में स्वस्थ जीवन पालन की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता है। कारखाने का डाक्टर मजदूरों के घरों का भी मुआयना करता है।

हर कारखाने में व्यायाम शाला, दौड़ने, खेलने-कूदने के मैदान कुश्ती के लिए अखाड़े और निशानेबाजी सीखने के लिए स्थान होते हैं। सेकड़ों युवक और युवतियाँ इन स्थानों में खेल-कूद में रोज भाग लेते हैं। दिमागी विषयों में शौक रखनेवाले जिन मजदूरों की इच्छा 'मजदूरों के महाविद्यालय'<sup>३</sup> में जाने की होती है उन के लिए आठ महीने की पढ़ाई-लिखाई का एक खास पाठ्यक्रम रखा गया है। इस पाठ्यक्रम को खत्म कर लेने के बाद वह महाविद्यालय में जा सकते हैं। इस महाविद्यालय में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, होनहार मजदूर नौजवानों को, तीन-चार साल शिक्षा दे कर विश्वविद्यालयों में भर्ती होने के कानिबल कर दिया जाता है। अस्तु, कारखाने से सीधा विश्वविद्यालय में चले जाने का मजदूरों के लिए रास्ता खुला रहता है। बच-प्राप्त मजदूरों का भी डाक्टरी मुआयना जय-तथ होता है। उन को आवश्यकतानुसार 'काम-कमेटी' दवादारु की सहायता पहुँचाती है। उन के लिए मी पढ़ने-लिखने के लिए खास पाठ-शालाएँ होती हैं, जिन में निरक्षरों को पचीस-पचीस के हर दर्जों में अंकगणित इत्यादि साधारण बातें सिखाई जाती हैं और कारीगरों को उन की कारीगरी में संबंध रखनेवाले प्राथमिक विज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। हर साधारण मजदूर को साल भर में पंद्रह दिन और जोरिम का काम करनेवालों को एक मास की पूरी मजदूरी पर छुट्टी मिलती है। इन छुट्टियों में सैर-सपाटे के लिए रेलों इत्यादि—पर खास रियायतें दी जाती हैं। हर कारखाने में अस्पताल भी होता है। बीमारी और कमजोर आदमियों को पहाड़ों इत्यादि स्वास्थ्य प्राप्त करने के स्थानों में भी ज़रूरत के अनुसार भेज दिया जाता है। कारखाने के सामाजिक जीवन का केंद्र प्रायः कारखाने का क्लबघर होता है। यहाँ रोज शाम को बहुत-से मजदूर—अधिकतर नौजवान—एकत्र होते हैं। कोई बैठ कर चाय पीता और गप्पें लड़ाता है; कोई गान के कमरे में बैठ कर पियानो बजाता या गाता है; कोई पढ़ने के कमरे में बैठ कर अखबार या किताब पढ़ता है; कोई अपनी पढ़ाई की दिक्कतों को जानकारों से बैठ कर समझता है। रविवार<sup>४</sup> और अक्सर क्लबघर की नाट्यशाला में मजदूरों के अलग अलग समूह नाटक रचते या गायनों-बाँदन का कार्यक्रम रखते हैं। कारखाने के एक भाग में मजदूरों को हवाई जहाजों पर उड़ने और लड़ाई में विपैली गैस इत्यादि भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि रूस की सरकार अपनी सारी मजदूर पेशा जन-संख्या को, पूँजीशाही दुश्मनों के मुकाबले के लिए, हमेशा तैयार रखना चाहती है। इसी प्रकार रहने के घरों की समस्या हल करने के लिए, 'काम-कमेटी' की एक अलग समिति होती है। 'काम-कमेटी' के सारे कामों का अहवाल सोवियट

सरकार की सारी कार्रवाई का लगा चिह्न हो जायगा। सोवियट रूस में प्रजासत्ता का रूप और अमल समझाने के लिए इतना हाल काफी है। कारखानों में जिस प्रकार प्रजासत्ता का अमल चल सकता है, उसी प्रकार शहर की दूसरी सारी सोवियटों में चलता है।

रूस की क्रांति के पहले जिस प्रकार कज़ाकों का कारखानों में डंडा चलता था, उसी प्रकार गाँवों में पुलिस के चौकीदारों का राज होता था। परंतु अब, कारखानों की तरह गाँव भी अपनी सोवियटों के द्वारा ही अपना सारा प्रबंध और शासन चलाते हैं। गाँव के लोगों की एक सार्वजनिक सभा में गाँव 'सोवियट' के सदस्य, सी की आवादी के लिए एक सदस्य के हिसाब से, चुन लिए जाते हैं। अमीर और गरीब किसानों में अभी तक रूस में झगडा चला आता है। इस लिए कारखानों की सोवियटों से गाँवों की सोवियटों के चुनावों में अधिक मारा-मारी रहती है। समष्टिवादी दल गाँवों की सोवियटों में अपने उम्मीदवारों का चुनाव कराने की बहुत कोशिश करता है। क्योंकि कारखानों की तरह गाँवों में 'समष्टिवादी दल' का इतना जोर नही है। अक्सर गाँवों की सोवियटों में समष्टिवादी दल के अधिक सदस्य नहीं चुने जाते हैं। फिर भी सोवियटों में चुने जाते वाले लोग आम तौर पर इस दल से सहायुभूति रखने वाले होते हैं। गाँव की स्त्रियों और मर्दों में कारखानों की स्त्रियों और मर्दों से जाग्रति कम होती है।

गाँव की सोवियट का प्रधान ग्राम सोवियट का सब से बड़ा कारगुजार हाकिम होता है, उस को वेतन भी दिया जाता है। 'गाँव सोवियट' के दो ही मुख्य काम होते हैं। एक तो सालखुफा या 'तहसील सोवियट' के लिए प्रतिनिधियों को चुनना और दूसरा गाँव की 'सामाजिक सस्थाओं' का संचालन और प्रबंध करना कारखानों की तरह गाँवों में भी स्कूल, क्लब, अखाडे और खेल-कूद के स्थान इत्यादि होते हैं, जिन का सारा काम-काज गाँव की सोवियट चलाती है। भगर गाँव की जरूरी समस्याओं को सोवियट गाँव की सार्वजनिक सभा के सामने तय होने के लिए रखती है। उदाहरणार्थ गाँव के लिए आवश्यक ईंधन गाँववाले अपने घोड़ों को ले जा कर खुद जंगल से लावें या एक सहकारी सस्था को ठेका दे कर यह काम इकट्ठा सारे गाँव के लिए करा लिया जाय, इस बात का निश्चय करने के लिए गाँव की सार्वजनिक सभा बुलाई जावेगी।

शहर की सोवियटों में एक हजार आबादी के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उन में आम तौर पर कम से कम पचास और अधिक से अधिक एक हजार सदस्य होते हैं। कारखाना, व्यापारी सस्थाओं, शिक्षालयों और उन सारी सस्थाओं, जहाँ मजदूरी पर लोग काम करते हैं, शहरों की सोवियटों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिन सस्थाओं में सी से कम मजदूर पेशा लोग काम करनेवाले होते हैं वे दूसरी बैरी ही छोटी सस्थाओं के साथ मिल कर चुनाव में भाग लेती हैं, क्योंकि कम से कम पाँच सौ काम करनेवालों के लिए ही एक प्रतिनिधि चुना जा सकता है। गाँव सोवियटों के सदस्यों को गाँव और अडोस-पडोस के नगरों की दस हजार से कम आबादी के कस्बों की प्रजा हर सी आदमियों की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुनती है। ग्राम सोवियटों



में ग्राम तोर पर कम से कम तीन और अधिक से अधिक पचास प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तीन मास के लिए होता। जिन गाँवों में प्रजा की सार्वजनिक सभा गाँव के शासन की समस्याओं पर विचार और निश्चय करती हैं वहाँ स्वीट्ज़रलैंड के गाँवों की तरह खालिस प्रजाशाही चलती है। रोज़मर्रा का काम-काज चलाने के लिए गाँव की सोवियटें अधिक से अधिक पाँच और शहरों की सोवियटें कम से कम तीन और अधिक से अधिक पंद्रह सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति चुन लेती हैं। परंतु लेनिनग्राड और मास्को की सोवियटों की कार्यकारिणी समितियों में चालीस सदस्य तक चुने जा सकते हैं। कार्यकारिणी समिति पूरे तोर पर उसी सोवियट को जवाबदार होती है, जो उस को चुनती है। हर सोवियट को या जिन गाँवों में सार्वजनिक सभा की खालिस प्रजाशाही होती है वहाँ उस सभा को अपने क्षेत्र में शासन की सारी सत्ता होती है। सोवियटों की बैठकें 'कार्यकारिणी-समिति' की ओर से या सोवियट के आधे सदस्यों की माँग पर कम से कम शहर में हफ्ते में एक बार और देहात में हफ्ते में दो बार ग्रामतौर पर बुलाई जाती हैं। हर सोवियट के फाम काज के विभिन्न विभाग होते हैं और उन की देर भाल उसी सोवियट की उप-समितियाँ और अधिकारी करते हैं। गाँव और शहर की सोवियटों की 'कार्यकारिणी-समिति' का कर्तव्य अपनी ऊपरी सोवियट संस्थाओं के आदेशों पर चलना अपने क्षेत्र की उन्नति के उपाय करना और स्थानिक समस्याओं को हल करना होता है।

## स्थानिक सोवियट कांग्रेसें

वोलोस्ट कांग्रेस, गाँवाँ और शहरों की सोवियटों के ऊपर की सारी सोवियटें 'सोवियट कांग्रेस' होती हैं, क्योंकि उन में प्रजा के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। प्रजा गाँव और शहर की सोवियटों के प्रतिनिधियों को चुनती है और गाँव और शहर की सोवियटें ऊपर की दूसरी सोवियटों के सदस्यों को चुनती हैं। सारी सोवियट कांग्रेसों में शहरों के मजदूरों को गाँव के किसानों से करीब तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक होता है। रूस की समष्टिवादी राज-व्यवस्था में मजदूरों को सामाजिक क्रांति का पदपाती माना गया है इस लिए उन को किसानों से तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक दिया गया है। गाँवों की सोवियटों के ऊपर सोवियटों की वोलोस्ट अर्थात् ताल्लुका या 'तहसील सोवियट' कांग्रेसें होती हैं। हर देहाती सोवियट के दस सदस्यों के लिए वोलोस्ट कांग्रेस में एक प्रतिनिधि नियमा जाता है। दस सदस्यों से कम सदस्यों की देहाती सोवियटों का एक एक प्रतिनिधि लिया जाता है।

**यूएज्द कांग्रेस**—यूएज्द या 'जिला सोवियट' कांग्रेसों में देहाती सोवियटों से, एक हजार की आबादी के लिए एक के हिसाब से मगर सारे जिले के लिए तीन सौ से अधिक नहा चुन कर प्रतिनिधि आते हैं। दस हजार से कम की आबादी के कस्बों की सोवियटों से भी प्रतिनिधि चुन कर 'जिला सोवियट कांग्रेसों' में आते हैं। एक हजार से कम आबादी की छोटी छोटी देहाती सोवियट मिल कर एक हजार के लिए एक के हिसाब से

प्रतिनिधि चुन लेती हैं। मगर वस्त्रों, कारखाने और व्यापारी सस्थाओं की सोवियटों को दो सौ मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि जिला कांग्रेस में भेजने का अधिकार होता है।

**प्रांतिक कांग्रेस**—‘प्रांतिक सोवियट कांग्रेस’ में शहरों की सोवियटों के प्रतिनिधि, पाँच हजार से अधिक आबादी की कारखाने के मजदूरों की वस्तियों के प्रतिनिधि और ताल्लुका ‘सोवियट कांग्रेस’ के प्रतिनिधि होते हैं। ‘ताल्लुका कांग्रेस’ से दस हजार की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से, शहरों, मजदूरों की वस्तियों और वस्तियों के बाहर के कारखानों और व्यापारी सस्थाओं से दो हजार मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से प्रांतिक कांग्रेसों में चुन कर प्रतिनिधि आते हैं। मगर सारे प्रांत से तीन सौ से अधिक प्रतिनिधि किसी हालत में नहीं लिए जाते हैं। ‘प्रांतिक कांग्रेस’ सोवियट की बैठक के पहले ही ‘जिला कांग्रेस’ की बैठक होने पर, ताल्लुका कांग्रेस के प्रजाय, जिला कांग्रेस ही ताल्लुकों की ओर से ‘प्रांतिक कांग्रेस’ के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है। जिन प्रांतीय नगरों में सोवियट नहीं होती हैं उन के भी दस हजार की आबादी के लिए एक के हिसाब से, ‘प्रांतिक कांग्रेस’ में प्रतिनिधि आते हैं।

**प्रादेशिक कांग्रेस**—‘प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस’ में, शहरी सोवियटों, से पाँच हजार की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से और जिला कांग्रेसों के पचीस हजार की आबादी के लिए एक के हिसाब से चुन कर सोवियट प्रतिनिधि आते हैं। मगर एक ‘प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस’ में पाँच सौ से अधिक प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं। किसी ‘प्रांतीय सोवियट कांग्रेस’ से फौरन पहले होने पर, शहरों और जिला सोवियटों की प्रजाय, प्रांतिक कांग्रेस से भी उसी हिसाब से ‘प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस’ में प्रतिनिधि आ सकते हैं। अगर प्रजातन्त्र की कांग्रेस से पहले किसी ‘प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस’ की बैठक होती है तो ‘प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस’ ही प्रजातन्त्र की कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है।

हर एक ‘सोवियट कांग्रेस’ अपनी एक कार्यकारिणी कमेटी चुन लेती है जो कांग्रेसों की बैठकों के दरमियान के समय में काम चलाती हैं। कार्यकारिणी के प्रधान और मंत्री और कभी कभी एक और सदस्य को वेतन भी मिलता है। ‘प्रांतिक सोवियट कांग्रेस’ की कार्यकारिणी में राज व्यवस्था के अनुसार २५ सदस्य तक चुने जा सकते हैं। मगर कांग्रेस को हर एक यूएज्द और उद्योगी जिले से कम से कम एक-एक प्रतिनिधि ले कर राज व्यवस्था में दो हुई सख्या से अधिक सख्या कार्यकारिणी में रखने का भी अधिकार होता है। अक्सर प्रांतिक कांग्रेसों की कार्यकारिणी में पचास तक सदस्य हो जाते हैं। इन में से हर एक सदस्य शासन के किसी न किसी विभाग का खास तौर पर ज्ञान प्राप्त कर के उस विभाग में काम करता है। प्रजातन्त्र के शासन विभागों के ही मुकाबले के प्रांतिक कांग्रेसों के शासन विभाग होते हैं जिन में शासन का सारा काम बाँट दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि की शासन नीति प्रांतिक सरकारों के यह विभाग

स्थानिक हालतों के अनुसार निश्चित करते हैं। हर विभाग की मूलनीति तो राष्ट्रीय सरकार ही निश्चित करती है, मगर स्थानिक जरूरतों के मुताबिक उस के अमल में थोड़ा बहुत फेरफार करने का मौका प्रांतिक सरकारों को रहता है। प्रांतिक सरकारों को अपना अधिकतर खर्च अपने उन उद्योगों के मुनाफे से चलाना होता है जो उन के अमल में होते हैं और जिन का प्रबंध वह चलाती हैं। कभी कभी किन्हीं खास स्थानिक जरूरतों के लिए उन्हें कुछ कर लगाने का भी अधिकार होता है। राष्ट्रीय कोष से प्रांतिक सरकारों को जो खर्च की मालाना इमदाद मिलती है, उस पर उन का बहुत कुछ सहारा रहता है। बहुत-सी प्रांतीय सरकारों की सारी आमदनी का लगभग आधा भाग आजकल शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च कर दिया जाता है। मगर गाँवों और कारखानों की सोवियटों तथा और सब सोवियटों की तरह प्रांतिक सोवियटों का शासन कार्य दूसरे यूरोप के देशों की तरह सरकारी नौकरों पर नहीं छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार गाँव में सोवियट का चुनाव हुआ प्रधान आजकल सब से बड़ा अधिकारी होता है उसी प्रकार 'प्रांतिक सोवियटों' में कार्यकारिणी के सदस्यों ने ज़ारशाही की पुरानी नौकरशाही का स्थान ले लिया है। बहुत-सी खास बातों के विशेषज्ञ जानकारों और दफ्तरों में काम करने के लिए क्लर्कों इत्यादि को तो रक्खा ही जाता है। मगर सोवियटों के चुने हुए सदस्य भी शासन का काम बड़ी मेहनत से करते हैं। चुनाव के समय इन प्रतिनिधियों को अपने काम का विद्या मतदारों के सामने रखना होता है। इस में सोवियटों के लिए व्याख्यानदाताओं, बुद्धिमानों या बड़े आदमियों को चुनने की किसी को फिक्र नहीं होती है। जो सदस्य मेहनती होते हैं और अच्छे अच्छे और अधिक संख्या में सार्वजनिक हित के काम कर के दिखाते हैं उन को ही प्रजा चुनती है।

सोवियटें बहुत-सी उप समितियों में बाँट दी जाती हैं और हर एक उप समिति को किसी न किसी विभाग के शासन का भार दे दिया जाता है। सोवियट के बाहर से भी कुछ सदस्य इन समितियों में लिए जा सकते हैं। हर एक सदस्य पर किसी न किसी काम का भार रहने से सब अपने को जिम्मेदार समझते हैं। किसी प्रतिनिधि को अस्पतालों को फी देर-रेर, किसी को स्कूलों और किसी को मजदूरी के घटों इत्यादि के नियमों के पालन की देर-रेर का काम सौंप दिया जाता है। सोवियटों की सभाएँ जल्दी-जल्दी या लगातार कई दिनों तक नहीं होती हैं। अक्सर मास्को से कोई न कोई बड़ा अधिकारी स्थानिक सोवियटों को राष्ट्रीय नीति समझाने के लिए आता-जाता रहता है। स्थानिक सोवियटों की बैठकों में मुखालिफ़ विभागों की रिपोर्टों पर विचार होता है और बजट पास किया जाता है। मगर सोवियट के हर सदस्य का मुख्य काम अपने शासन-कार्य को करना होता है। सोवियटें धारा-सभाओं की तरह सिर्फ जबाबदारी का अफाड़ा नहीं होती हैं। वहाँ कुछ कर के दिखाना होता है। अक्सर प्रांतिक सोवियटों की जगह पर बाहर के सदस्यों के लिए आकर ठहरने और जिस विभाग में उन्हें शौक हो उस में कुछ दिन काम कर के उस विभाग का सारा काम-काज समझ लेने के लिए प्रबंध रक्खा जाता है। हर क्षेत्र में वास्तविक सत्ता उस क्षेत्र की 'सोवियट कांग्रेस' को रहती है। साल में एक बार आम तौर पर

इन कांग्रेसों की लगभग दस दिन तक बैठकें होती हैं। कांग्रेसों में किसी प्रकार के कानून पास नहीं होते हैं। कांग्रेसों का वातावरण सार्वजनिक सम्मेलनों का-सा होता है और वहाँ सिर्फ शासन-नीति पर आम चर्चा होती है, तथा शासन के उसूलों के संबंध में ही प्रस्ताव पास किए जाते हैं। सोवियटों को ऊपर से आनेवाले सरकारी आदेशों का पालन, अपने क्षेत्रों की उन्नति के उपाय, स्थानिक शासन समस्याओं की पूर्ति, और अपने क्षेत्र की सारी सोवियटों के काम का ऐकीकरण करना होता है। सोवियट कांग्रेसों और उन की कार्य-कारिणी को अपने क्षेत्र की स्थानिक सोवियटों के काम-काज पर पूरा अधिकार होता है अर्थात् प्रादेशिक कांग्रेस का प्रदेश के अंदर की सारी सोवियटों पर अधिकार होता है, और प्रांतिक कांग्रेसों को प्रांत के अंदर की उन शहरी सोवियटों को छोड़ कर जो जिला सोवियट में नहीं जाती हैं और सारी सोवियटों पर अधिकार होता है। खास मामलों में केंद्रीय सरकार को खबर करने के बाद और आमतौर पर सब मामलों में अपने आधीन सोवियटों के सारे निश्चयों को 'सोवियट कांग्रेस' नामजूर और रद्द कर सकती हैं।

हर सोवियट का चुनाव वहाँ की स्थानिक सोवियट की निश्चित की हुई तारीख पर, एक 'चुनाव कमीशन' और स्थानिक सोवियट के प्रतिनिधियों के सामने किया जात है। चुनाव के नियम और तरीके 'केंद्रीय कार्यकारिणी' के आदेशानुसार 'स्थानिक सोवियट' तय करती है। चुनाव का अहवाल और मतों का फल एक काराज पर दर्ज कर के 'चुनाव कमीशन' और स्थानिक सोवियट के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के साथ और दूसरे चुनाव के आगजातों के साथ 'स्थानिक सोवियट' के पास भेज दिया जाता है। फिर चुनाव के नतीजे की जाँच स्थानिक सोवियट की एक 'देखभाल-समिति' कर के अपन रिपोर्ट स्थानिक सोवियट को देती है। झगड़ा होने पर किसी प्रतिनिधि के चुनाव के बाकायदा होने न होने का फैसला वही सोवियट करती है। किसी का चुनाव बाकायदा ठहराने पर नया चुनाव कराती है। सारा चुनाव ही और-बाकायदा होने पर उस सोवियट के ऊपर की सोवियट उस चुनाव को खारिज करने का हुक्म निकालती है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय कार्यकारिणी के पास तक चुनाव के झगड़ों की अपील जा सकती है। चुननेवाले मतदारों को हमेशा अपने चुने हुए सोवियटों पर प्रतिनिधियों को वापिस बुला लेने और नया चुनाव कराने का अधिकार भी होता है।

सोवियट-पद्धति की सरकार में विश्व न रहनेवालों का कहना है कि प्रतिनिधि पद्धति की सरकारों में सोवियट पद्धति सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि सोवियट-पद्धति में शासकों को प्रजा के बहुत नजदीक रहना पड़ता है। उन का यह दावा सिर्फ शहरों और गाँवों की सोवियटों के बारे में सच्चा हो सकता है, क्योंकि शहर की सोवियटें लगभग कारखानों के जीवन का आईना होती हैं और गाँव की सोवियट में सीधा किसान राज चलता है। मगर शहर और गाँव की सोवियटों से ऊपर की सोवियटों के विषय में उन का यह दावा ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऊपर की संस्थाओं को सोवियट कह भी नहीं सकते हैं। वे 'सोवियट कांग्रेस' होती हैं। रूस जैसे

लंबे चौड़े देश में, जहाँ अभी तक सड़कों और रेलों का इतना सुभीता नहीं है— इन कांग्रेसों की अक्सर बैठकें बुलाना, कांग्रेसों में आए हुए प्रतिनिधियों को कई दिन तक लंबी बैठकों के लिए रोक रखना अशक्य होता है। अस्तु, इन 'सोवियट कांग्रेसों' का मुख्य काम मुफरिखल के ज़िलों को केंद्र की खबर देते रहना होता है। कांग्रेसों में आने-वाले प्रतिनिधि बड़े ध्यान से मुख्तलिफ रिपोर्टों को सुनते हैं और चर्चा में भाग लेते हैं। फिर विभिन्न विषयों पर अपनी राय कायम कर के अपने स्थानों को चले जाते हैं। सोवियट कांग्रेसों को शासन पर लगातार कड़ी आँख रखने और शासन की अच्छी तरह से नुफता-चीनी करने का मौका नहीं होता है। सरकार का विरोधीदल रूस में कोई न होने से दूसरे देशों की तरह सरकारी काम की नुफताचीनी करने वाला विरोधीदल रूस में नहीं होता है। अस्तु, शासन, जाँच पड़ताल, नुफताचीनी और नियंत्रण का सारा काम 'कार्यवाहक समितियाँ' ही करती हैं। मगर उन के प्रजा के नज़दीक रहने का भेय सोवियट-पद्धति को देना उचित न होगा। शासन से प्रजा के संतुष्ट रहने के दो कारण बड़े जा सकते हैं एक तो 'कार्यवाहक समितियों' में समष्टिवादी दल के ही सदस्य अधिक होते हैं और 'समष्टिवादी-दल' प्रजा के दिल और दिमाग के नज़दीक रहने की बहुत कोशिश करना है। दूसरे साधारण आदमियों को रास्ता सुला होने से जन-२५, १२९ के मन को पहचाननेवाले बहुत से लोग 'कार्यवाहक समितियों' में आ जाते हैं।

सोवियट-पद्धति के टेढ़े चुनावों के विषय में भी शका की जा सकती है कि पेशे-वार चुनावों से लोगों को अपने पेशों की तंग बातों का ही चुनावों पर अधिक खयाल रखने का लालच रहता है, सब पेशों के लोगों का मिल कर अन्य देशों में अपने रहने के स्थानों के अनुसार मत देने से मतदारों को देश के सार्वजनिक हित का अधिक खयाल रहता है। इस शंका में बहुत कुछ सत्य है। मगर रूस में जा कर जिन बाहर के बहुत से लोगों ने वहाँ की हालत का अध्ययन किया है, उन का कहना है कि वहाँ चुनावों में तंग खयाली का जोर नहीं रहता है, इस के शायद दो कारण हो सकते हैं। एक तो पेशों की बातों के फैसले के लिए मजदूर-पेशा अपनी 'उद्योग संघों' पर निर्भर रहते हैं, जिन का सोवियट सरकार में काफी असर होता है। दूसरे चुनाव में चर्चा के प्रश्नों को चुनने और उन का वातावरण बनाने का काम एक समष्टिवादी दल ही करता है, जिस पर उस के विरोधी तंग खयाली का इलजाम तो दूर, उल्टा दुनिया भर की फिक्र की खामखयाली का इलजाम आम तौर पर लगाते हैं। हाँ, कुछ हद तक यह जरूर ठीक है कि इन चुनावों में राष्ट्र के के बड़े बड़े नीति के प्रश्नों का दूसरे देशों की तरह फ़ैसला नहीं होता है। उन का फैसला समष्टिवादी-दल के भीतरी दायरों में होता है। सोवियट सरकार की अधिकतर समस्याएँ शासन की समस्याएँ होती हैं। गाँव और शहर की सोवियट से लेकर 'संघीय कार्यवाहक समिति' तक में इन्हीं समस्याओं पर विचार होता है, कि किस प्रकार अमुक मास तक चीज़ों की आम कीमत घटाई जाए, किस प्रकार अमुक कारखानों की पैदावार बढ़ाई जाए, किस प्रकार अशिक्षित लोगों की संख्या कम की जाए, और स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, किस प्रकार लोगों का स्वास्थ्य सुधारा जाए और कृषि में उन्नति की जाए

इत्यादि इत्यादि । यह समस्याएँ मतदारों के सामने समष्टिवादी दल रखता है और उन का ज्ञान इन बातों में दिन दिन बढ़ाने का प्रयत्न करता है ।

## केंद्रीय सरकार

‘समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की सघ की सोवियटों की कांग्रेस’—सोवियट सघ की ‘सर्वोपरि सत्ताधारी संस्था ‘सघ सोवियट’ कांग्रेस होती है । उसी में राष्ट्र की सारी प्रभुता होती है । उस की बैठकों के बीच के काल में उस की सारी सत्ता सघ की ‘केंद्रीय कार्यवाहक समिति’ में रहती है । ‘सघ सोवियट कांग्रेस’ में शहरी सोवियटों से पचीस हजार मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि और ‘ग्रामिक कांग्रेसों’ से सवा लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से प्रतिनिधि आते हैं । प्रतिनिधियों का चुनाव ग्राम तौर पर ग्रामिक कांग्रेसों करती हैं । मगर ‘सघ कांग्रेस’ से पहले ‘प्रादेशिक कांग्रेस’ की बैठक होने पर ‘प्रादेशिक कांग्रेस’ भी ‘सघ कांग्रेस’ के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है । ‘सघ सोवियट कांग्रेस’ की ग्राम बैठकें साल में एक बार ‘कार्यवाहक समिति’ बुलाती है । सालाना कांग्रेस में करीब डेढ़ हजार प्रतिनिधि आते हैं और उस की लगभग दस दिन तक मास्को की नाट्यशाला<sup>१</sup> में बैठक चलती है । मंच पर विभिन्न विभागों के निभागपति और नेता चढ़ कर बैठते हैं । लगे-लगे व्याख्यान भी क्राडे जाते हैं । ‘कार्यवाहक समिति’ आवश्यकता समझने पर अपनी इच्छा से, या अपनी दो शाखाओं—‘सघ-सभा’ और ‘जातियों की सभा’—में से किसी की माँग पर, या दो संयुक्त प्रजातंत्रों की माँग पर ‘सघ सोवियट कांग्रेस’ की खास बैठक भी बुला सकती है । अगर कोई ऐसे कारण पैदा हो जाए जिन से ‘सघ कांग्रेस’ समय पर न बुलाई जा सके तो ‘कार्यवाहक समिति’ को ‘कांग्रेस की बैठक बुलाना सन्मति कर देने का हक भी होता है । दूसरी सोवियट कांग्रेसों की तरह सघ कांग्रेस भी सिर्फ नीति के ग्राम प्रश्नों पर चर्चा कर के प्रस्ताव पास कर देती है । कानून बनाने और शासन करने का मुख्य काम ‘कार्यवाहक समिति’ करती है ।

‘केंद्रीय कार्यवाहक समिति’—समाजवादी सोवियट प्रजातंत्रों की सघ की ‘केंद्रीय कार्यवाहक समिति’ कानून बनाने, शासन चलाने और नियन्त्रण का सारा काम काज करती है । ‘कार्यवाहक समिति’ के दो भाग होते हैं । एक ‘सघ सभा’<sup>२</sup> और दूसरी ‘जातियों की सभा’<sup>३</sup> । ‘सघ सोवियट कांग्रेस’ प्रजातंत्रों के प्रतिनिधियों में से, हर एक प्रजातंत्र की आबादी के लिहाज से लगभग ३७१ सदस्यों की एक ‘सघ सभा’ चुनती है । जातियों की सभा में सारे ‘संयुक्त प्रजातंत्रों’<sup>४</sup> से पाँच-पाँच प्रतिनिधि और स्वतंत्र क्षेत्रों<sup>५</sup> से एक-एक प्रतिनिधि चुन कर आते हैं । मगर ‘जातियों की सभा’ का चुनाव भी मजूर सोवियट सघ कांग्रेस करती है । केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रेसीडीयम, सघ कांग्रेस के ‘जन सचालकों की समिति’<sup>६</sup>, सघ के विभिन्न जन-सचालक के विभागों संयुक्त प्रजातंत्रों की कार्य-

<sup>१</sup>काउंसिल ऑफ़ दि यूनियन । <sup>२</sup>काउंसिल ऑफ़ नेशनैलीज । <sup>३</sup>समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ में सात सोवियट प्रजातंत्र और ग्यारह स्वतंत्र क्षेत्र शामिल हैं ।

<sup>४</sup>पीपुल्स कमोन्वेल्थ ।

कारिणी के सारे प्रस्तावों, फरमानों और दस्तुल अमलों की जाँच और देख भाल 'कार्य-वाहक समिति' की दोनों सभाएँ करती हैं। 'सब सभा' और 'जातियों की सभा' में पेश होने-वाले सारे प्रश्नों पर भी दोनों सभाएँ विचार करती हैं। 'सघीय कार्यवाहक समिति' ही सारे प्रस्तावों, दस्तुल अमलों और फरमानों को प्रकाशित करती, 'सब के कानूनी और शासन-कार्यों का एकीकरण करती और प्रेसीडियम और जन-सचालकों का काम काज निश्चित करती है।

राज के राजनैतिक और आर्थिक जीवन के सिद्धांतों को निश्चय करनेवाले सारे फरमान और प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के चालू ज्ञान्ते में फेरफार करनेवाले प्रस्ताव और फरमान मंजूरी के लिए 'सघीय कार्यवाहक समिति' के सामने आते हैं। 'सघीय कार्यवाहक समिति' के सारे प्रस्तावों और एलानों पर सब के सारे क्षेत्र में फोरम अमल होता है।

'सघीय कार्यवाहक समिति' को प्रेसीडियम, संयुक्त प्रजातंत्रों की सोवियट कांग्रेसों और उन की कार्यकारिणियों तथा राज के क्षेत्र के अंदर की और सब संस्थाओं के हुक्मों और प्रस्तावों को अमल में आने से रोक देने और रद्द करने का हक होता है। 'सघीय-कार्यवाहक समिति' की बैठकें साल में तीन बार उस के 'प्रेसीडियम' की ओर से बुलाई जाती हैं। सब-सभा के प्रेसीडियम या जातियों की सभा के प्रेसीडियम या किसी एक प्रजातंत्र की कार्यकारिणी की माँग पर, 'सघीय कार्यवाहक समिति' का प्रेसीडियम एक प्रस्ताव पास कर के, 'सघीय कार्यवाहक समिति' की खास बैठकें भी बुला सकता है।

'सघीय कार्यवाहक समिति' के सामने जो मसविदे आते हैं वे 'सब-सभा' और 'जातियों की सभा' दोनों में मंजूर होने पर ही सघीय कार्यवाहक समिति द्वारा मंजूर समझे जाते हैं। उन की मंजूरी का एलान 'सघीय कार्यवाहक-समिति' के नाम में किया जाता है। अगर किसी मसविदे पर दोनों सभाओं की राय नहीं मिलती है तो 'सब सभा' और 'जातियों की सभा' दोनों की एक सम्मिलित बैठक होती है, और उस में उस मसविदे पर विचार होता है। फिर भी अगर दोनों सभाओं की बहुसंख्या एकमत नहीं होती है तो दोनों में से किसी एक सभा की माँग पर वह प्रश्न दोहराने के लिए 'संघ सोवियट कांग्रेस' की साधारण सभा या एक खास सभा के पास भी भेजा जा सकता है। 'सब-सभा' और 'जातियों की सभा', दोनों, साथ साथ सदस्यों के अपने अलग अलग, 'प्रेसीडियम' चुन लेती है। यह प्रेसीडियम ही इन सभाओं की बैठकों के लिए कार्यक्रम तैयार कर के रखते हैं और सभाओं का काम काज चलाते हैं। इन दोनों प्रेसीडियम के चौदह सदस्यों और दोनों सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में सात सदस्यों को और चुन कर इक्कीस सदस्यों का मिल कर 'केंद्रीय कार्यवाहक समिति' का प्रेसीडियम होता है। कार्यवाहक समिति की बैठकों के बीच के काल में उस के 'प्रेसीडियम' को सब की सारी सत्ता होती है। 'कार्यवाहक समिति' अपने प्रेसीडियम के सदस्यों में से संयुक्त प्रजातंत्रों की संख्या के अनुसार तत् प्रधान चुन लेती है। 'केंद्रीय कार्यवाहक समिति' अपने तमाम काम के लिए 'सब

सोवियट कांग्रेस' को ही जवाबदार होती है। उस की बैठक केमलिन के एक पुराने दीवान में होती है, जहाँ ज़ारशाही के ज़माने में बड़ी अदालत बैठती थी। दर्शकों को आने का अधिकार होता है। हर सदस्य को एक गोपे में से बोलना होता है, इस लिए तक़ारी के लुफ़ के लिए यह जगह नहीं होती है। 'सोवियट सभ कांग्रेस' और उस की 'कार्यवाहक समिति' को सभ की राज-व्यवस्था को मज़ूर करने, बदलने, बढ़ाने, घटाने, सभ की परेलू और बाहरी नीति का संचालन करने, सभ की सीमा निश्चित करने और बदलने अथवा सभ की किसी ज़मीन को अलग करने और उस पर से सभ का अधिकार उठा लेने, प्रादेशिक सोवियटों की सभों की सीमाओं को निश्चित करने और उन के आपस के झगड़ों का फैसला करने, समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की सभ में नए सदस्यों को मिलाने और सभ से अलग हो जाने वालों की पुर्दाई को मज़ूर करने, शासन की सद्दलियत के लिए देश को हिस्सों में बाँटने और मिलाने तोल, माप और मुद्रा की पद्धतियों को तय करने, परराष्ट्रों से सयष और युद्ध की घोषणा और सधि करने, दूसरे देशों से क़र्ज़ लेने और व्यापारी चुगी लगाने और व्यापारी राजीनामे करने, सभ के 'प्राथिक जीवन की एक ग्राम बुनियाद तय करने और उस की विभिन्न शाखाओं की रूप-रेखा निश्चित करने, सभ का वज़त मज़ूर करने, सार्वजनिक कर लगाने, सभ की सेना का संगठन और संचालन करने, क़ानून बनाने, न्याय शासन का प्रबंध करने, 'जन-संचालको' और उन की पूरी कौंसिल को नियुक्त करने, हटाने और उन के प्रधान के चुनाव को मज़ूर करने, सभ के नागरिकों और परदेशियों के नागरिकता के अधिकारों की ज़बती और मिलने के सबंध में नियम प्रकाशित करने, अपराधियों को क्षमा प्रदान करने इत्यादि के बड़े अधिकार हैं। इन के अलावा भी और जिन बातों को वह अपने अधिकार में समझे, उन पर फैसला करने का अधिकार भी 'सभ कांग्रेस' और 'कार्यवाहक समिति' को होता है। मगर सोवियट राज व्यवस्था के मूल तत्वों को घटाने-बढ़ाने और बदलने तथा दूसरे देशों से सधियाँ मज़ूर करने का अधिकार खास तौर पर सिर्फ 'सभ सोवियट कांग्रेस ही को होता है। सोवियट सभ की सीमाओं में फेरफार करने उस की ज़मीन कम करने, तथा परराष्ट्रों से सयष और युद्ध और सधि के प्रश्नों का फैसला भी 'केंद्रीय कार्यवाहक समिति' उसी हालत में कर सकती है जब कि 'सभ सोवियट कांग्रेस' की बैठक बुलाना असमभव हो।

**केंद्रीय कार्यवाहक समिति का प्रेसीडियम**—केंद्रीय कार्यवाहक समिति की बैठकों के बीच के काल में कार्यवाहक समिति के प्रेसीडियम को सोवियट सभ की क़ानूनी, कार्यकारिणी और शासन की ख़ासपारि सत्ता होती है। सारे अधिकारियों और सस्याओं के सभ की राजव्यवस्था पर अमल करवाने और सभ सोवियट कांग्रेस और केंद्रीय कार्यवाहक समिति के प्रस्तावों पर अमल करवाने का काम 'प्रेसीडियम' ही करता है। सभ के 'जन संचालकों की समिति' और विभिन्न 'जन संचालको' तथा संयुक्त प्रजातंत्रों की केंद्रीय कार्यवाहक समितियों और जन-संचालकों की कौंसिल के प्रस्तावों को रोकने और रद्द करने का अधिकार केंद्रीय कार्यवाहक समिति के प्रेसीडियम को भी होता है। 'केंद्रीय प्रेसीडियम' अपनी ओर से प्रस्ताव पास करता और फरमान और आर्डिनेंस निकालता है और सधीय



व्यापार विभाग,<sup>१</sup> सार्वजनिक अर्थ की सर्वोपरि समिति<sup>२</sup> का विभाग, यह पाँच विभाग समुक्त कमसरियट<sup>३</sup> अर्थात् समुक्त विभाग कहलाते हैं क्योंकि वे सब की सरकार और समुक्त प्रजातंत्रों की सरकारों दोनों में एक से होते हैं। सभीय सरकार के यह विभाग अपने विभागों की शासन-नीति के आराम उखल्लों को तय कर देते हैं और समुक्त प्रजातंत्रों के इसी नाम के विभाग उन उखल्लों पर शासन चलाते हैं। समुक्त प्रजातंत्रों में भी सब की तरह इन विभागों के अलग अलग जन-सञ्चानक होते हैं। फिर भी सब के विभागों का प्रजातंत्रों के विभागों पर एक हद तक नियन्त्रण रहता है। 'मजदूर और किसानों की जाँच' का विभाग सोवियट शासन की अपनी अनोखी चीज है। नीचे से ऊपर तक सोवियट सरकार के शासन में इस विभाग का काम पग-पग पर मिलता है। इस विभाग का काम शासन की आराम जाँच-पड़ताल होता है। सारे विभागों के हिसाब-किताब की जाँच और सार्वजनिक कामों का मुआयना यह विभाग करता है। अक्सर इस विभाग की तरफ से विभिन्न विभागों के कामकाज के बारे में सख्त नुक्ताचीनी होती है, जिस से अधिकारियों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। इस विभाग को बेईमानी और लापरवाही का खोद खोद कर पता लगाने की फिक्र रहती है।

मगर सब से खास और सब से जरूरी सोवियट सरकार के विभागों में 'सार्वजनिक अर्थ सर्वोपरि-समिति' का विभाग होता है। सोवियट सब में हर उद्योग का प्रबंध चलाने के लिए अलग अलग संस्थाएँ होती हैं जिन को 'ट्रस्ट'<sup>४</sup> कहते हैं। विभिन्न उद्योगों के ट्रस्टों के काम का एकीकरण और मिलान का काम 'सार्वजनिक अर्थ समिति' का विभाग करता है। यह विभाग हर उद्योग की पैदावार की मिकदर और वस्तु तय करता है। चीजों की कीमत तय करने का काम भी इसी विभाग का होता है। पैदावार करने वाले मजदूरों और खरीदारों के हितों का अंतिम निपटारा करना भी इसी विभाग के हाथ में होता है। जन खेती की पैदावार और कारखानों की पैदावार के पदार्थों की कीमत में बहुत फर्क होता है और गाँवों या कस्बों में असतोष फैलने का डर होता है, तब इसी विभाग के फौसले पर सारी परिस्थिति निर्भर हो जाती है। सोवियट सब के सारे उद्योग की निर्माता और विधाता 'गोस्प्लान' नाम की संस्था होती है जो 'सार्वजनिक अर्थ विभाग' की सहकारिता में काम करती है। 'गोस्प्लान' हर उद्योग के अर्थों का अध्ययन करने, उस उद्योग की पैदावार के सन्ध में प्रजा की जरूरत पर विचार करने, और उन जरूरतों के अनुसार उन उद्योगों की पैदावार की मिकदर और वस्तु तय करने का काम करता है। वही एक उद्योग की पैदावार कम करने और दूसरे उद्योग की पैदावार बढ़ाने का निश्चय कर सकता है। कृषि, उद्योग, खानों इत्यादि के विषय में अर्थों को अध्ययन कर के, हर साल दूसरे साल के लिए 'सोवियट सब' की आर्थिक कार्रवाई का कार्यक्रम गढ़ना

<sup>१</sup>इटर्नल ट्रेड। <sup>२</sup>सुप्रीम कौंसिल आफ पब्लिक इकनमी। <sup>३</sup>कमसरियट।

<sup>४</sup>इन ट्रस्टों और यूजीयाही देशों के व्यापारी ट्रस्टों में बड़ा फर्क होता है। नाम एक होने पर भी दोनों बिल्कुल भिन्न हैं।

पर, सघीय न्यायालय के दारोगा की सलाह से जाँच कर के केंद्रीय कार्यवाहक समिति को रिपोर्ट करना, कार्यवाहक समिति की माँग पर विभिन्न प्रजातन्त्रों के प्रस्तावों के सघीय राज-व्यवस्था के अनुसार कानूनी या गैरकानूनी होने के विषय में राय देना, प्रजातन्त्रों के आपस के कानूनी झगड़ों का फैसला करना और सघ के सब बड़े अधिकारियों के खिलाफ उन के अधिकार के सबब में इलजामों के मुकदमों की जाँच करना होता है। 'सघीय न्यायालय' की कई अदालतें होती हैं। एक तो सारे न्यायाधीशों की 'पूरी अदालत' होती है। दूसरी 'दीवानी' और 'फौजदारी' की अलग अलग थोड़े-थोड़े न्यायाधीशों की अदालतें होती हैं। तीसरी 'फौजी अदालतें' होती हैं। 'पूरी अदालत' में ग्यारह न्यायाधीश होते हैं, जिन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, चार समुक्त प्रजातन्त्रों की बड़ी अदालतों के अध्यक्ष और एक समुक्त राज्य राजनैतिक विभाग का प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और शेष पाँच न्यायाधीशों को केंद्रीय कार्यवाहक समिति का प्रेसीडीयम नियुक्त करता है।

सघ के न्यायालय के दारोगा और उस के नायब को भी केंद्रीय कार्यवाहक समिति नियुक्त करती है। सरकार दारोगा की राय आम तौर पर सारे कानूनी मामलों पर लेती है। मगर उस की राय आखिर में न्यायालय के फैसले पर निर्भर होती है। मुकदमों में दारोगा सरकार की तरफ से अपराधी के खिलाफ न्यायालय के सामने अपराध पेश करता है। न्यायालय की 'पूरी अदालतों' के किसी फैसले से दारोगा की राय न मिलने पर दारोगा को केंद्रीय कार्यवाहक समिति के प्रेसीडीयम से शिकायत करने का हक होता है। न्यायालय की 'पूरी अदालत' की राय किनी प्रश्न पर माँगने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय कार्यवाहक समिति को उस के प्रेसीडीयम को, सघीय अदालत के दारोगा को समुक्त प्रजातन्त्रों की अदालतों के दारोगों को, या सघ के समुक्त राज्य राजनैतिक विभाग को होता है। दीवानी या फौजदारी के ऐसे जरूरी मुकदमों की जाँच के लिए, जिन से दो या दो से अधिक प्रजातन्त्रों पर असर पड़ता हो और 'कार्यवाहक समिति' के सदस्यों और सघीय जन-रक्षकों की व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी के मुकदमों को सुनने के लिए न्यायालय की 'पूरी अदालत' रास अदालतें नियुक्त करती है। मगर यह मुकदमे सघीय न्यायालय के सामने सिर्फ केंद्रीय कार्यवाहक समिति या उस के प्रेसीडीयम के रास प्रस्तावों से ही आ सकते हैं।

दूसरे सत्र विभागों की तरह न्याय का शासन भी सोवियट सरकार में समाजशाही का अटल राज्य क़ायम करने के इरादे से बनाया गया है। अपने न्यायालया को भी सोवियट सरकार खुलमखुला वर्ग-सघर्ष की सस्थाएँ मानती है। समष्टिवादी कहते हैं कि हर देश उस देश के लोगों की नीति, माल, सजा और मनुष्यों के एक-दूसरे से सघर्षों के बारे में जो आम सामाजिक राय होती है, उस के अनुसार ही न्यायाधीश मुकदमों में फैसला करते हैं। 'अस्तु, 'समाजशाही सोवियट सत्र' में भी न्यायाधीशों को समाजवाद की दृष्टि से ही फैसला करना चाहिए। अतएव सोवियट सघ की अदालतों को सिर्फ समाज की रक्षा का ही खयाल नहीं होता है, बल्कि उन्हें समाजशाही की स्थापना करनेवाली क्रांति की रक्षा

का खयाल रखना पड़ता है। पेशावर न्यायाधीशों को जहाँ तक हो सके कम फर के साधारण मजदूरपेशा लोगों को न्याय का काम सुपुर्द करने की भी सोवियट सरकार बहुत कोशिश करती है। प्रांतीय न्यायालयों के अध्यक्ष न्यायाधीश को वहाँ की कार्यवाहक समिति एक साल के लिए नियुक्त करती है। एक साल खत्म होने पर उस की फिर नियुक्ति हो सकती है, या उस का किसी दूसरे जिले को तगदला किया जा सकता है। स्थानिक सोवियट की बनाई हुई छत्री में से दो असेसर भी बारी-बारी से एक हफ्ते के लिए चुन लिए जाते हैं। यह दोनों असेसर न्यायाधीश के साथ मिल कर मुकदमों का फैसला करते हैं। हमारे देश के असेसरों की तरह यह सिर्फ न्यायाधीश को ऐसी सलाह देने वाले नहीं होते हैं, जिन की राय मानना न मानना न्यायाधीश की इच्छा पर होता है। सोवियट सभ के असेसरों को जूरी से भी अधिक अधिकार होना है। सोवियट शासन के मूल सिद्धांत के अनुसार असेसर और न्यायाधीश दोनों मजदूरपेशा होते हैं। मगर न्यायाधीश बनने से पहले लोगों को कुछ समय तक एक खास शिक्षा लेनी होती है। असेसर लोग भी रात्रि-भाँडालाघ्रा में इसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। बड़ी अपील की अदालतों में खास शिक्षा और योग्यता के विशेषज्ञ ही न्यायाधीश बनाए जाते हैं।

सोवियट सभ में भी वकील-पेशा लोग होते हैं। उन की एक 'वकील सभ' भी है जिस में अधिकतर पुराने जमाने के वकील हैं। मगर सोवियट विश्वविद्यालयों में भी वकालत की शिक्षा दी जाती है। हर अपराधी को उन्नाव के लिए सरकार की तरफ से एक मुफ्त वकील दिया जाता है। घनवान अपराधी अपने वकील चुन भी रख सकता है। मुकदमों में शाम तौर पर बहुत कम खर्च होता है और वे जल्द खत्म हो जाते हैं। सोवियट अदालतों में सिर्फ कानून की दृष्टि से अपराधी को सजा देने का खयाल नहीं रखा जाता है, बल्कि उन को सुधारने का खयाल रखा जाता है। पहली बार अपराध करने वाले को अगर उस के उसी प्रकार का अपराध दुहराने का भय नहीं होता है, सिर्फ लानत मलामत कर के सजा की बजाय शर्म के जरिए से सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। सोवियट सरकार के न्यायाधीश शानदार चुगा पहनकर शान शौकत से कुर्सी पर जम कर नहीं बैठते हैं। वे मीठी मीठी बातें कर के अपराधी के दिल की बात जानने और कानूनी धाराओं पर ही दृष्टि न रख कर अपराधी मनुष्य को मनुष्य की तरह समझाने की कोशिश करते हैं; बराबर अपराध करने वालों को दूसरे देशों की तरह जेल में रखा जाता है। मगर सोवियट सरकार की जेलों में चक्की से काफी आटा पिसा लेने, रामगोस कुटाने और तरह तरह की तरतलीफें दे कर कैदी को कैदी होने का दु सदायी ज्ञान कराने से अधिक कैदी को एक प्रकार का बीमार समझ कर उस के साथ अस्पताल का सा व्यवहार दिया जाता है। जेलों में हर एक अपराधी को कोई न कोई एक खास उद्योग या घधा सिखाया जाता है और कारखानों की मजदूरी के हिसान से, उस के घर का खर्च काट कर जो बाकी बचता है, उस को छूटने के समय मजदूरी के तौर पर दे दिया जाता है।

'लालसेना'—सोवियट सभ में रूस के किसानों के प्रिय लाल रंग को क्रांति के

बाद बड़ी महत्ता मिल गई है। सोवियट सघ का झंडा लाल होता है और जिस वस्तु को अधिक से अधिक मान देना होता है, उस में 'लाल' शब्द जोड़ दिया जाता है। अस्तु, सोवियट सघ की सेना 'लाल सेना' कहलाती है। सन् १९२० में सोवियट सघ के पास हर प्रकार की मिला कर ५३ लाख स्थायी सेना थी। मगर सन् १९२६ ई० तक बढ़ घटा कर सिर्फ ५ लाख ६२ हजार कर दी गई थी। स्थायी सेना के सिवाय रूस में 'जन सेना' भी होती है। सत्र मजदूरो और किसानों को कानूनन हर साल कई हफ्ते तक सेनिक शिक्षा लेनी होती है। रूसी सेना की दूसरी भी एक विशेषता है। सोवियट सघ के कारखाने उद्योग धंधे और दूसरी राजनैतिक स्थापना भी स्थायी सेना की पल्टनों में अपने अपने दस्ते चुन लेती है जिन को वह हमेशा हर प्रकार की सहायता पहुँचाती रहती है। उसी प्रकार पल्टनों के दस्ते अपने अपने गावों को चुन लेते हैं जिन को वे मदद पहुँचाते रहते हैं। इस सरकार की पद्धति से प्रजा और सेना में स्नेह रहता है और सेना प्रजा की रहती है। प्रजा के हितों के खिलाफ सेना का उपयोग दुर्लभ हो जाने के साथ ही इस पद्धति से सेना उपयोगी रचनात्मक काम में लगी रहती है और सेनिक भी अज्ञान और मूढ़ नहीं बन जाते हैं।

## राजनैतिक दल

समाजशाही सोवियट सघ में बस एक मजदूर पेशावादी में मानने वाले 'समष्टिवादी दल' का राज है। इटली की तरह एक राजनैतिक दल ने सरकार पर अपना कब्जा जमा कर दूसरे सारे दलों को तहस नहस कर दिया है। इस दल की सोवियट सरकार पर इतनी छाप है कि जिस प्रकार समष्टिवादी सिद्धांतों को बिना समझे सोवियट राज व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को समझना मुश्किल है। उसी प्रकार इस दल के काम को बिना समझे सोवियट शासन को अच्छी तरह समझना असंभव है। सोवियट राज व्यवस्था सिर्फ इस दल की उद्देश्य पूर्ति का एक हथियार है। सोवियट राज व्यवस्था में सरकार की सत्ता रखने वाले बहुत से अधिकारियों की योजना की गई है। ऐसी राज व्यवस्था को चलाने का भार अगर एक ही समष्टिवादी दल की तरह सुसंगठित और मजबूत दल पर न होता तो उस का चलना असंभव हो गया होता, रूस का 'समष्टिवादी' दल भी अपने दम का अनूठा राजनैतिक दल है। इस दल ने रूस में निचार और व्यवहार की क्रांति कर के सोवियट सघ में आज अपना असट राज अवश्य जमा लिया है। मगर रूस की राजक्रांति का अनुग्रा यह दल नहीं था। सत्र से पहला समाजवादी दल रूस में एक और ही दल था जिस का नाम 'नरोडनिकी' अर्थात् 'प्रजा इच्छा दल' था इस दल का जोर उन्नीसवीं सदी के तीसरे भाग में था और उस में अधिकतर विश्वविद्यालयों के शिक्षित लोग थे जिन में बहुत से धनवान भी थे। यह लोग समाजवादी सिद्धांतों को माननेवाले थे और रूस में अपने गावों की 'मीर' यानी पचासवीं की बुनियाद पर समाजशाही का अद्वितीय महल बनाने का स्वाभ देखते थे। यह लोग किसानों को अपना आराध्यदेव समझते और उन की गिरी हुई दशा पर तरस खा कर उन की हालत सुधारने और उसी उद्देश्य से उन

को क्रांति के लिए उभाड़ने का प्रयत्न करते थे। इस दल के बहुत-से स्त्री-पुरुष दाइयाँ और शिल्प बन कर गाँवों में किसानों को क्रांति के लिए उभाड़ने के इरादे से जाते थे। यह लोग यम और पिस्तौल में भी विश्वास रखते थे और अक्सर जुल्म करनेवाले सरकारी अफसरों का खून कर डालते थे। मगर ज़ार ऐलेक्जेंडर दूसरे को हत्या कर के इस दल ने अपने ऊपर सरकारी जुल्म की घटाटोप आँधी बुला ली थी और इस दल को अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने में नाकामयाबी रही थी। इस के बाद एक दूसरे 'समाजी क्रांतिकारी' नाम के दल की रूस में हवा बँधी थी, जो बढ़ता-बढ़ता आखिरकार लड़ाई के ज़माने में होनेवाली मार्च और नवंबर की रूस की क्रांतियों के बीच के काल में रूस का सब से बड़ा राजनैतिक दल बन गया था। यह दल भी हमेशा से रूस में फ़ौरन समाजशाही कायम कर देने का पक्षपाती था। समाजी क्रांतिकारी शुरू से मानते थे कि रूस में किसान भूत से ऊब कर क्रांति कर डालेंगे। मगर समाजशाही में विश्वास रखने के साथ ही इस दल के लोग निर 'अंतरराष्ट्रीयवादी' ही नहीं थे। वे देश-पक्षि में भी विश्वास रखते थे। अस्तु, पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने पर उन्होंने अपने देश की सरकार का साथ दिया था। इस दल में भी पहले अधिकतर शिक्षित लोग ही होते थे। मगर पीछे से बहुत-से मध्यम वर्ग के लोग और समझदार किसान भी इस दल में शामिल हो गए थे। मशहूर कैरेंसकी इसी दल का नेता था।

तीसरा दल 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' था। यह दल मार्क्स की वाणी और इतिहास की आर्थिक व्याख्या में अटल यकीन रखता था। मार्क्स की भविष्यवाणी के अनुसार—जिस को वह और उस के चेले विज्ञान पर निर्धारित मानते हैं—'संसार में गर्म-संघर्ष पैदावार की प्रगति के ज़रियों की उन्नति पर मुनहसिर है। जिस प्रकार पैदावार के ज़रियों की उन्नति होने और उद्योग-युग का प्रारंभ होने पर यूरोप में पुरानी नवाबशाही के मुक़ाबले में मध्यमवर्ग के पूँजीमनियों और व्यापारियों की जीत हुई और प्रजासत्तात्मक दल का विकास हुआ, उसी प्रकार उद्योग-युग के अंतिमकाल में मज़दूरपेशा लोगों की उन्नति बढ़वाने और उन का ज्ञान बढ़ जाने से मज़दूरों की क्रांति होगी और समाजशाही ही हुकूमत कायम होगी।' 'समाजी और प्रजासत्तात्मक दल' मार्क्स की इस भविष्यवाणी में वैसा ही कट्टर विश्वास रखता था, जैसा कि हमारे आर्यसमाजी 'वेदों के सब विद्याओं के भंडार' होने में विश्वास रखते हैं। मगर इस प्रकार का कट्टर विश्वास रखनेवाले व्यवहार में भी कट्टर हो जाते हैं, जिस से अक्सर, जहाँ बहुत करनेवाले सोचते ही रह जाते हैं, वे सफल हो जाते हैं। 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' अपने अकीदे के अनुसार मानता था कि रूस में समाजशाही स्थापित होने से पहले रूस को उद्योग-युग के धुएँ के बादलों और मशीनों की खड़खड़ में से हो कर गुज़रना ही होगा। उन की नज़र में और कोई छोटा रास्ता नहीं था। वे बमबाज क्रांतिकारियों की, सरकारी अफसरों की व्यक्तिगत

<sup>१</sup> सोशल रिवोल्यूशनरी ।

<sup>२</sup> सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ।

<sup>३</sup> एकात्मिक इंटरप्रेटेशन आफ़ हिस्ट्री ।

<sup>४</sup> इंटरनेशनलिस्ट ।

<sup>५</sup> मार्क्स ।

<sup>६</sup> फ़्रांस स्ट्रगल ।

हत्याओं को लाभदायक नहीं समझते थे। क्योंकि वे जनता के सामूहिक विद्रोह में विश्वास रखते थे। यह लोग क्रांतिकारी विचारों में किसानों को पिछड़ा हुआ मानते थे और उन को क्रांति के अयोग्य मान कर शहरों के मजदूरपेशा लोगों को ही क्रांति के लिए तैयार करने की कोशिश करते थे। यूरोपीय लड़ाई से पहले रूस में उद्योग-धंधों की उन्नति के कारण मजदूरपेशा लोगों की दिन दिन बढ़ रही थी। समाजी प्रजासत्तात्मक दल इन मजदूरपेशा लोगों से ही रूस में क्रांति करा कर रूस को जारशाही के पजे से छुड़ाना और जारशाही के स्थान में समाजशाही की स्थापना करना चाहता था।

‘समाजी क्रांतिकारी’ और ‘समाजी प्रजासत्तात्मक’ दलों के सदस्यों को रूस में जारशाही के ज़माने में, भारतवर्ष के पड़्यनकारियों की तरह छिप-छिप कर रहना और काम करना होता था। एक ही दल के सदस्यों को एक दूसरे का नाम तक नहीं मालूम होता था, क्योंकि यह लोग अक्सर झूठे नाम रख लिया करते थे अथवा एक दूसरे को किसी सख्या से पुकारते थे। यह लोग अक्सर छिपी जगहों में मिला करते थे और पुलिस से आँखमिथौनी सी खेलते हुए, हमेशा अपनी जान बचाने के लिए एक घर में आज तो फल दूसरे घर में भागे-भागे रहा करते थे। जो काम करते-करते पुलिस के हाथों में पड़ जाते थे, उन को जेल की हवा खानी पड़ती थी। एक दो बार जेल फाट आने पर फिर पकड़े जाने पर यह लोग रूस के काले पानी साईबेरिया को निर्वासित कर दिए जाते थे। इन दोनों दलों के लगभग सभी अच्छे अच्छे काम करने वाले सदस्यों को जेल की यातनाओं ने तपा कर भस्म बना दिया था। कच्चे और आरामतलब आदमियों के लिए इन दलों में जगह नहीं होती थी। ऐसे आदमियों की खुद ही इन दलों में शरीक होने की हिम्मत नहीं होती थी। जो लोग नोश में आ कर धोखे या गलती से सदस्य बन जाते थे, वे एक आध बार पुलिस के चक्कर में आते ही इन दलों को छोड़ कर भाग जाते थे। इन दलों के सदस्यों को मिल कर और संगठन के नियमों के अनुसार काम करना होता था। एक बार जिस बात का निश्चय हो जाता था उस पर दल के सदस्य सैनिक की तरह अमल करते थे, क्योंकि सिर्फ़ बावूनी लोगों को इन दलों में जगह न होने से सारे सदस्य छूँटे मँजे मनुष्य होते थे। सदस्य अपने दल के ऊपरी अधिकारियों के हुक्मों का मिलते ही पालन करते थे। कभी कभी स्त्री के एक हजार मील पश्चिम और पति को एक हजार मील पूर्व के किसी स्थान में काम के लिए बीबीस घंटे में एक दूसरे से विदा हो कर चले जाने का हुक्म मिलता था—ऐसे स्थानों में जाने का जहाँ से फिर लौट कर आने की ज़रा भी आशा नहीं होती थी। मगर स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को आखिरी सलाम कर के निश्चित समय के भीतर ही अपने-अपने लक्षित स्थानों को चले जाते थे। कम से कम बाद में कम्युनिस्ट या समष्टिवादी दल के नाम से मख्यात होनेवाले समूह में ऐसी फौलादी नियम बद्धता अवश्य थी।

इस सुसंगठित और अपने विश्वासों के लिए मर मिटनेवाले लोगों के ‘समाजी प्रजासत्तात्मक दल’ में से लेनिन ने उन लोगों को बाद में निकाल दिया था। जो जारशाही के खिलाफ़ गैरसमाजवादी दलों से भी मिल कर क्रांति के ज़माने में

काम करना चाहते थे। क्योंकि लेनिन सिर्फ एक वर्ग युद्ध में विश्वास करने वाले लोगों के नेतृत्व में ही क्रांति चाहता था। सारे दल में एक लेनिन ही ऐसा मनुष्य था जो रूस में फौरन सामाजिक क्रांति कर डालने की समावना में विश्वास रखता था। दूसरे सदस्य सामाजिक क्रांति चाहते जरूर थे, मगर उस की फौरन समावना में विश्वास नहीं रखते थे। मगर लेनिन की रण-रण इस विश्वास से पड़क रही थी, अस्तु, उस ने जान बूझ कर दल में फूट डाल कर फौरन क्रांति में विश्वास न रखनेवालों को दल से निकाल दिया था और खुशी से अपने भाषियों की सख्या कम कर ली थी। उस का यकीन था कि क्रांति में थोड़े से भ्रष्टाचार अटल विश्वासियों के दल से जितना काम बन सकेगा, उतना दिलमिल यत्नोन्मादों के एक लंबे चौड़े दल की सेना में नहीं बनेगा। मगर लेनिन को भी शायद इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि पिछली यूरोप की लड़ाई के जमाने में होनेवाली क्रांति में रूस में समाजशाही कायम हो कर बहुत काल तक टिक सकेगी। रूस में समाजशाही कायम कर के दुनिया के मजदूरपेशा लोगों को इस मिसाल से ससार व्यापी समाजशाही क्रांति का मार्ग दिखा देना ही लेनिन का उद्देश्य अधिक मालूम होता था। उस का खयाल था कि रूस की मजदूरशाही का अनुकरण पहले जर्मनी के मजदूर करेंगे और उस के बाद सारे यूरोप में मजदूरों की क्रांति फैल जावेगी। कुछ भी हो, लेनिन में यह भ्रष्टा और दृढ़ता थी, जो क्रांति का जीवन और सफलता की कुंजी होती है। उस ने भ्रष्टा से 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' पर अपना कब्जा जमा कर के उस को बाद में अपनी दृढ़ता से छेड़े हुए मतवालों का समष्टिवादी बोल्शेविक दल बना दिया था।

समष्टिवादी दल के हाथ में रूस की लगाम आ जाने पर इस दल ने बड़ी भ्रष्टा और दृढ़ता से काम लिया। लेनिन के हाथ में सत्ता आते ही उस ने मजदूरपेशा लोगों को अपने साथ लेने के लिए एलान कर दिया था कि 'समष्टिवादी दल राष्ट्र की सारी मिलकियत पर मजदूरपेशा का अधिकार स्थापित करना चाहता है। मजदूरपेशा लोगों को सिर्फ एक समष्टिवादी दल का साथ' देना चाहिए। 'क्योंकि समष्टिवादी-दल की हुकूमत में सब कुछ मजदूरपेशा ही का होगा। उन के डरने की कोई बजह नहीं है' क्योंकि 'हार जाने पर मजदूरपेशा लोगों के पास खोने का सिर्फ ज़रों हैं, और जीत जाने पर राष्ट्र की सारी मिलकियत पर उन का अधिकार होगा।' सत्ता हाथ में आते ही समष्टिवादी दल ने जमींदारों और ताल्लुकेदारों से जमीन भी छीन कर किसानों को सौंप दी थी। 'समष्टिवादी दल' के मन का लुभाने वाले इन एलानों को सुन कर और किसानों का ज़मीन पर कब्जा उस का प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर रूस के किसान और दूसरे मजदूरपेशा लोग स्वभावतः समष्टिवादी दल के साथ हो गए थे। क्रांति के बाद दूसरे देशों के रूस में हस्तक्षेप करने से और जारशाही के पुजारियों, पुराने पूँजीपतियों और जमींदारों के बोल्शेविक सरकार पर हमलों से मजदूरपेशा लोग और समष्टिवादी-दल का सबध और भी दृढ़ हो गया था। क्रांति सफल हो जाने के बाद अटल समाजशाही कायम करने के इरादे से समष्टिवादी दल ने पुरानी नौरशही को मानने वाले लोगों को चुन चुन कर शासन विभागों, सेना और

अदालतों से निकालना और उन की जगहों पर अपने दल के मजदूरपेशा वर्ग के सदस्यों को भरना शुरू किया था। बहुत-से इन सदस्यों में अच्छी तरह पढ़ना-लिखना भी नहीं जानते थे। सब तरह के शासन कार्य के लिए हजारों अधिकारियों की जरूरत थी। समष्टिवादी दल सारे अधिकारी अपने दल के सदस्यों में से ही बनाना चाहता था। दल के सदस्यों की संख्या भी बहुत नहीं थी। अस्तु, बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती थीं। फिर भी 'समष्टिवादी-दल' दूसरे दलमिल यकीन वालों के हाथ में किसी प्रकार का कोई अधिकार या सत्ता देना पसंद नहीं करता था।

रूस की क्रांति को हुए अब पंद्रह वर्ष हो चुके हैं। समष्टिवादी दल की सोवियट-सभ में अलबट सत्ता भी क़ायम हो चुकी है। मगर अभी तक रूस में समष्टिवादी-दल में शरीक होनेवाले को पहले एक उम्मीदवारी का समय काटना पड़ता है। इस उम्मीदवारी के समय में उस पर बड़ी बड़ी दृष्टि रक्खी जाती है। उस के चरित्र और बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। उस को मार्क्स के आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन और दल के लिए काम करने के तरीकों की शिक्षा लेनी होती है। उम्मीदवारी का समय खत्म होने पर, उस का इन बातों में इम्तहान भी होता है, जिस में बहुत-से उम्मीदवार नाशमयाब हो जाते हैं। किसी आदमी को उम्मीदवार बनाने या पूरा सदस्य बनाने से पहले दल की कोई शाखा उस के पूर्व इतिहास, उस के विचारों, उस के चरित्र और दल के काम में उस के उत्साह आदि की अच्छी तरह जाँच कर लेती है। पूरा सदस्य बन जाने पर भी नए सदस्य पर काफी समय तक बड़ी दृष्टि रक्खी जाती है। 'मध्यवर्गी बुद्धि' या 'मध्यवर्गी तर्क' की बीमारी का जरा भी लक्षण दीखते ही सदस्यों को समष्टिवादी-दल से निकाल दिया जाता है। बुद्धि पेशा-वालों को समष्टिवादी दल का विश्वासपात्र सदस्य बनना बड़ा कठिन होता है। मजदूर-पेशा लोगों को आसान होता है। मुग़निन है इस की वजह यह हो कि सोवियट सरकार के एक ही समष्टिवादी सिद्धांत के कार्य में परिणत करने के लिए बुद्धिमान तर्कशास्त्रियों के शिक्षित वर्ग के मुकाबले में सीधे-सादे साधारण और असली मजदूरपेशा वर्ग के लोग ही बेहतर साबित होते हैं। दल के आदेशों पर अक्षरशः अमल करने और सादा, एक प्रकार का गरीबी का, जीवन बिताना समष्टिवादी-दल के सदस्यों का फर्ज होता है। बड़े से बड़े नेता को दल की राय के खिलाफ जाने पर दल से निकाल देने में समष्टिवादी दल सकोच नहीं करता है। लेनिन की दाहिनी भुजा ट्राट्स्की और बोल्शेविक रूस के प्रचंड प्रचारक जिनेवोफ तक को कुछ वर्ष हुए दल की नीति का विरोध करने पर समष्टिवादी दल से निकाल कर फेंक दिया गया था। अब समष्टिवादी दल तो दूर, रूस और उस के अड़ोम-पड़ोस के देशों तक में इन नेताओं का सुखना दुर्लभ है। जब सोवियट सभ के ब्रह्मांत्रों की यह दशा की जा सकती है तो साधारण सदस्यों का तो पूछना ही क्या? उन को दल की नीति के विरुद्ध जाने पर दल से निकाला ही नहीं, बल्कि साइबेरिया के किसी दूरबर्ती उजाड़ ग्राम में निर्वासित तक किया जा सकता है।

समष्टिवादी दल के सभी सदस्यों को साधारण जीवन निभाना होता है और दल के



कोई सदस्य किसी सरकारी पद पर भी नियुक्त हो जाने पर अधिक से अधिक २२५ रूबल्स<sup>१</sup> से ज्यादा वेतन नहीं ले सकता है। 'समष्टिवादी दल' का सदस्य संघीय सरकार-मंत्री, बैंक या कारखाने का मैनेजर, कोई भी हो, इस से अधिक वेतन नहीं ले सकता है। दल के बाहर के विशेषज्ञों को बड़ी-बड़ी तनखायें भी दी जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कारखाने के समष्टिवादी दल के सदस्य मैनेजर का वेतन कम होता है और उस के नीचे काम करनेवाले विशेषज्ञ का जो समष्टिवादी नहीं होता, वेतन अधिक होता है। अस्तु, कोई योग्य और ईमानदार आदमी समष्टिवादी दल में अमीर बनने के विचार से शामिल नहीं होता है। वेईमानी के उद्देश से जो दल में शरीक हो कर और कोई पद प्राप्त कर के छिपे-छिपे जेबें गरम करते हैं, उन को पकड़े जाने पर बड़ी सख्त सजाएं दी जाती हैं। वहाँ तक कि गोली से मार दिया जाता है। फिर भी साधारण योग्यता के मनुष्यों को समष्टिवादी दल में शरीक हो जाने के अक्सर लाभ की संभावना रहती है, क्योंकि दल के सदस्यों को खास कर मजदूरों को हर सरकारी विभाग में तरजीह दी जाती है। बहुत-से साधारण योग्यता के लोग अब दल में गए सदस्यों को लेने के लिए बहुत कठिनाइयाँ न रक्खी जाने के कारण अपनी तरक्की के ख्याल से भी समष्टिवादी दल में शरीक हो जाते हैं। दल के सदस्यों से सरकारी काम के अलावा दल का इतना काम लिया जाता है कि उन को अक्सर दम मारने तक की कुरसत नहीं रहती है। शाम और सुबह तक उन बेचारों को अपनी बीबी-बच्चों के साथ गुजारना मुश्किल हो जाता है। अस्तु, आराम पसंद सेवा-भाय से हीन और ढीले-ढाले लोगों को समष्टिवादी दल में शरीक होना बड़ा कठिन होता है। वेईमानी के ख्याल से जो समष्टिवादी दल में शरीक होते हैं वे संचमुच हथेली पर जान रख कर चमकौले ठीकरो से खेलने आते हैं। उन्हें हर दुर्भाग्य के लिए तैयार रहना चाहिए।

समष्टिवादी दल का रुस में अधिकार हो जाने के समय से यह दल एक नई संतान रचने का प्रयत्न भी कर रहा है। शालाग्रो और विचारपीठों में नौ संतान को समष्टिवादी सिद्धांतों और विचारों में रंगने के साथ-साथ 'अगुआ'<sup>२</sup> और 'युवक संघों'<sup>३</sup> के दो आंदोलनों के द्वारा भी नौजवानों को तैयार किया जाता है। 'अगुआ' आंदोलन में 'स्काउटों' की तरह सोलह वर्ष तक के बच्चे होते हैं। युवक संघों में तेइस वर्ष तक के नौजवान और युवतिया होती हैं। उन लोगों के झुंड गर्मियों की छुट्टियों में मिल कर पर्यटन करने निकलते हैं, रात को खुले खेतों में सोते हैं, साथ-साथ गाते और नाचते हैं, किसानों को नई-नई बातें बताते हैं, गाँववालों को जा कर तरह-तरह की सहायता देते हैं और स्वयं मार्क्स के विद्वानों का अध्ययन और मनन करते हैं। इन दोनों आंदोलनों के द्वारा नौजवानों में खास कर सामाजिक बुद्धि पैदा करने की कोशिश की जाती है। इन में ही से बहुत-से नौजवान बाद में समष्टिवादी दल के सदस्य हो जाते हैं।

लेनिन के मजबूत हाथों में रह कर, समष्टिवादी दल के तीन लक्षण बन गए थे। एक तो चुन-चुन कर इस दल में सदस्य लिए जाते थे और दिलमिल यत्न करने वालों या अयोग्य आदमियों

को दल में भर कर सख्या बढ़ाने की कमी फिक्र नहीं की जाती थी। दूसरे नियमबद्धता पर सख्ती से श्रमल किया जाता था और सारे रास फैसले दल के मुख्य केंद्र पर ही होते थे। तीसरे केंद्रीकरण के साथ साथ दल के हर सदस्य से हमेशा अधिक से अधिक काम लिया जाता था। लेनिन के बाद भी दल की आज तक यही नीति है। मगर लेनिन के मरने पर कुछ दिन तक लेनिन-पथी और केंद्रीय दल के देवताओं की इतनी पूजा होने लगी थी कि ट्राट्स्की इत्यादि कई प्रख्यात नेताओं में उस का खुल्लमखुल्ला विरोध करना पड़ा। उस विरोध के लिए ट्राट्स्की और उस के कुछ साथियों को तो जलावतनी हो गई, मगर तब से लेनिन पथी नाम दल की सभाओं में विविध प्रश्नों पर चर्चा नहीं रोकी जाती है। अस्तु, अग्रे समष्टिवादी दल के भीतर एक छोटा सा विरोधी दल भी है जो समष्टिवादी दल के भाग्य विधाता देवताओं के प्रस्तावों का जैश का तैरा निगल जाने से पहले उन पर दल में अन्धवी तरह चर्चा और विचार होने पर दल को मजबूर कर देता है। मगर एक बार दल में निश्चय हो जाने पर यह विरोधी समूह भी उन बातों पर ईमानदारी से श्रमल करता है, जिस का वह विरोधी था। अगर विरोधियों में इतनी ईमानदारी और नियमबद्धता न हो, तो किसी दल का काम नहीं चल सकता है। समष्टिवादी सोवियट-सभ में तो ऐसे विरोधियों को ठिकने को जगह नहीं मिल सकती है। बोलशेविक क्रांति के प्रारंभ काल में समष्टिवादी दल में करीब दो लाख सदस्य थे। बाद में उन की सख्या बढ़ते बढ़ते करीब सात लाख हो गई थी। इस सख्या पर पहुँचने के बाद दल में काट छाँट की गई। सन् १९२६ ई० की मर्दमशुमारी के अनुसार सोवियट सभ में करीब सात लाख समष्टिवादी दल के पूरे सदस्य थे, जिन में लगभग ७५ हजार क्रियाशील। उम्मीदवारों इत्यादि को मिला कर कुल दस लाख के लगभग सदस्य थे। दल की ३२,११६ शाखाएँ और ३,०३३ समूह सदस्यों की शिक्षा के लिए खुले हुए थे। दल के ४६,६२१ पूरे सदस्य और ३४,२२२ उम्मीदवार सिर्फ लाल सेना में थे। सदस्यों में अधिकतर कारखानों के मजदूर, किसान, ऊँट इत्यादि और युवक सघों के लोग थे। जनवरी सन् १९२८ में फिर बढ़ कर समष्टिवादी दल में १,३०२,८१४ सदस्य हो गए थे और जनवरी सन् १९३० में उन की सख्या और भी बढ़ कर १८,५२,०६० हो गई थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक साल में करीब डेढ़ लाख नए सदस्य की श्रितत से समष्टिवादी दल की सख्या बढ़ती है, मगर जेसी एक तरफ सदस्यों की बढ़ती होती है वैसी ही दूसरी तरफ से काट-छाँट के द्वारा घटती भी होती रहती है। सन् १९२६ के जाड़े और सन् १९३० की गर्मी के बीच के ही एक काल में १,३१,४८६ सदस्य समष्टिवादी दल से किसी न किसी वजह से निकाल दिए गए थे। दल की केंद्रीय कार्यकारिणी की नियुक्ति की हुई एक कमेटी के सामने उन सदस्यों को जिन के निकालने का प्रस्ताव होता था, हाज़िर हो कर जमान देना होता था कि उन को दल में से क्यों न निकाल दिया जाए। करीब १७२ फीसदी सदस्यों को मध्यमवर्ग-बुद्धि रखने या उस बुद्धि के लोगों से सहानुभूति रखने के लिए निकाल दिया गया था। चार हजार को जारशाही की खुफिया और पुलिस में नौकरी करने की बात छिपाने के लिए निकाल दिया गया

था। लापरवाही और नौकरशाही का व्यवहार करने के लिए १६'४ फी सदी को निकाला गया था। क़रीब नारद हज़ार को रिश्वत जालसाज़ी गरन इत्यादि के इलज़ामों के लिए निकाला गया था। नियम-बद्धता की कमी के लिए २१फ़ी सदी को निकाला गया था, जिन में समुदायी जेतों पर काम न करने के लिए पाँच हज़ार, अनाज न देने के लिए तीन हज़ार, और दल के भीतर दलबंदी करने के लिए डेढ़ हज़ार को निकाला गया था। दल का काम न करने, उदाहरणार्थ चंदा न देने और सभाशा म न आने के लिए, ३६ हज़ार सदस्यों को निकाला गया था। शराबी होने और झिपा और कुटुंबियों से गैर-समष्टिवादी संबंध इत्यादि २०के के दूसरे कारणों के लिए २२६ फ़ी सदी को निकाला गया था। नियम बद्धता और समुदायी तथियत के अमल पर समष्टिवादी दन जितना अधिक, जोर देता है वह एक उदाहरण से साफ़ हो जायगा। एक बार सोवियट सरकार के एन प्रख्यात मंत्री री खी को एक स्टेशन पर पहुँचने में ज़रा देर हो जाने ने रेलगाड़ी पाँच ठू मिनट के लिए रोक ली गई थी। इस बात के लिए उस मंत्री के बड़प्पन का कुछ खयाल न कर के, उस से दल की भरी सभा में जवाब माँगा गया था।

समष्टिवादी दल की केंद्रीय कार्यकारिणी न चुनाव सालाना कांग्रेस में होता है। उस में ७१ सदस्य और ६७ उम्मीदवार होते हैं। यूरोप के दूसरे देशों के राजनीतिक दलों की तरह इस दल का लेनिन की मृत्यु के बाद से कोई ग़ाज़ाफ़दा नेता या अध्यक्ष नहीं होता है। केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की चुनी हुई नौ सदस्यों की एक समिति में नेतृत्व की सारी सत्ता रक्ती जाती है। दल की एक 'संगठन-समित' भी होती है जो दल के अधिकारियों की नियुक्ति की सँभाल रखती है। दूसरी एक 'केंद्रीय नियंत्रण समिति' सरकारी मज़दूर और किसानों की जाँच के विभाग से सहकार कर के सोवियट संघ में नौकरशाही को रोकने और दल के अंदर नियम-बद्धता कायम रखने का प्रयत्न करती है। तीसरी एन समष्टिवादी युवक सभों की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति भी समष्टिवादी दल के संगठन का ही अंग होती है। साल में हजारों सार्वजनिक सभाएँ दल की ओर से की जाती हैं, जिन में लाखों मज़दूर और किसान शरीक होते हैं।

मगर रूस के लोग अधिकतर किसान होने और सदियों तक भारतवर्ष की तरह दबे और कुचले रहने से बड़े दम्बू बन गए हैं। नारशाही के जुल्मों और उस काल की नौकरशाही के तरीक़ों, जिन में सहानुभूति, कल्पना और आम अक्ल को साक्र पर रख कर सिर्फ़ नियमों के बुद्धिहीन पालन ही का खयाल रखा जाता था, वे इतने आदी हो गए हैं कि सरकार के छोटे मोटे जुल्मों के विरुद्ध आवाज़ उठाने या सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी, सहानुभूति और पाबंदी से काम न करने की वह शिकायत करते दिचकते हैं और प्रायः भारतीयों की तरह अपने भाग्य ही को दोष देने लगते हैं। रूसी लोगों का दम्बूपना पाठकों को एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा, समष्टिवादी दन का क्रान्ता मास्को में हो जाने पर लेनिन ने ज़ार के महलों और अमीरों के राजभवनो को खाली कर के उन में मज़दूरों को जा कर रहने का हुक्म निकाला था। मगर मज़दूरों की उन राजभवनों

म जा कर रहने की दिम्मत ही नहा पगी, क्योंकि उन की समझ में नहां आया कि उन राजभवनों में वे गरीब कैसे पुस सकते हैं। तब लेनिन ने सेना भेज कर जबरदस्ती उन लोगों को उन राजभवनों में रक्खा था। इतने दमनू तो रूस के लोग हैं और सोवियट सरकार का इतना टेढ़ा मेढ़ा सगठन है, जिस में एक प्रश्न पर कई अधिकारियां और विभागों का विचार हो कर, इधर उधर जा कर, बड़े चक्कर से विचार होता है। अगर समष्टिवादी-दल प्रजा का ध्यान और प्रजा की दृष्टि सरकार की कार्यवाह्यता पर रगड़ न रखे सोवियट-संघ में ज़ारशाही के ज़माने से भी ऊँची भयंकर नौकर शाही चलने लगे। अस्तु, समष्टिवादी दल की देश भाल के विषय समष्टिवादी समाचार पत्रों में भी एक तरह आम लोगों की तरह तरह की शिकायतों के लिए खास तौर पर रक्खी जाती है। कोई भी रूसी समाजशाही संघ का नागरिक सरकार के किसी भी अधिकारी, विभाग या कार्यवाही की शिकायत समाचार पत्र के पास लिख कर भेज सकता है और वह समाचार पत्र उस शिकायत की जाँच कर फ सही होने पर उस शिकायत को छापता है। सं प्रसार का शिकायत समष्टिवादी और विभिन्न कारखानों के समाचार पत्रों में पत्रों को मिलती हैं। 'उस अधिकारी ने कारखाना में एक मजदूर लड़की से मजदूरी के सिवाय अपना घर का काम भी कराया'। 'कारखाना में कई मशीनें बेकार पड़ी हैं, मशीनों को उड़-चलाना चाहिए'। 'सरकार का अमुक कर लेने का ढंग उचित नहीं है, अमुक ढंग से कर लेना चाहिए'। इत्यादि हजारों शिकायतें और सरकार को आम आदमी की तकलीफों और विचारों के अनुसार मार्ग दिखानेवाली रायें समष्टिवादी समाचार पत्रों में रोज छपती हैं। समष्टिवादी दल के मुख्य पत्र 'प्रान्दा' के ही, सन् १९२७ ई० में, इस प्रकार की शिकायतें लिखानेवाले देश भर में तीन लाख सवाददाता थे। इन लोगों का अखबार की ओर से एक सम्मेलन बुला कर शिकायतों और राय भेजने का ढंग भी तय कर लिया गया था। 'प्रान्दा' का एक खास बड़ा विभाग इस प्रकार के पत्रों को पढ़ने के लिए है और उस विभाग का अध्यक्ष रूस का एक प्रख्यात नौजवान लेखक है, जो स्वयं समष्टिवादी दल का सदस्य भी नहा है। इन शिकायतें भेजने वालों को एक हद तक शिकायतें भेजने की सरकार की तरफ से पूरी आजादी दी गई है। अधिकारी उन पर शिकायतें करने के लिए जुल्म नहीं कर सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी के एक बार अपने खिलाफ शिकायत करने वालों को गुस्से में भर कर जान से मार डालने पर उस अधिकारी पर फल का मुकदमा न चला कर सोवियट सरकार के खिलाफ राज विद्रोह करने के मयकर अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। अस्तु, स्पष्ट है कि सोवियट सरकार प्रजा की शिकायतें सुनने को नितना महत्व देती है। अगर हजारों पत्रों को 'प्रान्दा' में छापना असंभव होता है। इस लिए छद्म छद्म शिकायतों को तो छाप दिया जाता है। बाकी शिकायतों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, जो समय समय पर शिकायतों से सबंध रखने वाले विभागों और संस्थाओं के पास भेज दी जाती है। इस ढंग से 'प्रान्दा' भी सरकार के सामने हर प्रश्न पर सोवियट संघ की प्रजा के विचारों का आईना बराबर रखता रहता है। सरकार प्रजा की शिकायत जान कर उन के दूर करने और प्रजा के विचारों के अनुसार चलने का पूरा प्रयत्न करती है। अस्तु

समाजशाही सोवियट संघ में मज़दूरपेशाशाही या समष्टिवादी दल का निरंकुश राज होने पर भी ग्राम प्रजा की राय का बड़ा खयाल रखा जाता है। लोगों की शिक्षायतों के पर समाचार-पत्रों में बराबर छपते रहने से और उन शिक्षायतों के बराबर दूर होने से रूस के दन्तू लोगों को भी भय न कर के सरकार के खिलाफ शिक्षायतें करने और सरकार की समालोचना करने का प्रोत्साहन मिलता है। साधारण समाचार-पत्रों के अतिरिक्त रूस में दीवारों पर लगाने वाले समाचार-पत्रों की एक नई प्रथा चली है। हर कारखाने, हर संस्था में, जहां मज़दूरपेशा की काफी संख्या काम करती है—यहां तक कि सरकारी दफ्तरों और सैनिकों की वारकों तक में—दीवारों पर एक बड़ा कामज चिपका दिया जाता है, जिस में उस संस्था में काम करने वालों की शिक्षायतें, लेख, चित्र और अभिनयों के संबंध में जुटहुले और व्यंग इत्यादि रहते हैं। इन दीवारी समाचार-पत्रों और उद्योग संघों की तुलनाचीनी और चुनाव की सभाओं के सरकार की नीति से संबंध रखने वाले प्रस्तावों से भी सरकार अर्थात् समष्टिवादी दल को अपनी नीति निर्माण में काफी सहायता मिलती है।

क्रांति के प्रारंभ में समष्टिवादी दल ने बड़ी ही सख्ती और कड़रता से काम लिया था, क्योंकि देशी और विदेशी विरोधियों के चारों तरफ से आक्रमण होने से दल को अपनी सत्ता कायम रखने के लाले पड़ रहे थे। अब तक भी जिस विरोध को समष्टिवादी दल अपनी इसी और समष्टिवादी क्रांति का विरोधी समझता है, उस को निर्दयता से क्रौरन कुचल देता है। मगर फिर भी अब समष्टिवादी दल अपने सिद्धांतों पर कड़रता से चलने के साथ-साथ प्रजा की राय के अनुसार चलने की भी बड़ी फिर रखने लगा है, क्योंकि वह समझता है कि जिस नई दुनिया का वह निर्माण करना चाहता है, उस के बनाने में प्रजा का हाथ और प्रजा की मर्जी की बड़ी जरूरत है। समष्टिवादी दल अब अपने आप को प्रजा का सेरक साबित करने का बड़ा प्रयत्न करता है। दल के कुछ लोग तो समष्टिवादी दल को प्रजा के विचारों को प्रकट करने वाला सिर्फ प्रजा का मुख और प्रजा की इच्छाओं को पूरा करने वाला सिर्फ प्रजा का अंग ही मानते हैं। चुनावों में अधिक से अधिक मतदारों के आ कर खुद अपनी स्वतंत्र मर्जी से समष्टिवादी दल के उम्मीदवारों के लिए मत देने और चुनचाप मत न दे कर अपने विचार प्रकट करने के लिए समष्टिवादी दल बड़ा उत्सुक रहता है। जितने अधिक आदमियों को हो सके, उतने अधिक अधिक आदमियों शासन और सरकारी काम का ज्ञान कराने के लिए नए-नए प्रतिनिधियों का चुनाव भी दल करता रहता है। रूस के समष्टिवादी दल के साधारण सदस्यों को जितना अंतरराष्ट्रीय राजनीति इत्यादि का ज्ञान होता है, उतना हमारे देश के बहुत-से लाट साहब की कौंसिल के सदस्यों तक को नहीं होता है। समष्टिवादी दल के इस चाल पर चलने से धीरे-धीरे रूस में समष्टिवादी दल की निरंकुशता का नाश हो कर एक दिन सभी प्रजासत्ता कायम हो जायगी या नहीं; यह अभी कहना बड़ा मुश्किल है। आजकल की रूसी समाजशाही सरकार में प्रजा की एक प्रकार से उतनी ही आवाज है, जितनी हमारे देश में शायद प्रजावत्सल 'अशोक' इत्यादि जैसे राजाओं

के राज्य में प्रजा की आवाज़ शासन में होती थी, मगर समाजशाही सोवियट संघ और समष्टिवादी दल दोनों ही राजनीति सभार की एक नई चीज़ हैं और उन का किसी से मुकाबला करना बड़ा कठिन है। दुनिया में समाजशाही सोवियट-संघ ही एक भ्रमजीवियों का प्रजातंत्र है।

## फिनलैंड की सरकार

### राज-व्यवस्था

सन् १८०९ ई० में फिनलैंड के स्वीडन से अलग हो कर रूस साम्राज्य में मिल जाने पर रूस के शहंशाह जार ने फिनलैंड को एक राज-व्यवस्था दी थी। इस राज व्यवस्था के अनुसार फिनलैंड को भीतरी शासन में पूरी स्वाधीनता दी गई थी। सिर्फ बाहरी देशों के लिए वह एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। सन् १८६९ ई० के एक कानून के अनुसार फिनलैंड की व्यवस्थापक-सभाओं की बैठकों का समय निश्चित किया गया था और सन् १९०६ ई० के एक दूसरे कानून के अनुसार सरकार की सारी सत्ता एक व्यवस्थापक-सभा को दे दी गई थी, जिस की बैठकें सालाना होती थीं। बाद में रूस ने फिनलैंड की सारी स्वाधीनता नष्ट कर के, उस को अपना निरा गुलाम बना कर रखने की नीति अख्तियार की, और फिनलैंड के लोगों ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ना शुरू किया। पिछले यूरोपीय युद्ध तक यही परिस्थिति कायम रही। रूस में क्रांति होते ही फिनलैंड को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देने का मौका मिल गया और जातीय स्वाधीनता की दुहाई देने वाले बोल्शेविक रूस ने सन् १९१८ ई० में फिनलैंड को एक स्वाधीन राष्ट्र मान लिया। फिनलैंड की व्यवस्थापक-सभा ने अस्थायी तौर पर राजा के सारे अधिकारों पर अपना कब्जा मान कर सिनेट के अध्यक्ष को प्रभुता चलाने का अधिकार दे दिया था। १२ दिसंबर, सन् १९१८ ई० को मेनरहीम को फिनलैंड का राज्याधिकारी भी चुन लिया गया था। मार्च, सन् १९१९ ई० के चुनाव के बाद फिनलैंड को प्रजातंत्र घोषित कर के जून में प्रोफेसर स्टालवर्ग को फिनलैंड प्रजातंत्र

का प्रमुख चुन लिया गया। इस राज-व्यवस्था में फिनलैंड के नागरिकों को कानून के सामने बराबर माना गया है और उन की ज़िदगी, उन की आरु, उन की व्यक्तिगत आजादी, उन की माल और मिलकियत, उन के धार्मिक निश्वासों, अख्तारी आजादी और मिलने-जुलने की आजादी को सुरक्षित माना गया है। फिनिश और स्वीडिश भाषाएँ प्रजातंत्र की राष्ट्रीय भाषाएँ मानी गई हैं।

**प्रजातंत्र का प्रमुख**—फिनलैंड प्रजातंत्र के प्रमुख को तीन सौ चुने हुए मतदार चुनते हैं, जिन को प्रजा उन्नी तरह चुनती है, जिन तरह व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को। प्रजातंत्र का प्रमुख राजनैतिक अर्थ में व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार नहीं होता है। मगर उस को कार्यकारिणी का सारा अधिकार माना गया है। कानून बनाने की सत्ता व्यवस्थापक-सभा और प्रमुख दोनों में मानी गई है। दोनों को कानूनों का प्रस्ताव करने का हक होता है। व्यवस्थापक-सभा में मजूर हो जाने के बाद कानून प्रमुख की मजूरी के लिए रखे जाते हैं और उसे उन को नामजूर कर देने का हक होता है। अगर तीन महीने के अंदर प्रमुख किसी कानून को मजूर नहीं करता है तो उस कानून को नामजूर समझा जाता है। परंतु व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव हो जाने के बाद भी अगर सभा उसी कानून को फिर जैसा का तैसा पास करती है तो प्रमुख की नामजुरी होने पर भी वह कानून अमल में आ जाता है।

प्रमुख को खास मौकों पर फरमानी कानून जारी करने, व्यवस्थापक सभा को खास बैठकें बुलाने, व्यवस्थापक-सभा को भंग कर के नया चुनाव कराने, अपराधियों को क्षमा करने, और विदेशियों को फिनलैंड का नागरिक बनाने के अधिकार भी होते हैं। प्रमुख ही फिनलैंड की तरफ से दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करता है और वही राष्ट्र की सारी सेनाओं का सेनाधिपति होता है। सेना सब्धी बातों को छोड़ कर और सारे निश्चय प्रमुख कौंसिल ऑफ़ स्टेट की सलाह से करता है।

**कौंसिल ऑफ़ स्टेट**—सरकार का काम चलाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दस मंत्रियों की एक कौंसिल ऑफ़ स्टेट होती है, जिस को प्रमुख नियुक्त करता है। यह मंत्री सम्मिलित रूप से मंत्रि मंडल की आम नीति के लिए और अलग अलग अपने विभागों के काम के लिए व्यवस्थापक सभा को जवाबदार होते हैं। उन का जीवन सभा के उन में निश्वास पर निर्भर होता है। प्रजातंत्र का प्रमुख, बिना विभाग के दो मंत्रियों को भी कौंसिल में रख सकता है। कौंसिल पर देर रस रखने के लिए व्यवस्थापक-सभा 'चांसलर ऑफ़ जस्टिस' नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करती है, जिस का काम यह देखना होता है कि देश के कानूनों के अनुसार अमल होता है या नहीं। कौंसिल या किसी मंत्री का कोई काम उस की राय से गैरकानूनी होने पर वह उस की शिकायत फौरन प्रमुख और व्यवस्थापक सभा से करता है। इस ढंग से मंत्रियों की राजनैतिक और कानूनी दोनों तरह से जवाबदारी रहती है।

**व्यवस्थापक-सभा**—फिनलैंड की व्यवस्थापक सभा सिर्फ एक सभा की होती



है। उस में दो सौ सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात निर्वाचन की पद्धति से चौसीस वर्ष के ऊपर के सब मताधिकार प्राप्त स्त्री और पुरुष नागरिक तीन साल के लिए चुनते हैं। निम्ना किसी मुलावे के अपने निश्चित समय पर हर साल सभा की बैठक जुड़ती है। ग्राम और पर उस की बैठकें १२० दिन तक होती हैं। मगर सभा अपनी बैठकों के दिनों की संख्या अपनी मर्जी से घटा उठा भी सकती है। सभा के एक तिहाई सदस्यों का विरोध होने पर साधारण मामलों का विचार सभा के दूसरे चुनाव के बाद तब के लिए स्थगित कर दिया जा सकता है। राज व्यवस्था से संबंध रखनेवाले मामलों पर विचार भी व्यवस्थापक सभा ही करती है। मगर उन के पास होने के लिए मतों की खास संख्याओं की जरूरत होती है। आय व्यय संबंधी मामलों का फैसला भी व्यवस्थापक-सभा करती है।

सरकारी शासन की बहुत हद तक देख-रेख करने का काम सभा का होता है और सरकार अपने शासन कार्य का सालाना विज्ञापन और जरूरत पड़ने पर खास कामों का विज्ञापन व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश करती है। 'वांसलर ऑफ् जस्टिस' भी सभा के सामने 'कौंसिल ऑफ् स्टेट' की कार्यवाही पर एक सालाना विज्ञापन पेश करता है। सभा के चुने हुए पाँच 'हिसान परीक्षक' सरकार के आय व्यय का सालाना विज्ञापन सभा के सामने रखते हैं। व्यवस्थापक-सभा सालाना एक बजट को भी नियुक्त करती है, जो साधारण कानूनों के पालन पर नजर रखता है और सालाना रिपोर्ट सभा के सामने रखता है। व्यवस्थापक सभा को सरकार से उस के कामों के बारे में पूछ-ताछ करने का हक होता है और यह 'कौंसिल ऑफ् स्टेट' के किसी सदस्य और 'वांसलर ऑफ् जस्टिस' पर कानूनों के अनुसार कर्तव्य न करने के लिए अभियोग तक चला सकती है। इस प्रकार के अभियोग बारह सदस्यों की एक 'राष्ट्रीय अदालत' के सामने आते हैं, जिस के आगे सदस्यों की तीन साल के लिए व्यवस्थापक सभा चुनती है।

**राजनैतिक दल**—फिनलैंड के राजनैतिक दलों में एक 'कृषि और किसान दल' है जो फिनलैंड के कृषि और राष्ट्रीय हितों का दल है। दूसरा एक अन्य यूरोपीय देशों की तरह 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' है। तीसरा एक 'संयुक्त दल' नाम का दल है जिस में तग और नरम विचारों के लोग हैं। चौथा 'स्वीडिश लोकदल' है जो फिनलैंड की दसवीं सदी आगदी वाले स्वीडिश भाषा भाषियों का दल है। पाँचवा उदार विचार के लोगों का एक 'प्रगतिशील दल' है। छठा एक 'समझौताहीन दल' है जिस को गैर कानूनी फरार दे दिया गया है। इन दलों की फिनलैंड की व्यवस्थापक सभा में सन् १९३० ई० में इस प्रकार शक्ति थी :—

दल	सदस्यों की संख्या	दल	सदस्यों की संख्या
कृषि और किसान दल	५६	स्वीडिश लोकदल	२१
समाजी प्रजासत्तात्मक दल	६६	प्रगतिशील दल	१२
गणक दल	४२	समझौताहीन दल	०

## ऐस्थोनिया की सरकार

फिनलैंड के लोगों से मिलते-जुलते ही ऐस्थोनिया के लोग हैं और फिनलैंड की तरह ही ऐस्थोनिया भी रूस की क्रांति होने तक रूस के आधीन था। तेरहवीं सदी में टिपूटोनिक जाति के 'तेग बहादुर सरदारों के समाज'<sup>१</sup> का आधा ऐस्थोनिया पर अधिकार था और शेष आधे देश पर, डेन लोगों का अधिकार था। करीब सौ वर्ष के बाद डेन लोगों से ऐस्थोनिया का आधा उत्तरी भाग जर्मनों ने खरीद लिया था और उस को लिवोनिया अर्थात् आज कल के लेटविया से मिला दिया था। 'तेग बहादुर सरदार समाज' नष्ट हो जाने पर शेष आधा भाग भी स्वीडन और पोलैंड में बँट गया था। बाद में सन् १६३६ ई० में स्वीडन का आज कल के ऐस्थोनिया के सारे भाग पर अधिकार हो गया था। फिर सन् १७२१ ई० में स्वीडन ने ऐस्थोनिया रूस को इस शर्त पर दे दिया था कि रूस ऐस्थोनिया में एक अलग राज-व्यवस्था कायम करेगा। तब से रूस की राज क्रांति तक ऐस्थोनिया रूस के अधिकार में था।

ऐस्थोनिया रूस का जल मार्ग होने से रूस के व्यापार के लिए बड़ा जरूरी था। जर्मनी और रूस के व्यापार का मार्ग ऐस्थोनिया ही था। दो सौ वर्ष तक, जब तक ऐस्थोनिया रूस साम्राज्य का प्रांत रहा, ऐस्थोनिया में एक स्थानिक धारासभा रहने पर भी अधिकार और सत्ता रूसी अधिकारियों और पुराने व्यवसायिक सरदारों के वंशज जमींदारों के हाथ में ही रही। देश के ६५ फी सदी लोग ऐस्थोनियन होने पर भी लोगों को शिक्षा रूसी और जर्मन भाषाओं में ही लेनी पड़ती थी। सन् १९०५ में रूसी क्रान्ति के लिए ऐस्थोनिया के लोगों ने सिर्फ अपनी जाति के लोगों को ही चुन कर पहले-पहल

<sup>१</sup> टिपूटोनिक आर्दर आफ़ दी माह्ट्स आफ़ दी सोट्स ।

अपनी हस्ती पर जोर दिया था। ऐस्थोनिया के इन प्रतिनिधियों ने उस समय सिर्फ़ रूसी साम्राज्य के अंतर्गत ऐस्थोनिया के लिए स्थानिक स्वाधीनता की ही हूमा में माँग रखी थी। मगर बाद में रूस में राज्यक्रांति हो जाने पर जुलाई सन् १९१७ में ऐस्थोनिया के नेताओं ने ऐस्थोनिया में एक राष्ट्रीय सरकार कायम हो जाने का एलान कर दिया था।

ऐस्थोनिया के नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए व्यवस्थापक-सम्मेलन कायम होने तक एक काम-चलाऊ सरकार कायम कर ली गई थी। इस काम-चलाऊ सरकार को बड़े भयंकर संकटों का सामना करना पड़ा। पहले तो बोलशेविक रुस की सेनाओं ने ऐस्थोनिया को घेर दबाया और फिर ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि के अनुसार ऐस्थोनिया में जर्मनी की सेनाओं ने जा कर अड्डा जमा लिया था जिस से मिटते हुए जर्मन ज़मींदारों का राज्य फिर से कायम हो गया था। मगर जर्मनी की हार होते ही ऐस्थोनिया के बंधन टूट गए। अप्रैल सन् १९१९ ई० में १२६ सदस्यों के एक 'राष्ट्रीय व्यवस्थापक सम्मेलन' का सारे नागरिकों के मतों से चुनाव हुआ। इस सम्मेलन ने ऐस्थोनिया को १६ मई को बाक्लायदा एक स्वाधीन प्रजातंत्र राष्ट्र एलान कर के; स्थायी राज-व्यवस्था बनने तक ऐस्थोनिया में एक काम-चलाऊ राज-व्यवस्था जारी कर दी। एक तरफ़ तो यह नई सरकार जर्मनी और रूस का मुकाबला करने, पड़ोसी राष्ट्रों को मदद करने, और उन से संधियाँ करने, तथा देश में सब प्रकार से सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करती रही और दूसरी तरफ़ नए राष्ट्र को नई राज-व्यवस्था रचती रही। आखिरकार नई राज-व्यवस्था बन कर १५ जून सन् १९२० ई० को सम्मेलन में मंज़ूर हुई और दिसंबर में सम्मेलन अपना काम पूरा कर के भंग भी हो गया। बाद में ऐस्थोनिया की पहली राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा का नवंबर १९२० में चुनाव हुआ और ४ जनवरी सन् १९२१ को उस की बैठक हुई।

ऐस्थोनिया प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था बड़ी सीधी-सादी और छोटी-सी है। एक सभा की एक छोटी-सी व्यवस्थापक-सभा में कानून बनाने की सत्ता रखी गई है। व्यवस्थापक-सभा ही कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अदालत के न्यायधीशों को चुनती है। प्रजा को प्रस्तावना और ह्वाले का अधिकार दे कर व्यवस्थापक-सभा पर प्रजा का अंकुश और व्यवस्थापक-सभा के द्वारा कार्यकारिणी और न्यायसत्ता पर प्रजा की हुक्मत रखने का साफ़ तौर पर इस राज-व्यवस्था में प्रबंध रखा गया है। सारे नागरिकों के लिए राष्ट्र की रक्षा में भाग लेना भी इस राज-व्यवस्था में अनिवार्य रखा गया है।

**व्यवस्थापक-सभा**—ऐस्थोनिया की एक सभा की व्यवस्थापक-सभा को 'रिज़ीकोगू' कहते हैं। इस में सौ सदस्य होते हैं, जिन को तीन साल के लिए अनुपात निर्वाचन की पद्धति से ऐस्थोनिया के २१ वर्ष से ऊपर के सारे मताधिकारी नागरिक चुनते हैं। यह सभा अपने अध्यक्ष और अधिकारियों का खुद चुनाव करती, कानून बनाती, राष्ट्र की धाय-व्यय तय करती और राष्ट्रीय शासन की देख-रेख करती है। सभा का काम चलाने के लिए कम से कम ५० सदस्यों की हाजिरी की जरूरत होती है। सभा

के एक तिहाई सदस्यों की माँग पर किसी भी मंजूर हो जानेवाले कानून पर दो मास लिए श्रमज स्थगित किया जा सकता है। इस दो मास के भीतर पचीस हजार मताधिकारी नागरिकों की माँग पर, उस कानून पर, प्रजा का हवाला लिया जा सकता और फिर उस कानून का मंजूर होना या नामंजूर होना प्रजा के मत पर निर्भर जाता है।

**कार्यकारिणी**—राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा कार्यकारिणी को नियुक्त कर है और कार्यकारिणी व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होती है। कार्यकारिणी के सदस्य में एक राष्ट्रपति और सात मंत्री होते हैं। कार्यकारिणी राष्ट्रीय नृजट तैयार कर के व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश करती, विदेशों से संधियाँ करती और उन को आखिरी मंजूरी के लिए सभा के सामने रखती और सभा के निश्चय के अनुसार युद्ध और संधि की घोषणा करती है। राष्ट्रपति को प्रजातंत्र का प्रतिनिधि-स्वरूप माना जाता है और उसमें व्यवस्थापक सभा का विश्वास कायम रहने की ज़रूरत होती है।

**राजनैतिक दलबंदी**—ऐस्थोनिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'कृषि संघ दल' नाम का किसानों का दल है। दूसरा 'ईसाई लोकदल' है, जो स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने का पक्षपाती है। तिसरा ऐस्थोनिया में आ कर बस जानेवालों का एक 'प्रवासी और पट्टेदारों का दल' है। चौथा गरम प्रजासत्तात्मक विचार के लोगों का एक 'लोकदल' है। पाँचवा गरम समाजी विचारों का एक 'गरम दल' है। छठा इंगलैंड से मजदूर दल से मिलता-जुलता एक 'समाजी मजदूर दल' है। इन दलों की १९२६-२७ की व्यवस्थापक-सभा में इस प्रकार ताकत थी :—

दल	सदस्यों की संख्या	दल	सदस्यों की संख्या
समाजी दल	२५	मजदूर दल	६
कृषि-संघ दल	२४	ईसाई लोकदल	४
प्रवासी और पट्टेदारों का दल	१४	रूसी राष्ट्रीय दल	२
गरम दल	१०	जर्मन बाल्टिक दल	३
लोकदल	६	मकान मालिकान-संघ	३

## लिथूनिया की सरकार

**राज-व्यवस्था**—ऐस्थोनिया की तरह लिथूनिया भी रूस और जर्मनी की अधीनता में रह कर, बहुत दिनों तक गुलाम और बंटा रहने के बाद, आखिरकार रूस की राज्य-क्रांति के बाद फरवरी सन् १९१८ ई० में स्वतन्त्र राष्ट्र बना था। लिथूनिया के राजनैतिक नेताओं की एक सभा के लिथूनिया को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर देने के बाद एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक सम्मेलन की रचना की गई थी, जिस की रनी हुई राज व्यवस्था पर पहली अगस्त सन् १९२२ ई० से अमल शुरू हुआ था और जिस में बाद में सन् १९२८ ई० में संशोधन किया गया था। इस राज व्यवस्था के अनुसार लिथूनिया एक स्वतन्त्र प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र है, जिस में प्रभुता प्रजा की मानी गई है। प्रजा को अपने प्रति निधियों की व्यवस्थापक-सभा के द्वारा हुक्म करने के अतिरिक्त, पच्चीस हजार मतदारों के हस्ताक्षरों से व्यवस्थापक सभा के विचार के लिए मसविदे पेश करने का अधिकार भी दिया गया है। राज व्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव 'सीमास' या सरकार या पचास हजार नागरिकों की तरफ से पेश किए जा सकते हैं। उन की मजूरी के लिए सीमास के ३ सदस्यों की सलाह के मतों की जरूरत होती है और इस मजूरी के तीन मास के भीतर, प्रजातन्त्र के प्रमुख या पचास हजार नागरिकों की माँग आने पर, उस संशोधन पर प्रजा का हवाला लिया जाता है। हवाले की माँग न आने पर तीन मास खत्म हो जाने पर संशोधन कानून बन जाता है।

**व्यवस्थापक-सभा**—इस देश की व्यवस्थापक-सभा को 'सीमास' कहते हैं जिस की सिर्फ एक ही सभा होती है। इस सभा में करीब ५० सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात निर्वाचन की पद्धति से पाँच साल के लिए, पच्चीस वर्ष के उमर के लिथूनिया के

[ २८६ ]

सारे स्त्री और पुरुष नागरिक चुनते हैं। सभा के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिए और एक सभा का काल पूरा होने से पहले ही दूसरी सभा का चुनाव हो जाना चाहिए। 'सीमास' को लिथुनिया की लिखित राज-व्यवस्था के विरुद्ध कोई कानून पास करने का अधिकार नहीं है और उस के मज़ूर या नामज़ूर किए हुए कानून के खिलाफ़ प्रजा से हवाले द्वारा, अपील भी की जा सकती है। 'सीमास' और प्रजासत्तात्मक देशों की व्यवस्थापक सभाओं की तरह हाज़ून बनाती, राष्ट्रीय उन्नत मज़ूर करती और देश के शासन की देखभाल करती है। सीमास की मजूरी के बाद ही लिथुनिया प्रजातन्त्र का प्रमुख दूसरे राष्ट्रों से संधियां कर सकता है। युद्ध और संधि की घोषणा भी सीमास खुद करती है, मगर एकदम सकट पड़ा हो जाने पर प्रमुख और मन्त्रिमंडल को आवश्यक कृतानुसार कार्रवाई करने का अधिकार होता है। सीमास की आमतौर पर साल भर में दो बार बैठकें होती हैं और प्रमुख या सदस्यों की इस सभा की माँग पर उस की सात बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। नए कानूनों को देखने और उन के मसविदे तैयार करने तथा प्रचलित कानूनों को नवीकर करने के लिए एक स्टेट काउंसिल भी है।

**कार्यकारिणी**—प्रजातन्त्र के प्रमुख और मन्त्रिमंडल के हाथ में राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता होती है। सीमास के बनाए हुए कानून के तरीके के अनुसार प्रजा के खास तौर पर चुने हुए प्रतिनिधि, प्रजातन्त्र के प्रमुख को सात वर्ष के लिए चुनते हैं। प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार चालीस वर्ष से कम उम्र के नहीं हो सकते हैं और न उन का दो बार से अधिक इस पद के लिए चुनाव हो सकता है। प्रमुख 'राष्ट्रीय नियन्त्रक' और प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री के चुने हुए मन्त्रिमंडल को मज़ूर करता है। 'राष्ट्रीय नियन्त्रक' का लिथुनिया की सरकार में करीब करीब वही काम होता है जो इंग्लैंड की सरकार में कंट्रोलर जनरल और ऑडिटर जनरल का होता है। राष्ट्रीय नियन्त्रक और मन्त्रिमंडल तभी तक पद पर रह सकते हैं, जब तक सीमास का उन पर विश्वास रहता है। राष्ट्रीय नियन्त्रक को मन्त्रिमंडल की बैठकों में बैठने और उन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। सीमास में मज़ूर हो जाने के बाद कानूनों को प्रमुख एक महीने के अंदर जारी कर देता है, मगर इस समय के भीतर ही, अपनी राय के साथ किसी कानून को सीमास के पास पुनः विचार के लिए लौटा देने का भी उस को हक होता है। इस प्रकार पुनः विचार के लिए लौटाए कानून को सीमास के दो तिहाई मतों से फिर मज़ूर करने पर प्रमुख उस कानून को जारी करने के लिए मज़बूर हो जाता है। प्रजातन्त्र के प्रमुख को सीमास भंग करने और सीमास की बैठकें न होने के समय में कानून जारी करने का भी अधिकार होता है और यह कानून सीमास द्वारा न बदले जाने तक वाक्यावदा माने जाते हैं। प्रजातन्त्र का प्रमुख मन्त्रिमंडल के अध्यक्षस्थान पर बैठ कर मन्त्रिमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, और उस के माँगने पर हर एक मंत्री को उस के सामने रिपोर्ट रखनी होती है। प्रजातन्त्र

का प्रमुख ही प्रजापति की सारी सेना का सेनापति होता है। मन्त्रिमंडल के सदस्य सम्मिलित तौर से और अलग अलग सरकार की सारी कार्रवाई के लिए व्यवस्थापक सभा को जवाबदार होने हैं।

**राजनैतिक दलबंदी**—इस नए राष्ट्र के कायम होने से आज तक इस देश की राजनैतिक हालत बराबर डाँवाडोल रही है। मजबूत राजनैतिक दल न होने से सरकारें जल्दी-जल्दी बनती और गिरती रहती रहती हैं। सन् १९२६ ई० में कर्नल ग्लोभास्टकी ने सेना की सहायता से उस समय में मन्त्रिमंडल को उलट दिया था। उस के बाद भी एक प्रधान मंत्री को फिर कत्न करने का प्रयत्न किया गया था।

लियूनिया के मुख्य राजनैतिक दलों में 'ईसाई प्रजासत्तात्मक सघ' नामक एक नरम दल है। दूसरा एक 'उदार दल' है, जिस के सन् १९३१ ई० की सीमास में २२ सदस्य थे। इस दल में ईसाई प्रजासत्तात्मक, कृषि सघ और मजदूर सघ तीन छोटे-छोटे दल शामिल हैं और सन् १९३१ की सीमास में कुल मिलाकर इस दल के तीस सदस्य थे। दूसरे दो 'राष्ट्रीय दल' और 'पौपुलिस्ट' नाम के छोटे-छोटे दल हैं। यूरोप के अन्य देशों की तरह एक 'समाज प्रजासत्तात्मक दल' भी है, जिस के सीमास में १५ सदस्य थे। एक 'अल्प सख्याओं का दल' भी है, जिस के कुल मिलाकर १३ सदस्य

## लटविया की सरकार

सन् १७७२ ई० में लटविया का एक भाग पहले-पहल रूस को मिला था और सन् १७९५ ई० में शेष भाग पर भी उस का अधिकार हो गया था। इस समय से रूस की राज्यक्रांति होने तक इस देश पर ऐस्थोनिया और लिथुनिया की तरह रूस का अधिकार था। सन् १९१७ ई० में पहले-पहल लटविया के जनमत ने लटविया को एक स्वाधीन राष्ट्र बनाने की आवाज उठाई थी और बाद में जनवरी, सन् १९१८ ई० में रूस के व्यवस्थापक सम्मेलन के सामने यह माँग रखी गई थी। लटविया को एक स्वाधीन राष्ट्र बनाने के लिए एक सगठन कायम कर लिया गया था जिस ने १८ नवंबर, सन् १९१८ ई० में रीगा में लटविया के स्वाधीन राष्ट्र बन जाने का आखिरकार एलान कर दिया था। नए राष्ट्र की राज व्यवस्था गढ़ने के लिए एक व्यवस्थापक-सम्मेलन बना लिया गया था, जिस ने १५ फरवरी, सन् १९२२ ई० को आखिरी सूरत में राज व्यवस्था को मजूर किया था। इस राज-व्यवस्था के अनुसार लटविया एक स्वाधीन और प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र है। जिस में प्रमुख प्रजा को है। सब नागरिकों को कानून की सजर में बराबर अधिकार है और अल्प संख्यक जातियों के आतीय और धार्मिक अधिकारों को राज व्यवस्था में सुरक्षित माना है।

**व्यवस्थापक-समा**—लटविया की व्यवस्थापक-समा को 'साइमा' कहते हैं। इस में सौ सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात निर्वाचन की पद्धति से तीन साल के लिए, इक्कीस वर्ष के ऊपर के सब स्त्री पुरुष नागरिक चुनते हैं। 'साइमा' राष्ट्र के कानून बनाने और शासन की देख-रेख का सारा काम करती है। वही सारे सदस्यों के बहुमत से प्रजातंत्र के प्रमुख को भी चुनती है।



**कार्यकारिणी**—प्रजातन्त्र का प्रमुख तीन साल के लिए चुना जाता है। उस की उम्र कम से कम चालीस वर्ष की होनी चाहिए और छः साल से अधिक लगातार कोई प्रमुख नहीं रह सकता है। प्रमुख प्रजातन्त्र की सारी सेनाओं का सेनाधिपति भी होता है। परन्तु युद्ध छिड़ने पर वह एक सेनापति की नियुक्ति कर देता है। वही प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री नौ सदस्यों का एक ऐसा मन्त्रिमण्डल नियुक्त करता है जिस पर 'साइमा' का विश्वास होता है। 'साइमा' की मजूरी से प्रमुख युद्ध की घोषणा कर सकता है। प्रमुख 'साइमा' और मन्त्रिमण्डल में सन्धि हो जाने पर प्रमुख को 'साइमा' को भग करने का प्रस्ताव करने का हक होता है। मगर इस प्रस्ताव की मजूरी के लिए, प्रजा के मत लिए जाते हैं और प्रजा का मत प्रमुख के प्रस्ताव के विरुद्ध होने पर प्रमुख को इस्तीफा रख देना होता है। प्रमुख के इस प्रकार इस्तीफा देने पर 'साइमा' कौरन ही बैठ कर नए प्रमुख का चुनाव कर लेती है। प्रजा का मत प्रमुख के प्रस्ताव के पक्ष में होने पर 'साइमा' भग कर दी जाती है और नया चुनाव किया जाता है।

**राजनैतिक दलबंदी**—'समाजवादी दल' लटविया का सन से बड़ा राज-नैतिक दल है। सन् १९३१ ई० में साइमा में करीब एक तिहाई सदस्य इसी दल के थे। फिर भी गाकी सदस्य कई छोटे छोटे दलों के होने से मन्त्रिमण्डलों को बनाने में परानर कठिनाई रहती है।

लटविया के दूसरे राजनैतिक दलों की 'संघ' में मुख्य एक 'गरम' मध्य-संघ' है जिस के कुल ११ सदस्य व्यवस्थापक-सभा में थे। एक 'किसान संघ' है जिस के कुल २६ सदस्य थे। एक 'राष्ट्रीय संघ' है जिस के कुल ८ सदस्य थे। एक 'श्रम-संघ' जातियों की संघ' है जिस के कुल १८ सदस्य थे। इन दल-संघों में निम्न प्रकार दल और सदस्य सन् १९३१ ई० की साइमा में थे :—

**'समाजी प्रजासत्तात्मक दलसंघ' : कुल ३६ सदस्य**

समाजी प्रजासत्तात्मक दल	२६ सदस्य
सन्तान समाजवादी दल	१ "
लटगालियन समाजी किसान-दल	१ "
गरम मजदूर संघ दल	६ "
समाजी प्रजासत्तात्मक मेशेवकी दल	२ "

**'गरम मध्य-दलसंघ' : कुल ११ सदस्य**

प्रजा सत्तात्मक मध्य दल	३ सदस्य
लटगालियन प्रगतिशील दल	३ "
मजदूर संघदल	३ "
अन्य	२ "

**'किसान-दलसंघ' : कुल २६ सदस्य**

किसान संघदल	१६ सदस्य
-------------	----------

नए किसान और छोटे किसानों का संघदल	४ ”
लटगालियन प्रजासत्तात्मक किसान दल	३ ”
लटगालियन ईसाई किसान दल	३ ”

( नरम ) 'राष्ट्रीय दल संघ' : कुल ८ सदस्य

राष्ट्रीय मध्य दल	३ सदस्य
ईसाई राष्ट्रीय दल	४ ”
मरान मालिक दल	१ ”

अल्प संख्या दलसंघ : कुल १८ सदस्य

जर्मन दल	६ सदस्य
सनातनी रूसी दल	२ ”
पुराने विश्वासियों का दल	२ ”
नरम प्रगतिशील रूसी दल	२ ”
आगडास इसराईल यहूदी दल	२ ”
मिसराखी यहूदी दल	१ ”
पोलिश दल	२ ”
अन्य	१ ”

इन दलों के अतिरिक्त बियों की एक 'राष्ट्रीय स्त्री-संघ' भी है ।

---

# आस्ट्रिया और हंगरी की सरकार

## पुरानी द्वाजाशाही

दूसरा एक साम्राज्य जिस के पिल्लू यूरोप की लड़ाई में अंग-भंग हो गए, रूस के दक्षिण का आस्ट्रिया-हंगरी का साम्राज्य था। इस साम्राज्य में जर्मन, हंगारियन, क्रोट्स, स्लोवेंस् और इटेलियन जातियों के लोग रहते थे, जो एक दूसरे से विलकुल भिन्न थे और अपनी-अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। साम्राज्य की राज-व्यवस्था भी, जैसा एक लेखक ने लिखा है—दुनिया के राजनैतिक अजायबघर की एक अजीब चीज थी। आस्ट्रिया और हंगरी दो देशों की राजशाही की मिल कर आस्ट्रिया-हंगरी में द्वाजाशाही थी। दोनों देश आपस के एक समझौते के अनुसार स्वतंत्र थे। हर एक की अलग-अलग राज-व्यवस्था, अलग-अलग व्यवस्थापक-सभाएं, मंत्री और अदालतें थीं। भीतरी शासन में दोनों देशों का पूरी स्वतंत्रता थी। एक को दूसरे के भीतरी काम-काज में दखल देने का हक नहीं था। मगर साम्राज्य का शासन दोनों देश मिल कर करते थे। दोनों का एक ही राजा था एक भंडा था, एक नागरिकता थी और दोनों के प्रतिनिधियों के मिल कर साम्राज्य का शासन चलाने के लिए एक ही संस्था थी। इस प्रबंध के दो देशों की सघ भी मामूली अर्थ में नहीं कह सकते हैं। आस्ट्रिया-हंगरी की इस द्वाजाशाही की राज-व्यवस्था के सन् १९१८ ई० तक तीन अंग थे। एक आस्ट्रिया की राज-व्यवस्था, दूसरा हंगरी की राज-व्यवस्था और तीसरा दोनों देशों के साम्बेदारी की शर्तों के कानून थे।

आस्ट्रिया की राज व्यवस्था में शहंशाह को मौजूबी तौर पर कार्यकारिणी का मुख्य माना गया था। शहंशाह के द्वारा एक मंत्रिमंडल के नियुक्त किए जाने की भी योजना थी। सन् १८६७ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के अनुसार शहंशाह के हर हुक्म

पर किसी न किसी मंत्री के दस्तखत की वंद भी रखी गई थी। मगर मंत्री व्यवस्थापक सभा को जवाबदार नहीं होते थे। धीरे धीरे मंत्रियों की व्यवस्थापक सभा को जवाबदारी की प्रथा भी पड़ी। मगर फिर भी आस्ट्रिया की व्यवस्थापक सभा के राजनैतिक-दलों के शासन के झगड़ों के कारण शहशाह को अपने हाथ में ताकत रखने का हमेशा मौका रहता था और वही अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करता था। इन मंत्रियों के प्राधीन एक जरूरतस्त नौकरशाही होती थी और इस लिए उन की पुरानी आस्ट्रिया में बनी ताकत होती थी। सन् १८२७ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के अनुसार आस्ट्रिया में दो सभाओं की एक व्यवस्थापक-सभा भी कायम की गई थी। इंग्लैंड की तरह एक सभा 'हाउस ऑफ़ पीयर्स' कहलाती थी जिस में मौलसी लार्ड्स, जेड पादरी,<sup>१</sup> और कुछ शहशाह के नियुक्त किए हुए सदस्य होते थे। नियुक्त किए हुए सदस्यों को रात में सख्या पढ़नी गई और उन का 'हाउस ऑफ़ पीयर्स' में सत्र से बड़ा रुद्ध बन गया था। दूसरी सभा में जिस को 'प्रतिनिधि सभा' कहते थे—पहले प्रांतिक प्रांत सभायां से चुन कर सदस्य आते थे। बाद में 'प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्रजा को दे दिया गया था। मगर सन् १८०७ ई० तक इन सदस्यों को चुनने का अधिकार, कर देने के अनुसार विभाजित, प्रजा के पाँच भागों का था। प्रत्येक भाग को प्रतिनिधियों की एक ख़ास सख्या चुनने का अधिकार था। सन् १८०७ ई० में इस प्रणाली व्यवस्था को तोड़ कर सत्र मनों को मत अधिकार दे दिया गया और सदस्यों का सख्या में भी फेर-फार किया गया। व्यवस्थापक सभा की दोनों सभायां को लगभग एक से ही अधिकार थे। सिर्फ़ रूपरेखा और अनिवार्य सेनिक सेवा से सत्र रखनेवाले मंसबिदों की पहली प्रतिनिधि-सभा में शुरू होने की केंद ज़रूरत थी। हर एक कानून को पास होने के लिए दोनों सभायां की स्वीकृति आवश्यक होती थी। मगर रूपरेखा से सत्र रखनेवाले मंसबिदों पर दोनों सभायां में मतभेद होने पर जिस सभा से क्रम सराया का प्रस्ताव आता था, उसी को स्वीकार मान लिया जाता था। व्यवस्थापक सभा की बैठकें न होने के समय में शहशाह को मंत्रियों की सलाह से हर प्रकार के आवश्यक कानून बनाने का अधिकार था। मगर व्यवस्थापक-सभा के बूखरी द्वार बैठते ही उन कानूनों को सभा की मजूरी के लिए सभा के सामने रखने जाने की वंद थी। मंत्रियों से व्यवस्थापक सभा में उन के काम के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते थे। परन्तु व्यवस्थापक सभा के उन में अविश्वास दिखाने पर भी मंत्री फ्रांस इत्यादि देशों की तरह पद त्याग करने के लिए मजबूर नहीं होते थे, क्योंकि वे उन देशों की तरह व्यवस्थापक सभा को जवाबदार नहीं होते थे। अस्तु, प्रजासत्तात्मक राज्य का दिखावा तो था मगर प्रजासत्तात्मक राज्य नहीं था। जर्मनी की तरह आस्ट्रिया में भी पिछली लड़ाई से पहले शहशाह की मर्जी के अनुसार चलने के लिए व्यवस्थापक सभा के तैयार न होने पर भी मंत्री किसी न किसी तरह अपने नौकरशाही के बड़े झुंड की सहायता से शहशाह की मर्जी का पालन करा ही लिया करते थे। नौकरशाही का बड़ा जोर था और उस को बड़े लंबे चौड़े अधिकार थे, जिन का यह प्रजा का इच्छा या हित का खयाल न कर के निरंकुशता से उपयोग

करती थी। सभाओं, व्याख्यानों, लेखों पर नजरशाही की तरफ से कड़ी दृष्टि रखी जाती थी। रिश्वतखोरी का भी बाजार गर्म रहता था। इसी प्रकार हंगरी की राज व्यवस्था भी अलग थी। आस्ट्रिया का शहशाह हंगरी का भी राजा और हंगरी राष्ट्र का सिरताज होता था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बैठ कर, राजा का चुनाव हुआ एक मन्त्रिमंडल हंगरी का शासन चलाता था। मगर हंगरी में मन्त्रिमंडल आस्ट्रिया की भाँति राजा को जवाबदार होने के बजाय हंगरी की व्यवस्थापक सभा को जवाबदार होता था। हंगरी की व्यवस्थापक-सभा की भी दो सभाएँ थी। एक 'राउस ऑफ़ मेगनेट्स' अर्थात् 'बड़े लोगों की सभा' और दूसरी 'प्रतिनिधि-सभा' कहलाती थी 'बड़े लोगों की सभा' में मौलसी और कुछ अधिकारी अपने पदों के कारण सदस्य होते थे। प्रतिनिधि सभा में प्रजा की तरफ से चुन कर प्रतिनिधि आते थे। सर्वसाधारण को 'प्रतिनिधि सभा' के सदस्य चुनने का अधिकार न था। सत्ताधिकार पाने के लिए थोड़े स कर देने की शर्त रखी गई थी, मगर आस्ट्रिया से हंगरी की सरकार फिर भी अधिक प्रजा सत्तात्मक थी।

आस्ट्रिया और हंगरी की इन अलग अलग राज व्यवस्थाओं के अतिरिक्त आस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य या द्वाजाशाही की एक तीसरी राज व्यवस्था थी। इस द्वाजाशाही की व्यवस्था में भी शहशाह सिरताज होता था और वह स्वयं अपने चुने हुए परराष्ट्र, युद्ध और अन्य तीन सचिवों और एक हिस्सेद्वारा की 'जाँच अदालत' की सहायता से आस्ट्रिया और हंगरी दोनों राष्ट्रों का आम शासन चलाता था, जो दोनों भागों की मर्जी से आम मान कर इस प्रबंध को सँप दिया जाता था। द्वाजाशाही की कोई व्यवस्थापक सभा नहीं थी। साठ साठ प्रतिनिधि दोनों राष्ट्रों की व्यवस्थापक सभाएँ हर साल चुन कर भेजता हैं, इन प्रतिनिधियों की सभा बारी बारी से दोनों देशों की राजधानियों, वियना और बुडापेस्ट से दोनों देशों के सम्मिलित काम काज के लिए धन मंजूर करने और उस काम काज की आम नीति पर विचार और निश्चय करने के लिए होती थी। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अलग अलग बैठकें होती थीं। किसी प्रश्न पर मतभेद होने पर दोनों में से कोई एक प्रतिनिधि मंडल दोनों प्रतिनिधि मंडलों की एक सम्मिलित-सभा की माँग कर सकता था। सम्मिलित सभा में हर प्रश्न पर बहुमत से निश्चय होता था। इस द्वाजाशाही का प्रबंध का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, फिर भी परराष्ट्र और सेना जैसे जरूरी विभागों का शासन इस प्रबंध के हाथ में था। द्वाजाशाही प्रबंध का ग्रहसचिव एक सम्मिलित वृत्त भी तैयार करता था, जिस पर दोनों प्रतिनिधि मंडलों के मत लिए जाते थे। द्वाजाशाही की तरफ से किसी प्रकार के सीव कर नहीं लगाए जाते थे। व्यापारी चुगी, करा और दोनों देशों के खजाना से हमदाद ले कर द्वाजाशाही शासन का खर्च चलाया जाता था। मुद्रा, रेल और वार इत्यादि जैसी और भी बहुत-सी बातों के संध में दोनों देशों में एक से कानून पास करा के एक आम नीति बना ली जाती थी, मगर उन का निश्चय दोनों देशों की व्यवस्थापक सभाएँ करती थीं, प्रतिनिधि मंडल नहीं।

इस विचित्र द्वाजाशाही से किसी देश को अधिक लाभ नहीं था, बल्कि उल्टी वह एक सरकार की कमजोरी का प्रत्यय थी। हा, इस प्रपञ्च से आस्ट्रिया में बसी हुई जर्मन-जाति और हंगरी में बसी हुई मैग्यार जाति के थुथके घमट की पूर्ति अचर्य होती थी, मगर आस्ट्रिया हंगरी के राज्य में बसी हुई दूसरी जातियों को यह प्रपञ्च विलुप्त पसंद नहीं था। वे द्वाजाशाही के बजाय जर्मनी की तरह एक सघ साम्राज्य चाहती थीं, जिस में उन की हस्ती को भी जगह हो। दूसरे देशों से सन्ध रखने में भी द्वाजा शाही कमजोरी दिखाती थी, क्योंकि परराष्ट्रों से सन्ध रखनेवाले हर प्रश्न पर दो प्रतिनिधि-मंडलों की राय एक करनी होती थी। इस द्वाजाशाही की मूल परराष्ट्र-नीति का ही यह नतीजा था कि सर्बिया से युद्ध छेड़ कर पिछली यूरोप की लड़ाई की महामारी दुनिया में फैला दी गई थी। यूरोप के राजनैतिक काँटे का बजन बराबर रखने के लिए इस द्वाजाशाही की रचना की गई थी। घटना राजनैतिक सगठन और व्यवस्था की दृष्टि से वह एक विलुप्त निकम्मी चीज थी। लड़ाई के शुरू शुरू में तो आस्ट्रिया हंगरी में बसनेवाली सभी जातियों ने मिल कर लड़ने का निश्चय किया था। मगर बाद में द्वाजाशाही को दलदल में फँसा देर कर पोल, जेक, स्लोवाक, जूगोस्लाव इत्यादि सारी जातियों ने अपने अपने लिए स्वराज्य की माँग शुरू कर दी थी। आस्ट्रिया की सेनाएँ भी जर्मनी की तरह लड़ाई के मैदान से, गोला बारूद और रसद न मिलने के कारण, भाग उठी थीं। अस्तु, शहशाह ने नेपा डूबती हुई देर कर आखिरकार एक एलान निकाला कि, 'आस्ट्रिया की सरकार को सहीय राज व्यवस्था कबूल है, जिस में साम्राज्य की सभी जातियों को स्वराज्य होगा और सारी जातियाँ बराबर की हैसियत से सघ की सदस्य होंगी।' मगर इस प्रकार के एलानों का समय बीत चुका था। हंगरी ने द्वाजा शाही का प्रपञ्च खत्म हो जाने और अपने उस प्रपञ्च से अलग हो कर स्वतन्त्र हो जाने का एलान कर दिया। आस्ट्रिया हंगरी की द्वाजाशाही की, लड़ाई के धक्के से, कमर टूटते ही दूसरी जातियों ने भी अपनी अपनी स्वतन्त्रता का एलान कर दिया और अस्थायी सधि का एलान देते ही उन की स्वतन्त्रता दूसरे देशों ने मंजूर कर ली। अस्तु, लड़ाई के बाद आस्ट्रिया हंगरी की सरकार टूट कर आस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, जेकोस्लोवाकिया, जूगोस्लाविया और रूमानिया की छ स्वतन्त्र सरकारों में बँट गई।

## नई आस्ट्रिया

**राज-व्यवस्था—**आस्ट्रिया की नई सरकार का अधिकार आस्ट्रिया में बसनेवाले सिर्फ ६५ लाख जर्मनों पर रह गया है। इस नए राष्ट्र में वियना, ऊपरी आस्ट्रिया, निचली आस्ट्रिया, सेल्ज़बर्ग, स्टीरिया, बर्जेलैंड, कैरेंथिया, बोरेल्बेर्ग और टाइरोल के भाग शामिल हैं। ११ नवंबर सन् १९१८ को ही, जिस दिन जर्मनी और मित्र-राष्ट्रों में अस्थायी सधि हुई थी, आस्ट्रिया के शहशाह ने अपनी कहानी खत्म समझ कर राजनीति के फगडों से अपने हाथ खींच लिया था और आस्ट्रिया के तीनों मुख्य राजनैतिक दलों—राष्ट्रीय जर्मन दल, डैसाई समाजवादी दल, समाजी प्रजासत्तात्मक दल—की एक अस्थायी

राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा ने कानून बना कर आस्ट्रिया के एक 'प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र' होने और उस में सारे अधिकार और सत्ता की जड़ प्रजा के होने का एलान कर दिया था। अस्थायी राजव्यवस्था में आस्ट्रिया—जो कि अब सिर्फ जर्मन आस्ट्रिया थी—को नए जर्मन प्रजातन्त्र का एक अंग भी माना गया था। जर्मन प्रजातन्त्र की राजव्यवस्था की ६१ वीं धारा में भी जर्मन आस्ट्रिया के जर्मन प्रजातन्त्र में शरीर होने की योजना रखी गई थी। मगर मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और आस्ट्रिया का यह सम्मिलन नहीं होने दिया। वारसेल्स की सुलह की ८० वीं धारा में जर्मनी को 'आस्ट्रिया की स्वाधीनता स्वीकार करने और आस्ट्रिया और मित्र-राष्ट्रों में तब हो जानेवाली आस्ट्रिया की सीमा स्वीकार करने तथा आस्ट्रिया की इस स्वाधीनता से बिना लीग ऑफ नेशंस की मर्जी के अभग मानने' के लिए मजबूर कर दिया गया था। 'अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा ने जनवरी १९१६ में एक व्यवस्थापक सम्मेलन के चुनाव की भी योजना की थी। इस 'व्यवस्थापक सम्मेलन' को दो साल के लिए चुनने और सारे जर्मन जिलों से २५० प्रतिनिधि चुनने का निर्णय किया गया था। बीस वर्ष के ऊपर के सन मर्द और स्त्रियों को अनुपात निर्वाचन की सूची पद्धति के अनुसार 'व्यवस्थापक-सम्मेलन' के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया था, पाँच फरवरी को चुनाव हुआ जिस में चालीस लाख मतदारों ने भाग लिया और ४ मार्च सन् १९१६ को 'व्यवस्थापक सम्मेलन' की बैठक शुरू हुई। अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा ने बहुत से अस्थायी कानून पास कर के सरकार के विभिन्न विभागों का सगठन कर लिया था। 'व्यवस्थापक सम्मेलन' के बैठते ही अस्थायी राष्ट्रीय सभा ने सरकार का भार उस को सौंप दिया और वह भग हो गई। १२ मार्च को 'व्यवस्थापक सम्मेलन' ने आस्ट्रिया के एक प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र होने और जर्मन प्रजातन्त्र का अंग होने का फिर नाकायदा एलान किया और अपने हाथ में सारी राष्ट्रीय सत्ता होने की घोषणा की।

व्यवस्थापक सम्मेलन के सामने नए आस्ट्रिया के राष्ट्र की राज व्यवस्था तैयार करने के साथ-साथ मित्र राष्ट्रों से सुलह करने, युद्ध के परिणाम स्वरूप देश में पैली हुई बेकारी, अकाल, बीमारी और गिरती हुई मुद्रा की कीमत ठीक रखने की बहुत-सी जटिल समस्याएँ थीं। इन सारी समस्याओं को सुलझाते हुए और मित्र राष्ट्रों से सितनर सन् १९१६ में सुलह कर के, अक्टूबर सन् १९२० ई० में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने आस्ट्रिया के नए राष्ट्र के लिए एक 'संघीय प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र' की राज व्यवस्था मजूर की। यह राज-व्यवस्था स्विट्जरलैंड की संघीय और सीधे चुनाववाली राज व्यवस्था तथा जर्मन प्रजातन्त्र की राज व्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के नमूने पर ढाली गई थी। उस पर नवंबर सन् १९२० ई० से प्रारंभ शुरू हुआ था और सन् १९२६ तक उस में प्रजातन्त्र के प्रमुख के अधिकार बढ़ाने के लिए कई संशोधन भी हुए थे।

इस राज व्यवस्था के अनुसार आस्ट्रिया नो प्रांता का एक संघीय राष्ट्र बना दिया गया है। विभिन्न प्रांत अपनी रक्षा, आर्थिक प्रबंध और व्यापारी चुगौनों के प्रबंध के लिए एक संघ में मिल गए हैं। संघ को बहुत सी शक्त है। परराष्ट्र नियम, पासपोर्ट

नियम, सघीय ग्राय व्यय और देश का ग्राम शासन सघ के हाथ में होता है। नागरिकता, धर्मों के प्रतिनिधित्व, व्यापार, दुहरे करों को और आर्थिक चलन में अडचनों को रोकने, अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद, मरुनों और जा-ता फौजदारी तथा शासन के सबध में कानून-सघ बनाती है। मगर उन को ग्रमल में प्राप्त लाते हैं। प्रातीय शासन, स्थानिक सरकार के काम काज, पचायती अदालतों, स्थानिक पुलिस, जंगलात, जमीन के सुधार के सबध में सिद्धांत निश्चय करने की सत्ता सघ को है, मगर तफसीली हुकम प्राप्त निभालते हैं। सब प्रकार के करो को लगाने और उन की ग्रामदनी को सघीय और प्रातीय खजानों में बाँटने की भी पूरी सत्ता सघ के हाथ में होती है। कार्यकारिणी की जो सत्ता सघ को नहीं दी गई है, वह प्रातों की स्वाधीन सत्ता में समाविष्ट मानी गई है। सघ और प्रातों की सरकार का काम प्रजा के चुने हुए 'जन सचालक' चलाते हैं। सघ और प्रातों को अपने अपने सेवकों पर पूरा अधिकार होता है।

**व्यवस्थापक-सभा**—सघीय व्यवस्थापक सभा की 'राष्ट्रीय-सभा' और 'सघीय सभा' दो सभाएँ हैं। 'राष्ट्रीय सभा' के चुनाव में २१ वर्ष के ऊपर सब मर्द और स्त्री नागरिक अनुपात निर्वाचन के अनुसार भाग लेते हैं और २४ वर्ष के ऊपर वे उम्मीदवार हो सकते हैं। किसी नागरिक का मतधिकार बिना अदालत के फैसले के नहीं जप्त किया जा सकता है। 'सघ सभा' का चुनाव प्रांतिक धारा सभाएँ करती हैं। 'राष्ट्र सभा' चार वर्ष के लिए चुनी जाती है। प्रजातंत्र का प्रमुख बसत गौर पतकड में साल में दो बार उस की बैठकें बुलाता है। राष्ट्र सभा के एक तिहाई सदस्यों की या सघीय सरकार की माँग होने पर भी राष्ट्र सभा फौरन बुलाई जाती है। सघ सभा में हर प्रात से आबादी के अनुसार इस प्रकार प्रतिनिधि चुन कर आते हैं—कि सब से बड़ी आबादी के प्रात से १२ सदस्य और दूसरे प्रातों से उन की आबादी और सन से बड़े प्रात की आबादी में जो निम्नत होती है, उतने। मगर हर प्रात से कम से कम तीन प्रतिनिधि अवश्य आते हैं। बियना और आस्ट्रिया के प्रातों की खास हैसियत मानी गई है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतिक धारा सभाएँ प्रात की धारा सभा की जिंदगी भर के लिए करती हैं।

कानूनी मसविदे राष्ट्र-सभा के सदस्यों, सघीय सरकार और सघ सभा की ओर से सघीय सरकार के द्वारा अथवा दो लाख मतदारों या तीन प्रातों के आधे मतदारों की प्रस्तावना पर सरकार के द्वारा राष्ट्र-सभा में पेश किए जा सकते हैं। राष्ट्र सभा में मजूर हो जानेवाले मसविदों को प्रधान मंत्री या 'फेडरल चांसलर' सघ सभा के पास भेज देता है। अगर 'सघ सभा' उस को जैसा का तैसा मजूर कर लेती है, तो उस को ग्रमल के लिए एलान कर दिया जाता है। अगर सघ सभा और राष्ट्र सभा की राय नहीं मिलती है, तो वह मसविदा फिर राष्ट्र सभा के पास पुन विचार के लिए भेजा जाता है और राष्ट्र-सभा उस को जैसा चाहे वैसा अपनी सभा में बहुमत से पास कर



सकती है, यशतः कि सभा में कम से कम आधे सदस्य हाजिर हो। मगर सब के आय-व्यय सन्धी तखमीनों या राष्ट्र-सभा के काम-काज और भग होने के सन्ध के प्रस्तावों में फेरफार करने का अधिकार 'सब सभा' को नहीं है। 'राष्ट्र-सभा' अपने पास किए हुए कानून पर अमल के लिए एलान होने से पहले हवाले के जरिए से प्रजा की राय भी ले सकती है। किसी एक कानून के द्वारा राज-व्यवस्था में किसी प्रकार का सशोधन करने के लिए व्यवस्थापक सभा के आधे सदस्यों की हाजिरी और सदस्यों की दो-तिहाई सख्या की मजूरी की जरूरत होती है। राज-व्यवस्था के आम सशोधनों पर व्यवस्थापक सभा की मजूरी के बाद हवाले के द्वारा प्रजा की राय लेनी पड़ती है। अगर राज-व्यवस्था के सिर्फ किसी अंग का सशोधन होता है तो 'राष्ट्र सभा' या 'सब-सभा' के एक तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर हवाला लिया जाता है। आम तौर पर चार प्रश्न दोनों सभाओं में बहुसख्या से मजूर होते हैं। राष्ट्रीय सधियों और उन सधियों की स्वीकृति के लिए, जिन से देश के कानून में फेरफार होता है, 'राष्ट्र सभा' की मजूरी आवश्यक होती है। 'राष्ट्र सभा' और 'सब-सभा' दोनों को सरकार की नीति और काम-काज में इस्तद्वेप करने का बहुत सा अधिकार होता है। पदार्थों की कीमते तय करने, मजदूरी तय करने इत्यादि का काम और दूसरा आर्थिक काम-काज 'राष्ट्र सभा' अपनी एक 'खाम कमेटी' के जरिए करती है।

'राष्ट्र सभा' की बैठक सिर्फ 'राष्ट्र सभा' के ही प्रस्ताव से स्थगित की जा सकती है और उस को फिर मिलने के लिए बुलावा, सभा के अध्यक्ष की तरफ से भेजा जाता है। अपना बार वर्ष का समय पूरा होने से पहले भी, कानून पास कर के, राष्ट्र सभा अपने आप को भग कर सकती है। 'राष्ट्र सभा' अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक नायब उपाध्यक्ष चुनती है। सभा का काम-काज सभा के ही रुत बनाए हुए एक कानून के नियमों के अनुसार चलाया जाता है। इस कानून को पास करने के लिए सभा के आधे सदस्यों की हाजिरी और दिए गए मतों की दो तिहाई सख्या की आवश्यकता होती है। एक तिहाई सदस्य आम तौर पर सभा में हाजिर न होने पर कोई भी सभा का फेसला गार्रायदा नहा होता है। सभा की बैठकें प्रजा के लिए खुली होती हैं। मगर अध्यक्ष या सदस्यों के पाँचवें भाग की प्रार्थना पर उद बैठकें भी हो सकती हैं, यशतः कि दर्शकों के हट जाने के बाद सभा बहुमत से उद बैठक करना स्वीकार कर ले।

'सब सभा' के सदस्यों का चुनाव तो अनुपात निर्वाचन के अनुसार प्रातीय धारा सभाएँ करती हैं, मगर कम से कम एक सदस्य उस दल का अवश्य चुने जाने की फेद रखती गई है, जिस दल की प्रातीय धारा-सभा में सब से बड़े दल के बाद सब से अधिक सख्या हो, या कई दलों की गरावर सख्या होने पर, जिस को पिछले चुनाव में सब से अधिक मत मिले हों। कई दलों का एक-सा हक होने पर चिद्धी डाल कर फेसला कर लिया जाता है। 'सब-सभा' के सदस्य किसी प्रातिन धारा सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। मगर प्रातिन धारा सभा के लिए चुने जाने का उन को अधिकार अवश्य होना चाहिए। प्रातीय धारा-सभाओं का काल पूरा हो जाने या उन के भग हो जाने पर भी उन के चुने हुए 'सब-

सभा' के सदस्य उस समय तक काम करते रहते हैं जब तक कि प्रांतीय धारा-सभाएं नए सदस्य 'सघ सभा' के लिए न चुन लें। 'सघ सभा' का अध्यक्ष हर छठे महीने बदल दिया जाता है। बारी बारी से वर्षमालाक्रम से हर प्रांत के सत्र से अधिक मतों से चुने जाने वाले प्रतिनिधि को 'सघ-सभा' का अध्यक्ष बनाया जाता है। सत्र सभा की बैठकें भी सभा का अध्यक्ष उसी स्थान पर बुलाता है, जहां 'राष्ट्र-सभा' की बैठकें होती हैं। 'राष्ट्र सभा' की तरह 'सघ-सभा' का भी कोई निश्चय बिना एक तिहाई सदस्यों की हाजिरी और बहुसंख्य की मजूरों के वाक्यावदा नहीं होता है। काम-काज के नियम का प्रस्ताव भी सघ सभा राष्ट्र सभा की तरह ही आधे सदस्यों की हाजिरी और उन की दो तिहाई संख्या की मजूरी से करती है। सघ सभा की चुनी बैठकों के सबंध में भी वही शर्तें रक्खी गई हैं, जो राष्ट्र-सभा के सत्र में। आस्ट्रिया की व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों को भी वही सारे अधिकार और रियायतें होती हैं जो ग्राम तौर पर प्रजासत्तात्मक देशों में व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को होती हैं अर्थात् बोलने और मत देने की स्वतंत्रता तथा सभा की बैठकों के समय में गिरफ्तारी और आज्ञादी इत्यादि। कोई सदस्य 'राष्ट्र-सभा' और 'सघ-सभा' दोनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है, मगर आस्ट्रिया में कोई भी सेना या सरकार का नौकर व्यवस्थापक सभा का उम्मीदवार हो सकता है। सदस्य हो जाने पर सभा की बैठकों में जाने के लिए उसे बराबर छुट्टी दी जाती है। 'राष्ट्र सभा' को 'जाँच-कमेटिया' नियुक्त कर के अधिकारियों और सरकारी विभागों के काम-काज की जाँच करने का अधिकार होता है और इस प्रकार का जाँच-कमेटियों के आगे, माँगने पर, अधिकारियों और अदालतों को हर प्रकार के कागज रखने होते हैं। 'राष्ट्र सभा' की एक स्थायी 'मुख्य-कमेटी' भी होती है जो 'राष्ट्र-सभा' की बैठकें न होने पर, जरूरत पड़ने पर, संघीय सरकार के सदस्यों की, सभा की बैठक में वाक्यावदा उन का चुनाव होने तक, अस्थायी नियुक्ति कर सकती है। राष्ट्र सभा और सघ सभा की मिल कर राष्ट्र सभा के स्थान पर 'संघीय सम्मेलन' की बैठक, आस्ट्रिया प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव करने और उस से प्रजातंत्र के प्रति राजभक्ति की शपथ लेने के लिए 'संघीय सम्मेलन' की बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्र सभा के प्रजातंत्र के प्रमुख पर अभियोग चलाने का निश्चय कर लेने पर या प्रमुख का स्थान किसी कारण से स्थायी रूप से खाल हो जाने पर, नए प्रमुख का चुनाव करने के लिए या प्रजातंत्र के प्रमुख से 'राष्ट्र सभा' की माँग पर उस के कामों के लिए जवाब दखाने के लिए, 'संघीय सम्मेलन' की बैठक संघीय चांसलर बुलाता है। अन्यथा सम्मेलन की बैठकें प्रजातंत्र का प्रमुख ही बुलाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता का स्थान पहले 'राष्ट्र सभा' का अध्यक्ष होता है और फिर 'सघ सभा' का अध्यक्ष। बाद में बारी बारी से दोनों सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं। 'राष्ट्र सभा' के काम-काज के नियमों के अनुसार सम्मेलन का काम-काज चलाया जाता है।

## कार्यकारिणी

**प्रजातंत्र का प्रमुख**—प्रजातंत्र के प्रमुख का सघ के सारे मतदार सीधा छः वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। छः वर्ष का समय पूरा होने पर वह सिर्फ एक बार और

फौरन ही दूसरे छः वर्ष के समय के लिए चुना जा सकता है। प्रमुख पद के लिए चुनाव में ३५ वर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी मतदार सड़ा हो सकता है। आस्ट्रिया के प्रमुख को फ्रांस के प्रजातन्त्र के प्रमुख की तरह ही अधिकार होते हैं। मगर आस्ट्रिया के प्रमुख को 'राष्ट्रीय संकट' के समय में जरूरी कानून पास करने का अधिकार भी होता है। 'राष्ट्रीय संकट' की राज व्यवस्था में, प्रमुख के इस अधिकार का उपयोग करने के लिए, इस प्रकार व्याख्या की गई है कि, 'अगर समाज को हानिकारक कोई जाहिर खतरा पैदा हो जाय और उस समय राष्ट्र सभा की बैठक न हो रही हो, या उस की बैठक करना असंभव हो या उस की बैठक जरूरदस्ती रोक दी गई हो तो प्रमुख को ऐसी हालत में मौके के अनुसार आवश्यक कानूनों को एलान और जारी करने का अधिकार है।' यह 'आवश्यक कानून' संघीय सरकार की तरफ से 'राष्ट्र सभा' की स्थायी कमिटी की राय से प्रमुख के सामने जारी करने के लिए पेश होने चाहिए। ऐसे 'आवश्यक कानून' राज-व्यवस्था, उद्योगी संगठन, आर्थिक विषय और किसानों की रक्षा के संघ में जारी नहीं हो सकते हैं, और उन को जल्दी से जल्दी 'राष्ट्र सभा' की बैठक के सामने, एक हफ्ते के अंदर, मजूरी के लिए पेश करने की भी शर्त रखी गई है। 'राष्ट्र सभा' इन 'आवश्यक कानूनों' में अपनी मर्जी के अनुसार संशोधन या जरूरत न रहने पर उन को विफा बहुमत से रद्द कर सकती है। हर हालत में 'आवश्यक कानूनों' के जारी होने की तारीख से चार हफ्ते के भीतर 'राष्ट्र-सभा' को उन के विषय में अपना फैसला जाहिर करना जरूरी माना गया है।

राज करने वाले राजघरानों या उन राजघरानों के लोग, जो पहले राज कर चुके हैं, प्रजातन्त्र के प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। जितने मत चुनाव में पड़े, उन के आगे से अधिक जिस उम्मीदवार को मिलते हैं, वही प्रमुख चुना जाता है। जब तक किसी को आगे से अधिक मत नहीं मिलते हैं, तब तक बार बार मत लिए जाते हैं। प्रजातन्त्र का प्रमुख, प्रमुख-पद पर रहते हुए किसी सार्वजनिक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता है और न वह और कोई धंधा कर सकता है। संघीय सम्मेलन प्रजातन्त्र के प्रमुख पर अभियोग चला सकता है। प्रमुख के काम करने के अयोग्य हो जाने या उस की जगह कुछ काल के लिए खाली हो जाने पर प्रमुख का काम संघीय चांसलर करता है। फ्रांस के प्रमुख की तरह आस्ट्रिया का प्रमुख बाहरी देशों के लिए प्रजातन्त्र का प्रतिनिधि होता है, वही उन से संधिया करता है और उस को एलची भेजने और लेने, सेना और सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, उन को रिताय देने अपराधियों की क्षमा करने के अतिरिक्त नाजायज वच्चों के माता पिता की अर्जी पर जायज करार देने का अधिकार होता है। प्रमुख अपना सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार खास फ़िस्म के अधिकारियों के लिए संघीय सरकार के उचित सदस्यों को भी सौंप सकता है। उसी तरह खास फ़िस्म की संधिया करने का अधिकार भी वह संघीय सरकार को सौंप सकता है। प्रमुख के सारे काम—सिवाय उन कामों के

जो कि राज व्यवस्था में उसी के लिए रखे गए हैं—ग्राम तौर पर सघीय सरकार या सघीय सरकार से अधिकार प्राप्त मंत्रियों के प्रस्ताव पर होते हैं। उस का कोई काम सघीय चांसलर या किसी अधिकार प्राप्त मंत्री की सही के बिना बाकायदा नहीं होता है। प्रमुख अपने कामों के लिए सघीय सम्मेलन को जवाबदार होता है।

**मंत्रि-मंडल**—सरकार के सारे कामों की जिम्मेदारी सब के मंत्रियों पर होती है। मंत्रि मंडल में एक चांसलर<sup>१</sup>, एक नायब चांसलर गृह, न्याय, अर्थ, समाज-हितकारी, व्यापार, खेती और जंगलात, युद्ध तथा शिक्षा इन आठ विभागों के आठ मंत्री होते हैं। राष्ट्र सभा की 'मुख्य कमेटी' के प्रस्ताव पर राष्ट्र सभा उन को इच्छा चुनती है और प्रजातन्त्र का प्रमुख उन को नियुक्त कर के उन से राज भक्ति की शपथ लेती है। सरकार का जो काम राज व्यवस्था में प्रमुख को सौंपा गया है, उस के अतिरिक्त सारा काम मंत्रि मंडल करता है। 'सघीय चांसलर' की प्रधानता में सम्मिलित रूप से सारे मंत्री आस्ट्रिया प्रजातन्त्र की सघीय सरकार होते हैं। चांसलर की गैरहाजिरी में नायब चांसलर उस का काम करता है। राष्ट्र सभा के सदस्य के होने के अधिकारी ही मंत्रि मंडल में चुने जा सकते हैं, मगर राष्ट्र-सभा के सदस्य, मंत्रि मंडल के सदस्य नहीं बन सकते हैं। राष्ट्र सभा की बैठक न होने पर राष्ट्र सभा की 'मुख्य समिति सभा' की बैठक होने तक अस्थायी रूप से मंत्रियों को नियुक्त कर देती है और फिर राष्ट्र सभा की बैठक होने पर राष्ट्र-सभा उन को बाकायदा चुन लेती है। एक मंत्रि मंडल के निकल जाने पर, दूसरे के चुनाव तक, प्रजातन्त्र का प्रमुख सरकार का काम जानने वाले मंत्रियों या विभागों के बड़े अधिकारियों को सौंप देता है और उन में से ही एक को अस्थायी मंत्रि मंडल का प्रधान नियुक्त कर देता है। उसी तरह किसी एक-दो मंत्रियों के जाने पर वह उन की जगह भर या उन के किसी कारण से काम के अयोग्य हो जाने पर एगजी मंत्री रख सकता है। राष्ट्र सभा के आधे सदस्यों की हाजिरी में सभा में मंत्रि मंडल या किसी एक-दो मंत्री में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर प्रजातन्त्र का प्रमुख मंत्रि मंडल से या जिस मंत्री में अविश्वास दिखाया जाता है, उस से इस्तीफा ले लेता है। मंत्रिमंडल अपनी इच्छा से भी प्रमुख को इस्तीफा दे सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के लिए राष्ट्र-सभा में कम से कम आधे सदस्यों की हाजिरी की जरूरत होती। मगर हाजिर सदस्यों के पाँचने भाग की माँग पर उस प्रस्ताव पर मत लेना तीसरे दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। वाद में भी बहुमत से मत लेना बंद किया जा सकता है। मंत्रि मंडल के सदस्यों को राष्ट्र सभा, सब सभा, सघीय सम्मेलन और इन सारी संस्थाओं की कमेटियों में भाग लेने तथा निमन्त्रण मिलने पर, राष्ट्र सभा की 'मुख्य कमेटी' चार्ल्याई में भी भाग लेने और मौलने का अधिकार होता है। इन संस्थाओं और कमेटियों को भी अपनी बैठकों में मंत्रि मंडल के सदस्यों को हाजिर रखने का अधिकार होता है। मंत्रि मंडल अपने काम के लिए 'राष्ट्र सभा' को जवाबदार होता है।

## स्थानिक-शासन और न्याय

**स्थानिक-शासन**—हर प्रांत में सब नागरिकों के मत से अनुपात निर्वाचन के अनुसार चुनी हुई, प्रांतीय धारा-सभा होती हैं। प्रांतीय धारा-सभा के मजूर किए हुए हर कानून को प्रांतीय गवर्नर एलान करने से पहले सघीय सरकार की मजूरी के लिए भेजता है और सघ के हितों के विरुद्ध समझने पर सघीय सरकार उस कानून का विरोध कर सकती है। सघीय सरकार के उद्देश को प्रांतीय धारा सभा अपने सदस्यों के बहुमत से बशर्ते कि उस बैठक में कम से कम आधे सदस्य हाजिर हों, रद्द कर सकती है। प्रजातन्त्र का प्रमुख सघीय सरकार के प्रस्ताव और सघ सभा की कम से कम आधे सदस्यों की हाजिरी में बहुमत से मजूरी मिलने पर किसी भी प्रांतीय धारा-सभा को भंग कर सकता है। धारा सभा भंग होने पर तीन हफ्ते के अंदर नया चुनाव होता है। प्रांत के गवर्नर और प्रांतिर धारा सभा द्वारा चुने हुए उस के साथी मंत्री स्थानिक शासन के लिए प्रांतीय धारा-सभाओं की और सघीय शासन की कर्वाइ के लिए सघीय अधिकारियों को जवाबदार होते हैं। प्रांत शासन के कार्य के लिए, जिलों में बाँटे गए हैं और जिले कम्यूनों में। प्रांतीय शासन का सारा काम प्रांतीय धारा सभा की चुनी हुई सरकार चलाती है। सघीय सरकार राज व्यवस्था में सौंपे हुए अपने खास कामों को करने के लिए अपने अधिकारी प्रांतों में रख सकती है अथवा उन कामों को प्रांतीय सरकार को सौंप सकती है। प्रांतीय धारा-सभाओं के सदस्यों को भी वही अधिकार और रियायत होती हैं जो सघीय व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों को होती हैं। प्रांतीय सरकार के सदस्य भी प्रांतीय धारा सभा के सदस्यों में से नहीं चुने जा सकते हैं। सिर्फ एक 'लोअर आस्ट्रिया के प्रांत की धारा-सभा की दो शाखाएँ होती हैं। एक 'प्रांत सभा' होती है, जिस में प्रांत के प्रतिनिधि होते हैं और दूसरी आस्ट्रिया की राजधानी वियना की 'नगर-सभा' होती है जिस में सिर्फ वियना शहर के प्रतिनिधि होते हैं। दोनों सभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या दोनों की आबादी के लिहाज से तय की जाती है। दोनों सभाओं को मिला कर लोअर आस्ट्रिया की 'प्रांतीय धारा सभा' होती है और वह प्रांत के सारे ग्राम प्रश्नों का फेसला करती है। जो नियम ग्राम नहीं होते हैं उन में दोनों सभाएँ अलग-अलग बिना प्रांत<sup>१</sup> और लोअर आस्ट्रिया प्रांत की प्रांतीय धारा-सभाओं की हैसियत से काम करती हैं। दोनों शाखाओं के संगठन की व्यवस्था और सघ-सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों भागों के लिए ग्राम प्रश्न नहीं माने गए हैं। प्रांतीय करों को भी शहर के लिए वियना की 'नगर सभा' और प्रांत के लिए दूसरी 'प्रांत सभा' लगाती है। वियना की 'शहर सभा' अर्थात् चुंग का चुनाव हुआ प्रधान<sup>२</sup> वियना प्रांत का गवर्नर होता है और एक चुनी हुई समिति को उस के साथ मिला कर वियना प्रांत की सरकार बनती है। प्रांत का गवर्नर अलग होता है। ग्राम शासन का कार्य प्रांतीय धारा-सभा का चुनाव हुआ एक 'शासन कमीशन' चलाता है जिस के वियना का गवर्नर और प्रांत का गवर्नर दोनों सदस्य होते हैं।

<sup>१</sup> वियना शहर को प्रांत माना गया है। <sup>२</sup> बर्गेमास्टर।

जिलों पर प्रात का अधिकार और कम्पूनों पर जिलों का अधिकार होता है। मगर जिलों और कम्पूनों की अलग अलग सभाएं और शासन समितियां होती हैं। 'जिला सभाओं' और 'कम्पून सभाओं' को सतीय राज व्यवस्था की शर्तों के अनुसार अपने क्षेत्रों के आर्थिक जीवन का नियंत्रण आय व्यय का प्रबंध करने और कर लगाने का अधिकार होता है। कम्पूनों का मुख्य काम अपने क्षेत्र में बसनेवालों की जान माल की रक्षा के लिए पुलिस का प्रबंध करना, सड़कों में प्रजा की जान बचाने और उन को आराम पहुँचाने का काम करना, और सड़कें, सार्वजनिक स्थानों और पुलों को ठीक रखना और कस्बों की 'सड़क पुलिस' गांवों की पुलिस बाजार और खाद्य पदार्थों का प्रबंध करनेवाली पुलिस स्वास्थ्य रक्षा पुलिस इमारतों और आग की पुलिस का प्रबंध करना होता है।

**न्याय**—दीवानी और फौजदारी की अदालतें आस्ट्रिया में दूसरी प्रजासत्तात्मक देशों की तरह होती हैं। लंबी सजाओं और राजनैतिक अपराधों के फैसले करने के लिए जज के साथ जूरी भी बैठती है। कुछ साल से अधिन सजा के अपराधों के न्याय के लिए जज के साथ असेसर बैठते हैं। पाँसी की सजा आस्ट्रिया में किसी को नहीं होती है, आस्ट्रिया की सब से बड़ी राष्ट्रीय अदालत, जिस में देश भर से अपीलें आती हैं वियना में बैठती है। दूसरी एक 'शासकी अदालत' भी वियना में बैठती है, जिस के सामने शासन अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों के मुकदमे पेश होते हैं। तीसरी एक 'व्यवस्थापकी अदालत' वियना में बैठती है जो संघ और प्रांतों के ऋगडों, प्रांतों के आपस के ऋगडों, अदालतों और अधिकारियों के ऋगडों, मामूली अदालतों और शासकी अदालत के ऋगडों, शासकी अदालतों से अपने ऋगडों, चुनावों के ऋगडों और धारा सभाओं द्वारा लगाए हुए अधिकारियों पर अभियोगों का न्याय करती है। चौथी एक इसाब किताब की 'जाँच अदालत' होती है, जिस को साधारण अर्थ में अदालत कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस का काम इंग्लैंड के आडीटर-जनरल की तरह राष्ट्र का इसाब पित्त तैयार कर के और उस की अच्छी तरह जाँच कर के राष्ट्र सभा के सामने रखना होता है। यह अदालत राष्ट्र सभा के अधीन होती है।

**राजनैतिक दल**—आस्ट्रिया का सब से बड़ा राजनैतिक दल 'समाजी प्रजा सत्तात्मक दल' है। इस दल के सन् १९३१ ई० की राष्ट्रसभा में ७२ सदस्य और सप्सभा में २० सदस्य थे। फिर भी यह दल व्यवस्थापक सभा में सरकार का निरोधी दल ही था, क्योंकि सरकार कई दलों की मिल कर बनी थी। यह दल आस्ट्रिया को जर्मनी से मिलाने का पक्षपाती है। मगर साथ ही साथ यह द्वितीय अंतरराष्ट्रीय के अनुसार समाज शांति का मानने वाला है। इस दल का जोर अधिकतर उद्योगी स्थानों में और शहरों में है। वियना में तो इस दल की बिल्कुल तृती ही बोलती है। वहा की चुगी पर उस का पूरा कब्जा है और इस चुगी के द्वारा उस ने अपनी रचनात्मक शक्ति का इज्जत के सामने

<sup>१</sup>सेवक इंटरनेशनल नरम विचारों के समाजवादियों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।

रूम की समाजशाही की तरह वन्य अन्ध्र नमूना रखता है। इस दल के हाथ-पाँव आस्ट्रिया के नगरों में फैली हुई मजदूर-सघों हैं। दल का एक भाग दूसरे दलों से मिल कर काम करने को राजी मालूम होता है, मगर डाक्टर और तो बोअर के नेतृत्व में बहु-संख्या बोलशेविक विचारों की है। यह दल धर्म और सरकार के पृथक्करण, प्रत्यक्ष करों खास कर आमदनी और मोन मजे के करों और मुद्रास्फीति में सुधार, बेकारी कम करने के लिए सार्वजनिक कार्य, बड़ी जिम्मेदारियों का का छोटी में पटवारा, कृषि की उन्नति, जमींदारों से किसानों की रक्षा के कानूनों, समाजी कानूनों, खास कर हुदापे के लिए बीमा, धार्मिक बातों से सन्ध न रखनेवाली शिक्षा, उद्योगों, रानों, बैंकों और व्यापार में समाजशाही नियंत्रण का पक्षपाती है।

इस से छोटा दूसरा दल 'ईसाई समाजी दल' है, जिस के १९३० ई० के चुनाव में ६३ सदस्य राष्ट्रसभा में चुन कर आए थे। यह दल इगर्जेंट के अनुदार या दक्षिण-पूरबी दल के विचार रखता है और इस के राजनीति और शिक्षा-सम्बन्धी विचारों में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के धार्मिक विचारों की बहुत कुछ छाप है। इस दल का एक अंग आस्ट्रिया में राजाशाही का पक्षपाती और दूसरा जर्मनी से एकीकरण का माननेवाला है। इस दल में अधिकतर मालदार लोग होते हैं। आर्थिक सुधारों की माँग यह दल सिर्फ मजदूरपेशा लोगों को समाजवादिता की नास्तिकता से दूर रखने के लिए करता है। मगर यह दल सरकार के सघीय संगठन का पक्षपाती है और अपने दल का संगठन भी उस ने सघीय सिद्धांतों पर किया है।

दूसरे दलों में 'पैन, जर्मन दल' और 'कृषि दल' का सन् १९३० से मिल कर 'राष्ट्रीय आर्थिक समूह' और 'कृषि-सघ' नाम का एक दल बन गया है। यह दल कट्टर देशभक्ति, जर्मनी से एकीकरण और देश की आर्थिक उन्नति को माननेवाला है। इस दल के राष्ट्रसभा में सन् १९३० ई० के चुनाव में १६ सदस्य चुने गए थे। इटली के फेसिस्टों से मिलता जुलता एक और 'हीमाट ब्लॉक' नाम का दल है, जो केवल सातिमय उपायों से सरकार पर दबाव डालने में विश्वास नहीं रखता है। इस दल के पिछले चुनाव में सिर्फ आठ सदस्य व्यवस्थापक सभा में चुन कर आए थे। मगर प्रांतों की धारा सभाओं में से इस दल के सदस्य काफी संख्या में हैं।

## हंगरी की नई सरकार

**राज-व्यवस्था**—आस्ट्रिया-हंगरी की दराजाशाही की बेवृत्तियों और पराजय से हंगरी में भी सन् १९१८ ई० के अक्टूबर मास में जो क्रांति हो गई थी, जिस में आस्ट्रिया की तरह हंगरी को भी 'हंगरी की प्रजा का प्रजातन्त्र' एलान कर दिया गया था। तेरह नवंबर को हंगरी के राजा चार्ल्स राज्य त्याग की घोषणा कर देने के बाद काउंट माइकेल फेरोल्सो हंगरी की 'काम चलाऊ सरकार' का प्रमुख बना था। मार्च में समष्टिवादी

<sup>१</sup> नेशनल एकानमिक ब्लॉक एंड ऐग्रीपन लीग।

<sup>२</sup> प्रोविज़नल गवर्नमेंट।

बोल्शेविक दल ने सरकार पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमा लिया था, और उन का नेता बेलाकुन सरकार का प्रमुख बन बैठा था। मगर शीन ही समष्टिवादी दल के खिलाफ एक दूसरी क्रांति हुई, जिस में उस के हाथों से सत्ता छीन ली गई। जनवरी सन् १९२० ई० में सर्वसाधारण के मत से एक 'राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा' चुनी गई और ऐडमिरल निकोल सहोथा को हगरी राज्य का उत्तराधिकारी राज्य प्रतिनिधि चुन लिया गया। हगरी को प्रजातन्त्र एलान कर के भी अभी राज व्यवस्था के अनुसार राजाशाही ही गिना जाता है, गोकि अभी तक हगरी का ताज किसी राजा के सिर पर रखना तय नहीं हुआ है। उत्तराधिकारी के अधिकार कानून बना कर निश्चय कर दिए गए हैं। उस को लगभग राजा के बराबर ही अधिकार हैं। मगर वह युद्ध और सधि की घोषणा नहीं कर सकता है और न किसी को 'पीयर' बना सकता है। वही हगरी की व्यवस्थापक सभा में मजूर हो जाने वाले कानूनों को अपनी सही से जारी करता है। फिर भी माना जाता है कि शाही मजूरी वह उन कानूनों के लिए नहीं दे सकता है। उत्तराधिकारी को जब तक रक्खा जायगा, वह भी अभी तक निश्चय नहीं हुआ है।

**कार्यकारिणी**—सरकार की कार्यकारिणी सत्ता प्रधानमन्त्री और दूसरे आठ मंत्रियों के एक मन्त्रि मंडल में होती है जो अपने काम के लिए व्यवस्थापक सभा को जवाबदार होते हैं। इन मंत्रियों को राज्य प्रतिनिधि मुख्य राजनैतिक दलों के नेताओं में से चुनता है। पुरानी स्थानिक सस्थाओं की सत्ता घटा कर नई राज व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की सत्ता उठा दी है।

**व्यवस्थापक-सभा**—हगरी की व्यवस्थापक-सभा की भी दो सभाएँ होती हैं—एक 'प्रतिनिधि सभा' और दूसरी 'बडी सभा'। प्रतिनिधि सभा में २४५ सदस्य होते हैं, जिन को सार्वजनिक मतधिकार से पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। 'प्रतिनिधि सभा' और 'बडी सभा' को मिल कर हगरी में सारी प्रभुता मानी गई है। मगर रुपया पैसा इकट्ठा करने और खर्च मजूर करने की यानी राष्ट्रीय 'धैली की सत्ता' 'प्रतिनिधि सभा' को ही होती है। अस्तु, उसी के हाथ में सरकार की लगाम रहती है। 'प्रतिनिधि सभा' की बहुत सी स्थायी कमेटियाँ होती हैं जो कानून बनाने का बहुत सा काम करती हैं, क्योंकि सब प्रकार के मसविदों पर पहले इन कमेटियों में विचार होता है और फिर वह सभा के सामने लाए जाते हैं। हर एक २४ वर्ष की उम्र के ऊपर के मर्द को, जो दस वर्ष तक कम से कम हगरी का नागरिक और दो वर्ष तक एक ही कम्प्यून में रह चुका है और जो चार वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पा चुका है या जो उस शिक्षा के बराबर शिक्षा पाए होने का सबूत दे सकता है, हगरी में मत अधिकार होता है। हर एक तीस वर्ष के ऊपर की उस स्त्री को भी मत अधिकार होता है, जो छ वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पा चुकी है या जिस ने चार वर्ष तक ही शिक्षा पाई है, और अपनी रोटी खुद कमाती है या जिस के तीन बच्चे हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर चुकने वाले हर मर्द और स्त्री को उम्र इत्यादि की बिना किसी कैद के मत अधिकार होता है। प्रतिनिधि सभा के लिए लड़े होनेवाले उम्मीदवार के लिए, मत अधिकार प्राप्त होने



के सिवाय, श्री और मर्द दोनों के लिए तीस वर्ष की उम्र की फ़ैद रखी गई है।

‘बड़ी सभा’ में २४२ सदस्य होते हैं। यह सभा पुरानी ‘बड़ों की सभा’ के स्थान में आधुनिक प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों पर उनाई गई है। इस में कुछ अधिकारी अपने पदों के कारण कुछ लोग अपनी हैसियत के कारण, कुछ चुने हुए और कुछ नियुक्त किए हुए सदस्य होते हैं। देश की सभ से बड़ी अदालत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सेना का सेनापति, राष्ट्रीय बैंक का प्रधान इत्यादि करीब दस अधिकारी ‘बड़ी सभा’ के सदस्य अपने पद के कारण होते हैं। हंगरी पर राज करने वाले पुराने हेप्सबर्ग राजवंश के २४ वर्ष की उम्र से ऊपर के हंगरी के नागरिक और हंगरी में रहने वाले तीन सदस्य, पादरी, विभिन्न धर्मों के प्रधान और शारी अदालतों के कुछ अधिकारी मिला कर ४० सदस्य, अपनी हैसियत की वजह से होते हैं। पुरानी ‘बड़ों की सभा’ के मोरुसी सदस्यों के वंशों के ३० सदस्य, विभिन्न नगरों की चुनियों से ७६ सदस्य और विश्व विद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं, उद्योग, व्यापार, कृषि संस्थाओं से और वकीलों इत्यादि के लगभग तीस प्रतिनिधि, उन संस्थाओं से चुन कर आते हैं। चालीस सदस्यों को जिदगी भर के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है।

**राजनैतिक दल**—हंगरी की सरकार आजकल जिस दल के हाथ में है उस का नाम ‘राष्ट्रीय ऐक्य दल’ है। यह दल सन् १९२१ ई० में हंगरी के पुराने ‘कृषि दल’ और ‘ईसाई राष्ट्र दल’ दो दलों के मेल में बना या। सन् १९३१ ई० में इस दल के प्रतिनिधि-सभा में १५६ सदस्य थे। इस दल में छोटे जमींदार, सरकारी नौकर पेशा लोग, कुछ कैथोलिक पादरी, प्रोटेस्टेंट लोग और मालदार किसान अधिकतर होते हैं। अस्तु यह दल इन्हीं वर्गों के हितों का अधिक खयाल रखता है। इस दल के सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या पुराने हेप्सबर्ग राजवंश की हंगरी की गद्दी पर बैठाने की पक्षपाती है। मगर दल ने इस विषय में अभी तक कोई पक्का निश्चय नहीं किया है और इस प्रश्न को छुला रखा गया है। इसी दल के प्रयत्न से हंगरी की नई व्यवस्थापक सभा की ऊपरी सभा कायम की गई थी, जिस में धनिकों को खास स्थान दिया गया है। यह दल कृषि और सामाजिक सुधारों, किसानों के सहकारी आंदोलन को सहायता देने, कृषि और शिक्षा की उन्नति करने और माल ढोने की सहूलियतें उठाने का पक्षपाती है।

इस के बाद दूसरा खास राजनैतिक दल ‘ईसाई राष्ट्रवादी आर्थिक दल’ है। जिस को ‘जिमी दल’ भी कहते हैं। यह दल सन् १९२३ ई० में पुराने ‘लोन दल’ ‘ऐक्य दल’ और ‘ईसाई समाजवादी दल’ के सदस्यों ने मिल कर उनाया या। सन् १९३१ ई० में इस दल के प्रतिनिधि-सभा में ३२ सदस्य थे। इस दल के कार्य-क्रम और ‘ऐक्य दल’ के कार्य-क्रम में अधिक फर्क नहीं है। परंतु इस दल में दक्षिणायनी लोगों की ही संख्या अधिक है। खास तौर पर यह दल ‘सामाजिक सुधारों’ और ‘ईसाई प्रजा के आर्थिक संगठन का’ पक्षपाती है। यह दल सरकार का सहायक है।

तीसरा ‘समाजी प्रजासत्तात्मक दल’ है। यह दल पुराना है। इस का जन्म सन्

१८६४ ई० में हुआ था और इस की पुर्नघटना सन् १९१६ में हुई थी। मगर सन् १९२१ ई० में इस दल के 'प्रतिनिधि सभा' में सिर्फ १४ सदस्य थे। यह दल आजकल की सरकार का कट्टर विरोधी दल है। इस दल में अधिकतर उद्योगी मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। इस दल का कार्यक्रम एक प्रकार की नरम वैध समाजशाही है और यह पत्रों के नए राष्ट्रीय मित्रता के व्यवहार का पक्षपाती है। दूसरे छोटे दलों में मध्यम वर्ग के उदार यहूदियों का एक 'राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल', दूसरा एक 'राष्ट्रीय स्वाधीनता दल' है जिस को 'जाति रक्षक' और 'जाग्रत मेग्यारस' के नामों से भी पुकारा जाता है। यह दल कुछ कुछ फेसिस्टी दल से मिलता-जुलता है और वह हंगरी की पुरानी सीमाओं को प्राप्त करने और हेप्सबर्ग राजवंश को गद्दी पर बैठाने का पक्षपाती है। तीसरा एक 'लेजिटिमिस्ट दल' है जो फौरन हेप्सबर्ग राजवंश को गद्दी पर बिठाना चाहता है। खास प्रश्नों पर समाजी प्रजासत्तात्मक दल और पट्टह या बीस दूसरे दलों के सदस्य हमेशा व्यवस्थापक सभा में सरकार के विरुद्ध मत देते हैं।

## पोलैंड की सरकार.

### राज-व्यवस्था

आजकल का पोलैंड राष्ट्र-लड़ाई से पहले के आस्ट्रिया, जर्मनी और रूसी साम्राज्यों से लिए हुए भागों से बना है। अठारहवीं सदी तक पोलैंड एक स्वाधीन राजा-शाही राष्ट्र था। सब से विचित्र बात इस राजाशाही की यह थी कि राजा अपने खादानी मौरूसी हक से पोलैंड की राजगद्दी पर नहीं बैठता था। उस का चुनाव होता था। पोलैंड की पुरानी व्यवस्थापक-सभा में भी एक बड़ा विचित्र नियम यह था कि हर कानून की मंजूरी और फर की स्वीकृति के लिए सदस्यों की बहुसंख्या की मंजूरी काफी नहीं होती थी, सर्वसम्मति की आवश्यकता होती थी। किसी एक सदस्य के विरोध करने पर ही हर मतविदा रद्द हो सकता था। सिर्फ एक सदस्य व्यवस्थापक-सभा की बैठकों में बराबर हाजिर न हो कर व्यवस्थापक-सभा को भंग होने के लिए भी बाध्य कर सकता था। इस वाद्विषात राजनैतिक योजना के कारण पोलैंड की राजनैतिक उन्नति नहीं होती थी। राजा के चुनावों के झगड़ों से देश में कलह और फिसाद फैला रहता था और दूसरे लालची राजाओं को पोलैंड में दखल जमाने का लालच रहता था। आप्रकार पोलैंड के लालची पड़ोसी आस्ट्रिया, रूस और जर्मनी तीनों ने मिल कर सन् १७७२ ई० में पोलैंड के भाग का आपस में बटवारा कर लिया। पोलैंड की सीमा घटा दी गई, राजा को चुनने की प्रथा बंद करके मौरूसी राजाशाही स्थापित कर दी गई और व्यवस्थापक-सभा के एक सदस्य के विरोध से कारंवाई बंद हो जाने की प्रथा भी खत्म कर दी गई। सन् १७९३ ई० में एक दूसरा बटवारा किया गया जिस में पुराने पोलैंड राष्ट्र का रहा-सहा भाग भी घाँट

जा गया और पोलैंड का राष्ट्र ही यूरोप के नकशे से लुप्त हो गया। इस के बाद एक ताबंदी तक पोलैंड के लोग अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे। कई बार तिया भी हुई। मगर उन को कुचल दिया गया और पिछली यूरोप की लड़ाई के प्रारम्भ पर पोलैंड पर इन्हीं तीन राष्ट्रों का अधिकार कायम था।

पिछली यूरोप की लड़ाई में सभी लड़नेवाले राष्ट्र दबी हुई भीमों को ग्राजाद करने के लिए लड़ने का दावा करते थे। जिन राष्ट्रों का जिन देशों की रद्ददी में हिस्सा था, वे उन देशों की स्वाधीनता का अपने आप को पक्षपाती एलान करने लगे थे। अस्तु, आस्ट्रिया, जर्मनी और रूस भी अपने आप को पोलैंड की स्वाधीनता का पक्षपाती एलान करने लगे थे। अगस्त सन १९१५ ई० में पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के बाद, जर्मनी ने नगर में पोलैंड के एक स्वाधीन राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी थी और घोषणा के बाद ही पोलैंड से सेना भर्ती करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था। परंतु पोलैंड लोगों ने सिर्फ घोषणा से सतुष्ट न हो कर स्वाधीन पोलैंड की राज-व्यवस्था कायम होने पहले जर्मनी को सेनाएं देने से साफ इन्कार कर दिया। अस्तु, मजबूर हो कर जर्मनी को पोलैंड के लिए एक राज-व्यवस्था का फौरन एलान करना पड़ा था, जिस में पोलैंड के उस भाग में जिस पर जर्मनी का कब्जा था, एक ७० सदस्यों की धारा-सभा स्थापित किए जाने, धारा-सभा के सदस्यों को धारसा और लोड्ज नगरों की चुगियों के द्वारा नियुक्त किए जाने, धारा-सभा द्वारा 'कौंसिल ऑफ स्टेट' के आठ सदस्य और धारसा के गवर्नर जनरल द्वारा 'कौंसिल ऑफ स्टेट' के चार सदस्यों और प्रधान के नियुक्त किए जाने, पोलिश भाषा राष्ट्रीय भाषा होने, गवर्नर-जनरल के पास से आनेवालों प्रश्नों पर 'कौंसिल ऑफ स्टेट' के विचार करने और उस को धारा-सभा में मसविदा पेश करने का अधिकार होने तथा धारा-सभा को गवर्नर-जनरल के भेजे हुए प्रश्नों पर विचार करने और कर लगाने का अधिकार देने की योजनाएं की गई थीं। पोलैंड के लोगों ने इस राज-व्यवस्था को मंजूर नहीं किया। जर्मनी की स्थापित की हुई धारा-सभा की तरफ से मुत्त मोड़ कर उन्होंने अपनी एक 'पोलिश राष्ट्रीय सभा' स्थापित कर ली। यह राष्ट्रीय सभा चाहती थी कि 'कौंसिल ऑफ स्टेट' इस के मत से बने, 'कौंसिल ऑफ स्टेट' को कानून बनाने और सेना के प्रबंध में भाग लेने के अधिकार हों, एक मिन कैथोलिक राजवश से पोलैंड के लिए एक राज्य प्रतिनिधि नियुक्त किया जाय, और 'कौंसिल ऑफ स्टेट' में बीस सदस्य हों जिन में से आठ उस भाग से हों, जिस पर जर्मनी का अधिकार था और चार उस भाग से जिस पर आस्ट्रिया का अधिकार था और सिर्फ एक सदस्य को गवर्नर-जनरल नियुक्त करे। आखिरकार जर्मनी और आस्ट्रिया की ओर से एक 'अस्थायी स्टेट कौंसिल' स्थापित की गई और उस में कुछ दिनों तक पोलैंड के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कौंसिल की तरफ से १७ जनवरी १९१७ ई० को ३१ सदस्यों की एक कमेटी पोलैंड के लिए राज-व्यवस्था तैयार करने के लिए बनाई गई। उस की तैयारी की हुई राज-व्यवस्था छ महीने बाद 'स्टेट कौंसिल' में मंजूर भी हुई। मगर इसी बीच में पोलैंड में राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन बहुत बढ़ गया। विचारियों ने इत्तफाक कर दा और मई

मात में समाजवादी दल ने 'स्टेट कौंसिल' से अपना संबंध तोड़ लिया। जुलाई में 'प्रजासत्तात्मक दल' के नेता पिल्सूड्स्की के साथ श्री भी बहुत-से सदस्य स्टेट कौंसिल से अलग हो गए। स्टेट कौंसिल के बाकी सदस्यों ने पोलैंड की सेना से राजभक्ति की शपथ लेने का प्रयत्न किया। मगर उन को उस में सफलता नहीं मिली। जुलाई के अंत में ही जर्मनों ने पिल्सूड्स्की को एक किले में कैद कर दिया; अस्तु, दूसरे मास से 'स्टेट कौंसिल' के शेष सदस्यों ने भी काम करना बंद कर दिया।

मजबूर हो कर जर्मनों को पोलैंड के लिए एक नई राज-व्यवस्था का सितंबर सन् १९१७ में एलान करना पड़ा। इस नई राज व्यवस्था के अनुसार पोलैंड के सिरमौर, जर्मनी और आस्ट्रिया के राजशाहों की नियुक्त की हुई। तीन सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिधि समिति' मानी गई थी, और इस समिति के द्वारा नियुक्त किए हुए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रि-मंडल तथा प्रजा का जुनी हुई एक व्यवस्थापक-सभा की भी योजना की गई थी। 'राज्य प्रतिनिधि समिति' को पोलैंड में सब कुछ सत्ता दी गई थी और उस ने शीघ्र ही 'राइस्ट्यानू' नाम की पोलैंड के लिए एक धारा-सभा बना दी, मगर यह राज-व्यवस्था भी अधिक दिन न चली और जर्मनी के हाथ से लड़ाई का मैदान निकल जाने पर 'अस्थायी सधि' होते ही 'राज्य प्रतिनिधि समिति' पोलैंड का अधिकार पिल्सूड्स्की को सौंप कर रफूचकर हो गई। पिल्सूड्स्की के हाथ में सत्ता आते ही उस ने एक 'व्यवस्थापक-सम्मेलन' बुलाने का एलान निकाल दिया और २६ जनवरी सन् १९१८ की तारीख उस सम्मेलन के चुनाव के लिए तय कर दी। सेना के आदमियों को छोड़ कर पोलैंड के और सब २१ वर्ष के ऊपर के स्त्री और पुरुषों को चुनाव में मत देने का अधिकार दे दिया गया था। इस 'व्यवस्थापक-सम्मेलन' की बैठक ६ फरवरी सन् १९१८ को हुई और २० फरवरी को सम्मेलन ने पोलैंड की राज-व्यवस्था के अस्थायी मूल कानून पास किए। पिल्सूड्स्की ने अधिकार त्याग कर के सारा अधिकार सम्मेलन को सौंप दिया। मगर सम्मेलन ने फौरन ही उस को पित राष्ट्रपति चुन लिया। व्यवस्थापक-सम्मेलन को पोलैंड की सारी प्रभुता और कानून बनाने की सत्ता होने का भी एलान किया गया। व्यवस्थापक-सम्मेलन के अध्यक्ष को सभा में मजूर हुए कानूनों को राष्ट्रपति और एक मंत्री की सही से जारी करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रतिनिधि और व्यवस्थापक-सम्मेलन के सब प्रकार के फैसलों को अमल में लाने का अधिकार माना गया। राष्ट्रपति को मंत्रि-मंडल नियुक्त करने की सत्ता भी दी गई और उस को और मंत्रि-मंडल को व्यवस्थापक-सम्मेलन के प्रति जवाबदार माना गया। राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रपति के द्वारा निकलने वाले सारे हुक्मों पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होने की भी शर्त रखली गई थी। यह सारा प्रबंध अस्थायी था, क्योंकि व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने एक स्थायी राज व्यवस्था का मसविदा रखने के लिए एक कमेटी बना दी गई थी। इस कमेटी के बनाए हुए राज-व्यवस्था के मसविदे पर महीनों तक विचार हो कर

आखिरकार ८ जुलाई सन् १९२० को वह व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने पेश हुआ । फिर इस मसविदे पर व्यवस्थापक-सम्मेलन और देश की सारी संस्थाओं में आठ-नौ महीने तक खूब चर्चा हो कर, कट-छट कर सत्रह मार्च सन् १९२१ को पोलैंड की नई राज-व्यवस्था मंजूर हुई ।

इस राज व्यवस्था के अनुसार पोलैंड राष्ट्र की प्रभुता एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा में मानी गई है, जिस की 'डाइट' और 'सिनेट' दो सभाएं हैं । पोलैंड प्रजातंत्र के प्रमुख को प्रायः की तरह दोनों सभाएं मिल कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की बैठक में चुनती हैं । सिनेट की राय से डाइट को भंग करने का अधिकार प्रमुख को दिया गया है, मगर राष्ट्र की सेना का मुख्य अधिकार व्यवस्थापक-सभा के हाथ में रक्ता गया है, प्रमुख के नहीं । डाइट के सदस्यों की दो तिहाई संख्या की राय से इस राज व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है । मगर राज-व्यवस्था के अमल में आने की तारीख से दस वर्ष बाद, हर पच्चीस वर्ष में एक बार डाइट और सिनेट की सम्मिलित सभा की बहुसंख्या से परिवर्तन हो सकेंगे ।

**व्यवस्थापक-सभा**—पोलैंड प्रजातंत्र की व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाएं डाइट और सिनेट—प्रजा चुनती है । इक्कीस वर्ष के ऊपर के सब स्त्री और पुरुष डाइट के चुनाव में मत दे सकते हैं और २५ वर्ष के ऊपर के उस के लिए रजिस्ट्र हो सकते हैं । डाइट का पाँच वर्ष के लिए अनुपात निर्वाचन के अनुसार चुनाव होता है । सिनेट के सदस्यों का चुनाव पोलैंड के १६ प्रांतों से आबादी के हिसाब से होता है । सिनेट के सदस्य भी निर्वाचन के अनुसार चुने जाते हैं, मगर सिनेट के मतदारों की संख्या तीस वर्ष से अधिक होती है । सिनेट का चुनाव भी डाइट के काल, पाँच वर्ष के लिए ही किया जाता है और उस की जिंदगी डाइट के साथ खत्म हो जाती है । प्रजातंत्र का प्रमुख सिनेट के सदस्यों की ३ संख्या की राय से डाइट को उस की जिंदगी पूरी होने से पहले भी भंग कर सकता है, मगर डाइट भंग होने के साथ सिनेट भी भंग हो जाती है ।

कानूनी मसविदे पहले डाइट में पेश होते हैं । डाइट में पास हो जाने के बाद हर मसविदा सिनेट में भेजा जाता है । अगर सिनेट डाइट के मंजूर किए हुए मसविदे में तीस दिन के अंदर कोई उअर पेश नहीं करती है, तो तीस दिन की मियाद खत्म हो जाने पर प्रजातंत्र का प्रमुख उस को कानून एलान कर के अमल के लिए जारी कर देता है; परंतु तीस दिन के अंदर सिनेट के मसविदे में कोई संशोधन पेश करने या उस का गिरोध करने पर मसविदा फिर डाइट के पास विचार के लिए भेजा जाता है । उस संशोधन के डाइट में बहुसंख्या से मंजूर हो जाने या सदस्यों की ३/५ की राय से उस के रद्द हो जाने पर, जिस सूत्र में अंत में वह डाइट से निकलता है, उसी सूत्र में उस का कानून होना एलान कर दिया जाता है ।

**कार्यकारिणी**—प्रजातंत्र की कार्यकारिणी सत्ता प्रजातंत्र के प्रमुख के हाथ

में होती है, जो डाइट को सम्मिलित रूप से जवाबदार एक मन्त्रिमंडल द्वारा सारा काम करता है। डाइट और सिनेट की एक सम्मिलित राष्ट्रीयसभा की बैठक में उस का सात वर्ष के लिए चुनाव होता है। प्रमुख युद्धकाल को छोड़ कर राष्ट्र की सेना का सेनापति माना गया है। प्रमुख दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करने के लिए पोलैंड प्रजातन्त्र का प्रतिनिधि होता है और उस को उन से समझौते और संधिया करने का अधिकार होता है, जिन को पीछे से वह डाइट के सामने सूचना के लिए रख देता है। मगर बिना डाइट की राय के उस को लड़ाई या सुलह करने का हक नहीं होता है। राज-व्यवस्था को तोड़ने, राजद्रोह तथा फौजदारी के अपराध के लिए समा के आगे सदस्यों की हाजिरी और हाज़िर सदस्यों की दूँ सख्या के मत से डाइट प्रजातन्त्र के प्रमुख पर अभियोग चला सकती है। इस प्रकार का अभियोग सिर्फ उस 'स्टेट ट्रिबूनल' के सामने ही और तय किया जा सकता है, जिस को डाइट और सिनेट हर बैठक के प्रारम्भ में चुन लेती हैं। प्रजातन्त्र के प्रमुख की तरफ से ही आमतौर पर डाइट और सिनेट को बैठकों के लिए बुलावा भेजा जाता है। जिस काल में इन सभाओं की बैठकें नहीं होती हैं, उस में प्रमुख को ज़रूरत पड़ने पर फरमान निकालने का अधिकार होता है, जिन पर क़ानूनों की तरह ही अमल किया जाता है। मगर सभाओं की बैठक होते ही फौरन यह फरमान सभा के सामने मज़बूरी के लिए रख दिए जाते हैं। सभा उन को नामज़ूर कर सकती है।

राष्ट्र के आर्थिक जीवन का एकीकरण कर के उस के योग्य संचालन के लिए राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि आर्थिक समिति भी कायम की गई है, जिस के द्वारा राष्ट्र भर के सारे आर्थिक हितों का सरकार से सहकार होता है। स्थानिक शासन, स्थानिक सभाओं के प्रतिनिधि, और कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मिल कर चलाते हैं। मगर राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीय राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि नियंत्रण समिति भी होती है, जिस का काम प्रांतिक शासन की देख रेख करना होता है। इस समिति के अध्यक्ष का स्थान राष्ट्रीय मंत्रियों की बराबरी का होता है; परंतु वह मन्त्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, स्वतन्त्र रूप से अपने काम के लिए डाइट को जवाबदार होता है। इस समिति की देखरेख और डाइट के, जॉच-कमीशन नियुक्त कर के, स्वयं शासन की जॉच करने की सत्ता होने से, राष्ट्रीय सरकार की स्थानिक शासन पर काफी दाब रहती है।

**राजनैतिक दल**—'सर्वदल-संघ' नामक राजनैतिक दल सरकारी दल है। इस दल का कोई खास राजनैतिक प्रोग्राम नहीं है। वह पिल्सुड्स्की की पूरी सहायता करने और कार्यकारिणी की सत्ता बढ़ाने के लिए राज व्यवस्था में परिवर्तन करने में विश्वास रखता है। इस दल में पुराने दलों के वे सारे लोग हैं, जो पिल्सुड्स्की के पक्षपाती हैं। पुरानी सेना के सदस्य और अधिकारी, गरम दल के लोग, प्रजासत्तात्मक दल के लोग, सरकार के साथी समाजवादी, अनुदार दल के बड़े ज़मींदार तथा अमीर, व्यापारी और दिमागी घघों के लोग इत्यादि सभी तरह के आदमी इस दल में हैं।

दूसरा एक राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल है, जिस में अधिकतर धनवान, व्यापारी, जमींदार, साहूकार, दूकानदार और मध्यमवर्ग के लोग और कुछ पुराने विचार के किसान और मजदूर भी हैं। यह दल पित्सुइस्की का और पोलैंड में वसनेवाली अल्प संख्या जातियों के स्थानिक स्वराज्य के आंदोलनों का विरोधी है। वह किसानों के स्वयं में एकदम क्रांतिकारी सुधारों का भी विरोध करता है और क्रांति का विरोधी और कैथोलिक पथ का पक्षपाती है। इस दल के अनुयायियों में मिश्रविद्यालयों के बहुत से विद्यार्थी हैं और यह दल 'बड़े पोलैंड का डेरा'<sup>१</sup> नाम की फेसिस्ट संस्था से मिल कर काम करता है।

तीसरा एक किसान दल है, जिस में धनवान, शांतिप्रिय, जमीन सुधारों के पक्षपाती और जमीन जब्ती के विरोधी, धार्मिक किसानों का एक समूह, दूसरा एक छोटे जमींदारों और खेतों पर मजदूरी करने वाले किसानों का एक गरम समूह जो बिना मुआयजे के जमींदारी की जमीन जबरन के किसानों में बांट देने और राष्ट्रीय अल्प संख्या जातियों के स्थानिक स्वराज्य और धार्मिक बातों को राजनीति से दूर रखने का हामी है और तीसरा एक गरम किसानों का समूह शामिल है। चौथा एक 'समाजवादी दल' है जो इन दलों में सब से पुराना है। यह दल वैध आंदोलन के द्वारा समाजशाही कायम करने में विश्वास रखता है। इस दल में उद्योग-सधों के लोग, गरम विचारों के शिक्षित लोग, छोटे किसान और खेतों पर काम करने वाले मजदूर अधिकतर हैं। यह दल राष्ट्रीय अल्प संख्याओं को स्थानिक स्वराज्य देने का पक्षपाती है और पित्सुइस्की, उस की सरकार, और कम्युनिज्म दोनों का विरोधी है।

दूसरा एक 'ईसाई प्रजासत्तात्मक दल' है, जिस में अधिकतर मध्यमवर्ग के छोटे लोग, उद्योग धंधों के मजदूर, कारीगर और दूसरे पेशावर लोग होते हैं। यह दल नरम, प्रजासत्तात्मक और धार्मिक विचारों का अनुगामी है। एक राष्ट्रीय मजदूर दल भी है जिस में मध्य-पोलैंड की उद्योग सधों के सदस्य ही अधिकतर हैं। यह दल गरम देशमति और कैथोलिक-पथी का पक्षपाती है और 'ईसाई प्रजासत्तात्मक दल' से मिल कर काम करता है। एक समष्टिवादी दल भी है, जिस को सन् १९२८ और १९३० के चुनावों में गैर कानूनी करार दे दिया गया था।

पोलैंड में दूसरी लड़ाई के बाद बने हुए राष्ट्रीय की तरह राष्ट्रीय अल्प-संख्याओं की कठिन समस्या रखी रहती है। 'यूक्रानी राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक संघ' यूक्रानी जाति का एक नया 'यूक्रानी राष्ट्र' चाहती है। इस संघ में भी एक छोटा सा गरम दल भी है। हाइट रशन, जर्मन और यहूदी जातियों के भी अपने अलग अलग दल हैं।



## जेकोस्लोवाकिया की सरकार

**राज-व्यवस्था**—पिछली यूरोपीय लड़ाई में टूट जाने वाले सम्राज्यों के खंडहरों से पैदा होने वाला दूसरा नया राष्ट्र जेकोस्लोवाकिया है। यह नया राष्ट्र पुराने बोहेमिया राज्य और मोरेनिया, साइलेशिया, तथा स्लोवाकिया के सम्मेलन से बना है। लड़ाई से पहले स्लोवाकिया पर हंगरी का अधिकार था और दूसरे भागों पर आस्ट्रिया का अधिकार था। इस नए राष्ट्र की दो मुख्य जातियों—जेक जाति और स्लोवाक जाति का, स्वाधीनता के लिए लड़ाई का इतिहास काफी लंबा है, जो इस छोटे ग्रंथ की मर्यादा के बाहर है। जेक जाति जर्मनों से अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए और स्लोवाक जाति मैगारों से अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक लड़ती रही और खास कर जेक जाति की आजादी के लिए लड़ाई के फल-स्वरूप जेकोस्लोवाकिया आखिरकार एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।

जेक लोगों ने आजादी के लिए जब-जब सिर उठाया था, तब-तब उन को कुचल दिया गया था। मगर सन् १८६० ई० में आस्ट्रियन डाइट के एक सदस्य प्रोफेसर मेज़रिफ की अप्पत्तता में जो 'हकीमी दल' नाम का दल बना था, उस ने राष्ट्रीय आजादी का झंडा पड़ा कर के धीरे-धीरे नौजवानों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। इस दल ने बनते ही जर्मन दलों से झगड़े शुरू कर दिए थे, और सन् १८१३ ई० में तो यहां तक नौबत पहुँच गई थी कि जर्मन दलों ने इस दल के साथ मिल कर काम करने तक से इन्कार कर दिया था। लड़ाई छिड़ने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने और भी जोर पकड़ा। सरकार ने आंदोलन को कुचलना शुरू किया, बहुत-से आदमियों को जेल में ठूस दिया और बहुत

से राष्ट्रीय अस्त्रधारों को बंद कर दिया। प्रोफेसर मेजरिक को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा। मेजरिक ने मित्रराष्ट्रों को जा कर अपने देश के दुःखों की कहानी सुनाई। मित्रराष्ट्र आस्ट्रिया के शत्रु थे ही, उन्होंने मेजरिक का स्वागत किया और जेकोस्लोवाकिया को एक स्वाधीन राष्ट्र बनाना अपना ध्येय निश्चय कर के, मेजरिक को भावी जेकोस्लोवाकिया की राष्ट्रीय सरकार का राष्ट्रपति मान लिया। सन् १९१८ की छठे जनवरी को, आस्ट्रिया की व्यवस्थापक सभा में जितने 'ज़ेक' प्रतिनिधि थे, उन की और बोहेमिया, मोरेविया और आस्ट्रियन साइलेशिया की धारासमाजों के सदस्यों की, एक 'सम्मिलित-सभा' में, जेकोस्लोवाकिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा करने और युद्ध के बाद 'सधि-सम्मेलन' में भाग ले कर अपने अधिकारों को रक्षा करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। मित्र राष्ट्रों की विजय होते ही शत्रु साम्राज्याधीन जातियों की स्वाधीनता का मित्र राष्ट्रों की तरफ से एलान कर दिया गया। जेकोस्लोवाकिया की स्वाधीनता की शर्त तो अस्थायी मुलह तक में रक्खी गई। अस्तु, जेकोस्लोवाकिया को अपनी स्वाधीन राज व्यवस्था रचने के लिए रास्ता साफ हो गया और सितंबर का अंत होते एक जेकोस्लोवाक राष्ट्रीय सभा बन गई। २८ अक्टूबर सन् १९१८ ई० को इस 'राष्ट्रीय सभा' ने नए राष्ट्र की सरकार की लगाम अपने हाथों में ले ली।

फौरन ही राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों का एक 'व्यवस्थापक-सम्मेलन' बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। चुनाव करना। उस समय की परिस्थिति में असंभव था, इस लिए सारे राजनैतिक दलों से व्यवस्थापक-सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुन कर भेजने की प्रार्थना की गई। बोहेमिया के जर्मनों को छोड़ कर दूसरे सारे दलों के प्रतिनिधियों का व्यवस्थापक-सम्मेलन १४ नवंबर सन् १९१८ को बैठे, जिस में जेकोस्लोवाकिया को एक 'स्वाधीन प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र' एलान कर दिया गया, और प्रोफेसर मेजरिक को जन्म भर के लिए प्रजातन्त्र का प्रमुख चुन लिया गया। सरकार का कामकाज चलाने के लिए एक मन्त्रिमंडल भी चुना गया जो सम्मेलन को जवाबदार था। फिर एक साल तक एक तरफ तो यह सम्मेलन नए राष्ट्र की राज व्यवस्था गढ़ने का काम करता रहा, और दूसरी तरफ देश में अस्थायी कानूनों के द्वारा व्यवस्था कायम करने और मित्रराष्ट्रों से जेकोस्लोवाकिया राष्ट्र की सीमाएं निश्चित करने के प्रयत्न करता रहा। वारसेल्स, सेंट जर्मन और ट्रियानोन की सधियों में मित्र राष्ट्रों ने जेकोस्लोवाकिया राष्ट्र की स्वाधीनता और सीमाओं पर अपनी स्वीकृति की आखिरी छाप लगा दी। उस के बाद 'व्यवस्थापक सम्मेलन' २० फरवरी सन् १९२० को नए राष्ट्र की नई राज व्यवस्था स्वीकार कर के १५ अप्रैल को भंग हो गया। अप्रैल में ही नई राज-व्यवस्था के अनुसार जेकोस्लोवाकिया की व्यवस्थापक-सभा का चुनाव हुआ। सधियों के अनुसार इस नए राष्ट्र में बोहेमिया, मोरेविया, स्लोवाकिया, साइलेशिया का एक भाग और वारपेथियन पहाड़ के दक्षिण का रुथेनिया का भाग मिला कर छह सौ मील लंबी जमीन शामिल की गई थी, जिस पर करीब षेड करोड़ मनुष्य बसते हैं और जिन में से दो तिहाई जेक जाति के लोग हैं।

ज़ेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का जन्म एक अंतरराष्ट्रीय संधि की शर्तों के अनुसार होने के कारण वे शर्तें भी उस ही राज-व्यवस्था का स्वभावतः एक अंग बन गई हैं। इन शर्तों में ज़ेकोस्लोवाकिया में बसी हुई अल्प संख्या जातियों के अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त रुमेनिया के लिए एक ऐसी योजना की गई है जो एक स्वाधीन राष्ट्र की राज-व्यवस्था में भिन्नकुल नहीं चीज़ है। मित्र-राष्ट्रों और ज़ेकोस्लोवाकिया में होनेवाली सेंट जर्मेन की संधि के अनुसार रुमेनिया को ज़ेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का अंग मानते हुए भी उस को एक अलग धारासभा दी गई है, जिस को शास कर धार्मिक शिक्षा, भाषा और स्थानिक शासन के संध में कानून बनाने के अधिकार के अतिरिक्त उस सारी सत्ता के प्रयोग का भी अधिकार है, जो ज़ेकोस्लोवाकिया की धारासभा उस को देना पसंद करे। इस भाग के गवर्नर को ज़ेकोस्लोवाकिया प्रजातन्त्र के प्रमुख के द्वारा नियुक्त किए जाने पर रुमेनिया की धारासभा को जवाबदार होने की शर्तें भी रखी गई हैं। इस भाग को, जहाँ तक बने वहाँ तक अपने वारिंशों में से ही अपने अधिकारियों को नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया है। इस भाग को दिए हुए सारे अधिकार लीग ऑफ़ नेशन्स की रक्षा में रखे गए हैं और इस भाग को ज़ेकोस्लोवाकिया के खिलाफ़ लीग ऑफ़ नेशन्स से अपील करने का भी हक़ है। अस्तु, इस संधि में रुमेनिया को 'राष्ट्र के भीतर राष्ट्र' का राजनैतिक इतिहास में अनेकता स्थान दिया गया है और संधि की यह शर्तें ज़ेकोस्लोवाकिया की राज व्यवस्था का अंग बन गई हैं।

**व्यवस्थापक-सभा**—ज़ेकोस्लोवाकिया प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र होने से राष्ट्र की प्रभुता प्रजा में मानी गई है। प्रजा की चुनी हुई व्यवस्थापकसभा को राष्ट्र की सारी सत्ता होती है। राष्ट्रीयव्यवस्थापकसभा की दो सभाएँ हैं—एक प्रतिनिधि सभा, दूसरी सिनेट। प्रतिनिधि सभा में तीन सौ सदस्य होते हैं, जिन को २१ वर्ष के ऊपर के सारे स्त्री और पुरुष नागरिकों को, अनुपात निर्वाचन के अनुसार चुनने का हक़ होता है। प्रतिनिधियों की उम्र २६ वर्ष से अधिक होती है और उन को छः वर्ष के लिए चुना जाता है। छः वर्ष से पहले भी प्रतिनिधि-सभा को भंग किया जा सकता है। इसी प्रकार २६ वर्ष के ऊपर के तमाम स्त्री पुरुष नागरिकों को सिनेट के सदस्यों को अनुपात निर्वाचन के अनुसार चुनने का अधिकार होता है। मगर सिनेट के उम्मीदवार कम से कम चालीस वर्ष की उम्र के होने के चाहिए। सिनेट में १५० सदस्य होते हैं और उन को आठ वर्ष के लिए चुना जाता है।

'प्रतिनिधि सभा' में मज़ूर हो जाने वाले मसविदे 'सिनेट' के नामज़ूर कर देने पर प्रतिनिधि सभा में लौट कर पुनः विचार के लिए आते हैं और हाज़िर सदस्यों की आधी से अधिक संख्या उन के पक्ष में फिर होने पर वे कानून बन जाते हैं। अगर 'सिनेट' के सदस्यों की तीन चौपाई संख्या 'प्रतिनिधि-सभा' के किसी मसविदे को नामज़ूर करती है तो, 'प्रतिनिधि-सभा' में फिर उसे मज़ूर कर के कानून बनाने के लिए प्रतिनिधि-सभा के कुल सदस्यों को ३ संख्या की मज़ूरी की ज़रूरत होती है। 'सिनेट' से प्रारम्भ होनेवाले मसविदे एक बार प्रतिनिधि-सभा में नामज़ूर हो जाने पर अगर 'सिनेट' में फिर पाँच हो कर,

प्रतिनिधि-सभा में दोराय सदस्यों की आधी सख्या से अधिक के द्वारा नामजूर होते हैं तों वे रद्द हो जाते हैं । राष्ट्रीय आय-व्यय से सन्ध रखने वाले माल मसविदों और देश की रक्षा से सन्ध रखने वाले मसविदों का श्रीगणेश सिर्फ प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है ।

मन्त्रि मंडल के सदस्य व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं और उपसमितियों की कार्यवाई में भाग ले सकते हैं । हर एक सभा में सभा के सारे सदस्यों की दो तिहाई सख्या की हाजिरी होने पर ही, किसी प्रश्न पर मत लिए जा सकते हैं । राज व्यवस्था में सशोधन करने और युद्ध की घोषणा करने के लिए दोनों सभाओं के सारे सदस्यों की ३ सख्या की मजूरी की जरूरत होती है । प्रजातन्त्र के प्रमुख पर अभियोग चलाने की मजूरी के लिए सारे सदस्यों की दो तिहाई सख्या के दो तिहाई मतों की जरूरत होती है । मसविदे सरकार या सभाओं, दोनों की तरफ से विचार के लिए पेश किए जा सकते हैं । हर प्रश्न के विचार के लिए साध ही उस सन्ध में होने वाले खर्च का तखमीना भी, हमेशा विचार के लिए, पेश किया जाता है । मन्त्रि मंडल की जिदगी व्यवस्थापक-सभा के उस में विश्वास पर निर्भर होती है । फिर भी राज व्यवस्था में सशोधन के अतिरिक्त और किसी मसविदे को, व्यवस्थापक-सभा के नामजूर कर देने पर भी, मन्त्रि मंडल अपने सदस्यों के सर्वमत से उस मसविदे पर हवाले के द्वारा प्रजा की राय ले सकता है और प्रजा के स्वीकार कर लेने पर वह मसविदा कानून बन जाता है । प्रजातन्त्र के प्रमुख को भी पुनः विचार के लिए मसविदा व्यवस्थापक-सभा के पास अपनी राय के साथ वापस भेजने का अधिकार होता है और ऐसी हालत में व्यवस्थापक-सभा के सारे सदस्यों की आधी से अधिक सख्या के मसविदे के पक्ष में होने पर ही वह मसविदा अपनी पहली दूरत में अर्थात् बिना परिवर्तन के पास हो सकता है । मगर प्रजातन्त्र का प्रमुख चाहे तो प्रतिनिधि सभा को भग कर के और भी विचार करने के लिए दबाव डाल सकता है । मन्त्रि मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के लिए प्रतिनिधि सभा के सारे सदस्यों की बहुसख्या की हाजिरी और हाजिर सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है । अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर मन्त्रि मंडल इस्तीफा रख देता है, और प्रमुख नए मन्त्रि मंडल को नियुक्त करने की कोशिश करता है ।

प्रजातन्त्र के प्रमुख के नियुक्त किए हुए तीन जजों के, बड़ी शासन की अदालत के नियुक्त किए हुए, दो जजों और 'राष्ट्रीय' न्यायालय के किए हुए, दो जजों कुल सात जजों की एक 'व्यवस्थापकी अदालत' भी होती है जिस के सामने 'व्यवस्थापक सभा' के पास किए हुए प्रस्ताव और मसविदों के कानूनी या गैर कानूनी होने का विचार और फेसला हो सकता है ।

**कार्यकारिणी**—राज-व्यवस्था के अनुसार आम तौर पर प्रजातन्त्र का प्रमुख सात वर्ष के लिए, 'व्यवस्थापक-सभा' की दोनों सभाओं की एक सम्मिलित, बैठक में चुना जाता है और उस का दो बार से अधिक चुनाव नहीं हो सकता है । मगर प्रोफेसर मेज़रिक की देश के प्रति अमूल्य सेवाओं के कारण प्रोफेसर मेज़रिक को जन्म भर तक

बार-बार प्रजातंत्र का प्रमुख चुना जा सकता है। मगर चुनाव वाक्तावदा होने के लिए व्यवस्थापक-सभा के सारे सदस्यों की बहुसंख्या की हाजिरी और हाजिर सदस्यों की ३ संख्या की मंजूरी की क़ैद रखी गई है। प्रमुख के अधिकारों के प्रयोग की जवाबदारी मंत्रि-मंडल पर होती है। प्रमुख राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है और दूसरे देशों से व्यवहार के लिए जेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का प्रतिनिधित्व रूप होता है। प्रमुख राष्ट्र की सेनाओं का सेनापति भी होता है। मगर युद्ध की घोषणा वह सिर्फ व्यवस्थापक-सभा की मंजूरी ले कर ही कर सकता है। प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रि-मंडल और प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है। मगर मंत्रि-मंडल जवाबदार व्यवस्थापक-सभा को होता है। प्रमुख को व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं को उन की जिन्दगी से पहले भंग कर देने का भी अधिकार होता है। मगर अपने समय के आखिरी छः मास में प्रमुख अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों में प्रधान मंत्री, परराष्ट्र-सचिव, गृह-सचिव, अर्थ-सचिव, राष्ट्रीय रक्षा (सेना) सचिव, न्याय सचिव, शिक्षा-सचिव, व्यापार-सचिव, सार्वजनिक कार्य-सचिव, डाक-तार-सचिव, रेल-सचिव, कृषि-सचिव, कानून और सार्वजनिक शासन संगठन-सचिव, समाज हितकारी कार्य-सचिव और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सचिव होते हैं। 'दिसाव-किताब जाँच-अदालत' का अध्यक्ष सरकार का सदस्य होता है, मंत्रि-मंडल का नहीं। एक प्रमुख विभाग का अध्यक्ष भी होता है।

**अदालतें**—पोलैंड की तरह जेकोस्लोवाकिया में भी एक बड़ी 'दिसाव-किताब जाँच-अदालत' होती है, जो राष्ट्रीय राजधानी प्राग में बैठती है और जिस का काम राष्ट्रीय आय-व्यय, राष्ट्रीय क़र्ज़ों, सार्वजनिक संस्थाओं और हज़ारों, राष्ट्र के खज़ाने से दिए जाने वाला हमदादों और राष्ट्रीय शासन के अंतर्गत सार्वजनिक धन पर केंद्रीय नियंत्रण रखना होता है। पोलैंड की तरह ही यह अदालत वास्तव में अदालत नहीं होती है। एक मंत्रियों की हैसियत के स्वतंत्र अधिकारी की अध्यक्षता में यह विभाग सीधा व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता है।

जेकोस्लोवाकिया की सब से बड़ी न्याय की अदालत प्राग में बैठती है। इस के अतिरिक्त प्राग में बोहेमिया की प्रांतीय अदालत भी होती है, जिस की दीवानी, फ़ौजदारी और व्यापारी तीन प्रांतीय शाखाओं के सिवाय १५ ज़िला अदालतें और २३१ स्थानिक अदालतें हैं। मोरेविया और साइलेशिया की एक अलग प्रांतिक अदालत है। उसी प्रकार स्लोवाकिया और रुमेनिया का भी अलग न्याय-विभाग है।

इस के अतिरिक्त प्राग में एक बड़ी 'शासकी अदालत' दूसरी एक चुनाव के क़गड़ों के लिए 'चुनाव अदालत', तीसरी एक 'पेटेंट अदालत', चौथी एक 'व्यवस्थापकी-अदालत' और पाँचवीं एक 'बड़ी फ़ौजी अदालत' भी होती है।

**राजनैतिक दल**—यूरोपीय युद्ध के बाद उत्पन्न हुए तमाम यूरोप के नए राष्ट्रों की तरह जेकोस्लोवाकिया में भी अल्प-संख्याओं का प्रश्न खड़ा रहता है। छोटे-से इस राज के अर्ज़ को देखते हुए राजनैतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। मोरेविया

के कैथोलिक पथी किसानों का 'जेकोस्लोवाक कैथोलिक लोकदल' है। स्लोवाकिया के कट्टर रोमन कैथोलिक लोगों का 'स्लोवाक कैथोलिक लोकदल' है। बड़े व्यापारियों और साहूकारों और समाजवाद के विरोधी मालदार मध्यम वर्ग के लोगों का 'जेकोस्लोवाक राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल' है। मध्यम-वर्ग के व्यापारियों ने इस दल से अलग हो कर अपना एक अलग 'जेकोस्लाव मध्यम वर्ग व्यापारी दल' बना लिया है। छोटे ज़मींदारों और किसानों का 'प्रजातंत्रीय कृषिदल' है। जाति और समष्टिवादियों के विरोधी समाजवादी उद्योगी वर्ग का 'जेकोस्लोवाक समाजी प्रजासत्तात्मक उद्योगी दल' है, जिस की स्थापना सन् १८७८ ई० में हुई थी और जिस ने प्रजातन्त्र के प्रारंभ से ही सरकार का रचनात्मक कार्यों में साथ दिया है। इसी से मिलता जुलता दूसरा एक 'जेकोस्लोवाक राष्ट्रीय समाजी दल' है, जिस की स्थापना सन् १८९७ ई० में हुई थी और जिस में उद्योगी वर्ग के सिवाय दूसरे वर्गों के लोग भी हैं। देश भर में समष्टिवादियों का एक 'समष्टिवादी दल' भी है। 'जेकोस्लोवाक राष्ट्रीय समाजवादी दल' के कुछ श्रमंतुष्ट लोगों ने सन् १९२८ ई० में इस दल से अलग हो कर एक नया 'स्लाव राष्ट्रीय समाजवादी दल' बना लिया है, जो जर्मनों की परवाह न कर के स्लोवाक जाति से घनिष्ठता रखने का पक्षपाती है।

इन के अतिरिक्त जर्मन और मेग्यार जातियों के दलों में जेकोस्लोवाकिया में बसने वाले पुराने विचारों के कैथोलिक जर्मन भाषाभाषी लोगों का एक 'जर्मन ईसाई समाजवादी लोक दल' है, उसी के मुकाबले का दूसरा मेग्यार जाति का 'मेग्यार ईसाई समाजवादी दल' है। प्रजातन्त्र और समाजवादी विचारों के विरोधी, राष्ट्रीय विचारों के जर्मन लोगों का एक 'जर्मन राष्ट्रीय दल' है, उस के मुकाबले का दूसरा एक 'मेग्यार राष्ट्रीय दल' है। जेक प्रजातंत्रीय कृषिदल की नकल का जर्मनों का एक 'किसान-दल' भी है। समाज-सुधारों, राष्ट्रीय मामलों में कट्टर राष्ट्रीयता और जातीय स्वराज्य मानने वाले जर्मन लोगों का एक 'जर्मन राष्ट्रीय समाजवादी दल' है। जेकोस्लोवाकिया में बसने वाले समष्टिवादियों के विरोधी और राष्ट्रीय प्रश्नों में कट्टर जर्मन उद्योगी वर्ग का एक 'जर्मन समाजी प्रजासत्तात्मक उद्योगी दल' है। सारे जर्मन दलों से निकले हुए नरम राष्ट्रीय विचारों के लोगों का सन् १९२८ ई० में 'जर्मन आर्थिक सघ' नाम का भी एक नया दल और बन गया है।

जेकोस्लोवाकिया में इतने बहुत से राजनैतिक दल होने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो अल्प-संख्या जातियों की संख्या काफी बड़ी है—सारी आबादी के २३ फी सदी जर्मन हैं, और ७½ मेग्यार हैं। दूसरे राज व्यवस्था के अनुसार चुनाव अनुपात-निर्वाचन की पद्धति के अनुसार होते हैं, जिस से छोटे छोटे दलों को भी अपनी क्रिस्तम आज़माने का लालच रहता है। नए छोटे-छोटे दलों की बाढ़ रोकने के लिए हाल में एक क़ानून पास किया गया था, जिस के अनुसार हर एक दल को कम से कम एक चुनाव क्षेत्र से एक निश्चित संख्या मतों की जिस को उस क़ानून में 'चुनाव के मतों की कम से कम संख्या' माना गया था, मिलने पर ही दूसरी जगहों पर उस दल के लिए, दिए गए मत उस के पक्ष में गिने जायेंगे। इस क़ानून से अब नए बिल्कुल ही छोटे-छोटे दलों का बनना अवरय

फठिन हो गया है। मगर फिर भी व्यवस्थापक सभा में इतने दल रहते हैं कि किसी एक दल को साफ बहुसंख्या मिलना या उस को अकेले अपनी ताकत पर सरकार की रचना करना नामुमकिन होता है। अस्तु, आमतौर पर हमेशा कई दलों को मिला कर सरकार बना करती है। जेकोस्लोवाकिया में राजनैतिक दलों की बुनियाद भी दो ही कारणों पर होती है एक तो राजनैतिक और आर्थिक हितों का संघर्ष, दूसरे जातीय भेद भाव। सन् १९२६ ई० तक अधिकतर राजनैतिक दल जातीय भेदभावों पर बनते थे। जेकोस्लोवाकिया राष्ट्र के जन्म के बाद की पहली आठ सरकारें सिर्फ जेक और स्लोवाक जातियों के दलों के मेल से ही बनी थीं, क्योंकि जर्मन प्रजातन्त्र के विरोधी थे और उन्होंने ने सरकार से एक प्रकार का असहकार-सा कर रक्खा था। सन् १९२६ ई० से जर्मन असहकार छोड़ कर सरकार के काम में भाग लेने लगे हैं और तब से जो मन्त्रि मंडल बने हैं, उन मंत्रियों में 'जातीय' मतों का विचार न रख कर सिर्फ 'राजनैतिक' मतों का विचार रक्खा गया है।

जेकोस्लोवाकिया राष्ट्र की उत्पत्ति से अब तक उस की राजनीति के रंग में कोई प्रातिकारी फेरफार नहीं हुआ है। सन् १९२५ में समष्टिवाद की अवयव बाद आई थी और समष्टिवादी दल की एकदम ताकत बढ़ गई थी। मगर सन् १९२६ ई० में फिर उन के विरुद्ध धारा बढ़ उठी थी। 'व्यवस्थापक-सम्मेलन' में 'कृषि-दल' के ५५, 'राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल' के ४६, 'कैथोलिक दल' के २४, 'समाजी प्रजासत्तात्मक' के ५३, 'राष्ट्रीय समाजवादी दल' के ३५, और 'स्लोवाक दलों' के ४१ सदस्य थे। जर्मन और मेग्यार जातियों का असहकार के कारण एक भी प्रतिनिधि न था। सन् १९२० ई० में पहली बाक्तायदा व्यवस्थापक-सभा का चुनाव होने पर 'जेकोस्लोवाक दलों' के १६२ सदस्य और 'जर्मन और मेग्यार दलों' के कुल ८२ चुन कर आए थे। सिर्फ एक 'समष्टिवादी दल' का एक भी सदस्य नहीं था। सन् १९२५ ई० के चुनाव में 'जेकोस्लोवाक दलों' के १६३ सदस्य चुन कर आए थे और 'जर्मन और मेग्यार दलों' के कुल ७५ सदस्य। और 'समष्टिवादी दल' के एक दम ४१ सदस्य चुन कर आ गए थे। सन् १९२६ के चुनाव में 'जेकोस्लोवाक दलों' के २०५ सदस्य और 'जर्मन और मेग्यार दलों' के ८६ सदस्य चुन कर आए थे। 'समष्टिवादी दल' से कम हो कर ३१ सदस्य रह गए थे। 'जेकोस्लोवाक दलों' में कृषिदल के ४९, 'कैथोलिकों' के ४४, 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' के ४३, और 'राष्ट्रीय समाजवादियों' के ३२ सदस्य थे। 'जर्मन और मेग्यार दलों' में 'कृषिदल' के १६, 'कैथोलिकों' के १६, 'राष्ट्रीय दल' के १४, और 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' के २१ सदस्य थे। 'जेकोस्लोवाकिया के सिर्फ एक 'समष्टिवादी दल' में सब जातियों के सदस्य होते हैं। जर्मन और मेग्यार दलों के सरकार में भाग लेने के बाद से दोनों जातियों के एक से दल मिल कर एक होने लगे हैं।

# यूगोस्लाविया की सरकार

## राज-व्यवस्था

पोलैंड और जेकोस्लोवाकिया की तरह यूगोस्लाविया का नया राष्ट्र भी यूरोपीय युद्ध के बाद बना है। यूगोस्लाविया में पुरानी सरबिया की रियासत आ जाती है, जो पहले स्वयं एक स्वतंत्र राजशाही थी और जिस में लड़ाई के बाद करीब दुगुना और क्षेत्र मिला कर नया यूगोस्लाविया का राष्ट्र बनाया गया है। इस नए यूगोस्लाविया राष्ट्र का सरकारी नाम 'सर्ब, क्रोए्स, और स्लोवेंस की रियासत' रखा गया है। सरबिया पर बहुत दिनों तक टर्की का अधिकार था। मगर दूसरी बाल्कन रियासतों की तरह सरबिया भी सन् १८७८ ई० में स्वाधीन हो गया था। मगर सरबिया में बसी हुई जूगोस्लाव जाति की बहुत-सी संख्या सरबिया के बाहर आस्ट्रिया और हंगरी के साम्राज्य में भी फैली हुई थी। सरबिया के राजनैतिक नेता बहुत दिनों से अपनी विपत्ती हुई जाति को मिला कर, एक बड़ा राष्ट्र बनाना चाहते थे। उन का यह उद्देश, बिना आस्ट्रिया-हंगरी का हेप्सबर्ग साम्राज्य टूटे पूरा होना असम्भव था, और इस लिए हमेशा सरबिया और आस्ट्रिया में मनमुटाव रहा करता था। मित्र-राष्ट्रों ने अपने शत्रु आस्ट्रिया-हंगरी का साम्राज्य छिन्न-भिन्न कर देने के इरादे से अपने लड़ाई के उद्देशों में 'स्लाव जातियों की स्वतंत्रता' का भी एलान किया था। इस एलान से स्लाव जातियों की स्वाधीनता के आंदोलन को लड़ाई के ज़माने में बड़ी उत्तेजना मिली और मित्र-राष्ट्रों की विजय होते ही विपत्ती हुई दक्षिण यूरोप की सारी स्लाव जातियों का आखिरकार एक 'सर्ब, क्रोए्स, और स्लोवेंस का राष्ट्र' बना ही दिया गया।



सरबिया का राजनैतिक इतिहास, सन् १८३० ई० से ले कर सन् १८७८ ई० तक, राज-व्यवस्थाएं बनने और मिटने, निरंकुश राजाओं के राजत्याग और क़त्लों और तुर्किस्तान की अधीनता से मुक्त होने के प्रयत्नों की तथा अंत में सन् १८७८ ई० में स्वाधीनता प्राप्त कर लेने की एक लंबी भूल-भुलैया की कहानी है। सन् १८८८ ई० में सरबिया को इतिहास में पहली बार एक ऐसी राज-व्यवस्था दी गई थी, जिस के अनुसार सरकार के मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार माना गया था। मगर यह राज-व्यवस्था बहुत दिनों तक कागज़ पर ही रही; अमल में नहीं आई। सन् १९०३ ई० में इस राज-व्यवस्था को अमल के लिए पुनर्जीवित किया गया था। पिछली लड़ाई में स्लाव जातियों को गुलामी में जकड़े रखने वाले हेन्सवर्ग साम्राज्य के टूटते ही, नवंबर सन् १९१८ ई० में स्लाव जातियों के क्रोशिया, स्लावोनिया, अल्बानिया, इस्ट्रिया, योस्निया, हर्ज़ेगोविना, दक्षिण हंगरी, सरबिया और मोन्टेनीग्रो से आने वाले प्रतिनिधियों की एक सभा में इन सब भागों के मिल कर एक हो जाने और एक स्वाधीन राष्ट्र बन जाने की घोषणा कर दी गई थी। इस नई संघ का केंद्र सरबिया की रियासत थी। फ़ौरन ही चुनाव कर के व्यवस्थापक-सम्मेलन बना लेना संभव नहीं था, इस लिए इस 'संघ' की सरकार का काम क़िलहाल सरबिया की सरकार को सौंप दिया गया था और वही इस कमजोर, असंगठित 'राजनैतिक संघ' का एक साल तक काम चलाती रही। मगर यह अव्यवस्थित हालत बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। अस्तु, यारी कठिनाइयों का सामना करते हुए सन् १९२० ई० में एक 'व्यवस्थापक-सम्मेलन' के चुनाव का प्रबंध किया गया। नवंबर सन् १९२० ई० में इस नए राष्ट्र के विभिन्न भागों से ४२० प्रतिनिधि चुन कर आ गए। इन प्रतिनिधियों में फ़रीब आघे 'गरम दल' और 'प्रजासत्तात्मक दल' दो दलों के सदस्य थे। बाक़ी दूसरे छोटे-छोटे दलों के लोग थे, जिन में 'क्रोशियन किसान दल' और 'क्रोशियन राष्ट्रीय दल' बड़े दल थे।

सयुक्त क्षेत्रों के प्रतिनिधि रह सकते थे। मगर न जाने क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों के प्रचलित कानूनों और शासन के ढंगों को मिला कर इस राज-व्यवस्था में एक करने का भी प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रीय एकता का प्रचार करने के लिए राज-व्यवस्था में तय की हुई शिक्षापद्धति तत्त्व में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया है। राज व्यवस्था मजबूर हो जाने के बाद व्यवस्थापक सम्मेलन ही यूगोस्लाविया की पहली व्यवस्थापक सभा बन कर काम चलाने लगा था।

**राजाशाही**—इस राज व्यवस्था के अनुसार यूगोस्लाविया में वैध<sup>१</sup>, व्यवस्थापकी<sup>२</sup> और मौलसी राजाशाही है। कानून शासन और न्याय इत्यादि के समूह की सारी सत्ता और अधिकारों का जन्मदाता राजछत्र माना गया है। राजछत्र और यूगोस्लाविया की व्यवस्थापक-सभा को, जिस को स्क्रूपस्टीना कहते हैं, कानून बनाने का अधिकार माना गया है, और राजछत्र और मंत्रियों को शासन का अधिकार है। न्याय शासन राजा के नाम पर होता है। दूसरे देशों से समूह के लिए राजा ही राष्ट्र का प्रतिनिधिस्वरूप होता है। वही युद्ध की घोषणा करता और सधि करता है। दूसरे किसी देश पर हमला करने के लिए अवश्य स्क्रूपस्टीना की मजूरी हो लेने की जरूरत होती है, मगर यूगोस्लाविया पर हमला होने पर, बिना किसी इजाजत और मजूरी के, फौरन राजा के नाम पर युद्ध की घोषणा की जा सकती है। राज की दूसरे राष्ट्रों से की हुई सधियों के लिए भी आम तौर पर स्क्रूपस्टीना की मजूरी की जरूरत होती है, मगर जिन राजनैतिक समझौतों के अनुसार यूगोस्लाविया की जमीन किसी दूसरे के कब्जे में न चली जाती हो, या उस पर से किसी दूसरे राष्ट्र की सेनाएँ न गुजरती हों, उन समझौतों को करने के लिए राजा को व्यवस्थापक सभा की मजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है। व्यवस्थापक सभा को रोलने, स्थगित करने और भग करने से, राजा के एलानों पर, उस विभाग के जवाबदार मंत्री के सही की जरूरत होती है, जिस का यह काम होता है। व्यवस्थापक-सभा में मजबूर हो जाने वाले कानून को अमल के लिए एलान न करने का अधिकार राजा को नहीं होता है।

**व्यवस्थापक-सभा**—यूगोस्लाविया की व्यवस्थापक सभा को 'स्क्रूपस्टीना' कहते हैं। उस की सिर्फ एक ही सभा होनी है। जिस में ३१३ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इन प्रतिनिधियों को २१ वर्ष के ऊपर के सारे मर्द नागरिक, अनुपात निर्वाचन के अनुसार चार साल के लिए चुनते हैं। सभा के लिए उम्मीदवारों की कम से कम तीस वर्ष की उम्र होने की शर्त रखी गई है। सभा की सालाना बैठकों के सिवाय विशेष बैठकें भी होती हैं। मसविदे सभा में पेश हो जाने के बाद, सभा की उपसमितियों के पाँच विचार के लिए भेजे जाते हैं। उपसमितियों में से वापिस आ जाने पर फिर उन पर सभा में तफसीलवार विचार होता है। यूगोस्लाविया में जाति भेद का बहुत जोर होने के कारण यहां की व्यवस्थापक सभा में, प्रश्नों पर निष्पक्ष विचार न हो कर आमतौर पर जाति भेद के विचार से ही चर्चा होती है, जिस का नतीजा यह होता है कि सभा और सरकार में

एमेशा तना तनी रहती है, मंत्रि-मंडल जल्दी-जल्दी टूटते और बनते हैं और किसी प्रश्न पर अच्छी तरह विचार नहीं हो पाता है। राज-व्यवस्था में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनों को होता है। राजा की तरफ से संशोधन का प्रस्ताव आने पर व्यवस्थापक-सभा मंजूर हो जाती है और नया चुनाव होता है। व्यवस्थापक-सभा में से ही संशोधन का प्रस्ताव उठने पर, उस प्रस्ताव पर साधारण मसविदों की तरह विचार होता है और सारे सदस्यों की ६ संख्या के मतों से प्रस्ताव मंजूर होने पर व्यवस्थापक-सभा मंजूर हो जाती है और नया चुनाव होता है। नई चुन कर आने वाली व्यवस्थापक-सभा में दोनों हालतों में संशोधन के प्रस्ताव की आखिरी मंजूरी के लिए सारे सदस्यों की बहुसंख्या की जरूरत होती है।

**कार्यकारिणी**—यूगोस्लाविया की सरकार की एक और विचित्र बात यह है कि मंत्री, राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनों, जवाबदार माने गए हैं। प्रधान मंत्री और करीब चौदह मंत्रियों का मिला कर एक मंत्रि मंडल होता है, जो राजा के नीचे काम करता है और जिस को राजा ही नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति भी राजा ही करता है। व्यवस्थापक-सभा, मंत्रियों पर, और कानूनी कार्यवाई के लिए, एक खास राष्ट्रीय अदालत के सामने मुकदमा चला सकती है। मंत्रियों को कानूनों के अमल के लिए फरमान निकालने का अधिकार भी होता है; मगर उन के इस अधिकार पर व्यवस्थापक-सभा का नियंत्रण रहता है और सभा के बनाए हुए इस संबंध के कानून की सीमा के अंदर ही वह फरमान निकाल सकते हैं।

**स्थानिक शासन और न्याय**—स्थानिक शासन प्रांतों, जिलों और कम्पूनों द्वारा चलाने की सुंदर व्यवस्था की गई है। प्रांतों को स्वाभाविक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं की सुनियामद पर बनाने और आठ लाख की आबादी से अधिक का कोई प्रांत हरगिज़ न बनाने की शर्त भी राज व्यवस्था में रखी गई है। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शासन चलाने और यह देख-रेख रखने के लिए कि प्रांतिक अधिकारी वाक्यावदा और राज व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, हर प्रांत में एक-एक गवर्नर रखती है। जिलों का स्थानिक शासन वहां की चुनी हुई स्थानिक संस्थाएं करती हैं।

अधिकारियों के आपस के झगड़े और अधिकारियों और नागरिकों के झगड़ों का फौसला करने के लिए 'शासकी अदालतें' होती हैं। साधारण न्याय का शासन साधारण अदालतें करती हैं, जिन के न्यायाधीश हर प्रकार से स्वाधीन होते हैं। हर जिले के मुख्य नगर में एक अदालत होती है, जिस में पहले मुकदमे जाते हैं। यहां से 'अपील अदालत' में अपील जा सकती है। अपील की अदालतें देश भर में चार हैं, जिन के चार अलग-अलग क्षेत्र हैं। अपील की अदालतों की अपीलें भी 'बड़ी अदालतों' में जा सकती हैं, 'बड़ी अदालतें' देश भर में तीन हैं, जिन के तीन क्षेत्र हैं। बेलग्रेड प्रांत में व्यापारी झगड़ों के लिए एक 'व्यापारी अदालत' भी है। सरविया, मेसीडोनिया और मांटीनेग्रो में 'धार्मिक अदालतें' भी हैं जिन में सनातन रीति से विवाह करने वालों के

तलाक के ऋण्डे तय होते हैं। क्योंकि इन तीन प्रांतों में 'खिगिल मैरेज' जायज नहीं मानी जाती है। दूसरे प्रांतों में तलाक के ऋण्डों का पैसला साधारण दीवानी की श्रदा लतों में होता है। यूगोस्लाविया में अपराधियों को अधिक से अधिक पाँसी या बीस वष की सख्त सज़ा दी जा सकती है।

**दलबंदी और सरकार**—दुर्भाग्य से यूगोस्लाविया की नई राज-व्यवस्था के प्रारम्भ से ही यूगोस्लाविया में जाति भेद की उड़ी कलह रही। यदा तदा कि जातिगत ऋण्डों और क्रोशिया के लिए स्वराज्य आंदोलन के कारण व्यवस्थापकी सरकार का चलना तब यूगोस्लाविया में नायुमकिन हो गया। मन्त्रिमण्डलों को चुनने और उन को कायम रखने में तो शुरू से ही बड़ी कठिनाई रहती थी। मगर सन् १९२८ ई० में व्यवस्थापक-सभा के भवन में ही क्रोशियन नेताओं का बध हो जाने के बाद से, क्रोशिया के प्रतिनिधियों ने व्यवस्थापक सभा का बहिष्कार कर दिया और एलान कर दिया कि, "जब तक क्रोशिया को कानून बनाने और शासन करने की पूरी आज़ादी नहीं मिल जायगी, तब तक क्रोशिया के प्रतिनिधि यूगोस्लाविया की व्यवस्थापक-सभा में कदम नहीं रखेंगे।"

सन् १९२९ ई० में राजा ने एक घोषणा निकाली कि "अब राजा और प्रजा के बीच में कोई चीज़ न रहेगी। मैंने निश्चय किया है कि २८ जून, सन् १९२१ की राज व्यवस्था पर अब से अमल न होगा। अस्तु, आजकल इस राष्ट्र की अवस्था बड़ी अनिश्चित है। राजनैतिक दलों ने काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। उन को भग कर दिया गया है। शाही फरमान ही कानून समझे जाते हैं।" ३ अक्टूबर, सन् १९२९ के एक फरमान के अनुसार इस राष्ट्र का नाम 'सर्ब्स, क्रोट्स और स्लोवेंस की रियासत' के बजाय 'यूगोस्लाविया रियासत' एलान कर दिया गया है, जिस से राजा के केंद्रीय अधिकार को ही कायम रखने के मज़बूत ह्वादे का पता चलता है। दूसरे एक फरमान में 'राष्ट्र की रक्षा के विचार से' अखबारों और राजनैतिक संस्थाओं की आज़ादी निलुल कम कर दी गई है। नए मन्त्रिमंडल में क्रोट जाति के लोगों ने भी भाग लिया है। न मालूम आगे इस राष्ट्र के भाग्य में क्या है।

## रूमानिया की सरकार

### राज-व्यवस्था

रूमानिया का राष्ट्र भी यूगोस्लाविया की तरह लड़ाई के बाद बनने वाला हल नया ही राष्ट्र नहीं है। मगर हा, लड़ाई के बाद इस राष्ट्र में बेस्सारेविया, बिना और ट्रान्सिल्वानिया की ज़मीन मिल जाने से यह राष्ट्र लगभग दुगुना हो गया और उस की सरकार की भी कायापलट हो गई है। रूमानिया में पुरानी सन् १८६६ की हुई राज-व्यवस्था जिस का सन् १८७८ और १८८४ ई० में दो बार संशोधन भी था सन् १९२३ तक क़ायम थी। उस के अनुसार रूमानिया में राजाशाही थी जो द्वार मंत्रियों के द्वारा राजकार्य चलाती थी। दो सभाओं की एक व्यवस्थापक-सभा 'प्रतिनिधि सभा' को माल और शिक्षा की बुनियाद पर मताधिकार प्राप्त मतदारों १८ वर्ग चुनते थे। दूसरी सभा 'सिनेट' को बड़े मालदार मतदारों के दो नते थे। मगर लड़ाई के बाद रूमानिया का राष्ट्र दुगुना हो जाने पर मार्च १९२३ ई० में रूमानिया के नए विस्तृत राष्ट्र के लिए नई राज-व्यवस्था बनाई ।।

**कार्यकारिणी**—इस नई राज व्यवस्था के अनुसार भी रूमानिया में मौलवी १६ी क़ायम है जो राज-व्यवस्था में दिए गए अपने अधिकारों का एक व्यवस्थापक-जवाबदार मंत्रि-मण्डल के द्वारा प्रयोग करती है। राजा दूसरे राष्ट्रों से राजनैतिक कर सकता है। मगर जिन समझौतों से राष्ट्र के व्यापार और जल-पर्यटन

१नेविगेशन ।

[ ३२६ ]

इत्यादि पर असर पड़ता है, उन के लिए व्यवस्थापक-सभा की मंजूरी की जरूरत होती है। राज-व्यवस्था के अनुसार, राज-व्यवस्था में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त राजा को और कोई अधिकार नहीं होते हैं।

मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता है। मगर मंत्रि-मंडल के सदस्य व्यवस्थापक-सभा के बाहर से भी लिए जा सकते हैं। मंत्रि-मंडल के वे सदस्य जो व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं होते हैं, सभा की चर्चाओं में भाग ले सकते हैं, मगर सभा में मत नहीं दे सकते हैं। कम से कम एक मंत्री भी सभा में हाज़िर न होने पर किसी प्रकार की चर्चा सभा में नहीं चल सकती है। मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा के प्रति जवाबदारी का राज-व्यवस्था में जिक्र नहीं है। मगर इंग्लैंड की तरह रियाज के अनुसार उन को सरकार के सारे कामों के लिए व्यवस्थापक-सभा के सामने जवाबदार माना जाता है और उन की इस जवाबदारी से राजा उन को बचा नहीं सकता है।

**व्यवस्थापक-सभा**—क़ानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं—‘प्रतिनिधि सभा’ और ‘सिनेट’ में होती है। इन तीनों की तरफ से क़ानूनी मसविदे विचार के लिए पेश किए जा सकते हैं। बिना तीनों की मंजूरी के कोई मसविदा क़ानून नहीं बन सकता है। रूमानिया की राज-व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि व्यवस्थापक-सभा में मंज़ूर हो जाने वाले क़ानूनों को, राजा के बजाय, न्याय-सचिव अमल के लिए एलान करता है। दोनों सभाएं जाँच-पड़ताल, पूछ-ताछ और अर्ज़ों के द्वारा सरकार के शासन पर हुकूमत रखती हैं।

प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का चुनाव, २१ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक, अनुपात-निर्वाचन की पद्धति के अनुसार करते हैं। रूमानिया में, स्विटज़रलैंड के कुछ भागों की तरह, मतदारों के लिए चुनाव में अपने मत का प्रयोग करना क़ानूनन अनिवार्य होता है। ‘प्रतिनिधि-सभा’ के उम्मीदवारों की उम्र कम से कम २५ वर्ष की होनी चाहिए। ‘सिनेट’ में दो प्रकार के सदस्य होते हैं—एक चुने हुए और दूसरे अपने अधिकारों और पदों के कारण। चुने हुए सदस्यों के एक भाग को ४० वर्ष के ऊपर के मतदार उसी दंग पर चुनते हैं, जिस प्रकार प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाते हैं। दूसरे एक भाग को, एक डिपार्टमेंट के लिए एक सदस्य के हिसाब से, सारे स्थानिक सभाओं के सदस्य चुनते हैं। तीसरे एक भाग को व्यापारी, उद्योगी, मज़दूरों और कृषि-संस्थाओं के खास तौर पर बनाए गए छः क्षेत्र अलग-अलग अपनी बैठकों में चुनते हैं। चौथे एक भाग को विश्वविद्यालयों के अध्यापक, हर विश्वविद्यालय के लिए एक सदस्य के हिसाब से, चुनते हैं। अपने अधिकारों और पदों के कारण ‘सिनेट’ के सदस्य बन कर बैठने वालों में ऊँचे धार्मिक संस्थाओं के अधिकारी, विद्वान संस्थाओं के सदस्य, ग़त प्रधान मंत्री और धारा-सभाओं के अध्यक्ष और कुछ पेंशनयाप्त जेनरल होते हैं। मगर इस सब सदस्यों की उम्र कम से कम चालीस वर्ष होने की शर्त होती है।

<sup>१</sup>स्थानिक शासन का सबसे बड़ा क्षेत्र।

सरकार और व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों के मतविदे तैयार करने और कानूनों का क्रम ठीक रखने के लिए सभा की एक 'घारा समिति' भी होती है। आय-व्यय संबंधी मतविदों को छोड़ कर और सारे मतविदों पर इस समिति की पहले राय ली जाती है। राज-व्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव भी राजा या दोनों सभाओं में से किसी सभा की ओर से उठ सकते हैं। संशोधन का प्रस्ताव पेश होने पर पहले दोनों सभाएं, अलग-अलग अपनी बैठकों में, सारे सदस्यों की बहुसंख्या से, यह निश्चय करती हैं कि उस संशोधन के प्रस्ताव की जरूरत है या नहीं। उस की जरूरत के बारे में दोनों सभाओं का एकमत हो जाने के बाद दोनों सभाओं के सदस्यों का एक 'मिश्रित कमीशन' उस संशोधन का रूप तय कर के सभा में पेश करता है। उस संशोधन को दोनों सभाओं में अलग-अलग पंद्रह दिन के अंतर से दो दो बार पढ़ा जाता है। फिर दोनों सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में दोनों सभाओं के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की हाज़िरी और हाज़िर सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों से उस संशोधन का आखिरी रूप निश्चय होता है। इस के बाद दोनों सभाएं मंग हो जाती हैं और नया चुनाव होता है। नई चुन कर आने वाली सभाएं और राजा मिल कर फिर उस संशोधन पर विचार करते हैं और इन सभाओं में फिर उस को मंज़ूर करने के लिए दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्यों की हाज़िरी और हाज़िर सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों की जरूरत होती है। इन वादियात भूल-भुलैयाओं में से राज-व्यवस्था के बड़े आवश्यक और बहुत थोड़े संशोधन ही सफलतापूर्वक निकल पाते हैं।

**स्थानिक शासन और न्याय**—प्रारंभ में स्थानिक शासन भी बिल्कुल केंद्रीय सरकार के ही हाथों में था। मगर अब स्थानिक शासन के प्रबंध में सुधार हो गया है और स्थानिक संस्थाओं को स्थानिक शासन के बहुत कुछ अधिकार दे दिए गए हैं।

रुमानिया की सबसे बड़ी 'राष्ट्रीय अदालत' के नीचे बारह अपील की अदालतें, हर जिले के लिए एक अदालत और हर तहसील और कस्बे के लिए एक-एक मजिस्ट्रेट की अदालतें होती हैं। सबसे बड़ी अदालत सिर्फ इस बात पर विचार करती है कि अभियोगों के विचार में कानून का पालन हुआ है कि नहीं।

**राजनैतिक दल**—बड़ी जागीरों और ज़मींदारियों के सन् १९१६ ई० में टूट जाने पर और सर्वसाधारण को मताधिकार मिल जाने पर पुराना 'अनुदार दल' टूट गया था। मगर पुराने 'उदार दल' पर किसानों के गरम दल और समाजवादी दल के हमलों के कारण यह दल लड़ाई के बाद 'अनुदार दल' बन गया था, यह दल श्रमीर व्यापारियों और साहूकारों का दल होने से उस को उन्हीं हितों का अधिक ख्याल रहता है और इसी लिए वह पुरानी मर्यादाओं को कायम रखने का पक्षपाती है। खेती-बारी के हितों से संबंध रखने वाला दूसरा एक 'राष्ट्रीय कृषि-दल' है। रुमानिया की ८० फी सदी आबादी किसानों की होने और सारे देश की ज़मीन का लग

हाथ में होने से इस दल का रुमानिया में सब से अधिक जोर है। इस दल का राजनैतिक कार्य-क्रम उदार है और आर्थिक कार्य-क्रम में देश की हालत के अनुसार 'सहकारी कार्य-क्रम का पक्षपाती है।

उदार दल से मिलता-जुलता पुरानी तबियत का एक दूसरा 'लोकदल' भी है। सर्वदल मंत्रि-मंडल का बनना असंभव होने पर राष्ट्रीय उदार दल के हाथ में सरकार की वागडोर सन् १९२७ ई० में आ गई थी। मगर रुमानिया के राजा फर्डिनेंड के मर जाने के बाद उत्तराधिकारी राजकुमार करोल के एक स्त्री को ले कर देश से भाग जाने और रुमानिया के तख्त पर न बैठने के कारण राज्य का काम चलाने के लिए जो राज्य-प्रतिनिधि क़ायम हुआ था, उस ने 'उदार दल' के मंत्रि-मंडल को बर्खास्त कर दिया था और सरकार की वागडोर 'राष्ट्रीय कृषि-दल' को सौंप दी थी, दूसरे चुनाव में 'उदार दल' की जिस के हाथ में लड़ाई के बाद से बराबर रुमानिया की सरकार की वागडोर रही थी, भयंकर हार हुई थी और राज्य-प्रतिनिधि का 'उदार दल' के हाथ से सरकार ले लेना प्रजा मत के अनुसार साबित हुआ। मगर जून सन् १९३० ई० में राजकुमार करोल के रुमानिया लौट आने और तख्त पर बैठ जाने के बाद रुमानिया के राजनैतिक दलों में बड़ी गड़बड़ मच गई। हर राजनैतिक दल में राजा करोल के पक्षपातियों और विरोधियों के दो गिरोह बन गए थे। 'राष्ट्रीय कृषि-दल' की बहुसंख्या करोल की समर्थक थी। मगर कृषि-दल के भीतरी झगड़ों और आर्थिक संकटों में पँस जाने से कृषि-दल के मंत्रि मंडल को अक्टूबर सन् १९३० ई० में इस्तीफ़ा रख देना पड़ा था, फिर भी 'कृषि-दल' का ही एक दूसरा मंत्रि-मंडल बनाया गया। मगर उस को भी ८ अप्रैल, सन् १९३१ ई० को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। अंत में प्रोफ़ेसर की अध्यक्षता में १६ अप्रैल को सब दलों से सदस्यों को ले कर एक 'संयुक्त सरकार' बनाई गई थी।

रुमानिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'उदार दल' है जिस का ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से मज़बूत संगठन रहा है और जिस के हाथ में लड़ाई के बाद से सन् १९२८ ई० तक लगातार सरकार की लगाम रही थी। दूसरा एक 'लोकदल' है जो सन् १९२० ई० तक मुख्तलिफ़ विचारों के लोगों की एक संघ की तरह था, सन् १९२० ई० के बाद से वह एक बाकायदा दल बन गया है। तीसरा 'राष्ट्रीय कृषि-दल' है जो लड़ाई के बाद बने हुए 'किसान-दल' और ट्रान्सिलवेनिया के 'राष्ट्रीयवादियों' के मेल से बना था। चौथा एक 'राष्ट्रीय दल' है जो राष्ट्रीय कृषि-दल से मिलने का विरोधी होने से अलग एक छोटा-सा दल बन कर रह गया है। पाँचवां रुमानिया के सारे समाजवादियों का एक 'समाजवादी दल' है। मगर इस दल का एक भी सदस्य व्यवस्थापक-सभा में नहीं है। छठा एक 'ईसाई रक्षण-संघ दल' है जिस का 'राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल' के नाम से सन् १९०७ ई० में जन्म हुआ। सातवां एक जर्मन लोगों का 'जर्मन व्यवस्थापकी दल' है। हंगरी और बलगोरिया की अल्प-संख्या जातियों के भी 'मेग्यार दल' और 'बलगोरियन दल' नाम के दो छोटे-छोटे दल हैं।



## टर्की की सरकार



**राज-व्यवस्था**—हमारे महाद्वीप एशिया को यूरोप से मिलाने वाले एशिया के यूरोप की सीमा पर द्वारपाल टर्की की सरकार की भी लड़ाई के बाद नितकुल खरत बदल गई है। तुर्क लोगों ने एक ज़माने में अपनी तलवार के जोर से टर्की साम्राज्य मध्य यूरोप और मित्र तरु पैना लिया था, मगर बाद में टर्की के सुल्तानों को हरम और दस्तरखानों से ही फुरसत न रहने के कारण और यूरोप के ईसाई राष्ट्रों के भयकर हमलों और बूट राजनीति के कारण तथा अपने घरेलू झगड़ों और दगाबाज़ियों के कारण टर्की की हालत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि यूरोप के राष्ट्रों में उस का नाम 'यूरोप का नीमार' पड़ गया था। लड़ाई के ज़माने तरु इस साम्राज्य की सरकार निरी सुल्तान शाही अर्थात् निपट राजाशाही थी। यूरोपीय राष्ट्रों के जोर डालने पर टर्की के सुल्तान अब्दुलहमीद द्वितीय ने सन् १८७६ ई० में अपने देश के लिए एक राज व्यवस्था का एलान किया था। इस राज-व्यवस्था के अनुसार टर्की में आजन्म नियुक्त सदस्यों की 'सिनेट' और प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की 'प्रतिनिधि सभा', दो सभाओं की एक व्यवस्थापक-सभा कायम की गई थी। व्यवस्थापक सभा की पहली बैठक भी १६ मार्च, सन् १८७७ ई० हुई थी, मगर उसी साल टर्की और रूस का युद्ध छिड़ जाने के कारण बाद में व्यवस्थापक सभा की बैठकें बंद कर दी गईं और फिर सन् १९०८ ई० में 'नौ जवान तुर्क दल' ने टर्की में क्रांति कर के सुल्तान अब्दुलहमीद को तख्ता से उतार दिया था, और पुरानी राज-व्यवस्था पर सरकार को अमल करने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरे साल इस राज-व्यवस्था में संशोधन भी हुआ था, मगर सरकार में फिर भी

लड़ाई के ज़माने तक निपट निरकुशशाही ही चलती रही और 'प्रतिनिधि-सभा' का सरकार पर कुछ क़ायू नहीं था।

मगर यूरोप की लड़ाई में जर्मनी के साथ ही टर्की की कमर टूट जाने पर मित्र-राष्ट्रों से सधि करने में सुल्तान ने जो कमज़ोरी दिखलाई और उन को जो-जो वैज्ञानिकियाँ सही पड़ी, उस ने तुर्कों के दिलों में एक आग लगा दी। सुल्तान की मित्र-राष्ट्रों से की हुई सन् १९१२ ई० की 'संधि की सधि' को तुर्कों ने मज़ूर नहीं किया। उन्होंने मुस्तफ़ा क़माल पाशा की अध्वक्षता में अगोरा को अपना केंद्र बना कर टर्की की स्वाधीनता कायम रखने के लिए ऐसी भयंकर लड़ाई की कि आखिरकार मित्र राष्ट्रों को मजबूर हो कर टर्की के राजनैतिक नेताओं से लज़्ज़ान में सन् १९२२-२३ ई० में एक दूसरी सधि करनी पड़ी, जिस के अनुसार कुस्तुनतुनिया और यूस पर तुर्कों का अधिकार कायम रहा। जिस समय तुर्क अपनी हस्ती कायम रखने के लिए जान हथेली पर रख कर लड़ रहे थे, उसी समय उन के नेता मुस्तफ़ा क़माल की ओर से सन् १९०८ ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्थापक-सभा बनी थी, उस के सदस्यों को अगोरा में मिलने के लिए बुलावा भेज दिया गया था। इस सभा ने एकत्र हो कर अग्रेल सन् १९२० ई० में 'एशिया माइनर की राष्ट्रीय टर्की सरकार' को तुर्क जाति की प्रभुता का 'एक मात्र प्रतिनिधि' एलान कर के सुल्तान की सरकार और कुस्तुनतुनिया में बैठने वाली व्यवस्थापक-सभा को तुर्कों की सरकार न होने का एलान कर दिया। फिर नवंबर सन् १९२२ ई० में इसी सभा ने सुल्तान को टर्की की गद्दी से उतार देने, तुर्क साम्राज्य के खत्म हो जाने और उस के हाथों में नए 'तुर्क राष्ट्र' की स्थापना होने का एलान किया। बाद में इस सभा ने अगोरा में बैठ कर २६ अक्टूबर सन् १९२३ को पुरानी टर्की की राज-व्यवस्था में इतने फेर पार किए कि उस को बिल्कुल बदल कर नया ही बना दिया। नए तुर्क राष्ट्र को 'प्रजातंत्र' घोषित कर के इसी सभा में मुस्तफ़ा क़माल को नए प्रजातंत्र का प्रमुख घोषित कर दिया गया। बाद में सन् १९२४ ई० में इस राज-व्यवस्था की फिर पुनर्पट्टा कर के उस को बिल्कुल 'यूरोपीय सरकारों' के साँचे में ढाल दिया गया।

**व्यवस्थापक-सभा**—नए तुर्क प्रजातंत्र की व्यवस्थापक सभा को 'यही राष्ट्रीय सभा'<sup>१</sup> के नाम से पुकारते हैं। यूगोस्लाविया की तरह इस व्यवस्थापक सभा की भी एक ही सभा होती है, जिस को क़ानून बनाने और कार्यकारिणी की सारी प्रभुता होती है। अठारह वर्ष के ऊपर के हर तुर्क नागरिक को राष्ट्रीय सभा के चुनाव में मत देने और तीस वर्ष से ऊपर के हर तुर्क मतदार को राष्ट्रीय सभा के लिए सम्मिदवार होने का हक़ होता है। सभा का चुनाव चार साल के लिए किया जाता है और उस की आम तीर पर साल में एक बार बैठक होती है, मगर साल भर में चार मास से अधिक सभा की बैठकें बंद नहीं रह सकती हैं और इस चार मास की छुट्टी का कारण राज-व्यवस्था में 'सदस्यों को अपने चुनाव के क्षेत्रों में जा कर सरकार पर हुकूमत करनेवाली शक्तियों को सगठित

करने और आराम और तफरीह का मौका देना' बताया गया है। सभा के सदस्यों के पाँचवें भाग की माँग पर या प्रजातन्त्र के प्रमुख या मन्त्रिमण्डल के प्रधान की माँग पर राष्ट्रीय सभा की खास बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय-सभा प्रश्नों, पूछ-ताछ, और जाँच के द्वारा सरकार पर अपनी देख रेल और दृढ़मत रखती है। साधारण कानूनों को बनाने की सत्ता के अतिरिक्त 'राष्ट्रीय सभा' को सुलह की सधिया और समझौते, युद्ध की घोषणा, 'बजट', कमीशन के बनाए हुए कानूनों को जाँच कर के मंजूर करने, सिक्का गढ़ने, एक हद तक अपराधियों को आम माफी देने, व्यक्तिगत अपराधियों की सज़ा कम करने और माफी देने और पाँसी की सज़ाओं को बहाल करने के अधिकार भी दिए गए हैं।

राष्ट्रीय सभा के एक तिहाई सदस्यों की राय से राज व्यवस्था में संशोधन का कोई संसदविदा पेश किया जा सकता है, मगर उस के मंजूर होने के लिए सभा के दो तिहाई सदस्यों के मतों की जरूरत होती है, परन्तु टर्की की राज-व्यवस्था की पहली धारा—जिस में टर्की के प्रजातन्त्र होने की घोषणा की गई है—के संशोधन में कोई संशोधन पेश नहीं हो सकता है।

**कार्यकारिणी**—प्रजातन्त्र के प्रमुख को राष्ट्रीय सभा अपनी जिंदगी यानी चार साल के लिए चुनती है। प्रमुख का समय पूरा हो जाने पर उस को फिर खड़ा होने का अधिकार भी होता है। राष्ट्रीय-सभा में पास होने वाले कानूनों को प्रमुख दस दिन के अंदर जारी करता है, मगर उन को जारी न कर के अपने वजूदात के साथ उन को राष्ट्रीय-सभा के पास फिर विचार करने के लिए भी वह भेज सकता है। राष्ट्रीय-सभा उस के वजूदातों की परवाह न कर के उन कानूनों को फिर जैसा का तैसा पास कर सकती है, और उस हालत में प्रमुख को मंजूर करने उन्हें जारी करना पड़ता है, मगर राज व्यवस्था के संशोधन और आय व्यय संबंधी प्रस्तावों को रोकने का अधिकार बिल्कुल प्रमुख को नहीं होता है। प्रजातन्त्र के प्रमुख के सारे हुकमों पर प्रधान मंत्री और जिस विभाग से वह हुकम संबंध रखता है, उस विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। राज-द्रोह के अपराध के लिए प्रमुख सिर्फ राष्ट्रीय-सभा को जवाबदार होता है, किसी अदालत में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। टर्की प्रजातन्त्र के प्रमुख को बड़ी ताकत होती। राज-व्यवस्था में उस को जो अधिकार दिए गए हैं, उन के अनुसार वह किसी कदर मांस के और किसी कदर स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल के प्रमुख की तरह कहा जा सकता है। मगर ताकत में इन दोनों देशों के प्रमुखों और अमेरिका प्रजातन्त्र के प्रमुख से भी टर्की का प्रमुख जबरदस्त होता है। टर्की का प्रमुख व्यवस्थापक-सभा में सब से बड़े दल का नेता भी होता है; क्योंकि अपने दल की सहायता से ही व्यवस्थापक सभा में वह चुना जाता है। राष्ट्र सभा के बहुसंख्या दल का नेता होने से वह जैसा चाहे वैसा राष्ट्र सभा को चला सकता है, मगर इस के अलावा राष्ट्र सभा के अध्यक्ष को भी वही चुनता है। अस्तु, टर्की प्रजातन्त्र के प्रमुख को चतुर्मुख की सत्ता होती है—प्रजातन्त्र के प्रमुख की, मन्त्रिमण्डल के प्रधान को नियुक्त करने वाला होने अर्थात् मन्त्रिमण्डल के प्रमुख

की, उसी तरह राष्ट्र-सभा को प्रमुख की और राष्ट्र-सभा के सब से बड़े दल के प्रमुख की। अतएव जितनी उस को सत्ता होती है, उतनी किसी प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र के प्रमुख को दुनिया में नहीं होती है।

प्रजातंत्र का प्रमुख 'संचालकों की समिति' के प्रधान को नियुक्त करता है। 'संचालक' इंग्लैंड के मंत्रियों की तरह होते हैं और उन के प्रधान की हैसियत इंग्लैंड के प्रधान मंत्री के बराबर की होती है। प्रधान राष्ट्र-सभा के सदस्यों में से 'संचालकों' को चुन कर उन को अपने प्रोग्राम के सभा के सामने पेश करता है और अपनी नियुक्ति के एक सप्ताह के भीतर ही राष्ट्र-सभा से 'विश्वास का मत' माँगता है। अस्तु, 'संचालकों की समिति' ही टर्की का मंत्रिमंडल होता है और उस के सदस्य सम्मिलित रूप से और अलग-अलग राष्ट्र-सभा को जवाबदार होते हैं।

राष्ट्र-सभा अनुभवी और छास बातों में दक्ष लोगों की एक 'कौंसिल ऑव स्टेट' भी चुनती है। यह सभा शासन-संबंधी प्रश्नों को तय करती है और ठेकों, रियायतों और सरकार की तरफ से पेश होने वाले मसविदों पर सरकार को सलाह देती है। संचालकों के बनाए हुए नियमों और हुकों को भी इस सभा की सलाह से लेने के बाद जारी किया जाता है।

**राजनैतिक दल और सरकार**—टर्की में यह एक 'लोकदल' का ही तरीका चलता है। इस दल को मुस्तफा कमाल पाशा ने सन् १९२३ ई० में बनाया था और इस दल ने सरकार पर कब्जा जमा कर मुस्तफा कमाल पाशा को एक तरह से टर्की का कर्ता-धर्ता बना दिया है। इटली और रूस की तरह टर्की में प्रजासत्तात्मक सरकार की धमियां खुलम-खुला तो नहीं उड़ाई जाती हैं। मगर उन दोनों देशों की तरह टर्की में भी एक ही दल का राज है। अस्तु, सरकार का रूप प्रजासत्तात्मक होने पर भी मुस्तफा कमाल का मुखौटा और स्टेलिन की तरह बिल्कुल 'स्वाधीन शासक' की सत्ता है।

लोकदल का आज कल प्रधान टर्की का एक दूसरा प्रख्यात राजनीतिज्ञ इस्मत-पाशा है। इस दल की शाखाएं और क्लब टर्की के चारों प्रांतों में फैले हुए हैं और यह दल टर्की की कायापलट करने में वैसा ही संलग्न है जैसा कि इटली का फेसिस्ट और रूस का समष्टिवादी दल। यह दल कट्टर राष्ट्रीयता और आधुनिक विचारों को मानने वाला है। टर्की का मुलतान हमेशा से दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था। मगर इस दल की मदद से मुस्तफा कमाल पाशा ने धर्मांध मुसलमानों के चीखने-चिल्लाने की कुछ परवा न कर के मार्च सन् १९२४ ई० में ही टर्की के कंधों से खिलाफत का जुआ उतार कर फेंक दिया था, उसी प्रकार उस ने शिक्षा-विभाग को मुल्लों के पंजों से निकाल कर शिक्षा-मंत्री और धार्मिक अदालतों को न्याय मंत्री के अधिकार में रख दिया था और 'पाक कानून' की व्याख्या करने वाले शेखुल इस्लाम को मंत्रिमंडल से ही निकाल दिया था। इस दल के हाथ में टर्की की सरकार आने के समय से बराबर यह दल टर्की को यूरोप के दूसरे आधुनिक राष्ट्रों के बराबर प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है। पर्दा-नशीन औरतों के माँह पर से कानूनों के द्वारा बुर्का उतार कर फेंक दिया गया है, जिस के

कारण ज़िरों को भी मैदान में आ कर टर्की के निर्माण में हिस्सा लेने का मौका मिला है। तुर्की भाषा की लिपि तक बदल दी गई है। आधुनिक टर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल अपने लोकदल की फौलादी कैची से काट-छाँट कर मुर्काए हुए टर्की को हर प्रकार से चमन बनाने का बड़ा प्रयत्न कर रहा है। मगर इस होशियार गाराबान के बाद भी लोकदल और टर्की की सरकार का न मालूम यही रूप रहेगा या नहीं।

## अल्बानिया की सरकार



सन् १९१२ ई० तक अल्बानिया टर्की के अधीन था। २८ नवम्बर, सन् १९१२ ई० को भयकर लड़ाई के बाद अल्बानिया ने टर्की से अपना पल्ला छुड़ा लिया था। मगर उस के स्वाधीन होते ही लालची बाल्कन रियासतें, अल्बानिया को आपस में बाँटने का प्रयत्न करने लगीं थीं जिस के परिणाम-स्वरूप बाल्कन युद्ध हुआ था और बाद में आस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में पड़ने से अतः अल्बानिया की स्वाधीनता सब ने क़मूल कर ली थी। अंतर्राष्ट्रीय सरत्तण में अल्बानिया को एक स्वतन्त्र रियासत गुलाई सन् १९१३ में घोषित किया गया था और बाद में वीड के शाहजादा विलियम को उस का मौरूसी राजा बना दिया गया था। मगर टर्की, बाल्कन रियासतों, और दूसरे राष्ट्रों के पड़यतों के कारण विलियम का राज न चल सका और एक साल के भीतर ही वह राज त्याग कर के चला गया। उस के चले जाने के बाद अल्बानिया बहुत से स्वतन्त्र भागों में बँट गया। पिछली यूरोप की लड़ाई में यूनानी, इतालियन, मोन्टेनेग्रिन, सर्ब, आस्ट्रिया, हंगेरियन, बल्गेरियन और फ्रेंच सेनाओं का अल्बानिया पर अधिकार रहा। अस्थायी संधि होने के समय अल्बानिया के अधिकतर भाग पर इटली का और बाक़ी भाग पर फ्रांस और यूगोस्लाविया का क़ब्ज़ा था। फिर भी एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी गई थी जो इटली के सहकार से काम करना चाहती थी। ईसाइयों के दो पक्षों के दो आदमी ले कर चार सदस्यों की एक 'राज्य प्रतिनिधि समिति' भी नियुक्त कर दी गई थी।

संधि-सम्मेलन में राष्ट्रों का अल्बानिया को बाँट लेने का इरादा देख कर अल्बानिया में राष्ट्रीयता की लहर उठ खड़ी हुई और अल्बानिया के लोगों ने 'राज्य-प्रतिनिधि समिति' के नीचे एक 'राष्ट्रीय सरकार' कायम कर ली। उन्होंने क्रांति कर के इटालियनों और फ्रांसीसियों को भी सन् १९२० ई० में अल्बानिया से हट जाने के लिए मजबूर कर दिया। मगर यूगोस्लाव सन् १९२१ ई० तक नहीं हटे और उन्होंने उत्तरी अल्बानिया पर भी कब्जा जमाने की कोशिश की, जिस पर 'लीग ऑफ नेशन्स' ने हस्तक्षेप कर के राष्ट्रों से कुछ परिवर्तनों के साथ युद्ध के पूर्व की अल्बानिया की सीमाओं को मंजूर करा लिया। मगर अल्बानिया की सीमाओं का आखिरी फैसला सन् १९२६ ई० में ही एक सम्झौते से हो पाया था। आखिरकार पहली सितंबर, सन् १९२८ ई० को अहमद बे जोगू प्रथम को अल्बानिया का मौलसी राजा घोषित कर के अल्बानिया को यूरोप के दूसरे स्वार्थीन राष्ट्रों की तरह एक स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अल्बानिया राष्ट्र की राज-व्यवस्था के अनुसार अल्बानिया में मौलसी प्रजासत्तात्मक और व्यवस्थापकी राजाशाही है। राज-व्यवस्था के संशोधन का प्रस्ताव राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनों की ओर से आ सकता है। मगर राज-व्यवस्था के संशोधन का काम हर ७५०० की आयु की आयु के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुना हुआ एक व्यवस्थापक-सम्मेलन ही कर सकता है।

**सरकार**—कानून बनाने की सत्ता राजा और एक सभा की एक व्यवस्थापक-सभा में है, जिस के सदस्यों की १५००० की आयु की आयु के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से प्रजा चुनती है। राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा और सात मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल में होती है। न्याय-शासन व्यवस्थापक-सभा और कार्यकारिणी से अलग राजा के नाम पर होता है। राजा राष्ट्र की सेनाओं का सेनाधिपति माना गया है। सेना-विभाग के अतिरिक्त राजा के सारे कर्मचारियों पर प्रधान मंत्री और एक मंत्री के दस्तखत होते हैं। टर्की की तरह बारह सदस्यों की एक 'कौंसिल ऑफ स्टेट' भी होती है। तीन अल्बानियन दो अंग्रेज और एक इटालियन, छः सदस्यों की, सिर्फ राजा को जवाबदार, एक 'राजमहल की मंत्रि-मंडली' भी होती है।

## बल्गेरिया की सरकार



**राज-व्यवस्था**—सन् १९०८ ई० तक बल्गेरिया भी टर्की के अधीन एक रियासत थी, जिस को एक हद तक अपने शासन की स्वतंत्रता थी। सन् १९०८ ई० के बाद से बल्गेरिया भी एक स्वाधीन राष्ट्र हो गया। उस की राज-व्यवस्था पुरानी सन् १८७९ ई० की राज-व्यवस्था पर बनी है, जिस में सन् १८९३ ई० और सन् १९०३ ई० में बहुत-से फेरफार किए गए थे। सन् १८७९ ई० की राज-व्यवस्था काफी उदार थी, मगर प्रजा के प्रतिनिधियों की सेवान्ये नाम की राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को वास्तव में बहुत कम सत्ता रहती थी। मालकन युद्धों की प्लेग के कारण भी बल्गेरिया को शांतिमय राजनैतिक जीवन बिताने का मुश्किल से ही समय रहता था। सन् १८८७ ई० तक बल्गेरिया पर रूस का अधिकार रहने से बल्गेरिया की व्यवस्थापक सभा के नेताओं को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति बनाना असंभव था। फिर राज-व्यवस्था में राजा की सत्ता बढ़ा देने के बाद राजा की सारी सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा में विरोधी दलों को कुचलने में किया जाने लगा था।

**व्यवस्थापक-सभा**—अल्बानिया की तरह बल्गेरिया में भी सिर्फ एक सभा की एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा है, जिस को सेवान्ये कहते हैं। इस राष्ट्रीय सभा में करीब २७४ सदस्य होते हैं; जिन को बल्गेरिया के सारे मर्द नागरिक चुनते हैं। सदस्यों को उम्र कम से कम तीस वर्ष की होती है, और उन को चार वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रीय सभा को कानून बनाने और आय-व्यय के तथा कार्यकारिणी के हुकमों पर नियंत्रण



पण के सारे अधिकार होते हैं। सारे मसविदे और प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के सामने पेश किए जाते हैं। सभा को शासन की जाँच पड़ताल करने के लिए उपसमितियाँ नियुक्त करने और सरकार से प्रश्न पूछने का हक होता है। सभा की साधारण बैठक के अतिरिक्त, जरूरत पड़ने पर खास बैठकें भी होती हैं।

राज-व्यवस्था में फेरफार करने और राजछत्र के अधिकार-सम्बन्धी नियम बनाने के लिए एक खास राष्ट्रीय सभा बैठती है, जिस को राष्ट्रीय सभा की तरह ही चुना जाता है। यद्यपि, इतना फर्क होता है कि राष्ट्रीय सभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से एक के बजाय दो प्रतिनिधि आते हैं।

**कार्यकारिणी**—बलगेरिया राष्ट्र की कार्यकारिणी की सारी सत्ता का केंद्र राजछत्र माना गया है। सन् १९११ ई० तक राजा, बलगेरिया के प्रतिनिधि की हैसियत से दूसरे राष्ट्रों से संधियाँ कर सकता था, मगर उन संधियों की आखिरी मजबूरी के लिए राष्ट्रीय-सभा की मजबूरी की जरूरत होती थी। सन् १९२१ ई० में सभा की मजबूरी की फ़ैद सभा की राय से ही हटा ली गई। राजा को मंत्रियों के द्वारा कानूनी मसविदे और प्रश्न राष्ट्रीय-सभा में पेश करने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय-सभा में मजबूर किए गए सारे मसविदों को कानून बनाने के लिए राजा की मजबूरी की जरूरत होती है। व्यवस्थापक-सभा को भंग करने का हक भी राजा को होता है। राज-व्यवस्था के अनुसार राजा और व्यवस्थापक-सभा या मन्त्रि मंडल और व्यवस्थापक-सभा में भयकर झगड़ा होने पर ही राजा व्यवस्थापक-सभा को भंग कर सकता है, मगर कौन सा झगड़ा भयकर है और कौन सा नहीं। इस का फैसला राजा और मन्त्रि मंडल करता है। अतः, व्यवस्थापक-सभा की जिंदगी बहुत हद तक कार्यकारिणी की कृपा पर निर्भर रहती है। सभा भंग होने के दो मास के भीतर ही नया चुनाव हो जाता है। देश के भीतर या बाहर से खतरा उत्पन्न हो जाने पर और व्यवस्थापक सभा की बैठक बुलाना असमभव हो जाने पर राजा को सारे प्रश्नों का फैसला करने, कानून बनाने और सारा शासन का काम-काज चलाने का, राज-व्यवस्था के अनुसार हक माना गया है, मगर ऐसी हालत में राजा प्रजा पर नए कर नहीं लगा सकता है तथा मन्त्रि मंडल की राय राजा के कामों से मिलनी चाहिए और मन्त्रि मंडल को राजा के सारे कामों की जवाबदारी अपने सिर पर ले लेनी चाहिए। फिर भी जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी मन्त्रि मंडल को अपने सारे काम व्यवस्थापक-सभा के सामने मजबूरी के लिए रख देने चाहिए।

मन्त्रि मंडल के सदस्यों और प्रधान मंत्री को राजा नियुक्त करता है। यह मंत्री सम्मिलित रूप से और अलग अलग राष्ट्र सभा की जवाबदार होते हैं। मंत्रियों के राजा के हर क्रमशः पर दस्तखत रहते हैं और इस लिए वह कानूनी और राजनैतिक तौर पर राजा और व्यवस्थापक सभा दोनों को जवाबदार होते हैं।

**स्थानिक शासन**—बलगेरिया में स्थानिक शासन विल्कुल फ्रांस के ढंग पर होता है। केंद्रीय सरकार के नियुक्त किए हुए प्रीफ़ेक्ट के अधीन डिपार्टमेंट का शासन एक

स्थानिक चुनी हुई समिति की सलाह से होता है। उसी प्रकार जिलों का नायब प्रीफेक्ट शासन चलाते हैं। उन से छोटा शासन चैन कम्यून होती है। जिस में लगभग विलकुल पचायती शासन चलता है और जो राष्ट्र के राजनैतिक जीवन की इकाई और बुनियाद होती है।

**राजनैतिक दल**—बल्गेरिया के लोग हमेशा से वेचैन तथियत के हैं, मगर विछली लड़ाई में और उस से पहले की कई लड़ाइयों में भी बल्गेरिया का बुरा हाल हो जाने से यहां के लोगों में और भी अधिक अराति और असंतोष फैला था, जिस के फलस्वरूप इस देश में समाजवादी, समष्टिवादी और किसानवादी गरम विचारों की जैसी हवा बही, वैसी यूरोप के दक्षिण-पूर्व के और किसी देश में नहीं बही।

लड़ाई खत्म होने के बाद एक बहादुर और होशियार किसान ऐलेक्जेंडर स्टावूलिस्की की अध्यक्षता में किसान दल ने बल्गेरिया में बहुत जोर पकड़ा था। दो बार प्रयत्न करने पर भी जब कई दल की सरकार न चल सकी, तो किसान-दल ने व्यवस्था पर-सभा भंग करा के नया चुनाव कराया, जिस में उन्हें छोटी सी सख्या व्यवस्थापक सभा में मिल गई थी। मगर इस दल के हाथ में सत्ता आते ही राजनैतिक दलों की भयंकर कलह शुरू हो गई और स्टावूलिस्की और उस का दल इस रास्ते में और भी कट्टर बन गया। उन्होंने समाज-सुधारों के एक गरम कार्यक्रम पर अमल करना और गाँवों को शहरों के खिलाफ उभाड़ना शुरू कर दिया, जिस से कुछ ही समय में इस दल ने दूसरे सारे राजनैतिक दला, अखबारों और धंधा पेशा लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। स्टावूलिस्की का समाज-सुधार का कार्यक्रम तो अच्छा था, मगर उस का शासन का ढंग अच्छा नहीं था। उस ने सारे पुराने दलों के भूतपूर्व मंत्रियों को पकड़ कर उन पर लड़ाई छेड़ने के इलजाम के लिए एक खास अदालत के सामने अभियोग भी चलाया था। इस दल का फोर्सिस्टा की तरह अनना एक अलग 'नारजी दल' था और कहा जाता है कि यह दल बल्गेरिया के राजा जार बोरिस को गद्दी से उतार पेंकने की तैयारी कर रहा था। स्टावूलिस्की की 'बालीस वर्ष तक गाँवों का राज कायम रखने' के इरादे की शेखी और उस के दल अडबड़ कामों के विरुद्ध बल्गेरिया के सभी दलों ने खास कर शिक्षितवर्ग ने आवाज उठाई। मगर स्टावूलिस्की ने चुनाव के नए कानून बना कर विरोधियों का पैघ आंदोलन तक करना असंभव कर दिया, जिस के फलस्वरूप गुप्त पडयनकारी आंदोलन बढ़ने लगा। आखिरकार अध्यापकों और सेना के अधिकारियों के एक गुट ने लगभग सारे शिक्षितवर्ग और सेना की सहायता से स्टावूलिस्की की सरकार को ६ जून, सन् १९२३ ई० को उखाड़ कर पेंक दिया और प्रोफेसर ऐलेक्जेंडर ज्ञानकौफ की अध्यक्षता में एक प्रकार की अर्ध-निरंकुश सरकार की स्थापना कर दी। जहां-तहां किसानों ने अपने दल की सत्ता कायम रखने के लिए हथियार उठाए, मगर उन को शीघ्र ही दबा दिया गया। स्टावूलिस्की को बुरी तरह कत्ल कर डाला गया।

इस के बाद भी बल्गेरिया में शांति नहीं हुई। बहुत दिनों तक इधर उधर मार-काट होती रही। सितंबर सन् १९२३ ई० को समष्टिवादियों की, जिन को बल्गेरिया

में बहुत काफी सख्या थी, कांति हुई और उस को भी भयकर क्रूरता से कुचल दिया गया। फिर जानकीफ सरकार के पक्षपाती सारे मध्यम वर्ग के पुराने दलों ने मिल कर एक 'प्रजासत्तात्मक मेत्री' नाम की दलों की एक सघ का संगठन किया, जिस को बड़ी मार-काट के बाद दूसरे चुनाव में आखिरकार व्यवस्थापक सभा में बहुसख्या मिल गई।

मगर दूसरे वर्ष भी हताग्रों और कल्लों की भरमार जारी रही। किसानों और समष्टिवादियों की 'सयुक्त सामना' नाम की एक सन्धा ने खास कर सरविया के प्रवासियों की सहायता से बलगेरिया में पड़यन्त्रकारी आंदोलन जारी रक्खा। इस सन्धा का इरादा जानकीफ सरकार को उलट देना था। इसी सन्धा की ओर से नववर्ष के दिन, बलगेरिया की राजधानी सोफिया का मुख्य क्लब, जिस में उसी दिन सरकारी अफसरों, अध्यापकों और मंत्रियों की एक भीड़ आनंदोत्सव मना रही थी और स्वयं राजा भी गया हुआ था, उठा देने का प्रयत्न किया गया था। दूसरी बार एक पहाड़ी रास्ते पर राजा की मोटर पर हमला किया गया था, जिस में राजा तो बच गया था, मगर उस के एक नीकर की जान चली गई थी। मगर इस सन्धा की सब से भयकर करतूतों में ईस्टर के दिन सोफिया के एक गिरजाघर को उड़ा देना था, जिस में एक सैनिक अफसर की मृतक किया में—जिस को कम्यूनिस्टों ने मार डाला था—भाग लेने वाले १५० आदमी खत्म हो गए थे। कहा जाता है कि इस गिरजाघर को कम्यूनिस्टों ने उड़ाया था। कुछ भी हो, इस घटना के बाद से सरकार की ओर से भयकर अत्याचार शुरू हुआ, और किसान और समष्टिवादी दलों के नेताओं की बुरी तरह से जाने ले ली गई। कानून बना कर बलगेरिया में समष्टिवाद तक को गैरकानूनी करार दे दिया गया; परंतु इन पड़यंत्रों, कल्लों और अत्याचारों से थक कर, बाद में जानकीफ मंत्रिमंडल के पक्षपाती दलों ने स्वयं इस मंत्रिमंडल के हाथ से सरकार की बागडोर ले ली और जनवरी सन् १९१६ ई० में ऍंड्रा लियापचेफ को नए मंत्रिमंडल का भार सौंपा। ऍंड्रा लियापचेफ ने अहिंसात्मक और पड़यंत्रों में भाग न लेने वाले लोगों का एक मंत्रिमंडल सैयार किया। उस की नीति धीरे-धीरे शान्तिमय और नरम उपायों से परिस्थिति को ठीक करने की थी। मगर उस के समर्थकों में मेल न होने और उस का व्यवस्थापक-सभा में बहुत निरोध होने से सन् १९३१ ई० के चुनाव में इस मंत्रिमंडल की भी हार हो गई थी, और आखिरकार उदार-दल, प्रजासत्तात्मक दल, किसान दल और गरम दल के सदस्यों में से प्रजासत्तात्मक दल के नेता एम० गेलीनौफ ने चार दलों का नया मंत्रिमंडल रचा था।

बलगेरिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'राष्ट्रीय उदार दल' और 'उदार दल' दोनों को मिला कर 'उदार दल' है। यह दल पुराने दलों के मेल से बना था। दूसरा 'प्रजासत्तात्मक मेत्री' नाम का दल है, जो स्टाबूलिस्की को निकालने के बाद बहुत से दलों को मिला कर बना था और जिस के मंत्रिमंडल की सन् १९३१ ई० में हार हो गई थी। इस दल का कार्य कम सरकार की सत्ता बढ़ाना, सरकारी खर्च कम करना, शिक्षा में सुधार करना और पड़ोस के राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहना है। आजकल यह दल सरकार के विरोधी दलों में से मुख्य दल है।

तीसरा 'प्रजासत्तात्मक दल' है जिस के हाथ में सन् १९०६-११ और १९१८ से १९१९ तक सरकार थी। यह दल न तो बिल्कुल गरम ही है और न बिल्कुल नरम ही। इसी दल के नेता मेलीनोफ ने 'प्रजासत्तात्मक मेत्रीदल' की हार हो जाने पर सन् १९३१ में प्रधान मंत्री बन कर नया मंत्रि-मंडल बनाया था। यह दल सब दलों के मिलने और देश में शांति प्रथम करने का पक्षपाती है। चौथा एक 'गरम दल' है जिस की सन् १९०६ ई० में प्रजासत्तात्मक दल से निकले हुए लोगों को ले कर जानकीफ ने स्थापना की थी। इस दल का कार्य-क्रम सहकारी संस्थाओं की रक्षा करना, करों में सुधार करना और बालकन राष्ट्रों की एक संघ बनाना है। इस दल का भी एक सदस्य मेलीनोफ मंत्रि-मंडल में था। पाँचवाँ एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' है इस की स्थापना सन् १८९३ ई० में हुई थी और दूसरे इसी नाम के यूरोपीय दलों की तरह यह दल शांतिमय उपायों से समाजशाही स्थापित करने में विश्वास रखता है। इसी दल के गरम लोगों ने अलग हो कर १९०३ में एक अलग दल बना लिया था, जो सन् १९१८ ई० में 'कम्युनिस्ट दल' कहलाने लगा था।

छठा दल 'किसान दल' है जिस की स्थापना सन् १८९९ ई० में हुई थी। उस की लड़ाई के बाद एकदम ताकत बढ़ जाने और उस के नेता स्ट्राबुलिस्की का हाल पाठकों को बताया ही जा चुका है। यह दल खेती की रक्षा करने और किसानों की ताकत बढ़ाने में विश्वास रखता है। स्ट्राबुलिस्की की हार के बाद इस दल में दो नेताओं की अध्यक्षता में हिंसा की विरोधी दो शाखाएँ भी बन गई हैं। इन दलों के अलावा सातवाँ एक 'मजदूर दल' भी है जो सन् १९२४ में 'कम्युनिस्ट दल' गैरकानूनी ठहरा दिए जाने पर इस नए नाम से उठ खड़ा हुआ है। इस दल की नीति और प्रोग्राम बिल्कुल पुराने 'कम्युनिस्ट दल' का-सा ही है।

## यूनान की सरकार

**राज-व्यवस्था**—पंद्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध से यूनान टर्की का एक प्रांत बन गया था, मगर उन्नीसवीं सदी में क्रांति कर के यूनान ने टर्की से अपनी स्वाधीनता छीन ली थी। क्रांति के ज़माने में फ्रांस की तरह कई राज-व्यवस्थाएँ यूनान के लिए बनाई और बिगाड़ी गई थीं, और किसी पर भी अमल नहीं हो पाया था, मगर यूरोपीय राष्ट्रों की लड़न में होने वाली सन् १८३० ई० की वार्फेंस में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के सह-क्षेत्र में यूनान एक स्वाधीन राष्ट्र क़रार दे दिया गया था। बवेरिया के राजकुमार ओटो को यूनान ने सन् १८३२ ई० की संधि में अपना राजा स्वीकार कर लिया था, और २५ जनवरी, सन् १८३३ ई० में वह यूनान के तख्त पर बैठ गया था। उस ने ग्यारह वर्ष तक बिना किसी निश्चित राज-व्यवस्था के, सिर्फ एक सत्ताहकार समिति की राय से राज-काज चलाया था, मगर सन् १८४३ ई० में यूनान में फिर क्रांति हो जाने पर राजधानी एथेन्स में एक व्यवस्थापक सम्मेलन की बैठक बुलाई गई थी, जिस ने बेल्जियम और फ्रांस की सन् १८३० ई० की राज-व्यवस्था के नमूने पर यूनान के लिए एक राज-व्यवस्थापक व्यवस्था गढ़ कर फरवरी सन् १८४४ ई० में मंज़ूर की थी।

सन् १८६२ ई० में यूनान से राजा ओटो को निकाल दिया गया और उस के स्थान पर डेनमार्क के शाहजादा जार्ज को यूनान की गद्दी पर प्रथम राजा जार्ज के नाम से बिठा दिया गया था। दूसरे साल जिस राष्ट्रीय सम्मेलन ने जार्ज को गद्दी पर बिठाया था, उसी ने पुरानी राज-व्यवस्था की पुनर्घटना कर के अक्टूबर सन् १८६४ ई० में यूनान के लिए एक नई प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था मंज़ूर की। इस राज-व्यवस्था के

अनुसार यूनान में एक व्यवस्थापकी वेध और मौलवी राजाशाही मानी गई थी, यूनान के राजा को फ्रीव फरीव इंग्लैंड के राजा का सा स्थान दिया गया था। राज व्यवस्था के एक अध्याय में प्रजा के अधिकारों का एलान था। राष्ट्र की प्रभुता राष्ट्र की प्रजा में मानी गई थी। कानून बनाने की सत्ता, राजा और व्यवस्थापक सभा में मानी गई थी। कार्यकारिणी की सत्ता राजा की थी, मगर वह उस का प्रयोग सिर्फ, व्यवस्थापक सभा को जवाबदार, मंत्रियों के द्वारा ही कर सकता था। न्याय शासन राजा के नाम पर स्वतन्त्र न्यायाधीश करते थे। व्यवस्थापक-सभा की सिर्फ एक सभा थी, जिस को सोलह सौ की आवादी के लिए एक प्रतिनिधि के दिसाव से चार वर्ष के लिए यूनान देश के सारे नागरिक चुनते थे। सन् १८११ ई० में इस राज व्यवस्था में संशोधन कर के व्यवस्था एक सभा की एक दूसरी सभा की तरह 'कॉन्सिल ऑव स्टेट' भी स्थापित की गई थी, जिस के तमाम कानूनी प्रस्तावों को जांचने और गैरकानूनी सरकारी फैसलों को रद्द कर देने का अधिकार दिया गया था।

मगर यूनान भी घलगारिया की तरह क्रांतियों, घरेलू कलह और झगड़ों और विदेशों के आक्रमणों और कूटनीति तथा मार-काट का शिकार रहा है। इन लगातार प्रहारों से, १८६४ की स्थापित यूनान की राजाशाही बिल्कुल जर्जर बन गई थी। अस्त, इस राष्ट्र की कमजोर सरकार पिछली लड़ाई के तूफान से बच कर निरुल आती तो बड़े अचभे की बात होती। सन् १८२३ ई० तक किसी प्रकार पुरानी राज-व्यवस्था चली। सन् १८२३ ई० के चुनाव में व्यवस्थापक-सभा के ४०१ सदस्यों में में ३७० सदस्य प्रजातन्त्रवादी वेनेज़ेलोस के दल के सदस्य चुन कर आए। उन्होंने मार्च सन् १८२४ में राजाशाही को खत्म कर के यूनान के प्रजातन्त्र राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी और अप्रैल में प्रजा ने अपने मतों से व्यवस्थापक-सभा के इस निश्चय का समर्थन किया। फिर इसी व्यवस्थापक सभा ने यूनान प्रजातन्त्र की नई राज-व्यवस्था रची जो २६ सितंबर, सन् १८२६ ई० को मंजूर हो जाने के बाद जारी कर दी गई। सन् १८२६ ई० में चुनी जाने वाली व्यवस्थापक सभा ने उस पर फिर विचार किया और जून सन् १८२७ ई० में यह अंतिम रूप में छाप दी गई। यह राज व्यवस्था अंग्रेजी, फ्रांसीसी और बेल्जियम की राज व्यवस्थाओं के सिद्धांतों पर गढ़ी गई है। मगर इस राज-व्यवस्था के अनुसार प्रजातन्त्र का रूप बदलने के बारे में कोई संशोधन पेश नहीं हो सकता है।

**व्यवस्थापक-सभा**—यूनान राष्ट्र की प्रजा की प्रभुता इस राष्ट्र की व्यवस्था-पक-सभा में मानी गई है। कानून बनाने की सत्ता व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाएँ—एक 'प्रतिनिधि-सभा' और दूसरी 'सिनेट'—में रखी गई है। 'प्रतिनिधि सभा' में कम से कम दो सौ और अधिक से अधिक ढाई—सौ सदस्य होते हैं। सभा के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम २५ वर्ष की होनी चाहिए और उन का चुनाव चार साल के लिए यूनान के सारे बालिग मर्द नागरिक करते हैं। 'सिनेट' में १२० सदस्य होते हैं, जिन में से ६२ सदस्यों को प्रजा चुनती है। हर ६८६४० जन संख्या की आवादी के एक निर्वाचन-क्षेत्र से सिनेट का एक सदस्य चुना जाता है। सिनेट के दस सदस्यों को प्रति-

निधि-सभा और सिनेट मिल कर चुनती है, और अठारह सदस्यों को व्यापारी, तिजारती, उद्योगी और वैज्ञानिक समस्याओं के मंडल चुनते हैं।

साधारण कानूनी मसविदे व्यवस्थापक-सभा में सरकार और सदस्यों की ओर से पेश हो सकते हैं। मगर आर्थिक मसविदे सिर्फ सरकारी सदस्य ही पेश कर सकते हैं। 'प्रतिनिधि-सभा' से आने वाले मसविदे पर 'सिनेट' को अपना मत चालीस दिन के अंदर दे देना पड़ता है। 'सिनेट' को 'प्रतिनिधि-सभा' के मसविदों को उदलने और नामजूर करने का अधिकार होता है। यदि 'प्रतिनिधि-सभा' अपने मसविदे को जैसा का तैसा ही पास करने पर अड़ जाती है तो दो महीने तक चुप रह कर बहुसंख्या से फिर 'प्रतिनिधि-सभा' में मसविदा पास हो जाने पर, कानून बन जाता है, और सिनेट के विरोध का उस पर कुछ असर नहीं होता है, परंतु 'सिनेट' की माँग पर दो महीने का समय बीतने के पहले दोनों सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में मसविदे पर निचार हो कर, सारे सदस्यों की बहुसंख्या से भी पेशला किया जा सकता है। राष्ट्रीय बजट 'प्रतिनिधि सभा' में पेश होता है, और 'सिनेट' को उस पर अपनी राय एक मास के अंदर आदि-र कर देनी पड़ती है, उस के बाद 'प्रतिनिधि-सभा' में बजट की आखिरी सूरत सभा की साधारण बहुसंख्या से तय की जाती है। यूनान की राज व्यवस्था की ४६ वीं धारा में कानून बनाने के ज्ञान्ते की सारी तफ सीला का जितना जिक्र किया गया है, उतना किसी दूसरी राज-व्यवस्था में नहा है।

यूनान का मंत्रि मंडल व्यवस्थापक सभा को जवाबदार होता है। फ्रांस की तरह यूनान में भी कानूनी और शासन के प्रश्नों का विचार करने के लिए व्यवस्थापक सभा की समितियाँ रहती हैं। व्यवस्थापक सभा के सामने आने से पहले सारे कानूनी मसविदों पर यह समितियाँ निचार कर लेती हैं। व्यवस्थापक सभा की एक 'परामर्श विषय समिति' भी होती है। शासन को जाँच पड़ताल के लिए खास तौर पर सभा जाँच-समिति भी नियुक्त कर सकती है।

**कार्यकारिणी**—कार्यकारिणी की सत्ता फ्रांस की तरह प्रजातन्त्र के प्रमुख में मानी गई है और यूनान के प्रमुख में भी फ्रांस के प्रमुख के मुकामले के अधिकार होते हैं। व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाएँ एक सम्मिलित सभा में सारे सदस्यों की कम से कम दूई संख्या की हाजिरी और हाजिर सदस्यों की आधी से अधिक संख्या के मतों से यूनान प्रजातन्त्र के प्रमुख का पाँच वर्ष के लिए चुनाव करती हैं। पहली बार मत पड़ने पर कोई न चुना जाने पर सब से अधिक मत पाने वाले उम्मीदवारों के लिए दूसरी और तीसरी बार तक मत पड़ते हैं। एक बाल पूरा हो जाने पर फौरन ही दूसरे काल के लिए कोई प्रमुख नहीं हो सकता है। प्रमुख का कोई हुकम बिना किसी जवाबदार मंत्री की सही के नकारावदा नहीं होता है। व्यवस्थापक-सभा के कानूनों को उलटने या नामजूर करने का हक प्रमुख को नहीं होता है। व्यवस्थापक सभा की बैठकें न होने पर प्रमुख—अगर सभा ने उस को यह अधिकार सौंपा है तो—फरमानी कानून भी जारी कर सकता है, जिस को फौरन ही दोनों सभाओं के सदस्यों की 'मिश्रित समितियाँ' मजूर कर लेती हैं।

मंत्रि मंडल के सदस्य प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में प्रभुत्व के तारे और एलानों के लिए व्यवस्थापक सभा को जवाबदार होते हैं। यूनान में मंत्रि मंडल की कार्यवाही भी इंग्लैंड के मंत्रि मंडल की तरह चलती है। प्रतिनिधि सभा के विश्वास पर मंत्रि मंडल की ज़िम्मेदारी निर्भर रहती है। सरकार की ग्राम नीति के लिए मंत्री सम्मिलित रूप से और अपने विभागों के लिए अलग-अलग प्रतिनिधि सभा को जवाबदार होते हैं।

**राजनैतिक दल और सरकार**—ऊपर की राज व्यवस्था यूनान में कायम तो है, मगर काम बिल्कुल भिन्न व्यवस्था पर चलता है; क्योंकि ऊपर की राज व्यवस्था बनने के समय से उसमें यूनान में अशांति और मारकाट मची रहती है। राजनैतिक नेताओं की व्यक्तिगत एक दूसरे से स्पर्धा और सैनिकों और खेवटों के झगड़ों के कारण, एक के बाद दूसरी सरकारें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। सन् १९२५ ई० में पेंगेलोस नामक एक सेनापति ने तलवार के ज़ोर से सरकार पर अपना अधिकार जमा कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को भग कर दिया था। उसने यूनान के लिए शुद्ध शासन और नई व्यवस्थापक-सभा के चुनाव का वादा किया था, मगर उस के एवज में मार्शल ला और अखबारों पर सरकारी देख-रेख कायम कर दी थी। अखिर, फिर यूनान में क्रांति हुई। पेंगेलोस भाग गया, और पुरानी राज व्यवस्था फिर कायम हुई।

यूनान के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'लोक-दल' है, जो व्यवस्थापकी सरकार की पुनर्स्थापना, कृषि और व्यापार की उन्नति, उद्योगों को सरकारी सहायता, मालिकों और मजदूरों में संधीय सहकार और मजदूरों के बुद्धिमानों के बीच का पक्षपाती है। पिछले चुनाव में इस के १६ सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुने गए थे। दूसरा कृषि दलों का पक्षपाती एक 'कृषि दल' है। अनुदार प्रजातन्त्रवादियों और प्रगतिशील उदार लोगों का एक 'उदार सभ' नामक दल है। अनुदार प्रजातन्त्रियों की संख्या बहुत कम है। प्रगतिशील उदारों का नेता पेनीनेलोप है और उनका कार्य-क्रम शासन का अधिकार विभाजन<sup>१</sup> कानून बनाने के लिए व्यवस्थापक सभा के बड़े बड़े कमीशनरों की स्थापना, आर्थिक पुनर्घटना, कृषि-उन्नति, उद्योग को काफी सरकारी सहायता और सरकारी ऋण में कमी करना है।

दूसरा एक 'प्रजातन्त्र सभ' नाम का दल है, जो पहले 'उदार दल' का गरम अंग था और जिस के सदस्यों को सन् १९२२ ई० में प्रजातन्त्र के पक्षपाती होने के कारण जेलों की हवा खानी पड़ी थी। सन् १९२३ ई० में पहली बार इस दल के नाग में बाकायदा प्रजातन्त्र शब्द जुड़ा था, तब से यह दल प्रजातन्त्र का मुख्य सहारा रहा है। इस दल का कार्य-क्रम यूनान की ग्राम पैदावार बढ़ाना और मजदूर पेशावर्ग को उठाना है। इस के अतिरिक्त एक 'समष्टिवादी दल' और दूसरा एक 'आज्ञादराय दल' भी है। 'आज्ञादराय दल' पुराने 'राजापक्षी दल' का अंग है और पूँजी और व्यक्तिगत मिलकियत की रक्षा, कृषि और व्यापार की उन्नति सिंगट्ज़रलैंड की सेना पद्धति और लीग ऑफ नेशन्स में मानता है।



## डेन्मार्क की सरकार



**राज-व्यवस्था**—डेन्मार्क को ५ जून, सन् १८४९ ई० में 'ग्रैंडलोव' नाम की राज व्यवस्था प्राप्त हुई थी। इस राज-व्यवस्था के अनुसार डेन्मार्क में एक मौलवी राजाशाही और 'रिखडाग' नाम की व्यवस्थापक-सभा की स्थापना की गई थी। 'रिखडाग' की दो सभाएं थी एक 'लैंड्सटिंग' और दूसरी 'फोर्टिंग'। लैंड्सटिंग में ४० वर्ष की उम्र से ऊपर के मालदारवर्ग के १८ सदस्य होते थे, जिन को राजा नियुक्त करता था। फोर्टिंग के सदस्यों को ३० वर्ष के ऊपर के डेन्मार्क के सारे मर्द नागरिक चुनते थे। कार्यकारिणी प्रजा के प्रतिनिधियों को जवाबदार नहीं होती थी। अस्तु, 'फोर्टिंग' की राजा और 'लैंड्सटिंग' के मुकाबले में कुछ नहीं चलती थी। 'लैंड्सटिंग' मालदारों का शत्रु होने से हमेशा 'फोर्टिंग' का विरोध करती थी। सन् १८६४ ई० तक दोनों सभाओं में हमेशा झगड़ा होता रहता था। आम तौर पर प्रजा के प्रतिनिधियों की मर्जी के खिलाफ सरकार का काम चलाया जाता था और कर लगाए जाते थे। बीस वर्ष तक 'राजा' और 'लैंड्सटिंग' के समर्थन से एक मंत्रि-मंडल ने 'फोर्टिंग' के विरोध में सरकार चलाई थी, और इस बीस वर्ष में एक बार भी फोर्टिंग ने कभी सरकार के लिए एक कौड़ी मंजूर नहीं की थी। सन् १८६४ ई० में पहली बार दोनों सभाओं में समझौता हुआ था; मगर फिर भी दोनों सभाओं का झगड़ा कायम ही रहा, जिस में फोर्टिंग और उस के गरम दल की ताकत प्रजा की नहायता से बढ़ती गई और लैंड्सटिंग की ताकत कम होनी गई। पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने के बाद डेन्मार्क में राजनैतिक स्थिति काफी भयंकर हो गई थी, जिस के कारण राज व्यवस्था में सन् १९१५ ई० में फेर फार करना पड़ा था। लड़ाई के बाद वारसेल्ज की सधि के

अनुसार डेन्मार्क का क्षेत्र बढ़ जाने पर फिर राज व्यवस्था में संशोधन हुआ था और इस के बाद के रूप में अभी तक वह डेन्मार्क में जारी है। इस राज व्यवस्था के अनुसार डेन्मार्क में सीमित राजशाही और व्यवस्थापकी सरकार है। राज व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं में मंजूर हो जाने के बाद रिग्सडाग को भंग कर दिया जाता है और नया चुनाव किया जाता है। नई रिग्सडाग के फिर उन प्रस्तावों के मंजूर करने पर संशोधनों पर प्रजा के मतदारों का हवाला लिया जाता है। सारे मतदारों की कम से कम ४५ फी सदी संख्या और मत देने वालों की गहुर संख्या के संशोधनों के पक्ष में होने पर संशोधन मंजूर होते हैं।

**कार्यकारिणी**—राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा में मानी गई है। राजा को, राज व्यवस्था की शर्तों के अंदर, सारे राष्ट्रीय मामलों में सब कुछ अधिकार होता है। मगर इस अधिकार का प्रयोग वह करने मंत्रियों के द्वारा करता है। राज व्यवस्था के अनुसार सरकार का काम चलाने के लिए मंत्री 'जवाबदार' होते हैं। मगर व्यवस्थापक सभा को वे जवाबदार माने गए हैं या किस को, इस का यहाँ कुछ साफ जिक्र नहीं है। यह जरूर सच है कि कानूनों और शासन से संबंध रखने वाले पैसलों पर, उन के नाकाबदा होने के लिए, राजा और किसी न किसी मंत्री दोनों के हस्ताक्षरों की जरूरत होती है। फिर भी यह निहत्तुल साफ नहीं है कि उस मंत्री के हस्ताक्षर कर देने से उस की किस को जवाबदारी हो जाती है। शायद मंत्रियों की जवाबदारी का अभी तक डेन्मार्क में सिर्फ यही ग्रंथ होता है कि गैरकानूनी कामों के लिए उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। मगर धीरे धीरे डेन्मार्क में भी दूसरे देशों की तरह एक दिन मंत्रियों की व्यवस्थापक सभा, खास कर प्रतिनिधि सभा, को जवाबदारी का रिनाज अवश्य कायम हो जायगा।

मंत्रियों को नियुक्त करना और डिहालना भी राजा का काम होता है। मंत्रियों की सभा को डेन्मार्क में 'फॉसिल ऑफ् स्टेट' कहते हैं और उस के अध्यक्ष के स्थान पर राजा स्वयं बैठता है। सुवराज्य भी बालिश होने पर मंत्रियों की सभा में परावर बैठता है। राजा के न आने पर, राजा मंत्रियों की सभा के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में काम राज चलाने का प्रबंध करता है। मगर इस हालत में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बैठने वाली मंत्रियों की सभा सिर्फ 'मंत्रि सभा' कहलाती है। और राजा को इस सभा के पैसलों का विरोध करने और उन को पुन विचार के लिए 'फॉसिल ऑफ् स्टेट' की दूसरी सभा में रखने का हक होता है। रिना रिग्सडाग की मंजूर के राजा को मुद छेड़ने, सधि करने, दूसरे राष्ट्रों से मैत्री जोड़ने और व्यापारी सम्मति करने, राष्ट्रीय जमीन देने, और कोई इस प्रकार का सम्मति करने का जिस से देश के प्रचलित कानूनों पर असर पड़े, हक नहीं होता है।

**व्यवस्थापक सभा**—डेन्मार्क की व्यवस्थापक सभा को 'रिग्सडाग' कहते हैं और 'फोर्टिंग' और 'लड्सटिंग' उस की दो शाखाएँ होती हैं। 'फोर्टिंग' में करीब १४६

सदस्य होते हैं, जिन को २५ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक चार साल के लिए चुनते हैं। हर मतदार को उम्मीदवार होने का हक होता है। लैंड्सटिंग में ७८ सदस्य होते हैं, जिन को निरवृत्त निर्वाचन क्षेत्रों से और टेडे चुनाव से २५ वर्ष के ऊपर के मतदारों द्वारा आठ साल के लिए चुना जाता है। मगर लैंड्सटिंग के सारे सदस्यों का एक साथ चुनाव नहीं होता है। हर चार साल बाद इस सभा के आधे सदस्य चुने जाते हैं। रिंग्सडाग की सभाओं की बैठके हर साल अक्टूबर के पहले मंगलवार से शुरू हो कर छ सात महीने तक होती रहती हैं। रिंग्सडाग के सदस्यों को राजधानी कोपेनहेगन में रहने पर ४२०० क्रोनर सालाना और प्राचीन ग रहने पर ५००० क्रोनर सालाना भत्ता मिलता है।

रिंग्सडाग की दोनों सभाओं की साधारण और खास बैठके बुलाने और स्थगित करने का काम राजा करता है। राजा 'फोर्टिंग' को भग भी कर सकता है। एक बार फोर्टिंग भग हो कर नई चुन आने के बाद भी, किसी मसविदे पर उस का और 'लैंड्सटिंग' का मतभेद कायम रहने पर, 'लैंड्सटिंग' भी भग की जा सकती है। राजा को 'रिंग्सडाग' में कानून पेश करवाने का अधिकार होता है और रिंग्सडाग में मंजूर हुए कानून के लिए राजा की मजूरी की जरूरत होती है। 'रिंग्सडाग' की दूसरी बैठकों तक, राजा के किसी कानून को मंजूर न करने पर, वह कानून रद्द हो जाता है। 'रिंग्सडाग' की बैठकें न होने के समय राजा को फरमानों का कानून जारी करने का भी अधिकार होता है। मगर यह फरमान राज-व्यवस्था के बिगड़ नहीं हो सकता है और उन को रिंग्सडाग की सभा होते ही सभा की मजूरी के लिए रख दिया जाता है। डेन्मार्क में हर सिर्फ कर-सबधी कानूनों के अनुसार ही लगाए जा सकते हैं।

**राजनैतिक दल और सरकार**—डेन्मार्क हमारे देश की तरह वृद्धि प्रधान देश है। मगर कुछ वर्षों से बड़ा उद्योग की भी नड़ी उन्नति हो गई है, जिस से देश की आगामी का लगभग एक तिहाई भाग ग्राम उद्योग और कारीगरी पर ज़िंदगी बसर करता है। ज़मींदार और अमीर किसान डेन्मार्क में 'उदार दल' के पक्षपाती हैं। छोटे किसान आम तौर पर 'गरम दल' के पक्षपाती होते हैं। 'समाजी प्रजासत्ता दल' का बाहुमूल 'उद्योग सर्व' है। मालदार लोग 'अनुदार दल' के समर्थक हैं।

'अनुदार दल' लैंड्सटिंग को फोर्टिंग के बराबर शक्तिशाली बनाने और सेना को मजबूत करने में विश्वास रखता है। सन् १९२० ई० से यह दल 'उदार दल' का 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' और 'गरम दल' के विरोध में बराबर साथ देता है। 'उदार दल' फोर्टिंग को लैंड्सटिंग से अधिक शक्तिशाली रखने, स्वतंत्र व्यापार नीति, सरकार के कम से कम हस्ताक्षर और मजदूरों के बीमा का पक्षपाती है। 'गरम दल' सन् १९०५ में उदार 'दल' से टूट कर बना था। यह दल समाज सुधारों, सेना की कमी और ज़मीन को छोटे-छोटे पट्टों में बाँटने का हामी है। 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' यूरोप के दूसरे इसी नाम के दलों के समाजशाही कार्य कम को मानने वाला है। दूसरे छोटे दलों में एक

‘सत्यवादी राष्ट्र दल’ है, जो ‘एक कर’ के सिद्धांतों का पक्षपाती है। दूसरा जर्मन ग्रन्थ सख्या का जर्मनी के हितों की चिंता रखने वाला एक ‘स्नेसनिग दल’ है। सन् १९२६ ई० के चुनाव के बाद रिंग्सडाग में विभिन्न दलों के इस प्रकार सदस्य थे.—

दल	फोकरिंग	लैंड्सटिंग
अनुदार दल	२४	१२
गरम दल	१६	८
समाजी प्रजासत्तात्मक दल	६१	२७
उदार दल	४४	२८
सत्यवादी राष्ट्र दल	३	०
स्नेसनिग दल	१	०

इस साल का मन्त्रिमंडल समाजी प्रजासत्तात्मक दल और गरम दल के मेल से बना था।

डेन्मार्क में सहकारी संस्थाओं का बड़ा जोर है। सहकारी संगठन से डेन्मार्क की खेती को बड़ा फायदा पहुँचा है। सन् १९०६ ई० के एक साल में इन सहकारी संस्थाओं के द्वारा करीब डेढ़ अरब का व्यापार हुआ था।

## हालैंड की सरकार



**राज-व्यवस्था**—हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास भी बड़ा ज्वलत और रोमांचकारी है, मगर हमारे मतलब के लिए इतना काफी होगा कि सन् १८१४ ई० से हालैंड बेल्जियम के सामे में 'सयुक्त राज्य नेदरलैंडस्' का सदस्य था और सन् १८४० ई० में बेल्जियम के अलग हो जाने पर उस की राज-व्यवस्था अलग हो गई थी। मगर सन् १८४८ ई० तक इस राज व्यवस्था में, मंत्रियों की जवाबदारी तथा ऊपरी सभा के सदस्यों की नियुक्ति के स्थान में चुनाव के प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों का समावेश नहीं हुआ था। सन् १८८७ ई० और सन् १८९६ ई० की योजना के अनुसार सिर्फ हैसिमत वाले वर्गों को मताधिकार था। मगर सन १९१६ के एक सुधार में २३ वर्ष के ऊपर के सब स्त्री और पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया है। हालैंड की राज-व्यवस्था के अनुसार इस देश में राजाशाही और प्रजासत्तात्मक और जवाबदार सरकार है। राजगद्दी के उत्तराधिकारियों के सन्ध में भी राज व्यवस्था में बड़ी तफसील से योजना की गई है। सन् १९२० ई० के एक 'शाही राज व्यवस्था संशोधन कमीशन' ने राजवंश का कोई उत्तराधिकारी न रहने पर हालैंड में बिना राजा की सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया था। मगर इस प्रस्ताव को मंजूर न कर के सन् १९२२ ई० में राजछत्र के बारे में यह योजना की गई थी कि राजछत्र का कोई उत्तराधिकारी न रहने पर हालैंड की व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं के 'सम्मिलित सम्मेलन' के हाथ में सारी सत्ता आ जायगी और यही सम्मेलन नया उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा।

**व्यवस्थापक-सभा**—हालैंड की व्यवस्थापक-सभा को 'स्टेट्स जेनरल' कहते हैं और उसमें 'ऊपरी' और 'निचली' दो सभाएँ होती हैं। 'निचली सभा' में १०० सदस्य होते हैं, जिन को सारे मताधिकारी नागरिक चार साल के लिए, अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से चुनते हैं। 'ऊपरी सभा' में ५० सदस्य होते हैं, जिन को प्रातिक्रिधारा सभाएँ चुनती हैं। सन् १६२२ ई० तक 'ऊपरी सभा' के सदस्यों को नौ वर्ष के लिए चुना जाता था और सदस्यों की एक तिहाई संख्या का हर तीसरे वर्ष चुनाव होता था। सन् १६२२ के एक संशोधन के बाद से ऊपरी सभा का चुनाव छः वर्ष के लिए होता है और प्राथमिक सदस्य हर तीसरे साल बदल जाते हैं। कानून बनाने की सत्ता 'स्टेट्स जेनरल' और राजा दोनों में मानी गई है। हर एक कानून की मजूरी के लिए दोनों सभाओं की राय की जरूरत होती है। सारे कानून 'निचली सभा' में पेश होते हैं। उन को मंजूर करने और रद्द करने का अधिकार 'ऊपरी सभा' को होता है। रजद भी पहले निचली सभा में ही पेश होता है।

**कार्यकारिणी**—सरकार के सारे कामों के लिए मंत्री जवाबदार होते हैं। राजा को किसी कानून को नामजूर कर देने और व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं का एक सभा को भंग करने का हक जरूर होता है। मगर जवाबदारी मंत्रियों की होने से राजा अपने इस अधिकार का प्रयोग भी मंत्रि मंडल और व्यवस्थापक सभा की राय के अनुसार ही करता है। सन् १६२२ ई० तक मंत्रि मंडल की राय से युद्ध छेड़ने और दूसरे राष्ट्रों से संधियाँ मंजूर करने का भी अधिकार राजा को था। मगर अब इस सत्ता के प्रयोग के लिए भी व्यवस्थापक सभा की आज्ञा की आवश्यकता होती है। राज व्यवस्था में राजा के मंत्रियों को नियुक्त करने और निरालने के अधिकार का अधिक है; प्रधान मंत्री या मंत्रि मंडल का कहीं कोई जिन नहीं है। परंतु इंग्लैंड की तरह डेन्मार्क में भी प्रजासत्तात्मक सरकार का विकास होने के कारण वहाँ भी यह एक व्यवस्थापक रिवाज बन गया है कि राजा निचली सभा के बहुसंख्या दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त करता है तथा उस की राय से मंत्रि मंडल नियुक्त करता है। मगर डेन्मार्क में मंत्रियों को दोनों सभाओं की चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होता है, जो इंग्लैंड में नहीं होता है। मगर किसी सभा के सदस्य न होने पर, उस में मत देने का उन को अधिकार नहीं होता है। दूसरे प्रजासत्तात्मक राष्ट्रों की तरह मंत्रियों की सभाओं में आलोचना की जाती है और उन के काम-काज के विषय में उन से प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यवस्थापक सभा का साल में आम तौर पर एक बार जलसा होता है। मगर मंत्रि मंडल की राय से राजा अधिक जल्मे भी बुला सकता है।

चौदह सदस्यों की एक 'कौंसिल ऑफ़ स्टेट' भी होती है, जिस को राजा राष्ट्र के प्रख्यात पुरुषों में से चुनता है और जिस का अध्यक्ष वह स्वयं होता है। कानूनों और शासन की नीति और परमान निरालने के विषय में राजा और मंत्रि-मंडल इस सभा से सलाह लेता है।

**स्थानिक-शासन**—स्थानिक शासन प्रांतों और कम्प्यूनों के द्वारा चलाया जाता है। हालैंड में कुल ग्यारह प्रांत और ११०० कम्प्यूनों हैं। हर प्रांत में प्रजा की चुनी हुई एक 'धारा-सभा' होती है और इस सभा के सदस्यों की एक छोटी 'कार्यकारिणी समिति' प्रांतीय सरकार का काम-काज चलाने के लिए होती है। 'कार्यकारिणी समिति' को 'धारा-सभा' की राय से प्रांत के हित में सब प्रकार के फरमानों काबू भी जारी करने का अधिकार होता है। मगर केंद्रीय सरकार की मंजूरी इन फरमानों के लिए जरूरी होती है। केंद्रीय सरकार 'कौंसिल ऑफ़ स्टेट' की राय से इन फरमानों को मंजूर करने से इन्कार कर सकती है। एक 'साहो कमिशनर' हर प्रांतीय 'धारा-सभा' और उस की 'कार्यकारिणी समिति' का अध्यक्ष होता है और बड़ी प्रांतीय अधिकारियों के काम-काज की देख-भाल करता और केंद्रीय सरकार के हुक्मों का पालन करता है।

कम्प्यूनों की भी चुनी हुई सभाएं होती हैं। उन को शासन के ऐसे उपनियम बनाने का अधिकार होता है जो प्रांतीय सरकार की सत्ता के विरुद्ध न हों। कम्प्यून की सभा का मेयर अर्थात् अध्यक्ष केंद्रीय सरकार नियुक्त करती है, जिस से केंद्रीय सरकार की कम्प्यूत पर हुक्मत कायम रहती है। 'प्रांतीय कार्यकारिणी समिति' को कम्प्यून का बजट नामजूर कर देने का हक होता है।

**न्याय**—न्याय-शासन के लिए हेग में एक सब से बड़ी 'राष्ट्रीय अदालत' होती है, जो नीचे की अदालतों से अपीलों और व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों, मंत्रियों और दूसरे बड़े अधिकारियों के शासन-संबंधी अपराधों के गुरुदमों पर विचार करती है। उस के नीचे पाँच 'अपील की अदालतें', इक्कीस 'ज़िला अदालतें' और १०१ स्थानिक 'छोटी अदालतें' होती हैं। न्यायधीशों को जन्म भर के लिए राजा चुनता है। 'राष्ट्रीय अदालत' के न्यायधीशों को यह व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा की बनाई हुई एक सूची में से नियुक्त करता है।

शासन के कगड़ों के लिए एक 'शासकी अदालत' और सैनिक अपराधों के लिए एक 'सैनिक अदालत' भी हेग में होती हैं।

**राजनैतिक दलबंदी**—हालैंड के गरम सरकारपक्षी दलों में अधिकतर धार्मिक दल हैं, जिन में से एक 'रोमन कैथोलिक राष्ट्रीय दल', दूसरे 'क्रांति-निरोधी दल' और तीसरे 'ईसाई ऐतिहासिक सब' तीन दलों का सन् १९०० से १९२५ ई० तक राशि-लित समूह था। इन दलों के भी गरम अंग हैं। मगर व्यवस्थापक-सभा के गरम दलों में एक 'उदार दल', दूसरा 'उदार प्रजासत्तात्मक दल', तीसरा 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' और चौथा 'समिष्टवादी दल' है। ये दल विचारों में एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि कभी इन सब का मिल कर एक मजबूत सरकार का विरोधी समूह नहीं बनता है। फिर भी एक बात में ये सारे दल एक मत हैं कि सरकार को धार्मिक प्रभावों से दूर रहना चाहिए और सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालैंड के दल धार्मिक,

अनुदार, प्रजासत्तात्मक और समाजवादी इत्यादि; सब प्रकार के विचारों पर बने होने के कारण इस देश में मन्त्रिमंडलों का बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार तो यहाँ तक नौशा पहुँच गई थी कि अक्टूबर सन् १९२३ से जनवरी सन् १९२४ ई० तक हालैंड में कोई मन्त्रिमंडल ही नहीं बन सका था। मजबूर हो कर राजा को पुराने मन्त्रिमंडल का इस्तीफा नामजूर करना पड़ा था; क्योंकि इतना समय बीत जाने पर भी कोई प्रधान मंत्री नया मन्त्रिमंडल नहीं बना सका था।

**रोमन कैथोलिक दल**—निरा धार्मिक दल है। 'क्रांति-विरोधी दल' 'उदारवाद' और समाजवाद का विरोधी, आरेंज विलियम के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय सरकार का पक्षपाती, अनुदार, कट्टर राष्ट्रीयवादी, आरेंज-बश का समर्थक, मजबूत जल और थल सेना रखने, रविवार के दिन पूरी शांति रखने और पूजा पाठ करने, मौत की सजा को पुनर्जीवित करने, जबरदस्ती टीका लगाना बंद करने और मुर्दा जलाना बंद करने का तरफदार है। इसी दल के प्रजासत्तात्मक विचारों के विरोधी सदस्यों ने अलग हो कर एक 'ईसाई ऐतिहासिक सघ दल' बनाया था। जिस के राजनैतिक और धार्मिक विचार भी 'क्रांति-विरोधी दल' से मिलते-जुलते हैं, मगर आर्थिक विचारों में यह दल 'उदार दल' से मिलता है।

**उदार दल**—में अधिकतर बड़े व्यापारी और विद्वान लोग होते हैं। यह दल उदार सिद्धांतों यानी स्वतंत्र व्यापार, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप खास कर उद्योग में और मजदूरों के हितकारी कानूनों का हामी है। इस दल के गरम लोगों ने सन् १९०१ में अलग अलग होकर 'उदार प्रजासत्तात्मक दल' बना लिया था, जो अब मजदूरों के लिए बहुत से सुधारों का पक्षपाती और सेना बढ़ाने का विरोधी है। दूसरे दो 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' और 'समष्टिवादी दल' इसी नाम के यूरोप के दूसरे दलों की तरह हैं।



## नार्वे की सरकार



**राज-व्यवस्था**—यूरोप के बिल्कुल उत्तर-पश्चिम कोने में, हाथी की सूँड़ की तरह लटकने वाले स्कैंडीनेवियन पेनिनशुला के दोनों राष्ट्रों, नार्वे और स्वीडन, की सरकारें यूरोप की पुरानी सरकारों में हैं। नार्वे की राज-व्यवस्था सन् १८१४ ई० में बनी थी। उस के बाद उस में कुछ संशोधन भी हुए हैं। इस राज-व्यवस्था के अनुसार नार्वे एक स्वाधीन राष्ट्र है जिस में अलंड मौरूसी राजाशाही सरकार है।

**कार्यकारिणी**—राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राज-व्यवस्था के अनुसार राजा में मानी गई है। मगर बहुत दिनों के राजा और प्रजा में झगड़े के बाद अब ऐसा रिवाज बन गया है कि राजा की सत्ता का प्रयोग प्रजासत्तात्मक और प्रजा के जवाबदारी के के सिद्धांत पर होता है। राजा की सहायता करने के लिए एक प्रधान मंत्री और कम से कम सात और मंत्रियों का एक मंत्रि मंडल होता है। राजा के हर हुक्म पर, उस के बाकायदा होने के लिए, किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। राजा को व्यवस्थापक-सभा भंग करने का हक नहीं होता है। उस व्यवस्थापक-सभा में मनूर हुए किसी भी कानून को नामंजूर कर देने का हक जरूर होता है। मगर राजा के नामंजूर कर देने पर भी वही कानून तीन व्यवस्थापक-सभाओं में बराबर पास होने पर कानून बन जाता है और राजा की नामंजूरी का तीन बार के बाद फिर कुछ भी असर नहीं होता है। राज्य के सारे अधिकारियों को, मंत्रि-मंडल की सलाह से, राजा नियुक्त करता है। मगर नियुक्ति के सात नियम होते हैं, जिन के अनुसार सिर्फ खास योग्यता के मुख्य लोग ही अधिकारी बन सकते हैं। मंत्रि-मंडल में बिना कम से कम आधे सदस्यों की हाजिरी के कोई फैसला

नहीं किया जा सकता है। मन्त्रिमंडल का जीवन व्यवस्थापक सभा के विश्वास पर निर्भर होता है, क्योंकि कानून बनाने और खर्च पैसे के सारे अधिकार व्यवस्थापक सभा के होते हैं।

**व्यवस्थापक सभा**—नार्वे की व्यवस्थापक सभा को 'स्टोरटिंग' कहते हैं। हर २३ वर्ष के ली और मर्द नार्वे के नागरिक को जो देश में कम के कम पाँच साल बस चुका हो और चुनाव के समय भी देश में रहता हो, व्यवस्था सभा के लिए मत देने का अधिकार होता है। व्यवस्था सभा में कुल १५० सदस्य होते हैं, जिन को तीन साल के लिए, गाँवों की निरक्षर शहरों से दुगुने के हिसाब से, अनुगत निर्वाचन की पद्धति के अनुसार नागरिक चुनते हैं। व्यवस्थापक सभा के उम्मीदवारों को तीस वर्ष के ऊपर की उम्र का, देश में दस वर्ष तक बस चुकने वाला, और जिस क्षेत्र से वह उम्मीदवार हो वह अति अधिकार होना जरूरी होता है।

**स्टोरटिंग**—को कानून बनाने और रद्द करने, कर लगाने और हटाने, सरकारी आय व्यय का पेंसला करने, और राजा की दूखे राष्ट्रों से की हुई वसाम सधियाँ और मैत्रियों का मुलाहिजा करने का अधिकार होता है। 'स्टोरटिंग' की एक 'स्थायी उपसमिति' होती है जो सभा के सामने आने वाले कानूनी और आर्थिक मसलियों पर पहले विचार कर के सभा को अपना मत उन विषयों पर भेज देती है। व्यवस्थापक सभा की 'चुनाव समिति' कई समितियाँ नियुक्त करती है, जिन के पास विभिन्न विभाग के आय व्यय के प्रस्ताव विचार के लिए जाते हैं। एक 'परराष्ट्र विषय समिति' भी होती है। 'स्टोरटिंग' को सारी सरकारी सधियों, रिपोर्टों और कामजातों को दाखिल दफतर करा लेने का हक होता है, क्योंकि सारे सरकारी शासन पर उस का अक्रुश माना गया है। विदेशों से किए गए आवश्यक समझौतों के लिए भी 'स्टोरटिंग' की मजूरी की जरूरत होती है। मन्त्रिमंडल के सदस्यों के 'स्टोरटिंग' की कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक होता है। मगर वे मत नहीं दे सकते हैं। मन्त्रिमंडल के सदस्य हो कर वे व्यवस्थापक सभा में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की तरह नहा बैठ सकते हैं। फिर भी उन को दूसरे सदस्यों की तरह कानून मसविदे पेश करने का हक होता है।

व्यवस्थापक सभा की दो सभाओं के विषय में नार्वे में विचित्र योजना की गई है। स्टोरटिंग अपने सदस्यों में से एक चौथाई को चुन कर उस की 'लैंगटिंग' नाम की व्यवस्थापक सभा की एक सभा बना लेती है। और स्टोरटिंग के बाकी तीन चौथाई सदस्यों की, 'ओडेल्सटिंग' नाम की, व्यवस्थापक सभा की दूसरी सभा बन जाती है। इन दोनों सभाओं की कार्रवाई के चलाने के लिए, हर एक में, कम से कम दो तिहाई सदस्यों की हाजिरी की जरूरत होती है। दोनों सभाएँ अपने अपने अध्यक्ष और मंत्री को चुन चुकी हैं। कानून बनाने का डग भी नार्वे में विचित्र है। सब मसविदे 'ओडेल्सटिंग' में पेश होते हैं, और इस सभा में मंजूर हो जाने के बाद 'लैंगटिंग' में भेजे जाते हैं। फिर लैंगटिंग उस पर विचार कर के उस को मंजूर या नामंजूर करती है। नामंजूर करने

पर 'लेंगटिंग' करने बज्जहत बताती है। लेंगटिंग से पुन विचार के लिए वापस आने पर 'ग्रोडेल्सटिंग' मसजिदों पर फिर विचार करती है और उस को वैसा ही या सशोधित कर के फिर लेंगटिंग के पास भेज देती है। इस प्रकार ग्रोडेल्सटिंग का मजूर किया हुआ कोई मसजिदा जब दो बार लेंगटिंग के सामने रखा जा कर दोनों बार नामजूर हो जाता है, तब 'स्टोरटिंग' की पूरी सभा को बैठक होनी है और दो निहाई सदस्यों के मत से उस मसजिदे का आखिरी फसला कर दिया जाता है। काहू उनाने के इस ढंग को बहुत से राजनीति के विद्वान पसंद करते हैं। नास्त्व म इस ढंग से व्यवस्थापक-सभा की 'दो सभाओं की समस्या' का अच्छा हल हो जाता है।

राज-व्यवस्था म सशोधन के प्रस्तावों को पास करने के लिए 'स्टोरटिंग' के दो निहाई मतों की जरूरत होती है। मगर इस प्रकार के सशोधन चुनाव के बाद 'स्टोरटिंग' की सभा में पहले या दूसरे साल में ही पेश और मजूर हो सकते हैं, तीसरे वर्ष में नहीं।

**स्थानिक शासन, सेना और न्याय**—नार्वे के स्थानिक शासन की खास बात यह बड़ी जा सकती है कि यहां केंद्रीय सरकार का स्थानिक शासन में बहुत ही कम दखल होता है। राष्ट्रीय रक्षा के खास प्रश्नों का विचार एक 'राष्ट्रीय रक्षण समिति' करती है। इस समिति का अध्यक्ष 'राष्ट्रीय रक्षण सचिव' होता है और दूसरे सदस्य जल और थल सेना के सब से बड़े चार अधिकारी होते हैं। न्यायशासन नार्वे में दूसरे सम्य देशों की तरह ही है। मगर जेलखाने यहां के आधुनिक और मानवी पद्धति पर होते हैं। जेलखानों को, अपराधियों को तकलीफ देने की जगह न मान कर, सुधारने की जगह माना जाता है। स्त्रिया और पागलों की जेलें अलग होती हैं। आवागमनों को भी आवागमनों में पकड़ कर जेल में नहीं डाल दिया जाता है, उन के लिए खास खेती-बारी के उपनिवेश बना दिए गए हैं।

**राजनैतिक दलबंदी**—नार्वे के राजनैतिक दलों में एक 'सरकारपक्षी दल' है। यह दल उदार, अनुदार और राष्ट्रीय विचारों के लोगों का मिश्रण है और समाजवादियों और शरानदी के आंदोलन का विरोधी है। यह दल राष्ट्र के आर्थिक जीवन और आय व्यय की खासतौर पर उन्नति करने और प्रजासत्तात्मक सरकार और व्यक्तिगत मिलिक्रयत की रक्षा करने का हामी है। दूसरा एक 'उदार दल' है जो 'सरकारपक्षी दल' से मिल कर काम करता है। यह दल उदार, राष्ट्रीय विचारों का है और लोगों के सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति के व्यक्तिगत अधिकारों में मानता है। तीसरा एक 'किसान दल' है जो प्रजासत्तात्मक सरकार, अमन और कानून में विश्वास रखता है और नातिकारी हमलों से सरकार की रक्षा करना और सरकार का खर्च कम करना चाहता है। यह दल यह भी मानता है कि नार्वे की उन्नति और हित के लिए नार्वे में एक, स्वाधीन और आर्थिक दृष्टि से मजबूत, किसान वर्ग का बनाना आवश्यक है।

दूसरे दलों में एक चौथा 'प्रजापक्षी दल' है जो आज कल की सरकार के ढंग पर

ही, धीरे धीरे आर्थिक, सामाजिक, और सस्कृति के सुधारों के द्वारा 'राष्ट्रीयता' और प्रजासत्ता की उन्नति करना चाहता है। यह दल राष्ट्रीय भाषा आंदोलन का पक्षपाती है। पाँचवाँ एक 'गरम लोकदल' है। जो 'प्रजापक्षी दल' से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यह दल राष्ट्रीय और गरम प्रजासत्तात्मक नीति अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता, पड़ोसी देशों से मैत्री, स्वतंत्र व्यापार श्रमजीवियों के आर्थिक स्वाधीनता देने वाले सुधारों, शराबबंदी और राष्ट्रीय भाषा आंदोलन का पक्षपाती है।

छठा एक 'नार्वेजियन श्रमजीवी दल' है। इस दल में नार्वे का 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' भी मिल गया है। यह दल समाजशाही कायम करने में मानता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिर्फ व्यवस्थापक समाज का ही इस्तेमाल न कर के, सन प्रकार के ज़रियों और खास कर 'वर्ग युद्ध' का पक्षपाती है। सातवाँ दूसरे देशों से मिलता जुलता एक 'समष्टिवादी दल' है।

इन दलों का नार्वे के प्रजामत पर असर का स्पष्ट ज्ञान पाठकों को सन् १९३० ई० के चुनाव के अंकों से हो जायगा। विभिन्न दलों को इस चुनाव में निम्न प्रकार मत मिले थे और उन के सदस्य 'स्टोरटिंग' में निम्न प्रकार चुने गए थे—

दल	मत	प्रतिनिधि
सरकार पक्षी दल और सदार दल	३५४५७८	४४
किसान दल	१८७८१६	२५
प्रजा पक्षी दल और गरम लोकदल	२४८०१०	३४
नार्वेजियन श्रमजीवी दल	( सन् १९२७ के चुनाव में ३६८१०० मत और सदस्य ५६ )	४८
समष्टिवादी दल	( सन् १९२७ के चुनाव में ४००६१ मत और सदस्य ३ )	०

## स्वीडन की सरकार



**राज-व्यवस्था**—स्वीडनिया पेनिन्सुला के दूसरे राष्ट्र स्वीडन की राज-व्यवस्था सन् १८०९ ई० से प्रारंभ होती है। इस के अनुसार इस देश में मौलसी राजा-शाही की सरकार है। मगर इस राज-व्यवस्था के बाद के संशोधनों और परिवर्तनों से राजा की सत्ता बिल्कुल घट गई है और व्यवस्थापक-सभा की सत्ता बहुत बढ़ गई है, जिस से स्वीडन में राजाशाही कायम रहते हुए भी सरकार इंग्लैंड की तरह, प्रजासत्तात्मक बन गई है।

**राजा और मंत्रि-मंडल**—स्वीडन की राज-व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र की कार्यकारिणी और न्यायसत्ता राजा और मंत्रि-मंडल में मानी गई है। चारासत्ता अर्थात् कानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा में मानी गई है। मंत्रि-मंडल की कार्यवाही के सारे कामकाजों को व्यवस्थापक-सभा की एक समिति देखती है जिस से मंत्रि-मंडल पर व्यवस्थापक-सभा का पूरा अंकुश रहता है। व्यवस्थापक-सभा मंत्रि-मंडल के सदस्यों पर और कानूनी कार्यवाही के लिए अभियोग भी चला सकती है। स्वीडन का राजा, राज-व्यवस्था के अनुसार, 'लूथरन चर्च' का अनुयायी होना चाहिए। उस को परराष्ट्र-नीति के संचालन का अधिकार होता है। मगर इस विषय में भी उस को मंत्रि-मंडल और 'परराष्ट्र विषय समिति' की सलाह से ही काम करना पड़ता है और सारे कामकाजों को व्यवस्थापक-सभा की 'परराष्ट्र विषय समिति' के सामने रखना होता है। विदेशों से होने वाले तमाम जरूरी समझौतों को आखिरी मंजूरी के लिए व्यवस्थापक-सभा के सामने रखना होता है।

सारे ज़रूरी मसविदे हमेशा सरकार की तरफ से व्यवस्थापक-सभा में पेश होते हैं। व्यवस्थापक-सभा में मंजूर हो जाने के बाद राजा की मंजूरी से मसविदे कानून बन सकते हैं। साधारण सदस्यों के मसविदों की तरह सरकारी मसविदों में भी सभा आज्ञादी से संशोधन करती है। वजट और कर-संबंधी मसविदे पेश तो ज़रूर राजा की तरफ से होते हैं; मगर उन के संबंध में पूरा अधिकार व्यवस्थापक सभा को होता है। 'सालिसिटर-जेनरल' और 'सेनिक्र सालिसिटर जेनरल' नाम के दो खास अधिकारियों के द्वारा भी व्यवस्थापक-सभा शासन पर अकुश रखती है। स्वीडन के 'राष्ट्रीय बैंक' और 'राष्ट्रीय कर्जा बोर्ड' पर भी व्यवस्थापक-सभा का सीधा अधिकार होता है।

**व्यवस्थापक-सभा**—स्वीडन की व्यवस्थापक-सभा को 'रिक्सडाग' कहते हैं। इस की 'ऊपरी' और 'निचली' दो सभाएँ होती हैं। दोनों सभाओं को करीब-करीब सारे प्रश्नों में एक-सी सत्ता और अधिकार होता है। 'ऊपरी सभा' में १५ सदस्य होते हैं, जिन को जिला सभाएँ और नगरों में खास तौर पर नियुक्त किए हुए मतदार आठ साल के लिए चुनते हैं। 'ऊपरी सभा' के चुनाव के लिए देश भर में १६ चुनाव-क्षेत्र हैं। इन चुनाव-क्षेत्रों को आठ भागों में बाँट दिया गया है, जिन में हर एक भाग हर छाल बारी-बारी से आगामी आठ साल के लिए ऊपरी सभा के सदस्यों की संख्या के आठवें भाग को चुनता है। ऊपरी सभा के उम्मीदवारों को ३५ वर्ष की उम्र का और पचास हजार क्रोनर की क्षीमत की मिलक्रियत का मालिक या तीन हजार क्रोनर की सालाना आमदनी वाला होने की ज़रूरत होती है। अष्टादस वर्ष के ऊपर के मतदारों को अनुपात-निर्वाचन के अनुसार 'ऊपरी सभा' के चुनाव में मत देने का हक होता है। दूसरी 'निचली सभा' में २२० सदस्य होते हैं। उन को २४ वर्ष के ऊपर के सारे स्त्री पुरुष नागरिक मतदार चार साल के लिए चुनते हैं। 'निचली सभा' के सारे हकदार मतदारों को देशत में अपने चुनाव-क्षेत्रों से और शहरों में किसी एक चुनाव-क्षेत्र से उम्मीदवार होने का हक होता है। इस सभा का चुनाव भी अनुपात-निर्वाचन की पद्धति पर होता है।

दोनों सभाएँ अपने-अपने अध्यक्षों को खुद चुनती हैं। दोनों सभाओं में एक-एक अध्यक्ष और दो दो उपाध्यक्ष होते हैं और उन को इस हिसाब से चुना जाता है कि स्वीडन के तीनों बड़े राष्ट्रीय दलों के बारी-बारी से अध्यक्ष होते हैं। 'रिक्सडाग' के सामने आने वाले विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए बहुत सी 'स्थायी समितियाँ' होती हैं जिन में दोनों सभाओं से आधे-आधे और राजनैतिक दलों से अनुपात-निर्वाचन के सिद्धांत पर सदस्य लिए जाते हैं। इन समितियों में मुख्य 'परराष्ट्र विषय समिति' 'व्यवस्थापक समिति' 'वजट समिति', 'कर समिति' 'बैंक समिति' 'कानून समिति' और 'कृषि समिति' होती हैं। 'व्यवस्थापक समिति' मंत्रि-मंडल की कार्रवाई के कागज़ों को देखती-भालती है और राज-व्यवस्था तथा स्थानिक शासन से संबंध रखने वाले मसविदों का विचार और प्रस्ताव करती है। 'वजट समिति' राष्ट्रीय आय-व्यय के सारे प्रश्नों पर विचार करने के कारण सच से आवश्यक समिति गिनी जाती है। इन समितियों का स्वीडन की 'रिक्सडाग'

के काम-काज में खास स्थान होता है, क्योंकि उन में दोनों सभाओं के सदस्य मिल कर साथ-साथ काम करते हैं। अगर किसी ऐसे विषय पर जिस पर कोई समिति निचार करती है, रिकसडाग की दोनों सभाओं का मत एक-दूसरे से भिन्न होता है तो वह समिति जहाँ तक बने वहाँ तक जरूर कोई न कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करती है जिस से दोनों सभाओं में समझौता हो जाय। हर मसविदे की आखिरी मंजूरी के लिए दोनों सभाओं की मंजूरी की जरूरत होती है; परंतु आय व्यय संबंधी प्रश्नों पर दोनों सभाओं का मतभेद होने पर दोनों सभाओं की एक 'सम्मिलित बैठक' में सारे सदस्यों के बहुमत से फैसला किया जाता है। अस्तु; राष्ट्रीय आय-व्यय के प्रश्नों का आखिरी फैसला रिकसडाग की निचली सभा के हाथ में ही रहता है; क्योंकि निचली सभा के सदस्यों की संख्या ऊपरी सभा के सदस्यों से कहीं अधिक होती है।

हर चौथे वर्ष 'रिकसडाग' देश के छः प्रसिद्ध विद्वानों की एक 'सलाह समिति' सालिसिटर जेनरल को 'अखबारी आजादी' कायम रखने में सहायता करने के लिए भी नियुक्त करती है।

**स्थानिक शासन और न्याय**—प्रांतीय शासन चलाने के लिए राजा स्वीडन की राजधानी स्टाफहोम के लिए एक बड़े गवर्नर और देश के शेष चौबीस प्रांतों के लिए एक-एक प्रीफेक्ट को नियुक्त करता है। इन प्रीफेक्टों के नीचे काम चलाने के लिए नायब होते हैं। प्रांतों की छोटी-छोटी कम्यूनों और क्लस्कों में मतदारों की 'सार्वजनिक सभाएं' और बड़ी जगहों में चुनी हुई 'स्थानिक सभाएं', स्थानिक 'शासन' 'पुलिस' और 'आर्थिक जीवन' के सारे प्रश्नों का फैसला करती हैं। प्राथमिक शिक्षा और धार्मिक प्रश्नों का फैसला स्थानिक 'धार्मिक सभाएं' करती हैं। हर प्रांत में प्रांत का भीतरी काम-काज चलाने के लिए एक चुनी हुई 'प्रांतीय सभा' होती है, जिस की अपने चुने हुए अध्यक्ष की अध्यक्षता में सालाना बैठकें होती हैं। स्थानिक सभा का चुनाव भी अनुपात-निर्वाचन के अनुसार होता है और उन में स्त्री, मर्द दोनों भाग लेते हैं।

न्याय शासन कार्यकारिणी से त्रिस्तुल्य स्वतंत्र होता है और उस का संचालन, राष्ट्र के दो बड़े अधिकारियों, चांसलर ऑफ् जस्टिस् और एटर्नी जेनरल के हाथों में होता है। चांसलर ऑफ् जस्टिस् को स्वयं राजा नियुक्त करता है और वही राजा का वकील भी होता है। एटर्नी जेनरल को व्यवस्थापक सभा नियुक्त करती है और वह सारी अदालतों के काम की देख माल रखता है। स्वीडन की सब से बड़ी अदालत स्टाफहोम में बैठती है। उस में चौबीस न्यायाधीश होते हैं, जिन की सात सात की तीन अदालतें होती हैं। इन तीन राष्ट्रीय अदालतों के नीचे तीन अपील की अदालतें और उन के नीचे २१४ जिला अदालतें हैं, जिन में लगभग ६१ शहरी अदालतें और १२३ गाँवों की अदालतें हैं। अपील की अदालतों में अदालत का एक अध्यक्ष, न्यायाधीश, और असेसर होते हैं। जिला अदालतों में, शहरों में, मेयर और शहर सभा के दो सदस्यों की अदालत बन जाती है; और मुफत्सिल की अदालतों में एक न्यायाधीश और छः साल के लिए प्रजा के चुने हुए १२ पंच होते

हैं। पक्षों को कानूनी और गवाही दोनों के प्रश्नों का न्यायाधीश के साथ मिल कर फैसला करने का हक होता है। मगर पक्षों में मत भेद होने पर फैसला न्यायाधीश के ऊपर रहता है। सारे पक्षों का एक मत होने पर न्यायाधीश का मत त्रिकद्व होने पर भी फैसला पक्षों के मतानुसार होता है। बड़े शहरों में जहाँ शहर समाए होती हैं, हर निर्वाचन-क्षेत्र में तीस सदस्यों की एक अदालत होती है। आवपाशी के झगड़ों का फैसला करने के लिए 'खास अदालतें' और 'कोर्ट मार्शल' और 'पुलिस अदालतें' भी होती हैं। शासन के झगड़ों का आम तौर पर फैसला शासन अधिकारी करते हैं। मगर एक बड़ी 'शासन अदालत' भी है जिस के सामने अभियोग जा सकते हैं।

**राजनैतिक दल**—स्वीडन की व्यवस्थापक सभा की प्रथा के अनुसार स्वीडन में मन्त्रि-मंडलों के रचने में देश के सभी बड़े दलों का हाथ होता है। किसी एक दल की व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या न होने से मन्त्रि-मंडल दलबन्दी के अनुसार नहीं चला पाते हैं।

स्वीडन के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'सरकार-पक्षी दल' है जो सन् १८६९ ई० से पहले भी था। यह मजबूत राष्ट्रीय रक्षा और प्रचलित सामाजिक और आर्थिक जीवन को कायम रखने का पक्षपाती है। दूसरा एक 'किसान संघ दल' है जो संकुचित पुराने विचारों का है और खास कर किसानों की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक उन्नति का पक्षपात रखता है। 'उदार दल' और 'लोक-दल' नाम के दो दल सन् १९२० ई० में शराब बंदी के प्रश्न पर पुराने 'संयुक्त उदार दल' से टूट कर बन गए। यह दोनों दल समाज सुधार, स्वतंत्र व्यापार, लीग ऑफ नेशंस और शांति के पक्षपाती हैं।

दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों की तरह स्वीडन में एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' भी है इस दल के सन् १९२०, १९२१, १९२४ और सन् १९२५ में मन्त्रि-मंडल थे। एवं 'समष्टिवादी दल' भी है। विभिन्न राजनैतिक दलों का सरकार पर प्रभाव जानने के लिए व्यवस्थापक सभा में उन की संख्या जान लेना उपयोगी होगा। यह सन् १९३२ ई० में निम्न प्रकार थी—

	ऊपरी सभा	निचली सभा
सरकार पक्षी दल	५०	७३
किसान संघ दल	१६	२७
उदार दल	८	४
लोकदल	२३	७८
समाजी प्रजासत्तात्मक दल	५२	६०
समष्टिवादी दल	१	८



## पुर्तगाल की सरकार

**राज-व्यवस्था**—यूरोप के शेष पुराने राष्ट्रों में यूरोप के दक्षिण पश्चिम कोण में निकले हुए आइबेरियन पेनिन्सुला के दो देशों, पुर्तगाल और स्पेन, की सरकारों का बयान करना और रह गया है। पुर्तगाल १२वीं सदी से एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसी देश के मुसाफिर वेस्कोडिगामा ने पहले-पहल हमारे देश और यूरोप से व्यापारिक संबंध जोड़ा था। हिंदुस्तान के व्यापार के लिए जी तोड़ कर लड़ने वाले यूरोपीय देशों में यह देश भी था, जिस की, फ्रांस की तरह उन लड़ाइयों में हार हो जाने के कारण, भारतवर्ष में सिर्फ अरब गोआ, डामन और डिउ इन तीन छोटे से स्थानों में जागीरें रह गई हैं। फिर भी इस देश की संस्कृति की छाप हमारे देश के बंबई की तरफ कर्हवाल्हो, डीसोज़ा, फर्नेंडीज़ और अल्वा जैसे नामों के हिंदुस्तानी रोमन कैथोलिक ईसाइयों के एक छोटे समूह में और पुर्तगाल के अधिकार और संसर्ग की निशानी बंबई के साताकुज़ और विलेपार्ले<sup>१</sup> नाम के स्थानों के पुर्तगीज़ नामों और मराहूर गुजराती आफूस आम<sup>१</sup> में रह गई है। पुर्तगाल में सन् १६१० ई० तक राजाशाही सरकार थी। सन् १६१० ई० में राजाशाही को खत्म कर के प्रजातन्त्र की स्थापना कर दी गई थी; मगर प्रजातन्त्र राज व्यवस्था कायम हो जाने पर भी पुर्तगाल में अभी तक वही पुरानी विसपिंग और अव्यवस्था चली आती है जो प्रजातन्त्र कायम होने से पहले सौ वर्ष तक थी।

<sup>१</sup> इस आम को भारतवर्ष में शायद पुर्तगाल से लाया गया था। इस का असली नाम अलफ़ोंज़ो था जिस का गुजराती अपभ्रंश आफूस हो गया है।

प्रजातन्त्र कायम होने से पूर्व राजा और प्रजा का आए दिन झगड़ा होता रहता था। कभी क्रांति हो जाती थी और राजा गद्दी से उतार दिया जाता था या उस से जनर्दस्ती प्रजासत्तात्मक राज व्यवस्था मजबूर करा ली जाती थी, कभी राजा मजबूर की हुई राज-व्यवस्था को तोड़ कर फिर अपनी पुरानी चाल पर चलने लगता था। इन झगड़ों और राजनैतिक उथल-पुथल ने देश का आर्थिक सर्वनाश कर रखा था, जिस के परिणामस्वरूप आखिरी क्रांति हुई और प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। राजाशाही के ज़माने के पुराने पेशावर राजनीतिकों को देश के हित की अपेक्षा खुद अधिकार की कुवियों पर बैठने ही की अधिक चिंता रहती थी। चुनावों के प्रबंध में उड़े होशियार होने के कारण ये आपस के गुटों में समझौते कर के किसी न किसी तरह, कभी प्रजातन्त्रवादी और स्वतन्त्र सदस्यों का चुनाव नहीं होने देते थे।

सरकार का खुला और वाक्ताव्य विरोध दबा दिया जाने से स्वाधीनता के लिए लातायित आत्माएँ मजबूर हो कर क्रांति के घाट उतरने का प्रयत्न करती थीं। सन् १६०३ ई० में भी पुर्तगाल में प्रजातन्त्र की स्थापना करने के लिए एक क्रांति हुई थी। मगर वह निष्फल गई थी। राजा को आम तौर पर किसी न किसी तरह स्वयं प्राप्त करने की चिंता रहती थी, और राजनैतिक नेताओं को किसी न किसी प्रकार पद प्राप्त करने की चिंता रहती थी। दोनों में से किसी को राष्ट्रीय कोप की हालत ठीक करने का कभी खयाल नहीं रहता था। सरकार को हर साल बजट में नुकसान होता था। चुनाव में मतदारी को स्थानिक गिरजों में जा कर मत डालने पड़ते थे। पादरी, धनवान और ज़मींदार लोग आपस में मिल कर इस बात का इतज़ाम कर लेते थे कि चुनावों में देहाती जिलों में उन की ताकत कायम रहे।

अखिर, प्रजातन्त्र को लाठी के जोर पर कायम करना पड़ा था, परन्तु पुर्तगाल के दुर्भाग्य से अभी तक वहाँ लाठी का जोर कायम है। शहरों में जरा जरा बात में बखेड़े हो जाते हैं। राजनैतिक नेताओं का क्रांतिकारी गुट बनाने की तरफ रुकान रहता है। कई बार लाठी के जोर से राजाशाही को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न भी किया जा चुका है। आगे भी डर है कि इस बात के प्रयत्न किए जायेंगे। दुर्भाग्य से नए राजनैतिक नेता भी, पुरानों की तरह, अपनी व्यक्तिगत वृद्धि और अपने लिए पद और अधिकार प्राप्त करने तथा अपनी होशियारी दिखाने की चेष्टा में ही अधिन लग्न रहते हैं। राष्ट्रहित के लिए नीति निर्माण करने की बहुत कम चिंता करते हैं। सन् १६०८ ई० में पुर्तगाल के राजा का वध हुआ था और उस के उत्तराधिकारी राजा के राज्य-त्याग कर के भाग जाने पर प्रजातन्त्र का एलान किया गया था। फिर सन् १६११ ई० में, २१ वर्ष के ऊपर के पुर्तगाल के सारे भेदों के मतों से एक व्यवस्थापक सम्मेलन का चुनाव किया गया था। इस सम्मेलन ने एकमत से राजाशाही के पुर्तगाल में खत्म हो जाने का एलान किया था और राज-व्यस को देश निकाला दे कर प्रजातन्त्र की नई राज व्यवस्था रच कर पुर्तगाल में स्थापित की थी। सम्मेलन के चुनाव में राजाशाही में विश्वास रखने वालों को मत देने

का अधिकार नहीं दिया गया और गिरजों में मत डालना भी बंद कर दिया गया था। नई राज व्यवस्था की हर दसवें साल पुनर्घटना की जा सकती है।

**व्यवस्थापक-सभा**—पुर्तगाल की व्यवस्थापक-सभा को कांग्रेस कहते हैं और उस की दो सभाएँ होती हैं। 'प्रतिनिधि-सभा' और 'सिनेट'। प्रतिनिधि सभा में १६४ सदस्य होते हैं, जिन को तीन साल के लिए पुर्तगाल के सारे मर्द नागरिक चुनते हैं। सिनेट में ७१ सदस्य होते हैं, जिन को छ साल के लिए देश भर की चुगियाँ चुनती हैं। सिनेट के आधे सदस्यों का हर तीसरे साल चुनाव होता है। प्रतिनिधि-सभा के उम्मीदवारों की २५ साल उम्र और सिनेट के उम्मीदवारों की ३५ साल उम्र होने की शर्त रखी गई है। आर्थिक मसविदे, सरकारी मसविदे और जल और थल सेना के संगठन से संबंध रखने वाले मसविदे पहले प्रतिनिधि-सभा के सामने पेश होते हैं। सिनेट को सारे मसविदों के संशोधन और नामजूर करने का अधिकार होता है। हर मसविदे की मजूरी के लिए दोनों सभाओं के एकमत की जरूरत होती है, और दोनों सभाओं का एकमत करने के लिए, मत भेद होने पर, दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक भी की जाती है। दोनों सभाओं से मजूर हो जाने पर कानून प्रजातन्त्र के प्रमुख के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं। कानून नामजूर करने का अधिकार प्रमुख को नहीं होता है। व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं में मिला कर राष्ट्र की सारी कानून बनाने की, व्यवस्थापक और शासन सत्ता मानी गई है। मगर शासन-सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक सभा एक जवाबदार मंत्रि मंडल के द्वारा करती है। प्रजातन्त्र की स्थापना होने के बाद कई बार व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं को लंबे लंबे समय के लिए भंग भी किया जा चुका है।

**कार्यकारिणी**—पुर्तगाल प्रजातन्त्र के प्रमुख का चुनाव, चार साल के लिए, व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाएँ मिल कर करती हैं। प्रमुख पुर्तगाल का अधिकार प्राप्त नागरिक और ३५ वर्ष से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। एक साल पूरा हो जाने पर फिर दूसरे साल के लिए कोई प्रमुख नहीं चुना जा सकता है। प्रमुख मंत्रि-मंडल को नियुक्त और हटाता करता है, व्यवस्थापक सभा की सलाह और सलाह देकर बुलाता, कानूनों को एलान और जारी करता और मंत्रि-मंडल के फरमानों को अमल में रखता है। प्रमुख व्यवस्थापक-सभा को मंत्रि मंडल की सलाह से भंग भी कर सकता है। परदेशों से व्यवहार करने के लिए प्रमुख पुर्तगाल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। मगर युद्ध की घोषणा करने, संधि करने और दूसरे राष्ट्रों से सम्झौते करने के लिए प्रमुख को पहले व्यवस्थापक सभा की मजूरी ले लेनी होती है, क्योंकि इन सारी बातों के लिए जवाबदार मंत्रि मंडल ही माना जाता है।

मंत्रि मंडल को राजनैतिक और कानूनी तौर पर भी सारे कामों के लिए जवाबदार माना जाता है। मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभाओं की बैठकों में हाजिर रहना पड़ता है और प्रधान मंत्री को मंत्रि-मंडल की ग्राम नीति के लिए जवाब देना होता है। पुर्तगाल के मंत्रि मंडल मजबूत, योग्य और टिकाऊ नहीं होते हैं। एक १६२० के साल में ही नी

मणि मंडल बने और बिगड़े थे। बहुत से छोटे छोटे दलों से मिला कर मणि-मंडल बनाए जाते हैं। इन दलों को अधिकतर चुनावों के फल लूटने की अधिक अभिलाषा रहती है और यह इतने छोटे-छोटे और नुसगठित होते हैं कि न तो उन से मतदारों के समूह को ही कोई शिद्दा मिलती है और न मणि-मंडल ही टिकाऊ और जोरदार बन पाते हैं। व्यवस्थापक-सभा की चंगलता का खेल पुर्तगाल में जारी रहता है। एक सन् १९२६ ई० में ही पहले तो जेनरल वीस्ट्रा ने सेना की सहायता से सरकार पर कब्जा जमा लिया था और बाद में उस को निर्वासित कर के जेनरल केमेना ने सरकार को अपने हाथ में कर लिया था। सन् १९२८ ई० में प्रजा का मत लिए जाने पर प्रजा ने जेनरल केमेना की सरकार में अपना विश्वास अवश्य जाहिर किया था। मगर इस सरकार ने प्रजा का मत लेने से पहले ही अपने विरोधियों को खत्म कर दिया था, जिस से प्रजा को किसी और के पक्ष में मत देने का मौका नहीं था। यह सरकार एक प्रकार से निरी सेना की निरकुश-शाही है। अस्तु, इस को भी टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है। सन् १९३० ई० में पुर्तगाल के सारे अनुभवी शासकों का, सरकार की तरफ से राजधानी लिस्बन में, साधारण राज-नैतिक जीवन को पुनः स्थापित करने का निवार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। मुमकिन है इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप पुर्तगाल में एक मजबूत सरकारी दल कायम हो जाय। जो अपने हाथ में जेनरल केमेना की सरकार को लेकर भविष्य में उस की नीति पर कानूनी रीति से अमल शुरू करे।

**राजनैतिक दल**—पुर्तगाल के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'राजाशाही दल' है जो पुर्तगाल में पुनः राजाशाही स्थापित करने का इरादा रखता है। दूसरा कैथोलिक लोगों का एक 'कैथोलिक दल' है। तीसरा एक 'राष्ट्रीय दल' है, जिस में सकुचित विचारों के प्रजातन्त्रवादी होते हैं। चौथा एक 'उदार प्रजातन्त्र संघ' नाम का दल है, जिस में उदार विचारों के प्रजातन्त्रवादी होते हैं। पाँचवाँ एक 'आर्थिक हितों की संघ' नामक दल है, जिसमें राष्ट्रीय और सकुचित प्रजातन्त्र विचारों के व्यापारी लोग होते हैं। छठा 'प्रजातन्त्र दल' है, जो प्रजातन्त्रवादियों का दल है और जिस के गरम और नरम दो भाग हैं। एक 'समाजवादी दल' और दूसरा एक 'समष्टिवादी दल' भी हैं।

## स्पेन की सरकार



**राज-व्यवस्था**—पुर्तगाल के पड़ोसी आइबेरियन पेनिन्सुला के दूसरे देश स्पेन की सरकार यूरोप की सब से आखिरी प्रजातंत्र सरकार है, जिस ने प्रजातंत्र का रूप सिर्फ सन् १९३१ ई० में धारण किया था। सन् १८७६ ई० से स्पेन में व्यवस्थापक राजाशाही चली आती थी। इस राज-व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक सभा और मतदारों को जो कुछ सत्ता थी उस को सन् १९२३ ई० में १२ सितंबर के दिन जेनरल प्राइमो डे रिवेरा ने सेना की सहायता से अपने हाथ में कर लिया था। राजाशाही को कायम रक्खा गया था; मगर सरकार का काम एक डाइरेक्टरी के हाथों में आ गया था।

पुरानी राजाशाही राज-व्यवस्था देखने में काफ़ी उदार थी। इस राज-व्यवस्था के अनुसार क़ानून बनाने का अधिकार राजा और 'कौर्टेस' नाम की एक व्यवस्थापक-सभा को था। 'कौर्टेस' की दो समायें थीं एक 'प्रतिनिधि सभा' और दूसरी 'सिनेट'। दोनों सभाओं को बराबर के अधिकार थे। 'सिनेट' में तीन वर्ग के सदस्य होते थे। एक वर्ग को राजा जिंदगी भर के लिए नियुक्त करता था; दूसरा वर्ग अपने हक से सिनेट का सदस्य होता था; और तीसरे वर्ग को स्थानिक अधिकारी, गिरजों के अधिकारी, विश्व-विद्यालय और दूसरी विद्वान संस्थाएं चुनती थीं। 'प्रतिनिधि-सभा' में ४१७ सदस्य होते थे, जिन को देश के सारे मर्द नागरिक चुनते थे। मंत्री गण व्यवस्थापक-सभा को ज़वाबदार होते थे। इस राज-व्यवस्था में प्रजा को मिलने-बैठने की स्वतंत्रता, अपनी तथियत के अनुसार शिक्षा लेने की स्वतंत्रता, अख्तियारी आज़ादी, व्यक्तिगत संरक्षण, अखंड गृह-स्वतंत्रता और गुप्त

पत्र व्यवहार के अधिकार भी दिए गए थे। मगर इस राज-व्यवस्था का जैसा उदार रूप लगता था वैसा व्यवहार में नहीं था। कई बार सेना की मदद से भी यह राज-व्यवस्था उल्टी-पुल्टी जा चुकी थी। अस्तु, उस की स्थिरता में लोगों का बहुत विश्वास नहीं रहता था। स्पेन के करीब आधे लोग असह्य थे; अखबार प्रजासत्ता को कायम रखने के अव्योग्य थे; देश के एक भाग को दूसरे से संबद्ध रखना मुश्किल था क्योंकि रास्ते खराब थे; और देश के दोनों बड़े दल—अनुदार दल और उदार दल—आपस के झगड़ों के कारण बहुत-से छोटे-छोटे फिरफ़लों में बँटे हुए थे। यह सारे फिरफ़े और दल समाजवादियों के मुक़ाबले के लिए अवश्य मिल कर एक हो जाते थे। मगर ग्राम और परमंत्रि-मंडल जल्दी-जल्दी बनते और बिगड़ते थे, और स्पेन की राजनीति में हमेशा गड़बड़ और अस्थिरता रहती थी।

इस अस्थिर राजनीति का अंत सन् १६२३ ई० में सेना ने कर दिया। सन् १६१८ ई० से सैनिक अधिकारियों के सेना के हितों की रक्षा और सैनिक संगठन में उन्नति करने के बहाने से गुट बन रहे थे। सन् १६२१ ई० में मोरोको की घटनाओं के बाद से सेना ने व्यवस्थापकी राज-व्यवस्था का खुला विरोध शुरू कर दिया। १३ सितंबर, सन् १६२३ को स्पेन के राजा ने आखिरकार चालू मंत्रि-मंडल से इस्तीफा ले लेने की जेनरल ग्राइमो डे रिवेरा की माँग स्वीकार की और मंत्रि-मंडल को बरखास्त कर के राजा ने अपने फरमान से ग्राइमो डे रिवेरा की अध्यक्षता में जेनरलों की एक अस्थायी डाइरेक्टरी को सरकार का भार सौंप दिया। इस अस्थायी डाइरेक्टरी को राजा की मज़बूरी के लिए ऐसे फरमान बना कर पेश करने का हक माना गया था जो डाइरेक्टरी की समझ में प्रजा के हित के लिए जरूरी हों और इन फरमानों की, जब तक कि 'कौर्टेस' उन को तयदील कर के राजा से मज़ूर न करा ले तब तक, साधारण कानूनों की तरह साक्ष्य मानी गई थी। रिवेरा ने स्पेन का सार्वजनिक जीवन शुद्ध करने के लिए तीन महीने की मुहलत माँगी और फरमान निकाल कर उस ने 'कौर्टेस' और मंत्रि-मंडल को भंग कर दिया और राज-व्यवस्था में प्रजा को दिए गए सारे अधिकारों को भी खत्म कर दिया। सिर्फ़ शुद्ध और परराष्ट्र विभाग के दो मंत्रियों को उस ने कायम रखा। पुराने दलों को इस सैनिक अधिकार का विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी। रिवेरा ने यह भी घोषणा की थी कि उस का कार्य-क्रम पूरा करने के लिए छत वर्ष की जरूरत होगी और डाइरेक्टरी ने उस के कार्य-क्रम को मज़ूर कर के, सन् १६२४ ई० में 'धर्म, देश और राजा' के मूँढे के नीचे 'स्वदेशमत्त सभ' नाम के एक नए दल की स्थापना की थी।

तीन दिसंबर सन् १६२५ ई० को रिवेरा ने एक फरमान निकाल कर स्पेन में फिर डाइरेक्टरी भंग कर के मंत्रि-मंडल की स्थापना की। मगर मंत्रि-मंडल का कायम कर के भी रिवेरा ने पुनः व्यवस्थापकी सरकार कायम नहीं की। केवल देश का सामाजिक और आर्थिक संगठन सुधारने के विचार से उस ने सैनिक शासन के स्थान में अहलेकालम शासन कायम करने का निश्चय किया था। यह सरकार भी उतनी ही कड़ी और निरंकुश थी जितनी पहली सैनिक सरकार, और मंत्रियों के फरमानों की भी वैसी ही भरमार कायम

रही। परंतु धीरे-धीरे रिवेरा की समर्थक शक्तियां क्षीण होने लगीं थीं। सेना और पादरियों को प्रजा के प्रतीकार का भय हो उठा था, और व्यापारी लोग व्यापार की कमी की शिकायतें करने लगे थे। अस्तु, उदार दल को सरकार से मिलाने का प्रयत्न किया गया। मगर वह सफल नहीं हुआ। सन् १९३० ई० में रिवेरा का विरोध इतना बढ़ गया कि राजा को रिवेरा से आखिरकार इस्तीफा रखा लेना पड़ा।

जेनरल बेरेंगुइर की अध्यक्षता में नई सरकार बनी। मगर सरकार के ढंग में कोई खास सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया गया और राजनैतिक असंतोष कायम रहा। देश भर में इपर-उधर बराबर हड़तालों होती रहीं, जिन को रोकना असंभव हो गया। विद्यार्थियों में भी राजनैतिक असंतोष फैला और विश्व-विद्यालयों में आए दिन हड़तालों होने लगीं। इस असंतोष को दूर करने के लिए नए मंत्रि-मंडल ने व्यवस्थापक-सभा के आम चुनाव का मार्च सन् १९३२ में बांटा दिया। उद्योगी क्षेत्रों में फिर भी उत्साह होते रहे। १७ दिसम्बर को वायुयानों के एक अट्टे पर विद्रोह हो गया जो फहा जाता है कि क्रांति का प्रयत्न था। मगर इस विद्रोह को फौरन दबा दिया और बहुत-से प्रजातंत्रवादीयों को पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया। जनवरी में 'उदार दल' समाजवादी दल और प्रजातंत्रवादीयों ने एलान किया कि वे आनेवाले सरकारी चुनावों में भाग न लेंगे। अस्तु, फरवरी में ही एक शाही एलान के द्वारा पुरानी राज-व्यवस्था में दिए गए अधिकारों को चुनाव के जमाने तक के लिए कायम कर दिया गया, और 'उदार दल' ने चुनाव में भाग न लेने का अपना निश्चय बदल दिया। मगर १२ फरवरी को ही 'उदार दल' की तरफ से सरकार से कह दिया गया कि चुनाव के बाद नई व्यवस्थापक-सभा बैठने पर 'उदार दल' एक 'व्यवस्थापक सम्मेलन' बुलाने की मांग करेगा। इस खबर को पाते ही १४ फरवरी को राजा ने एक दूसरा फरमान निकाल कर आनेवाले चुनाव को बंद कर दिया और मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा रख दिया।

अखबारों की आज़ादी पर फिर सरकारी अंकुश लगा दिया गया। मंत्रि-मंडल बनाने के कई प्रयत्नों के बाद आखिरकार १८ फरवरी को, राजाशाही के पक्षपाती नेताओं की एक सभा में, एक 'संयुक्त दल' की स्थापना की गई, जिस ने अपनी सेवा राजा के फंदों में रखी और ऐडमिरल अज़नार की अध्यक्षता में एक नया मंत्रि-मंडल कायम हुआ। इस मंत्रि-मंडल के जमाने में, १२ अप्रैल को, सारे स्पेन में चुंगियों के चुनाव हुए, जिस में 'प्रजातंत्रवादीयों' को हर जगह अभूतपूर्व सफलता मिली। इस नई हवा से पैदा हुई परिस्थिति पर विचार करने के लिए मंत्रि-मंडल की जल्दी-जल्दी बैठकें हुई और राजा के राज-त्याग की अफवाहें फैलने लगीं। आखिरकार १४ अप्रैल को ७ बजे ब्रॉडकास्ट पर एलान हुआ कि, स्पेन में प्रजातंत्र की विजय हुई है और सरकारी दफ्तरों पर प्रजातंत्रवादीयों का शांतिमय कब्जा हो गया है। इस एलान के एक घंटे के बाद राजा अपने कुटुंब के साथ स्पेन छोड़ कर चला गया। मगर दूसरे दिन उस की तरफ से एलान निकला कि उस ने अपने किसी अधिकार का त्याग नहीं किया है, और देश छोड़ कर वह सिर्फ खून-खराबा बचाने के लिए चला गया है।

पन-व्यवहार के अधिकार भी दिए गए थे। मगर इस राज-व्यवस्था का जैसा उदार रूप लगता था वैसा व्यवहार में नहीं था। कई बार सेना की मदद से भी यह राज-व्यवस्था उल्टी-मुल्टी जा चुकी थी। अस्तु, उस की स्थिरता में लोगों का बहुत विश्वास नहीं रहता था। स्पेन के करीब आधे लोग असह्य थे; अखबार प्रजासत्ता को क्रायम रखने के अयोग्य थे; देश के एक भाग को दूसरे से संबद्ध रखना मुश्किल था क्योंकि रास्ते खराब थे; और देश के दोनों बड़े दल—अनुदार दल और उदार दल—आपस के झगड़ों के कारण बहुत-से छोटे-छोटे फिरछों में बँटे हुए थे। यह सारे फिरछे और दल समाजवादियों, मुक्तावहों के लिए अवश्य मिल कर एक हो जाते थे। मगर आम तौर पर मंत्रि-मंडल जहाँ जल्दी बनते और बिगड़ते थे, और स्पेन की राजनीति में हमेशा गड़बड़ और अस्थिरता थी।



## पारिभाषिक शब्दों की सूची

Adjournment of the House	स्थगित, सभा स्थगित
Administration	शासन
Administrative	शासकी
Alliance	मैत्री
Aristocracy	कुबेरशाही, अमीरशाही
Aristocratic	कुबेरपंथी, अमीरपंथी या अमीरी
Article, Act	धारा
Auditor	हिसाब-परीक्षक
Authority	सत्ता या सत्ताधारी
Bill	मसविदा
Bourgeois, Middle Class	मध्यम वर्ग
Cabinet or Council of Ministers	मन्त्रिमंडल
Capitalism	पूँ जीशाही
Centralisation	केंद्रीकरण, केंद्रीयता
Class struggle or Class war	वर्गसंघर्ष, वर्गयुद्ध या वर्गसंग्राम
Compulsory Referendum	लाचारी दयाला
Communism	
Communist	

डोन अल्काला जेमोरा की अध्यक्षता में एक 'काम-चलाऊ सरकार' बना ली गई। इस सरकार को बहुत-से शासन, आर्थिक और धार्मिक संकटों का सामना करना पड़ा और उस ने सारी समस्याओं को सफलता से सुलझाया। अगस्त में नई राज-व्यवस्था का मसविदा 'कौर्टेस' के सामने पेश हुआ और उस पर कई हफ्ते तक उस सभा में विचार होता रहा। अक्टूबर में कौर्टेस ने जेजुइट-पंथी लोगों को स्पेन से निकाल देने और उन की माल और जायदाद ज़न्त कर लेने तथा दूसरे धार्मिक पंथों पर सरकार की कड़ी देख रेख रखने और उन की जायदाद भी ज़न्त कर ली जाने की संभावना का और व्यापार, उद्योग और शिक्षा के कार्यों में उन को भाग न लेने-देने का निश्चय किया। इस पर डोन अल्काला जेमोरा और गृह-मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और डोन मैनुइल अज़ाना की अध्यक्षता में दूसरी नई सरकार बनी। २० नवंबर, को एक प्रस्ताव पास कर के 'कौर्टेस' ने स्पेन के भूतपूर्व राजा को देशद्रोह का अपराधी ठहराया और उस को मुजरिम करार दे कर उस की जायदाद ज़न्त कर ली। नवंबर के अंत में नई राज-व्यवस्था 'कौर्टेस' ने मंजूर कर ली। बारह दिसंबर को डोन अल्काला जेमोरा को छः साल के लिए स्पेन के नए प्रजातंत्र का प्रमुख चुन लिया गया। दूसरे ही दिन काम चलाऊ सरकार ने इस्तीफा रख दिया और १५ दिसंबर को डोन अज़ाना की अध्यक्षता में स्पेन का प्रथम व्यवस्थापक मंत्रि-मंडल बना।

---

## पारिभाषिक शब्दों के

Adjournment of the House	स्थगित, सभा स्थगित
Administration	शासन
Administrative	शासकी
Alliance	मैत्री
Aristocracy	कुवेरशाही, अमीरशाही
Aristocratic	कुवेरपयी, अमोरपयी या अमीरी
Article, Act	धारा
Auditor	हिसाब-परीक्षक
Authority	सत्ता या सत्ताधारी
Bill	मसविदा
Bourgeois, Middle Class	मध्यम वर्ग
Cabinet or Council of Ministers	मन्त्रिमंडल
Capitalism	पूँजीशाही
Centralisation	केंद्रीकरण, केंद्रीयता
Class struggle or Class war	वर्गसंघर्ष, वर्गयुद्ध या वर्गसंग्राम
Compulsory Referendum	लाचारी हवाला
Communism	समष्टिवाद
Communist	समष्टिवादी
Conservative	पुरातन, दक्षिणानुसी, अनुदार
Constituency	निर्वाचन या चुनावक्षेत्र
Constituent Assembly	व्यवस्थापक-सम्मेलन
Constitution	राजव्यवस्था
Constitutional Monarchy	व्यवस्थापकी राजाशाही
Crown	राजछत्र या राजगद्दी
Decree	फरमान, हुक्म
Delegate, Representative	प्रतिनिधि
Delegation	प्रतिनिधि-मंडल या प्रतिनिधित्व
Democracy	प्रजासत्ता, प्रजासत्तात्मक राज, या :
Democratic	प्रजासत्तात्मक
Dictatorship of the Proletariat	निरंकुश मजदूर पेशाशाही
Direct Democracy.	प्रत्यक्ष या सीधी प्रजासत्ता

## पारिभाषिक शब्दों की २

Adjournment of the House	स्थगित, सभा स्थागत
Administration	शासन
Administrative	शासकी
Alliance	मैत्री
Aristocracy	कुबेरशाही, अमीरशाही
Aristocratic	कुबेरपंथी, अमीरपंथी या अमीरी
Article, Act	धारा
Auditor	हिसाब-परीक्षक
Authority	सत्ता या सत्ताधारी
Bill	मसविदा
Bourgeois, Middle Class	मध्यम वर्ग
Cabinet or Council of Ministers	मंत्रिमंडल
Capitalism	धूर् जीशाही
Centralisation	केंद्रीकरण, केंद्रीयता
Class struggle or Class war	वर्गसंघर्ष, वर्गयुद्ध या वर्गसंग्राम
Compulsory Referendum	लाचारी हयाला
Communism	समष्टिवाद
Communist	समष्टिवादी
Conservative	पुरातन, दक्षिणानुसी, अनुदार
Constituency	निर्वाचन या चुनावक्षेत्र
Constituent Assembly	व्यवस्थापक-सम्मेलन
Constitution	राजव्यवस्था
Constitutional Monarchy	व्यवस्थापकी राजाशाही
Crown	राजछत्र या राजगद्दी
Decree	फरमान, हुक्म
Delegate, Representative	प्रतिनिधि
Delegation	प्रतिनिधि-मंडल या प्रतिनिधित्व
Democracy	प्रजासत्ता, प्रजासत्तात्मक राज, या
Democratic	प्रजासत्तात्मक
Dictatorship of the Proletariat	निरंकुश मजदूर पेशाशाही
Direct Democracy.	प्रत्यक्ष या सीधी प्रजासत्ता

डोन अल्काला जेमोरा की अध्यक्षता में एक 'काम-चलाऊ सरकार' बना ली गई। इस सरकार को बहुत से शासन, आर्थिक और धार्मिक सरुतों का सामना करना पड़ा और उस ने सारी समस्याओं को सफलता से सुलझाया। अगस्त में नई राज-व्यवस्था का मसविदा 'कौर्टेस' के सामने पेश हुआ और उस पर कई हफ्ते तक उस सभा में विचार होता रहा। अक्टूबर में कौर्टेस ने जेजुइट पथी लोगों को स्पेन से निकाल देने और उन की माल और जायदाद जन्त कर लेने तथा दूसरे धार्मिक पथों पर सरकार की कड़ी देख रेख रखने और उन की जायदाद भी जन्त कर ली जाने की सभावना का और व्यापार, उद्योग और शिक्षा के कामों में उन को भाग न लेने देने का निश्चय किया। इस पर डोन अल्काला जेमोरा और यह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और डोन मैन्युइल अजाना की अध्यक्षता में दूसरी नई सरकार बनी। २० नवंबर, को एक प्रस्ताव पास कर के 'कौर्टेस' ने स्पेन के भूतपूर्व राजा को देशद्रोह का अपराधी ठहराया और उस को मुजरिम करार दे कर उस की जायदाद जन्त कर ली। नवंबर के अंत में नई राज व्यवस्था 'कौर्टेस' ने मंजूर कर ली। बारह दिसंबर को डोन अल्काला जेमोरा को छः साल के लिए स्पेन के नए प्रजातंत्र का प्रमुख चुन लिया गया। दूसरे ही दिन काम चलाऊ सरकार ने इस्तीफा रख दिया और १५ दिसंबर को डोन अजाना की अध्यक्षता में स्पेन का प्रथम व्यवस्थापक मंत्रि मंडल बना।

---

## पारिभाषिक शब्दों की सूची

Adjournment of the House	स्थगित, सभा स्थगित
Administration	शासन
Administrative	शासकी
Alliance	भेदी
Aristocracy	कुचेरशाही, अमीरशाही
Aristocratic	कुचेरपथी, अमीरपथी या अमीरी
Article, Act	धारा
Auditor	रिखाब-परीक्षक
Authority	सत्ता या सत्ताधारी
Bill	मसविदा
Bourgeois, Middle Class	मध्यम वर्ग
Cabinet or Council of Ministers	मन्त्रिमंडल
Capitalism	धुँ जीशाही
Centralisation	केंद्रीकरण, केंद्रीयता
Class struggle or Class war	वर्गसंघर्ष, वर्गयुद्ध या वर्गसंग्राम
Compulsory Referendum	लाचारी इनाला
Communism	समष्टिवाद
Communist	समष्टिवादी
Conservative	पुरातन, दक्कियानूसी, अनुदार
Constituency	निर्वाचन या चुनावक्षेत्र
Constituent Assembly	व्यवस्थापक सम्मेलन
Constitution	राजव्यवस्था
Constitutional Monarchy	व्यवस्थापकी राजाशाही
Crown	राजछत्र या राजगद्दी
Decree	फरमान, हुक्म
Delegate, Representative	प्रतिनिधि
Delegation	प्रतिनिधि-मंडल या प्रतिनिधित्व
Democracy	प्रजासत्ता, प्रजासत्तात्मक राज, या प्रजाशाही
Democratic	प्रजासत्तात्मक
Dictatorship of the Proletariat	निरंकुश मजदूर पेशाशाही
Direct Democracy.	प्रत्यक्ष या सीधी प्रजासत्ता

Direct Election	प्रत्यक्ष निर्वाचन या सीधा चुनाव
Dissolve	सभामग
Dual Monorchy	द्वयशाही
Executive	कार्यकारिणी, कारगुजार
Executive Committee	कार्यकारिणी, कार्यवाहक, कारगुजार
Executive Officer	कारगुजार हाकिम या अफसर
Executive Power	कार्यकारिणी सत्ता
Feudalism	नयायशाही, नबाबी
First Ballot	पहला पर्चा
Freedom of the Press	लेख स्वतन्त्रता, लिखने की या अखबार आ।
Freedom of Speech	वाक् स्वतन्त्रता, बोलने की आजादी
Free Trade	स्वतन्त्र व्यापार
Fundamental	मूल
Indirect Election	परोक्ष निर्वाचन या टेदा चुनाव
Initiative	प्रस्तावना
Judiciary	न्यायसत्ता
Jurisdiction	अधिकार सीमा
Labour Minister	श्रमसचिव
Law, Act	कानून
Learned profession	विद्वानपेशा
Learned Societies	विद्वान संस्थाएँ
Left Parties	प्रभावशील या गरमदल
Legislative Power	धारा सत्ता या कानून बनाने की सत्ता
Liberalism	उदारवाद
Limited Monarchy	सीमित राजाशाही
Lower Chamber	निचली सभा
Majority	बहुसंख्या, बहुमत
Migration	प्रवास
Militia	जनसेना
Ministerial party	मन्त्रिदल
Ministry	मन्त्रिमंडल
Minority	अल्पसंख्या
Monarchy	राजाशाही
Money Bill	आलमसविदा, अर्थात् मसविदा

Monopoly	ईजारा
Motion of Adjournment	चर्चास्थगित प्रस्ताव
National Minorities	राष्ट्रीय अल्प-संख्याएँ
Optional Referendum	इच्छितपारी इवाला
Ordinances	फरमानगी, कानून, फरमान
Parliament	व्यवस्थापक सभा
Parliamentary	व्यवस्थापकी
People's Commissioners	जनसचालक
Popular Government	प्रजाराज, जनराज, जनसत्ता
Prohibition	शराबप्रदी
Proletariat	उद्योगीवर्ग, मजदूरपेशा
Promulgate the Law	कानून ऐलान या जारी करना
Proportional Representation	अनुपात निर्वाचन
Prorogue	सभा विसर्जन
Public Opinion	जनमत
Pure Democracy	खालिस प्रजासत्ता या प्रजाशाही
Radical	गरम
Reactionary	उल्दी बुद्धि
Referendum	इवाला
Reformist	सुधारी
Republic	प्रजातन्त्र राज्य, प्रजातन्त्र
Right Parties	सरकार पक्षीदल या नरमदल
Representative Government	प्रतिनिधि सरकार
Residuary Power	शेष सत्ता
Responsible Government	जवाबदार या ज़िम्मेदार सरकार
Settlement	निवास
Social welfare	समाजहित
Socialism, Socialist State	समाजशाही
Socialists	समाजवादी
Standing Army	स्थायी सेना
Suffrage, Franchise	मताधिकार
Supreme Authority	सर्वोपरि सत्ता, सर्वोपरि सत्ताधारी
Trade Union	मजदूरसंघ या उद्योगसंघ
Unanimous	सर्वमत
Universal Suffrage	सार्वजनिक मताधिकार



Upper Chamber

\* ऊपरी सभा

Vote by Division

\* बॉट से मत

Watchword

\* ध्येयशब्द, ध्येयमन्त्र